प्रतियोगिता दर्पण

अप्रैल 2024 मूल्य ₹ 125.00

हिन्दी मासिक

शिक्षित युवा वर्ग के स्वर्णिम भविष्य के लिये

For e-magazine:
http://emagazine.pdgroup.in

√दुआओं में याद रखना _

गगनयान मिशन हेतु चयनित अंतरिक्ष यात्री

हल प्रश्न-पत्र

- 69वीं बीपीएससी (मुख्य), 23
- यू.जी.सी.-नेट/जेआरएफ, 23

मॉडल हल

- सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा
- उ.प्र. पीसीएस (प्रा.) परीक्षा

- चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिंहराव व डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न
- चुनावी बॉण्ड योजना असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द
- उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित
- झारखण्ड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी
- भारत के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में • ज्ञानपीठ पुरस्कार (2023), बाफ्टा पुरस्कार (2024)
- मौद्रिक नीति: 2023-24 की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा • नौवाँ रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में सम्पन्न
- मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट-3डीएस का प्रक्षेपण • पहली बार किसी निजी कम्पनी का लैंडर चन्द्रमा की सतह पर उतरा
- लोकतंत्र सूचकांक (2023) : भारत का 41वाँ स्थान • भ्रष्टाचार बोध सूचकांक: भारत का 93वाँ स्थान
- छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स व चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स सम्पन्न • उ.प्र., बिहार, छत्तीसगढ़ व झारखण्ड के बजट (2024-25)

पतंजलि®

देश का पहला और एकमात्र,

राख से बना

निम्बू व नीम की शक्ति वाला

पतंजलि डिशवाश बार और लिक्विड

चिकनाई पर सख़्त
हाथों पर नर्म

संस्थापक सम्पादक
स्व. श्री महेन्द्र जैन

सम्पादक
राहुल जैन

प्रधान सलाहकार
डॉ. रवि कान्त

रजिस्टर्ड ऑफिस
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002

सम्पादकीय ऑफिस
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी,
आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा–282 005
फोन–2531101, 2530966
ई-मेल : सम्पादकीय : publisher@pdgroup.in
कस्टमर केयर : care@pdgroup.in

दिल्ली ऑफिस
4845, अंसारी रोड, दरियागंज,
नई दिल्ली–110 002
फोन–011-23251844, 43259035

हैदराबाद ऑफिस
16-11-23/37, मूसारामबाग, टीगल गुडा
आर.टी.ए. ऑफिस के सामने मेन रोड
(यूनियन बैंक के बगल में), हैदराबाद–500 036
(तेलंगाना) मो.–09391487283

पटना ऑफिस
पारस भवन (प्रथम तल), खजांची रोड,
पटना–800 004
मो.–09334137572

हल्द्वानी ऑफिस
8-310/1, ए.के. हाउस हीरानगर, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल–263 139
(उत्तराखण्ड) मो.–07060421008

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

के पाठकों से...

प्रिय पाठको !

आपकी सर्वाग्रगण्य एवं लोकप्रिय पत्रिका **'प्रतियोगिता दर्पण'** का **अप्रैल 2024 अंक** आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष एवं सन्तोष की अनुभूति हो रही है. पत्रिका के प्रस्तुत अंक को आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है. प्रकाशन से सम्बन्धित सभी लोगों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग से यह अंक इतना अधिक परीक्षोपयोगी बन पाया है.

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से इस अंक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सारगर्भित एवं विश्लेषणात्मक लेख दिए गए हैं. इनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं–लोक सभा व विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल संवर्धन : वर्तमान आवश्यकता, भारतीय लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव, समुद्री शैवाल : भविष्य का भोजन, वायु प्रदूषकों का पौधों पर प्रभाव.

पत्रिका के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चयनित हल प्रश्न-पत्र आवश्यक व्याख्या एवं संकेतों के साथ दिए गए हैं. इनमें से कुछ प्रश्न-पत्र इस प्रकार हैं–

हल प्रश्न-पत्र–69वीं बीपीएससी (मुख्य) परीक्षा का हल प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन-II

ऐच्छिक विषय–वाणिज्य–यू.जी.सी.–नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा, 2023.

हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि **"कठिन परिश्रम एवं उचित और सामयिक मार्गदर्शन सफलता प्राप्त करने का मूलमंत्र है." प्रतियोगिता दर्पण** आपका सही एवं सामयिक मार्गदर्शन करने में बेजोड़ है. आप प्रयास कीजिए, आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए प्रतियोगिता दर्पण आपके साथ है.

नियमित रूप से एवं समझदारी के साथ प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए. यह आपको अभीष्ट सफलता दिलाने एवं आपके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में पूर्णतः सक्षम है.

आपकी चतुर्दिक सफलता एवं स्वर्णिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

राहुल जैन
(सम्पादक)

All rights reserved. No part of this Magazine may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, Electronic, Mechanical, Photocopying, Recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. While every effort has been made to ensure accuracy of the information published in this edition, neither publisher nor any of its employees accept any responsibility for any error or omission. Articles that cannot be used are returned to the authors if accompanied by a self addressed and sufficiently stamped envelope. But no responsibility is taken for any loss or delay in returning the material. Pratiyogita Darpan assumes no responsibility for statements and opinions advanced by the authors nor for any claims made in the advertisements published in the Magazine.

Drishti IAS

IAS GS फाउंडेशन कोर्स

प्रिलिम्स + मेन्स | ऑफलाइन व लाइव ऑनलाइन

- **500+ कक्षाएँ**
  1200+ घंटे
- **निशुल्क अध्ययन सामग्री**
  पुस्तकें + प्रिंटेड नोट्स
- **संशय निवारण**
  क्वालिटी मेंटरशिप
- **असीमित बार देखने की सुविधा**
  कोर्स की वैधता तक

एडमिशन आरंभ

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम

UGC-NET कोर्सेज़

लाइव ऑनलाइन

पेपर-1 | इतिहास | भूगोल | राजनीति विज्ञान | हिंदी साहित्य

- निशुल्क पाठ्य-सामग्री
- निशुल्क ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़

एडमिशन आरंभ

अभी डाउनलोड करें
Drishti Learning App

विंडोज़ पर भी उपलब्ध

Target: IAS प्रिलिम्स 2024
GS | CSAT

ऑनलाइन

- संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज
- ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़
- 1 वर्ष की कोर्स वैधता
- प्रतिदिन 1 कक्षा, सप्ताह में 6 दिन कक्षाएँ

एडमिशन आरंभ

UPPCS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2024

ऑफलाइन व ऑनलाइन

- कुल 16 टेस्ट्स की टेस्ट सीरीज़
- फ्लेक्सी फॉर्मेट की सुविधा
- MCQs प्रश्नों के माध्यम से व्यापक कवरेज
- दृष्टि सेंटर्स पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़

एडमिशन आरंभ

IAS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2024

ऑफलाइन व ऑनलाइन

- 19 GS तथा 10 CSAT के टेस्ट्स शामिल
- तथ्यात्मक तथा अवधारणात्मक प्रश्न
- MCQs प्रश्नों के माध्यम से व्यापक कवरेज
- दृष्टि सेंटर्स पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़

एडमिशन आरंभ

87501 - 87501

मुखर्जी नगर
641, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली - 110009

करोल बाग
21, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

प्रयागराज
ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211001

लखनऊ
बलिंगटन चौराहा, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001

जयपुर
हर्ष टावर 2, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान - 302015

46 वर्ष | नवम् अंक | अप्रैल 2024

प्रतियोगिता दर्पण

हिन्दी मासिक

546 वाँ सफलतम अंक

इस अंक में...

7 सम्पादकीय

9 राष्ट्रीय घटनाक्रम

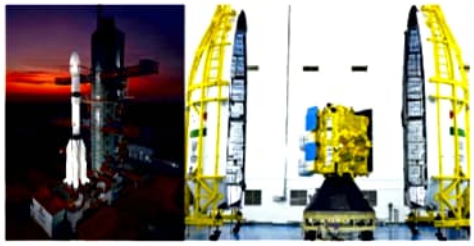

13 अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

20 आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

24 राज्य समाचार

33 नवीनतम सामान्य ज्ञान

40 खेलकूद

43 रोजगार समाचार

47 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

50 दिव्य दर्पण

55 **कॅरियर लेख :** सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के प्रतीक : आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व

अनुप्रेरक युवा प्रतिभाएं

59 **रीमा शर्मा**
68वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित (44वाँ स्थान)

62 **रतीश कुमार**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

63 **अनीशा कुमारी**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

66 **अभिराम कुमार**
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

68 स्मरणीय तथ्य

विश्व परिदृश्य

70 भारत और बांग्लादेश सम्बन्ध : सम्भावनाएं व चुनौतियाँ

72 भारत की हिन्द महासागर रणनीति

फोकस

74 (1) भारतीय चुनाव प्रणाली : सुधार की आवश्यकता

77 (2) चुनावी बॉण्ड असंवैधानिक : गोपनीयता *बनाम* पारदर्शिता के बीच बहस

80 (3) भारत में राजकोषीय संघवाद

सभी प्रकार की मासिक पत्रिका मैगजीन पढ़ने वाले इस पेज को किलक करे जरूर करे 👇

https://t.me/Magazine9876

Those who read all types of monthly magazines must join this group.

Please touch this page

👆 👆

विविधा

83 ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल

86 वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं

लेख

91 **राजनीतिशास्त्र लेख**—लोक सभा और विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा

92 **आर्थिक एवं वाणिज्यिक लेख**—63वाँ सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23

94 **आर्थिक लेख**—ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल संवर्धन : वर्तमान आवश्यकता

97 **समाजशास्त्रीय लेख**—भारतीय लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

99 **सागरीय कृषि लेख**—समुद्री शैवाल : भविष्य का चिकित्सीय भोजन

102 **कृषि लेख**—वायु प्रदूषकों का पौधों पर प्रभाव

105 **सार संग्रह**

हल प्रश्न-पत्र

108 69वीं बीपीएससी (मुख्य) परीक्षा (5.1.2024) का हल प्रश्न-पत्र : सामान्य अध्ययन-II

ऐच्छिक विषय

122 यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा-2023 (13.6.2023) का हल प्रश्न-पत्र : वाणिज्य

मॉडल हल प्रश्न

134 यूपीएससी सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा 2024 हेतु विशेष हल प्रश्न : सामान्य अध्ययन-I

145 उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ (प्रा.) परीक्षा, 2024 हेतु विशेष हल प्रश्न : सामान्य अध्ययन-I

वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान

161 उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

162 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

166 भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समीक्षा 2024 पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न

168 आर्थिक घटनाचक्र : बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न

ज्ञानार्जन के नवीन क्षितिज

172 क्या आप जानते हैं ?

173 अपना ज्ञान बढ़ाइए

श्रेष्ठतर प्रतिभागी

174 **प्रथम पुरस्कृत निबन्ध**—"जाति व्यवस्था की ओर वापस लौटती भारतीय राजनीति"

176 **निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-535 का परिणाम**

177 **सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक-219**

प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित किसी भी सामग्री अथवा चित्र के लिए सम्पादक की सहमति होना आवश्यक नहीं है. –सम्पादक

सम्पादकीय

स्व-प्रेरणा जनित उपलब्धि बुद्धिमान व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण

"You are your master. Only you have the master keys to open the inner locks."

— **Amit Ray**

जो खुद के कल से आज को बेहतर बनाना चाहता है, जो प्राप्त हो चुका उस उपलब्धि पर नहीं इठलाता है, बल्कि प्राप्त हो गई हर उपलब्धि के वर्तमान क्षण को सजाता है, वह व्यक्ति जीवन की श्रेष्ठतम सम्भावना का साक्षात्कार कर पाता है.

हम में से प्रत्येक व्यक्ति को सतत् आगे बढ़ना होता है, हर दिन अपने कर्म क्षेत्र में खुद की योग्यताओं को विकसित करना होता है, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे और पछाड़ दिए जाएंगे. हमें हार नहीं जीत पसंद है. अपमान नहीं स्व-मान पसंद है, तो निश्चित है कि हर हाल में हमारा विकास हो, हम अपने कल से आज को बेहतर बनाएं. इसके लिए हमें प्रेरणा, तो चाहिए ही, परन्तु हमारी प्रेरणा टीवी के विज्ञापन न हों. स्कूल, कॉलेज या नगर राज्य के इलेक्शन ना हों, बढ़ती महँगाई की मार या गलाकट प्रतिस्पर्धी माहौल ना हो. हमारी प्रेरणा का स्रोत बाहरी चुनौतियाँ या दबाव न हों. हमारी प्रेरणा किसी दुःखद घटना का, मृत्यु शोक या वियोग का इंतजार न करें. हमारे विकास की प्रेरणा किसी परीक्षा की घड़ी की मोहताज न बने.

हमें हर दिन को अपना अन्तिम दिन समझते हुए अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ कृत्यों को आज ही पूरा कर लेना है और इसके लिए हमारी प्रेरणा कोई और नहीं हम स्वयं बनें. हम ही अपने हालातों को बुनें. अपने जीवन का पथ हम स्वयं चुनें.

प्रेरणाओं के स्रोत अनेक हैं—

(1) इच्छाओं से उत्पन्न प्रेरणा—यह भी भीतर से ही उत्पन्न होती है.

अक्सर हम सभी इच्छा जनित प्रेरणा के चलाए चलते हैं और इच्छानुसार प्रवृत्ति करने में जीवन भर मशगूल रहते हैं, किन्तु हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होतीं. जब हम एक स्तर तक पहुँचते हैं तुरन्त दूसरे को देखकर मन में प्रतिस्पर्धा जगती है और तुलनात्मक रीडिंग चालू हो जाती है. इस तरह हम सदा आगे बढ़ते जाते हैं. इच्छा जनित प्रेरणा में अगर दुर्भावना न हो, हीन भावना न हो, प्रदर्शन की गौरव परक भावना न हो, अधीरता से उत्पन्न निराशा न हो तो इंसान अपने जीवन में एक चिर स्थायी समृद्धि व वैभव प्राप्त कर पाता है. इच्छाएं उठना मनुष्य के मन का स्वाभाविक क्रम है. अगर हम इच्छाओं को अपने विवेक से संशुद्ध (Filter) करके अपनाएं तो जीवन सुखद बनता है. अन्यथा लोगों को इच्छाओं की बेलगाम दौड़ में गिर-पड़ कर मर जाते देखा गया है. कई लोग किसी एक फील्ड में अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के दबाव में आकर कुछ इस कदर अतिक्रमण कर बैठते हैं कि वे अपने दुष्कृत्यों का फल भोग बहुत तड़प-तड़प कर मरते हैं. जैसे आज के युवाओं में शोर्टकट धन कमाने की बेलगाम इच्छा ने उन्हें जुआ, सट्टा, चोरी, विश्वासघात तक करने को उतारू बना दिया. वे अपने ही माता-पिता के धन को चुराकर अपना कर्जा उतार रहे हैं अथवा अय्याशी करते पाए जा रहे हैं. ये अनियंत्रित इच्छाएं व अविवेकजनक प्रेरणाएं आदमी के पूरे जीवन पर कालिख पोत देती हैं. दोस्तों के साथ रिश्तों को सुनकर अपने लिए भी किसी को फँसाने की चेष्टा, किसी की कमी को जानकर उसको ब्लेकमेल करने की चेष्टा, जो आज के युवाओं में देखी जा रही है, उसके लिए समाज के अनुभवी लोग बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. अपने कॅरियर के बचाव के लिए भी कई लोग औरों का जीवन उजाड़ने में संकोच नहीं करते हैं. इस प्रकार की इच्छाजनित प्रेरणाएं आदमी को भयंकर गर्त में डाल रही हैं.

(2) प्रदर्शन जनित प्रेरणाएं—जब अपने से अधिक उच्च उपलब्धि वालों को देखकर, उनके खर्चे, उनके शौक-मौज को जान-देखकर आपमें कोई प्रेरणा जागृत होती है और आप भी वैसा बनने की चेष्टा में प्रयासरत् रहते हैं तब वह प्रदर्शन जनित प्रेरणा कहलाती है. आजकल हॉलीवुड व बॉलीवुड को देख-देखकर लोग अपना जीवन भी वैसे ही नाटकीय अंदाज में जीना पसन्द करते हैं, यह उनकी ख्वाहिश बन जाती है कि वे भी हनीमून मनाने विदेशों में जाएं, शादी-विवाह किसी क्रूज पर रचाएं, अपने घर में बन-ठन कर बैठ जाएं व नौकरों से अपना हर काम कराएं, इस तरह की प्रतिष्ठा पाने के लिए भी लोग बहुत कुछ करने में तत्पर दिखाई पड़ते हैं. बिना थके अत्यधिक परिश्रम करते हुए धनोपार्जन करके उसे विलासिता के साधनों पर खर्च कर सकें पर जरा सोचिए, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या कोई आदमी, जो समझदार है, वह इसलिए अपने आपको नैतिक-अनैतिक धंधों में लिप्त करेगा या अत्यधिक परिश्रम करके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा जिसके फलस्वरूप वह कल का आराम पा सके और बड़ी बीमारी हो जाने पर बड़े हॉस्पीटल में नामी-गिरामी डॉक्टर से इलाज पा सके. क्या हम कल के खर्चों के लिए आज को खराब करना पसंद करेंगे? अगर नहीं..... तो हमें हमारी आज की जीवनशैली व कार्यशैली में मौजूद प्रेरणा के तल को पहचान लेना बहुत जरूरी है. हमें विलासी जीवन जीने की इच्छा से आज के स्वास्थ्य की हानि पहुँचाने वाली शैली को अपनाना बिल्कुल भी विवेकपूर्ण नहीं होगा.

(3) विवेक जनित प्रेरणा—यही प्रेरणा बुद्धिमानी का लक्षण है. बुद्धिमान इंसान की यह पहचान है कि वह इच्छाओं के वशीभूत होकर या अधीर बनकर किसी भी काम को करने में उतावला नहीं होता. वह सोच-समझकर बोलता, लिखता, पढ़ता या करता है. बुद्धिमान इंसान कभी भी औरों की देखा-देखी नहीं करता.

बुद्धिमान कभी भी औरों से प्रभावित होकर कुछ भी कृत्य-अकृत्य नहीं कर बैठता है. उसकी उपलब्धियाँ न किसी दिखावे की मोहताज होती हैं, न ही किसी नकल या अंधविश्वास की उपज. उसे जब जहाँ जो ठीक लगता है, वही करता है और आवश्यक ही बोली बोलता है.

ऐसे बुद्धिमानों द्वारा ही जमाना गौरव पाता है और युगों-युगों तक उनके गौरव गीत गाता है.

आत्मप्रेरित व विवेकप्रेरित जिन्दगी जीने वाला समझदार इंसान अपनी सानी आप होता है, वह विशिष्ट अहसासों से जीता हुआ, जो कुछ भी उपलब्धियाँ हासिल करता है, वे उपलब्धियाँ ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण बनकर स्वर्णिम इतिहास की रचना कर डालती हैं. आत्मप्रेरित जीने के लिए आपको स्वयं को जानना व अपने लक्ष्य की और उसकी प्राप्ति के मार्ग की स्पष्ट समझ रखना अति आवश्यक है.

बेहतर तो यही है कि हम आत्मप्रेरित होकर जीने के लिए अपने भीतर अपना जमीर जगाएं, अपने इष्ट को पहचानें और अपनी योग्यताओं का सृजनात्मक उपयोग करना सीखें.

●●●

आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं

2024

1–12 मार्च—एस.एस.सी. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एसएसएफ कॉंस्टेबिल (जीडी) व राइफलमैन (जीडी) असम राइफल्स परीक्षा, 2024

10 मार्च—उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2023

11–16 मार्च—म.प्र. पी.एस.सी. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, 2023

16–22 मार्च—उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2024

17 मार्च—राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, 2024 (कक्षा–6)

17 मार्च—भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा, 2024

21 अप्रैल—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2024

21 अप्रैल—सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024

22 अप्रैल—भारतीय सेना अग्निवीर सामान्य प्रवेश परीक्षा, 2024-25

24 अप्रैल—उत्तर प्रदेश बी.एड. (द्विवर्षीय) प्रवेश परीक्षा, 2024

28 अप्रैल—मध्य प्रदेश पीएससी राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2024

15–31 मई—कॉमन यूनिवर्सिटी एन्ट्रेन्स टेस्ट (अण्डर-ग्रेजुएट) परीक्षा, 2024
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 26 मार्च, 2024)

26 मई—संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज प्रारम्भिक परीक्षा, 2024

2 जून—छत्तीसगढ़ प्री.बी.एड. एवं प्री.डी.एल.एड. परीक्षा, 2024
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 24 मार्च, 2024)

22 जून—राजस्थान एस.एस.सी. पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

13 जुलाई—राजस्थान एस.एस.सी. पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

20 जुलाई—राजस्थान एस.एस.सी. पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

21 जुलाई—छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024
(ऑनलाइन अन्तिम तिथि : 7 अप्रैल, 2024)

28 जुलाई—राजस्थान एस.एस.सी. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

1-2 अगस्त—राजस्थान एस.एस.सी. छात्रावास अधीक्षक (अल्पसंख्यक मामलात विभाग) सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

11 अगस्त—राजस्थान एस.एस.सी. लिपिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024

21–24 सितम्बर—राजस्थान एस.एस.सी. पशु परिचर (Animal Attendent) सीधी भर्ती परीक्षा, 2023

निबन्ध प्रतियोगिता

विषय—"अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की ऊँची उड़ान"
अन्तिम तिथि—28 अप्रैल, 2024.
शब्द संख्या—लगभग 2000 शब्द.

1. निबन्ध कागज के एक ओर ही टंकित अथवा स्वहस्तलिखित होना चाहिए.
2. निबन्ध के साथ प्रतियोगी अपना पासपोर्ट आकार का छायाचित्र भेजें. प्रथम तीन निबन्धों पर क्रमशः ₹ 2000, ₹ 1500 व ₹ 1000 चेक के माध्यम से व प्रमाण-पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे. अन्य 5 अनुशं"त निबन्धों को आकर्षक प्रमाण-पत्र व उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य तक की वांछित पुस्तक पुरस्कारस्वरूप दी जाएगी.
3. प्रत्येक प्रविष्टि पर अपना नाम English के Capital Letter में लिखें जिस नाम से आपका बैंक खाता हो, बैंक का नाम, खाता नम्बर व बैंक का IFSC कोड नं. भी अवश्य लिखें.

वार्षिक सदस्यता शुल्क

प्रतियोगिता दर्पण

	हिन्दी	अंग्रेजी
एक प्रति मूल्य	125.00	125.00
वार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	1130·00	1125·00
रजिस्टर्ड डाक से	1350.00	1345·00
द्विवार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	2105·00	2100·00
रजिस्टर्ड डाक से	2545·00	2540·00

	सामान्य ज्ञान दर्पण	सक्सेस मिरर
एक प्रति मूल्य	₹ 45.00	25.00
वार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	₹ 405.00	225.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹ 620.00	440.00
द्विवार्षिक मूल्य :		
साधारण डाक से	₹ 755.00	420.00
रजिस्टर्ड डाक से	₹ 1185.00	850.00

वार्षिक सामूहिक सदस्यता शुल्क

प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) Pratiyogita Darpan (English)	₹ 2520/-
सामान्य ज्ञान दर्पण (हिन्दी) प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) Pratiyogita Darpan (English)	₹ 2950/-
सामान्य ज्ञान दर्पण (हिन्दी) प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी) सक्सेस मिरर (हिन्दी) Pratiyogita Darpan (English)	₹ 3200/-

QR कोड को स्कैन करें

अथवा ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारी वेबसाइट www.pdgroup.in पर विजिट करें

- कृपया अपना सदस्यता-शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही प्रेषित करें. चेक स्वीकार नहीं होंगे. आप हमारी Website: www.pdgroup.in द्वारा भी सदस्यता शुल्क अदा कर सकते हैं.
- अपने स्पष्ट पते के साथ यह भी सूचित करें कि आप किस माह से किस माह तक के लिए ग्राहक बन रहे हैं.
- पुराने ग्राहक कृपया अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें.
- मनीऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट '**प्रतियोगिता दर्पण**' के नाम से आगरा में देय ही स्वीकार किए जाएंगे.

प्रतियोगिता दर्पण

1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास **आगरा**—282 005
फोन : 2531101, 2530966
Website : www.pdgroup.in
E-mail : care@pdgroup.in

राष्ट्रीय घटनाक्रम

- **समान नागरिक संहिता विधेयक (2024) उत्तराखण्ड में पारित : सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल**
- **हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात् चंपई सोरेन झारखण्ड के नए मुख्यमंत्री**
- **चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया**
- **मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट-3 डीएस का सफल प्रक्षेपण**
- **5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट-2 को हिन्द महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता**
- **देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल**
- **गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए**
- **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए : पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि**

समान नागरिक संहिता विधेयक (2024) उत्तराखण्ड में पारित : सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल

फरवरी 2024 में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए एक विधेयक लाया गया. इस **समान नागरिक संहिता, विधेयक 2024** (Uttarakhand Uniform Civil Code Bill–2024) को विधान सभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विधेयक को 6 फरवरी, 2024 को विधान सभा में प्रस्तुत किया तथा 2 दिन तक चली बहस के पश्चात् सदन ने अगले ही दिन 7 फरवरी को ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया. 70 सदस्यी विधान सभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या ही 47 होने के कारण सदन में विधेयक पारित कराने में कोई कठिनाई सरकार को नहीं थी. विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव भी ध्वनिमत से ही सदन ने खारिज कर दिया. **समाज में भेदभाव व कुरीतियाँ समाप्त करने के लिए लाए गए इस विधेयक के अधिनियमित होने से सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता एवं विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान होगा. महिलाओं व पुरुषों के लिए समान अधिकारों का प्रावधान इसमें किया गया है. अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है.**

सहमति सम्बन्ध (Live in Relationship) को मान्यता प्रस्तावित अधिनियम में दी गई है, किन्तु इसके लिए कड़े प्रावधान विधेयक में किए गए हैं. 'लिव इन रिलेशनशिप' के लिए पंजीकरण अनिवार्य करते हुए एक माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहने पर जुर्माने एवं सजा का प्रावधान विधेयक में किया गया है. 'लिव इन रिलेशनशिप' में पैदा संतान को पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी भी विधेयक में बनाया गया है.

समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को विधान सभा में लाने से पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने एवं विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था. समिति द्वारा विधेयक का प्रारूप 2 फरवरी, 2024 को ही मुख्यमंत्री को सौंपा था जिस पर मंत्रिमण्डल के विचार के पश्चात् विधेयक विधान सभा में 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था. समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा आगे इसे राष्ट्रपति को सन्दर्भित किया गया है. राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् ही यह विधेयक अधिनियमित होगा. **अधिनियमित होने के पश्चात् उत्तराखण्ड स्वतंत्रता के पश्चात् देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा. वर्तमान में देश में गोवा में ही समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है, किन्तु यह पुर्तगाली शासन काल से ही वहाँ लागू है.**

हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात् चंपई सोरेन झारखण्ड के नए मुख्यमंत्री

रांची में कुछ महँगे भूखण्डों की सेल डीड में हेराफेरी कर अवैध तरीके से उनकी खरीद-बिक्री करने के मामले में कुछ अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारियों के

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते श्री चंपई सोरेन

पश्चात् प्रवर्तन न्यायालय ने अन्ततः झारखण्ड के मुख्यमंत्री रहे श्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी, 2024 को लम्बी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. **गिरफ्तारी से पूर्व ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को सौंप दिया था.** इसके साथ ही उनके विश्वसनीय श्री चंपई सोरेन ने नई सरकार के गठन के लिए 43 विधायकों के समर्थन का दावा भी राज्यपाल को प्रस्तुत कर दिया. (81 सदस्यीय विधान सभा में सरकार के गठन हेतु 42 विधायकों का समर्थन आवश्यक है.) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका में उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को महागठबंधन (झामुमो-कांग्रेस-राजद) विधायकों ने अपना नेता पहले ही चुन लिया था. हेमंत सोरेन वस्तुतः अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के इच्छुक थे, किन्तु उनके बड़े भाई की विधवा एवं विधायक के विरोध के चलते यह विचार उन्हें त्यागना पड़ा. झामुमो के कुछ विधायक भी कल्पना के पक्ष में नहीं थे.

महागठबंधन विधायक दल के नए नेता चंपई सोरेन को राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने 2 फरवरी, 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ रांची में ग्रहण कराई. कांग्रेस व राजद के एक-एक मंत्री को भी शपथ उनके साथ ग्रहण की. बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर 2000 में गठित इस राज्य के वह 12वें मुख्यमंत्री हैं. 5 फरवरी को विधान सभा के विशेष सत्र में 47-29 के मतांतर से बहुमत साबित कर दिया है. अपनी मंत्रिपरिषद् का विस्तार 16 फरवरी को उन्होंने किया हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी नई मंत्रिपरिषद् में शामिल किया गया है.

बिहार का विभाजन कर झारखण्ड राज्य का गठन नवम्बर 2000 में हुआ था. तब से अभी तक केवल रघुवर दास ने ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है. प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री के रूप में यह दूसरी पारी थी तथा दोनों बार ही वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.

अलग-अलग कार्यकालों को जोड़ कर देखा जाए, तो झारखण्ड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं. हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार झारखण्ड के मुख्यमंत्री रहे हैं, किन्तु उनका कुल कार्यकाल अर्जुन मुंडा से कम ही रहा है.

चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया

लोक सभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी, 2024 को रद्द कर किए चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम थे जिनके तहत् भारत का कोई भी नागरिक या कम्पनी स्टेट बैंक की चुनींदा शाखाओं से बॉण्ड खरीद कर अपनी पसन्द के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते थे. यह बाँड ₹ 1,000, ₹ 10,000, ₹ 1,00,000, ₹ 10,00,000, ₹ 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे तथा इन बॉण्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था. इन बॉण्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था, जिन्होंने लोक सभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1 प्रतिशत मत प्राप्त किए हों. चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाते हुए इनमें काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी.

योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर 5 या सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान **पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी, 2024 को सुनाया. पीठ के सर्वसम्मति वाले 2 अलग-अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है.** फैसले में कहा गया है कि इस योजना में सूचना के अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता दी गई है. चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखने के प्रावधान को मतदाता के सूचना के अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार वाले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन फैसले में बताया गया है. इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29सी(1), कम्पनी अधिनियम की धारा 182(3) व धारा 13ए(बी) का उल्लंघन भी न्यायालय के फैसले में बताया गया है. पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग से दिए अपने फैसले में उपर्युक्त फैसले से मेल खाते हुए फैसले के लिए कुछ अलग कारण बताए हैं.

चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए संविधान पीठ ने ऐसे बॉण्ड जारी करना तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश भारतीय स्टेट बैंक को दिए है. इसके साथ ही 12 अप्रैल, 2019 से अब तक योजना के तहत् खरीदे गए बॉण्ड, खरीदने वालों के नाम, राजनीतिक दलों की ओर से भुनाई गई राशि व भुगतान की तारीख का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने को पीठ ने कहा है. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि, जो बॉण्ड भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें बैंकों को वापस किया जाए. बैंक दानकर्ता के खाते में बॉण्ड की राशि लौटाएगा.

मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट-3 डीएस का सफल प्रक्षेपण

पीएसएलवी-सी 58 के जरिए एक्सपोसैट (EXPOSAT) के 1 जनवरी, 2024 को किए गए सफल प्रक्षेपण के पश्चात् वर्ष 2024 में अपने दूसरे मिशन के तहत् भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO/इसरो) ने तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह (Meteorological Satellite) इनसैट-3 डीएस (INSAT-3DS) का सफल प्रक्षेपण 17 फरवरी, 2024 को किया. पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम के सम्बन्ध में सटीक जानकारियों के लिए इन्सैट-3 डीएस का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट **जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च ह्वीकल (GSLV) एफ14** के जरिए किया गया. सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से 20 मिनट की उड़ान के पश्चात् जीएसएलवी-एफ14 द्वारा 2274 किग्रा के इनसैट-3 डीएस को पृथ्वी की अंडाकर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (Geo Synchronous Transfer Orbit–GTO) में स्थापित किया गया. जहाँ से चरणबद्ध तरीके से इसकी कक्षा को उठाते हुए 36,000 किमी की ऊँचाई पर स्थित वृत्ताकार जियो स्टेशनरी ऑर्बिट (GTO) में पहुँचाने का कार्य अगले कुछ दिन में पूरा कर लिया गया.

भू-स्थैतिक कक्षा (जियो स्टेशनरी ऑर्बिट) में इनसैट-3डीएस पहले से कार्यरत् इनसैट-3डी व इनसैट-3डीआर की मौसम सम्बन्धी सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाएगा. (इनसैट-3डी का प्रक्षेपण 26 जुलाई, 2013 को तथा इनसैट-3डीआर का 8 सितम्बर, 2016 को किया गया था). इनसैट-3डीएस का जीवन काल 10 वर्ष अनुमानित किया गया है.

इनसैट-3डीएस मिशन का वित्तीयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभाग [भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT), इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज व अन्य एजेंसियाँ] इस उपग्रह द्वारा भेजी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे.

इनसैट-3डीएस के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह उपग्रह मौसम सम्बन्धी सेवाओं में बदलाव लाएगा और मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाएगा.

*इनसैट-3डीएस के सफल प्रक्षेपण के पश्चात् इसरो का अगला मिशन नासा के सहयोग से **निसार** (NISAR–NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) उपग्रह का प्रक्षेपण है. निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला संयुक्त उपक्रम है. इस अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समझौते 2014 में हुआ था.*

5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट-2 को हिन्द महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता

अंतरिक्ष में जमा होते जा रहे निष्क्रिय उपग्रहों के कचरे को कम करने की दिशा में अपने प्रयास में इसरो (ISRO) को एक और

60. उदयमार्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
61. सतकोसिया गोर्ज (ओडिशा)
62. नंदा लेक (गोवा)
63. रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य (कर्नाटक)
64. सिरपुर वेटलैण्ड (मध्य प्रदेश)
65. तमपारा लेक (ओडिशा)
66. हीराकुड रिजर्वोयर (ओडिशा)
67. अनसूपा लेक (ओडिशा)
68. यशवंत सागर (मध्य प्रदेश)
69. चित्रणगुडी पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
70. सुचिंदम थरूर वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स (तमिलनाडु)
71. वादुवूर पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
72. कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
73. थाणे क्रीक (महाराष्ट्र)
74. हायगाम वेटलैण्ड कंजर्वेशन रिजर्व (जम्मू-कश्मीर)
75. शालबुध वेटलैण्ड कंजर्वेशन रिजर्व (जम्मू-कश्मीर)
76. कराइवेट्टी पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
77. लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन (तमिलनाडु)
78. अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व (कर्नाटक)
79. अघनाशिनी एस्चुएरी (कर्नाटक)
80. मगदी केरे संरक्षण रिजर्व (कर्नाटक)

गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किए

भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय

गगनयान की उड़ान के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ

सम्भावित है. इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किमी ऊँची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा. इस उड़ान के लिए वायु सेना के 4 पायलट्स का चयन भारतीय पायलटों के एक समूह से किया गया था तथा उड़ान के लिए विगत लगभग 3 वर्षों से कड़ा प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा था. इनमें रूस में गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में दी गई ट्रेनिंग भी शामिल है. **अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुने गए इन चारों पायलट्स के नामों का खुलासा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 फरवरी, 2024 को तिरुअनंतपुरम् के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र पर एक समारोह में किया. इनमें ग्रुप कैप्टेन प्रशांत बालकृष्णन् नायर, ग्रुप कैप्टेन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टेन अजीत कृष्णन तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं.**

इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स (Astronaut Wings) भी प्रधानमंत्री ने प्रदान किए. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (VSSC) की अपनी इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति का अवलोकन भी किया. कैप्सूल की तरह के इस क्रू मॉड्यूल में ही इन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष उड़ान के दौरान रहना है. धरती से लगभग 400 किमी ऊँची कक्षा में 3 दिन की उड़ान के पश्चात् इस मॉड्यूल को समुद्र में सुरक्षित उतारा जाएगा.

गगनयान मिशन के लिए चुने गए पायलट्स में ग्रुप कैप्टेन प्रशांत नायर मूलतः केरल के हैं. 1978 में जन्मे प्रशांत नायर 1998 में, चेन्नई में 1982 में जन्मे ग्रुप कैप्टेन अजीत कृष्णन 2003 में, प्रयागराज में 1982 में जन्मे ग्रुप कैप्टेन अंगद प्रताप 2004 में तथा लखनऊ में 1985 में जन्मे विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला 2006 में एनडीए के रास्ते वायु सेना में शामिल हुए थे. 40 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् किन्हीं भारतीयों की अंतरिक्ष की यह यात्रा होगी. 40 वर्ष पूर्व 1984 में भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी मिशन के तहत् सोयुज T-11 यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी, किन्तु इस बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की यह यात्रा भारतीय मिशन के तहत् भारत के ही यान में होनी है. ●●●

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम हटाए गए : पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि

वर्ष 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण अक्टूबर 2023 में किया गया था तथा 2022 के इन (70वें) पुरस्कारों की घोषणा अभी की जानी है. ***इन पुरस्कारों के तहत् दी जाने वाली पुरस्कार राशियों में कुछ वृद्धि सरकार ने जहाँ की है, वहीं कुछ पुरस्कारों के नामों में भी परिवर्तन किया गया है.*** *सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझावों के तहत् इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम पुरस्कारों से हटा लिए गए हैं. निम्नलिखित कुछ परिवर्तन इन पुरस्कारों के मामलों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, जो आगामी पुरस्कारों से ही लागू होंगे–*

- *इंदिरा गांधी के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' का बदलकर अब* ***किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म*** *(Best Debut Film of a Director) किया गया है. इस पुरस्कार के तहत् दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹ 3 लाख किया गया है.*
- *राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 'नरगिस दत्त पुरस्कार' को अब 'सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म' तथा पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के साथ मिलाते हुए तीनों के स्थान पर एक* ***राष्ट्रीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म*** *(Best Feature Film Promoting National, Social and Environmental Values) नाम दिया गया है.*
- *सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कारों के नाम बदलकर* ***मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री*** *के पुरस्कार जहाँ किया गया है वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व सहायक अभिनेत्री पुरस्कारों का नाम अब* ***'सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री'*** *किया गया है.*
- *समिति की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत् दी जाने वाली पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि की गई है.* ***सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत् दी जाने वाली पुरस्कार राशि को ₹ 10 लाख से बढ़ाकर ₹ 15 लाख जहाँ किया गया है.*** *फिल्मों के मामले में स्वर्ण कमल के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि को ₹ 2 लाख से बढ़ाकर ₹ 3 लाख किया गया है तथा रजत कमल के साथ दी जाने वाली राशि को ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 2 लाख किया गया है. (स्वर्ण कमल सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, किसी निर्देशक की पहली फिल्म, भरपूर मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए जहाँ दिया जाता है, वहीं रजत कमल राष्ट्रीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सभी अभिनव श्रेणियों, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, संगीत व ऐसी ही अन्य श्रेणियों के विजेताओं को दिया जाता है.)*

कामयाबी फरवरी 2024 में उस समय मिली जब 6·35 किमी ऊपर सूर्य तुल्य कालिक कक्षा (Sun-Synchronous polar orbit) में विगत 5 वर्षों से निष्क्रिय पड़े. उपग्रह कार्टोसैट-2 को उसने धरती पर वापस लाकर उसके जले हुए कचरे को हिन्द महासागर में गिरा दिया. हाई रिजॉल्यूशन इमेजिंग उपग्रह कार्टोसैट-2 का प्रक्षेपण 17 वर्ष पूर्व 10 जनवरी, 2007 को किया गया था तथा 2019 तक हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें इसने उपलब्ध कराईं जिसके बाद विगत 5 वर्षों से यह अपनी कक्षा में निष्क्रिय पड़ा था. सामान्यत 30 वर्ष का समय इसके डिऑर्बिटिंग में लगता, किन्तु इसके बचे हुए ईंधन का उपयोग करके इसकी कक्षा को घटाते हुए वापस वातावरण में प्रवेश इसरो ने कराया जहाँ जलकर 14 फरवरी, 2024 को यह हिन्द महासागर में जा गिरा.

अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (United Nations Committee on the Peaceful Uses of outer space) व इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee) आदि की सिफारिशों के अनुरूप अंतरिक्ष के कचरे से उपग्रहों के टकराने के जोखिमों को कम करने की नीति के तहत् कार्टोसैट-2 का सुरक्षित निपटान इसरो द्वारा किया गया है.

यह पहला अवसर नहीं है जब निष्क्रिय हो चुके किसी उपग्रह को धरती पर लाकर वापस नष्ट इसरो द्वारा किया है. ऐसे अपने निष्क्रिय उपग्रहों को पहले भी उनकी कक्षा से निकाल कर इसरो द्वारा नष्ट किया जा चुका है. पिछले ही वर्ष ऐसे ही एक उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) को, जो 10 वर्ष तक सेवाएं देने के पश्चात् पृथ्वी की निचली कक्षा में निष्क्रिय पड़ा था, धीरे-धीरे उतार कर प्रशांत महासागर में 7 मार्च, 2023 को गिराने में सफलता इसरो ने प्राप्त की थी.

देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल

देश में 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों (Wetlands) को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है. इस आशय के प्रमाण-पत्र रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉ. मुसौदा मुंबा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड्स डे से 2 दिन पूर्व 31 जनवरी, 2024 को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव को नई दिल्ली में सौंपे गए. रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए नए भारतीय वेटलैण्ड्स में से 2 कराइवेट्टी पक्षी अभयारण्य (Karaivetti Bird Sanctuary) व लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन (Longwood Shola Reserve Forest) तमिलनाडु में तथा 3 अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व (Ankasamudri Bird Conservation Reserve), अघनाशिनी एस्चुएरी (Aghanashini Estuary) और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व (Magadi Kere Conservation Reserve) कर्नाटक में है. इन्हें मिलाकर रामसर स्थलों में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या अब 80 हो गई है. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 तक देश के 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र ही रामसर स्थलों की सूची में शामिल थे तथा विगत 10 वर्षों में ही यह संख्या बढ़कर 80 हो गई है. अकेले 2022 में देश के 28 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था.

वेटलैण्ड्स के महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुए थे, उसके तहत् की अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई है. इन्हें रामसर साइट्स (Ramsar Sites) कहा जाता है. भारत 1982 में ही रामसर सन्धि में शामिल हुआ था तथा भारत के 80 आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है. इनका कुल क्षेत्रफल 13·3 मिलियन हेक्टेयर हो गया है.

वर्तमान में देश के 80 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 16 तमिलनाडु में व 10 उत्तर प्रदेश में हैं. ओडिशा व पंजाब के 6-6 आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हैं. इनकी पूरी सूची निम्नलिखित है–

भारत के सभी 80 रामसर स्थलों की सूची (फरवरी 2024 की स्थिति)

1. अष्टमुडी वेटलैंड (केरल)
2. ब्यास संरक्षण रिजर्व (पंजाब)
3. भितरकनिका मैंग्रोव (ओडिशा)
4. भोज वेटलैंड्स (मध्य प्रदेश)
5. चन्द्रताल (हिमाचल प्रदेश)
6. चिल्का झील (ओडिशा)
7. डीपोर बील (असम)
8. पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स (पश्चिम बंगाल)
9. हरिके वेटलैंड्स (पंजाब)
10. होकेरा वेटलैंड (जम्मू-कश्मीर)
11. कांजली वेटलैंड (पंजाब)
12. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)
13. केशोपुर-मियानी कम्युनिटी रिजर्व (पंजाब)
14. कोल्लेरू झील (आंध्र प्रदेश)
15. लोकटक झील (मणिपुर)
16. नालसरोवर पक्षी अभयारण्य (गुजरात)
17. नंदुर मदमहेश्वर (महाराष्ट्र)
18. नंगल वन्यजीव अभयारण्य (पंजाब)
19. नवाबगंज पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
20. पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
21. प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
22. पौंग बाँध झील (हिमाचल प्रदेश)
23. रेणुका झील (हिमाचल प्रदेश)
24. रोपड़ वेटलैंड (पंजाब)
25. रुद्रसागर झील (त्रिपुरा)
26. समन पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
27. सांभर झील (राजस्थान)
28. सैंडी पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
29. सरसई नवर झील (उत्तर प्रदेश)
30. सस्तमकोट्टा झील (केरल)
31. सुरिनसर-मानसर झीलें (जम्मू-कश्मीर)
32. त्सोमोरिरी (लद्दाख)
33. ऊपरी गंगा नदी (उत्तर प्रदेश)
34. वेम्बनाड कोल वेटलैंड (केरल)
35. वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)
36. सुन्दरबन वेटलैंड (पश्चिम बंगाल)
37. आसन बैराज (उत्तराखण्ड)
38. कंवर झील या कबर ताल (बिहार)
39. लोनार झील (महाराष्ट्र)
40. समसपुर पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
41. सूर सरोवर (उत्तर प्रदेश)
42. त्सो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स (लद्दाख)
43. थोल झील (गुजरात)
44. वाधवाना (गुजरात)
45. सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (हरियाणा)
46. भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य (हरियाणा)
47. रिवजादिया वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात)
48. परनीरा वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)
49. हैदरपुर वेटलैण्ड्स (उत्तर प्रदेश)
50. किरिकिली पक्षी अभयारण्य (गुजरात)
51. पल्लीकर्नई मार्श रिजर्व फोरेस्ट (गुजरात)
52. पिचवरम मैंग्रोव (गुजरात)
53. पाला आर्द्रभूमि (मिजोरम)
54. साख्यसागर (मध्य प्रदेश)
55. कूंथनकुलम पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
56. गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व (तमिलनाडु)
57. वेम्बानूर वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स (तमिलनाडु)
58. वेल्लोड पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)
59. वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात व कतर की यात्रा
- भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वाँ स्थान : ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट
- अमरीका की निजी कम्पनी का मून लैंडर ओडीसियस चन्द्रमा की सतह पर उतरा
- हेलेनिक रिपब्लिक (ग्रीस) के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा
- अल सेल्वाडोर में नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कतर यात्रा से तीन दिन पूर्व ही कतर ने मृत्यु दण्ड पाए आठ भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा किए
- पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वाँ दौर
- हिन्द महासागर सम्मेलन (2024) आस्ट्रेलिया में पर्थ में सम्पन्न
- इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक (2023) में भारत का विश्व में 41वाँ स्थान
- अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम
- मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण
- नौवाँ रायसीना संवाद नई दिल्ली में सम्पन्न

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात व कतर की यात्रा

देश के उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 दिन की संयुक्त

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा 13-14 फरवरी को की जिसके पश्चात् 14-15 फरवरी को कतर (Qatar) की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की. वर्ष 2015 के पश्चात् श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह 7वीं यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते एवं गहरे द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रतीक है. **प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की पिछली यात्रा 1 दिसम्बर, 2023 को COP-28 में भागीदारी के सिलसिले में सम्पन्न की थी, जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायर अल नाहयान (Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Naryan) वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9-10 जनवरी, 2024 को ही भारत आए थे.**

13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात पहुँच पर आबू धाबी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगवानी स्वयं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की तथा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं के बीच विगत 7 माह में यह छठी मुलाकात थी.

मेजबान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट (World Government Summit) 2024 में भागीदारी, आबू धाबी में विशाल हिन्दू मन्दिर का उद्घाटन व भारतीय मूल के लोगों को सम्बोधन का एक कार्यक्रम यूएई में दो दिन के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य कार्यक्रम थे.

मेजबान राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) श्री अजीत डोभाल, विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी जहाँ इस वार्ता में शामिल थे वहीं यूएई की ओर से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद की कैबिनेट के सभी उच्चस्तरीय मंत्री इसमें शामिल रहे. वार्तालाप के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौतों पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुए जिनमें दो समझौते यूएई में भारतीय रूपे कार्ड व यूपीआई को स्वीकार किए जाने के लिए है. इनके बदले में यूएई के डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म आनी (AANI) व जयवान (JAYWAN) को भारत में स्वीकार किया जाएगा. भारत में आधारित संरचना क्षेत्र में यूएई के पेंशन फंड से बड़ी मात्रा में निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए द्विपक्षीय निवेश समझौतों (Bilateral Investment Treaty–BIT) भी सम्पन्न किया गया.

दुबई में 14 फरवरी को सम्पन्न वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिति में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को सम्मानित अतिथि (Guest of Honour) के तौर पर मेजबान उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum) ने आमंत्रित किया था. **यह सम्मेलन प्रति वर्ष दुबई में आयोजित होता है, जो सरकारों को भविष्य की चुनौतियों व इनके लिए अनुभव साझा करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इससे पूर्व 2018 में भी ऐसे सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था. इस वर्ष के विश्व सरकार सम्मेलन का थीम 'भविष्य की सरकारों को आकार देना' (Shaping the Future Governments) तथा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों में 10 राष्ट्रपति व 10 प्रधानमंत्री शामिल थे.**

संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिन्दू मंदिर का उद्घाटन श्री मोदी का यूएई की इस यात्रा में एक अन्य बड़ा कार्यक्रम था. पश्चिम

बीएपीएस हिन्दू मंदिर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य

एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण (BAPs), संस्था जिसने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर सहित विश्व के अनेक देशों में मंदिर बनवाए हैं, द्वारा कराया गया है. दुबई-आबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अबू मरेखह (Abu Mreikhah) शहर में 27 एकड़ भूमि पर ₹ 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में बने इस मंदिर का उद्घाटन श्री मोदी ने 14 फरवरी में मंत्रोच्चार के बीच किया.

यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान व विभिन्न पंथों के आध्यात्मिक गुरुओं के अतिरिक्त भारत के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, उद्यमी व बॉलीवुड स्टार आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे.

भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहराते रिश्तों का ही यह परिणाम है कि यूएई अब भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा 7वाँ बड़ा निवेशक भी अब हो गया है. यूएई में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों की संख्या लगभग 35 लाख है, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 35 प्रतिशत है. भारतीय मूल के लगभग 1·5 लाख से अधिक छात्र यूएई के स्कूलों में पढ़ते हैं तथा शीघ्र ही भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का एक कार्यालय दुबई में खोला जाएगा. भारत के आईआईटी दिल्ली का एक परिसर हाल ही में आबूधाबी में स्थापित किया गया है. प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगस्त 2019 की यूएई यात्रा के दौरान उन्हें इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायेद' से सम्मानित किया गया था.

आबू धाबी में श्री मोदी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम वहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयोजित किया गया था. इसे अहलान मोदी (हैलो मोदी) नाम दिया गया था. भारतीय मूल के लगभग 40 हजार लोगों ने इस कार्यक्रम में श्री मोदी का स्वागत किया. इस कार्यक्रम में जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत व यूएई के सम्बन्धों की भरपूर प्रशंसा की और कहा कि भारत व यूएई मिलकर 21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं. वहाँ रह रहे भारतीयों को इस नए इतिहास का एक बड़ा आधार उन्होंने बताया.

संयुक्त अरब अमीरात की दो दिन की इस ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात् 14 फरवरी की शाम को ही श्री मोदी कतर (Qatar) की राजधानी दोहा पहुँचे जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ. प्रधानमंत्री के रूप में कतर की उनकी यह दूसरी यात्रा थी. इससे पूर्व जून 2016 में कतर की यात्रा उन्होंने की थी. कतर की उनकी यह यात्रा कतर द्वारा 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के 3 दिन बाद ही सम्पन्न हुई. कतर में दोहा हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी विदेश राज्य मंत्री ने की. कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी (Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani) के साथ वार्ता का श्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम था. 15 फरवरी को सम्पन्न इस वार्ता में श्री मोदी ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा कर स्वदेश भेजने के लिए कतर के अमीर के प्रति शुक्रिया कहा (कतर के अमीर के साथ श्री मोदी की यह मुलाकात पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के तीन दिन बाद ही हुई थी.) अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, अंतरिक्ष, शहरी आधारिक संरचना एवं आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्धों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई. ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के सम्बन्ध महज क्रेता-विक्रेता से ऊपर उठकर नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहमति दोनों पक्षों में हुई. वार्ता के पश्चात् श्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज की मेजबानी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने की. दोहा में रह रहे भारतीय मूल के प्रवासियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का भारी स्वागत तिरंगे के साथ किया. बाद में उसी शाम को उनकी स्वदेश वापसी हुई.

भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त

भारत एवं म्यांमार की सीमा पर वर्ष 2018 से लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime–FMR) को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दी है. 2018 से लागू इस व्यवस्था के तहत् सीमा के निकट रहने वाले लोगों को सीमा पार कर दूसरे देश में 16 किमी की दूरी तक आवाजाही की सुविधा दी गई थी. सीमा पर हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए पूरी 1643 किमी लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा 6 फरवरी को गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी. इसके पश्चात् ही सीमा पर मुक्त आवाजाही की सुविधा बन्द करने की संस्तुति गृह मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय से की गई. गृह मंत्रालय की इस आशय की सिफारिश के बाद भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही की सुविधा को सरकार ने बन्द कर दिया है.

भारत व म्यांमार के बीच पूरी 1643 किमी सीमा पर बाड़ लगाने के साथ-साथ सीमा पर बेहतर निगरानी के लिए एक पेट्रोलिंग ट्रैक बनाने की घोषणा भी गृह मंत्री ने की है. कुल सीमा में से मणिपुर के मोरेह में 10 किमी के हिस्से में बाड़ लगाई भी जा चुकी है.

ज्ञातव्य है कि मिजोरम, मणिपुर, नगालैण्ड व अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1643 किमी लम्बी भारत-म्यांमार सीमा एफएमआर के तहत् संचालित होती है. सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत् यह व्यवस्था 2018 में लागू की गई थी. यह व्यवस्था भारत-म्यांमार सीमा के निकट रहने वाले लोगों को वीजा के बिना ही एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक आवागमन की अनुमति प्रदान करती थी. सीमा पर रहने वाले लोगों को क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए इसके लिए समझौता दोनों देशों ने सम्पन्न किया था. इस सुविधा के दुरुपयोग को देखते हुए एफएमआर को बन्द करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय अब गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है. इंफाल क्षेत्र के मैतई समूहों की यह माँग रही है कि खुली सीमा के माध्यम से आदिवासी भारत में प्रवेश करते हैं. खुली सीमा का लाभ उठा कर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लग रहे हैं.

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में 93वाँ स्थान : ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट

विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन **भ्रष्टाचार बोध सूचकांक** (Corruption Perception Index–CPI) के आधार पर जर्मनी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है. 13 विभिन्न मानकों के आधार पर विभिन्न देशों के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की गणना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा की जाती है. सूचकांक का मान 0–100 के बीच रहता है. **किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है. सम्बन्धित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक माना जाता है. सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है.** जर्मनी की गैर-सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों/क्षेत्रों के लिए यह सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते रहे हैं, जिनमें रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देश से अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की ओर होता है. **इस प्रकार सर्वोच्च सूचकांक वाले देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान की जाती है, जो न्यूनतम भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि सबसे कम सूचकांक वाला देश अर्थात् सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाला देश सबसे नीचे दर्शाया जाता है.**

विभिन्न राष्ट्रों के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल के वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई है. 31 जनवरी, 2024 को जारी इस रिपोर्ट में

180 देशों/क्षेत्रों के लिए यह सूचकांक आकलित है तथा उनके आधार पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इन राष्ट्रों की रैंक निर्धारित की गई है. इसमें अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है. भारत के लिए 2022 के लिए इस सूचकांक में स्कोर 40 था तथा 180 देशों में 85वाँ स्थान था. ताजा 2023 की रिपोर्ट **(जो जनवरी 2024 में जारी हुई), में भारत के लिए सूचकांक स्कोर 39 है तथा 180 देशों में भारत का स्थान 93वाँ है, जो देश में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है.**

सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश

रैंक	देश	भ्रष्टाचार बोध सूचकांक स्कोर
1	डेनमार्क	90
2	फिनलैण्ड	87
3	न्यूजीलैण्ड	85
4	नॉर्वे	84
5	सिंगापुर	83
6	स्वीडन	82
6	स्विट्जरलैण्ड	82
8	नीदरलैण्ड्स	79
9	जर्मनी	78
9	लक्जेमबर्ग	78
11	आयरलैण्ड	77

सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश

172	निकरागुआ	17
172	ईक्वेटोरियल गुनिया	17
172	हैती	17
172	उत्तर कोरिया	17
176	यमन	16
177	वेनेजुएला	13
177	दक्षिण सूडान	13
177	सीरिया	13
180	सोमालिया	11

भारत व पड़ोसी देशों की रैंक

26	भूटान	68
76	चीन	42
93	भारत	39
108	नेपाल	35
115	श्रीलंका	34
133	पाकिस्तान	29
149	बांग्लादेश	24
162	अफगानिस्तान	20
162	म्यांमार	20

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट में सर्वोच्च पहला स्थान 90 सूचकांक के साथ डेन्मार्क का है. वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम माना गया है. उसके पश्चात् फिनलैण्ड दूसरे व न्यूजीलैण्ड तीसरे स्थान पर है. इनके लिए यह सूचकांक क्रमशः 87 व 85 आकलित है. 2022 की 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट में फिनलैण्ड व न्यूजीलैण्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे. नॉर्वे पिछले वर्ष भी चौथे स्थान पर था. इस वर्ष भी 84 सूचकांक के साथ उसका चौथा स्थान है. इनके पश्चात् 83 सूचकांक के साथ सिंगापुर पाँचवें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैण्ड व स्वीडन संयुक्त रूप से छठे स्थान पर हैं. आठवाँ स्थान नीदरलैण्ड्स का है. पहले 10 स्थानों पर रहे इन राष्ट्रों के नाम तालिका में दर्शाए गए हैं. अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन व अमरीका का क्रमशः 20वाँ व 24वाँ द. कोरिया का 32वाँ, मॉरिशस का 35वाँ, सऊदी अरब का 53वाँ तथा चीन का 76वाँ स्थान इस वर्ष की रैंकिंग में है.

इस वर्ष भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल की इस सूची में सबसे नीचा (180वाँ) स्थान दक्षिणी सोमालिया का है. इस प्रकार इसे सर्वाधिक भ्रष्ट देश रिपोर्ट में बताया गया है. सोमालिया पिछले वर्ष इस सूची में सबसे निचले स्थान पर था. 13 सूचकांक के साथ सीरिया, वेनेजुएला व द. सूडान संयुक्त रूप से नीचे से दूसरे स्थान पर हैं तथा 16 सूचकांक के साथ यमन इस सूची में नीचे से पाँचवें 176वें स्थान पर है.

भारत के पड़ोसी देशों में 26वें व 76वें स्थान के साथ क्रमशः भूटान व चीन भारत से बेहतर स्थिति में हैं, चीन पिछले वर्ष 65वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 76वें स्थान पर है. वहाँ भी भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि को यह दर्शाता है. अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश में स्थिति भारत से खराब है. श्रीलंका का इस सूची में जहाँ 115वाँ स्थान है, नेपाल 108वें, पाकिस्तान 133वें, बांग्लादेश 149वें, अफगानिस्तान व म्यांमार संयुक्त रूप से 162वें स्थान पर हैं. इस प्रकार इन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर भारत से भी अधिक आकलित किया गया है.

अमरीका की निजी कम्पनी का मून लैंडर ओडीसियस चन्द्रमा की सतह पर उतरा

चन्द्रमा की सतह पर जापान के **मून लैंडर** SLIM (मून स्नाइपर) की 19 जनवरी, 2024 को हुई सॉफ्ट लैंडिंग के पश्चात् इस दिशा में एक और सफलता अमरीका की एक निजी कम्पनी इंटुएटिव मशींस (Intuitive Machines) को फरवरी 2024 में मिली जब कम्पनी द्वारा भेजे गए छह पैरों वाले रोबोट लैंडर **ओडीसियस** (Odysseus) ने ईस्टर्न टाइम के अनुसार 22 फरवरी को सायं तथा भारतीय समयानुसार 23 फरवरी को प्रातः 4 : 30 बजे चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालापर्ट ए (Malapart A) नाम के क्रेटर में उतरने में सफलता प्राप्त की. अमरीका की निजी कम्पनी इंटुएटिव मशींस द्वारा ओडीसियस का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन-9 रॉकेट के जरिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी, 2024 को किया गया था. केवल एक सप्ताह की यात्रा के पश्चात् इसकी सफल लैंडिंग चन्द्रमा की सतह पर हुई. **इसके साथ ही इंटुएटिव मशींस चन्द्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कम्पनी हो गई है.** इससे पूर्व यह उपलब्धि अमरीका, रूस, चीन, भारत व जापान की सरकारी एजेंसियों को ही प्राप्त थी. **भारत के चन्द्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त, 2023 को चन्द्रमा दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जबकि जापान के मून लैंडर SLIM (मून स्नाइपर) ने यह उपलब्धि 19 जनवरी, 2024 को ही प्राप्त की थी.** 1972 में अपोलो-17 मिशन के 5 दशक पश्चात् अमरीका का कोई अंतरिक्ष यान चन्द्रमा की सतह पर उतरा है.

चन्द्रमा की सतह से डाटा जुटाने के लिए केवल एक सप्ताह का ही समय ओडीसियस लैंडर के पास था, क्योंकि इसकी लैंडिंग के 7 दिन पश्चात् ही वहाँ रात हो गई थी. चन्द्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है तथा रात में वहाँ तापमान – 100 डिग्री से भी कम हो जाने तथा सौर ऊर्जा न मिलने के कारण रोवर कार्यशील नहीं रहेगा.

चन्द्रमा की सतह पर लैंडर उतारने का ओडीसियस मिशन यद्यपि एक निजी कम्पनी का था, अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' का सहयोग समर्थन इसे प्राप्त था. चन्द्रमा से डाटा एकत्र करने के लिए नासा ने कुछ उपकरण व पेलोड ओडीसियस के साथ भेजे थे. इनके लिए 118 मिलियन डॉलर का वित्तीयन भी नासा द्वारा किया गया था.

ज्ञातव्य है कि ओडीसियस की सफल लैंडिंग से कुछ ही दिन पूर्व एक अन्य अमरीकी कम्पनी का पेरेग्रिन लैंडर अपने मिशन में नाकामयाब रहा था.

हेलेनिक रिपब्लिक (ग्रीस) के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा

यूरोपीय देश ग्रीस (Greece), जिसका औपचारिक नाम **हेलेनिक रिपब्लिक**

नई दिल्ली में हेलेनिक रिपब्लिक (ग्रीस) के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

(Hellenic Repuplic) है तथा जिसे आमतौर पर यूनान से जाना जाता है, के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस (Kyriakos Mitsotakis) ने 21-22 फरवरी, 2024 को भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा की. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर सम्पन्न इस यात्रा पर उनके साथ आए शिष्टमण्डल में उनकी पत्नी मारेवा ग्रैबोत्स्की मित्सोताकिस के अतिरिक्त ग्रीस के वरिष्ठ अधिकारियों व उच्च स्तरीय उद्यमियों का शिष्टमण्डल भी शामिल था. नई दिल्ली में फरवरी 2024 में सम्पन्न नौवें **रायसीना संवाद** (Raisina Dialogue) में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वह आमंत्रित थे.

15 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् ग्रीस के किसी राष्ट्र/सरकार प्रमुख की भारत की यह यात्रा थी. वर्ष 2008 में ग्रीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, जबकि भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2023 में ही ग्रीस की यात्रा की थी. उनकी उस यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के सम्बन्धों ने सामरिक सम्बन्धों का रूप ले लिया था.

अपनी इस पहली ही भारत यात्रा के लिए ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस 20 फरवरी को नई दिल्ली पहुँच गए थे जहाँ हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उसी दिन उनसे भेंट कर भारत व ग्रीस के आपसी सहयोग में वृद्धि के लिए चर्चा की. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 फरवरी को किया. नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी मेहमान प्रधानमंत्री ने अर्पित की. उसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण वार्ता हैदराबाद हाउस में सम्पन्न हुई.

द्विपक्षीय वार्ता में क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा दोनों पक्षों में हुई. आतंकवाद के मामले में भारत व ग्रीस की चुनौतियाँ एक जैसी हैं. इस मामले में सहयोग पर चर्चा वार्ता में हुई. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक दो गुना करने का लक्ष्य दोनों प्रधानमंत्रियों की अगस्त 2023 की बैठक में निर्धारित किया गया था, इस दिशा में प्रगति की समीक्षा वार्ता में की गई. दोनों देशों के बीच कारोबार एवं कामगारों के सुगम आवागमन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित **मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौते** (Mobility and Migration Partnership Agreement–MMPA) को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करने की दिशा में भी बातचीत दोनों पक्षों में हुई. भारत व यूरोप के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आदि के विस्तार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रस्तावित **भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर** (India-Middle East-Europe Economic Corridor–IMEEC) पर चर्चा भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने की. स्वतंत्र, खुली एवं नियम आधारित समुद्री सुरक्षा एवं शांति के लिए UNCLOS (United Nations Convention on the Law of Seas) के प्रति प्रतिबद्धता दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यक्त की. अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में रही. ग्रीस की 2025-26 के लिए सुरक्षा परिषद् की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन के लिए मोदी ने वार्ता में जहाँ दोहराया वही भारत की 2028-29 के लिए सदस्यता के प्रति ग्रीस ने समर्थन की पुष्टि मेहमान प्रधानमंत्री ने की. भारत के नेतृत्व वाले अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के लिए ग्रीस के समर्थन के प्रति हर्ष भारत की ओर से व्यक्त किया गया.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पिछले वर्ष अगस्त 2023 में 40 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् ग्रीस जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री जहाँ बने थे वहीं मित्सो ताकिस 15 वर्षों के पश्चात् भारत की यात्रा पर आने वाले ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं. हाल ही के समय में भारत व ग्रीस के बीच तेजी से बढ़ते हुए सम्बन्धों के पीछे तुर्किये को भी एक बड़ा कारण राजनयिक क्षेत्रों में माना जा रहा है. सीमावर्ती तुर्किये के साथ ग्रीस के सम्बन्ध जहाँ खराब हैं वहीं भारत व तुर्किये के आपसी रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं. दोनों ही देशों के तुर्किये के साथ खराब सम्बन्धों के बीच भारत व ग्रीस ने अपने द्वितीय सम्बन्धों को सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) तक ले जाने का निर्णय अगस्त 2023 में श्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान किया गया था. इस यात्रा के दौरान श्री मोदी को ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से भी सम्मानित किया गया था.

21 फरवरी को ही नई दिल्ली में नौवें रायसीन संवाद (Raisina Dialogue) का शुभारम्भ ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मिलकर किया. वैश्विक चिंतन के इस कूटनीतिक विमर्श में मुख्य वक्ता के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री आमंत्रित थे. इनके उद्घाटन सत्र को सम्बोधित ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक मंच की एक महान् शक्ति के रूप में चिह्नित किया और कहा कि भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना यूरोप की विशेष नीति का आधार होना चाहिए.

अल सेल्वाडोर में नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु राष्ट्रपति निर्वाचित

मध्य अमरीका देश अल सल्वाडोर (El Salvador) में राष्ट्रपति नायब बुकेले (Nayib Bukele) लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति फरवरी 2024 में निर्वाचित हुए हैं. 42 वर्षीय बुकेले ने 85 प्रतिशत मत इस चुनाव में प्राप्त किए हैं. 2019 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभालने से पूर्व राजधानी सान सल्वाडोर के मेयर वह रहे थे. 2019 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभालने के बाद देश में हावी गैंगस्टरों व माफियाओं पर सख्त शिकंजा उन्होंने कसा था जिससे वहाँ हत्याओं की दर ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर आ गई थी. इसके लिए डिक्टेटर के रूप में कार्य उन्होंने किए, किन्तु जनता में इससे लोकप्रियता उन्हें प्राप्त हुई. इस प्रकार कूल डिक्टेटर के रूप में ख्याति प्राप्त बुकेले को ही सफलता इस चुनाव में प्राप्त हुई है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में सख्त रवैया अपनाने के कारण ही अल सेल्वेडोर, जो विश्व के सर्वाधिक हिंसा ग्रस्त देशों में गिना जाता था, सर्वाधिक सुरक्षित देशों में रूपांतरित हो गया था. इसलिए ही दुनिया ने सबसे अच्छे तानाशाह के रूप में उनकी गणना होती थी.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व ही कतर ने मृत्यु दण्ड पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा किए

भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता फरवरी 2024 में उस समय परिलक्षित हुई जब कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को 11 फरवरी, 2024 को रिहा कर दिया, जिन्हें जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा वहाँ अक्टूबर 2023 में सुनाई गई थी. इनकी रिहाई प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व ही कर दी गई.

अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करने वाले इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को भ्रष्टाचार और जासूसी के एक मामले में कथित रूप से शामिल रहने के लिए अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था तथा कतर की एक अदालत ने इन 8 को उपर्युक्त सजा 26 अक्टूबर को सुनाई थी. उनकी गिरफ्तारी एवं मुकदमे का कोई खुलासा कतर प्रशासन द्वारा न किए जाने के कारण भारत सरकार ने इस फैसले को चौकाने वाला बताते हुए गम्भीरता से लिया था तथा कतर के साथ बातचीत करके उन्हें कानूनी मदद उपलब्ध कराई. भारतीय नौसैनिक की सकुशल रिहाई के लिए प्रयास विदेश मंत्रालय द्वारा किए जा रहे थे.

समझा जाता है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी की कतर के अमीर से दुबई में कॉप-28 के अवसर पर हुई बातचीत के पश्चात् इन 8 की मौत की सजा को कम कर उम्र कैद में बदल दिया गया था. भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों ने अन्ततः इनकी रिहाई के लिए मार्ग

प्रशस्त किया तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी की कतर यात्रा के 3 दिन पहले ही 11 फरवरी, 2024 को इन्हें रिहा करते हुए भारत के लिए इन्हें रवाना कर दिया गया जिससे 12 फरवरी को प्रातः यह नई दिल्ली पहुँचे. रिहा किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों में—कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं—इनमें से सात 12 फरवरी को नई दिल्ली पहुँच गए थे.

कतर की यात्रा पर 14 फरवरी को दोहा पहुँचे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इनकी सकुशल रिहाई के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद भी दिया.

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वाँ दौर

भारत व चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control–LAC) पर जून 2020 में हुए सैन्य टकराव के पश्चात् उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता (Corps Commander Level Talks) का 21वाँ दौर सीमा पर ही चुशुल मोल्दो (Chushul Moldo) बैठक बिन्दु पर 19 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. बैठक के पश्चात् सीमा क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए आवश्यक आधार के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे शेष क्षेत्रों में सेनाओं को पूरी तरह पीछे हटाने की माँग पिछले दौर की वार्ता में रखी गई थी. इस पर अपने-अपने दृष्टिकोण इस दौर में भी दोनों पक्षों ने साझा किए किन्तु कोई ठोस प्रगति वार्ता में नहीं हुई. विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न इस वार्ता में उपयुक्त सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए संवाद बनाए रखने पर सहमति जहाँ रही वहीं साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने को भी प्रतिबद्धता दोनों पक्षों ने व्यक्त की.

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की समाप्ति के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की पिछली 20वें दौर की वार्ता चुशुल मोल्दो बिन्दु पर ही 9-10 अक्टूबर, 2023 को सम्पन्न हुई थी.

हिन्द महासागर सम्मेलन (2024) आस्ट्रेलिया में पर्थ में सम्पन्न

भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वाँ हिन्द महासागर सम्मेलन (Indian Ocean Conference) आस्ट्रेलिया में पर्थ में 9-10 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. हिन्द महासागर के देशों की सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी व 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मुख्य वक्ता थे. सम्मेलन को सम्बोधित करने वालों में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग व सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन भी शामिल थे.

'स्थायी और सतत् हिन्द महासागर की ओर' (Towards a Stable and Sustainable Indian Ocean) सातवें हिन्द महासागर सम्मेलन का थीम था. इसी परिप्रेक्ष्य में उन मुद्दों पर चर्चा सम्मेलन में की गई, जो हिन्द महासागर में शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं.

हिन्द महासागर सम्मेलन एवं परामर्शी मंच है, जो हिन्द महासागर के देशों के साथ लाने के लिए कार्य करता है. इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करना है. इस सम्मेलन का आयोजन 2016 में शुरू हुआ था तथा ऐसा पहला सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में हुआ था. ऐसा पिछला छठा सम्मेलन 2023 में बांग्लादेश में ढाका में सम्पन्न हुआ था, जबकि उससे पूर्व पाँचवाँ सम्मेलन 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में हुआ था.

इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक (2023) में भारत का विश्व में 41वाँ स्थान

विभिन्न देशों में शासन में लोकतंत्र की स्थिति के आकलन हेतु लोकतंत्र सूचकांक की गणना ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट (EIU) द्वारा 2006 से की जाती रही है. वर्ष 2023 के लिए ऐसी सूचकांक रिपोर्ट 15 फरवरी, 2024 को जारी की गई, जिसमें 167 देशों व क्षेत्रों के लिए लोकतंत्र सूचकांक आकलित किए गए हैं. छोटे-मोटे सूक्ष्म देश की इस अध्ययन क्षेत्र के बाहर हैं, जिससे यह माना गया है कि विश्व की लगभग समस्त जनसंख्या इस अध्ययन के दायरे में है.

0–10 मान वाला यह सूचकांक विश्व के इन देशों में लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत करके करता है, जिन देशों के लिए सूचकांक का मान 8 से अधिक है, उन्हें ही पूर्ण लोकतंत्र (Full democracy) वाले देश के रूप में इस अध्ययन के तहत् माना गया है. 8 से कम, किन्तु 6 या 6 से अधिक सूचकांक वाले देशों में दोषपूर्ण लोकतंत्र (Flawed democracy) की स्थिति स्वीकार की गई है, जिन देशों के लिए लोकतंत्र सूचकांक 6 से कम, किन्तु 4 या 4 से अधिक है, उन्हें संकर शासन (Hybrid Regime) वाले देश में तथा 4 से कम सूचकांक मान वाले देशों को सत्तावादी शासन (Authoritarian Regime) वाले देशों के रूप में रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है.

इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट (EIU) की फरवरी 2024 की रिपोर्ट में भारत के लिए यह सूचकांक 7·18 आकलित है तथा 167 देशों में 41वाँ स्थान उसे इस वर्ष दिया गया है. इस प्रकार भारत की रैंक में 5 पायदान का सुधार इस वर्ष हुआ है. पिछले वर्ष 2022 के सूचकांकों में भारत के लिए यह सूचकांक 7·04 आकलित था तथा 167 देशों में 46वाँ स्थान भारत को दिया गया था. 5 मानकों पर आधारित इस सूचकांक में सुधार हाल की वर्षों में यद्यपि हो रहा है (2020 में भारत के लिए यह सूचकांक 6·61 था, जो 2021 में 6·91 तथा 2022 में 7·04 था तथा जो अब 2023 के लिए 7·18 आकलित किया गया है. स्थिति में लगातार सुधार के बावजूद सूचकांक के इस मान के साथ भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र (Flawed Democracy) की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है. लोकतंत्र की स्थिति के सम्बन्ध में भारत के सभी पड़ोसी देशों में स्थिति भारत से भी खराब इस रिपोर्ट में बताई गई है. पड़ोसी देशों में 6·17 सूचकांक के साथ 70वें स्थान पर रहे श्रीलंका में भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति है. अन्य पड़ोसी देशों में बांग्लादेश (सूचकांक 5·87, 75वीं रैंक), भूटान (सूचकांक 5·54, 81वीं रैंक), नेपाल (4·60, 98वीं रैंक) पाकिस्तान (सूचकांक 3·25, 118वीं) में संकर शासन (Hybrid Regime) की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है. चीन के लिए लोकतंत्र सूचकांक 2·12 आकलित है. इससे वहाँ सत्तावादी शासन (Authorative Regime) की स्थिति है. भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार अफगानिस्तान में भी सत्तावादी शासन है.

लोकतंत्र सूचकांक (2023)
शीर्ष राष्ट्र

रैंक	राष्ट्र	स्कोर (लोकतंत्र सूचकांक)
1	नॉर्वे	9·81
2	न्यूजीलैण्ड	9·61
3	आइसलैण्ड	9·45
4	स्वीडन	9·39
5	फिनलैण्ड	9·30
6	डेनमार्क	9·28
7	आयरलैण्ड	9·19
8	स्विट्जरलैण्ड	9·14
9	नीदरलैण्ड्स	9·00
10	ताइवान	8·92

सबसे नीचे के 10 राष्ट्र

158	ईक्वेटोरियल गुनिया	1·92
159	लाओस	1·71
160	चाड	1·67
161	तुर्कमेनिस्तान	1·66
162	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो	1·68
163	सीरिया	1·43
164	मध्य अफ्रीका गणराज्य	1·18
165	उत्तर कोरिया	1·08
166	म्यांमार	0·85
167	अफगानिस्तान	0·26

भारत व पड़ोसी देशों की रैंक

41	भारत	7·18
70	श्रीलंका	6·17
75	बांग्लादेश	5·87
81	भूटान	5·54
98	नेपाल	4·60
118	पाकिस्तान	3·25
148	चीन	2·12
166	म्यामांर	0·85
167	अफगानिस्तान	0·26

इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट का यह सूचकांक 5 श्रेणियों पर आधारित है—चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद Electoral Process and Pluralism) सरकार का कामकाज (Functioning of Government), राजनीतिक भागीदारी (Political Participation), राजनीतिक संस्कृति (Political Culture) और नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties), इनके कुल अंकों के आधार पर देशों को चार प्रकार के शासन में बाँटा गया है. पूर्ण लोकतंत्र (Full Democracy) (8 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले), दोषपूर्ण लोकतंत्र (Flawed Democracy), (6 से ज्यादा, लेकिन 8 या 8 से कम अंक वाले), संकर शासन (Hybrid Regime) (4 से ज्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक हासिल करने वाले) और सत्तावादी शासन (Authoritarian Regime) (4 या उससे कम अंक वाले).

लोकतंत्र सूचकांक (2023) की दृष्टि से विश्व में शीर्षक स्थान नॉर्वे का है, जिसके लिए यह सूचकांक 9·81 आकलित है. 9·61 व 9·45 स्कोर के साथ दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः न्यूजीलैण्ड व आइसलैण्ड का है. स्वीडन (स्कोर 9·39), फिनलैण्ड (9·30) व डेनमार्क (9·28) क्रमशः चौथे, पाँचवें व छठे स्थान पर हैं. उनके पश्चात् क्रमशः आयरलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड्स व ताइवान के स्थान हैं. 167 देशों की इस सूची में सबसे निचला 167वाँ स्थान अफगानिस्तान का है, जिसके लिए 2023 के लिए लोकतंत्र सूचकांक 0·26 आकलिक है. इससे एक पायदान ऊपर 166वाँ स्थान म्यांमार का इस वर्ष भी है. म्यांमार के लिए यह सूचकांक 0·85 आकलित है. उसके ऊपर के तीन स्थान क्रमशः उत्तर कोरिया व मध्य अफ्रीकी गणराज्य व सीरिया के हैं.

विश्व के अन्य प्रमुख देशों में जापान (सूचकांक 8·40) व यूनाइटेड किंगडम (8·25) क्रमशः 16वें व 18वें स्थान पर जहाँ पूर्ण लोकतांत्रिक देशों में हैं वहीं फ्रांस (8·07) 23वें स्थान पर व अमरीका (7·85) 29वें स्थान पर भारत की तरह दोषपूर्ण लोकतंत्र वाले देशों में हैं.

वर्ष 2023 के लिए आकलित लोकतंत्र सूचकांकों के आधार पर इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट की फरवरी 2024 में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के केवल 24 देशों में, जहाँ विश्व की 7·8 प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है, पूर्ण लोकतंत्र की स्थिति है, जबकि 50 देशों में, जहाँ 37·6 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, दोषपूर्ण लोकतंत्र है. संकर शासन (Hybrid Regime) वाले देशों तथा सत्तावादी शासन (Authoritarian Regime) वाले देशों की संख्या क्रमशः 34 व 59 तथा इन देशों में रहने वाले लोगों की संख्या विश्व जनसंख्या का क्रमशः 15·2 प्रतिशत व 39·4 प्रतिशत रिपोर्ट में बताई गई है.

लोकतंत्र/शासन की स्थिति के अनुसार देशों की संख्या

लोकतंत्र/शासन की स्थिति	देशों की संख्या	कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जनसंख्या* (प्रतिशत)
पूर्ण लोकतंत्र	24	7·8
दोषपूर्ण लोकतंत्र	50	37·6
संकर शासन	34	15·2
सत्तावादी शासन	59	39·4
	167	100

* यह मान लिया गया है कि अध्ययन में शामिल देशों की जनसंख्या ही विश्व की कुल जनसंख्या है, क्योंकि कुछ छोटे-मोटे सूक्ष्म क्षेत्र ही अध्ययन से बाहर हैं तथा उनकी जनसंख्या नगण्य मान ली गई है.

अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको के नाम

अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड रूस के जेनेडी पडाल्का (Gennady Padalka) के नाम था. विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर 878 दिन 11 घण्टे 29 मिनट व 48 सेकण्ड तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड जेनेडी ने 2015 में बनाया था. उनका यह रिकॉर्ड अब रूस के ही ओलेग कोनोनेंको (Oleg Kononenko) ने फरवरी 2024 में भंग कर दिया है. 15 सितम्बर, 2023 को पाँचवीं बार अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए कोनोनेंको ने

ओलेग कोनोनेंको : अंतरिक्ष प्रवास का नया विश्व रिकॉर्ड

अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल मिलाकर 878 दिन व 12 घण्टे से अधिक का समय 4 फरवरी, 2024 को पूरा कर लिया था. 59 वर्षीय कोनोनेंको की मौजूदा अंतरिक्ष यात्रा सितम्बर 2024 में समाप्त होगी. तब तक उनके अंतरिक्ष प्रवास की कुल अवधि 1110 दिन हो जाएगी, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा.

उल्लेखनीय है कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों में विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड अमरीका की 64 वर्षीय पैगी ह्विटसन (Peggy Whitson) के नाम है. ह्विटसन का विभिन्न चरणों में कुल मिलाकर अंतरिक्ष प्रवास 675 दिन 3 घण्टे व 49 मिनट का रहा है.

मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण

धरती पर रहते हुए चिकित्सकों ने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण 10 फरवरी, 2024 को किया. इसके लिए इस्तेमाल किए गए रोबोट को मीरा (MIRA—Miniaturized in Vivo Robotic Assistant) नाम दिया गया है. केवल 2 पाउंड वजन का 'मीरा' एक रोबोटिक सिलेंडर है. चलने में मदद के लिए उसके नीचे दो मूवेबल प्रोंग लगे हैं, जिनके अन्त में 2 छोटे टूल्स हैं. इनमें से एक चीजों को पकड़ता है तथा दूसरा उन्हें काटने का काम करता है. इन्हीं टूल्स की मदद से रोबेट द्वारा सर्जरी की जाती है. **मीरा रोबोट** का विकास कई वर्षों के परिश्रम एवं प्रयास के पश्चात् नासा (NASA) के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनीवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रो. शेन फरिटर (Shen Farritor) व उनकी टीम ने किया है. मीरा रोबोट की मदद से अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक रोबोट की सर्जरी 10 फरवरी, 2024 को सफलतापूर्वक की गई. मीरा का नियंत्रण धरती पर सर्जन्स की टीम ने किया.

अंतरिक्ष स्टेशन पर रोबोटिक सर्जरी के इस परीक्षण को अंतरिक्ष सर्जरी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

नौवाँ रायसीना संवाद नई दिल्ली में सम्पन्न

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च

रायसीना संवाद के अवसर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

फाउंडेशन के तत्वावधान में नौवाँ रायसीना संवाद (Raisina Dialogue) नई दिल्ली में 21-23 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष/शासन, प्रमुख उद्योगपति, शिक्षाविद्, पत्रकार व रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आदि शामिल थे. विश्व के समक्ष विद्यमान राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर मंथन के लिए इसमें उपस्थित थे. हेलेनिक रिपब्लिक (ग्रीस) के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस (Kyriakos Mitsotakis) इस वर्ष इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के साथ-साथ उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ता (Keynote Speaker) भी थे. **इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम–चतुरंगा : संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण** (Chaturanga : Conflict, Contest, Cooperate, Creat) था. 21 फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया.

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि मित्सोताकिस ने भारत को विश्व मंच पर एक महान् शक्ति के साथ-साथ वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी भी बताया इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना यूरोप की विदेश नीति की आधारशिला होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ग्रीस अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत व यूरोपीय क्षेत्र के रिश्तों के बीच एक प्रमुख द्वार बन सकता है. भारत मध्यपूर्व-यूरोप के बीच प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर में भी ग्रीस की भूमिका को महत्वपूर्ण उन्होंने बताया. रूस-यूक्रेन युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे यूरोपीय धरती पर कोई युद्ध नहीं, बल्कि स्थानीय युद्ध से कहीं अधिक बताते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता व अन्तर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के लिए एक क्रूर चुनौती उन्होंने बताया और कहा कि इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका भारत को निभानी है.

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के विस्तार की आवश्यकता पर जोरदार तरीके से बल दिया. उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसके सदस्यों की संख्या लगभग 50 थी तथा आज जब इसके सदस्यों की संख्या चार गुना हो गई है. सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी 5 ही है. इस कमी के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए पश्चिमी देशों की भी उन्होंने आलोचना की.

रायसीना डायलॉग भू-राजनैतिक (Geopolitics) व भू-आर्थिक (Geo-economics) मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है. इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था. यह एक ऐसा बहुउद्देशीय सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णय कर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार एवं उद्योग-व्यापार जगत् के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं.

23 फरवरी को भी एक अन्य सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा भारतीय विदेश मंत्री ने उठाया तथा कहा कि जी-20 का विस्तार यदि हो सकता है, तो सुरक्षा परिषद् का क्यों नहीं? रूस और चीन के बीच बढ़ रही निकटता के लिए पश्चिमी देशों की नीतियों को जिम्मेदार उन्होंने बताया. भारत-चीन सम्बन्धों के लिए सन्तुलन की स्थिति में पहुँचना व इसे बरकरार रखने को एक चुनौती बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच तात्कालिक मुद्दा तथा नियमों का चीन की ओर से पालन नहीं किया जाना है.

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए चैक गणराज्य के विदेश मंत्री जेन लिपावस्की, आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट वियतनाम के उपविदेश मंत्री डू हंग वियत आदि अन्य भागीदारों ने भी विभिन्न सत्रों में सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए (i) टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स : रेगुलेशंस और वास्तविकताएं, (ii) ग्रह के साथ शक्ति : निवेश और इनोवेटर, (iii) युद्ध और शांति : शस्त्रागार और विषमताएं, (iv) उपनिवेशवाद से मुक्ति बहुपक्षवाद : संस्थाएं और समावेशन, (v) 2030 के बाद का एजेंडा : लोग और प्रगति तथा (vi) लोकतंत्र की रक्षा : समाज और सम्प्रभुता सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में चर्चा के प्रमुख मुद्दे थे. ●●●

नवीन संशोधित संस्करण

उपकार

छत्तीसगढ़ वृहद् संदर्भ

(नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित)

लेखकद्वय : संजय त्रिपाठी एवं श्रीमती चंदन त्रिपाठी

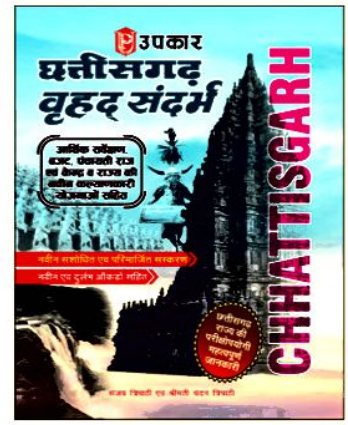

कोड नं. : 1437 मूल्य : ₹ 395/-

पुस्तक की विशेषताएँ

पुस्तक का प्रथम खण्ड 'छत्तीसगढ़ : विविध अध्ययन' सामान्य विषयों का है जिसमें छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, कृषि, खनिज, वन, उद्योग, जल संसाधन, अर्थव्यवस्था एवं अन्य विविध विषयों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

पुस्तक का द्वितीय खण्ड 'छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला एवं स्थापत्य' का है जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रत्येक काल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है.

पुस्तक का तृतीय खण्ड 'छत्तीसगढ़ की संस्कृति' का है जिसमें छत्तीसगढ़ी संस्कृति से सम्बन्धित प्रदेश की संस्कृतिगत विशिष्टताओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का उल्लेख किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य से सम्बन्धित प्रामाणिक जानकारी अब एक ही पुस्तक में उपलब्ध

उपकार प्रकाशन, आगरा-5
● E-mail : sales@upkar.in
● Website : www.upkar.in

आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य

- **मौद्रिक नीति की 2023-24 की छठी अन्तिम द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित**
- **चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹ 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि**
- **अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में ढील**
- **2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8·25 प्रतिशत**
- **भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूँजी में वृद्धि**
- **दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या व टेलीडेंसिटी आदि के सम्बन्ध में 'ट्राई' की रिपोर्ट**
- **पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी**

मौद्रिक नीति की 2023-24 की छठी अन्तिम द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगातार 6 द्वैमासिक समीक्षाओं में रेपो दर में वृद्धियों से मुद्रास्फीति पर काबू पाने के पश्चात् इस वर्ष 2023-24 में सभी 6 द्वैमासिक समीक्षाओं में रेपो दर व अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन आरबीआई ने नहीं किया है. वर्ष 2023-24 की 6 अप्रैल, 2023 की पहली, 8 जून की दूसरी, 10 अगस्त की तीसरी, 6 अक्टूबर, 2023 की चौथी तथा 8 दिसम्बर, 2023 की पाँचवीं द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखने के पश्चात् 8 फरवरी, 2024 की छठी अन्तिम द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर को रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखा है, जिससे यह नीतिगत दर अभी 6·50 प्रतिशत ही बनी हुई है. रेपो दर में कोई परिवर्तन न होने से अन्य सम्बद्ध दरों में भी कोई परिवर्तन फरवरी 2024 में नहीं हुआ है, जिससे बैंक दर व सीमान्त स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) 6·75–6·75 प्रतिशत के अपने पूर्व स्तर पर ही बने हुए हैं. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर भी 6·25 प्रतिशत के पूर्व स्तर पर बरकरार है. रिवर्स रेपो दर (3·35 प्रतिशत), नकद आरक्षण अनुपात (4·50 प्रतिशत) तथा सांविधिक तरलता अनुपात (18·00 प्रतिशत) में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. **मुद्रास्फीति की दर को 4 ± 2 प्रतिशत के लक्षित स्तर में ही बनाए रखने को मौद्रिक नीति की पहली प्राथमिकता दी गई है.**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति 5·2 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान आरबीआई ने पहली द्वैमासिक समीक्षा में अप्रैल 2023 में व्यक्त किया था, जिसे घटाकर 5·1 प्रतिशत आरबीआई ने जून 2023 में तथा 5·4 प्रतिशत अगस्त, अक्टूबर व दिसम्बर 2023 में किया था. अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति व उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को देखते हुए 2023-24 में मुद्रास्फीति 5·4 प्रतिशत ही रहने का आरबीआई का ताजा 8 फरवरी, 2024 का अनुमान है. 2023-24 की चौथी अन्तिम तिमाही Q_4 में यह 5·0 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान है. अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानूसन सामान्य मानते हुए मुद्रास्फीति की दर 4·5 प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का अनुमान है तथा इसकी (2024-25 की) चारों तिमाहियों में यह क्रमशः 5·0 प्रतिशत, 4·0 प्रतिशत, 4·6 प्रतिशत, 4·7 प्रतिशत फिलहाल अनुमानित है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6·4 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में द्वैमासिक समीक्षा के समय व्यक्त किया जिसे बढ़ाकर 6·5 प्रतिशत अप्रैल 2023 में आरबीआई ने किया था तथा जून, अगस्त व अक्टूबर 2023 में भी यही अनुमान बरकरार रखा था, इस अनुमान को 6·5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7·0 प्रतिशत आरबीआई ने 8 दिसम्बर,

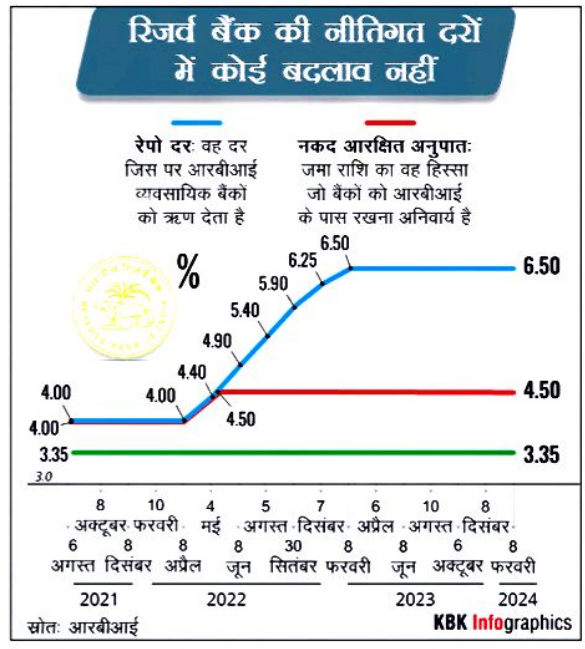

2022-23 व 2023-24 में प्रमुख बैंकिंग दरें (प्रतिशत)								2023-24					
	8 अप्रैल, 2022 की स्थिति	4 मई, 2022 की स्थिति	8 जून, 2022 की स्थिति	5 अगस्त, 2022 की स्थिति	30 सितम्बर, 2022 की स्थिति	7 दिसम्बर, 2022 की स्थिति	8 फरवरी, 2023 की स्थिति	6 अप्रैल, 2023 की स्थिति	8 जून, 2023 की स्थिति	10 अगस्त, 2023 की स्थिति	6 अक्टूबर, 2023 की स्थिति	8 दिसम्बर, 2023 की स्थिति	8 फरवरी, 2024 की स्थिति
रेपो दर	4·00	4·40	4·90	5·40	5·90	6·25	6·50	6·50	6·50	6·50	6·50	6·50	6·50
रिवर्स रेपो दर	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35	3·35
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट	3·75	4·15	4·65	5·15	5·65	6·00	6·25	6·25	6·25	6·25	6·25	6·25	6·25
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट	4·25	4·65	5·15	5·65	6·15	6·50	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75
बैंक रेट	4·25	4·65	5·15	5·65	6·15	6·50	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75	6·75
नकद आरक्षण अनुपात (CRR)	4·00	4·50*	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50	4·50
सांविधिक तरलता अनुपात	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00	18·00

* यह दर 21 मई, 2022 से 4·50 प्रतिशत की गई थी.

2023 को किया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी में वृद्धि 7·0 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 8 फरवरी, 2024 को व्यक्त किया है. 2024-25 की चारों तिमाहियों Q_1, Q_2, Q_3 व Q_4 में जीडीपी में वृद्धि क्रमशः 7·2 प्रतिशत, 6·8 प्रतिशत, 7·0 प्रतिशत व 6·9 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान फरवरी 2024 की समीक्षा में आरबीआई ने व्यक्त किया है.

मौद्रिक नीति की 2024-25 की पहली द्वैमासिक समीक्षा के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक 3-5 अप्रैल, 2024 को होगी. इससे मौद्रिक नीति की अगली द्वैमासिक समीक्षा (2024-25 की पहली द्वैमासिक समीक्षा) 5 अप्रैल, 2024 को जारी की जाएगी.

चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य ₹ 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि

चीनी सत्र (अक्टूबर-सितम्बर) 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price–FRP) में ₹ 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है. अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाले चीनी सत्र (2024-25) के लिए यह मूल्य ₹ 340 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, पिछले वर्ष 2023-24 के लिए यह मूल्य ₹ 315 प्रति क्विंटल था, जबकि उससे पूर्व 2022-23 के लिए यह मूल्य ₹ 305 प्रति क्विंटल 2021-22 के लिए ₹ 290 प्रति क्विंटल तथा 2020-21 के लिए यह ₹ 285 प्रति क्विंटल था. 2017-18 के पश्चात् यह दूसरा अवसर है जब गन्ने के

अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में ढील

अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियाँ—यथा उपग्रहों की स्थापना एवं प्रचालन आदि मामलों में ***केवल सरकारी अनुमोदन के रूट से ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)*** *के लिए अनुमति अभी तक उपलब्ध थी. इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक विदेशी कम्पनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में भारी छूट प्रदान करने का निर्णय सरकार ने फरवरी 2024 में लिया है. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल 21 फरवरी, 2024 की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत् उपग्रह सम्बन्धित गतिविधियों को 3 उपक्षेत्रों में बाँटकर प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए एफडीआई ने ऑटोमैटिक अनुमोदन की सीमाएं निर्धारित की गई हैं. इन सीमाओं से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक होगी.*

21 फरवरी, 2024 को अनुमोदित नई नीति के तहत्—

(i) उपग्रह-विनिर्माण और प्रचालन (Satellite Manufacturing and Operation), उपग्रह डाटा उत्पाद तथा ग्राउंड एवं यूजर सेगमेंट में ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई 74 प्रतिशत तक हो सकता है. इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी.

(ii) उपग्रह लॉन्च ह्वीकल और उससे जुड़ी प्रणालियों या उपप्रणालियों तथा उपग्रह लॉन्च करने या उतारने के लिए स्पेस पोर्ट बनाने आदि क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई की सीमा अधिकतम 49 प्रतिशत होगी. इन क्षेत्रों में इस सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी.

(iii) नई नीति के तहत् उपग्रहों के पार्ट्स, प्रणाली या उपप्रणाली बनाने के मामले में एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100 प्रतिशत रहेगी.

सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि रोजगार सृजन के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को आत्मसात् करने तथा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.

अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को ऑटोमैटिक रूट से लाने के सरकार के ताजा फैसले से तेजी से उभर रहे घरेलू अंतरिक्ष उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. सस्ती दर पर और उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत पहले ही विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है. इस क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से विदेशी निवेश आने से अब ज्यादा विदेशी कम्पनियों के आने का रास्ता साफ होगा. इस क्षेत्र में विदेशी निवेश से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा पूरा अंतरिक्ष उद्योग तेजी से ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी बनेगा.

केन्द्र सरकार ने भारत की अंतरिक्ष नीति की घोषणा अप्रैल 2023 में की थी. इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई थी. अंतरिक्ष सेक्टर में विदेशी निवेश में वृद्धि आने वाले दिनों में काफी बल इस सेक्टर को मिलेगा तथा आत्म-निर्भर भारत की दिशा में भी कदम आगे बढ़ेंगे.

उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) में ₹ 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस वर्ष की गई है. इससे पूर्व पिछले वर्ष 2023-24 में ₹ 10 प्रति क्विंटल की वृद्धि ही इसमें की गई थी. 2024-25 के लिए एफआरपी में ₹ 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि का फैसला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA) की 21 फरवरी, 2024 की बैठक में किया गया. कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 2024-25 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत A2 + FL लागत (वास्तविक भुगतान की गई लागत के साथ पारिवारिक श्रम का मूल्य) पर ₹ 340 प्रति क्विंटल का एफआरपी किसानों को 107 प्रतिशत प्रतिफल प्रदान करेगा.

- 2024-25 के लिए गन्ने का उपर्युक्त उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 10·25 प्रतिशत रिकवरी वाले गन्ने के लिए है. इससे अधिक प्रति 0·1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी की स्थिति में ₹ 3·32 प्रति क्विंटल अधिक मूल्य देय होगा, किन्तु 10·25 प्रतिशत से कम (किन्तु 9·5 प्रतिशत से अधिक) रिकवरी की स्थिति में प्रति 0·1 प्रतिशत कम रिकवरी के मामलों में ₹ 3·32 प्रति क्विंटल की कटौती एफआरपी में की जाएगी.
- 9·5 प्रतिशत से कम रिकवरी वाले गन्ने के मामले में ₹ 315·10 प्रति क्विंटल का मूल्य किसानों को देय होगा.

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य होता है. चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती हैं. किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा आदि में राज्य सरकारें इससे अधिक मूल्य की घोषणा करती हैं जिसे राज्य सलाहकारी मूल्य (State Advised Price–SAP) कहा जाता है.

गन्ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी)

चीनी सत्र	रुपए प्रति क्विंटल
2013-14	210
2014-15	220
2015-16	230
2016-17	230
2017-18	255
2018-19	275
2019-20	275
2020-21	285
2021-22	290
2022-23	305
2023-24	315
2024-25	340

2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8·25 प्रतिशत

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमाओं पर ब्याज दर में 0·10 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation—EPFO) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने की है. तदनुरूप इन जमाओं पर कर्मचारियों को 8·25 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होगा. यह विगत 3 वर्षों में इन जमाओं पर सर्वोच्च ब्याज दर है. इससे ईपीएफओ के 6·5 करोड़ सब्सक्राइबर्स लाभान्वित होंगे. **इससे पूर्व 2022-23 में ईपीएफ जमाओं पर देय ब्याज जहाँ 8·15 प्रतिशत थी, 2021-22 में यह 8·10 प्रतिशत ही थी,** जो पिछले चार दशकों में इसकी सबसे कम ब्याज दर थी.

2023-24 के लिए ब्याज दर में 0·10 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि के प्रस्ताव को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रम एवं रोजगार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में 11 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में मंजूरी प्रदान की गई. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात् बढ़ी हुई ब्याज दर को अधिसूचित किया जाएगा.

हाल ही के वर्षों में ईपीएफ जमाओं पर ब्याज दर

वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत)
2015-16	8·80
2016-17	8·65
2017-18	8·55
2018-19	8·65
2019-20	8·50
2020-21	8·50
2021-22	8·10
2022-23	8·15
2023-24	8·25

दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या व टेलीडेंसिटी आदि के सम्बन्ध में 'ट्राई' की रिपोर्ट

दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या, उसके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण ब्रॉड बैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या तथा इसके सेवा प्रादाताओं की बाजार हिस्सेदारी तथा विभिन्न दूरसंचार मण्डलों में टेलीडेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या) आदि के सम्बन्ध में विस्तृत आँकड़े दूरसंचार नियामक निकाय ट्राई (TRAI–Telecom Regulatory Authority of India) द्वारा 22 फरवरी, 2024 को जारी किए गए. ट्राई के इन आँकड़ों में अनुसार–

- दिसम्बर 2023 के अन्त में टेलीफोन के शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 662·56 मिलियन थी. (इनमें 633·44 मिलियन उपभोक्ता वायरलैस टेलीफोन के व 29·12 मिलियन वायर लाइन टेलीफोन के थे.) पूर्व माह नवम्बर के अन्त की तुलना में यह संख्या 0·45 प्रतिशत अधिक थी, जबकि एक वर्ष पूर्व दिसम्बर 2022 की तुलना में यह 1·55 प्रतिशत अधिक थी.
- दिसम्बर 2023 के अन्त में टेलीफोन के ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या 527·77 मिलियन थी. यह एक माह पूर्व नवम्बर 2023 की तुलना में 0·31 प्रतिशत अधिक थी, जबकि एक वर्ष पूर्व दिसम्बर 2022 की तुलना में यह 1·88 प्रतिशत अधिक थी.
- दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1190·33 मिलियन थी. (इनमें 1158·49 मिलियन उपभोक्ता वायरलैस टेलीफोन के तथा 31·84 मिलियन वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ता थे) दिसम्बर 2023 के अन्त में टेलीफोन उपभोक्ताओं की यह संख्या पूर्व माह की तुलना में 0·39

भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूँजी में वृद्धि

किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदने वाली केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India–FCI) की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए इसकी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) में वृद्धि सरकार ने फरवरी 2024 में की है. 1965 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई की अधिकृत पूँजी ₹ 10,000 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर ₹ 21,000 करोड़ किया गया है. पूँजी में वृद्धि से खाद्य निगम की ऑपरेशन क्षमता में वृद्धि होगी तथा अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से यह पूरा कर सकेगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद के अतिरिक्त खाद्य भंडार बनाए रखकर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत् खाद्यान्नों का वितरण करना इसके दायित्वों में शामिल है. इन कार्यों के लिए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कैश क्रेडिट व शॉर्ट टर्म लोन आदि का सहारा लेता है. अधिकृत पूँजी में वृद्धि से इसकी स्वयं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा इस पर ब्याज का बोझ कम होगा तथा इसकी कार्य संचालन की आर्थिक लागत कम होगी.

प्रतिशत अधिक थी, जबकि एक वर्ष पूर्व दिसम्बर 2022 की तुलना में यह 1·70 प्रतिशत अधिक थी. दिसम्बर 2022 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1170·38 मिलियन थी.

- दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ता 55·66 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता 44·34 प्रतिशत थे.

टेलीडेंसिटी

- टेलीफोन कनेक्शनों की उपर्युक्तानुसार संख्या के चलते देश में टेलीडेंसिटी (प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दिसम्बर 2023 के अन्त में 85·23 प्रतिशत थी, जो शहरी क्षेत्रों में 133·76 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में 58·56 प्रतिशत थी. एक वर्ष पूर्व दिसम्बर 2022 के अन्त में देश की टेलीडेंसिटी 84·56 प्रतिशत थी.
- दिसम्बर 2023 के अन्त में देश के कुल 22 लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज (LSAs) में सबसे कम टेलीडेंसिटी 56·43 प्रतिशत बिहार में, 66·57 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में व 67·82 प्रतिशत मध्य प्रदेश में थी.
- दिसम्बर 2023 के अन्त में सर्वाधिक टेलीडेंसिटी 278·28 प्रतिशत दिल्ली में, दूसरे स्थान पर 121·77 प्रतिशत केरल में तथा तीसरे स्थान पर 120·12 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में थी.

विभिन्न लाइसेंस सर्विस एरियाज में टेलीडेंसिटी (दिसम्बर 2023 की स्थिति)

राज्य/मण्डल	टेलीडेंसिटी
बिहार	56·43
उत्तर प्रदेश	66·57
मध्य प्रदेश	67·82
असम	72·38
ओडिशा	75·98
पूर्वोत्तर	80·16
राजस्थान	81·94
प. बंगाल	82·15
हरियाणा	89·08
जम्मू-कश्मीर	89·75
गुजरात	92·24
आन्ध्र प्रदेश	94·34
कर्नाटक	102·11
तमिलनाडु	102·93
महाराष्ट्र	103·10
पंजाब	113·76
हिमाचल प्रदेश	120·12
केरल	121·77
दिल्ली	278·28
सम्पूर्ण भारत	**85·23**

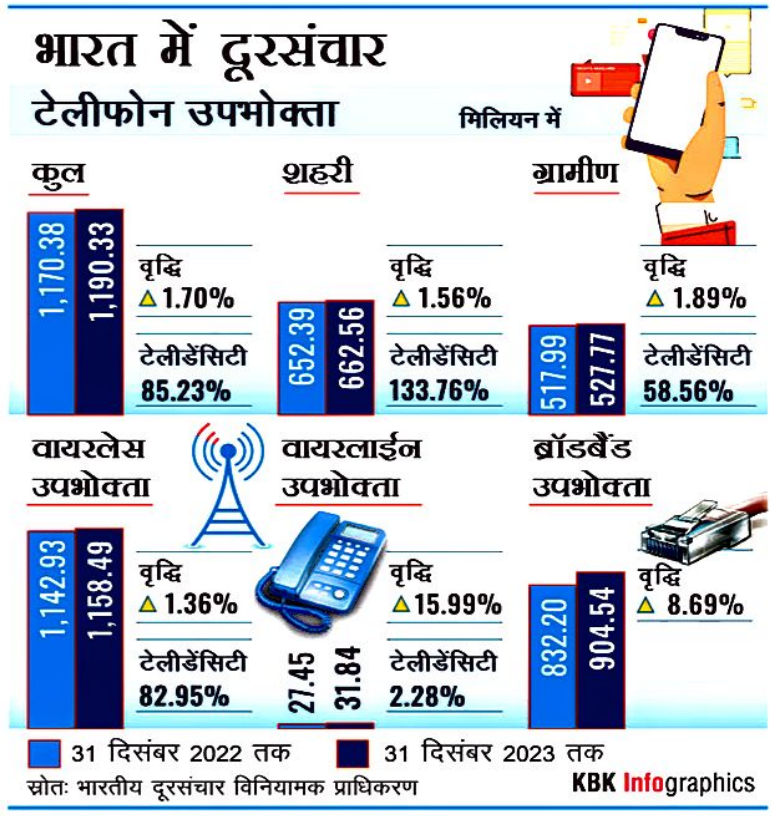

ट्राई के अद्यतन आँकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2023 के अन्त में देश में मोबाइल (वायरलैस) फोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1158·49 मिलियन थी. ट्राई द्वारा फरवरी 2024 में जारी इन आँकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2023 के अन्त में वायरलैस फोन सेवा बाजार में सर्वाधिक 39·69 प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस जियो की थी, जबकि 32·95 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल का इसमें दूसरा स्थान था. विभिन्न सेवा प्रादाताओं की बाजार हिस्सेदारी के निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है कि इस बाजार में निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व है.

मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न सेवा प्रादाताओं की बाजार हिस्सेदारी
(दिसम्बर 2023 के अन्त की स्थिति)

कम्पनी	बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत)
रिलायंस जियो	39·69
भारती एयरटेल	32·95
वोडाफोन आइडिया	19·25
बीएसएनएल	7·94
एमटीएनएल	0·17
रिलायस कम्यू.	0·0002

टेलीफोन परिदृश्य एक दृष्टि में
(दिसम्बर 2023 की स्थिति)

	वायरलैस	वायर लाइन	योग
टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या (मिलियन)	**1158·49**	**31·84**	**1190·35**
शहरी उपभोक्ता	633·44	29·12	662·56
ग्रामीण उपभोक्ता	525·05	2·72	527·77
टेलीडेंसिटी			
(प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन)	**82·95**	**2·28**	**85·23**
शहरी क्षेत्रों में	127·88	5·88	133·76
ग्रामीण क्षेत्रों में	58·26	0·30	58·56
कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत	54·68	91·46	55·66
ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत	45·32	8·54	44·34
ब्रॉड बैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन)	565·28	38·35	904·54
	+ 0·91		

शेष पृष्ठ 32 पर

राज्य समाचार

छत्तीसगढ़

2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने 9 फरवरी, 2024 को विधान सभा में प्रस्तुत किया. श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सत्ता में आई भाजपा सरकार का इस कार्यकाल में यह पहला ही बजट है जिसमें कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है, ₹ 1,47,500 करोड़ के साथ 'मोदी की गारंटी'

बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी

के वायदों को पूरा करने के लिए समर्पित इस बजट में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का दावा किया गया है. GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) की थीम पर आधारित यह बजट 10 स्तम्भों पर खड़ा है. इसमें रिफॉर्म तीव्र आर्थिक विकास, अधिकाधिक पूँजीगत व्यय, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग तथा निजी निवेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विकास पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने नवगठित सरकार के इस पहले ही बजट को अमृतकाल की नींव का बजट करार दिया है.

बजट में 2024-25 के लिए सकल अनुमानित व्यय ₹ 1,47,500 करोड़ है. कुल व्यय में सामाजिक क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 35 प्रतिशत तथा सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है.

आय व्यय का समायोजन

सन्दर्भित वर्ष (2024-25) में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,47,500 करोड़ व कुल व्यय भी लगभग इतना ही बजट में प्रस्तावित है. कुल व्यय में ₹ 1,24,840 करोड़ राजस्व व्यय (Revenue Expenditure), ₹ 22,300 करोड़ पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) तथा ₹ 305 करोड़ ऋणों के अग्रिमों के रूप में अनुमानित हैं, पूँजीगत व्यय (₹ 22,300 करोड़) कुल व्यय का 15 प्रतिशत है तथा 2023-24 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है. 2024-25 के दौरान ₹ 1,47,500 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों में ₹ 1,25,900 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ व शेष ₹ 21,600 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ हैं. ₹ 1,25,900 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) में ₹ 93,700 करोड़ कर राजस्व (₹49,700 करोड़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व + ₹ 44,000 करोड़ केन्द्रीय करों में से राज्य का

छत्तीसगढ़ बजट (2025-26) : प्राप्तियाँ एवं व्यय के अनुमान

क्र. स.	शीर्ष	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 पुनरीक्षित अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
I	राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)	**106000·73**	**111350·00**	**125900·00**
क.	राज्य का राजस्व	**56200·00**	**59000·00**	**68400·00**
	1. कर राजस्व	38000·00	40600·00	49700·00
	2. कर भिन्न राजस्व	18200·00	18400·00	18700·00
ख.	केन्द्र से प्राप्तियाँ	**49800·73**	**52350·00**	**57500·00**
	3. केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	34800·73	39750·00	44000·00
	4. सहायक अनुदान	15000·00	12600·00	13500·00
II.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7+8)	**15500·00**	**36268·08**	**21600·00**
	5. उधार एवं अग्रिम की वसूली	300·00	200·00	150·00
	6. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0·00	0·00	0·00
	7. शुद्ध लोक ऋण	11500·00	32368·08	19750·00
	8. लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ	3700·00	3700·00	1700·00
III.	कुल प्राप्तियाँ (I+II)	**121500·73**	**147618·08**	**147500·00**
IV.	कुल व्यय (9+10+11)	**121500·21**	**148617·89**	**147445·63**
	9. राजस्व व्यय	102500·66	127019·55	124840·01
	10. पूँजीगत व्यय	18660·20	21258·99	22300·02
	11. ऋण एवं अग्रिम	339·35	339·35	305·60
V.	पुनर्प्राप्तियाँ एवं ऋण अदायगी	**10869·97**	**10995·73**	**13122·44**
VI.	कुल विनियोग	**132370·18**	**159613·62**	**160568·07**
VII	ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6919·87	7038·38	7851·01
VIII	राजस्व आधिक्य/घाटा (I-9)	**3500·07**	**–15669·55**	**1059·99**
IX	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा (1+5+6+8)–IV)	**–15199·48**	**–33367·89**	**–19695·63**
X	प्राथमिक घाटा (IX-VII)	**–8279·61**	**–26329·51**	**–11844·62**
XI	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव)	**509043#**	**505887(A)**	**561736**
XII	राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी के प्रतिशत में)	**–2·99%**	**5·81%**	**2·90%**

सभी प्रकार की मासिक पत्रिका मैगजीन पढ़ने वाले इस पेज को किलक करे जरूर करे 👇

https://t.me/Magazine9876

Those who read all types of monthly magazines must join this group.

Please touch this page

👆 👆

अंश) के रूप में तथा ₹32,200 करोड़ करेतर राजस्व (Non-Tax Revenue) के रूप में (₹18700 करोड़ राज्य के स्वयं के करेतर राजस्व + ₹ 13,500 करोड़ केन्द्र से सहायक अनुदानों के रूप में) प्राप्त होने का अनुमान बजट में लगाया गया है.

प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों के चलते 2024-25 के दौरान राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹1059·99 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा (वित्तीय घाटा) ₹ 19,965·63 करोड़ अनुमानित है. 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 2·90 प्रतिशत होगा, जो एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा से कम है.

राज्य की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2022-23 के त्वरित अनुमान से 6·56 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) बढ़ने का अनुमान है. यह अनुमानित राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर 7·3 प्रतिशत से कम है. इसके साथ ही, 2023-24 में, कृषि क्षेत्र में भारत की 1·82 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ में 3·23 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 7·93 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ में 7·13 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में भारत की 7·72 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में छत्तीगढ़ में 5·02 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है. वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹4,64,399 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹5,05,886 करोड़ होने का अनुमान है, जो 8·93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

- *त्वरित अनुमानों के अनुसार 2023-24 में राज्य के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 14·41 प्रतिशत की तुलना में 15·32 प्रतिशत है, औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर 30·97 प्रतिशत की तुलना में 53·50 प्रतिशत है और सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 54·62 प्रतिशत की तुलना में 31·19 प्रतिशत है.*
- *2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 7·31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1·47,361 प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 7·9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 1,85,854 अनुमानित है.*

अन्य महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं

- बजट में कोई नया कर नहीं, न ही पहले के किसी कर में वृद्धि.
- 2024-25 में राज्य सरकार का पूँजीगत व्यय कुल बजट व्यय का 15 प्रतिशत प्रस्तावित, यह 2023-24 के 20 प्रतिशत तथा पिछले 5 वर्षों के औसत पूँजीगत व्यय 12 प्रतिशत की तुलना में अधिक प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए ₹ 35 करोड़ का प्रावधान.
- राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय योजना किया गया तथा इस योजना के तहत् भूमिहीन कृषि मजदूरों को पूर्व वर्ष के ₹ 7000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹ 10,000 वार्षिक भुगतान इसके लिए ₹ 500 करोड़ का प्रावधान.
- खूबचंद आयुष्मान योजना अब वीर नारायण सिंह योजना होगी.
- नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा.
- भिलाई में उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जाएगी.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी.
- छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में तथा छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (CIMS) प्रत्येक संभाग में स्थापित किए जाएंगे.
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन करने की घोषणा.
- रायपुर भिलाई के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाएगा.
- अमृत मिशन योजना के लिए ₹ 700 करोड़ का प्रावधान.
- छोटे एवं मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए व आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए कृषि **उन्नति योजना** के तहत् ₹ 10,000 करोड़ का प्रावधान. इसके 24·72 लाख किसान (पूर्व वर्ष की तुलना में 2·30 लाख अधिक) लाभान्वित होंगे.
- **तेंदूपत्ता संग्राहकों** को गत वर्ष ₹ 4,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर ₹ 5,500 प्रति मानक बोरा भुगतान.
- महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में **महतारी वंदन योजना** के तहत् प्रति वर्ष ₹ 12,000 सहायता का प्रावधान.

बिहार

बिहार बजट : 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार का बजट प्रदेश की नवगठित एनडीए

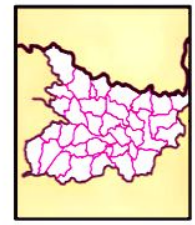

सरकार के वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी, 2024 को विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया. बजट प्रस्तुति से 2 सप्ताह पूर्व ही

राज्य की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में बताया कि विगत एवं दशक में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आकार में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर राज्य का जीएसडीपी 2012-13 के ₹ 2·57 लाख करोड़ से बढ़ कर 2022-23 में ₹ 4·42 लाख करोड़ हो गया है. उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आँकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर वृद्धि 2022-23 में 3·1 प्रतिशत रही, जबकि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7·24 प्रतिशत रही (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार) इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10·64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी तेजी से बढ़ी है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. बिहार की यह वृद्धि दर देश के अन्य सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों से अधिक है, जबकि 10·2 प्रतिशत वृद्धि के साथ असम दूसरे स्थान पर तथा 9·2 प्रतिशत वृद्धि के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है.

नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरूप बिहार में वर्ष 2015-16 की बहुआयामी गरीबी 51·89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-21 में 33·79 प्रतिशत हो गई है. बिहार में गरीबी दर में यह गिरावट सभी राज्यों में सर्वोपरि है. इस अवधि में, जहाँ बिहार में गरीबी दर में 18·13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गई वहीं पूरे देश में मात्र 9·89 प्रतिशत अंकों की ही गिरावट हुई. इस अवधि में राज्य के 2·25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी बताया कि देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम बिहार में कराया गया. बिहार जाति आधारित गणना, 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर बिहार में राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% (यथा अनु. जाति 20%, अनु. जनजाति 02%, अ. पि.व. 25% तथा पि. व. 18%) आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर (सामान्य) वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत् लागू है. इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया है.

श्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार का त्यागपत्र देकर भाजपा के साथ मिलकर एनडीए

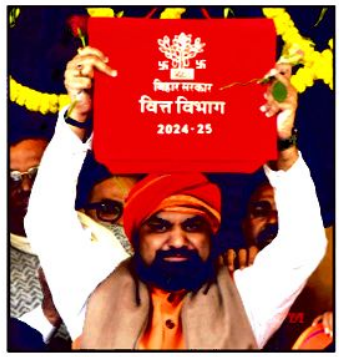

बजट दस्तावेजों के साथ वित्त मंत्री सम्राट चौधरी

सरकार का गठन 28 जनवरी, 2024 को किया था तथा नवगठित सरकार का यह पहला ही बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व सामाजिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार के कुल व्यय का 38·89 प्रतिशत भाग सामाजिक सेवाओं पर, 29·95 प्रतिशत सामान्य सेवाओं पर तथा 22·68 प्रतिशत भाग आर्थिक सेवाओं पर व्यय करने का प्रावधान बजट में किया गया है. ₹ 2,78,725·72 करोड़ का यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. राज्य सरकार के पहले के 7 निश्चय-1 की योजनाओं को पूरा करके 7 नए निश्चय-2 की योजनाओं पर काम आगे बढ़ाने का लक्ष्य पिछले वर्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के बजट में भी रखा था. सरकार के इन 7 निश्चय-2 पर काम आगे बढ़ाते हुए, 2024-25 में इनके लिए ₹ 5040 करोड़ का प्रावधान किया गया है. (सरकार के 7 निश्चय-2 के विभिन्न अवयवों में युवा शक्ति-बिहार की प्रगति, सशक्त महिला-सक्षम, महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव, स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ सम्पर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा शामिल हैं.)

प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 2,78,725·72 करोड़ बजट में अनुमानित है. इसमें ₹ 1,78,706·09 करोड़ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) तथा ₹1,00,019·63 करोड़ स्कीम व्यय है. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2023-24 के बजट अनुमान ₹1,61,855·67 करोड़ की तुलना में ₹16,850·42 करोड़ अधिक है.

- 2024-25 में कुल प्रस्तावित व्यय में स्कीम व्यय 35·88 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64·12 प्रतिशत प्रस्तावित है.
- 2024-25 में कुल **पूँजीगत व्यय** ₹ 53,048·72 करोड़ अनुमानित है, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 19·03 प्रतिशत है.
- ₹ 53,048·72 करोड़ पूँजीगत व्यय में ₹ 29,415·91 करोड़ पूँजीगत परिव्यय होगा, जबकि ₹ 22,392·72 करोड़ ऋण राशि के रूप में वापस की जानी है. ₹1,240·09 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाना प्रस्तावित है जिसमें ₹ 700 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए होगा.
- बजट में 2024-25 में कुल **राजस्व व्यय** ₹ 2,25,677·00 करोड़ अनुमानित है, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 80·97 प्रतिशत

बिहार बजट (2024-25) : आय-व्ययक एक दृष्टि में
(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान
	2023-24	2023-24	2024-25
1	2	3	4
1. राजस्व प्राप्तियाँ	212326·97	214494·26	226798·40
2. कर राजस्व (क+ख)	152437·31	153137·31	167311·92
(क) संघीय करों में राज्य का अंश	102737·26	102737·26	113011·92
(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	49700·05	50400·05	54300·00
3. राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	6511·74	6581·84	7325·86
4. केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	53377·92	54775·11	52160·62
5. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	49758·44	63037·96	52127·31
6. ऋणों की वसूली	431·91	431·91	439·18
9. कुल प्राप्तियाँ (1+5)	262085·40	277532·22	278925·72
10. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	161855·67	179973·30	178706·09
11. राजस्व खाते पर, जिसमें	138012·19	156129·82	156085·84
(क) ब्याज भुगतान	18354·44	18354·44	20526·19
13. पूँजीगत खाते पर	23843·48	23843·48	22620·25
(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	21487·65	21487·65	20621·99
(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2071·04	2071·04	1770·72
(ग) पूँजीगत व्यय	163·50	163·50	123·50
(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	121·29	121·29	104·03
14. (क) राज्य स्कीम	37941·34	59465·26	40838·76
14. (घ) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	29·73	93·52	19·63
14. स्कीम व्यय	100029·73	134977·22	100019·63
17. कुल व्यय (10+14)	261885·40	314950·52	278725·72
18. राजस्व व्यय (11+15)	207848·00	250023·82	225677·00
19. पूँजीगत व्यय (13+16)	54037·40	64926·70	53048·72
20. राजस्व घाटा (18-1)	– 4478·97	35529·56	– 1121·40
21. राजकोषीय घाटा (17–(1+6+13क+13ख)	25567·83	76465·66	29095·43
22. प्राथमिक घाटा (21–12क)	7213·39	58111·22	8569·24
23. जीएसडीपी	858928·00	860238·00	976514·00
24. राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	2·98	8·89	2·98
25. ब्याज भुगतान/कुल राजस्व प्राप्तियाँ	8·64	8·56	9·05

है तथा पूर्व वर्ष 2023-24 के राजस्व व्यय (बजट अनुमान) ₹2,07,848·00 करोड़ से ₹17,829·00 करोड़ अधिक है. राजस्व व्यय में ₹ 20,526·19 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु हैं.

- 2024-25 कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,26,798·40 करोड़ अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,12,326·97 करोड़ (बजट अनुमान) की तुलना में ₹ 14,471·44 करोड़ अधिक है.
- 2024-25 में राज्य सरकार को राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में ₹ 54,300·00 करोड़ तथा गैर-कर राजस्व के रूप में ₹ 7,325·86 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है. गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में खनन से ₹ 3,500·00 करोड़ तथा ₹1,719·26 करोड़ ब्याज प्राप्तियों से अनुमानित हैं.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 51,688·14 करोड़ ऋण लिया जाना प्रस्तावित है.

राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा

प्राप्तियों एवं व्यय के उपर्युक्त अनुमानों के चलते 2025-26 में राज्य सरकार का राजस्व घाटा (राजस्व व्यय–राजस्व प्राप्तियाँ) – ₹ 1,121·40 करोड़ होगा अर्थात् राजस्व खाते में ₹ 1121·40 करोड़ का आधिक्य रहने का अनुमान है. संशोधित आकलन के अनुसार पूर्व वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा ₹ 35,529·56 करोड़ रहा है.

2025-26 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) ₹ 29,095·43 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है, जो जीएसडीपी का 2·98 प्रतिशत होगा तथा एफआरडीपी अधिनियम से निर्धारित सीमा के भीतर ही रहेगा. पूर्व वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2·98 प्रतिशत रहने का लक्ष्य बजट में था, किन्तु संशोधित आँकड़ों में यह 8·89 प्रतिशत अनुमानित किया गया है.

प्राथमिक घाटा 2025-26 में ₹ 8,569·24 करोड़ रहने का बजट में अनुमान है.

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं.
- 2024-25 के दौरान राज्य सरकार का कुल प्रस्तावित व्यय.
- ₹ 2,78,725·72 करोड़ जिसमें स्कीम व्यय ₹ 1,00,019 करोड़.
- पूँजीगत व्यय ₹ 53,048·72 करोड़, जो कुल व्यय का 19·03 प्रतिशत
- महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना हेतु 2024-25 में ₹ 250 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है.
- पटना में 'स्लम' में रह रही महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वाच्छांगिनी परियोजना चालू की गई है.
- राज्य सरकार 2024-25 में शिक्षा पर सर्वाधिक ₹ 52,639·03 करोड़ व्यय करेगी. यह कुल प्रस्तावित व्यय का 18·89 प्रतिशत गृह विभाग को ₹ 16,323·83 करोड़, राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का ₹15,235·11 करोड़, स्वास्थ्य पर ₹ 14,932·09 करोड़ एवं ग्रामीण विकास पर ₹14,296·71 करोड़ का व्यय अनुमानित है.
- निश्चय-2 पर 2024-25 में ₹ 5,040 करोड़ के व्यय का प्रावधान इसमें ₹ 700 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु.
- कृषि में शोध करने वाले पीएचडी के छात्रों को अन्य छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रति माह ₹ 10 हजार दिए जाएंगे.
- वैशाली के बिदुपुर में पान विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी.
- अपने स्वयं के करों से 2024-25 में ₹ 54,300 करोड़ के कर राजस्व की प्राप्तियों का बजट में अनुमान. इनमें ₹ 42,500 करोड़ वाणिज्य कर से, ₹ 7,500 करोड़ स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से, ₹ 3,700 करोड़ ट्रांसपोर्ट टैक्स से तथा ₹ 600 करोड़ भू-राजस्व से प्राप्त होने का अनुमान.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बजट : 2024-25

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार

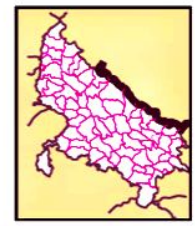

खन्ना, ने 5 फरवरी, 2024 को विधान सभा में प्रस्तुत किया. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट (कुल

रुपया कहाँ से आता है (प्रतिशत)

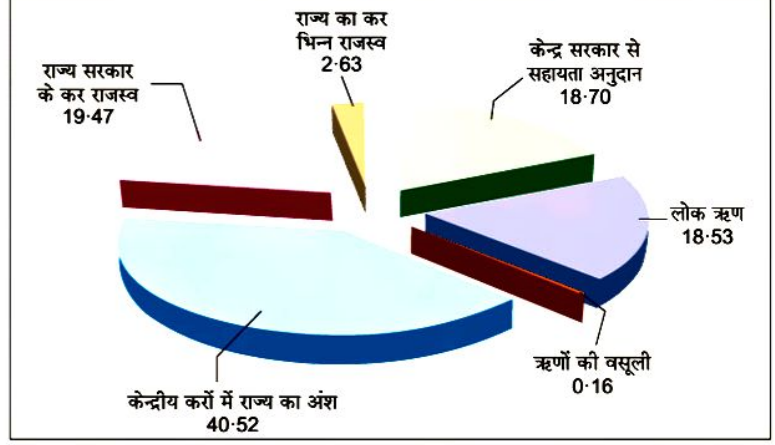

रुपया कहाँ जाता है

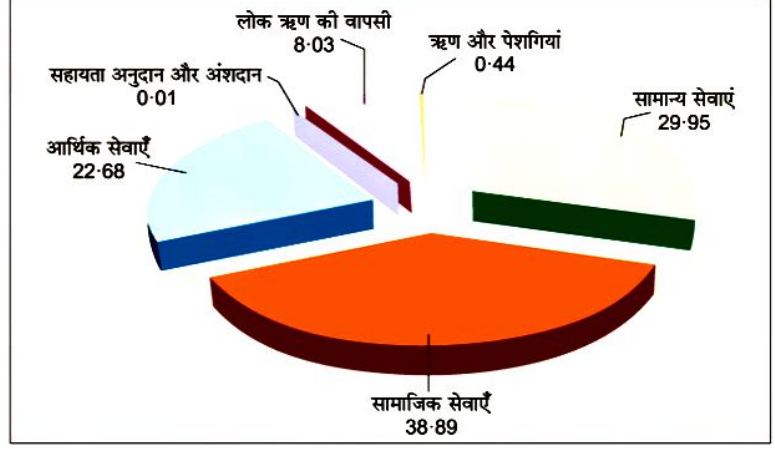

मिलाकर आठवाँ बजट) है, जबकि श्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत यह प्रदेश का पाँचवाँ बजट

बजट दस्तावेजों के साथ
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

है. रामराज्य के लक्ष्य पर केन्द्रित ₹ 7·36 लाख करोड़ के इस बजट का आरम्भ व अन्त राम नाम के साथ ही हुआ. प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, देवीपाटन व प्रयागराज आदि के लिए बड़ी राशियों का प्रावधाान बजट में किया गया है.

उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजट में केन्द्र सरकार से कदम मिलाते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास अमृतकाल के इस दूसरे बजट में किए गए हैं. शीघ्र ही होने वाले लोक सभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में सभी वर्गों के हितों का ध्यान इसमें रखा गया है. विकास को गति प्रदान करने व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में ₹ 2,03,782·38 करोड़ पूँजीगत परिव्यय के रूप में रखे गए हैं, जो बजट में प्रस्तावित ₹7,36,437·71 करोड़ के कुल व्यय का प्रतिशत लगभग 27·67 प्रतिशत है. बजट में ₹ 24,863·57 करोड़ की नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं.

बजट में प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन

उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट में सन्दर्भित वर्ष में सरकार का कुल व्यय ₹ 7,36,437·71 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,21,333·82 करोड़ अनुमानित हैं. इसमें ₹ 6,06,802·40 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 1,14,531·42 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश ₹ 4,88,902·84 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व का अंश ₹ 1,17,899·56 करोड़ शामिल ₹ 4,88,902·84 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व ₹ 2,70,86·00 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 2,18,816·84 करोड़ शामिल हैं.

व्यय

2024-25 के दौरान प्रदेश सरकार का कुल व्यय ₹ 7,36,437·71 करोड़ बजट में अनुमानित है. इसमें ₹ 5,32,655·33 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 2,03,782·38 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है. प्राप्तियों एवं व्यय के इन आँकड़ों के आधार पर 2025-26 में ₹ 74,147·07 करोड़ की राजस्व बचत जहाँ होगी वहीं राजकोषीय घाटा ₹ 86,530·51 करोड़ अनुमानित है, जो 2024-25 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3·46 प्रतिशत है.

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों) से कुल व्यय घटाने के पश्चात् ₹ 15,103·89 करोड़ का घाटा बजट में अनुमानित है. लोक लेखे से ₹ 5,500 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात् 2024-25 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम ₹ 9603·89 करोड़ ऋणात्मक अनुमानित किया गया है. प्रारम्भिक शेष ₹ 38,189·66 करोड़ को हिसाब में लेते हुए 2024-25 में अन्तिम शेष ₹ 28,585·77 करोड़ होना अनुमानित किया गया है.

कर प्राप्तियाँ

2024-25 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (State GST) तथा 'वैट' से ₹ 1,56,982 करोड़, आबकारी शुल्क ₹ 58,308 करोड़, स्टाम्प एवं पंजीकरण से ₹35,652 करोड़ तथा वाहन कर से ₹ 12,505 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान बजट में लगाया गया है.

वर्ष 2022-23 के वास्तविक आँकड़े वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण तालिका में प्रदर्शित है.

2024-25 का सार (₹ करोड़ में)

		2022-23 वास्तविक आँकड़े	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 संशोधित अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
1.	राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ	**417241·50**	**570865·66**	**525217·84**	**606802·40**
	2. कर राजस्व*	343832·45	445871·59	410866·44	488902·84
	3. करेत्तर राजस्व @	73409·05	124994·07	114351·40	117899·56
4.	पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**68184·26**	**112427·08**	**102427·08**	**114531·42**
	5. ऋणों की वसूली	1337·32	3312·18	3312·18	3298·63
	6. उधार और अन्य देयताएं	66846·94	109114·90	99114·90	111232·79
	(जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम)	0·00	10000·00	0·00	10000·00
7.	कुल प्राप्तियाँ (1+4)	**485425·76**	**683292·74**	**627644·92**	**721333·82**
8.	राजस्व लेखे पर व्यय जिसमें	379978·06	502354·01	454771·32	532655·33
	9. ब्याज अदायगियाँ	43007·98	52755·56	49316·64	53711·99
10.	पूँजी लेखे पर व्यय जिसमें	125927·49	187888·42	177591·05	203782·38
	11. पूँजीगत परिव्यय	93028·39	147617·29	146177·12	154747·47
	12. ऋण की अदायगियाँ	22690·46	31181·43	21317·81	39806·17
	(जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान सहित)	0·00	10000·00	0·00	10000·00
13.	कुल व्यय (8+10)	**505905·55**	**690242·43**	**632362·37**	**736437·71**
14.	राजस्व बचत (1-8)	**37263·44**	**68511·65**	**70446·52**	**74147·07**
15.	राजकोषीय घाटा	**64636·27**	**84883·16**	**82514·54**	**86530·51**
16.	प्रारम्भिक घाटा (15-9)	**21628·29**	**32127·60**	**33197·90**	**32818·52**

* इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है.
@ इसमें राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित है.

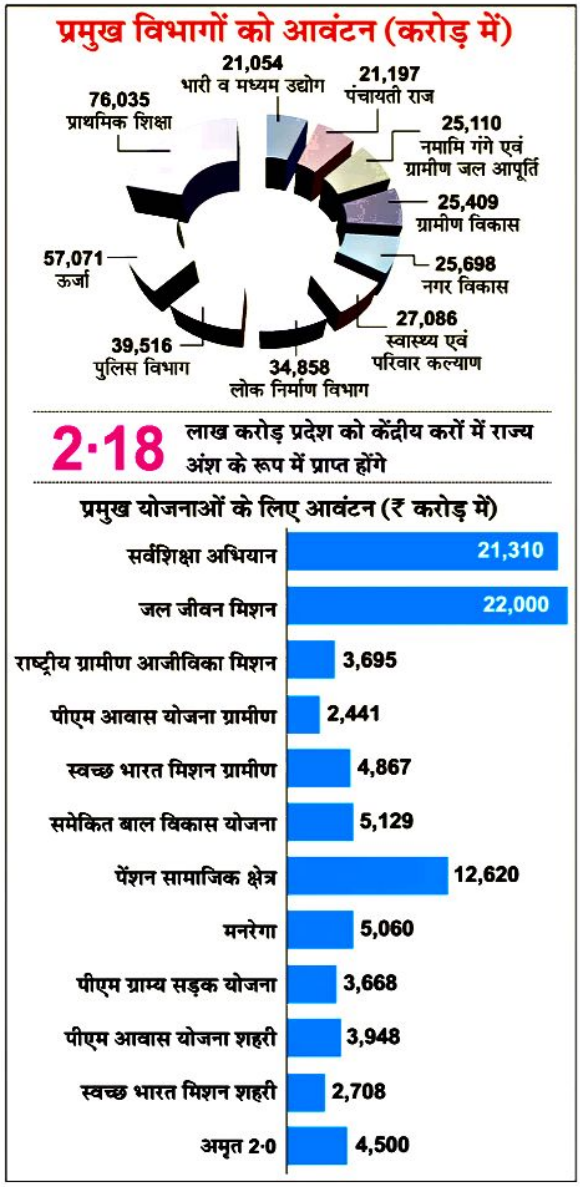

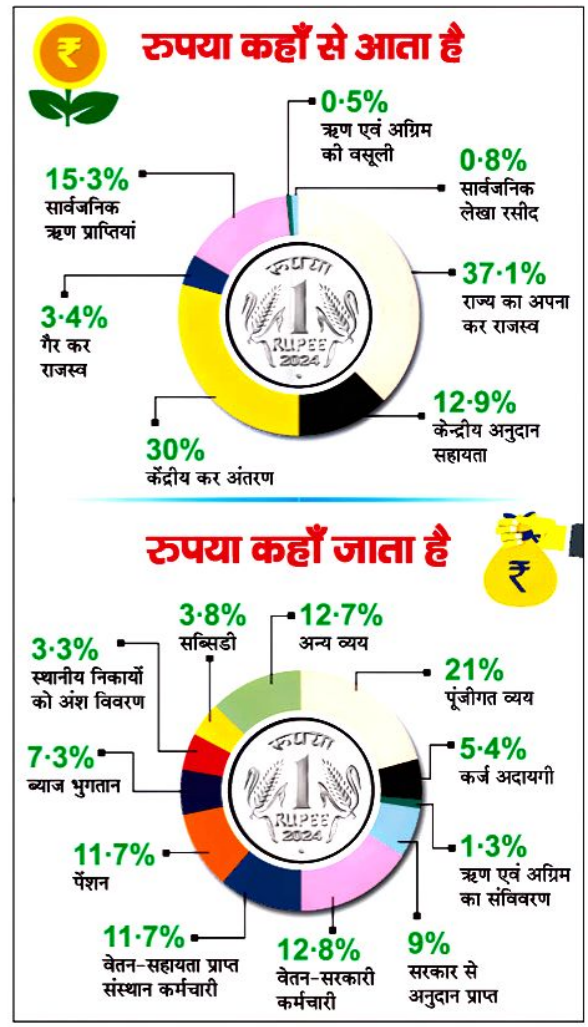

अन्य महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं

- बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं.
- बजट में 2024-25 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 7,36,437·71 करोड़ प्रस्तावित जिसमें ₹ 5,32,655·33 करोड़.
- राजस्व खाते पर तथा ₹ 2,03,782·38 करोड़ पूँजी खाते में प्रस्तावित.
- ₹ 24,863·57 करोड़ की नई योजनाएं बजट में शामिल.
- दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एयरो सिटी विकसित करने की बजट में घोषणा.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2023 तक प्रदेश के ₹ 2·62 करोड़ किसानों के खातों में लगभग ₹ 63,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित.
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत् पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की राशि ₹500 प्रति माह से बढ़ा कर ₹ 1000 प्रति माह की जा चुकी है.
- प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन ₹ 1000 प्रति माह की दर से प्रदान की जा रही है.
- प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं.
- वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं. 16 अन्य जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
- राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की जा चुकी है.
- वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है.
- प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,840 से बढ़कर 3,828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में यह 2,550 से बढ़कर 5,250 हो गई है. इस प्रकार एम.बी.बी.एस. कुल 9,078 सीटें प्रदेश में उपलब्ध हो गई हैं.
- सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1,543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में यह संख्या 480 से बढकर 1,775 हो गई है. इस प्रकार पीजी की कुल 3,318 सीटें प्रदेश में अब उपलब्ध हो गई हैं.

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड प्रदेश में वितरित किए गए हैं. लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष ₹ 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.
- महाकुम्भ मेला 2025 की तैयारियों हेतु ₹ 2500 करोड़ के बजट में प्रावधान किया गया है.
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है.
- कान्हा गौशाला एवं बेस द्वारा पशु आश्रय योजना हेतु ₹ 400 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है.
- वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की स्थापना की जाएगी.
- प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है.

झारखण्ड

झारखण्ड बजट (2024-25)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखण्ड सरकार का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 27 फरवरी, 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया. श्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के एक माह के भीतर ही 2024-25 के लिए बजट वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने प्रस्तुत किया. यूपीए की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली

मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव बजट दस्तावेजों के साथ

पिछली सरकार में भी डॉ. उरांव ही वित्त मंत्री थे तथा पिछला बजट भी उन्होंने ही प्रस्तुत किया था तथा श्री चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का यह पहला ही बजट था.

₹ 1,28,900 करोड़ के इस बजट में सभी वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है. बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए पहली बार 'बाल बजट' भी बनाया गया है जिसमें बच्चों से सम्बन्धित कुल 80 योजनाओं को शामिल किया गया है. ₹ 8,868·69 करोड़ के बाल बजट में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास कल्याण आदि की योजनाएं शामिल हैं. कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र के लिए ₹ 4,606·57 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. गठबंधन सरकार की पुरानी योजनाओं को विस्तार देते हुए नई योजनाएं भी बजट में शामिल की गई हैं. **विकास की गति को तेज करने के प्रयास के तहत् बजट में सर्वाधिक ₹ 46,399 करोड़ का प्रावधान जहाँ आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए किया गया है, दूसरे स्थान पर ₹ 45,377 करोड़ सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए तथा तीसरे स्थान पर ₹ 37,124 करोड़ सामान्य प्रक्षेत्र के लिए प्रस्तावित किए गए हैं.** पंचायतों के मुखिया, प्रमुख, वार्ड सदस्यों व जिला परिषद् सदस्यों के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान बजट में जहाँ किया गया है वहीं किसानों का ₹ 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा बजट में की गई है.

प्राप्तियों एवं व्यय का समायोजन

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार का कुल व्यय ₹ 1,28,900 करोड़ रहने का बजट अनुमान है, जो 2023-24 के बजट अनुमान ₹ 1,16,418 करोड़ से ₹ 15·15 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध (Establishment and Committed Exp.) व्यय का बजट अनुमान ₹ 49,117·30 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान ₹ 45,445 करोड़ से 3·6 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम व्यय का कुल बजट अनुमान ₹ 79,782·70 करोड़ का है, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में यह ₹ 70,973 करोड़ था.
- 2024-25 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय ₹ 91,831·54 करोड़ बजट

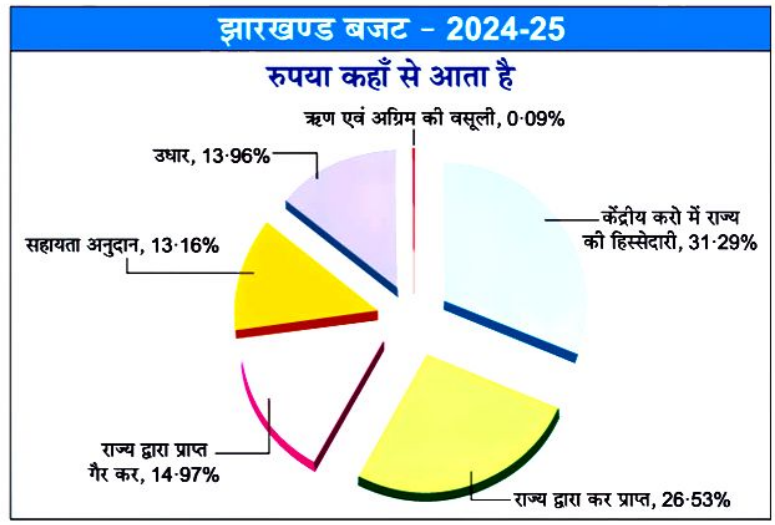

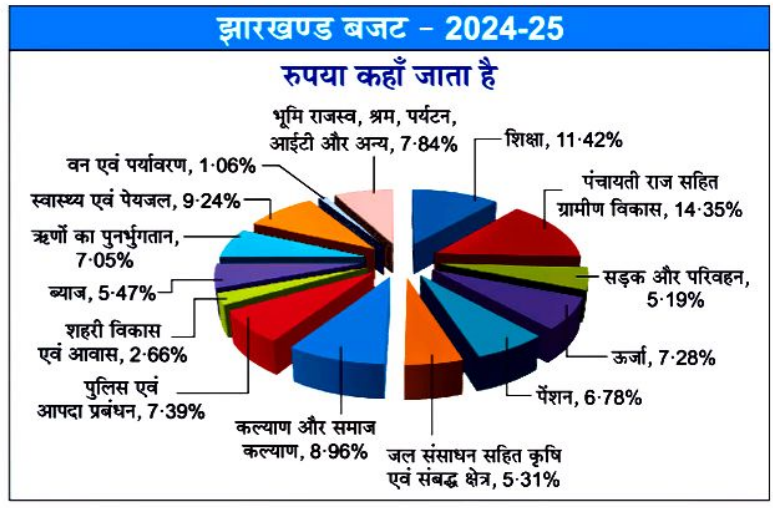

झारखण्ड बजट (2024-25) एक झलक

(₹ करोड़ में)

	स्रोत	2022-23 वास्तविक	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 संशोधित अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
1.	राजस्व प्राप्तियाँ	80245·22	98337·15	95228·75	110800·00
2.	कर राजस्व	56521·62	64639·29	65237·36	74538·22
	(क) केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	31404·12	33779·29	36525·62	40338·22
	(ख) राज्य का स्व कर राजस्व	25117·50	30860·00	28711·74	34200·00
3.	कर-भिन्न राजस्व	23723·59	33697·86	29991·40	36261·78
	(क) राज्य का स्व कर–भिन्न राजस्व	12830·06	17259·44	16115·76	19300·43
	(ख) केन्द्र सरकार से अनुदान	10893·54	16438·42	13875·64	16961·35
4.	पूँजी प्राप्तियाँ	11392·60	18080·85	25289·61	18100·00
	(क) ऋणों की वसूली	46·41	80·85	7289·61	100·00
	(ख) अन्य प्राप्तियाँ (विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ)	0·00	0·00	0·00	0·00
	(ग) उधार एवं अन्य देयताएं	11346·19	18000·00	18000·00	18000·00
5.	कुल प्राप्तियाँ (1+4)	91637·82	116418·00	120518·36	128900·00
6.	स्थापना व्यय	41211·83	45445·00	46989·82	49117·30
7.	राजस्व खाते पर जिसमें	34328·93	39020·49	40574·83	40523·69
	(क) ब्याज भुगतान	6238·29	6787·09	7499·04	7054·57
8.	पूँजी खाते पर	6882·90	6424·51	6414·99	8593·61
9.	स्कीम व्यय	50425·99	70973·00	73528·54	79782·70
	(क) राजस्व खाते पर	32352·70	45655·51	47518·36	51307·85
	(ख) पूँजी खाते पर	18073·29	25317·49	26010·18	28474·85
10.	कुल व्यय (8+9)	91637·82	116418·00	120518·36	128900·00
	(क) राजस्व व्यय (7+9 क)	66681·64	84676·00	88093·19	91831·54
	(ख) पूँजी खाते पर व्यय (8+9 ग)	24956·18	31742·00	32425·17	37068·46
11.	राजस्व घाटा (10 क–1)	– 13563·58	– 13661·15	– 7135·56	– 18968·46
	स.रा.घ.उ. (GSDP) का प्रतिशत	– 3·44	– 3·40	– 1·67	– 4·03
12.	प्रभावी राजस्व घाटा (11-9ख)	– 17512·70	– 20764·19	– 12488·00	– 29560·92
	स.रा.घ.उ. (GSDP) का प्रतिशत	– 4·45	– 4·91	– 2·92	– 6·29
13.	राजकोषीय घाटा				
	{10 – (1+4 क+1-4 ख+1-5 क+1-8 ख)}	4616·73	11674·57	11690·74	9499·68
	स.रा.घ.उ. (GSDP) का प्रतिशत	1·17	2·76	2·73	2·02
14.	प्राथमिक घाटा (13–7क)	– 1821·56	4887·48	4191·70	2445·11
	स.रा.घ.उ. (GSDP) का प्रतिशत	– 0·41	1·15	0·98	0·52

में अनुमानित किया गया है, जो 2023-24 में ₹ 84,676 करोड़ अनुमानित था.

- 2024-25 में कुल पूँजीगत व्यय ₹ 37,068·46 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो 2023-24 के बजट में ₹ 31,742 करोड़ अनुमानित था.
- इस प्रकार 2024-25 में राज्य सरकार के **राजस्व एवं पूँजीगत** व्यय क्रमशः ₹ 91,831·54 करोड़ एवं ₹ 37,068·46 करोड़ हैं, जो कुल व्यय ₹ 1,28,900 करोड़ का क्रमशः 72·7 एवं 27·3 प्रतिशत है.
- 2024-25 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,10,800 करोड़ अनुमानित हैं, जो 2023-24 के बजट अनुमान (₹ 98,337·15 करोड़) की तुलना में 18·4 प्रतिशत अधिक है.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल ₹ 74,538·22 करोड़ के कर राजस्व में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में ₹ 34,200 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान ₹ 30,860 करोड़ से 18·4 प्रतिशत अधिक है. कर राजस्व ने शेष ₹ 40,338·22 करोड़ केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में अनुमानित है.
- 2024-25 में राज्य को अपने स्रोतों से गैर-कर राजस्व के रूप में हुई. ₹ 19,300·43 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है, जो 2023-24 बजट अनुमान ₹ 17,259·44 करोड़ की तुलना में 25·4 प्रतिशत अधिक है. इन प्राप्तियों एवं व्यय के यह बजट अनुमान एक दृष्टि में बजट एक झलक बॉक्स में दर्शाए गए हैं.

राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा

- उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि 2024-25 में राजस्व बचत (Revenue Surplus) ₹ 18,968·46 करोड़ रहने का अनुमान है, जो राज्य के GSDP का 4·03 प्रतिशत होगी. 2023-24 में राजस्व बचत ₹ 13,661·15 करोड़ अनुमानित की

गई थी, किन्तु संशोधित आकलन में यह ₹ 7,135·36 करोड़ रही है.

- 2023-24 में राजकोषीय घाटा ₹ 11,674·57 करोड़ [जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) का 2·76 प्रतिशत] पिछले वर्ष बजट में लक्षित था, जो संशोधित आकलन में यह जीएसडीपी का 2·73 प्रतिशत अनुमानित किया गया है. 2024-25 में राजकोषीय घाटा ₹ 9,499·68 करोड़ (जीएसडीपी का 2·02 प्रतिशत) रहने का लक्ष्य बजट में है.

अन्य महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं

- 2024-25 के लिए ₹ 1,28,900 करोड़ के कर में कोई नया कर नहीं.
- 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का – 4·03 प्रतिशत, राजकोषीय घाटा 2·02 प्रतिशत तथा प्राथमिक घाटा 0·52 प्रतिशत अनुमानित.
- 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की विकास दर 6·8 प्रतिशत रही तथा 2023-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में झारखण्ड में यह 7·1 प्रतिशत रही तथा 2024-25 में 7·7 प्रतिशत अनुमानित है.
- विगत 4 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है. 2019-20 में कुल व्यय में स्थापना व्यय 47·53 प्रतिशत था, जो 2024-25 में 38·62 प्रतिशत प्रस्तावित है.
- मनरेगा के तहत् 2024-25 में 9 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य.
- 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए ₹ 11,316·07 करोड़ तथा कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र के लिए ₹ 4,606·57 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
- राज्य में 19 नए महाविद्यालयों (15 डिग्री महाविद्यालय व 4 महिला महाविद्यालय) की स्थापना का निर्णय.
- 2024-25 में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹ 12,314·21 करोड़ तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए ₹ 2,411·77 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
- राँची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय.
- 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत् घरेलू व शहरी उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
- नगर विकास एवं आवास हेतु ₹ 3,429·86 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
- राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सिद्धो-कान्हू युवा क्लब की स्थापना की गई.
- 2024-25 के लिए राज्य की योजना का कुल आकार ₹ 79,782·70 करोड़.
- तकनीकी संस्थानों में संस्थानों व डिप्लोमा के छात्रों को क्रमशः ₹ 30,000 व ₹ 15,000 प्रतियोगी दर से आर्थिक सहायता.
- राशन दुकानदारों के कमीशन में भी वृद्धि.

●●●

शेष पृष्ठ 23 का

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि दिसम्बर 2023 के अन्त में वायरलैस फोन सेवा बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 8·10 प्रतिशत ही थी, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 91·90 प्रतिशत थी.

पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी

दिसम्बर 2018 में प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी, 2024 को पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी. महाराष्ट्र में यवतमाल में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में कुल मिलाकर ₹ 21,000 करोड़ से अधिक की राशि इस किश्त के तहत् प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा कर दी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह इस योजना की यह तीसरी अन्तिम किश्त थी. इस वित्तीय वर्ष में इससे पूर्व इस योजना की पहली किश्त 27 जुलाई, 2023 को तथा दूसरी किश्त 15 नवम्बर, 2023 को पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की गई थी. इससे 2023-24 की तीनों किश्तें पात्र किसानों को प्राप्त हो गई हैं तथा 28 फरवरी, 2024 को दी गई किश्त इस योजना के तहत् किसानों को दी गई कुल मिलाकर 16वीं किश्त थी. इससे अब 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹ 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि अब तक दी जा चुकी है. इस योजना के तहत् 2024-25 की पहली किश्त अब जून-जुलाई 2024 में सम्भावित है, जो पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त होगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है, कृषि भूमि जिनके नाम हैं. संस्थागत भूमि धारक इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत् अथवा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने वाले किसान भी इस योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता. कृषि भूमि का उपयोग यदि कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है, तो ऐसे भूस्वामी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं.

दिसम्बर 2018 में शुरू की गई, इस योजना के तहत् प्रति वर्ष ₹ 2000-2000 की 3 किश्तें (वर्ष में कुल मिलाकर ₹ 6000-6000 की राशि) किसानों के खाते में जमा की जाती है. योजना की ₹ 2000 की पहली किश्त 2018-19 में 24 फरवरी, 2019 को पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए जमा कराई गई थी. बाद में 3-3 किश्तें 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में जमा कराने से 2023-24 के अन्त तक कुल 16 किश्तें पात्र किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी हैं तथा ₹ 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है.

संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. पिछले लेखा वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इस योजना के तहत् लाभ के पात्र नहीं हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना ई-केवाईसी कराना आवश्यक है.

●●●

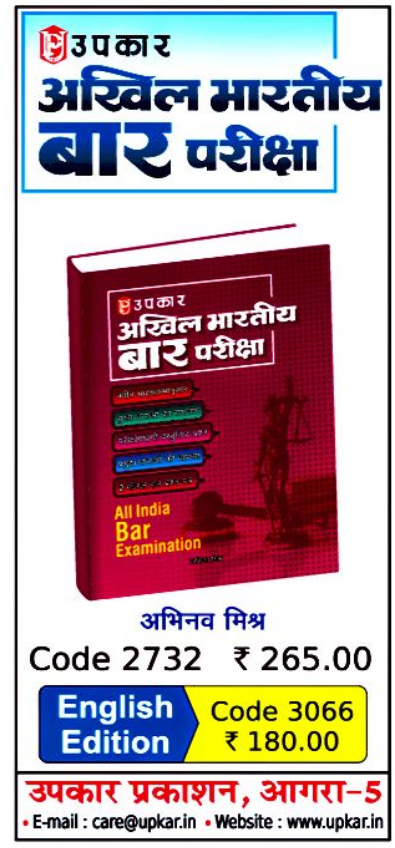

नवीनतम सामान्य ज्ञान

शब्द संक्षेप
(Abbreviation)

यूपीआई–(यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस)
UPI–Unified Payment Interface

व्याख्या–यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक पक्ष दूसरे को तुरन्त धन ट्रांसफर कर सकता है. पूर्णतः डिजिटल होने के कारण यूपीआई का उपयोग 24 घण्टे तथा सार्वजनिक अवकाश के दिन भी किया जा सकता है.

नियुक्तियाँ
(Appointments)

संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के चेयरमैन

इण्डियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के 1990 बैच के अधिकारी संजय कुमार जैन इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के नए चेयरमैन सह प्रबन्ध निदेशक फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. जनवरी 2021 में महेन्द्र प्रताप पाल के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त था. नवनियुक्त चेयरमैन संजय जैन अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि (31 दिसम्बर, 2026) अथवा अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे.

भारतीय मूल के डॉ. समीर शाह बीबीसी के नए चेयरमैन

भारतीय मूल के डॉ. समीर शाह बीबीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. 40 वर्ष से भी अधिक समय तक यूके ब्रॉडकास्टिंग से सम्बद्ध रहे डॉ. समीर शाह ने अपना यह कार्यभार 4 मार्च, 2024 से सँभाला है. इस पद पर इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा.

समीर शाह

वर्ष 2019 में ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ-II द्वारा **कमाण्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर** के रूप में सम्मानित 72 वर्षीय डॉ. समीर शाह इस पद को सँभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं.

लेफ्टि. जनरल उपेन्द्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के उप प्रमुख

भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग इन चीफ रहे लेफ्टि. जनरल उपेन्द्र द्विवेदी थल सेना के उप प्रमुख (Vice-Chief) फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. इस पद पर लेफ्टि. जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार का स्थान उन्होंने लिया है. लेफ्टि. जनरल सुचिन्द्र कुमार को अब उनके स्थान पर उत्तरी कमान का कमाण्डर बनाया गया है.

लेफ्टि. जनरल उपेन्द्र द्विवेदी

कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के 21 दिन बाद न्यायमूर्ति पी. एस. दिनेश कुमार सेवानिवृत्त

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत् रहे न्यायमूर्ति पी. एस. दिनेश कुमार इसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए थे. मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना यह कार्यभार 3 फरवरी, 2024 को ही उन्होंने सँभाला था, किन्तु 21 दिन बाद ही 24 फरवरी को वह सेवानिवृत्त हो गए. इस प्रकार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पी. एस. दिनेश कुमार का कार्यकाल 21 दिन ही रहा.

भारत की किसी उच्च न्यायालय में सबसे कम कार्यकाल न्यायमूर्ति संजय यादव का रहा है, जो जून 2021 में केवल 15 दिन तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे.

न्यायमूर्ति अरुण भंसाली उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश

राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल ने 5 फरवरी, 2024 को मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में आयोजित ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई. इस पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान न्यायमूर्ति भंसाली ने लिया है.

न्यायमूर्ति मणिन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति मणिन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. इस पद पर अपना यह कार्यभार 6 फरवरी, 2024 को उन्होंने सँभाला है. इस नियुक्ति से पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में ही वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे.

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश

उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार 7 फरवरी, 2024 से सँभाला है. इस नियुक्ति से पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे.

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन मेघालय उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन अब मेघालय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. राज्यपाल फागू चौहान ने 11 फरवरी, 2024 को शिलाँग में आयोजित संक्षिप्त समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई.

न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गौहाटी उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गौहाटी उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं. इस पद पर अपना यह कार्यभार 5 फरवरी, 2024 को उन्होंने संभाला है. इस नियुक्ति से पूर्व वह राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे. गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संदीप मेहता जिन्हें अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है, का स्थान उन्होंने लिया है.

न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार 4 फरवरी, 2024 से सँभाला है. इस नियुक्ति से पूर्व वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे.

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रितु बाहरी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं. वैसे देश में वर्तमान में वह दूसरी मुख्य न्यायाधीश हैं. वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय में भी एक महिला न्यायाधीश (न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल) मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत् हैं.

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य व गीतकार गुलजार को संयुक्त रूप से 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार

साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च (58वाँ) ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए संस्कृत भाषा एवं वेद-पुराण के प्रकांड विद्वान् जगद्गुरु रामभद्राचार्य व गीतकार गुलजार (पूरा नाम सम्पूर्ण सिंह कालरा) को संयुक्त रूप से दिया जाएगा. भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस आशय की घोषणा 17 फरवरी, 2024 को की गई. रामानंद सम्प्रदाय के वर्तमान चार जगद्गुरुओं में से एक स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए तथा गीतकार गुलजार को उर्दू भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है.

- *संस्कृत भाषा के लिए दूसरी बार तथा उर्दू के लिए पाँचवी बार यह पुरस्कार दिया गया है.*
- *भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भाषा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, किन्तु एक बार 2018 का यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए भी अमिताभ घोष को दिया जा चुका है.*
- *1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी एकल कृति के लिए ही दिया जाता था, किन्तु उसके पश्चात् लेखक के किसी भाषा में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है.*
- *साहित्य के क्षेत्र में देश के इस सर्वोच्च पुरस्कार के तहत् बागदेवी की प्रतिभा व प्रशस्ति-पत्र के साथ ₹ 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है.*

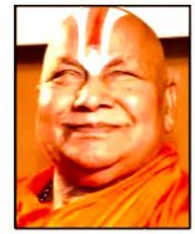

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य

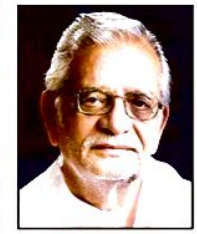

गीतकार गुलजार (सम्पूर्ण सिंह कालरा)

वर्ष 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रामभद्राचार्य दृष्टिहीन होते हुए भी प्रख्यात विद्वान्, शिक्षाविद् एवं दार्शनिक हैं तथा 100 से अधिक पुस्तकों व ग्रंथों की रचना उन्होंने की है जिनमें चार महाकाव्य व रामचरित मानस पर हिन्दी टीका आदि शामिल हैं. 1988 से वह रामानंद सम्प्रदाय के जगद्गुरू हैं तथा 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.

वर्ष 2023 के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे साहित्यकार सम्पूर्ण सिंह कालरा 'गुलजार' नाम से प्रसिद्ध हैं. हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ-साथ वह कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार और प्रसिद्ध शायर भी हैं. उनकी रचनाएं मुख्य रूप से हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में हैं. बेहतरीन शायरों में से एक माने गुलजार को इससे पूर्व 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2009 में फिल्म 'स्लमडाग मिलियनेयर' में उनके लिखे गीत 'जय हो' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है. इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार

वर्ष	पुरस्कार विजेता	वर्ष	पुरस्कार विजेता
1965	जी. शंकर कुरूप (मलयालम)	1994	प्रो. यू. आर. अनंतमूर्ति (कन्नड़)
1966	ताराशंकर बंध्योपाध्याय (बांग्ला)	1995	एम. टी. वासुदेवन नायर (मलयालम)
1967	(1) के. वी. पुटप्पा (कन्नड़)	1996	श्रीमती महाश्वेता देवी (बांग्ला)
	(2) उमाशंकर जोशी (गुजराती)	1997	अली सरदार जाफरी (उर्दू)
1968	सुमित्रानन्दन पन्त (हिन्दी)	1998	गिरीश कर्नाड (कन्नड़)
1969	फिराक गोरखपुरी (उर्दू)	1999	(1) निर्मल वर्मा (हिन्दी)
1970	विश्वनाथ सत्यनारायण (तेलुगू)		(2) गुरदयाल सिंह (पंजाबी)
1971	विष्णु डे (बांग्ला)	2000	इन्दिरा गोस्वामी (असमिया)
1972	रामधारी सिंह 'दिनकर' (हिन्दी)	2001	राजेन्द्र केशवलाल (गुजराती)
1973	(1) डॉ. दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे (कन्नड़)	2002	डी. जयकांतन (तमिल)
	(2) गोपीनाथ मोहन्ती (ओडिया)	2003	विंदा करंदीकर (मराठी)
1974	विष्णु सखा खाण्डेकर (मराठी)	2004	रहमान राही (कश्मीरी)
1975	ए. वी. अकिलन्दम (तमिल)	2005	कुँवर नारायण (हिन्दी)
1976	श्रीमती आशापूर्णा देवी (बांग्ला)	2006	(1) रवीन्द्र केलकर (कोंकणी),
1977	शिवराम करन्थ (कन्नड़)		(2) सत्यव्रत शास्त्री (संस्कृत)
1978	एच. एस. अज्ञेय (हिन्दी)	2007	ओ. एन. वी कुरूप (मलयालम)
1979	डॉ. वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य (असमिया)	2008	अखलाख मोहम्मद खान (शहरयार)
1980	एस. के. पोट्टेकट (मलयालम)	2009	(1) अमरकांत (हिन्दी) (2) श्री लाल शुक्ला (हिन्दी)
1981	अमृता प्रीतम (पंजाबी)	2010	चन्द्रशेखर कंवर (कन्नड़)
1982	महादेवी वर्मा (हिन्दी)	2011	प्रतिभा राय (ओडिया)
1983	मस्ति वेंकटेश आयंगर (कन्नड़)	2012	डॉ. रावुरी भारद्वाज (तेलुगू)
1984	तक्षी शिवशंकर पिल्लई (मलयालम)	2013	प्रो. केदारनाथ सिंह (हिन्दी)
1985	पन्नालाल पटेल (गुजराती)	2014	भालचन्द्र नेमाड़े (मराठी)
1986	सच्चिदानन्द राउतराय (ओडिया)	2015	रघुवीर चौधरी (गुजराती)
1987	वि. वा. शिरवाडकर (मराठी)	2016	शंख घोष (बांग्ला)
1988	सी. नारायण रेड्डी (तेलुगू)	2017	कृष्णा सोबती (हिन्दी)
1989	कुर्रतुल एन. हैदर (उर्दू)	2018	अमिताव घोष (अंग्रेजी)
1990	विनायक कृष्ण गोकाक (कन्नड़)	2019	अक्कीथम अच्युतम नम्बूदिरी (मलयालम)
1991	सुभाष मुखोपाध्याय (बांग्ला)	2021	नीलमणि फूकन (असमिया)
1992	नरेश मेहता (हिन्दी)	2022	दामोदर मॉउलो (कोंकणी)
1993	डॉ. सीताकान्त महापात्र (ओडिया)	2023	स्वामी रामभद्राचार्य (संस्कृत) व गुलजार (सम्पूर्ण सिंह कालरा) (उर्दू)

बाफ्टा फिल्म पुरस्कार (2024)

ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एण्ड टेलीविजन आर्ट्स (BAFTA) के वर्ष 2024 के (77वें) पुरस्कारों (बाफ्टा पुरस्कारों) का वितरण लन्दन के रॉयल एलबर्ट हॉल में 18 फरवरी, 2024 को किया गया.

- क्रिस्टोफर नोलन (Christopher Nolan) द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर (Oppenheimer) की इस वर्ष इन पुरस्कारों में धूम रही. सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत् इसे मिले.
  इस फिल्म को सर्वाधिक 13 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था.
- दूसरे स्थान पर 5 पुरस्कार योरगोस लैंथिमोस द्वारा निर्देशित फिल्म पूअर थिंग्स (Poor Things) को प्राप्त हुए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अतिरिक्त कास्ट्यूम मेक अप प्रोडक्शन डिजाइन व विजुअल इफैक्ट के पुरस्कार इनमें शामिल हैं.
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म 'ओपेनहाइमर को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसी फिल्म के निर्देशन के लिए क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया.

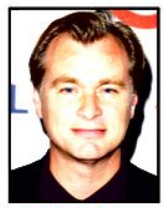
क्रिस्टोफर नोलन

- फिल्म ओपेनहाइमर में भूमिका के लिए आयरिश अभिनेता सिलियन मर्फी (Cillian Murphy) को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा फिल्म पूअर थिंग्स में बेल्ला बैक्स्टर की भूमिका के लिए अमरीकी अभिनेत्री एम्मा स्टोन (Emma Stone) को मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत् दिया गया.

एम्मा स्टोन

- ब्रिटिश सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार गुयाना मूल की ब्रिटिश क्यूरेटर जून गिवानी (June Givanni) को तथा बाफ्टा फेलोशिप ब्रिटिश अभिनेत्री एवं निर्देशिका सामंथा जेन मॉर्टन को दिया गया (बाफ्टा की फेलोशिप बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान है).

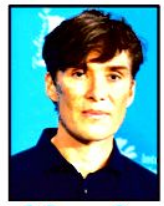
सिलियन मर्फी

इन पुरस्कारों के तहत् प्रमुख पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है—

सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर—क्रिस्टोफर नोलन (फिल्म—ओपेनहाइमर)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म—ओपेनहाइमर (निर्देशक—क्रिस्टोफर नोलन)

सर्वश्रेष्ठ गैर-अंग्रेजी फीचर फिल्म—द जोन ऑफ इन्ट्रेस्ट (जर्मन, पोलिश फिल्म)

मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री—एम्मा स्टोन (फिल्म—पूअर थिंग्स)

मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता—सिलियन मर्फी (ओपेनहाइमर)

सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता—रॉबर्ट डाउनी जूनियर (ओपेनहाइमर)

सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री—डा वाइन जॉय राडोल्फ (द होल्डोवर्स)

सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग—ओपेनहाइमर

सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी—ओपेनहाइमर

सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन—पूअर थिंग्स

सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन—पूअर थिंग्स हॉली वेडिंगटन

सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग—द होल्डोबर्स

सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीनप्ले—एनाटोमी ऑफ ए फॉल

सर्वश्रेष्ठ एडेप्टेड स्क्रीनप्ले—अमरीकन फिक्शन—कॉर्ड जेफरसन

सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंटरी—20 डेज इन मारियुपूल

सर्वश्रेष्ठ एनीमेटेड फिल्म—द बॉय एण्ड द हेरोन

बाफ्टा फैलोशिप—सैंडी पॉवेल (ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिजाइन)

साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक उच्चायुक्त

पाकिस्तान ने वरिष्ठ राजनयिक साद अहमद वाराइच (Saad Ahmed Warraich) को भारत में अपने उच्चायोग में नया प्रभारी **चार्ज डी'एफेयर** (Charge D'Affair) नियुक्त किया है. अपना यह कार्यभार 26 फरवरी, 2024 में उन्होंने सँभाला है. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के दूत रह चुके साद अहमद ने इस पद पर एजाज खान का स्थान लिया है.

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने भारत में उच्चायुक्त के दर्जे को कम कर दिया था. तब से दोनों देशों में उच्चायोगों का प्रभार उच्चायुक्तों के स्थान पर **चार्ज डी'एफेयर्स** ने ही सँभाला हुआ है.

अगस्त 2019 तक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया थे. उसके पश्चात् पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग का प्रभार भी चार्ज डी'एफेयर ने ही सँभाला हुआ है. भारतीय विदेश सेवा की गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का चार्ज डी'एफेयर अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया था.

आलोक कुमार विश्व हिन्दू परिषद् के नए अध्यक्ष

विश्व हिन्दू परिषद् में कार्याध्यक्ष रहे आलोक कुमार को अब इस संगठन का अध्यक्ष ने केन्द्रीय प्रबन्ध समिति की अयोध्या में फरवरी 2024 में सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया है. इस पद पर डॉ. आर.एन. सिंह, जो 2021 से अध्यक्ष थे, का स्थान श्री आलोक कुमार ने लिया है.

विश्व हिन्दू परिषद् में अध्यक्ष का चुनाव 3-3 वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है.

न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर को भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाले सर्वोच्च संख्या निकाय लोकपाल का अध्यक्ष फरवरी 2024 में नियुक्त किया है. न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष के मई 2022 में अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् लोकपाल प्रमुख का पद रिक्त था तथा लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यह कार्यभार सँभाले हुए थे. न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष देश के पहले ही लोकपाल थे.

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर

राष्ट्रपति भवन से 27 फरवरी, 2024 को जारी विज्ञप्ति में न्यायमूर्ति खानविलकर की लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के साथ ही उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतु राज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया है. वहीं, सुशील चन्द्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की को गैर-न्यायिक लोकपाल नियुक्त किया गया है.

लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य (4 न्यायिक व 4 गैर-न्यायिक) हो सकते हैं.

निधन
(Death)

फली सैम नरीमन

प्रख्यात विधि विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता फली सैम नरीमन (Fali Sam Nariman) का 95 वर्ष की आयु में 21 फरवरी,

2024 को नई दिल्ली में निधन हो गया. रंगून (अब यांगून) में एक फारसी परिवार में जन्मे नरीमन 1942 में जब 12 वर्ष के थे, तभी जापानी आक्रमण के कारण नरीमन का परिवार भारत आ बसा था. यहाँ बम्बई उच्च न्यायालय में 1950 में वकालत उन्होंने शुरू की थी. बाद में सर्वोच्च न्यायालय से वह जुड़े. 7 दशकों से भी अधिक समय तक वकालत से जुड़े रहे फली ने राष्ट्रीय महत्व के कई ऐतिहासिक मामलों में भारतीय न्यायपालिका में 'भीष्म पितामह' के रूप में ख्याति उन्होंने अर्जित की. मई 1972 में भारत के अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल वह नियुक्त किए गए थे, किन्तु 1975 में आपातकाल लागू होने के एक दिन बाद ही त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था. 1991 में पद्म भूषण से तथा 2007 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था.

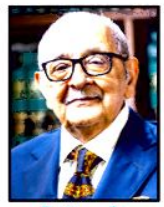
फली सैम नरीमन

दो दशक तक वह बार एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष रहे थे तथा 1999 में उन्हें राज्य सभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था. उनके द्वारा रचित पुस्तकों में बिफोर मेमोरी फेड्स (Before Memory Fades) (आत्म कथा), गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट (God Save the Supreme Court), द स्टेट ऑफ द नेशन (The State of the Nation) व इंडियाज लीगल सिस्टम : कैन इट बी सेव्ड आदि शामिल हैं.

हेज गींगोब (Hage Geingob)

नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गींगोब का 4 फरवरी, 2024 को 82 वर्ष की आयु में राजधानी विंडहोक में कैंसर से निधन हो गया. गींगोब 2015 से नामीबिया के राष्ट्रपति थे तथा उससे पूर्व 1990 से 2002 तक तथा 2012 से 2015 तक वह प्रधानमंत्री रहे थे. वर्ष 2017 से सत्तारूढ़ स्वापो (SWAPO) पार्टी के अध्यक्ष भी वह थे.

सेबेस्टियन पिनेरा (Sebastian Pinera)

चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का 74 वर्ष की आयु में 6 फरवरी, 2024 को लैगो रैंको (Lago Ranco) में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया. 2010–14 तथा 2018–22 के दौरान चिली के राष्ट्रपति वह रहे थे.

एलेक्सी नवलनी

रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) का रूस के आर्कटिक क्षेत्र में एक जेल में 16 फरवरी, 2024 को रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया. 47 वर्षीय नवलनी को रूस विरोधी कार्य करने, भ्रष्टाचार व कुछ अन्य मामलों में 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. पेशे से वकील नवलनी पुतिन को लोकतंत्र विरोधी बताते थे तथा रूस में होने वाले चुनावों को फर्जी बताते थे. रूसी अधिकारी नवलनी को अमरीकी एजेंसी सीआईए की कठपुतली बताते थे.

एलेक्सी नवलनी

अगस्त 2020 में नवलनी को चाय के जरिए जहर रूस में दिया गया था, किन्तु जर्मनी में हुए इलाज के बाद वह स्वस्थ होकर 2021 में रूस लौट आए थे. जर्मनी से वापस आते ही रूस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

दत्ताजीराव गायकवाड़

भारत के सर्वाधिक उम्र के टेस्ट खिलाड़ी दत्ताजीराव गायकवाड़ का 95 वर्ष की आयु में वड़ोदरा में 13 फरवरी, 2024 को निधन हो गया. 1952–61 के दौरान कुल 11 टेस्ट मैच उन्होंने भारत के लिए खेले थे. 1959 में इंगलैण्ड के दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान भी वह रहे थे. उनके पुत्र अंशुमान गायकवाड़ भी टेस्ट क्रिकेटर रहने के बाद भारतीय टीम के कोच भी रहे थे.

दत्ताजीराव गायकवाड़

उषा किरण खान

हिन्दी व मैथिली की प्रसिद्ध लेखिका प्रो. उषा किरण खान का 78 वर्ष की आयु में पटना में 11 फरवरी, 2024 को निधन हो गया. हिन्दी एवं मैथिली में दर्जनों पुस्तकों की रचयिता उषा किरण खान साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिन्दी सेवी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान व विद्या निवास पुरस्कार आदि पुरस्कारों के अतिरिक्त पद्मश्री (2015) से भी सम्मानित थीं.

जैन मुनि आचार्य विद्यासागर

जैन समाज के वर्तमान समय के वर्धमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर ने 18 फरवरी, 2024 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चन्द्रगिरि तीर्थ पर संल्लेखना कर देह त्याग दी. (संल्लेखना जैन धर्म में एक प्रथा है, जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग किया जाता है.) वर्तमान में जैन धर्म के सबसे बड़े एवं उच्च प्रतिष्ठित गुरु आचार्य विद्यासागर ने 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी. उन्होंने आजीवन नमक-चीनी, दूध-दही, हरी सब्जी व सूखे मेवों का सेवन नहीं किया था. यहाँ तक कि पानी भी दिन भर में एक ही बार वह पीते थे. उन्होंने सबसे अधिक 505 मुनियों को दीक्षा दी थी. उनके निधन से देश-विदेश में जैन समाज में शोक व्याप्त हो गया.

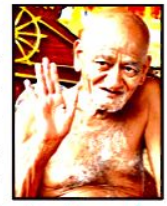
जैन मुनि आचार्य विद्यासागर

उनके देह त्याग पर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक रहा.

अमीन सयानी

बीते दशकों में रेडियो कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जबर्दस्त ख्याति प्राप्त अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में 21 फरवरी, 2024 को मुम्बई में निर्धन हो गया. अपनी आवाज के जादू से विनाका गीत माला कार्यक्रम से विशेष ख्याति उन्होंने प्राप्त की थी. 1952 में शुरू हुए इस कार्यक्रम को 4 दशक तक उन्होंने प्रस्तुत किया. इसके अतिरिक्त फैशन शो, फिल्म समारोहों व पुरस्कार समारोहों आदि में भी अपनी मखमली आवाज से कार्यक्रमों का संचालन उन्होंने किया. अपने कार्य क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित अमीन सयानी को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

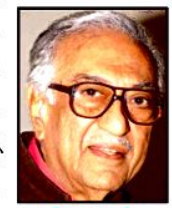
अमीन सयानी

केल्विन किप्टम

मैराथन दौड़ में विश्व रिकॉर्डधारी कीनियाई धावक केल्विन किप्टम (Kelvin Kiptum) का केवल 24 वर्ष की आयु में नैरोबी में एक सड़क दुर्घटना में 11 फरवरी, 2024 को निधन हो गया. किप्टम के साथ उनके कोच की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई. **अनेक मैराथन दौड़ों के विजेता किप्टम ने 8 अक्टूबर, 2023 को ही शिकागो मैराथन 2 घण्टे व 35 सेकण्ड में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था.**

केल्विन किप्टम

मनोहर जोशी

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी का 23 फरवरी, 2024 को मुम्बई में निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. शिव सेना के नेता मनोहर जोशी 1995–1999 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 2002–2004 के दौरान लोक सभा के अध्यक्ष रहे थे. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी वह रहे थे.

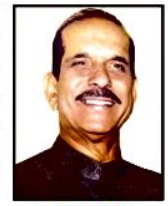
मनोहर जोशी

पंकज उधास

जाने माने गज़ल गायक पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी, 2024 को मुम्बई में निधन हो गया. उनकी पहली गजल एलबम आहट 1980 में जारी हुई थी जिसके पश्चात् 50 से अधिक एलबम उनकी जारी हुई. चिट्ठी आई है·····', ना कजरे की धार·····', चांदी जैसा रंग है तेरा ····· आदि गज़लों को आवाज देकर भारी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की थी. कुछ हिन्दी फिल्मों में भी गीतों के लिए पार्श्व गायन उन्होंने किया था वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.

पंकज उधास

पुस्तकें (Books)

ब्रेकिंग द मोल्ड : रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर (Breaking the Mould : Reimagining India's Economic Future)
—रघुराम जी. राजन व रोहित लांबा

11 रूल्स फॉर लाइफ (11 Rules for Life)
—चेतन भगत

फोर्टीन डेज़ (Fourteen Days)
—मार्गरेट एटवुड

कीप योअर फ्रेंड्स क्लोज़ (Keep Your Friends Close)
—लीह कोनेन

वर्ष/दिवस/सप्ताह (Year/Days/Week)

वर्ष 2024 भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित (Year of Naval Civilians)

भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों (Naval Civilians) के प्रशासन, दक्षता व कल्याण में सुधार के लिए चालू वर्ष 2024 को 'नौसेना नागरिकों का वर्ष' (Year of Naval Civilians) घोषित किया है. इस सन्दर्भ में भारतीय नौसेना की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि नौसेना के नागरिक कार्मिक भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं तथा सभी क्षेत्रों में इसकी परिचालन प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. वर्ष 2024 को उनके लिए समर्पित वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ताकि उनके प्रशासन, प्रशिक्षण व कल्याण आदि को बढ़ावा दिया जाए.

फरवरी 2024

2 फरवरी—वर्ल्ड वेटलैण्ड्स डे

4 फरवरी—श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस

4 फरवरी—विश्व कैंसर दिवस

10 फरवरी—नेशनल डिवर्मिंग डे

10 फरवरी—विश्व दाल दिवस (World Pulses Day)

(10 फरवरी को प्रतिदिन विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में 20 दिसम्बर, 2018 को किया गया था. तदनुरूप ऐसा पहला दिवस 10 फरवरी, 2019 को मनाया गया था.)

11 फरवरी—विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं व बालिकाओं का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science)

(प्रति वर्ष 11 फरवरी को इस रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसम्बर, 2015 को पारित किया गया था.)

12 फरवरी—राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस

13 फरवरी—विश्व रेडियो दिवस

(एक माध्यम के रूप में रेडियो की महत्ता को स्वीकार करते हुए 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय यूनेस्को (UNESCO) के 36वें सत्र में 3 नवम्बर, 2011 को किया गया था.)

14 फरवरी—वैलेंटाइन दिवस

20 फरवरी—संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस.

(सामाजिक-भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था.)

20 फरवरी—अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के 'स्टेटहुड दिवस'

मिजोरम, जो पहले असम का एक जिला था, को 1972 में केन्द्रशासित क्षेत्र बनाया गया था. बाद में 20 फरवरी, 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था.

अरुणाचल प्रदेश भी पहले केन्द्रशासित क्षेत्र था तथा पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 20 फरवरी, 1987 को दिया गया था.

21 फरवरी—अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

(बांग्लादेश के भाषा आन्दोलन दिवस 21 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति यूनेस्को द्वारा 17 नवम्बर, 1999 को प्रदान की गई.)

24 फरवरी—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस

(24 फरवरी, 1944 को सेंट्रल एक्साइसेज एण्ड साल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है.)

28 फरवरी—राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

(प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सी. वी. रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध 'रमन प्रभाव' जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया, की खोज 28 फरवरी, 1928 को की गई थी. इसी उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है.)

महोत्सव (Festivals)

आदि महोत्सव (2024)

राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव (2024), जिसे आदि महोत्सव के नाम से प्रायः जाना जाता है, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 10–18 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (Tribal Cooperative marketing Development Federation of India—TRIFED) द्वारा प्रति वर्ष आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को किया.

आदिवासी व जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देने तथा उनके खान-पान हस्तशिल्प व हस्तकला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनके उत्पादों के स्टॉल महोत्सव में लगाए जाते हैं. इस वर्ष 300 से अधिक स्टॉल आदि महोत्सव (2024) में लगाए गए थे.

10 फरवरी को महोत्सव में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में ही जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जन जातियों के लिए उद्यम पूँजी निधि (Venture Capital Fund for Scheduled Tribes—VSF-ST) की शुरूआत भी की.

विविध (Miscellaneous)

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो

विविध प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (2024) का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 1–3 फरवरी, 2024 को हुआ. देश-विदेश की 800 से अधिक कम्पनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया. ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कम्पोनेंट्स के अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, साइकिल्स व ई-बाइक्स, बैटरीज व कंस्ट्रक्शन से सम्बन्धित उपकरण आदि उत्पाद इनमें शामिल थे.

आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट

गौड़ीय मिशन, जिसने वैष्णव सम्प्रदाय के मौलिक सिद्धान्तों को संरक्षित करने व उनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर स्मृति उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में भारत मंडपम में 8 फरवरी, 2024 को किया गया. गौड़ीय मिशन के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस स्मृति उत्सव में स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जारी किया.

भारत टेक्स–2024

भारतीय टैक्सटाइल उद्योग की अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में 26–29 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. 11 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ द्वारा आयोजित एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया. 1100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों ने दो स्थानों भारत मंडपम व यशोभूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया.

सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला (2024)

सांस्कृतिक विविधता, हस्तशिल्प एवं कला का प्रसिद्ध (37वाँ सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा में फरीदाबाद में 2–18 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर के साथ द्वीप प्रज्ज्वलित कर इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी को किया.

सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करतीं राष्ट्रपति

इस वर्ष मेले का थीम राज्य गुजरात था तथा मेले में भागीदार (Partner) देश का दर्जा तंजानिया को प्रदान किया गया था.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (2024)

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (National Book Trust—NBT) व भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में (51वाँ) विश्व पुस्तक मेला 10–18 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. प्रगति मैदान में सम्पन्न इस मेले का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया. भारत के अतिरिक्त 14 अन्य देशों के प्रकाशकों ने भी अपने स्टॉल मेले में लगाए. सऊदी अरब को मेले में विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था. इस वर्ष के विश्व पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत : एक जीवंत परम्परा (Multi Lingual India : A Living Tradition) थी.

●●●

पाँच वर्ष के अन्तराल के पश्चात् भारतीय वायु सेना का युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024

भारतीय वायु सेना ने अपनी आक्रामक एवं मारक क्षमता का विशाल प्रदर्शन राजस्थान में जैसलमेर में 17 फरवरी, 2024 को अपने युद्धाभ्यास वायुशक्ति 24 के तहत् किया. इस वर्ष के इस अभ्यास का थीम 'आकाश से बिजली का प्रहार' (Lightning Strike from the Sky) था. वायु सेना के राफेल एसयू 30, एमकेआई, मिग-29, मिराज-2000, तेजस व हॉक सहित 120 से अधिक विमानों ने दिन के साथ-साथ रात में भी सटीक निशाने लगाकर अपनी आक्रामक शक्ति का प्रदर्शन इस युद्धाभ्यास के तहत् किया. अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने भी जमीनी लक्ष्यों पर हमले का प्रदर्शन इस अभ्यास के तहत् किया, जबकि वायु सेना के लम्बी दूरी के एक मानव रहित ड्रोन ने भी सटीक निशाना लगाते हुए एक नकली दुश्मन रडार साइट को नष्ट किया. दो घण्टे की छोटी-सी अवधि में 2 वर्ग किमी क्षेत्र में लगभग 50 टन आयुध (Ordnance) इस प्रदर्शन के दौरान गिराया गया.

एक लड़ाकू विमान

वायु शक्ति भारतीय वायु सेना का 3-3 वर्ष के अन्तराल पर होने वाला प्रदर्शन है ऐसा पिछला वायु शक्ति प्रदर्शन 5 वर्ष पूर्व फरवरी 2019 में किया गया था. उसके पश्चात् रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच 2022 में यह स्थगित कर दिया गया था.

मिलन 24 : भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास

*भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास **मिलन 2024** विशाखापट्टनम में 19–27 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. 9 दिन के इस नौसैनिक अभ्यास में अमरीका, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, द. कोरिया, वियतनाम मलेशिया व इंडोनेशिया सहित 50 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल थीं मित्र देशों के 15 युद्धपोत व एक नौसैनिक पेट्रोलिंग विमान इसमें शामिल थे, जबकि भारत के दोनों विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत व विक्रमादित्य सहित लगभग 20 युद्धपोतों व लगभग 50 विमानों ने इसमें हिस्सा लिया.*

- *मिलन-24 का बन्दरगाह चरण 19–23 फरवरी को व समुद्री चरण 24–27 फरवरी, 2024 को सम्पन्न हुआ. बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा सतह रोधी युद्ध संचालन इसमें शामिल थे.*
- *मिलन भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है जिसकी शुरूआत 1995 में केवल चार देशों—इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका व थाइलैण्ड के साथ हुआ था.*
- *ऐसा पिछला 11वाँ आयोजन 25 फरवरी-4 मार्च, 2022 को विशाखापट्टनम में ही हुआ था जिसमें 39 देशों ने भाग लिया था.*

धर्म गार्जियन 24 : भारत व जापान के सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास

*भारतीय सेना व जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच दो सप्ताह के सैन्य अभ्यास **धर्म गार्जियन** का पाँचवाँ संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी, 2024 को प्रारम्भ हुआ है. इस संयुक्त अभ्यास में भारत की सैन्य टुकड़ी में राजपूताना राइफल्स के 40 जवान शामिल हैं. इतने ही जवान जापान की 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी में थे.*

धर्म गार्जियन भारत व जापान के सैन्य बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्याभ्यास है. वर्ष 2018 में शुरू हुए इस सैन्याभ्यास आयोजन वैकल्पिक रूप से भारत व जापान में किया जाता है. धर्म गार्जियन अभ्यास का पिछला चौथा संस्करण जापान में शिगा प्रान्त में 17 फरवरी-2 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुआ था.

कर्पूरी ठाकुर व लाल कृष्ण आडवाणी के पश्चात् अब दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह व पी.वी. नरसिंह राव तथा हरित क्रांति के जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर व देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति भवन से क्रमशः 23 जनवरी व 3 फरवरी, 2024 को जारी विज्ञप्तियों में की गई थी. इसके एक सप्ताह के भीतर 9 फरवरी, 2024 को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों–चौधरी चरण सिंह व पी.वी. नरसिंह राव तथा देश में हरित क्रांति जनक कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. इन तीनों को देश का यह सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत प्रदान करने की घोषणा की गई है. इन्हें शामिल करते हुए देश में भारत रत्न से सम्मानितों की कुल संख्या अब 53 हो गई है.

चौधरी चरण सिंह

चौधरी चरण सिंह

पी.वी. नरसिंह राव

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गाँव में एक किसान परिवार में 23 दिसम्बर, 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं कानून की शिक्षा प्राप्त कर वकालत व्यवसाय में लग गए तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे. कांग्रेस में शामिल रहे चरण सिंह पहली बार 1937 में विधायक (संयुक्त प्रांत) बने. उत्तर प्रदेश में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यभार सँभालने के पश्चात् 1967-68 तथा 1970 के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह बाद में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में जनवरी-जुलाई 1979 के दौरान वित्त मंत्री व उप-प्रधानमंत्री रहे. जुलाई 1979 से अगस्त 1979 तक थोड़े समय तक प्रधानमंत्री वह रहे. इस दौरान पहले कांग्रेस में वह रहे तथा बाद में भारतीय क्रांति दल व लोक दल नाम से अपने दलों का गठन उन्होंने किया. इस बीच जनता पार्टी में भी वह रहे. **किसी भी दल में रहते हुए तथा किसी भी पद पर रहते हुए किसानों के हितों के लिए वह समर्पित रहे. इसलिए उनके जन्म दिवस 23 दिसम्बर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है.** 84 वर्ष की आयु में इनका निधन 29 मई, 1987 को हुआ. किसान हितों के लिए इनके संघर्ष एवं समर्पण को देखते हुए नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल को किसान घाट नाम दिया गया है. उनके निधन के पश्चात् उनकी तीसरी पुण्य तिथि 29 मई, 1990 को उनकी स्मृति में एक विशेष स्मारक डाक टिकट सरकार द्वारा जारी किया गया था तथा अब मरणोपरान्त उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.

पी. वी. नरसिंह राव

राष्ट्रपति भवन की 9 फरवरी, 2024 की विज्ञप्ति के तहत् भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव हैं. आन्ध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता श्री नरसिंह राव 1957–77 के दौरान आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे थे. इस दौरान 1971–73 के दौरान मुख्यमंत्री भी वह रहे. 1977 के बाद लोक सभा के सदस्य रहते हुए इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकारों में गृह मंत्री व विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर वह रहे. **1991–96 की अवधि में प्रधानमंत्री का पद ऐसे समय में उन्होंने सँभाला था जब देश गम्भीर आर्थिक संकट के दौर में था. ऐसे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी सरकार में वित्त मंत्री बना कर आर्थिक सुधारों का सिलसिला उन्होंने शुरू कराया. उनकी सरकार ने ही उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू कर अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.** उनकी इन्हीं नीतियों के कारण देश में आर्थिक सुधारों का जनक उन्हें ही डॉ. मनमोहन सिंह ने करार दिया. 28 जून, 1921 को जन्मे पी.वी. नरसिंह राव का निधन 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में 23 दिसम्बर, 2004 को हुआ था.

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन

भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं. 1960 के दशक में खाद्य संकट के दौर से गुजर रहे भारत में मेक्सिको के बीजों को पंजाब के बीजों की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर अधिक उत्पादन देने वाले बीज इन्होंने विकसित किए. **1967 में 'पद्मश्री', 1972 में पद्म भूषण व 1989 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था.** 7 अगस्त, 1925 को कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन ने 1979 में कृषि मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया था. वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था. 2007–13 के दौरान राज्य सभा के मनोनीत सदस्य वह रहे थे. इनकी अकादमिक उपलब्धियों को देखते हुए देश-विदेश के 80 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी. **1971 में रेमन मैगसेस पुरस्कार तथा 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था.** पिछले ही वर्ष 28 सितम्बर, 2023 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था.

वैज्ञानिक शोध हेतु घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार (2023)

के.के. बिड़ला फाउण्डेशन का वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज की प्रोफेसर अदिति सेन को दिया जाएगा. फाउण्डेशन की 19 फरवरी, 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार प्रो. सेन ने भौतिकी विज्ञान में क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस पुरस्कार के तहत् प्रो. सेन को ₹ 5 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी. के. के. बिड़ला फाउण्डेशन का यह पुरस्कार भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है. प्रो. अदिति सेन यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं.

दर्ज की जो भारतीय टीम की रनों की दृष्टि से टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी विजय है.

राजकोट मैच में ही भारत के यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में 12 छक्के लगाकर टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्कों के पाकिस्तान के वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की. यशस्वी जायसवाल ने लगातार दो (विशाखापट्टनम व राजकोट) टेस्ट मैचों में दोहरे शतक भी बनाए.

महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज गति से दोहरा शतक : आस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैण्ड का नया विश्व रिकॉर्ड

आस्ट्रेलिया की अनाबेल सदरलैण्ड ने 16 फरवरी, 2024 में पर्थ में द. अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में 248 गेंदों पर ही दोहरा शतक बनाकर महिला टेस्ट मैच में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस मामले में अपने ही देश की केरेन रोल्टन का रिकॉर्ड 22 वर्षीय अनाबेल ने भंग किया. केरेन रोल्टन ने 2001 में लीड्स में इंगलैण्ड के विरुद्ध 306 गेदों पर दोहरा शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया था जिसे अनाबेल सदरलैण्ड ने 16 फरवरी, 2024 को भंग किया.

नई दिल्ली मैराथन (2024)

नई दिल्ली में 25 फरवरी, 2024 को सम्पन्न 9वीं अपोलो टायर्स नई दिल्ली मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग के एशियाई मैराथन के पूर्व विजेता सेना के गोपी थोनाकल व महिला वर्ग में अश्विनी मदान जाधव विजेता रहे. 2017 में भी इस दौड़ के विजेता रहे गोपी थोनाकल ने 42·195 किमी की यह दौड़ पूरी करने में 2 घण्टे 14 मिनट व 40 सेकण्ड लिए, जबकि अश्विनी मदान ने यह दौड़ 2 घण्टे 52 मिनट 25 सेकण्ड में पूरी की.

गोपी थोनाकल

पुरुष वर्ग में रेस जीतने के बावजूद गोपी पेरिस ओलम्पिक के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके. उसकी अर्हता के लिए समय 2:08:10 निर्धारित था. मैराथन दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी 2:12:00 का है, जोकि 1978 से शिवनाथ सिंह के नाम है.

25 फरवरी की नई दिल्ली मैराथन में श्रिनु बुगाथा व अक्षय सेनी पुरुषों में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. **(श्रिनु बुगाथा 2021 में नई दिल्ली मैराथन के विजेता रहे थे.)**

इस वर्ष की दौड़ में महिलाओं में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः थाकोर निरमाबेन भरतजी व दिव्यंका चौधरी ने प्राप्त किया.

विजेताओं के नाम एक दृष्टि में

फुल मैराथन (42·195 किमी)

पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
प्रथम गोपी थोनाकल (2:14:40)	अश्विनी मदान जाधव (2:52:25)
द्वितीय श्रिनु बुगाथा (2:14:41)	थाकोर निरमाबेन भरतजी (2:55:47)
तृतीय अक्षय सेनी (2:15:27)	दिव्यंका चौधरी (2:57:06)

एशियाई इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप (2024) : 4 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में भारत का स्थान

11वीं एशियाई इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन ईरान में तेहरान में

ज्योति याराजी

17–19 फरवरी, 2024 को हुआ. 4 स्वर्ण व 1 रजत सहित कुल 5 पदक जीतकर इसकी पदक तालिका में तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया. 8 स्वर्ण, 6 रजत व 1 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ चीन का शीर्ष स्थान पदक तालिका में रहा. दूसरा स्थान कजाखस्तान का रहा.

पदक तालिका : पहले 8 देश

रैंक	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1	चीन	8	6	1	15
2	कजाखस्तान	4	2	4	10
3	भारत	4	1	0	5
4	ईरान	3	5	7	15
5	जापान	3	4	1	8
6	किर्गिस्तान	1	2	1	4
7	कुवैत	1	0	0	1
8	ओमान	1	0	0	1

इस आयोजन में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक ज्योति याराजी (महिलाओं की 60 मी बाधा दौड़), हरमिलन बैंस (महिलाओं की 1500 मी), तेजिंदर पाल सिंह तूर (पुरुषों की शॉट पुट) व गुलबीर सिंह (पुरुषों की 3000 मी) ने जीते, जबकि रजत अंकिता ध्यानी ने **(महिलाओं की 3000 मी)** जीता. ज्योति याराजी व तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अपने यह स्वर्ण पदक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीते.

- पिछले वर्ष कजाखस्तान में इस आयोजन में भारत ने 1 स्वर्ण, 6 रजत व 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते थे.
- एशियाई इनडोर एथलेटिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2008 में दोहा में रहा था, जब 5 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत में प्राप्त किया था.

बैडमिंटन एशिया 4 टीम चैम्पियनशिप में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक

बैडमिंटन एशिया व बैंडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया के तत्वावधान में मलेशिया

में शाह आलम में 13–18 फरवरी, 2024 को सम्पन्न 2024 की बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा. स्वर्ण पदक के लिए थाइलैण्ड की टीम को फाइनल में 3–2 से पी.वी. सिंधु के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पराजित किया. तीसरा संयुक्त स्थान इंडोनेशिया व जापान का रहा.

फाइनल मुकाबले में थाइलैण्ड के विरुद्ध खिताबी विजय के लिए पी.वी. सिंधु पहले एकल मुकाबले में ट्रांसा जाली व गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी पहले युगल मुकाबले में विजयी रही, किन्तु अश्मिता चालिहा दूसरे एकल में तथा प्रिया कोंजेगबाम व श्रुति मिश्रा की जोड़ी दूसरे युगल में पराजित हुई. इससे मुकाबला 2-2 से बराबरी पर आ गया था. पाँचवें अन्तिम निर्णायक मुकाबले में हरियाणा की फरीदाबाद की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने मैच जीतकर भारत को 3–2 से खिताबी विजय दिला दी.

इस टूर्नामेन्ट में **पुरुष वर्ग** में खिताब चीन ने जीता जबकि मेजबान मलेशिया का दूसरा स्थान रहा. तीसरा संयुक्त स्थान जापान व द. कोरिया का रहा.

इस द्विवार्षिक टूर्नामेंट का आगामी आयोजक 2026 में होगा.

खेलकूद

क्रिकेट

अण्डर-19 आईसीसी विश्व कप (2024) : भारत को फाइनल में हरा कर आस्ट्रेलिया विजेता

द. अफ्रीका की मेजबानी में 19 जनवरी–11 फरवरी, 2024 को खेले गए अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) के (15वें) अंडर-19 विश्व कप का फाइनल मैच गत विजेता भारत व आस्ट्रेलिया की टीमों के बीच बेनोनी (Benoni) में खेला गया. भारतीय टीम को इस मुकाबले में 79 रनों से हराकर आस्ट्रेलिया ने चौथी बार यह कप जीतने में सफलता प्राप्त की. भारत ने सर्वाधिक 5 बार सीमित ओवरों (50-50 ओवरों) का यह टूर्नामेंट जीता है.

2-2 वर्ष के अन्तराल पर होने वाले इस टूर्नामेंट का आगामी आयोजन जिम्बाब्वे व नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में 2026 में होगा.

जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद् के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के महासचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद् (ACC) के अध्यक्ष जनवरी 2024 में पुनः निर्वाचित हुए हैं. उनका यह चुनाव परिषद् की इंडोनेशिया में बाली में 31 जनवरी, 2024 को सम्पन्न वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से हुआ.

जय शाह

भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के पुत्र जय शाह जनवरी 2021 से एशियाई क्रिकेट परिषद् के अध्यक्ष हैं.

टेस्ट क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन भारत के दूसरे गेंदबाज

भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट कॅरियर का 500वाँ विकेट 16 फरवरी, 2024 को राजकोट में इंगलैण्ड के विरुद्ध टेस्ट शृंखला के तीसरे मैच में लिया. **500 टेस्ट विकेट लेने वाले वह अनिल कुम्बले के बाद भारत के दूसरे तथा विश्व के नौवें गेंदबाज हैं** अश्विन ने यह उपलब्धि अपने कॅरियर के 98वें टेस्ट मैच में प्राप्त की है.

रविचंद्रन अश्विन

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधन के नाम है.

ये रिकॉर्ड बनाया था. **नेपाल ने उस मैच में रिकॉर्ड 314 रन बनाए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा टी-20 स्कोर है.**

टी-20 में सबसे तेज शतक

गेंद	बल्लेबाज	बनाम	स्थान	वर्ष
33	लाफ्टी ईटन (नामीबिया)	नेपाल	कीर्तिपुर	2024
34	कुशल मल्ला (नेपाल)	मंगोलिया	हांगझू	2023
35	डेविड मिलर (द. अफ्रीका)	बांग्लादेश	पोट्चेफस्ट्रूम	2017
35	रोहित शर्मा (भारत)	श्रीलंका	इंदौर	2017
35	एस. विक्रमासेकरा (चेक गणराज्य)	तुर्की	इफोव काउंडी	2019

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज

(16 फरवरी, 2024 तक की स्थिति)

खिलाड़ी	टेस्ट मैच खेलने की अवधि	टेस्ट मैच	विकेट
मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)	1992–2010	133	800
शेन वार्न (आस्ट्रेलिया)	1992–2007	145	708
जेम्स एंडर्सन (इंग्लैण्ड)	2003–	185	695
अनिल कुम्बले (भारत)	1990–2008	132	619
स्टुअर्ड ब्रॉड (इंगलैण्ड)	2007–2023	167	604
ग्लेन मैक्ग्रॉ (आस्ट्रेलिया)	1993–2007	124	563
कूर्टनी वाल्श (वेस्टइंडीज)	1984–2001	132	519
एन. एम. लियॉन (आस्ट्रेलिया)	2011	127	517
रविचंद्रन अश्विन (भारत)	2011	98	500
डेल स्टेयन (द. अफ्रीका)	2004–2019	93	439

द. अफ्रीका के विरुद्ध न्यूजीलैण्ड की पहली टेस्ट शृंखला विजय

दो टेस्ट मैचों की शृंखला खेलने के लिए द. अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैण्ड का दौरा फरवरी 2024 में किया. यह दोनों ही मैच जीतकर न्यूजीलैण्ड ने यह शृंखला 2–0 से जीती तथा **तांगिवाइ शील्ड** (Tangiwai Shield) पर कब्जा किया.

द. अफ्रीका के विरुद्ध न्यूजीलैण्ड की यह पहली ही टेस्ट शृंखला विजय है.

टी-20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक : नया विश्व रिकॉर्ड

टी-20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का रिकॉर्ड अब नामीबिया के जॉन निकोल लाफ्टी ईटन (Jan Nicol Loftie Eaton) के नाम हो गया है. 22 वर्षीय लाफ्टी ने 27 फरवरी, 2024 को नेपाल में कीर्तिपुर में नेपाल के विरुद्ध एक टी-20 मैच में केवल 33 गेंदों पर शतक बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस मामले में नेपाल के कुशल मल्ला के 34 गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड को लाफ्टी ईटन ने तोड़ा. मल्ला ने पिछले वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध

इंगलैण्ड के विरुद्ध टेस्ट शृंखला (2024) में भारत की निर्णायक बढ़त

भारत के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की शृंखला खेलने के लिए इंगलैण्ड की क्रिकेट टीम ने

यशस्वी जायसवाल : टेस्ट पारी में सर्वाधिक 12 छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी

भारत का दौरा जनवरी–मार्च 2024 में किया. इस दौरे के 4 टेस्ट मैच ही फरवरी 2024 के अन्त तक खेले जा चुके थे. इनमें से हैदराबाद में पहला टेस्ट ही इंगलैण्ड ने जीता, जबकि विशाखापट्टनम, राजकोट व राँची में अगले 3 टेस्ट जीत कर 3–1 की निर्णायक बढ़त भारतीय टीम ने बना ली थी. (शृंखला का 5वाँ अंतिम टेस्ट धर्मशाला में 7–11 मार्च को खेला जाना अभी शेष है.)

इस शृंखला के राजकोट मैच में भारतीय टीम ने 434 रनों से विजय इंगलैण्ड के विरुद्ध

तीरंदाजी

अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष निर्वाचित

केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ (Archery Association of India) के अध्यक्ष जनवरी 2024 में निर्वाचित हुए हैं. वर्ल्ड आर्चरी से निलम्बित चल रहे भारतीय तीरंदाजी संघ का यह चुनाव दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत् नई दिल्ली में वर्ल्ड आचेरी ने पर्यवेक्षक सहित तीन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में जनवरी 2024 में सम्पन्न हुआ.

अर्जुन मुंडा

फुटबाल

फरवरी 2024 में भारत की फीफा रैंकिंग 117 : 7 वर्ष में सबसे नीचे स्तर पर

हाल ही में एएफसी एशियाई कप में निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारतीय फुटबाल टीम की फीफा रैंकिंग फरवरी 2024 में 117 थी, जो विगत 7 वर्षों में टीम की सबसे खराब रैंकिंग थी. यह जनवरी 2017 में प्राप्त की गई 129वीं रैंक के पश्चात् टीम की अब तक की सबसे खराब रैंक थी.

फीफा रैंकिंग में भारत की अब तक की सबसे खराब रैंक 173 वर्ष 2015 में रही है. हाल ही में दिसम्बर 2023 में भारतीय टीम 102वें स्थान पर थी.

फीफा (FIFA) द्वारा फरवरी 2024 में जारी पुरुष टीमों की रैंकिंग में पहले 10 स्थानों पर निम्नलिखित टीमें थीं–

रैंक	टीम
1	अर्जेन्टीना
2	फ्रांस
3	इंगलैण्ड
4	बेल्जियम
5	ब्राजील
6	नीदरलैण्ड्स
7	पुर्तगाल
8	स्पेन
9	इटली
10	क्रोएशिया

पुरुषों की फुटबाल टीमों की आगामी रैंक फीफा द्वारा 4 अप्रैल, 2024 को जारी की जाएगी.

टेनिस

डेविस कप : प्ले ऑफ दौर में भारत ने पाकिस्तान को हराया

डेविस कप टेनिस के प्ले ऑफ दौर में भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ तथा इसके मैच पाकिस्तान में 3-4 फरवरी, 2024 को खेले गए. इस दौर में भारतीय टीम ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी टीम को 4–0 से हराकर विश्व कप ग्रुप-1 में स्थान बनाया.

60 वर्ष के अन्तराल पर पाकिस्तान खेलने पहुँची भारतीय टीम के रामकुमार रामनाथन व श्रीराम बालाजी ने अपने एकल मुकाबले 3 फरवरी को जीते थे. 4 फरवरी को युकी भांवरी व साकेत माइनेनी की युगल मुकाबले में जीत तथा निकी पूनाचा की रिवर्स सिंगल्स जीत से भारत की बढ़त 4–0 की हो गई जिसके बाद दूसरा रिवर्स सिंगल्स खेला ही नहीं गया.

इस विजय के पश्चात् भारतीय टीम अब सितम्बर 2024 में विश्व ग्रुप-1 में भाग लेगी, जबकि पाकिस्तानी विश्व ग्रुप-2 में ही रहेगा.

कुश्ती

सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप (2024)

भारतीय ओलम्पिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा जयपुर में फरवरी 2024 में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में टीम खिताब रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) ने जीता. दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (SSCB) व महाराष्ट्र का रहा. फ्रीस्टाइल कुश्ती में महिला वर्ग में शीर्ष स्थान हरियाणा का रहा. रेलवे व पुदुचेरी क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे.

विविध

छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स (2023) तमिलनाडु में सम्पन्न : पदक तालिका में महाराष्ट्र का शीर्ष स्थान

खेल मंत्रालय की पहल खेलो इंडिया की शृंखला में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स (2023) तमिलनाडु में 19–31 जनवरी, 2024 को सम्पन्न हुए. तमिलनाडु में 4 शहरों–चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै व त्रिची में इसकी विभिन्न

स्पर्द्धाओं का आयोजन हुआ. इन खेलों का उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर. एन. रवि मुख्यमंत्री श्री एम. के. स्टालिन, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम व खेल राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रमाणिक आदि की उपस्थिति में इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जनवरी को किया था. वीरा मंगई इन खेलों की शुभंकर (Mascot) थी. (भारतीय रानी वेलु नचियार, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था को प्यार से वीरा मंगई कहा जाता है).

फुटबाल, वॉलीबाल व बैडमिंटन आदि सहित 26 खेलों की 275 से अधिक प्रतिस्पर्द्धाओं के अतिरिक्त 1 डेमो खेल इन खेलों में शामिल है. तमिलनाडु का पारम्परिक खेल सिलंबम (Silambam) डेमो खेल के रूप में इन खेलों में शामिल था.

36 राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के 5630 से अधिक खिलाड़ियों ने 13 दिन तक चले इन खेलों में विभिन्न स्पर्द्धाओं में भाग लिया.

57 स्वर्ण, 48 रजत व 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदकों के साथ गत विजेता महाराष्ट्र ने ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान इस बार भी प्राप्त किया. दूसरा स्थान मेजबान तमिलनाडु का रहा जिसने 38 स्वर्ण, 21 रजत व 39 कांस्य सहित कुल 98 पदक इन खेले में अपने नाम किए. 35 स्वर्ण, 22 रजत व 46 कांस्य सहित कुल 103 पदकों के साथ गत उपविजेता हरियाणा का इस बार तीसरा स्थान रहा.

छठे एशियाई यूथ गेम्स (2023) की पदक तालिका

क्र.	राज्य/केन्द्र-शासित क्षेत्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1.	महाराष्ट्र	57	48	53	158
2.	तमिलनाडु	38	21	39	98
3.	हरियाणा	35	22	46	103
4.	दिल्ली	13	18	25	56
5.	राजस्थान	13	17	17	47
6.	तेलंगाना	13	4	7	24
7.	उत्तर प्रदेश	11	13	18	42
8.	पंजाब	11	13	15	39
14	मध्य प्रदेश	6	12	12	30
19	उत्तराखण्ड	5	3	8	16
20	झारखण्ड	3	3	5	11
21	बिहार	2	2	1	5
25	छत्तीसगढ़	0	6	2	8

शेष पृष्ठ 144 पर

रोजगार समाचार

राजस्थान में शीघ्र लिपिक एवं निजी सहायक ग्रेड-II संयुक्त सीधी भर्ती-2024

राजस्थान में शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक तथा विभिन्न कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 29 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 474 है, जिसमें 451 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 23 पद अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—(i) सीनियर सेकेण्डरी (ii) कम्प्यूटर ज्ञान की स्तर की परीक्षा या समकक्ष योग्यता तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में कार्य करने का ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2024 को)—21–40 वर्ष विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा एक अन्य छूट के तहत् "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के पहले चरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दो प्रश्न-पत्र होंगे. पहले प्रश्न-पत्र में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान व राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे तथा दूसरा प्रश्न-पत्र सामान्य हिन्दी व अंग्रेजी का होगा.

इस परीक्षा के आधार पर चुनींदा अभ्यर्थियों को आशुलिपि व टंकण गति परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in देखें.

उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) मुख्य परीक्षा

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधीन कनिष्ठ विश्लेषक (औषधि) के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (लखनऊ) द्वारा 18 मई, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं जिन्हें 2023 की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET) में वैध स्कोर कार्ड जारी किया हुआ हो. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 361 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—फार्मेसी में स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

आयु सीमा—(विज्ञापन वर्ष की 1 जुलाई को) 21–40 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी-परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के सम्बन्ध में अलग से यथा समय सूचित किया जाएगा.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in देखें.

उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) मुख्य परीक्षा

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अधीन कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (लखनऊ) द्वारा 15 मई, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं जिन्हें 2023 की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET) में वैध स्कोर कार्ड जारी किया हुआ हो. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 417 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता.

आयु सीमा—(विज्ञापन वर्ष की 1 जुलाई को) 21–40 वर्ष. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी-परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के सम्बन्ध में अलग से यथा समय सूचित किया जाएगा.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in देखें.

झारखण्ड में विभिन्न न्यायालयों में टायपिस्ट, कोर्ट रीडर व डिपोजिशन टायपिस्ट की रिक्तियाँ

झारखण्ड में विभिन्न न्यायालयों में उपर्युक्त रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन, झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा 31 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 218 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक की उपाधि तथा साथ में हिन्दी/अंग्रेजी टंकण की वांछित योग्यता.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2024 को)—21–35 वर्ष, विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित टंकण परीक्षा में निष्पादन के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाइट देखें.

झारखण्ड में विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर्स की रिक्तियाँ

झारखण्ड में विभिन्न सिविल कोर्ट्स में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा 31 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 399 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक की उपाधि तथा साथ में स्टेनोग्राफी तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण की वांछित योग्यता

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2024 को)—21–35 वर्ष, विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी/टंकण की परीक्षा में निष्पादन के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु झारखण्ड उच्च न्यायालय की वेबसाइट देखें.

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन विभिन्न विषयों में टीजीटी की भर्ती

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन अंग्रेजी, हिन्दी, होमसाइंस, फाइन आर्ट्स, संस्कृत, डीपीई, गणित व सोशल साइंस आदि विभिन्न विषयों के लिए टीजीटी (मास्टर्स एवं मिस्ट्रेसेज) के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 18 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 303 है. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—विभिन्न विषयों के मास्टर्स/मिस्ट्रेसेज के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हेतु विस्तृत विज्ञापन देखें.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2024 को)—21–37 वर्ष, विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ किस्म की परीक्षा में 50 अंकों के पहले भाग में जनरल अवेयरनैस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिन्दी, इंगलिश आदि के प्रश्न होंगे, जबकि 100 अंकों के दूसरे भाग में विषय सम्बन्धी प्रश्न होंगे. इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट https://www.chdeducation.gov.in देखें.

सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में एप्रेंटिस के रूप में सम्बद्धता का अवसर

सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में एक वर्ष की एप्रेंटिस के रूप में सम्बद्धता हेतु पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर एप्रेंटिस के 3000 पद उपलब्ध हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक.

आयु सीमा—अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 2004 के बीच होना चाहिए. विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 10 मार्च, 2024 को किया जाएगा. वस्तुनिष्ठ किस्म की 1 घण्टे की अवधि की इस ऑनलाइन परीक्षा में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनैस, जनरल इंगलिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तथा रीजनिंग एबिलिटी व कम्प्यूटर एप्टीट्यूड आदि के प्रश्न होंगे. आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण एप्रेंटिसशिप पोर्टल www.nats.education.gov.in पर कराएं.

झारखण्ड में बी.एड./एम.एड./बीपीएड/एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2024

इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा 21 अप्रैल, 2024 को किया जाएगा. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि 15 मार्च, 2024 है. 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों वाली प्रवेश परीक्षा में लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी, टीचिंग एप्टीट्यूड व रीजनिंग एबिलिटी के क्रमशः 30, 40 व 30 प्रश्न होंगे. प्रवेश परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है.

उपर्युक्त प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध आवेदन की प्रक्रिया व विस्तृत जानकारी हेतु पर्षद की वेबसाइट http://jceceb.jharkhand.gov.in देखें.

हरियाणा पुलिस में पुरुष व महिला कॉंस्टेबिल्स की रिक्तियाँ

हरियाणा पुलिस में पुरुष व महिला कॉंस्टेबिल्स (जनरल ड्यूटी) के 6000 पदों पर नियुक्ति हेतु ग्रुप C के कॉमन एंट्रेस टेस्ट (CET) उत्तीर्ण उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 21 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों में 5000 पद पुरुष कॉंस्टेबिल्स के लिए तथा 1000 पद महिला कॉंस्टेबिल्स के लिए हैं. विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण; मैट्रिक परीक्षा में हिन्दी अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय होना चाहिए.

आयु सीमा—(1 फरवरी, 2024 को)—18–25 वर्ष, विभिन्न वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है.

इस भर्ती के लिए फिजीकल मेजरमेंट टेस्ट व फिजीकल स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को **नॉलेज टेस्ट** में शामिल किया जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, कृषि, एनिमल हसबेंडरी आदि के 10 + 2 स्तर के प्रश्न होंगे.

इस भर्ती के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन व अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कमीशन की सम्बन्धित वेबसाइट https://adv012024.hryssc.com देखें.

Code : 2384, 1059

राजस्थान में छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती-2024

राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 में शामिल हुए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 112 है, जिसमें 110 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 2 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—हायर सेकेण्डरी (पुरानी स्कीम) सीनियर सेकेण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण. कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित ओ लेवल (या समकक्ष) या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण तथा साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को)—18–40 वर्ष. विभिन्न मामलों में आयु सीमा में

नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट भी देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है. परीक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अलग से दी जाएगी. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व ऑनलाइन आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in व www.rssb.rajasthan.gov.in देखें.

राजस्थान में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II सीधी भर्ती-2024

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 में शामिल हुए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 17 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 335 है, जिसमें 314 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 21 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है, रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को)—21 से 40 वर्ष. विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट भी देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है. परीक्षा एवं उसके पाठ्यक्रम आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अलग से दी जाएगी. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व ऑनलाइन आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in व www.rssb.rajasthan.gov.in देखें.

राजस्थान में लिपिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2024

राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग में लिपिक ग्रेड II तथा राज्य के अधीनस्थ विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 में शामिल हुए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 20 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 4197 है, जिसमें 3433 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के व 764 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है, रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—सीनियर सेकेण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी ओ (अथक समकक्ष) अथवा उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को) 18–40 वर्ष. विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट भी देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा में पहले चरण में दो प्रश्न पत्र 100-100 अंकों के होंगे. इनमें पहला प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का तथा दूसरा सामान्य हिन्दी व अंग्रेजी का होगा. दूसरे चरण की परीक्षा में कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी में टंकण की परीक्षा होगी. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व ऑनलाइन आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov. in व www.rssb.rajasthan.gov.in देखें.

राजस्थान में पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती–2024

राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक (महिला) के पद पर नियुक्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 में शामिल हुए पात्र महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 21 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 209 है, जिसमें 164 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 45 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है, रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक तथा कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी उत्तीर्ण ओ अथवा समकक्ष या उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण तथा साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को)—18–40 वर्ष, विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार और देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है. परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति द्वारा अलग से दी जाएगी. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov. in व www.rssb.rajasthan.gov.in देखें.

राजस्थान में पर्यवेक्षक (Supervisor)(महिला अधिकारी) सीधी भर्ती–2024

राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिकता के लिए पर्यवेक्षक (Supervisor) (महिला अधिकारिकता) के पद पर नियुक्ति हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-20 में शामिल हुए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,

जयपुर द्वारा 15 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 176 है, जिसमें 142 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 34 पद अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है, रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक तथा साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को)—18–40 वर्ष. विभिन्न मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार और देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, कम्प्यूटर ज्ञान, भूगोल, सामान्य विज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी तथा हिन्दी व अंग्रेजी आदि के प्रश्न होंगे. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in व www.rssb.rajasthan.gov. in देखें.

राजस्थान में पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) सीधी भर्ती–2024

राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए पर्यवेक्षक (महिला) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र महिला उम्मीदवारों से जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है. ऑनलाइन आवेदन-पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर 21 मार्च, 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं. इस भर्ती के तहत् उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या 202 है, जिसमें 175 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के व 27 पद अनुसूचित क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए हैं.

विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान इस भर्ती के तहत् उपलब्ध है. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है.

शैक्षणिक योग्यता—स्नातक तथा साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव तथा साथ में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान.

आयु सीमा—(1 जनवरी, 2025 को)—18–40 वर्ष. महिलाओं के लिए तथा विभिन्न अन्य मामलों में आयु सीमा में नियमानुसार छूट उपलब्ध है. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त एक अन्य छूट के इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार और देय होगी.

"The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

इस भर्ती के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के पहले खण्ड में भाषा ज्ञान, तर्कशक्ति व सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जबकि 200 अंकों का दूसरा खण्ड पोषण व स्वास्थ्य ज्ञान तथा शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा का होगा. इस भर्ती के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी व आवेदन हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov. in व www.rssb.rajasthan.gov.in देखें. ●●●

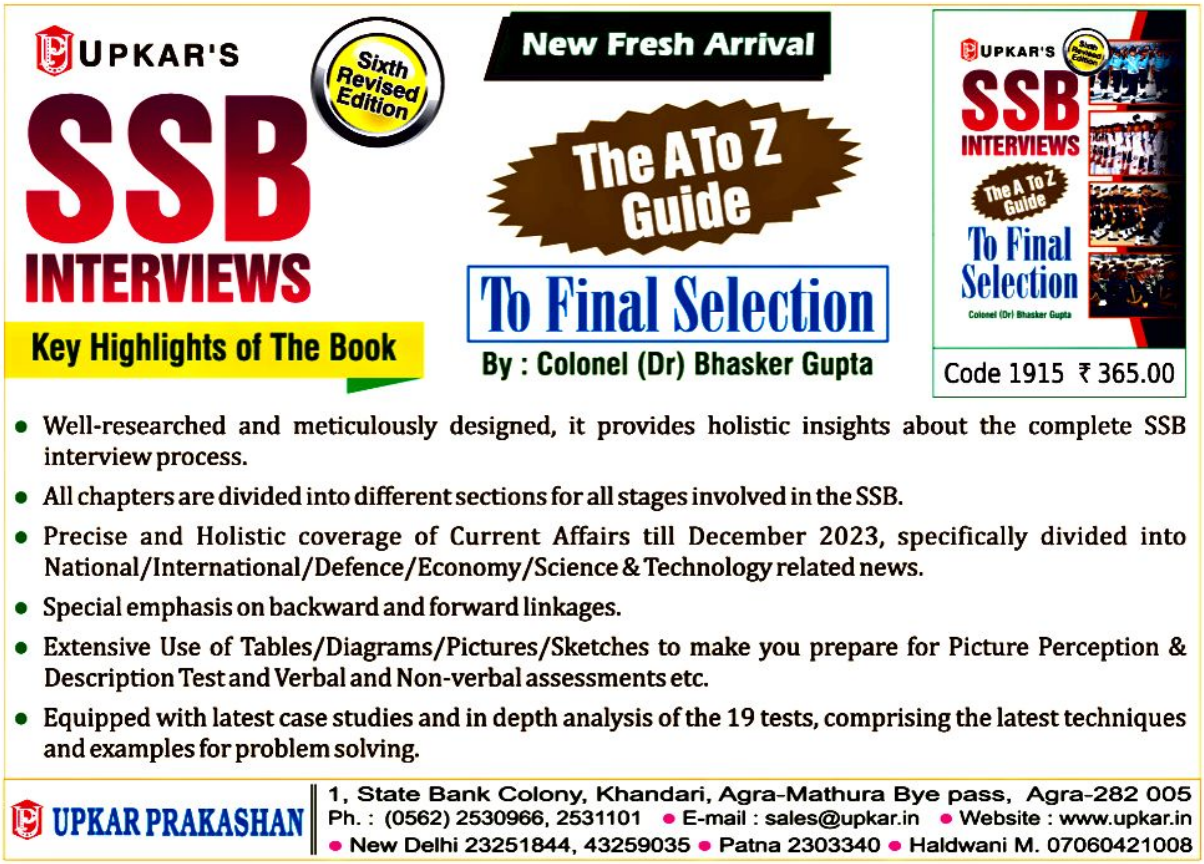

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मानव दिमाग में चिप का लगना–चिकित्सा विज्ञान की क्रान्तिकारी उपलब्धि

एलन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कम्पनी, **'न्यूरालिंक'** ने मानव दिमाग में वायरलेस कम्प्यूटर चिप प्रत्यारोपित करने में सफलता प्राप्त कर ली है. न्यूरालिंक के अनुसार इस प्रत्यारोपण के बाद नेत्रहीन की रोशनी लौट सकती है और बधिर सुन सकते हैं.

न्यूरालिंक प्रत्यारोपण प्रक्रिया के तहत् दिमाग में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करते हैं. इस उपकरण में एक हजार से अधिक इलेक्ट्रोड हैं. इससे मिर्गी और पार्किंसन के मरीजों को भी लाभ होगा. चिप की मदद से लकवाग्रस्त रोगी अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं.

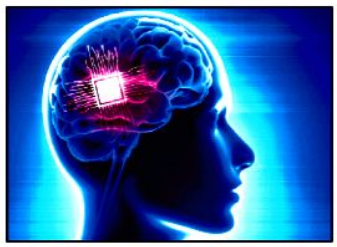

चिप लगने के बाद दिमाग की स्थिति

चिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इंसान के दिमाग में प्रत्यारोपित किया जाता है. न्यूरालिंक ऐप की मदद से व्यक्ति बिना तार के बातचीत कर सकता है. ऐप व्यक्ति की गतिविधि और विचारों को समझकर उसके भाव को प्रकट करता है. उपकरण बिना तार के भी चार्ज किया जा सकेगा.

मस्क ने बताया कि न्यूरालिंक के पहले उत्पाद को टेलीपैथी कहा जाएगा. सबसे पहले इसका प्रयोग वे लोग करेंगे, जो लकवाग्रस्त होने के कारण अपना हाथ-पैर खो चुके हैं.

मस्क ने बताया कि प्रत्यारोपण के नतीजे संतोषजनक हैं. तकनीक न्यूरॉन स्पाइक का पता लगाने में सक्षम है. न्यूरालिंक इंसानी दिमाग के पैदा होने वाले सिग्नल समझ रही है. मस्क भविष्य में इसमें कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं. न्यूरालिंक एलन मस्क की स्टार्टअप कम्पनी है, जो 2017 में शुरू हुई थी. इसमें वैज्ञानिक और इंजीनियरों की बड़ी टीमें हैं.

एलन मस्क ने तो पिछले वर्ष ही दावा कर दिया था कि यह न्यूरलचिप लोगों को उनकी यादों को सँभालकर रखने यानी स्मार्टफोन की तरह ही बैक अप मेमोरी बनाने का मौका देगी. इस चिप के जरिए लोगों की याददाश्त को भी बढ़ाया जा सकेगा. हालाँकि, इस चिप यंत्र के दुरुपयोग की गुंजाइश भी बहुत है, अगर किसी विद्यार्थी को यह चिप लग जाए, तो परीक्षा का अर्थ ही बदल जाएगा.

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा, जो इस चिप का लाभ न लेना चाहे. भला कौन नहीं चाहेगा अपनी तमाम यादों को संजोना ? स्मृतिदोष से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इससे काफी मदद मिलेगी. न्यूरलचिप दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है. मस्क इंसानी दिमाग में कम्प्यूटर इंटरफेस प्लांट कर इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को जोड़ने की भी चाहत रखते हैं

ग्लोबल वार्मिंग का समाधान–अंतरिक्ष में छाता

ग्लोबल वार्मिंग अनेक विनाशकारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि, जंगलों की आग और बर्फ का पिघलना प्रमुख है. धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समस्या के समाधान के प्रयास में लगे हुए हैं. इसके लिए कुछ विधियों पर कार्य हो रहा है और कुछ पर विचार-मंथन चल रहा है. इनमें प्रमुख विधियाँ हैं, जीवाश्म ईंधन में कटौती करना, वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड की सान्द्रता को कम करना और तीसरा है अंतरिक्ष में विशालकाय छाता (सन शेड) बनाकर सौर विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकना.

इस प्लैनेटरी सनशेड (छाता) की रूपरेखा तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम प्लैनेटरी सनशेड फाउंडेशन रखा गया है और प्रोफेसर मॉर्गन गुडविन इसके कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं.

सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए अंतरिक्ष में एक मेगास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज-1 पॉइंट पर स्थापित होगा. प्लान है कि जब अंतरिक्ष में यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो सूर्य की ज्यादातर रोशनी को अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट कर देगा. फाउंडेशन का कहना है कि प्लैनेटरी सनशेड का निर्माण सम्भव है. फाउंडेशन का कहना है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी तेजी से बदली है, जिससे आज के समय लोगों और सामग्री को भेजने की लागत में गिरावट आई है, जो इसे सम्भव बना सकता है.

ज्वालामुखी में सुरंग बनाकर बिजली का उत्पादन होगा

आइसलैण्ड ज्वालामुखी के नीचे सुरंग खोदकर भूतापीय ऊर्जा से बिजली पैदा करेगा. 2026 में क्राफला मैग्मा टेस्टवेड के अन्तर्गत क्राफला ज्वालामुखी पर मैग्मा कक्ष तक सुरंग खोदी जाएगी.

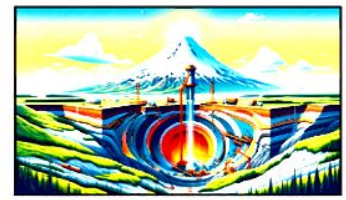

ज्वालामुखी से बिजली पैदा करने का संयंत्र

ज्वालामुखी विशेषज्ञों के मुताबिक, मैग्मा की ऊर्जा का यदि पहले ही इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ज्वालामुखी फटने का डर कम हो जाएगा. आइसलैण्ड वर्षों से गर्म पानी के स्रोतों के जरिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है. यह भाप टरबाइन चलाती है, जिससे बिजली पैदा होती है. आइसलैण्ड के 90 प्रतिशत घरों में इसका इस्तेमाल हो रहा है.

यदि यह परियोजना सफल रही, तो दुनिया भर के ज्वालामुखियों के फटने का खतरा कम किया जा सकता है.

विलक्षण है सेन्टर फॉर वन हेल्थ (मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की एक साथ निगरानी)

'सेन्टर फॉर वन हेल्थ का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनडीसी) के परिसर में बना है, जो देश के प्रत्येक गाँव से लेकर ब्लॉक और जिले तक की निगरानी रखेगा. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, यूएन एन्वायरमेन्ट तथा अमरीका के एफडीए विभाग के सम्पर्क में रहेगा.

रेबीज, सर्पदंश, जीवाणु रोग पर अध्ययन भी शुरू–*सेन्टर फॉर वन हेल्थ ने सबसे पहले रेबीज, सर्पदंश और जीवाणु रोग पर अध्ययन शुरू किया है. वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत मृत्युदर वाले रेबीज से मुक्ति का लक्ष्य तय किया है. वहीं, सर्पदंश को लेकर सभी राज्य के मुख्य अस्पतालों को एक नेटवर्क से जोड़ा है.*

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित कई नई तकनीकों से लैस यह सेन्टर किसी भी संदिग्ध वायरस या व्यक्ति मिलने पर महज एक दिन में अलर्ट जारी कर सकेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गाँव या शहर में कोई खास तरह के संक्रमण या अलग लक्षण वाला कोई व्यक्ति या पशु मिलता है, तो उसके बारे में जिला प्रशासन से केन्द्र तक को सूचना मिलेगी. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे माइक्रो प्लान को साझा किया है, जिसमें बताया गया कि सरकार ने वन्य विभाग, राजस्व स्वास्थ्य विभाग और राज्य पशुचिकित्सा विभाग तीनों को

सरकार ने गाँव, ब्लॉक, जिला और राज्य के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी वन हेल्थ केन्द्र बनाया है. 4 से 5 राज्य को मिलाकर एक क्षेत्रीय केन्द्र होगा, जो सीधे दिल्ली स्थित सेन्टर फॉर वन हेल्थ के साथ सम्पर्क में रहेगा. सभी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम, संसाधन और कर्मचारियों की नियुक्ति के फैसले लिए जा सकेंगे.

साथ में रखते हुए गाँव, ब्लॉक, जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर 5 तरह का निगरानी तंत्र विकसित किया है. दुनिया के बाकी देशों की तुलना में यह योजना सबसे बड़ी और अलग है, जिसमें देश के 2 लाख से ज्यादा गाँव और 700 से ज्यादा जिले शामिल हैं.

दो हजार से अधिक पक्षी–प्रजातियाँ बिलोपन के कगार पर

मानवीय गतिविधियों और वनों तक मनुष्य की चहलकदमी से दुनिया के 12 प्रतिशत पक्षियों की चहचहाट हमेशा के लिए थम गई. ब्रिटेन के सेन्टर फॉर इकोलॉजी एण्ड हाइड्रोलॉजी द्वारा किए गए शोध से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आँकड़े पहले के आँकड़ों से दोगुना हैं. यह समस्त संसार के लिए चिन्ता की बात है.

पक्षियों के बिना दुनिया की कल्पना सूनी लगती है.

पक्षियों के बिलोपन के मुख्य कारण

- *जीवाश्म ईंधन का बढ़ता प्रयोग पक्षियों के लिए जानलेवा.*
- *वनों की कटाई से पक्षियों का आशियाना खत्म हो रहा है.*
- *शिकार के स्तर में भी बढ़ोतरी है पक्षियों के गायब होने का कारण.*
- *जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं मौत की बड़ी वजह.*
- *पक्षियों के ठिकानों में इंसानों की दखलंदाजी बढ़ना भी है कारण.*

नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 12 लाख वर्षों में पक्षियों की 1430 प्रजातियाँ पूरी तरह खत्म हो गई हैं. प्रमुख शोधकर्ता डॉ. रॉब कुक का कहना है कि जीवाश्म ईंधन समेत अन्य कारणों से पक्षियों की 640 प्रजातियों के खत्म होने के साक्ष्य मिले हैं. डोडो पक्षी भी इसकी भेंट चढ़ गया.

वैज्ञानिकों ने द्वीपों पर रहने वाले पक्षियों पर अध्ययन किया, क्योंकि ये पक्षी कहीं और नहीं जाते हैं. द्वीपों पर रहने वाले 90 प्रतिशत पक्षी लुप्त हुए हैं. स्टैटिस्टिकल मॉडल से अन्य पक्षियों की स्थिति का भी पता लगाया है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पक्षियों की 2 हजार से ज्यादा प्रजातियाँ लुप्त हुई हैं. 14वीं सदी में पक्षियों को सबसे ज्यादा क्षति हुई है.

घट रहा है भारतीयों का कद–एक सर्वेक्षण

यह एक सुस्थापित तथ्य है कि कद की दृष्टि से दुनिया में सबसे छोटे लोगों में भारतीय भी शामिल हैं. अब स्थिति यह है कि वैश्विक रुझान के विपरीत, भारतीयों का कद लगातार घटता जा रहा है. यदि यह स्थिति जारी रही, तो भारतीय बच्चे ओहदे के मामले में भले ही अपने माता-पिता को पीछे छोड़ दें, लेकिन कद में पीछे ही रहेंगे. एक शताब्दी पहले की तुलना में भारतीयों का कद बढ़ा है, लेकिन 80 के दशक के मध्य से भारतीयों के कद में प्रति वर्ष कमी दर्ज की जा रही है.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार भारतीय पुरुषों की औसत लम्बाई 1 सेमी कम पाई गई, जबकि महिलाओं के कद में करीब-करीब नहीं के बराबर बदलाव हुआ. पुरुषों के कद में सबसे ज्यादा गिरावट कर्नाटक में दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद झारखण्ड और हरियाणा का स्थान है. कद में यह कमी भले ही त्रुटिपूर्ण नमूना की रेंज में आती हो, किन्तु लम्बाई में बढ़ोतरी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं.

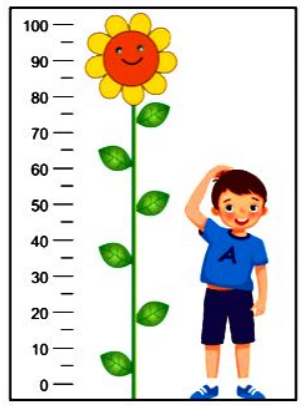

- 01 शताब्दी पहले के मुकाबले बढ़ा है भारतीयों का कद.
- 80 के दशक के मध्य से हर वर्ष घट रही है भारतीयों की लम्बाई.

पूर्व के दोनों दशकों सहित ताजा दशक के दौरान महिलाओं के कद में सर्वाधिक इजाफा केरल में हुआ. पुरुषों के कद में सबसे अच्छी बढ़ोतरी 90 और 2000 के दशक के दौरान केरल में दर्ज की गई, जबकि ताजा दशक के दौरान पुरुषों की लम्बाई में सबसे अच्छी बढ़ोतरी हिमाचल में दर्ज की गई. देश में औसत कद के लिहाज से सबसे छोटी महिलाएं मेघालय, त्रिपुरा, झारखण्ड और बिहार में हैं. इनका औसत कद विश्व में सबसे कम औसत महिला लम्बाई वाले देशों के बराबर है.

यह भी पाया गया कि अगड़ी जातियों के मर्द लम्बे होते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मर्द छोटे होते हैं.

एक शोध के मुताबिक किसी वयस्क की लम्बाई में जीन की भूमिका बहुत कम होती है और खान-पान, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य की भूमिका बहुत अधिक होती है. यदि हम पूर्व के दशक (1995-96 से 2005-06) की बात करें, तो देश के पुरुषों के औसत कद में आधा सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन इसी अवधि में छह राज्यों की औसत लम्बाई में कमी दर्ज की गई.

सुदूर अंतरिक्ष में ज्वालामुखियों की दुनिया

नासा ने पृथ्वी से 63 करोड़ किमी दूर 'ज्वालामुखियों की दुनिया' की तस्वीरें जारी की हैं. यह जगह बृहस्पति ग्रह का चन्द्रमा 'आईओ' है.

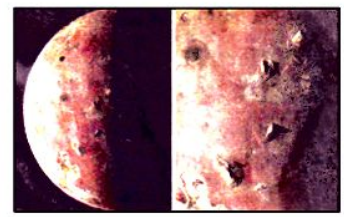

बृहस्पति का 'आई ओ' चन्दमा

जूनो अंतरिक्षयान आईओ से सिर्फ 1500 किमी की दूरी से गुजरा. अंतरिक्षयान पर लगे शक्तिशाली कैमरे जूनोकैम ने ये तस्वीरें खींची हैं. इसमें आईओ पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी नजर आ रहे हैं.

आईओ अनेक फूटते ज्वालामुखियों और लावा से भरा हुआ है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह और उसके अन्य चन्द्रमा यूरोपा और गेनीमेड अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे अपनी ओर खींचते हैं.

नतीजा यह होता है कि आईओ लगातार खिंचता और सिकुड़ता रहता है. ये क्रियाएं इसकी सतह पर ज्वालामुखियों के फूटने और लावा के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं.

जैव ईंधन के गुण और दोष

- जैव ईंधन बायोडिग्रेडेबल ईंधन है, जो बायोमास-पौधों, शैवाल या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है.
- बायोमास की पूर्ति आसानी से की जा सकती है, यही कारण है कि जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के विपरीत ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्वच्छ स्रोत है.
- जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल हैं, क्योंकि वे कोयले और पेट्रोल की तरह वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं.
- आजकल तरल जैव ईंधन-इथेनॉल और बायोडीजल पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है.
- इथेनॉल मकई, गन्ना या पौधों की सामग्री को किण्वित करके प्राप्त किया जाता है. अमरीका और ब्राजील इथेनॉल के अग्रणी उत्पादकों में से हैं, जिसे हरित ईंधन के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है.
- बायोडीजल का उत्पादन वनस्पति तेलों, पशु वसा और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से किया जाता है. बायोडीजल के मुख्य स्रोत पाम, सोयाबीन और रेपसीड हैं.
- अन्य जैव ईंधन संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) है, जो ऑक्सीजन को छोड़कर बायोमास के पाचन से बनाया जाता है.
- सीबीजी का उत्पादन कृषि अवशेष, मवेशी गोबर, गन्ना प्रेस मिट्टी, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट से किया जा सकता है.
- जहाँ तक बायोगैस का सवाल है, यह नवीकरणीय है, क्योंकि मनुष्य और जानवर अपशिष्ट पैदा करते रहेंगे.
- एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज के रूप में हमें ऐसे कचरे के उत्पादन को हतोत्साहित करना चाहिए, जो लैंडफिल और कचरा डंप को ओवरफ्लो कर देता है.

मानव-अस्तित्व के लिए चिन्ताजनक है पूरी दुनिया में भूजल का गिरता स्तर

विश्व के अधिकांश भागों में भूजल का स्तर गिर रहा है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा भारत सहित 40 से अधिक देशों में लगभग 1700 से अधिक जल भृत्यों की जाँच में पाया गया कि सन् 2000 के बाद से लगभग आधे में भूजल स्तर गिर गया है. यह अध्ययन दुनिया भर के कुओं के परीक्षण से डेटा संग्रह करने और भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति बताने वाला दुनिया का पहला अध्ययन है. अध्ययन में 3 वर्ष लगे, जिनमें से 2 वर्ष केवल डेटा को छाँटने में लगे. पिछले 100 वर्षों में 15 लाख कुओं से 300 मिलियन जल स्तर माप को समझने के लिए डेटा को एकत्र किया गया.

खेती वाले इलाकों में भूजल स्तर ज्यादा गिरा

अध्ययन के अनुसार भूजल स्तर में गिरावट उन क्षेत्रों में अधिक थी, जहाँ जलवायु शुष्क है तथा बहुत सारी भूमि पर खेती की जाती थी, जिसमें कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली और संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च मैदानी क्षेत्र शामिल थे. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सांता बारबरा के ब्रेन स्कूल ऑफ एनवायरर्नमेंटल साइंस एण्ड मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक स्कॉट जसेचको ने कहा कि भूजल कमी जलधाराओं का कम होना, भूमि का डूबना आदि है. शोधकर्ताओं ने लगभग 500 जलभृतों में 2000-20 के जल स्तर की तुलना 1980-2000 के रुझानों से की. जलभृतों के 30 प्रतिशत छोटे समूह में, 2000 के बाद से भूजल स्तर पिछले 2 दशकों की तुलना में तेजी से गिरा है, लेकिन उनमें से 20 प्रतिशत में, भूजल में गिरावट पहले से धीमी हो गई है. भूजल में गिरावट का कारण अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है. शहरों के बाहर, कृषि के लिए सिंचाई भूजल का सबसे बड़ा उपयोग हो रहा है. किसी क्षेत्र में होने वाली बारिश या बर्फ की मात्रा में बदलाव सभी जगहों पर सामान्य कारण था.

कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में पेड़-पौधे विफल हो रहे हैं–डरावनी स्थिति

वायुमण्डल में विद्यमान कार्बन डाइ-ऑक्साइड का अवशोषण कर पेड़-पौधे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है. अभी हाल में किए गए शोधों से स्पष्ट हुआ है कि पेड़ों में साँस लेने और जलवायु-परिवर्तन का सामना करने की क्षमता कम हो गई है.

गर्म और सूखे जलवायु के कारण वायु-मण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे असफल हो रहे हैं.

सामान्यतया प्रकाश संश्लेषण के जरिए पेड़ हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं. यह उनकी वृद्धि में सहायक होता है. हालाँकि उच्च तापमान और सीमित पानी की सप्लाई से यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में चल रही है, जिसमें पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वायुमण्डल में छोड़ देते हैं, इसे 'फोटो-रेस्पिरेशन' नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार फोटो-रेस्पिरेशन की दर दोगुनी हो गई है, जिसके पीछे गर्म जलवायु और पानी की कमी मुख्य कारण है. ऐसी प्रतिक्रिया दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के बाद होती है.

अब वैज्ञानिक जीवाश्म का रूप ले चुकी लकड़ी पर शोध करने की योजना बना रहे हैं ताकि 10 हजार वर्ष पहले फोटो-रेस्पिरेशन की दर पता लग सके. इनका कहना है कि लकड़ी में मौजूद कुछ आइसोटोप, विशेषकर मेथॉक्सिल समूहों से इसका पता लगेगा. अध्ययन के मुख्य लेखक और पेन स्टेट के जियोसाइंस के रिसर्च प्रोफेसर मैक्स लॉयड ने कहा, 'वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करने के बजाए वापस भेज रहे हैं. इस प्रक्रिया को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जो सामान्य नहीं है.'

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

उपकार हरियाणा सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में

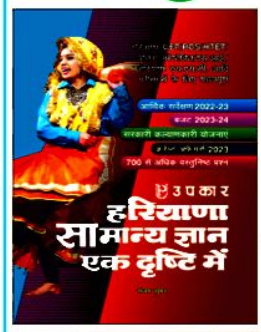

कोड : 1059

मूल्य : ₹ 105/-

लेखक : संजय सुमन

हरियाणा CET/PCS/HTET पुलिस कॉन्स्टेबिल/ एस.आई./हरियाणा एस.एस.सी. आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार टॉपिकवाइज अपडेट.
- बजट 2023-24 के आँकड़े.
- नवीन परीक्षोपयोगी समाचारों (2022-23) से अपडेट.
- 2022-2023 में घोषित योजनाओं के साथ.
- खेलकूद की नवीनतम घटनाएं
- प्रत्येक टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण व राजकीय रिपोर्टों से अपडेट.
- टॉपिकवाइज 700 से अधिक परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश.

उपकार प्रकाशन, आगरा–5 | E-mail : care@upkar.in Website : www.upkar.in

दिव्य दर्पण

संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण

"हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृति निश्चयः।।"

अर्थात्—यदि तुम युद्ध करोगे और युद्ध में मारे जाओगे, तो स्वर्ग पहुँचोगे अथवा विजयी होगे, तो पृथ्वी पर राज्य का आनन्द लोगे. अतः कुंतीपुत्र! युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो।

सिविल सेवा हेतु प्रश्नोत्तर प्रसंग

उपर्युक्त प्रसंग श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के दौरान दिया गया है. यहाँ युद्ध का संदर्भ हमारी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी से है, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी का विद्यार्थी यदि अंतिम रूप से सफल भी नहीं होता है, तो वह आगे जिस भी क्षेत्र में अपना कॅरियर शुरूआत करता है, वहाँ भी बेहतर प्रबंधन, कौशल और ज्ञान का समन्वय दिखाता है. अतः यह प्रसंग ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो अक्सर अंतिम सफलता न मिलने पर हताश और निराश होकर आत्महत्या तक जैसे आपराधिक कृत्यों को अपना लेते हैं. यह प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि हमें जीवन के किसी भी कार्य में दो सकारात्मक नजरिए से ही आगे बढ़ना चाहिए. एक यदि सफल हुए, तो यह हमें बेहतर सेवा का मौका देगा और यदि असफल भी हुए, तो यह हमें कुछ सीखने दूसरों से बेहतर करने की प्रेरणा देगा, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन भी कई हजार बार असफल प्रयासों के बाद अंततः सफल होता है.

कला एवं संस्कृति

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न—सल्लेखना/संधारा प्रथा से क्या तात्पर्य है ? परम्परा और संविधान मूल्यों के संदर्भ में इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क स्पष्ट कीजिए.

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जैनमुनि आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा सल्लेखना कर अपना देह त्याग दिया. दिगम्बर मुनि परम्परा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपने जीवनकाल में लगभग 505 जैन मुनियों को दीक्षा दी.

***परीक्षा विशेष**—सल्लेखना प्रथा, मान्यता पर पक्ष और विपक्ष में तर्क ऐतिहासिक संदर्भ (चंद्रगुप्त द्वारा सल्लेखना) अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 26 के आधार पर तार्किक निष्कर्ष आदि.*

उत्तर—सल्लेखना/संधारा जैन धर्म की नैतिक आचार परम्परा के अनुसार एक व्रत है. यह स्वेच्छा से भोजन और तरल पदार्थों का सेवन धीरे-धीरे कम करके मृत्यु तक उपवास करने की धार्मिक प्रथा है. जैन परम्परा के अनुसार संधारा जीवन के अंतिम समय में तप-विशेष की आराधना है. उल्लेखनीय है, कि जैन धर्म में दो पंथ हैं, श्वेताम्बर और दिगम्बर. श्वेताम्बरों द्वारा इसे संधारा, जबकि दिगम्बरों द्वारा इसे सल्लेखना कहा जाता है. संधारा के शुरूआती लघु अवधि के उपवास को नौकार्थी कहा जाता है और जब इसे ही बढ़ाकर 3 घंटे किया जाता है, तो इसे पोर्थी कहा जाता है. शुरूआती उपवास में उबला पानी पीकर किए जाने वाले उपवास को पिविहार और बिना पानी के उपवास को सौविहार कहा जाता है. धीरे-धीरे इस उपवास की अवधि को बढ़ाया जाता है और कुछ दिनों बाद पूर्णतः अन्न-जल का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है. परम्परा के अनुसार संधारा लेने से पूर्व गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य माना गया है. संधारा लिए व्यक्ति की मृत्यु को 'समाधि मृत्यु' कहा जाता है. संधारा साधु/साध्वी और सामान्य गृहस्थ भी ले सकता है.

संधारा परम्परा और विवाद

संधारा परम्परा पर समय-समय पर इस बात पर तर्क-वितर्क उठते रहे कि क्या यह संवैधानिक तौर पर मान्य है, जबकि भारत में इच्छा मृत्यु को अभी तक पूर्णतः मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसके तर्क में न्यायमूर्ति टी.के. तुकोल अपनी पुस्तक 'सल्लेखना इज नॉट सुसाइट' में लिखते हैं कि संधारा का उद्देश्य 'आत्मशुद्धि' है. इसमें कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया जाता है.

वर्ष 2006 में पेशे से वकील निखिल सोनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और याचिका में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत् इसे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत् जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इस पर रोक की माँग की. वर्ष 2015 में यह विवाद एक बार पुनः चर्चा में आया जब राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर संधारा प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया. राजस्थान उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 306 के तहत् दोषी करार दिए जाने का फैसला दिया. उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा 306 के अन्तर्गत दुष्प्रेरणा में किसी व्यक्ति को उकसाने या किसी काम को करने में जानबूझकर उस व्यक्ति की सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है. इस फैसले में धारा 306 के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 309 के तहत् आत्महत्या के अपराध की भी बात की गई.

हालाँकि बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले को जैन समुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर संधारा की प्रथा को जारी रखने की इजाजत दी.

पक्ष में तर्क

जैन धर्म की मान्यता के अनुसार सल्लेखना/संधारा आत्महत्या नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है. उनके अनुसार सल्लेखना का व्रत तब लिया जाता है, जब जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हों या जब शरीर जीवन के किसी भी प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ हो.

- एक अन्य तर्क का आधार देते हुए कहा गया है कि वर्ष 1863 में तात्कालीन प्रीवी काउंसिल ने संधारा प्रथा को अनादि काल से प्रचलित माना है. दूसरा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 भी प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है.
- पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य ही मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति है. इसलिए जैन धर्म ईश्वर नहीं, बल्कि 'आत्मा' को मान्यता देता है और जब व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता है, तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है. इसी मुक्त आत्मा को जैन धर्म में देवता माना गया है. अतः जैन मान्यता के अनुसार हर जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है. यही कारण है कि जैन धर्म में एक नहीं, बल्कि अनेक ईश्वर हैं.
- जैन मतालम्बियों का मानना है कि संधारा का निर्णय शांत, एकचित्त और हर्ष उल्लास के साथ लिया जाता है, जबकि आत्महत्या का निर्णय तनाव, कुंठा या किसी दबाव में लिया जाता है. इसके अतिरिक्त आत्महत्या एक क्षणिक प्रक्रिया है, जबकि संधारा एक धीमी और

लम्बी प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति चाहे, तो व्रत तोड़ भी सकता है.

- ऐतिहासिक काल में भी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावणबेलगोला (कर्नाटक) पर जाकर सल्लेखना लिया था.

आलोचनात्मक परीक्षण

पक्ष और विपक्ष में तर्कों के आधार पर प्रथम दृष्टया इस मामले में सहमति या असहमति की राय बन सकती है, लेकिन जब इसे थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो सवाल उठता है कि क्या अनुच्छेद 26 की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 (जीवन जीने का अधिकार) के उल्लंघन की अनुमति देता है. दूसरा धार्मिक आस्थाएं, कानूनी दृष्टि से तटस्थ नजरिए की माँग करती है और अंततः भारत जैसे एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में यह मान्यताएं कैसे एक-दूसरे समुदाय की माँगों को जायज और प्रभावित करता है ?

अनुच्छेद 25, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार और अनुच्छेद 26 उसे प्रबंधन करने का अधिकार देता है, बशर्ते इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विपरीत कृत्य न हो. अतः इस आधार पर संधारा का समर्थन करने वाले समुदाय का तर्क है कि संधारा न तो किसी सार्वजनिक व्यवस्था, न ही नैतिकता और न ही किसी स्वास्थ्य के विपरीत कृत्य है.

वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) जिसमें कहा गया कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है." प्रश्नचिह्न लगता है कि क्या धार्मिक प्रथाओं के आधार पर जीवन के इस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है. इस सम्बन्ध में तर्क दिया जाता है कि संधारा के साथ कोई अवैधता या आपराधिकता नहीं जुड़ी है, क्योंकि यह "केवल जीवन जीने की कला के समान ही मृत्यु की कला में महारत हासिल करने की एक जैन परम्परा का हिस्सा है" दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि किसी को अपने पसंद के धर्म को मानने के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार में उसके सिद्धांतों, परम्पराओं और रीति-रिवाजों का भी पालन करना शामिल है. इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 का दावा तभी किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 12 में परिभाषित 'राज्य' द्वारा उसके 'जीवन' या 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से वंचित किया जाता है. इस प्रकार निजी व्यक्तियों द्वारा अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 21 के पूर्वावलोकन के अन्तर्गत नहीं आता है.

धर्मनिरपेक्षता राज्य के सम्बन्ध में भी सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज *बनाम* गुजरात राज्य (1975) केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ न तो ईश्वर/धर्म विरोधी है, न ही समर्थक. यह तटस्थता के सिद्धान्त पर आधारित है.

निष्कर्षता किसी भी धर्म समुदाय की आस्थाएं और परम्पराएं उसे एक विशेष नजरिए से देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती है. एक ही संस्था किसी के लिए मानवीय तो किसी के लिए अमानवीय हो सकती है. अतः ऐसे मामलों में अंततः हमें अपनी कानूनी व्याख्याओं, तटस्थता और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर ही सहमति या असहमति का दृष्टिकोण बनाना चाहिए.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए–

1. सल्लेखना/संधारा वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए रोक लगा दी गई है.
2. अनुच्छेद 26 किसी धार्मिक सम्प्रदाय के लोगों को धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(B)

राष्ट्रीय

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का सामान्य परिचय देते हुए भारतीय कृषि में उनके योगदान का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए.

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिवंगत भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है. श्री स्वामीनाथन जी ने कृषि और किसानों के कल्याण हेतु भारत में उल्लेखनीय योगदान दिया. उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए.

उत्तर–

प्रारम्भिक जीवन

अपने कॅरियर की शुरूआत में, उन्होंने सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन स्वामीनाथन की रुचि कृषि में थी और जल्द ही उन्होंने इस क्षेत्र में शोध करना शुरू कर दिया. उन्होंने भारत और विदेश दोनों में इस क्षेत्र से सम्बन्धित कई संस्थानों में काम किया, जैसे–

- खाद्य और कृषि संगठन परिषद् (1981–85) के एक स्वतंत्र अध्यक्ष,
- प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में (1984–90 तक),
- 1989–96 तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) भारत के अध्यक्ष,
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक आदि.

एम.एस. स्वामीनाथन का हरित क्रांति में योगदान

श्री स्वामीनाथन का शोध उन्हें यूरोप और अमरीका के शैक्षणिक संस्थानों में ले गया और 1954 में, उन्होंने कटक के केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में जैपोनिका किस्मों से इंडिका किस्मों में उर्वरक प्रतिक्रिया के लिए जीन स्थानांतरित करने पर काम करना शुरू किया.

- उन्होंने इसे 'उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने का पहला प्रयास बताया, जो अच्छी मिट्टी की उर्वरता और अच्छे जल प्रबंधन का समाधान दे सकती थीं.
- इसकी आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि आजादी के बाद भारतीय कृषि बहुत अधिक उत्पादक नहीं थी. वर्षों के औपनिवेशिक शासन ने इसके विकास को प्रभावित किया और देश के पास इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए संसाधनों की कमी थी. परिणामस्वरूप, मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक फसलों को भी अमरीका जैसे देशों से आयात करना पड़ा.
- एक IARI वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने डॉ. नॉर्मन बोरलॉग की नव विकसित मैक्सिकन बौनी गेहूँ की किस्म के बारे में सीखा, जो अनाज के उच्च स्तर और बढ़े हुए बायोमास का समर्थन करने के लिए मजबूत डंठल संरचना विकसित कर सकती है.
- भारतीय किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक से सशक्त बनाने के लिए, डॉ. स्वामीनाथन ने गेहूँ उगाने के लिए भारतीय मिट्टी के लिए अनुकूल उर्वरकों, विभिन्न उच्च उपज देने वाली गेहूँ की किस्मों और कुशल कृषि तकनीकों पर शोध किया.
- इसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण उत्तरी क्षेत्र–पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों को आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूँ की इन किस्मों की खेती के लिए छोटे प्रदर्शन और परीक्षण भूखंड स्थापित करने के लिए राजी किया.

- डॉ. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया तथा पहले वर्ष में ही गेहूँ की फसल तीन गुना कर दी. कुल मिलाकर, चार फसल मौसमों में गेहूँ की फसल 12 मिलियन से बढ़कर 23 मिलियन हो गई. यह उत्पादन में एक बड़ी छलांग थी और इसीलिए इसे एक क्रांतिकारी कदम कहा गया.
- गौरतलब है कि 1966 में, जिस वर्ष भीषण सूखा पड़ा था, अमरीका से 10 मिलियन टन पीएल480 गेहूँ का आयात किया गया था.
- किन्तु जैसे ही हरित क्रांति पूरे भारत में फैली, देश भर के किसानों ने बेहतर सिंचाई विधियों, गेहूँ की फसलों में क्रॉस–ब्रीडिंग और उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो गया और अनाज आयात पर निर्भरता समाप्त हो गई.
- IARI में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला और उसके जेनेटिक्स डिवीजन की स्थापना की, जिसने पौधों की कोशिकाओं और जीवों पर विकिरण के प्रभाव और उससे उत्पन्न उत्परिवर्तन पर अभूतपूर्व शोध किया.
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त, डॉ. स्वामीनाथन ने पूरे भारत में हजारों आईसीएआर केन्द्र स्थापित करके किसानों को मौसम और फसल पैटर्न पर शिक्षित करने के लिए काम किया.
- 1980–82 तक, उन्हें भारत के योजना आयोग में कृषि और ग्रामीण विकास का प्रभारी बनाया गया, जिसके दौरान उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के तहत् विकास के फोकस क्षेत्र के रूप में पर्यावरण और महिलाओं को शामिल किया.
- 1982 में, वह फिलीपींस में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक बने, यह पद सँभालने वाले पहले एशियाई थे और चावल की खेती में महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. एम.एस. स्वामीनाथन मैक्सिको मूल के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दीं.
2. 1882 में उन्हें ढाका स्थित अन्तर्राष्ट्रीय 'चावल अनुसंधान' संस्थान का महानिदेशक बनाया गया.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(C)

सामाजिक मुद्दा

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–भारत में महिला आंतरिक प्रवासन के सम्बन्ध में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़ों का उल्लेख करते हुए महिला प्रवासियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए.

चर्चा में क्यों ?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), जो देश में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (Indicators) पर डेटा एकत्र करता है, ने आंतरिक प्रवास के सम्बन्ध में डेटा जारी किया है.

उत्तर–आंतरिक प्रवास से तात्पर्य देश की सीमा के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवासन से है. इसे प्रेरित करने वाले कारकों में प्रमुखतः रोजगार की तलाश, स्टडी या कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारक हो सकते हैं.

हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा जून 2020 से 2021 तक भारत में आंतरिक प्रवासन पर आँकड़े जारी किए हैं. इस अवधि में कुल आंतरिक प्रवासन लगभग 27% रहा है. सर्वेक्षण में पुरुषों के साथ-साथ महिला प्रवासन, प्रवासन के कारणों और प्रवासी महिलाओं की रोजगार में भागीदारी आदि पर विस्तृत आँकड़े दिए गए हैं.

महिला प्रवासन के कारण

पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के बीच प्रवासन के लिए प्रमुख कारणों में विवाह (लगभग 81%) सर्वप्रमुख है. तत्पश्चात् परिवार के सदस्यों के प्रवासन के कारण प्रवास (10%), रोजगार की तलाश में प्रवासन (2·42%) और शिक्षा के लिए प्रवासन (0·48%) सम्मिलित है.

प्रवासी महिलाओं की रोजगार स्थिति

पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग तीन-चौथाई प्रवासी महिलाएं बेरोजगार हैं. इसके अलावा लगभग 14% प्रवासी महिलाएं स्वयं और वेतन-रोजगार वाली नौकरियों में हैं. इसके अतिरिक्त लगभग 12% महिलाएं असंगठित श्रम रोजगार में हैं. सर्वेक्षण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, कि प्रवासी महिलाओं के एक बड़े प्रतिशत (लगभग 85%) के पास 10 वर्ष से कम की शिक्षा है जोकि उनके रोजगार के अवसरों को सीमित करने के प्रमुख कारणों में सर्वप्रमुख हैं. सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 के बाद कामकाजी महिलाओं में से लगभग 55% महिलाएं दोबारा काम पर नहीं लौटीं और जो वापस आईं, उन्होंने अपनी कोविड-19 से पूर्व आय का मात्र 56 प्रतिशत ही प्राप्त किया. महिला रोजगार के सम्बन्ध में एक अन्य तथ्य कि अधिकांश महिलाएं अपने घरेलू उद्यमों में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में काम करती हैं, जोकि प्रायः पंजीकृत रोजगार के आँकड़ों में नहीं आता है.

प्रवासी महिला रोजगार के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत में महिला श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा घरेलू कृषि कार्यों या घरेलू व्यवसायों में संलग्न है, हालाँकि वे अपनी सेवाएं बिना किसी वेतन के प्रदान करती हैं. अतः ऐसी स्थिति में उनकी गणना रोजगार में नहीं के समान ही रहती है.
- सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासी महिलाओं की सीमित सामाजिक नेटवर्क और नए वातावरण में पहुँच की कमी से अक्सर रोजगार पाने की उनकी सम्भावनाओं को सीमित करता है.
- वर्तमान श्रम नीतियों की जटिलताएं या क्रियान्वयन का अभाव महिला प्रवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं करती है.

निष्कर्ष

आंतरिक प्रवासन के सम्बन्ध में अधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और उनके आँकड़ों के आधार पर अधिक व्यावहारिक नीतियों का निर्माण और उनका सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. महिला घरेलू श्रम के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र करना और नवीन परिस्थितियों के आधार पर श्रम परिभाषाओं में संशोधन भी एक समाधान हो सकता है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा जारी आँकड़ों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारत में महिलाओं के आंतरिक प्रवासन में विवाह के कारण प्रवासन सर्वाधिक स्थान रखता है.
2. भारत में प्रवासी महिलाओं में लगभग एक-चौथाई महिलाएं रोजगार में हैं.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(A)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं ? शीत निष्क्रियता के दौरान

शारीरिक परिवर्तन, निष्क्रियता की अवधि और क्रियाविधि का संक्षेप में उल्लेख कीजिए.

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने शीत निष्क्रियता या ब्रुमेशन नामक सरीसृपों (Reptiles) द्वारा अपनाई गई जीवित रहने की रणनीति पर प्रकाश डाला है.

उत्तर–शीत निष्क्रियता में असमतापी व समतापी जीव कम तापमान और भोजन उपलब्धता जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए शीत निष्क्रियता या ब्रुमेशन की अवस्था में चले जाते हैं. इसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है, जिससे कम ताप के कारण जन्तुओं के आंतरिक शरीर का भाग प्रभावित नहीं होता है. इसमें चमगादड़, स्तनधारी पक्षी, कीट पतंगे, छिपकली, भालू आदि प्रमुख उदाहरण हैं. इसके अतिरिक्त मगरमच्छ, कछुआ, मधुमक्खी, घोंघा, मेढक और केंचुआ ग्रीष्म निष्क्रियता (Aestivation) के उदाहरण हैं. ग्रीष्म निष्क्रियता केवल असमतापी जीवों में होती है.

शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के अतिरिक्त एक अन्य विभाजन ब्रह्मोष्मी (Ectothermic) और आन्तरोष्मी (Endothermic) के रूप में भी किया जाता है.

ब्रह्मोष्मी वे प्राणी हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है. ये प्रायः शीत रुधिर वाले प्राणी होते हैं. ये शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के फलस्वरूप जीवित रहते हैं.

आन्तरोष्मी वे प्राणी हैं, जिनके शरीर का ताप स्थिर रहता है. ये प्रायः गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं. ये प्राणी शरीर की उपापचय क्रियाओं द्वारा अपने शरीर का ताप नियमित करते रहते हैं.

शीत निष्क्रियता के दौरान शारीरिक परिवर्तन

शीत निष्क्रियता के दौरान जीव चयापचय दर अथवा मेटाबॉलिज्म में उल्लेखनीय कमी से है. यह कम भोजन सेवन और कम बाहरी तापमान से निपटने के लिए एक ऊर्जा बचत तंत्र है. शीत निष्क्रियता में जीव हृदय गति और श्वसन में उल्लेखनीय कमी का अहसास करते हैं, जिससे ऊर्जा संरक्षण में सहायता मिलती है.

शीत निष्क्रियता की अवधि

इसकी अवधि सरीसृपों की विभिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है और यह भौगोलिक स्थिति और जलवायु स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित भी होती है. इसमें जीव कुछ सप्ताह या कई महीनों तक शीत निष्क्रियता में रहते हैं.

क्रियाविधि

शीत निष्क्रियता में जाने से पहले जीव प्रायः कम भोजन की प्रक्रिया से गुजरते हैं. इसके बाद उनके द्वारा विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान की खोज की जाती है. जब पुनः वातावरण तापमान जीवों के अनुकूल हो जाता है, तब जानवर धीरे-धीरे शीत निष्क्रियता से बाहर निकल आते हैं और यह अवधि उनके लिए सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण होती है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–शीत निष्क्रियता से तात्पर्य है–

(A) जटिल परिस्थितियों में ताप अनुकूलन की स्थिति

(B) केवल असमतापी जीवों में ताप अनुकूलन की स्थिति

(C) एक लम्बी शीत अवधि की पर्यावरणीय विशेषता

(D) शीत अवधि में सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति

उत्तर–(A)

अर्थव्यवस्था

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्लू इकॉनोमी 2·0 की अवधारणा के माध्मय से पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने की महत्ता पर जोर दिया है ?

चर्चा में क्यों ?

1 फरवरी, 2024 को तात्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी अंतरिम बजट 2024-25 में अन्य प्रमुख घोषणाओं के साथ पर्यावरणीय अनुकूल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकॉनोमी 2·0 को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है.

उत्तर–वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में 'नीली अर्थव्यवस्था' की अवधारणा के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया है. इसके माध्यम से समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग पर ध्यान देने के साथ बजट का लक्ष्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.

ब्लू इकॉनोमी

ब्लू इकॉनोमी/नीली अर्थव्यवस्था में स्थिरता पर जोर देने के साथ महासागरों, समुद्रों और तटों से सम्बन्धित सभी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं. विश्व बैंक इसे समुद्री स्वास्थ्य के रूप में संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार सृजन के लिए समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग के रूप में परिभाषित करता है. उल्लेखनीय है, कि इस अवधारणा को गुंटर पॉली ने अपनी 2010 की पुस्तक 'द ब्लू इकॉनोमी : 10 साल, 100 नवाचार, 100 मिलियन नौकरियों' में प्रस्तुत किया था. अर्थात् कहा जा सकता है, कि ब्लू इकॉनोमी नवीन व्यवसाय मॉडल के साथ सामाजिक समावेशन, पर्यावरण स्थिरता के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर जोर देती है.

भारत के लिए महत्व

- भारत की लम्बी तटीय अवस्थिति, समुद्री जीवन की समृद्ध जैव विविधता और हाल ही में लक्षद्वीप समेत अन्य तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के साथ नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय संरक्षण पर अत्याधिक महत्व देती है.

अंतरिम बजट में विशेष

- ब्लू इकॉनोमी 2·0 के तहत् वित्त मंत्री ने 5 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की घोषणा की है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत् उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.
- इसका उद्देश्य जलीय कृषि निर्यात को दोगुना कर ` 1 लाख करोड़ करना और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है.
- अंतरिम बजट में 'नीली अर्थव्यवस्था 2·0' का संदर्भ दिया गया है, जो जुलाई 2022 में जारी मसौदा नीति ढाँचे पर आधारित है. इस ढाँचे में राष्ट्रीय लेखांकन, महासागर प्रशासन, मत्स्यपालन, जलीय कृषि, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और अन्तर्राष्ट्रीय जुड़ाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सिफारिशों को रेखांकित किया गया है.
- उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा पिछले वर्ष की गई जी-20 देशों की अध्यक्षता में भी 'नीली अर्थव्यवस्था' को एक प्रमुख एजेंडा के तौर पर रखा गया था. सम्मेलन के दौरान ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में 'नीली अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर व्यापक चर्चा हुई.

भारत द्वारा प्रयास

भारत द्वारा अपनी समग्र अर्थव्यवस्था में समुद्री आधारित 'ब्लू इकॉनोमी' को बढ़ावा देने के लिए 'डीप ओशन मिशन', 'भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स', 'सागरमाला परियोजना', 'ओ-2-स्मार्ट', 'एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन', 'राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति' आदि को मिशन मोड़ के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है.

सम्बन्धित चुनौतियाँ

भारत के लिए 'ब्लू इकॉनोमी' के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक बुनियादी ढाँचे की कमी है. अन्य प्रमुख चुनौतियों में

परम्परागत मत्स्य व्यवसाय की गतिविधियाँ, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल स्तर में वृद्धि और असामान्य परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय तटीय विवाद (भारत-श्रीलंका, भारत-मालदीव) आदि सम्मिलित है.

निष्कर्ष

सम्बन्धित चुनौतियों और उपलब्ध अवसर के दृष्टिकोण से एक सतत् और सन्तुलित विकास योजना की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बुनियादी ढाँचे के विकास, समुद्री आईसीटी, शिपिंग, समुद्री अनुसंधान और भविष्य केन्द्रित लक्ष्यों पर कार्य करते हुए नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर आगे बढ़ना चाहिए.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–नीली अर्थव्यवस्था 2·0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. अंतरिम बजट 2024-25 में जलीय कृषि निर्यात को मौजूदा ` 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने की बात की गई है.
2. 'नीली अर्थव्यवस्था 2·0' के तहत् समद्री अर्थव्यवस्था से 55 लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही नहीं है/हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

उत्तर–(A)

सि. से. मु. परीक्षा

प्रश्न–पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताते हुए इसकी सीमाओं और भारत के सन्दर्भ में इसका मूल्यांकन कीजिए.

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार द्वारा बाजार अस्थिरता के कारण निवेशकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की बात की है. समिति बाजार जोखिमों के साथ खुली अर्थव्यवस्था की प्रमुख सम्भावनाओं और सीमाओं पर भी विचार करेगी.

उत्तर–

- पूँजीवाद, जिसे मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी देशों में एक प्रमुख आर्थिक व्यवस्था है.
- इसमें उत्पादन के अधिकांश साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जो आय वितरित करने और कीमतों का निर्धारण करने के लिए बाजार की ताकतों द्वारा निर्देशित है.
- पूँजीवाद का मूलभूत पहलू लाभ की खोज है. इसके सम्बन्ध में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का तर्क है कि पूँजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने स्वार्थ में कार्य करते हैं. यह तर्कसंगत स्व-हित आर्थिक समृद्धि को संचालित करता है, क्योंकि लेन-देन में दोनों पक्ष दूसरों की इच्छाओं को पूरा करके अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं.
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में, कारखानों, खानों और रेलमार्गों जैसी पूँजीगत सम्पत्ति निजी स्वामित्व में होती है, श्रम को मजदूरी के माध्यम से मुआवजा दिया जाता है और निजी मालिकों को पूँजीगत लाभ प्राप्त होता है.
- प्रतिस्पर्धी उपयोगों के बीच पूँजी और श्रम के आवंटन में कीमतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

पूँजीवादी व्यवस्था की आलोचना

- इसके सम्बन्ध में एक आलोचना यह की जाती है कि पूँजीवादी विकास की अन्तर्निहित अस्थिरता पर केन्द्रित है. जैसाकि पूँजीवाद लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है, यह तकनीकी प्रगति और पूँजी संचय के सामाजिक अवसरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव करता है. आर्थिक उछाल के बाद बाजार में तेजी, मंदी और विकास और संकुचन का चक्र आता है.
- मार्क्स की दास कैपिटल में प्रस्तुत पूँजीवाद की मार्क्सवादी आलोचना, तर्क देती है कि पूँजीवाद की अस्थिरता बड़ी फर्मों में पूँजी के संकेन्द्रण से जटिल हो जाती है. मार्क्स के अनुसार, यह एकाग्रता विघटन की ओर ले जाती है और अंततः श्रमिक वर्ग के विद्रोह होने पर समाजवाद के साथ पूँजीवाद का प्रतिस्थापन होता है.
- अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा प्रस्तावित एक अन्य आलोचना, निवेश में मंदी से उबरने में पूँजीवाद की सम्भावित विफलता पर प्रकाश डालती है. कीन्स ने सुझाव दिया कि पूँजीवाद उच्च बेरोजगारी के साथ संतुलन की स्थिति में रह सकता है, जिसके लिए कुल माँग को प्रोत्साहित करने और मंदी से उबरने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है.
- धन और आय का वितरण इसके सम्बन्ध में आलोचना का एक अन्य क्षेत्र है. आलोचकों का तर्क है कि कुछ लोगों के हाथों में पूँजीवाद का संकेन्द्रण आय असमानताओं को बढ़ाता है.
- कुछ मामलों में, अधिकारियों के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार सामान्य श्रमिकों के मुआवजे से काफी अधिक होते हैं. मार्क्सवादी आलोचकों का तर्क है कि शोषण का सुझाव देते हुए श्रमिकों को उनके श्रम के मूल्य की तुलना में व्यवस्थित रूप से कम भुगतान किया जाता है.

भारत के सन्दर्भ में पूँजीवाद का मूल्यांकन

- भारत विश्व में एक तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है, जिसमें पूँजीवाद और वैश्वीकरण दो महत्वपूर्ण चालक बने हुए हैं. हालाँकि भारत में न तो पूर्णता पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था. भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जो सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं.
- तर्क दिया जाता है कि भारत को अधिक तेजी से विकास के लिए पूर्णता पूँजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए.

समर्थन के बिंदु

- भारत को अपने विकास को बढ़ाने के लिए एक मुफ्त बाजार बनाने की जरूरत है, लेकिन यह समावेशी विकास होना चाहिए.
- भारत में जिस तरह आर्थिक विकास का स्वरूप बदल रहा है वह पूँजीवादी व्यवस्था की तरफ अधिक झुका हुआ नजर आता है, लेकिन इस प्रवृत्ति के साथ भारत ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे उपाय भी लागू किए हैं, जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं.
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे उपाय भारत में पूँजीवाद को एक कल्याणकारी स्वरूप देते हैं.
- अतः भारत में पूँजीवाद का अर्थ उद्योगों पर विनियमों की अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए, बल्कि उद्योगों को श्रमिकों के लाभ के लिए कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के रूप में होनी चाहिए.
- निष्कर्षता पूँजीवादी व्यवस्था के साथ उचित सरकारी विनियमन, सम्पत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे का विकास और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भारत के आर्थिक विकास के साथ पूँजीवादी व्यवस्था के एक प्रमुख दोष क्रोनी पूँजीवाद को भी रोकने में मदद कर सकता है.

सि. से. प्रा. परीक्षा

प्रश्न–पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में सही नहीं है ?

(A) इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है

(B) इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है

(C) मार्क्स ने दास कैपिटल में पूँजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया है

(D) जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस व्यवस्था की आलोचना की है

उत्तर–(C) ●●●

सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के प्रतीक : आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व

—अतुल कपूर

यदि रचनात्मकता और नवीनता सिविल सेवा परीक्षा को परिभाषित करती है, तो इस शिखर को जीतने के लिए प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयोजन आवश्यक है. सही मायनों में, यह वर्तमान रुझानों को प्रतिबिंबित करने का प्रतीक है.

हाँ, यूपीएससी का इरादा स्पष्ट है और सेट-अप बदल गया है; आपको यह समझने की जरूरत है कि यहाँ सफल होने के लिए क्या-क्या आवश्यक है, जो उम्मीदवार परीक्षा-योजना और इसमें शामिल जटिलताओं को समझ लेते हैं, उसके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान हो जाता है और जो उम्मीदवार इसके प्रति अनजान रहते हैं, उनके लिए यूपीएससी एक दुष्चक्र से कम नहीं और बार-बार प्रयास करने के बाद भी ऐसे उम्मीदवारों से सफलता दूर रहती है.

यदि आप प्रीलिम्स को अप्रत्याशित कहते हैं; ऐसी मानसिकता के साथ आप अपने प्रयास को अव्यवस्थित बना रहे हैं और अवांछनीय चिंताओं को आमंत्रित कर रहे हैं जिससे अंततः परिणाम अप्रिय हो सकते हैं. बेहतर होगा, इस आवेग का मुकाबला स्मार्ट योजना और समझदारी भरे कदमों से करें.

अप्रत्याशितता पर काबू पाने के लिए केवल उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करें जो आपके नियंत्रण में हैं.

याद रखें, आपका लक्ष्य अन्तिम योग्यता-सूची में अपना नाम पाना है और यदि आप अपना नाम शीर्ष रैंक पर पाते हैं, तो यह सोने पर सुहागा होगा. यह निश्चित रूप से आपको क्लाउड-9 पर ले जाएगा.

सिविल सेवा परीक्षा 2024 अधिसूचना जारी; परीक्षा-प्रक्रिया शुरू

यह अवसर उन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिनकी सिविल सेवा में कॅरियर बनाने की योजना है और इस प्रक्रिया की शुरूआत के साथ एक ऐसी मंजिल की यात्रा शुरू हो रही है, जो बड़ी है.

सिविल सेवा परीक्षा 2024 की अधिसूचना 14 फरवरी, 2024 को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई. अधिसूचना में परीक्षा का विवरण शामिल है, जैसे—रिक्तियों की संख्या, आरक्षण, शुल्क, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम के साथ परीक्षा की योजना आदि.

सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए रिक्तियों की अनुमानित संख्या 1056 है, जिसमें बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित 40 रिक्तियाँ शामिल हैं. सिविल सेवा परीक्षा में पदों के विभाजन के लिए दो श्रेणियाँ हैं—ग्रुप ए और ग्रुप बी.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में साक्षात्कार से पूर्व दो चरण होंगे—

- प्रारम्भिक परीक्षा 26 मई, 2024 को आयोजित की जाएगी.
- मुख्य परीक्षा 20 सितम्बर, 2024 से आयोजित की जाएगी.

प्रारम्भिक परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे—

1. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र I 200 अंक (100 प्रश्न)

2. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र II (CSAT) 200 अंक (80 प्रश्न) (क्वालीफाइंग)

- दोनों पेपरों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0·66 अंक की नकारात्मक अंकन होगी.

मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होंगे

1. अनिवार्य भारतीय भाषा का प्रश्न-पत्र (योग्यता प्रकृति)

2. अंग्रेजी भाषा का प्रश्न-पत्र (योग्यता प्रकृति)

3. निबंध प्रश्न-पत्र 250 अंक 3 घण्टे

4. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र—1 250 अंक 3 घण्टे

5. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र—2 250 अंक 3 घण्टे

6. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र—3 250 अंक 3 घण्टे

7. सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र—4 250 अंक 3 घण्टे

8. वैकल्पिक विषय प्रश्न-पत्र—1 250 अंक 3 घण्टे

9. वैकल्पिक विषय प्रश्न-पत्र—2 250 अंक 3 घण्टे

कुल (लिखित) 1750 अंक

साक्षात्कार 275 अंक

कुल योग 2025 अंक

भाषा के प्रश्न-पत्र क्वालीफाइंग प्रकृति के होंगे और अंकों को अंतिम योग्यता के लिए नहीं गिना जाएगा.

वैकल्पिक पेपर अधिसूचना में दिए गए विषयों की सूची से उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होंगे.

जोश के साथ परिश्रमपूर्वक प्रयास करें

सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना एक बहुत बड़ा अवसर है, पर सफलता दर इतनी कम है कि कई उम्मीदवार जब सफलता की सम्भावनाओं के बारे में सोचते हैं, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं.

परीक्षा प्रक्रिया ऐसी है कि कई उम्मीदवार पहली ही बार में शीर्ष रैंक हासिल कर लेते हैं; जबकि कई लोगों के लिए कई प्रयास के बाद भी अप्रिय परिणामों के कारणों का पता लगाना कठिन होता है.

धैर्य और संकल्प दिखाएं और पहले ही प्रयास में योग्यता-सूची में जगह बनाएं. यह परीक्षा आपकी पहुँच के भीतर है; और इसके लिए एक कुशल योजना बनाएं, जो पूरे मिशन में आपका मार्गदर्शन करेगी.

हाँ, जो चीज आपको मंजिल तक पहुँचने में मदद करती है वह है आपका दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, समर्पण, धैर्य, दृढ़ता, सही दिशा में प्रयास, लक्ष्य पर ध्यान और स्वयं पर विश्वास.

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको सिविल सेवा परीक्षा को चरण-दर-चरण नहीं देखना चाहिए; यह एक नियोजित अध्ययन-योजना है, जिसमें लक्ष्य के प्रति अल्पकालिक दृष्टिकोण की कोई गुंजाइश नहीं है.

जैसा कि देखा गया है, कई अभ्यर्थी केवल प्रारम्भिक परीक्षा को ही देखते हैं, विशेषकर वे जो अपना पहला प्रयास कर रहे हैं. सच में ऐसे कई उम्मीदवारों की भीड़ है, जो अपनी पूरी ऊर्जा प्रारम्भिक परीक्षा पर ही लगा देते हैं जैसे कि यही पहला लक्ष्य है, परन्तु ये उम्मीदवार इस बात से चूक रहे हैं कि प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है.

आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, इसका स्पष्ट दृष्टिकोण रखें

आपको सफल होने के लिए उत्सुक रहना होगा और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है.

हमेशा व्यक्तिगत विकास और निरन्तर सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

'प्रतिस्पर्धी भावना' विकसित करके आपको चुनौतियों को स्वीकार करने और इन बाधाओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

स्पष्ट रूप से मन बना लें कि खेल तब तक समाप्त नहीं जब तक आप वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर लेते. जहाँ तक तैयारी और प्रदर्शन का सवाल है, लगातार, आपको दूसरों से बहुत आगे रहना होगा. सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए आपको बस अपने लक्ष्य के

प्रति जुनूनी होना होगा और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनती प्रयास करने होंगे.

तैयारी में कितना समय लगेगा?

आमतौर पर, यह आपके ज्ञान और योजना के स्तर, समझ, आपके सबल-पक्ष और कमजोरियों और आपकी तैयारी की रणनीति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है; फिर भी अपने प्रयास को सार्थक बनाने के लिए आपको न्यूनतम एक वर्ष की तैयारी की आवश्यकता है.

टॉपर्स और यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी कम-से-कम एक वर्ष की तैयारी का सुझाव देते हैं, क्योंकि आपको सम्पूर्ण प्रारम्भिक और मुख्य पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और व्यापक तरीके से कवर करने के लिए समय की आवश्यकता होगी ही.

हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं, जिन्होंने अधिसूचना के बाद तैयारी शुरू करके इस परीक्षा को क्रैक किया है. वे असाधारण समर्पण, अनुशासन और स्मार्ट कार्य का प्रदर्शन करते इसे सम्भव बनाते हैं. उनकी बुद्धि, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, आत्मसात करने की स्पष्ट शक्ति और सबसे अहम्, अंत तक डटे रहने की इच्छा उन्हें वह क्षमता दिखाने में मदद करती है, जिससे वे बने हैं.

उनमें से अधिकांश उम्मीदवार कामकाजी पेशेवर हैं, जो आमतौर पर इसे अल्पकालिक तैयारी के रूप में देखते हैं और अधिसूचना जारी होने के बाद तैयारी शुरू करते हैं. उनमें से कुछ थोड़ी देर से 28-29 वर्ष की उम्र में शुरू करते हैं इसलिए उनके पास 2-3 से अधिक प्रयासों का लाभ उठाने का ही समय होता है.

हालाँकि, उनमें से कुछ उम्मीदवार सफलता प्राप्त करने वालों की सूची में स्थान प्राप्त करते हैं. और इसका कारण है कि वे लक्ष्य निर्धारित करने, लक्ष्य हासिल करने में पारंगत हैं और उनकी मानसिकता उपलब्धि हासिल करने वालों की है.

भले ही तैयारी शुरू करने के निर्णय में देरी हो, फिर भी आप 'कैच-अप' कर सकते हैं

सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरह से अलग प्रतियोगिता है, जहाँ आपको विश्वविद्यालय परीक्षा की तुलना में कम समय में कई विषयों से सम्बद्ध कंटेंट को सीखने और समझने की आवश्यकता होती है.

हम यह अच्छी तरह से समझते हैं कि कम समय में वांछित स्तर हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपके पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हैं और वह भी स्मार्ट तरीके से.

यदि आपने इस परीक्षा में शामिल होने का निर्णय थोड़ी देर से ले, तैयारी शुरू की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लापरवाही से तैयारी करनी चाहिए. इससे स्थिति जटिल हो सकती है.

प्रतियोगिता के बारे में जागरूक होने के कारण, आप जानते हैं कि आपको ऐसे उम्मीदवारों के सामने खड़ा किया गया है, जो दीर्घकालिक तैयारी में लगे हुए हैं. सब कुछ कवर करने और दूसरों के साथ 'पकड़ने' के उद्देश्य से, आप अनुकूलित अध्ययन-सामग्री की तलाश करते हैं और बस खुद को अध्ययन में डुबो देते हैं.

ऐसी कई साइटें और टॉपर्स के ब्लॉग हैं, जो पुस्तक-सूचियाँ और अध्ययन-संसाधन प्रदान करते हैं, जो उम्मीदवारों को क्या पढ़ना है इसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं.

प्रीलिम्स 2024 : क्या आप इस बार परीक्षा में शामिल रहे हैं?

क्या आप इस प्रतियोगिता में उतरने की सोच रहे हैं? आएं, वास्तव में एक बड़ा भाग्य यहाँ इंतजार कर रहा है !

इस परीक्षा की खूबसूरती यह है कि लाखों नए उम्मीदवारों के साथ-साथ कई असफल उम्मीदवार और यहाँ तक कि कुछ सफल उम्मीदवार भी अपनी अधूरी इच्छा के साथ अगला प्रयास इसे पास करने की सोच के साथ उतरते हैं.

अपने पिछले प्रदर्शन से विचलित हुए बिना, ऐसे उम्मीदवार एक बार फिर से सिविल सेवा परीक्षा के लिए पूरे दिल से तैयारी करते हैं, जो लक्ष्य के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण वाले कई उम्मीदवारों को वांछित सफलता प्राप्त करने में मदद करता है.

यह सब एक समग्र दृष्टिकोण के बारे में है और 'एकीकृत दृष्टिकोण' के साथ प्रभावी तैयारी योजना मदद करेगी, क्योंकि आपको परीक्षा के प्रत्येक चरण और आवश्यकताओं को समझकर सम्पूर्ण परीक्षा-योजना को लक्षित करने की आवश्यकता है.

अब, जब प्रारम्भिक परीक्षा 26 मई को है, तो आपको प्रीलिम्स से सम्बन्धित आवश्यकताओं और अगले कुछ महीनों में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने की आवश्यकता है और अपनी तैयारियों के मूल्यांकन के साथ-साथ एक त्वरित संशोधन आपको इसे बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा.

यदि आपने अभी-अभी सिविल सेवा परीक्षा 2024 की तैयारी शुरू की है, तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास सीमित समय है. ऐसी स्थिति में, आपके पास सभी योजनाएं स्पष्ट होनी चाहिए.

आप महत्वाकांक्षी हैं और पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से कवर करने के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन कम समय में तैयारी के लिए पारम्परिक शैली काम नहीं करेगी; इतनी मेहनत करने में परिणामी प्रभाव निरर्थक हो सकता है, क्योंकि आप शायद तैयारी में शामिल जटिलताओं से चूक सकते हैं.

दोहराना; एकाधिक पुनरीक्षण लाभदायक है

आप सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को विस्तृत और संरचित तरीके से कवर करें. सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आपको बार-बार रिवीजन पर जोर देना चाहिए ताकि स्पष्टता आए और मन में अवधारणाएं स्पष्ट हों.

जैसे-जैसे आप पढ़ते हैं, दोहराते हैं और लिखते हैं, इस प्रक्रिया में आपमें विश्लेषणात्मक क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है. विभिन्न स्रोतों से आप जो सामग्री पढ़ते हैं, वह आपको समझने, व्याख्या करने और उसे सन्दर्भ में लागू करने में मदद करती है.

पूरे पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और व्यापक तरीके से संशोधित करें. यह तभी सम्भव होगा जब आप छोटे, स्पष्ट नोट्स बनाने की आदत इस तरह से विकसित करेंगे कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक कीवर्ड के लिए आपके पास वर्तमान घटनाक्रम के साथ अद्यतन अपडेट किए गए नोट्स हों.

ये संक्षिप्त होने चाहिए, फिर भी उनमें सार होना चाहिए. इन्हें इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं और तथ्यों को पढ़कर आपको भारी-भरकम किताबों की ओर लौटने की जरूरत न पड़े और एक पंक्ति आपको पूरी कहानी याद दिला दे.

निश्चित रूप से, ये अंततः आपके लिए गेम-चेंजर साबित होने वाले हैं.

प्रीलिम्स मॉक-टेस्ट के साथ अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करें

अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए, आपको समय-समय पर मूल्यांकन की आवश्यकता है. यह पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रश्नों के प्रकार और यहाँ तक कि पूछे गए प्रश्नों के कठिनाई स्तर से परिचित होने में मदद करेगा.

यह उन क्षेत्रों के बारे में एक उचित विचार देता है, जो आपके सबल-पक्ष हैं और क्या आप इस क्षेत्र से प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम हैं. क्या कोई ऐसा विषय/टॉपिक्स हैं, जहाँ आप बार-बार गलती करते हैं?

पूरे प्रयास में कितने प्रश्न गलत हैं या कितने अनुत्तरित रह गए, मॉक-टेस्ट के अंत में यह जानकारी सामने आती है.

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नेगेटिव-मार्किंग है; आप कितने नकारात्मक अंक आकर्षित करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे. आप अनुभागीय परीक्षण और यहाँ तक कि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षण भी लेते हैं.

अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जितना सम्भव हो उतने मॉक-टेस्ट दें और अभ्यास के साथ गति और सटीकता बनाएं, जो परीक्षा हॉल में प्रश्नों का उत्तर देते समय आपकी मदद करेगी.

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पिछले वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू) तैयार करना है, जो आपको वर्तमान रुझानों को पहचानने में मदद करते हैं. यह आपको परीक्षकों की अपेक्षाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में उचित जानकारी देता है. समय-प्रबंधन के लिए भी यह मदद करता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए आसानी से योजना बना सकते हैं कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने में कितना समय लगेगा और मेन्स के लिए, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक उत्तर को शब्द-सीमा में कितने मिनट में लिखना है?

जब आप मॉक-टेस्ट हल करते हैं, तो यह क्या काम करता है?

जब आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हों, तो कल्पना करें कि यह कैसी होगी और अंततः आप कहाँ पहुँचेंगे. नियमित आत्मनिरीक्षण आपके कदमों और आपको किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर नजर रखेगा.

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए. अभ्यास के दौरान, इसे एक आदत बना लें और यह आपको परीक्षा हॉल में अनुकूल रूप से पुरस्कृत करेगा.

जैसे ही आप प्रश्न-पत्र का उत्तर देना शुरू करते हैं, प्रश्न-पत्र में आने वाले आसान/ज्ञात प्रश्नों को हल करने से आपका तनाव कम होगा और उच्च प्रयास की आशा बढ़ेगी. यह कदम आपके संचित ज्ञान और स्मृति को सक्रिय करता है.

इसके अलावा, जैसे ही आप उन्हें पलक झपकते ही सही से चिह्नित कर लेते हैं, आपमें आत्मविश्वास विकसित होता है और साथ ही आपका बहुमूल्य समय भी बचता है जिसका उपयोग कठिन/अज्ञात प्रश्नों को हल करने में किया जा सकता है.

बिन्दुओं को जोड़ने का आपका कौशल, विषय के भीतर या दूसरे विषय के साथ अंतर्संबंधित सूचना को जोड़ने बोध और प्रासंगिक जानकारी को याद रखने की आपकी क्षमता जादू कर देती है.

अभ्यास के समय सबसे पहले, आपको उन प्रश्नों को चिह्नित करना चाहिए जहाँ आप 100% आश्वस्त हैं. आपको ऐसे सभी प्रश्न छोड़ देना चाहिए जहाँ आपको संदेह और भ्रम हो या पूर्ण अज्ञान हो.

इससे यह पता चल जाएगा कि मॉक-टेस्ट को हल करते समय आप पहले चरण में कितने प्रश्नों को सही के रूप में चिह्नित कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सभी सम्भावनाओं में, ये पर्याप्त नहीं होंगे.

सुरक्षित क्षेत्र तक पहुँचने के लिए आपको कई और प्रश्नों को सही चिह्नित करने की आवश्यकता होगी और यहाँ उन्मूलन तकनीक, तर्क, सामान्य ज्ञान, अंतर्ज्ञान, बुद्धिमान अनुमान इत्यादि जैसी परीक्षा तकनीकों की भूमिका आती है जिन्हें आप सही उत्तर देने के लिए लागू करते हैं.

अभ्यास आपको अपने उत्तर में सटीकता बढ़ाने में मदद करता है.

आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित ऐसी अधिक जानकारी www.iaspassion.com पर प्राप्त कर सकते हैं जहाँ मैं नियमित रूप से योगदान देता हूँ. आप मुझे ट्विटर @atulkpr पर भी फॉलो कर सकते हैं.

करने को बहुत कुछ है, लेकिन सीमित समय बचा है

यह जरूरी है कि आपने जो योजना बनाई है उस पर कार्रवाई करें. आपको प्रीलिम्स के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी समझदारी से प्रयास करने होंगे.

यथार्थवादी लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें. ईमानदारी से अपनी दिनचर्या की समीक्षा करें और समझें कि कितना समय उत्पादक है और आप किन गतिविधियों पर समय बर्बाद कर रहे हैं. आपको अपनी अध्ययन-योजना को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए.

आप तैयारी के लिए प्राथमिकताओं की पहचान और निर्धारण करें, ये वास्तव में आने वाले समय में आपकी अध्ययन-योजना को प्रभावित करेंगे. इसलिए, आत्म-मूल्यांकन करते समय सावधान रहें और अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार रहें.

आपको यह भेद करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी प्रासंगिकता है; दूसरे शब्दों में, आपको पढ़ी गई जानकारी की गुणवत्ता और गहराई पर ध्यान देना होगा.

अपनी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करें और इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखें. सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें. अपना ख्याल रखें, तनाव और चिंता से बचें.

सीखें और स्पष्ट समझ विकसित करें

प्रभावी ढंग से अध्ययन करें, न कि केवल याद रखने के लिए, बल्कि सामग्री को समझने और सीखने का प्रयास करें. पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों पर एक नजर डालने से आपको रुझान का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा, नवीनतम सूचनाओं से अवगत रहना भी आवश्यक है. यह एक लम्बी यात्रा है; ज्ञान और जागरूकता को अद्यतन करने के लिए समाचार-पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने से परीक्षा के प्रत्येक चरण में बहुत मदद मिलेगी.

पहले उन विषयों को पढ़ें और दोहराएं जो आपको अपेक्षाकृत आसान लगते हैं और फिर कठिन विषयों की ओर बढ़ें. इससे आत्मविश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी, जो लगन से तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है.

अगले विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इससे सम्बन्धित पर्याप्त जानकारी है. यदि नहीं, तो इसे अपनी प्राथमिकता सूची में रखें और उस मोर्चे पर खुद को अपडेट करें.

ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें

जब आप शुरू करते हैं, तो स्वतः गति बढ़ती है, लेकिन जल्द ही आप बहुत सारी समस्याओं और चिंताओं से घिर जाते हैं. आपकी आदतें और आत्म-सीमित करने वाले विश्वास आपकी तैयारी में बाधक बनते हैं, जो अध्ययन-योजना में बाधा डालते हैं.

आपको लक्ष्य सिद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखनी होगी और सफल होने के लिए कदम-दर-कदम ताकत दिखाते हुए आगे बढ़ना होगा.

जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल प्रयास कर रहे हैं, तो आप कभी-कभी खुद को नकारात्मकता वाले कुछ लोगों से घिरा हुआ या आलोचना में शामिल पा सकते हैं.

ऐसी स्थितियों में आपको ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए और आशावाद और स्थिरता वापस पाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए. सभी अनावश्यक चीजों पर ध्यान न दें और अपनी अध्ययन-योजना में निरन्तरता बनाए रखें.

अगर कोई ऐसी चीज है, जो आपको नीचे लाती है या आपका ध्यान भटकाती है, तो आपको खुद को नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए. यह आपके मित्र, सहकर्मी या परिवार के कुछ सदस्य हो सकते हैं; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे सभी विकर्षणों से दूर रहें.

अगर यह पूरी तरह से सम्भव नहीं है, तो कम-से-कम आप ऐसे लोगों के साथ कम समय बिता सकते हैं.

पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आया है?

पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए आपको मानक पाठ्य-पुस्तकों, प्रासंगिक अध्ययन-सामग्री और समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की आवश्यकता है. इससे आपमें स्पष्टता विकसित होती है और तार्किक सोच विकसित होती है.

आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक उद्देश्य के लिए है और यदि आप 'बुनियादी बातों का ध्यान रखें और विवरण सही जगह पर आ जाएंगे' सिद्धांत का पालन करते हैं; आप इसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे.

चूँकि यह प्रारम्भिक परीक्षा के लिए व्यापक-गहन और मुख्य परीक्षा के लिए चयनात्मक-व्यापक अध्ययन-योजना हुआ करती थी, बदलते रुझान के लिए वास्तविक दुनिया से सम्बन्धित ज्ञान और जागरूकता की आवश्यकता होती है और प्रश्न-पत्रों को कुशलता से सँभालने में 'एक मील चौड़ी और एक इंच गहरी' जानकारी की सुविधा होती है.

सूर्य के नीचे प्रत्येक चीज पर महारत हासिल करना व्यावहारिक रूप से असम्भव है, लेकिन जितनी सम्भव हो उतनी चीजों के बारे में थोड़ा-सा जानने से आपकी सम्भावनाएं उज्ज्वल हो जाती हैं.

क्या यह आपका दूसरा या अगला प्रयास है?

अपने पिछले प्रयास में आप प्रारम्भिक परीक्षा के पहले चरण में या साक्षात्कार के स्तर पर फिसल गए, आपको नए सिरे से शुरूआत करनी पड़ती है. हालाँकि, जो उम्मीदवार साक्षात्कार स्तर पर विफलता का सामना करते हैं, उनके लिए यह अधिक दर्दनाक है. आखिरी पड़ाव पर पहुँचकर वहाँ से गिरना किसी झटके से कम नहीं है.

इसके अलावा, अनुकूल परिणाम की उम्मीद में, कभी-कभी उम्मीदवार प्रीलिम्स की तैयारी को नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसे मामलों में, आपको तैयारी के लिए केवल कुछ ही दिन मिलते हैं.

हालाँकि, इस यात्रा में असफलता सफलता का अभिन्न अंग है. सकारात्मक मानसिकता वाले उम्मीदवार असफलता को आसन्न उपलब्धि की सीढ़ी के रूप में देखते हैं.

आत्मनिरीक्षण करें और अप्रिय परिणाम पर अपना दृष्टिकोण बनाएं. सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें कि आपने क्या गलतियाँ कीं, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनसे आपको परेशानी हुई या जहाँ आप अपेक्षाओं से कम रह गए.

अपने करीबी लोगों से आत्मविश्वास और प्रेरणा प्राप्त करें, जो आपकी यात्रा को समझते हैं और अपने गुरुओं, दोस्तों और वरिष्ठों से मदद लेने में संकोच नहीं करें.

प्रत्येक प्रयास एक नई यात्रा है, अपना सब कुछ झोंक दें और विजेता बनकर सामने आएं.

जीएस पेपर 2 (सीएसएटी) को नजर-अंदाज न करें; अगर ऐसा किया गया तो यह आपकी योजनाओं को पटरी से उतारने की ताकत रखता है.

सामान्य अध्ययन पेपर 2 (एप्टीट्यूड टेस्ट) क्वालीफाइंग है, लेकिन आपको अपनी किस्मत को जीवित रखने के लिए न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक सुरक्षित करने की आवश्यकता है.

CSAT के लिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका पाठ्यक्रम को देखना और समझ, गणित, तर्क और योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना है.

हाल के वर्षों में, यह पेपर कई उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बन गया है; यहाँ तक कि कई प्रतिभाशाली, विज्ञान/मेडिकल/इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को भी अर्हता प्राप्त करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना मुश्किल लगता है.

आपके पास जीएस पेपर 2 (सीएसएटी) के लिए एक रणनीति होनी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए.

आपको पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का प्रयास करना चाहिए और इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कहाँ खड़े हैं. नियमित अभ्यास से आपको वास्तविक परीक्षा का सामना करते समय सटीकता बनाने और समय-प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.

इसलिए, अपने गणितीय, तर्क और भाषायी कौशल को सीखने और शार्प करने के लिए नियमित रूप से कुछ समय समर्पित करें और इसे गंभीरता से लें.

आपके सामने चीजें बिलकुल स्पष्ट हैं और आपको बस स्मार्ट योजना बनाने की जरूरत है ताकि आप समय का प्रभावी उपयोग कर सकें.

प्रीलिम्स 2024 कुछ सप्ताह दूर है; यह खुद पर और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने का समय है.

सकारात्मक मानसिकता रखें विजयी रवैया अपनाएं.

आपको बड़ी सफलता की शुभकामनाएं!

●●●

उपकार

प्रैक्टिस सैट रेलवे भर्ती बोर्ड

नवीन पैटर्न पर आधारित 20 प्रैक्टिस सैट्स

असिस्टेंट लोको पायलट/टेक्निशियन

प्रथम चरण-कम्प्यूटर आधारित परीक्षा

Code : 2555
₹ 145.00

विषय विशेषज्ञों द्वारा संकलित
योग्यता आधारित प्रश्न
(व्याख्यात्मक हल सहित)

सम्पादक मण्डल

उपकार प्रकाशन, आगरा-5

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

उपकार रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल

कॉन्स्टेबिल (एक्ज़ीक्यूटिव)

कोड : 2414
मूल्य : ₹ 225.00

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा

• नवीन पाठ्यक्रमानुसार तथा परीक्षा पैटर्न पर आधारित
• गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (विश्लेषणात्मक उत्तरों के साथ)
• संक्षिप्त एवं सारगर्भित अध्ययन सामग्री
• विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित मॉडल प्रश्न-पत्र

डॉ. लाल एवं शर्मा

उपकार प्रकाशन, आगरा-5

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "दृढ़ता, धैर्य एवं आत्म-अनुशासन के साथ सतत् कठिन परिश्रम तथा निरन्तर लेखन का अभ्यास"

—रीमा शर्मा

68वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित (44वाँ स्थान)

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर श्रीमती रीमा शर्मा ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई की पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूलरूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्रीमती रीमा—आपके द्वारा दिए गए अवसर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

प्र. द.—किस तरह और कब आपको सिविल सेवाओं की गरिमा एवं महत्व का अनुभव हुआ ?

श्रीमती रीमा—मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हूँ और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक लोक सेवक की भूमिका को मैंने अच्छी तरह देखा और समझा है. हाल ही में कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवक की भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है.

प्र. द.—वह क्षण कब आया जब आपने सिविल सेवाओं में कॅरियर की सम्भावनाएं तलाशने का फैसला लिया ?

श्रीमती रीमा—2016 में मैंने अपनी एक दोस्त को IPS बनते देखा. तभी से मैं उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पढ़ती थी जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी. 2021 में मैंने भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचती थीं ? क्या आप पिछले वर्षों के टॉपर्स के साक्षात्कारों का कोई असर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में अनुभव करती हैं ? इन टॉपर्स में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया ?

श्रीमती रीमा—मैं सोचती थी कि टॉपर्स बहुत मेहनती व अनुशासित रहते होंगे, इसलिए टॉपर्स द्वारा बताई गई परीक्षा की तैयारी की रणनीति का अनुसरण करने का प्रयास करती थी. कुछ टॉपर्स की सामग्री एवं उत्तर-पुस्तिकाओं के अध्ययन से मुझे बहुत लाभ हुआ.

मैं डॉ. प्रीतपाल कौर बत्रा (2016 बैच IPS) व श्रीमती अनू कुमारी मैम (2017 बैच IAS) से बेहद प्रभावित रही हूँ.

प्र. द.—सिविल सेवा-केवल यह ही एक लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रही थीं ?

श्रीमती रीमा—परीक्षा के परिणाम की अनिश्चित प्रकृति को देखते हुए, मुझे हमेशा लगता है कि प्लान-बी रखना बहुत महत्वपूर्ण है. मैंने अपनी तैयारी के पहले ही IIPM हैदराबाद से MBA किया था तथा Human Resource Management विषय में UGC-NET (JRF) भी Qualify किया है.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगी ?

श्रीमती रीमा—अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पति और माता-पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना एवं सफलता की ओर प्रेरित किया.

इसके अलावा मैं अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग की टीम को देना चाहूँगी जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया.

प्र. द.—इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम क्या रहा है ? तैयारी हेतु दिशा एवं सही मार्गदर्शन कहाँ से मिला ?

श्रीमती रीमा—सर्वप्रथम मैंने इसके Syllabus और Previous Years के प्रश्न-पत्रों का अध्ययन किया तथा Online माध्यमों जैसे—YouTube, Telegram की मदद से कुछ नोट्स तैयार किए. इसके अतिरिक्त सही दिशा एवं मार्गदर्शन मुझे मेरे कोचिंग शिक्षकों से भी मिला.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थीं और सफलता के प्रति आश्वस्त थीं ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्रीमती रीमा—67वीं BPSC की तुलना में, 68वीं BPSC का Mains मेरा बेहतर गया था, परन्तु एक अलग पेपर के रूप में जुड़े Essay Paper की वजह से उतना आश्वस्त नहीं थी. Final Result में 44वीं रैंक देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ.

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी थी ?

श्रीमती रीमा—प्रथम स्थान पर मैंने बिहार पुलिस सेवा को रखा था, परन्तु मैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हूँ और यह पद पाकर मैं बहुत खुश हूँ.

प्र. द.—बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में आज सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी गम्भीरता से तैयारी में लगी रही. किस चीज ने आपका विश्वास बरकरार रखा ?

श्रीमती रीमा—मुझे लगता है यदि आप समाज में वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सिविल सेवा सबसे उचित माध्यम है. काम में विविधता तथा समाज में बदलाव लाने की चाहत ने मुझे इस क्षेत्र के लिए प्रभावित किया, जिससे कि मैं बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद निरन्तर प्रयासरत् रही.

प्र. द.—यह सफलता कितने प्रयासों में प्राप्त की और आप अपने पिछले प्रयासों को किस प्रकार देखती हैं ?

श्रीमती रीमा—यह सफलता मुझे दूसरे प्रयास में मिली. हालाँकि, पहला प्रयास भी मेरे लिए अहम् रहा. इस असफलता ने मुझे स्व-आकलन करने का अवसर दिया और उन कमियों को दूर करके इस बार सफलता प्राप्त की.

प्र. द.—समय प्रबंधन-चाहे वह तैयारी हो या फिर परीक्षा में उत्तर लिखते समय एक महत्वपूर्ण कारक है. क्या आपने इस दौरान समय को लेकर कोई कठिनाई महसूस की ? यदि हाँ, तो कैसे आपने इसका सामना किया ?

श्रीमती रीमा—इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में लिखते समय Time Management का बहुत महत्व है. 68वीं BPSC के बाद प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी तथा सामान्य अध्ययन के पेपरों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ, लघु प्रश्न तथा विस्तृत प्रश्नों के कारण पेपर को 3 घंटे में समाप्त करना एक बड़ी चुनौती है, जोकि मैंने भी फेस किया. मैंने इसके लिए उत्तर लेखन पर विशेष ध्यान दिया.

प्र. द.—आपका ऐच्छिक विषय क्या था एवं इनके चुनाव का क्या आधार था ?

श्रीमती रीमा—ऐच्छिक विषय—भूगोल.

मुझे एक ऐसा वैकल्पिक विषय चाहिए था जिसके लिए अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, साथ ही जिसे सीमित समय में पूरा किया जा सके तथा जिसके अध्ययन से मुझे प्रारम्भिक परीक्षा में भी सहायता मिल सके. इस प्रकार मैंने पाया कि भूगोल विषय मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है. हालाँकि, अब यह एक Qualifying पेपर है.

प्र. द.—आपने सभी प्रयासों में ऐच्छिक विषय यही रखे या कोई बदलाव रहा.

श्रीमती रीमा—67वीं एवं 68वीं दोनों परीक्षाओं में मेरा ऐच्छिक विषय भूगोल ही रहा है.

प्र. द.—आपने प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए क्या योजनाएं बनाईं ?

श्रीमती रीमा—प्रारम्भिक परीक्षा हेतु मैंने Previous Years Papers का अध्ययन किया और फिर NCERT की किताबों से शुरूआत की. इसके अलावा Current Affairs के लिए अखबार और प्रतियोगिता दर्पण का सहारा लिया.

मुख्य परीक्षा के लिए भी मैंने Previous Years Papers की Study करके टॉपिक एकत्रित किए और फिर गुरुजनों एवं Online Resources की मदद से उनका अध्ययन किया. दोनों स्तर पर मैंने रिवीजन और Test देने पर ज्यादा Focus किया.

साक्षात्कार हेतु मैंने अपने व्यक्तित्व पर कुछ काम किया. साथ ही दैनिक न्यूज पेपर व घटनाओं से अवगत रही. मैंने अपने DAF को अच्छी तरह से तैयार किया था तथा Hesitation दूर करने के लिए एक-दो Mock Interview भी दिए थे.

प्र. द.—आपने निबन्ध के लिए किस प्रकार की तैयारी की ? आपने किस विषय पर निबन्ध लिखा एवं उस विषय को ही चुनने का क्या कारण था ?

श्रीमती रीमा—निबन्ध चूँकि 68वीं BPSC में पहली बार Introduce हुआ था, इसलिए इसे समझने के लिए मैंने YouTube से कुछ वीडियो देखे तथा UPSC टॉपर्स की Copies को बार-बार पढ़ा. कुछ Understanding के बाद तथा सामान्य अध्ययन के सिलेबस को आधार मानकर विभिन्न विमाओं में निबन्ध को प्रस्तुत किया Anecdotes व Quotations का भी उचित प्रयोग किया था. बिहार स्पेशल निबंध के लिए बिहार को कुछ लोकोक्तियों के Meanings याद किए थे.

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व—*मेरे दादाजी—श्री किशन चंद शर्मा*

सबल पक्ष—*आत्मविश्वास, काम के प्रति लगन और धैर्य.*

दुर्बल पक्ष—*कलात्मक अभिरुचि न होना, कभी-कभी स्वास्थ्य पर ध्यान न दे पाना.*

रुचियाँ—*बागवानी व संगीत सुनना.*

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय में किस प्रकार सन्तुलन बनाया ?

श्रीमती रीमा—मैंने अपने Daily routine में विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए अलग-अलग Time-slot बनाए थे जिस कारण मैं सामान्य अध्ययन एवं ऐच्छिक विषय में संतुलन बना पाई.

प्र. द.—नैगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए क्या सावधानी एवं रणनीति की जरूरत है ?

श्रीमती रीमा—निश्चित रूप से गहन अध्ययन के साथ-साथ, बार-बार रिवीजन तथा Practice की जरूरत है. साथ ही परीक्षा में तुक्का लगाने से भी बचना चाहिए.

प्र. द.—साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे की और आपका साक्षात्कार कब था ? किस बोर्ड में था एवं क्या-क्या प्रश्न पूछे गए ? क्या आप अपने साक्षात्कार से सन्तुष्ट थीं ?

श्रीमती रीमा—साक्षात्कार हेतु मैंने अपने DAF पर मुख्य फोकस रखा. साथ ही, समसामयिक घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया. मेरा साक्षात्कार 14.1.2024 को कोसी बोर्ड में था. मुझसे Graduation Subject (Physics), हॉबी, Past Preference व कुछ Situation Based प्रश्न पूछे गए.

प्र. द.—किस शैक्षिक स्तर पर सिविल सेवाओं की तैयारी के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए ? आपके अनुसार इस परीक्षा की पूर्ण तैयारी में कितना समय लगना चाहिए ?

श्रीमती रीमा—मुझे नहीं लगता कि सिविल सेवा की तैयारी के बारे में सोचने का कोई निश्चित समय है. कहा भी गया है कि "जब जागो तब सवेरा". इसलिए जब समय मिले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. मैंने भी शादी के 12 वर्ष बाद तैयारी शुरू की थी. मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता के दौर में दो-तीन वर्ष तक संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से सफलता निश्चित मिलती है.

प्र. द.—आपके अनुसार विज्ञान और मानविकी विषयों में से किस विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं ?

श्रीमती रीमा—गत वर्षों के परीक्षाफल को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि किस विशेष विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने की सम्भावना ज्यादा है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त करना आपकी लेखन कला और विषय की गहन समझ के ऊपर निर्भर करता है. यदि आपने प्रश्न की माँग के अनुसार उत्तर दिया है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने की सम्भावना ज्यादा है.

प्र. द.—आपके अनुसार इस परीक्षा में हिन्दी माध्यम को लेकर तैयारी करने एवं सफलता प्राप्त करने के बारे में क्या विचार हैं ?

श्रीमती रीमा—मुझे लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा में माध्यम से ज्यादा लेखन शैली एवं विषय की गहन समझ ज्यादा मायने रखती है. जिस भी माध्यम में अभ्यर्थी को भाषा पर पकड़ हो और अपने ज्ञान को लेखन-शैली के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त कर पाए, वही माध्यम श्रेष्ठ है. माध्यम सफलता में बाधक नहीं है.

प्र. द.—क्या अभ्यर्थी के परिवार की शैक्षिक, आर्थिक और जनांकिकीय स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है ? यदि हाँ तो कैसे ?

श्रीमती रीमा—जी, हाँ. अभ्यर्थी की शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का प्रभाव तैयारी पर पड़ता है. यदि आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बुनियादी शिक्षा अच्छी तरह नहीं हुई है, तो सफल होने के लिए ज्यादा समय और प्रयास लग सकते हैं. हालाँकि आजकल Online Resources की उपलब्धता के कारण आर्थिक स्थिति सफलता में बाधक नहीं है.

प्र. द.—एक मानक प्रतियोगिता पत्रिता में क्या विशेष सामग्री एवं संकलन की अपेक्षा रखती हैं ?

श्रीमती रीमा—समसामयिक घटनाओं की तथ्य सहित विस्तृत व्याख्या, वर्तमान परीक्षाओं का प्रश्न-पत्र, निबन्ध, विचारकों के सारगर्भित विचार आदि का संकलन.

प्र. द.—भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली प्रतियोगिता पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण को इन मानकों के कितने करीब पाते हैं ? इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगी ?

श्रीमती रीमा—अपनी तैयारी के दौरान, मैंने प्रतियोगिता दर्पण को एक अनिवार्य Book के रूप में प्रयोग किया. इसने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

व्यक्ति परिचय

नाम : *रीमा शर्मा*
पिता का नाम : *श्री सुखदेव शर्मा*
माता का नाम : *श्रीमती मीना शर्मा*
जन्मतिथि : *30.06.1988*
शैक्षिक योगयता–
MBA : *2012-14, MGU, Meghalaya, IIPM Hyderabad, 81·61%*
BA/B.Sc. : *2008, H.P. University, Shimla, MCMDAV College, Kangra (H.P.), 73·3%*
12th : *2005, HP Board, Dharamshala (Himachal Pradesh), G.Sr.Sec. School Dharamshala, Mahantan (H.P.), 76%*
10th : *2003, HP Board of School, Education, Dharmashala (H.P.), G.H.S. Bhater Una (H.P.), 89·29%*

प्र. द.–क्या आपने सामान्य अध्ययन के अतिरिक्तांकों की सीरीज का उपयोग किया, जो पिछले कई वर्षों से अभ्यर्थियों के बीच बहुत पसन्द की जा रही है ?

श्रीमती रीमा–जी, हाँ. प्रारम्भिक परीक्षा के समय समसामयिकी, वार्षिकांक एवं मुख्य परीक्षा के समय अर्थव्यवस्था आदि अतिरिक्तांकों का उपयोग किया.

प्र. द.–प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी कैसी लगी ? इसके प्रकाशन का समय, इसका आकार एवं इसकी सामग्री के बारे में विचार व्यक्त करें.

श्रीमती रीमा–प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसमें वर्ष भर की महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन उपलब्ध हो जाता है. इससे रिवीजन करना आसान हो जाता है तथा समय की भी बचत होती है.

प्र. द.–भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या आपने तैयारी और प्रयासों हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की थी ?

श्रीमती रीमा–नहीं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अप्रत्याशित है और अधिक Competition होने के कारण सम्भावनाएं कम हो जाती हैं. इसलिए मैंने कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या निर्धारित नहीं की थी.

प्र. द.–आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्रीमती रीमा–मेरी सफलता का मूलमंत्र है–Consistency, Persistent Hard Work, Self Motivation धैर्य.

जब संघर्ष लम्बा होता है तब Consistency एवं धैर्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं.

प्र. द.–आपने सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए कौन-कौनसी पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का उपयोग किया ?

श्रीमती रीमा–सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए मैंने NCERTs (6-10th), The Hindu Newspapers, Hindustan (Patna Edition), प्रतियोगिता दर्पण मासिक, Spectrum (Modern History), M. Laxmikanth (Polity) आदि का उपयोग किया.

प्र. द.–अपनी दैनिक दिनचर्या के कुछ कार्यों के बारे में बताएं, जो तैयारी का अनिवार्य अंग रहे.

श्रीमती रीमा–रोजाना न्यूज पेपर पढ़ना, उत्तर-लेखन (रोजाना एक से दो), नोट्स को रिवाइज करना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को Solve करना.

प्र. द.–कोई सुझाव या संदेश आगामी अभ्यार्थियों को देना चाहेंगी.

श्रीमती रीमा–स्वयं पर विश्वास रखें, समर्पित और प्रतिबद्ध रहें. पूर्ण समर्पण से लगातार प्रयास करें तथा जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक रुकें नहीं. Time Management पर विशेष ध्यान दें तथा हमेशा सीखने की इच्छा रखें. पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें तथा सदैव सकारात्मक बने रहें.

प्र. द.–आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "निष्ठा और एकाग्रता के साथ कठिन परिश्रम तथा निरन्तर लेखन-अभ्यास"

—रतीश कुमार
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर श्री रतीश कुमार ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार लोक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री रतीश—धन्यवाद

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है?

श्री रतीश—श्रमिक समुदाय के कल्याण के लिए प्रथम बिहार प्रशासनिक सेवा (एसडीएम) द्वितीय बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

श्री रतीश—वैकल्पिक विषय—समाजशास्त्र

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री रतीश—यह सामान्य अध्ययन के साथ-साथ मेरे शौक यानी सोशल नेटवर्किंग, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक सम्बन्ध आदि में सहायक है, इसलिए मैंने इसे अपने वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र के रूप में चुना.

प्र. द.—चूँकि वैकल्पिक विषय क्वालीफाईंग हो चला है, BPSC का यह कदम उम्मीदवारों की पसंद को कैसे प्रभावित करेगा?

श्री रतीश—सामान्य अध्ययन पेपर के लिए सहायक और अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं के लिए समय बचाता है.

प्र. द.—67वीं BPSC प्रीलिम्स का प्रश्न-पत्र लीक हो गया, इसका आपकी तैयारी के गेम-प्लान पर क्या प्रभाव पड़ा?

श्री रतीश—यह अधिक ध्यान के साथ तैयारी के लिए समय बचा.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री रतीश—दूसरा प्रयास

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से सन्तुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ?

श्री रतीश—मैं सफलता के लिए आश्वस्त था, लेकिन श्रम अधीक्षक के साथ टॉपर के रूप में नहीं.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुए ?

श्री रतीश—परिणाम से पहले मुझे लगता था कि टॉपर्स असाधारण व्यक्ति होते हैं, लेकिन अब, मुझे लगता है कि सामान्य समर्पित व्यक्ति समर्पण और आत्मविश्वास के साथ टॉपर बन सकते हैं.

प्र. द.—क्या आप वह क्षण याद कर सकते हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था?

श्री रतीश—जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय, बेगुसराय में कक्षा VI में था, तब बेगुसराय की जिला कलेक्टर आईएएस हरजोत कौर ने निरीक्षण के लिए स्कूल का दौरा किया था, तब मुझे सिविल सेवा के महत्व का एहसास हुआ.

प्र. द.—आखिर किस समय आपने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का मन बनाया ?

श्री रतीश—बी.टेक पूरा करने और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने के बाद.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री रतीश—नहीं.

प्र. द.—समय प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

श्री रतीश—मुख्य परीक्षा के लिए लेखन-अभ्यास सफलता पाने के लिए प्रतिदिन 2 घण्टे तक लेखन अभ्यास-किया.

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

श्री रतीश—दैनिक एक मॉक-टेस्ट सेट अभ्यास.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

श्री रतीश—मुख्य परीक्षा के लिए प्रति पाली 3 घंटे का लेखन अभ्यास और मासिक पत्रिका में प्रकाशित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सम्पादकीय पृष्ठ पढ़ना.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

श्री रतीश—कई कोचिंग सेंटर में मॉक इंटरव्यू दिए.

प्र. द.—सिविल सेवा-केवल यही एक मात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री रतीश—पहले से ही डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था.

प्र. द.—आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी, गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

शेष पृष्ठ 64 पर

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "दृढ़ संकल्प, एकाग्रचित्त अध्ययन, तैयारी में निरन्तरता तथा प्रयासों में निरन्तर सुधार"

—अनीशा कुमारी

67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर सुश्री अनीशा कुमारी ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई की पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार लोक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

सुश्री अनीशा—आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है?

सुश्री अनीशा—मेरी प्राथमिकताएं बीएएस, बीपीएस, बीईएस इत्यादि हैं. ये मुख्य सामाजिक समस्याओं हेतु कार्य करने वाली उच्च प्रभाव वाली नौकरियाँ हैं. खाकी वर्दी और इस काम की कमांडिंग प्रकृति के कारण बीपीएस के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है.

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

सुश्री अनीशा—वैकल्पिक विषय हिन्दी भाषा और साहित्य

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

सुश्री अनीशा—हिन्दी भाषा और साहित्य में मेरी रुचि बचपन से ही रही है. मैंने पहले ही पाठ्यक्रम में अधिकांश चीजें पढ़ ली थीं और मैं इग्नू से हिन्दी में एमए कर रही हूँ, ये मुख्य कारक थे और अतीत में हमने देखा है कि यह विषय उच्च स्कोरिंग रहा है, जिससे यह स्पष्ट विकल्प बन गया है.

प्र. द.—चूँकि वैकल्पिक विषय क्वालीफाईंग हो चला है, BPSC का यह कदम उम्मीदवारों की पसन्द को कैसे प्रभावित करेगा ?

सुश्री अनीशा—यह निश्चित रूप से वैकल्पिक विषय के लिए कम समय देकर रणनीति को बदलता, तो है, लेकिन निबन्ध की तैयारी के लिए भी समय आवंटित किया जाना है. कभी-कभी यदि इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल जैसे वैकल्पिक विषय होते हैं, तो तैयारी के दौरान ही सामान्य अध्ययन के लिए एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं.

प्र. द.—आपने बीपीएससी के नए पैटर्न को कैसे समझा और इसका उम्मीदवारों की तैयारी के तरीके पर क्या बदलाव पड़ेगा?

सुश्री अनीशा—नया पैटर्न अध्ययन के अधिक गतिशील दृष्टिकोण की माँग करता है. एनसीईआरटी और पाठ्यपुस्तकें अब अधिक आवश्यक हैं, क्योंकि अवधारणाओं पर पकड़ की माँग बढ़ गई है.

प्र. द.—67वीं BPSC प्रीलिम्स का प्रश्न-पत्र लीक हो गया, इसका आपकी तैयारी के गेम-प्लान पर क्या प्रभाव पड़ा?

सुश्री अनीशा—हम जानते थे कि दोबारा परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी. इसलिए, ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं थी. बस, कई बार रिवीजन, टेस्ट और करंट अफेयर्स को अपडेट करना था.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

सुश्री अनीशा—यह मेरा तीसरा प्रयास था.

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थीं और उच्च सफलता के प्रति आशावान थीं ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

सुश्री अनीशा—जब मैंने पीडीएफ में अपना नाम देखा, तो मैं खुशी से लगभग रो पड़ी, लेकिन मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 2-3 बार जाँच की.

जब मैंने अपनी माँ को इस बारे में बताया, तो वह भावुक हो गईं और फिर मुझे उपलब्धि का एहसास हुआ.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचती थीं ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुईं ?

सुश्री अनीशा—टॉपर्स ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है. उन्होंने उच्च उपलब्धियाँ हासिल की हैं और ऐसा करना आसान नहीं है.

प्र. द.—क्या आप वह क्षण याद कर सकती हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था ?

सुश्री अनीशा—2019 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने सीनियर्स को बीपीएससी की तैयारी करते देखा था इसलिए, मैंने उनसे मार्गदर्शन माँगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी.

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

सुश्री अनीशा—पहले मैंने सोचा कि 2 प्रयास पर्याप्त होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी.

प्र. द.—समय-प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

सुश्री अनीशा—मैं ज्यादातर समय सेल्फ स्टडी कर रही थी, इसलिए समय-प्रबंधन मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं था. मेरी माँ और भाई ने मुझे घर के दैनिक कामों से आजादी दे दी थी. इसलिए मेरे लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित करना आसान हो गया. जब तक बहुत जरूरी न हो, मैं सामाजिक समारोहों से दूर रहती थी.

प्र. द.—इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है. शुरू में तैयारी के लिए आपको सही सलाह कहाँ से मिली ?

सुश्री अनीशा—2019 में मेरी सीनियर शालिनी दीदी ने मुझे तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया.

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

सुश्री अनीशा—प्री और मेन्स की तैयारी एक साथ एनसीईआरटी और अन्य मानक पुस्तकों के साथ, ऑनलाइन कक्षाओं और सामग्रियों से की गई.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

सुश्री अनीशा—मुख्य परीक्षा के लिए मैं फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के लिए सार्थक संवाद में शामिल हुई और ऑनलाइन समूहों में उत्तर लिखना भी साथ-साथ चल रहा था. रणनीति में बदलाव के लिए प्री और मेन्स दोनों की एक साथ तैयारी जरूरी थी.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

सुश्री अनीशा—मेरी तैयारी डीएएफ उन्मुख थी और करंट अफेयर्स अपडेट भी साथ-साथ रहा. मैं कई ऑफलाइन साक्षात्कारों में शामिल हुई और वहाँ से मिले विभिन्न इनपुट पर काम किया. इसके अलावा, दोस्तों और वरिष्ठों के बीच वीडियो और ऑडियो कॉल पर चर्चा भी बहुत मददगार रही.

प्र. द.—सिविल सेवा-केवल यही एक मात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रही थीं ?

सुश्री अनीशा—मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती थी. इसलिए, यूजीसी नेट की तैयारी भी चल रही थी.

प्र. द.—आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

सुश्री अनीशा—हम कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे हम 30 वर्षों तक करना पसन्द करेंगे, वह भी अच्छे वेतन के साथ.

प्र. द.—आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए?

सुश्री अनीशा—ग्रेजुएशन के दौरान या उसके बाद आप, जो भी चुनेंगे वह आपकी प्राथमिकता और क्षमता पर निर्भर करेगा, क्योंकि कुछ लोग इसे अपने पहले प्रयास में भी पास कर लेते हैं.

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व—*एपीजे अब्दुल कलाम*
सबल पक्ष—*मैं शांत हूँ और कई सम्भावनाओं से गुजरने के बाद ही निर्णय लेती हूँ.*
दुर्बल पक्ष—*भावनाओं के प्रति संवेदनशील*
रुचियाँ—*उपन्यास पढ़ना और साइकिल चलाना.*

प्र. द.—क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

सुश्री अनीशा—यह वास्तव में बहुत मददगार थी, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सामग्री एक ही स्थान पर संकलित होने से काफी मेहनत बच गई.

व्यक्ति परिचय

नाम—अनीशा कुमारी
पिता का नाम—श्री सूर्य नारायण यादव
माता का नाम—श्रीमती सविता देवी
शैक्षिक योग्यता—
10th 2013 : BSEB, Lohchi high School, 56·8%
12th 2013-15 : BSEB, BRM College, 53·2%
Graduation 2015-19 : TMBU, Bhagalpur, 61%
Post-Graduation 2019-23 : Munger University, 7·8 cgpa

प्र. द.—आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

सुश्री अनीशा—दशरथ मांझी कहते थे "जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं".

जिस भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, उसमें एकाग्रचित्त प्रयास का सरल, लेकिन शक्तिशाली उदाहरण आवश्यक है.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

सुश्री अनीशा—माता-पिता, मेरा भाई और स्कूल से लेकर बीपीएससी की तैयारी तक सभी शिक्षक, विशेषकर सर्वेश सर. अन्त में, मेरे मित्र और वरिष्ठ, जो मेरे मेंटर बने.

प्र. द.—कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगी ?

सुश्री अनीशा—इस लम्बी और कठिन यात्रा के लिए निरन्तरता और एकनिष्ठ मानसिकता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें शामिल होने से पहले इसके लिए तैयार रहें.

प्र. द.—आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

शेष पृष्ठ 62 का

श्री रतीश—सरकारी सुरक्षा के तहत आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के उन्नयन के लिए.

प्र. द.—आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए?

श्री रतीश—स्नातक अंतिम वर्ष से.

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व—*मेरे माता-पिता*
सबल पक्ष—*आत्मविश्वास और बिना शर्त परिवार का समर्थन और उनका विश्वास*
दुर्बल पक्ष—*सीधापन*
रुचियाँ—*सोशल नेटवर्किंग और गपशप*

प्र. द.—क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

श्री रतीश—प्रतियोगी परीक्षा के लिए सर्वोत्तम और अपेक्षा के बहुत करीब उपयोगी. बीपीएससी, यूपी-पीएससी, आदि सभी के लिए.

प्र. द.—आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्री रतीश—PYQ विश्लेषण और अद्यतन करेंट अफेयर्स.

व्यक्ति परिचय

नाम—रतीश कुमार
पिता का नाम—श्री राजेन्द्र मेहतो
माता का नाम—श्रीमती गायत्री देवी
शैक्षिक योग्यता—
10th : जवाहर नवोदय विद्यालय, बेगुसराय
12th : PCM जवाहर नवोदय विद्यालय, बेगुसराय
Bachelor of Engineering (E & C Engg.) : IET डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय खन्दारी, आगरा

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री रतीश—ईश्वर, परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त.

प्र. द.—कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री रतीश—प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अधिक-से-अधिक करंट अफेयर्स के अध्ययन की आवश्यकता होती है, मुख्य परीक्षा के लिए लेखन-अभ्यास की आवश्यकता होती है और साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञों से पूछताछ का सामना करना पड़ता है. और यह सब आपको करना है.

प्र. द.—आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. ●●●

प्रतियोगिता दर्पण

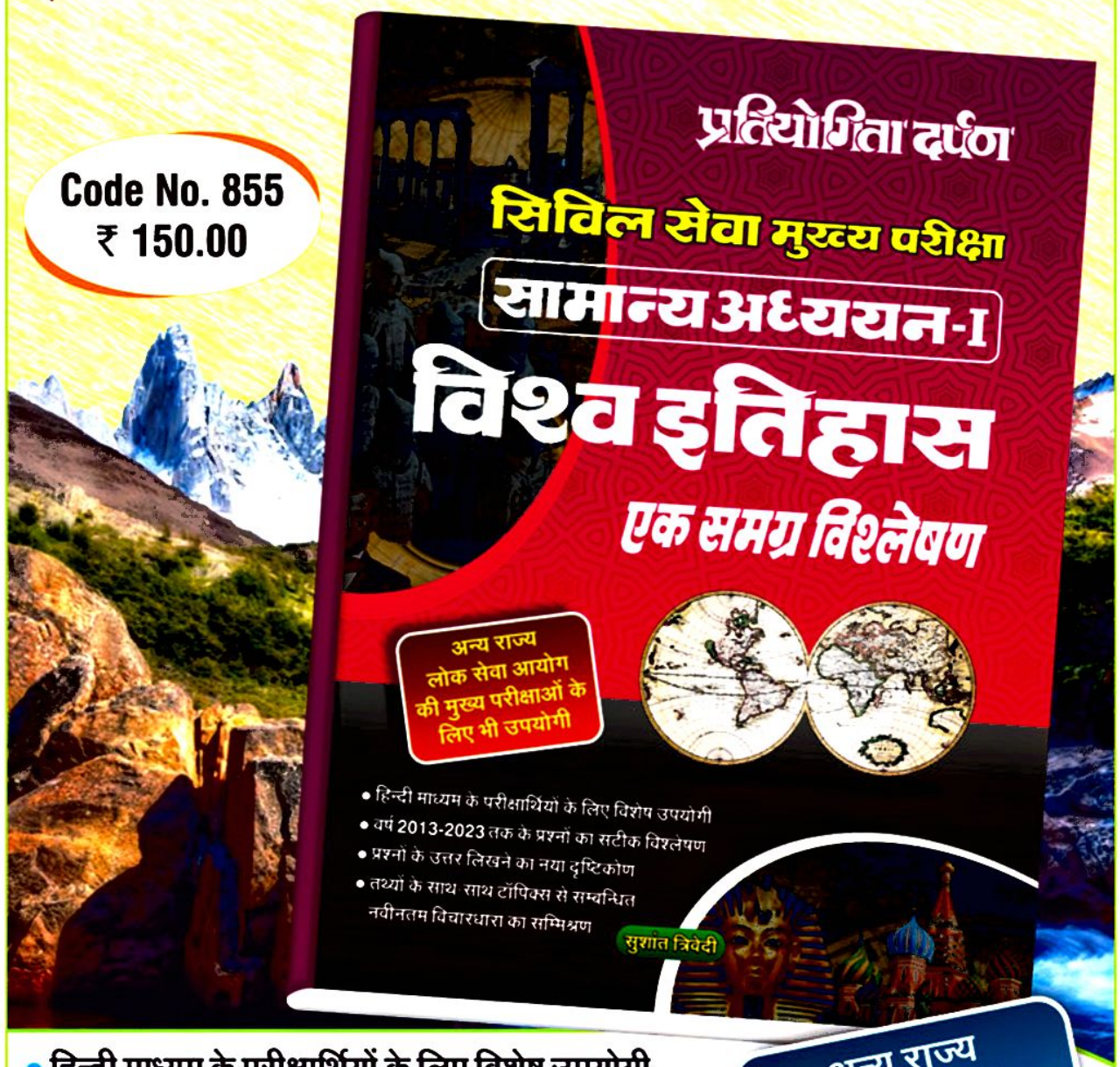

Code No. 855
₹ 150.00

- **हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों के लिए विशेष उपयोगी**
- **वर्ष 2013-2023 तक के प्रश्नों का सटीक विश्लेषण**
- **प्रश्नों के उत्तर लिखने का नया दृष्टिकोण**
- **तथ्यों के साथ-साथ टॉपिक्स से सम्बन्धित नवीनतम विचारधारा का सम्मिश्रण**

अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी

Available on : pdgroup.in amazon Flipkart

प्रतियोगिता दर्पण
1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
फोन : (0562) 2530966, 2531101 • E-mail : sales@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • पटना 2303340 • हल्द्वानी मो. 07060421008

मेरी सफलता का मूलमंत्र है, "असीम धैर्य, कार्य के प्रति समर्पण एवं लक्ष्य-केन्द्रित प्रयास"

—अभिराम कुमार
67वीं बिहार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर श्री अभिराम कुमार ने एक गौरवपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है, जिसके लिए वह प्रशंसा एवं हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं. प्रतियोगिता दर्पण के साथ उनकी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता यहाँ मूल रूप में प्रस्तुत है.

प्र. द.—बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार लोक सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई.

श्री अभिराम—आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

प्र. द.—इन सेवाओं में आपने क्या प्राथमिकता दी है?

श्री अभिराम—पहली प्राथमिकता बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस) थी, क्योंकि बीएएस विविध प्रकृति की नौकरी देता है जहाँ मैं समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग यानी महिलाओं, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी आदि से जुड़ सकूँ.

प्र. द.—आपका वैकल्पिक विषय क्या था ?

श्री अभिराम—वैकल्पिक विषय-मैथिली भाषा एवं साहित्य

प्र. द.—आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या रहा ?

श्री अभिराम—

- यह मेरी मातृभाषा है.
- साहित्य समाज का दर्पण है. इसलिए यह मुझे समाज की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने में मदद करेगी.
- पाठ्यक्रम छोटा है और अन्य विषयों की तुलना में कम समय में तैयार किया जा सकता है. साथ ही, यह बहुत स्कोरिंग है.

प्र. द.—चूँकि वैकल्पिक विषय क्वालीफाईंग हो चला है, BPSC का यह कदम उम्मीदवारों की पसंद को कैसे प्रभावित करेगा?

श्री अभिराम—यह विकल्प को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उम्मीदवार ऐसा वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं जो उनके सामान्य अध्ययन के पेपर में मदद करेगा. साथ ही, उम्मीदवार अन्य वैकल्पिक विषय भी चुन सकते हैं, जो उन्हें रुचिकर लगे.

प्र. द.—आपने बीपीएससी के नए पैटर्न को कैसे समझा; इसका उम्मीदवारों की तैयारी के तरीके पर क्या असर पड़ेगा?

श्री अभिराम—यह निश्चित रूप से उम्मीदवारों की तैयारी के तरीके को बदल देगा. अब एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ गया है, मानक पुस्तकों का महत्व बढ़ गया है. नियमित रूप से अखबार पढ़ने की भी जरूरत है और नियमित रूप से नोट्स बनाने की भी जरूरत है.

प्र. द.—67वीं BPSC प्रीलिम्स का प्रश्न-पत्र लीक हो गया, इसका आपकी तैयारी के गेम-प्लान पर क्या प्रभाव पड़ा?

श्री अभिराम—पेपर लीक की खबर मेरे लिए बेहद निराशाजनक थी, लेकिन मैं अपनी रणनीति और योजना पर दृढ़ था, मुझे परीक्षा के लिए अध्ययन करना था और कोई अन्य विकल्प नहीं था इसलिए मैं ऐसी नकारात्मक खबरों पर काबू पाने में कामयाब रहा.

प्र. द.—यह आपका कौनसा प्रयास था ?

श्री अभिराम—दूसरा प्रयास

प्र. द.—क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और उच्च सफलता के प्रति आशावान थे ? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री अभिराम—नहीं, मैं अपने परिणाम को लेकर आश्वस्त नहीं था, मेरी मुख्य परीक्षा का विश्लेषण करने के बाद मेरे भाई को यकीन था कि मैं चयनित हो सकता हूँ. परिणाम के बाद हम दोनों विश्वास नहीं कर पा रहे थे.

प्र. द.—अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे ? क्या इनमें से किसी टॉपर से आप प्रभावित हुए ?

श्री अभिराम—मैंने हमेशा टॉपर्स की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि इस परीक्षा की प्रकृति बहुत गतिशील है और प्रत्येक चरण बहुत चुनौतीपूर्ण है. वैसे भी टॉपर बनना बहुत कठिन है. मैं हमेशा से एक सिविल सेवक बनना चाहता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉपर भी बन सकता हूँ.

प्र. द.—क्या आप वह क्षण याद कर सकते हैं जब आपको सिविल सेवाओं के महत्व का एहसास हुआ था?

श्री अभिराम—मैंने बचपन से अपने दादाजी (सूर्य नारायण यादव) को देखा है कि वह किस तरह लोगों से जुड़ते हैं और कैसे लोगों की सेवा करते थे. उनकी सेवा के तरीके ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए खींच लिया.

प्र. द.—आखिर किस समय आपने 'सिविल सर्विसेज' में कॅरियर बनाने का मन बनाया?

श्री अभिराम—ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी

प्र. द.—क्या तैयारी के शुरू में आपने अपने लिए इस परीक्षा का सामना करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रयासों की संख्या सम्बन्धी सोच बनाई थी ?

श्री अभिराम—मैंने केवल 2 वर्ष के बारे में सोचा था, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी एक चक्रव्यूह की तरह है, जहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका अपने लिए एक सीट हासिल करना है.

प्र. द.—समय-प्रबंधन को लेकर इस परीक्षा की तैयारी में या फिर परीक्षा भवन में कोई कठिनाई हुई ?

श्री अभिराम—किसी भी उम्मीदवार के लिए समय-प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के दौरान मुझे हमेशा परिस्थितियों से चुनौती मिली. मैं अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ था और खाना

पकाने और यात्रा (अनुत्पादक कार्य) के दौरान अध्ययन और पुनरीक्षण के लिए विभिन्न तरीके विकसित किए. मैं पढ़ाई से जुड़ी हर बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता था और अनुत्पादक काम करते हुए उन रिकॉर्डिंग को सुनता था. मैं यूट्यूब और गूगल जैसे डिजिटल मीडिया से सबसे अधिक लाभ उठाता हूँ.

प्र. द.—इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है शुरू में तैयारी के लिए आपको सही सलाह कहाँ से मिली ?

श्री अभिराम—मेरे भाई और बहन सही सलाह के प्रमुख स्रोत थे. इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की.

प्र. द.—प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी हेतु क्या रणनीति रही ?

श्री अभिराम—कुछ मानक पुस्तकें हैं जिन पर आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जैसे एनसीईआरटी (6-12), राजव्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत, राजीव अहीर द्वारा इतिहास-स्पेक्ट्रम, इम्तियाज अहमद द्वारा बिहार स्पेशल, घटना-चक्र, ल्यूसेंट, मानक समाचार-पत्र और एक मासिक/वार्षिक करंट अफेयर्स पत्रिका.

अपने खुद के नोट्स बनाएं और खूब रिवीजन करें. दूसरी अहम चीज है टेस्ट सीरीज. सुनिश्चित करें कि आप कम-से-कम 30-40 मॉक टेस्ट दें और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखें.

प्र. द.—शुरू से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना क्या रही ?

श्री अभिराम—मानक समाचार-पत्र (द हिन्दू), विजन मासिक करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण, संघ और राज्य बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना/कुरुक्षेत्र पत्रिका. प्रीलिम्स के लिए उल्लिखित एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों का निरन्तर अध्ययन.

प्र. द.—आपने निबन्ध के लिए किस प्रकार तैयारी की ?

श्री अभिराम—अखबार का गहन अध्ययन करें और उससे नोट्स बनाएं. विजन मासिक पत्रिका, योजना/कुरुक्षेत्र पत्रिका, संसद टीवी पर विशेषज्ञ चर्चा और गूगल पर उपलब्ध टॉपर्स कॉपी देखें.

प्र. द.—साक्षात्कार हेतु किस प्रकार की तैयारी की ?

श्री अभिराम—इंटरव्यू के लिए आपको खुद को आत्मविश्वास से व्यक्त करने की जरूरत है और मॉक इंटरव्यू इसमें बहुत मदद करता है. मेरे कुछ शिक्षकों और मित्रों ने मुझमें अधिकारियों जैसे गुण विकसित करने में बहुत मदद की. विजन डेली करंट अफेयर्स और फोरम आईएएस ने मुझे खुद को अपडेट रखने में मदद की. इसके अलावा एक स्थानीय समाचार-पत्र पढ़ें और यूट्यूब पर विशेषज्ञों की चर्चा देखें.

प्र. द.—सिविल सेवा-केवल यही एक मात्र लक्ष्य था या किसी और कॅरियर विकल्प के लिए साथ-साथ तैयारी कर रहे थे ?

श्री अभिराम—तैयारी के दौरान मैं सिविल सेवा के उम्मीदवारों को भी सलाह दे रहा था और मुझे पढ़ाना पसंद है.

प्र. द.—आज के बदलते आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी, गम्भीरता से तैयारी में लगे रहे. आखिर किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा ?

श्री अभिराम—तैयारी के दौरान अंतिम पंक्ति के लोगों की सेवा हमेशा मेरे दिमाग में थी, जिसने मुझे प्रेरित किया. कुछ समय ऐसा भी आया जब मैंने अपना समर्पण खो दिया था लेकिन यह मेरा परिवार था जिसने हमेशा मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थन और प्रेरणा दी.

व्यक्तिगत विशेषताएं

पसंदीदा व्यक्तित्व—*महेंद्र सिंह धोनी पूर्व भारतीय कप्तान*
सबल पक्ष—*त्वरित शिक्षार्थी, समय- प्रबंधन, अनुकूलनशीलता, टीम कार्यकर्ता*
दुर्बल पक्ष—*आत्म-आलोचक, कलात्मक नहीं होना.*
रुचियाँ—*कॉमेडी वीडियो देखना*

प्र. द.—आपकी राय में सिविल सेवा की तैयारी किस शैक्षिक स्तर से शुरू करनी चाहिए और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना न्यूनतम समय रखना चाहिए?

व्यक्ति परिचय

नाम—अभिराम कुमार
पिता का नाम—श्री मिथलेश कुमार
माता का नाम—श्रीमती प्रभा कुमारी
शैक्षिक योग्यता—
10th 2009 : C.B.S.E. Jesus and Mary Academy, Darbhanga 84%
12th 2012 : B.S.E.B. +2 Raj High School, Darbhanga, 70·6%
BE 2012-16 : V.T.U. Siddaganga Institute of Technology, Bangalore 76·7%

श्री अभिराम—ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के दौरान ही सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है. इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका चयनित होना है.

प्र. द.—क्या आपने तैयारी के दौरान प्रतियोगिता दर्पण का उपयोग किया ?

श्री अभिराम—प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका एक बहुत अच्छी पत्रिका है और इस परीक्षा की माँग के लिए बहुत प्रासंगिक है

प्र. द.—आपकी सफलता का मूलमंत्र क्या है ?

श्री अभिराम—धैर्य, दृढ़ता और समर्पण ही एकमात्र रहस्य है.

प्र. द.—अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे ?

श्री अभिराम—मेरे माता-पिता, भाई, बहन, स्वेता कुमारी मित्रगण एवं गुरुजन को अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ.

प्र. द.—कोई सुझाव या सन्देश अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे ?

श्री अभिराम—स्व-अध्ययन पर भरोसा करें, मानक पुस्तकों पर भरोसा करें, सभी नोट्स स्वयं तैयार करें, पर्याप्त संख्या में मॉक टेस्ट दें, समूह चर्चा करें और रिवीजन करें, रिवीजन करें, और रिवीजन करें.

प्र. द.—आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

●●●

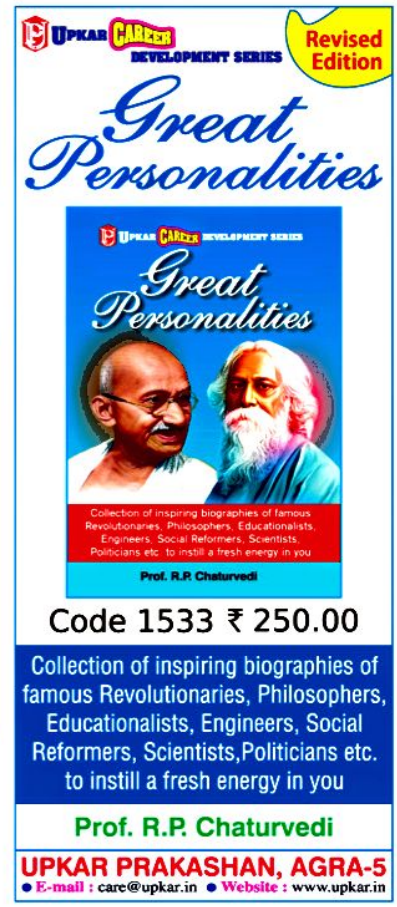

स्मरणीय तथ्य

राष्ट्रीय

1. भारत के किस पहले राज्य की विधान सभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 8 फरवरी, 2024 को पारित किया गया ? **—उत्तराखण्ड**
☞ उत्तराखण्ड राज्य स्वतंत्रता प्राप्त भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर कानून बनाया है. इस कानून से अनुसूचित जनजातियों को अलग रखा गया है. केवल गोवा में स्वतंत्रता से पूर्व ही यूसीसी लागू है.
2. भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को महँगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6 फरवरी, 2024 से लिया है ? **—भारत चावल**
☞ उपभोक्ताओं को महँगाई से राहत देने के लिए सरकार ने ₹ 29 प्रति किग्रा की रियायती दर पर 'भारत चावल' की पेशकश की है. 'भारत आटा' और 'भारत दाल' के बाद सरकार ने इसे शुरू किया है. यह 5 किग्रा और 10 किग्रा के पैक में पेश किया गया है.
3. भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जिन्हें 31 जनवरी, 2024 को बाली, इंडोनेशिया में सम्पन्न एशियन क्रिकेट कौंसिल की जनरल मीटिंग में इस कौंसिल (ACC) का प्रमुख पुनः निर्वाचित किया गया है. **—जय शाह**
☞ जय शाह ने 30 जनवरी, 2021 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से एसीसी की कमान सँभाली थी. शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव भी हैं.
4. भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों के किस संगीत बैंड ने 4 फरवरी, 2024 को लॉस एंजिल्स, अमरीका में 'दिस मोमेंट' के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता ? **—शक्ति**
☞ शक्ति बैंड की 30 जून, 2023 को जारी एल्बम 'दिस मोमेंट' को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है. शक्ति बैंड में गायक शंकर महादेवन, गिटार वादक जॉन मैक्लॉघलिन, तबला वादक जाकिर हुसैन, तालवादक वी. सेल्वागणेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन सम्मिलित हैं.
5. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस्कॉन (ISKCON) के संस्थापक किस संत महात्मा की 150 वीं जयंती पर 8 फरवरी, 2024 को एक डाक टिकट तथा एक सिक्का नई दिल्ली में जारी किया ? **—स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद**
☞ अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्हें स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, सनातन हिन्दू धर्म के एक प्रसिद्ध गौडीय वैष्णव गुरु तथा धर्मप्रचारक थे. यह इस्कॉन (ISKCON—International Society for Krishna Consciousness) जिसे सामान्यतः हरे कृष्णा आंदोलन भी कहा जाता है.
6. 17 से 21 फरवरी, 2024 तक अन्तर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया ? **—चंडीगढ़**
☞ चंडीगढ़ में टैगोर थियेटर में आयोजित महोत्सव में रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमरीका और श्रीलंका के कठपुतली कलाकारों ने भाग लिया.
7. उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानम द्वारा फरवरी 2024 में विश्वभारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान व कवि को प्रदान करने की घोषणा की गई है ? **—प्रो. रहसबिहारी द्विवेदी**
☞ महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार अयोध्या के डॉ. देवीसहाय पांडेय दीप, व्यास पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर आन्जनेय शास्त्री एवं नारद पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर गोपबन्धु को दिया जाएगा.
8. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट (AIPDM) 12–16 फरवरी, 2024 को कहाँ आयोजित की गई ? **—लखनऊ, उत्तर प्रदेश**
☞ मीट के उद्घाटन में केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विन वैष्णव एवं समापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे. इस सम्मेलन में केन्द्र व राज्यों की 29 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगभग 1200 सदस्यों ने भाग लिया.
9. भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण 11 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में किया गया ? **—सपनों की रोशनी**
☞ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक सपनों की रोशनी 50 वर्ष पहले लिखी गई डायरी पर आधारित है जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है.
10. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को मुफ्त बिजली देने किस योजना की घोषणा की ? **—पीएम सूर्य घर योजना**
☞ ₹ 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है.
11. असम सरकार ने 13 फरवरी, 2024 को वहाँ के किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया ? **—काजी नेमू (खट्टे नींबू)**
☞ इस फल को 2016 में जीआई टैग मिला था और इसे असम राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है. 'काजी नेमू' अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है.
12. उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी किन बॉण्डों को असंवैधानिक 15 फरवरी, 2024 को घोषित किया है ? **—इलेक्टोरल बॉण्ड**
☞ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉण्ड खरीद कर कोई भी व्यक्ति या कम्पनी बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था.
13. इसरो (ISRO) ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी, 2024 को नियंत्रित तरीके से हिन्द महासागर में गिरा कर नष्ट किया ? **—कार्टोसैट–2 (Cartosat-2)**
☞ कार्टोसैट-2 सैटेलाइट को पीएसएलवी सी-7 (PSLV C7) द्वारा 10 जनवरी, 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से लॉन्च किया गया था जिसका प्रमुख कार्य जमीन की तस्वीरें लेना था.
14. इसरो (ISRO) ने 17 फरवरी, 2024 को मौसम का अध्ययन करने के लिए अपने किस आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया ? **—इंसैट-3 डीएस (INSAT-3DS)**
☞ इसरो ने इंसैट-3डीएस सैटेलाइट का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश से जीएसएलवी एफ14 (GSLV F14) द्वारा किया गया.
15. भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 17 फरवरी, 2024 को किस नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया ? **—वायु शक्ति 2024**
☞ वायुसेना द्वारा पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में सम्पन्न हुए दिन-रात के वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, सुखोई-30, चिनूक और अपाचे सहित कुल 121 विमान सम्मिलित थे. इसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया. ऐसा पिछला अभ्यास 16 फरवरी, 2019 को हुआ था.

अन्तर्राष्ट्रीय

1. वर्ल्ड गवर्नमेंटस सम्मिट (World Governments Summit) 12–14 फरवरी, 2024 को कहाँ आयोजित की गई ? ***–दुबई***

☞ शिखर सम्मेलन में 20 वैश्विक नेताओं की भागीदारी रही. इनमें 10 राष्ट्रपति और 10 प्रधानमंत्री शामिल हैं. वैश्विक सभा में 120 से अधिक देशों की सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी, 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया तथा 'भविष्य की सरकारों को आकार देना' विषय पर मुख्य भाषण दिया.

2. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस (IOC) में 9-10 फरवरी, 2024 को कहाँ सम्मिलित हुए ? ***–पर्थ, आस्ट्रेलिया***

☞ 7वें सम्मेलन का विषय 'स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर' था. हिन्द महासागर सम्मेलन (आईओसी) एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो वर्ष 2016 में सिंगापुर में शुरू हुआ था.

3. ब्रांड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स-2024 में भारत के किस उद्योगपति को विश्व में दूसरा तथा भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है ? ***–मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड)***

☞ रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 (Brand Guardianship Index 2023) में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है. मुकेश अंबानी इस सूचकांक में भारत में पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर हैं.

4. किस राष्ट्र ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा को क्षमा करते हुए फरवरी 2024 में मुक्त कर दिया ? ***–कतर***

☞ भारतीय नौसैनिकों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे भारत के अनुरोध पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार अब इन्हें रिहा कर दिया गया है तथा 7 नौसैनिक 12 फरवरी, 2024 को भारत वापस आ गए हैं.

5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है ? ***–निमहांस (NIMHANS), बेंगलूरू***

☞ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बेंगलूरू, कर्नाटक में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो सांइसेज (NIMHANS) को 2019 में स्थापित नेल्सन मंडेला अवार्ड देने की घोषणा की है.

6. भारत की डिजिटल पेमेंट सुविधा यूपीआई (UPI) का प्रयोग फरवरी 2024 में किन देशों में प्रारम्भ की गई ? ***–फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका***

☞ भारत के पेमेंट सिस्टम यूनीफाइड पेमेंटस इंटरफेस (UPI) को औपचारिक रूप से फरवरी 2024 में पहले फ्रांस में एफिल टॉवर पर प्रारम्भ किया गया. 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका प्रारम्भ किया.

7. फरवरी 2024 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की टीम को हराकर किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता रही ? ***–आस्ट्रेलिया***

☞ आस्ट्रेलिया की टीम ने गत चैम्पियन भारत की टीम को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में 11 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में 79 रनों से हराकर विश्व कप जीत लिया.

8. चीन ने अंटार्कटिका में अपने किस नवनिर्मित अनुसंधान स्टेशन पर 7 फरवरी, 2024 को कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? ***–किनलिंग (Qinling)***

☞ चीन ने अंटार्कटिका के पैसिफिक ओशन सेक्टर में अपना नया अनुसंधान स्टेशन किनलिंग स्थापित किया है. यह जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी वातावरण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुसंधान करेगा.

9. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी, 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिन्दू मंदिर का उद्घाटन किया ? ***–संयुक्त अरब अमीरात (UAE)***

☞ बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) हिन्दू मंदिर, जो संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारम्परिक हिन्दू पत्थर मंदिर है, दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास, अबू मुरीख में स्थित है. यह लगभग 27 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसे 2019 से बनाया जा रहा है. संयुक्त अरब अमीरात में तीन अन्य हिन्दू मंदिर हैं, जो दुबई में स्थित हैं.

10. चीन में लूनर वर्ष 2024 वहाँ की व्यवस्था, संस्कृति और परम्परा के अनुसार किस जानवर का वर्ष है ? ***–ड्रैगन (Dragon)***

☞ ड्रैगन वर्ष 10 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ होकर 28 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा. चीनी भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2024 में अवसर, परिवर्तन और चुनौतियाँ आने का अनुमान है. चीनी संस्कृति में ड्रैगन एक शुभ और असाधारण प्राणी के रूप में जाना जाता है.

11. रूस में जेल में बंद पुतिन सरकार के किस अत्यधिक विरोधी नेता का निधन समाचार-पत्रों के अनुसार 16 फरवरी, 2024 को हो गया ? ***–एलेक्सी नेवेलनी (Alexei Navalny)***

☞ 47 वर्षीय एलेक्सी नेवेलनी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर का खुलकर विरोध किया तथा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे. सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था. नेवेलनी सखारोव प्राइज से सम्मानित थे.

12. जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने 17 फरवरी, 2024 को अपने किस रॉकेट के मॉडल का सफल परीक्षण किया ? ***–एच 3 (H 3)***

☞ अधिक पेलोड क्षमता (6·5 मीट्रिक टन) एवं कम कीमत में प्रक्षेपण करने में सक्षम एच 3 रॉकेट का यह दूसरा परीक्षण है, पहला परीक्षण असफल रहा था. 2025 में इस एच 3 का भारत के साथ मिलकर संयुक्त लूनर प्रोजेक्ट लूपेक्स प्रस्तावित है.

13. 15 फरवरी, 2024 के समाचारों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान को पीछे छोड़ कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया ? ***–जर्मनी***

☞ विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान अमरीका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी एवं चौथा स्थान जापान का हो गया है. भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

14. किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाने के लिए एक विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया गया ? ***–ग्रीस (Greece)***

☞ ग्रीस की संसद में कानून पर, 300 सांसदों में से 176 ने प्रस्ताविक कानून को पक्ष में वोट दिया, जबकि 76 सांसद इस कानून के खिलाफ थे. ग्रीस अब विवाह समानता स्थापित करने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है.

15. 18 फरवरी, 2024 को मलेशिया में खेले गए महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता ? ***–भारत***

☞ भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाइलैंड की टीम को हराकर इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता. भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का इस टूर्नामेंट में यह पहला गोल्ड मेडल है. ●●●

विश्व परिदृश्य

✍ डॉ. अरुणोदय बाजपेयी

भारत और बांग्लादेश सम्बन्ध : सम्भावनाएं व चुनौतियाँ

दक्षिण एशिया में भारत की चुनौतियाँ कम नहीं हो रही है. भारत ने अपने पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए 2014 में 'पड़ोस पहले' (Neighbourhood First) की नीति का आरम्भ किया था. इस नीति के बावजूद दक्षिण एशिया में भारत के छोटे पड़ोसी देशों का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है. भारत की पड़ोस नीति की असफलता में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक व आर्थिक उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारण है. गत दो दशकों में चीन ने दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों को भारत के विरुद्ध एक प्रभावी विकल्प प्रदान कर दिया है. पाकिस्तान तो पहले से चीन का हर मौसम का मित्र देश है. हाल के वर्षों में श्रीलंका, नेपाल तथा मालदीव भी चीन के समारिक साझेदार बन गए है. हालाँकि, चीन बांग्लादेश में भी अपना सामरिक व आर्थिक प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वहाँ चीन को वांछित सफलता नहीं मिली है. बांग्लादेश की सत्ता में काबिज अवामी लीग तथा उसकी नेता शेख हसीना वाजेद के साथ बांग्लादेश की आजादी से ही विशेष सम्बन्ध रहे हैं. शेख हसीना बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्ररहमान की बेटी है. शेख मुजीबुर्ररहमान ने भारत के सहयोग से पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने ही अवामी लीग पार्टी की स्थापना की थी. अतः आज भी अवामी लीग बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत के योगदान को स्वीकार करती है. शेख हसीना कुल पाँचवीं बार तथा निरन्तरता में चौथी बार जनवरी 2024 में सम्पन्न चुनावों में विजयी होकर प्रधानमंत्री बनी है. उनका वर्तमान कार्यकाल जनवरी 2028 तक है. इसके पहले 1996 में प्रधानमंत्री बनी थी तथा 2009 से लगातार प्रधानमंत्री के पद पर कायम है.

भारत ने पाँचवीं बार शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है, लेकिन उनकी जीत विवादों में हुई है. तथ्य यह है कि बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी लगातार तीन बार से चुनावों का बहिष्कार करती रही है. उसकी माँग है कि चुनाव एक स्वतंत्र व निष्पक्ष अन्तिरम सरकार की देख-रेख में कराए जाएं, लेकिन शेख हसीना ने यह शर्त नहीं मानी तथा उन्होंने बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी की भागीदारी के बिना ही चुनाव सम्पन्न करा दिए. अमरीका तथा उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश में इन चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष नही माना. अमरीका तो पहले ही मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर बांग्लादेश के विरुद्ध 2023 में प्रतिबन्धों की घोषणा कर चुका है. भारत बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है, लेकिन इस मामले में भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है. ऐसी स्थिति में भारत को पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करना कठिन होता जा रहा है. उधर चीन अमरीका के प्रतिबन्धों का विरोध कर रहा है तथा वह इस मामले में अमरीका तथा पश्चिमी देशों की आलोचना भी कर चुका है. दूसरा भारत को इस बात की भी चिन्ता है कि जब भी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होगा, तो भारत बांग्लादेश के सम्बन्ध तनावपूर्ण होंगे. इसका कारण यह है कि बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान व चीन की समर्थक पार्टी मानी जाती है. इसमें कतिपय इस्लामिक अतिवादी तत्व भी शामिल है, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया था.

भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति

बांग्लादेश में 2009 से लगातार अवामी लीग के शासन काल में भारत व बांग्लादेश के सम्बन्धों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इस अवधि में सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ. 2011 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बांग्लादेश की यात्रा की थी. इस यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि दोनों देशों ने लम्बे समय से लम्बित अन्तःक्षेत्रों के आदान-प्रदान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. बाद में 2015 प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद से सम्बन्धित अन्तःक्षेत्रों (Enclaves) के हस्तांतरण के समझौता को पूरा कर लिया. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2017 तथा 2022 में भारत की महत्वपूर्ण यात्राएं की थी. इसके बाद 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा नौ अतिथि देशों को आमंत्रित किया गया था. इसमें दक्षिण एशिया से एक मात्र देश बांग्लादेश को आमंत्रित किया गया था. अतः सितम्बर 2023 में जी-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए शेख हसीना ने भारत की यात्रा की थी. यह घटना दोनों देशों के बीच सम्बन्धों की गहराई को प्रमाणित करती है.

उक्त उच्च स्तरीय यात्राओं के द्वारा दोनों के पारस्परिक लाभकारी सम्बन्धों को मजबूती देने में मदद मिली है. इसके अलावा दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख विकास साझीदार भी बन गया है. भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को देखते हुए बांग्लादेश ने भी चीन से सामरिक दूरी बनाए रखने की कोशिश की है. वर्ष 2020 में बांग्लादेश ने भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में चीन द्वारा सोनादिया पोर्ट के विकास का समझौता रद्द कर दिया था. इससे चीन को बांग्लादेश में सामरिक पहुँच बनाने के प्रयासों को झटका लगा था.

भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति

1. सम्पर्कता को प्राथमिकता–भारत व बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किमी लम्बी सीमा है, जो भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगती सीमाओं में सबसे लम्बी है. दूसरा बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बांग्लादेश से होकर अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बेहतर सम्पर्कता स्थापित कर सकता है. वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों से सम्पर्क स्थापित करने का एकमात्र संकरा थलमार्ग दार्जलिंग से होकर (चिकन नेक) गुजरता है. पुनः सम्पर्कता व्यापार, निवेश तथा विकास में भी सहायक है. इसी लिए दोनों देश अपने सम्बन्धों में सम्पर्कता के विकास पर विशेष जोर दे रहे हैं. वर्तमान में दोनों देशों के बीच कई बस व रेलवे सेवाएं कार्यरत् हैं. इनमें 1999 से चालू कोलकाता-ढाका बस सेवा तथा 2001 से कार्यरत् ढाका-अगरतला बस सेवा प्रमुख हैं. इसके अलावा दोनों देशों के बीच 2008 से कोलकाता व ढाका के बीच मैत्री रेल सेवा, 2017 से कोलकाता व खुलना के बीच बन्धन रेल सेवा तथा 2021 से जलपाईगुड़ी व अखूरा के बीच मिताली रेल सेवा कार्यरत् है. नवम्बर 2023 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अगरतला-अखूरा रेलवे लाइन का उद्घाटन किया हैं, जो कई दशकों से बन्द पड़ी थी.

दोनों देशों के बीच पहले से कई सम्पर्कता परियोजनाओं पर काम चल रहा है. दोनों देशों

ने 2022 में कतिपय रेल सम्पर्कता प्रोजेक्ट जैसे–कौनिया-न्यू गीतलदाहा लिंक लाइन, हिल्ली-बीरमपुर रेल लाइन, कतिपय रेलवे लाइनों का उन्नतीकरण तथा सिराजगंज कान्टेनर डिपो का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की गई. भारत ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि वह बांग्लादेश को अपनी भूमि से निःशुल्क निर्यात की इजाजत देगा.

दोनों देशों ने भारत की सहायता से मोंगला व चिटगाँव बन्दरगाहों के विकास के कार्य पर सन्तोष व्यक्त किया तथा आशा व्यक्त की है कि जल्दी ही इन बन्दरगाहों को पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया जाएगा. इसके अलावा दोनों देशों ने अन्य उपक्षेत्रीय सम्पर्कता परियोजनाओं विशेषकर प्रस्तावित बांग्लादेश-भूटान-इण्डिया-नेपाल (BBIN) सड़क मार्ग परियोजना को यथा शीघ्र मूर्तरूप देने पर सहमति व्यक्त की है. भारत ने बांग्लादेश से यह भी अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल के हिली से अपने क्षेत्र से होकर मेघालय के महेन्द्रगंज तक सड़क मार्ग के विकास हेतु सहमति प्रदान करे.

2. व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी– उल्लेखनीय है कि भारत एशिया में बांग्लादेश के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार बन गया है. बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत खाद्य पदार्थों जैसे–चावल, गेहूँ, प्याज आदि की आपूर्ति कर रहा है. द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों देशों ने कस्टम स्टेशनों तथा बंदरगाहों पर ढाँचागत सुविधाओं को बढ़ाने तथा व्यापार पर लगे गैर-टैरिफ प्रतिबन्धों को शिथिल करने का प्रयास किया है. दोनों देश व्यापार व निवेश को बढ़ाने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं. भारत ने विकास साझेदारी के अन्तर्गत बांग्लादेश में कई विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है.

3. सीमा प्रबन्धन–भारत व बांग्लादेश की लम्बी सीमा कई जगहों पर खुली तथा प्राकृतिक बाधाओं से युक्त है. इसका प्रबन्धन करना एक कठिन कार्य है. दोनों देशों ने सीमा पर बचे हुए फेन्सिंग कार्य को पूरा करने तथा जीरो लाइन के 150 गज की दूरी तक विकास कार्यों को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों देशों ने सीमा पर नशीली दवाओं व अन्य वस्तुओं के अवैध व्यापार तथा मानव तस्करी के विरुद्ध सक्रिय साझा प्रयासों को मजबूत कर रहे हैं. इसी सन्दर्भ में दोनों देशों ने आतंकवाद तथा उग्रवाद को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है. बांग्लादेश ने वहीं निवास कर रहे भारत के अतिवादी नेताओं को पहले ही भारत को प्रत्यर्पित कर दिया है.

4. जल संसाधनों का बँटवारा–गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के अलावा अन्य कई साझा नदियाँ दोनों देशों के बीच बहती हैं. अतः जल संसाधनों का बँटवारा दोनों देशों के सम्बन्धों में एक प्रमुख मुद्दा है. गंगा नदी के जल बँटवारे को लेकर 1996 में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था. 2011 में दोनों देशों तीस्ता नदी के जल बँटवारे को लेकर एक समझौता तैयार किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण बांग्लादेश के बार-बार अनुरोध के बावजूद इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं, लेकिन 2022 में लम्बे समय बाद कुशियारा नदी के जल बँटवारे को लेकर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. दूसरी तरफ भारत ने त्रिपुरा राज्य की सिचाई आवश्यकता के लिए पानी की आपूर्ति हेतु दोनों देशों के बीच फेनी नदी पर समझौते के लिए बांग्लादेश से अनुरोध किया है. फिर भी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे की माँगों पर सकारात्मक रुख अपनाने पर सहमति व्यक्त की है.

5. ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग–उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश अपनी इनर्जी आवश्यकताओं के लिए भारत पर निर्भर है. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इनर्जी सेक्टर में उप-क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया. दोनों देशों ने आपस में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के विकास पर बल दिया. दोनों देशों ने पहले से प्रस्तावित कटिहार (बिहार)–पार्बतीपुर (बांग्लादेश)–बोरनगर, (असम) बिजली ट्रांसमिशन लाइन के शीघ्र पूरा करने पर बल दिया. इस लाइन के पूरा हो जाने के बाद बांग्लादेश में बिजली की कमी को पूरा किया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि दोनों देश वर्तमान में इंडिया-बांग्लादेश फ्रेंडशिप तेल पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा भारत से बांग्लादेश को तेल की आपूर्ति की जा सकेगी. दोनों नेताओं ने इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की.

6. क्षेत्रीय मुद्दे–दोनों नेताओं ने कतिपय क्षेत्रीय विषयों पर भी विचार-विमर्श किया. दोनों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है. भारत ने बांग्लादेश द्वारा बिम्सटेक संगठन का सचिवालय स्थापित करने के लिए आभार व्यक्त किया. भारत ने इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश का सहयोग करने का आश्वासन दिया.

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण

दोनों देशों के बीच तनाव के कतिपय मुद्दे निम्नलिखित हैं–

1. सीमा प्रबन्धन तथा भारत में अवैध बांग्लादेशी नागरिक–भारत के विभिन्न राज्यों में बांग्लादेश से आए अवैध नागरिकों का निवास भी दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण माना जाता है. 3 वर्ष पूर्व असम में नेशलन नागरिक रजिस्टर की गणना में पाया गया था कि वहाँ बांग्लादेश से आए 29 लाख व्यक्ति अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता है. वर्तमान सीमा का प्रबन्धन भी कई बार दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन जाता है. इसका तात्कालिक कारण यह होता है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति कई बार भारत के सीमा रक्षक बलों द्वारा मार दिए जाते हैं अथवा घायल कर दिए जाते हैं.

2. तीस्ता नदी का जल बँटवारा–बांग्लादेश अपने उत्तरी क्षेत्रों में सिचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तीस्ता नदी के जल बँटवारे पर समझौता करने का निरन्तर अनुरोध करता रहता है. वर्ष 2011 में इस समझौते का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी के विरोध के कारण यह समझौता आजतक हस्ताक्षरित नहीं हो पाया. परिणामस्वरूप बांग्लादेश ने अपने उत्तरी क्षेत्र में जल संसाधनों के संचयन के लिए चीन से सहायता की गुहार की है. चीन सदैव इस प्रकार के अवसर की तलाश में रहता है. यह स्थिति दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों के लिए उचित नहीं मानी जा सकती है.

3. अल्पसंख्यक हिन्दुओं के प्रति हिंसा–बांग्लादेश में इस्लामिक उग्रवाद की निरन्तर वृद्धि हो रही है. इसके कारण वहाँ रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा व भेदभाव की घटनाएं निरन्तर होती रहती हैं. इससे भारत में चिन्ता उत्पन्न होना स्वाभाविक है, यद्यपि औपचारिक तौर पर बांग्लादेश की सरकार हिन्दू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए सदैव वचनबद्ध है.

निष्कर्ष–भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध वर्तमान में सकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं. दोनों देशों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे है. वास्तव में प्राचीन काल से ही बांग्लादेश भारत का अंग रहा है. बांग्लादेश के साथ सम्पर्कता का भारत के लिए सामरिक महत्व है. भारत अपने उत्तरी-पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाले दार्जलिंग गलियारे पर चीन को लेकर चिन्तित है. इसी लिए भारत बांग्लादेश के रास्ते उत्तर-पूर्व राज्यों के साथ सम्पर्कता का विकास कर रहा है. बांग्लादेश सार्क तथा बिम्सटेक दोनों का सदस्य है तथा वैश्विक मामलों में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है. दोनों देशों में तनाव के कतिपय मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के सम्बन्धों का वर्तमान समय में उज्ज्वल भविष्य है.

भारत की हिन्द महासागर रणनीति

हिन्द महासागर की सुरक्षा एक बार फिर चर्चा में है. दिसम्बर तथा जनवरी 2023-24 में यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल द्वारा गाजा पर किए जा रहे आक्रमण के विरोध में हिन्द महासागर के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से में व्यापारिक जहाजों के आवागमन की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. भारत का व्यापार भी इस घटना से प्रभावित है. भारत आ रहे एक व्यापारिक पोत को भी क्षतिग्रस्त किया गया है. भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए अपनी नौसेना की एक टुकड़ी इस क्षेत्र में तैनात की है. सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्री डकैती की चुनौती पहले से विद्यमान है. वस्तुतः भारत की सुरक्षा तथा विकास दोनों के लिए हिन्द महासागर बहुत महत्वपूर्ण है. हिन्द महासागर का भारत की सुरक्षा व विकास में ऐतिहासिक महत्व रहा है. हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर तथा अटलांटिक महासागर के बाद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है. इसका क्षेत्रफल लगभग 70·56 वर्ग किमी है तथा पृथ्वी के कुल समुद्री भाग के क्षेत्रफल का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा हिन्द महासागर द्वारा आच्छादित है. इस क्षेत्र को हिन्द महासागर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. हिन्द महासागर की तटीय सीमा 38 देशों के साथ लगती है, जो विश्व की 37 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन सभी देशों का सामूहिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद विश्व के कुल उत्पाद का 10 प्रतिशत है. हिन्द महासागर का आर्थिक व सामरिक महत्व है. विश्व के दो-तिहाई समुद्री तेल भण्डार, विश्व के एक-तिहाई गैस भण्डार तथा विश्व के 60 प्रतिशत यूरेनियम भण्डार हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित है. विश्व में पूर्व व पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार के सभी मार्ग हिन्द महासागर से होकर गुजरते है. हिन्द महासागर का सामरिक महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसमें कई संकरे मार्ग (Choke Points) भी स्थित है. हिन्द महासागर में इन संकरे मार्गों की संख्या सात है–पश्चिमी तट पर मोजाम्बिक चैनल, बाब-अल-मंडेब, स्वेज नहर, होरमुज की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर लोम्बोक खाड़ी, सुण्डा की खाड़ी, तथा मलक्का की खाड़ी. इन संकरे मार्गों को नियंत्रित कर हिन्द महासागर में व्यापार मार्गों को अवरुद्ध किया जा सकता है.

भारत के लिए हिन्द महासागर का महत्व

भारत के लिए आर्थिक व सामरिक रूप से हिन्द महासागर का महत्व सर्वविदित है. हिन्द महासागर में भारत की तटीय सीमा 16·6 किमी है. भारत की तटीय व उसके द्वीपों की सुरक्षा हिन्द महासागर में भारत की स्थिति पर निर्भर करती है. भारत के दूर-दराज समुद्र में स्थित द्वीपों जैसे–अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली आदि की सुरक्षा हिन्द महासागर में भारत की स्थिति पर ही नियंत्रण करती है. हिन्द महासागर में अपने प्रभुत्व के कारण ही ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय देश भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो सके थे. सुरक्षा की कतिपय नई चुनौतियाँ भी है. इनमें आतंकवाद, समुद्री डकैती (Piracy), नशीली दवाओं तथा हथियारों का अवैध व्यापार, समुद्र का बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं आदि प्रमुख हैं. 2008 में भारत के मुम्बई शहर के ताज होटल में जो आतंकवादी हमला हुआ था. उसमें आतंकवादी समुद्री मार्ग से ही भारत आए थे. इस समय अदन की खाड़ी तथा सोमालिया के तट के पास समुद्री डकैती की समस्या निरन्तर बनी हुई है. भारत ने इससे निबटने के लिए 2007 से ही इस क्षेत्र में अपनी नौसेना तैनात की हुई है. अतः व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत की सुरक्षा में हिन्द महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका है. हिन्द महासागर में भारत की प्रभावी उपस्थिति से ही भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है.

भारत का सारा समुद्री व्यापार हिन्द महासागर से ही सम्पन्न होता है. भारत की 75 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हिन्द महासागर के मार्गों से ही होती है. समुद्री मार्गों की सुरक्षा के बिना व्यापार का निर्बाध आवागमन नहीं हो सकता है. हिन्द महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में यमन स्थित हूती अतिवादियों ने आवागमन को खतरा उत्पन्न कर इसकी सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कर दिया है. यमन के हूती विद्रोही गाजा पर इजरायली आक्रमण के विरोध में व्यापारिक जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं. इन व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए भारत को अलग से अपनी नौसेना के जहाजों को तैनात करना पड़ा है.

इसके अलावा हिन्द महासागर में तेल, गैस तथा पालीमेटालिक नोड्यूल के रूप में अनेक बहुमूल्य धातुओं तथा मछली तथा अन्य समुद्री जीवों का भण्डार है. हिन्द महासागर के इसी सामरिक तथा आर्थिक महत्व को देखते हुए अमरीका के 19वीं शताब्दी के महान् सामरिक विचारक अल्फ्रेड माहॅन ने कहा था कि जो भी हिन्द महासागर पर नियंत्रण करता है उसका एशिया पर नियंत्रण होगा. 21वीं शताब्दी में विश्व के भविष्य का निर्धारण हिन्द महासागर में नियंत्रण पर निर्भर करेगा.

हिन्द महासागर में चीन की घुसपैठ तथा अन्य चुनौतियाँ

भारत हिन्द महासागर क्षेत्र व दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति है तथा इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) है. आजादी के बाद भारत ने निरन्तर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन गत दो दशकों से चीन इस क्षेत्र में अपने सामरिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया है. हिन्द महासागर में जहाँ उसने पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह को 40 वर्षों के लिए पट्टे पर ले रखा है वहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा बन्दरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर प्राप्त कर लिया है. इसके अलावा चीन म्यांमार में क्याउकपियू बन्दरगाह का विकास कर रहा है. मालद्वीप में मोइजू की नई सरकार आने के बाद एक बार फिर चीन का सामरिक प्रभाव बढ़ गया है. चीन ने मालदीव के कतिपय द्वीपों को मालदीव की पूर्व अब्दुल्ला यामीन सरकार के शासन (2013–18) के दौरान ही मालदीव के कतिपय द्वीपों को लीज पर प्राप्त कर लिया है. उसने हिन्द महासागर के उत्तर-पश्चिम में स्थित देश मजबूती में अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया है. चीन अपनी रणनीति के अन्तर्गत हिन्द महासागर में अपना प्रभाव निरन्तर बढ़ा रहा है. 1990 के दशक में उसने यह कार्य भारत के चारों ओर स्थित देशों में नौसैनिक सुविधाओं को प्राप्त कर सम्पन्न किया था. इसे चीन की मोतियों की माला नीति (String of Pearls) के नाम से जाना जाता है. चीन द्वारा भारत को घेरने तथा हिन्द महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने को कार्य 2013 से लागू उसकी बी.आर.आई. परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है. चीन ने विगत 2 वर्षों में शोध के नाम पर हिन्द महासागर में अपने टोही पोतों की तैनाती भी शुरू कर दी है. अगस्त 2002 में चीन के युवांग वांग 5 नामक रिसर्च पोत ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बन्दरगाह में 2 दिन की यात्रा की थी इसी तरह अगस्त 2023 में चीन के एक अन्य रिसर्च पोत शी यान 6 को श्रीलंका के कोलम्बो बन्दरगाह में डाक करने के अनुमति प्रदान की थी, लेकिन भारत के विरोध के कारण बाद में श्रीलंका ने चीनी पोतों को एक वर्ष के बाद यह सुविधा न देने की घोषणा की थी. वर्तमान में चीन के इस रिसर्च पोत ने मालदीव में अपनी पहुँच बना ली है, क्योंकि वहाँ पर नवम्बर 2023 से चीन समर्थित मोइजू सरकार सत्ता में है. चीन की सामरिक घुसपैठ के अलावा हिन्द महासागर में आतंकवाद समुद्री डकैती, प्रदूषण, अवैध व्यापार आदि की चुनौतियाँ निरन्तर मौजूद हैं.

भारत की हिन्द महासागर रणनीति

हिन्द महासागर में भारत के लिए चीन की घुसपैठ सहित अन्य चुनौतियाँ बनी हुई है, लेकिन हिन्द महासागर में अपने महत्वपूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए भारत इन चुनौतियों के प्रति सजग है. भारत ने हिन्द महासागर में अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए 3 स्तर की रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है. इस रणनीति के 3 आयाम निम्नलिखित हैं–

(अ) नौसैनिक क्षमता का विकास–भारत की हिन्द महासागर में रणनीति का पहला आयाम चुनौतियों के हिसाब से अपनी नौसैनिक क्षमता का विकास करना है. वर्ष 2004 में भारत की नई मैरीटाइम नीति घोषित की गई जिसके अन्तर्गत भारतीय हितों को देखते हुए भारतीय नौसेना का कार्यक्षेत्र हिन्द महासागर के साथ ही प्रशान्त महासागर तक विस्तारित किया गया. भारत ने अपनी नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रान्त का निर्माण किया है. इस विमान के लिए अलग से जेट विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ बातचीत का क्रम जारी है. भारत ने स्वयं कई विध्वंसक पोतों का विकास किया है. भारत द्वारा प्रोजेक्ट 75 के अन्तर्गत 5 आधुनिक पनडुब्बियों का विकास किया है तथा आधुनिक तकनीकी से लैस टोही विमानों का आयात अमरीका से किया जा रहा है. इस प्रकार अपनी नौसेना को 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के हिसाब से विकसित करने का प्रयास किया है. हूती विद्रोहियों की चुनौती का सामना करने के लिए 2024 जनवरी में भी इस क्षेत्र में विध्वंसक पोतों की तैनाती की गई है. इस प्रकार भारत हिन्द महासागर में एक सुरक्षा-प्रदाता देश के रूप में कार्य कर रहा है तथा उसी हिसाब से अपनी नौसैनिक क्षमता का विकास कर रहा है.

(ब) क्षेत्रीय सहयोग व समन्वय–भारत की हिन्द महासागर में रणनीति का दूसरा आयाम सुरक्षा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है. भारत ने अपनी कई पहलों के माध्यम से हिन्द महासागर में अपनी क्षेत्रीय रणनीति को लागू किया है. इनमें से कुछ पहलों का उल्लेख निम्नवत् है–

1. भारत ने 2011 में श्रीलंका तथा मालदीव के साथ मिलकर कोलम्बो सुरक्षा कानक्लेव नामक सुरक्षा मंच की स्थापना की थी बाद में इसमें मॉरिशस को भी शामिल कर लिया गया है. इस सहयोग का मंच का प्रमुख उद्देश्य समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन देशों के मध्य सहयोग को मजबूत करना है.

2. सागर परियोजना (SAGAR—Security and Growth for All in the Region)–वर्ष 2015 में आरम्भ की गई इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत शांति व स्थिरता की स्थापना करना चाहता है. इसके अन्तर्गत समुद्री सुरक्षा, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम तथा इस क्षेत्र के जीवन्त विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है.

3. आई.एफ.सी.–आई.ओ.आर. (IFC–IOR)–वर्ष 2018 में भारतीय नौसेना ने इन्फारमेशन फ्यूजन सेण्टर फार इण्डियन ओशन रीजन की स्थापना की थी. इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य हिन्द महासागर में वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं व गतिविधियों को एकत्र कर उसे सहयोगी देशों के साथ साझा करना है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा सके. यह केन्द्र भारत के गुरुग्राम शहर में स्थित है.

4. इण्डियन ओशन नावल सिम्पोजियम–भारत द्वारा इसकी स्थापना 2008 में की गई थी. यह एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें समुद्री सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर सहयोगी देशों के बीच विचार-विमर्श किया जाता है.

5. इण्डो-पैसिफिक ओशन एनिशिएटिव (IPOI—Indo-Pacific Ocean Initiative)–इस स्थापना 2019 में भारत द्वारा की गई थी. इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की सुरक्षा व विकास के लिए क्षेत्रीय देशों में सहयोग को बढ़ाना है.

6. इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association)–हिन्द महासागर के तटीय देशों के द्वारा 1997 में इस संगठन की स्थापना की गई थी. भारत इसका सक्रिय सदस्य है. इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों तथा टिकाऊ विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है. यह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है तथा ओपेन रीजनलिज्म के सिद्धान्त पर आधारित है.

(स) वैश्विक सहयोग–हिन्द महासागर में भारत की रणनीति का तीसरा आयाम समान विचारधारा वाले देशों के बीच इस क्षेत्र में शांति व स्थायित्व के लिए सहयोग को बढ़ाना है. भारत तथा तीन देशों–अमरीका, जापान तथा आस्ट्रेलिया ने 2017 में हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में एक खुली व नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से क्वाड (QUAD) की स्थापना की थी. क्वाड अब नियमित आधार पर प्रतिवर्ष अपने शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है. अब तक इसके 5 सम्मेलन आयोजित हो चुके है. क्वाड हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण उत्पन्न अस्थिरता के स्थान पर एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं. चीन ने क्वाड की आलोचना की है. क्वाड की स्थापना से इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता व उसके बढ़ते सामरिक प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी.

निष्कर्ष–इसमें कदापि सन्देह नहीं है कि हिन्द महासागर भारत की सुरक्षा तथा उसके विकास में हिन्द महासागर की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है. इसके साथ ही भारत इस क्षेत्र में न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है वरन् सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) है. भारत वर्तमान में विश्व पटल पर एक उभरती हुई शक्ति भी है. अतः भारत के लिए यह अपरिहार्य है कि अपने वैध हितों की रक्षा के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखें. हिन्द महासागर में पहले से आ रही समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ जैसे–समुद्री डकैती, आतंकवाद, प्रदूषण आदि आज भी विद्यमान है, लेकिन भारत के लिए चिन्ता की सबसे बड़ी बात हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती हुई सामरिक घुसपैठ है. 1990 के दशक में चीन ने अपनी मोतियों की माला रणनीति के तहत् भारत को घेरने की कोशिश की थी. वर्तमान में 2013 से चीन यही कार्य अपनी महत्वाकांक्षी योजना बी.आर.आई. के माध्यम से कर रहा है. चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों जैसे–म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव तथा पाकिस्तान में नौसैनिक सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं.

भारत हिन्द महासागर में अपने व्यापक हितों की रक्षा के लिए तीन आयामों वाली रणनीति को क्रियान्वित कर रहा है. इसके प्रथम आयाम में देश की नौसैनिक क्षमता का विकास करना है. दूसरे आयाम में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाकर हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को मजबूत बनाना है. इस रणनीति के तीसरे आयाम के रूप में भारत इस क्षेत्र में खुली व नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के मध्य वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. भारत की त्रि-आयामी नीति को सफलता भी मिल रही है. भारत हिन्द महासागर में समुद्री डकैती तथा हूती विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सफल अभियान का संचालन कर रहा है. यह रणनीति हिन्द महासागर में भारत के व्यापक हितों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रही है.

●●●

फोकस 1

भारतीय चुनाव प्रणाली : सुधार की आवश्यकता

✍ डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान

अप्रैल-मई 2024 में 18वीं लोक सभा तथा आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम विधान सभाओं के आम चुनाव होने जा रहे हैं. यदि स्थितियाँ सामान्य रहीं, तो इन्हीं के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर विधान सभा के लिए भी चुनाव कराए जा सकते हैं. निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण तरीके से मतदान कराना तथा इसके माध्यम से बिना किसी रक्तपात के शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन कराना, भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार तथा कानून एवं व्यवस्था के संरक्षक राज्यों के लिए एक गम्भीर चुनौती है. चुनाव किसी भी लोकतन्त्र के लिए एक सर्वाधिक सशक्त तत्व है तथा जब तक चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते रहते हैं, तब तक राष्ट्र में ईमानदार जनप्रतिनिधित्व कायम रहता है. विश्व के सबसे बड़े एवं सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली वाला देश भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि केन्द्र एवं राज्यों में यदि विगत 73 वर्षों में शान्तिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तान्तरण हुआ है, तो इसका श्रेय मुख्य रूप से भारत की निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली को जाना चाहिए.

भारतीय चुनाव प्रणाली की कतिपय कमजोरियाँ

भारत के विशाल भौगोलिक आकार तथा भारत की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक-सांस्कृतिक विविधताओं के सन्दर्भ में चुनाव प्रणाली में समय-समय पर किए गए सुधारों से यह उत्तरोत्तर सुदृढ़ हुई है, लेकिन इसमें आज भी अनेक कमजोरियाँ दृष्टिगोचर होती हैं. सामान्यतया भारत की निर्वाचन प्रणाली निम्नलिखित कमजोरियों से ग्रसित है–

कम मतदान प्रतिशत के साथ विधायिका में ईमानदार और वास्तविक प्रतिनिधित्व का अभाव–मतदान का औसत 55–65 प्रतिशत के बीच रहता है. इसका अर्थ है कि 45–35 प्रतिशत जनता की राष्ट्रीय राजनीति और नीतियों के निर्धारण में कोई भूमिका ही नहीं है.

राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों पर से उठता विश्वास–भारत के राजनीतिज्ञों पर से आम आदमी का विश्वास डगमगाने लगा है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स तथा नेशनल इलेक्शन वाच द्वारा सन् 2014 और उसके बाद के निर्वाचनों में विजयी सांसदों/विधायकों की सम्पत्तियों तथा उनके विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामलों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है. उसके अनुसार 543 सांसदों में से 34 प्रतिशत (184) के विरुद्ध न्यायालयों में आपराधिक वाद लम्बित हैं, 76 सांसद हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण एवं चोरी जैसे गम्भीर अपराधों में आरोपी हैं.

उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा (2022) के लिए सम्पन्न चुनावों में निर्वाचित कुल 403 विधायकों में से 205 विधायकों के विरुद्ध न्यायालयों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार जीतने वाले 39 प्रतिशत विधायकों (158) के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे जघन्य अपराध के मामले न्यायालयों में लम्बित हैं. निर्वाचित विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के 90 विधायक (35%), समाजवादी पार्टी के 111 विधायक (43%), राष्ट्रीय लोकदल के 5 (62·5%), सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 4 (66·66%), निषाद पार्टी के 4 (66·66%), अपना दल के 2 (22·22%) विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है.

नवम्बर-दिसम्बर 2023 में सम्पन्न 5 राज्यों–मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुल निर्वाचित 678 विधायकों में से 37% विधायकों (253) के विरुद्ध न्यायालयों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. मध्य प्रदेश के 39%, छत्तीसगढ़ के 19%, राजस्थान के 31%, तेलंगाना के 69% और मिजोरम के 7·5% विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड है.

राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधियों का राजनीतिकरण–भारतीय राजनीति का विद्रूपयुक्त चेहरा यह बताता है कि अपराधियों के चुनाव न लड़ने पर कोई रोक न होने के कारण हत्या, अपहरण, आगजनी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त लोग भी केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने में सफल हो जाते हैं कि मामला न्यायालय में लम्बित है. न्यायप्रणाली की विडम्बना यह है कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की न्यायिक प्रक्रिया में 20 से 30 वर्ष तक का समय लग जाता है.

सर्वाधिक खर्चीली चुनाव प्रणाली–भारत की निर्वाचन प्रणाली को सर्वाधिक खर्चीला माना जाता है. लोक सभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को ₹ 2 करोड़ से ₹ 10 करोड़ तक का खर्चा उठाना पड़ता है.

स्पष्ट है कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की जाती है और यह सारा-का-सारा धन काला धन होता है.

राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चन्दे में अपारदर्शिता–यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि भारत के औद्योगिक घराने सभी बड़े राजनीतिक दलों को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का चन्दा देते हैं. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) के एक विश्लेषण के अनुसार– राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाले चन्दे का 87 प्रतिशत उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों से आता है. इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि राजनीतिज्ञों एवं व्यावसायिक जगत् के कर्ता-धर्ताओं के बीच गहरी साँठगाँठ है. कानूनन भारत के राजनीतिक दल विदेशी कम्पनियों से चन्दा नहीं ले सकते. अब एनडीए सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 को संशोधित करके राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी कम्पनियों से चन्दा लेने को वैधता प्रदान कर दी है. इतना ही नहीं अब राजनीतिक दलों द्वारा 5 अगस्त, 1976 के बाद विदेशी कम्पनियों से लिए गए चन्दों की जाँच भी नहीं की जा सकेगी. 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले से राजनीतिक दल विदेशी कम्पनियों से लिए गए चन्दे के मामलों में जाँच के घेरे में थे.

राजनीतिक दलों द्वारा बैंकिंग चैनल से चंदा लेने के लिए 2 जनवरी, 2018 को 'चुनावी बॉण्ड योजना' अधिसूचित की गई थी तथा दावा किया गया था कि चुनाव सुधारों की दिशा में यह एक बड़ा कदम था. सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड कर रहे थे तथा इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गबई, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र शामिल थे, ने 15 फरवरी, 2024 को सुनाए गए सर्वसम्मत निर्णय से चुनावी बॉण्ड योजना को यह कहते हुए असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया कि इस योजना में चंदा देने वालों के नाम उजागर न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (A) के प्रावधानों का उल्लंघन है. संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों के नाम सहित समस्त विवरण 6 मार्च, 2024 तक भारत निर्वाचन आयोग को दे तथा भारत निर्वाचन आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे. तार्किक, संवैधानिक एवं विधिक रूप से यह

निर्णय उचित प्रतीत होता है और स्वागत किए जाने योग्य है, लेकिन इस निर्णय के बाद राजनीतिक दलों के वित्तीयन में काले धन का प्रयोग बढ़ेगा, जो चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर से अन्धी गली की ओर ले जाएगा.

कालेधन के रूप में लिए गए चन्दे का तो कोई भी राजनीतिक दल लेखा-जोखा ही नहीं रखता. यही कारण है कि लगभग सभी राजनीतिक दल स्वयं को 'सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, 2005' के दायरे में आने का विरोध कर रहे थे. केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने एक निर्णय में सभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों–कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सीपीआई-एम, सीपीआई तथा बहुजन समाज पार्टी को सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आच्छादित होने का निर्णय 3 जून, 2013 को सुनाया था. इस निर्णय के विरुद्ध सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन लाने सम्बन्धी विधेयक का अनुमोदन कर दिया.

मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने की हेराफेरी–राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की शह पर जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जाती है. विरोधी राजनीतिज्ञों के समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए जाते हैं, जबकि सत्तादल के समर्थकों के नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में जोड़ दिए जाते हैं.

सभी उम्मीदवारों को नकारने का मुद्दा–समाजसेवी अन्ना हजारे और उनके समर्थक एक स्वर से यह माँग करते रहे हैं कि मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वे चुनाव में खड़े एक को छोड़कर सभी को नापसन्द करने के स्थान पर 'कोई भी पसन्द नहीं' का भी विकल्प चुन सकें. सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर-दिसम्बर 2013 में सम्पन्न मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा मिजोरम के चुनाव में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (None Of The Above–NOTA) का विकल्प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा बटन के रूप में रखा.

भारत निर्वाचन आयोग अब प्रत्येक निर्वाचन में नोटा का विकल्प रखता है. 2018 में सम्पन्न विधान सभाओं के निर्वाचन में मध्य प्रदेश में 5·42 लाख मतदाताओं (1·4%) ने 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं, का विकल्प चुना. कम-से-कम 12 विधान सभाओं में भारतीय जनता पार्टी की पराजय का मुख्य कारण 'नोटा' रहा, क्योंकि विजयी प्रत्याशी को मिले मतों एवं पराजित भारतीय जनता पार्टी को मिले मतों का अन्तर 'नोटा' में पड़े मतों से कम था. यही स्थिति

चुनाव खर्च की सीमा
(6 जनवरी, 2022 से प्रभावी)
[कण्डक्ट ऑफ इलेक्शन्स (संशोधन) रूल्स 2014 के नियम 90 के तहत्]

क्र.	प्रदेश	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
1.	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, प. बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना	₹ 95 लाख	₹ 40 लाख
2.	नगालैण्ड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़	₹ 95 लाख	₹ 28 लाख
3.	जम्मू-कश्मीर	₹ 95 लाख	₹ 40 लाख
4.	गोवा	₹ 75 लाख	₹ 28 लाख
5.	अरुणाचल प्रदेश	₹ 75 लाख	₹ 28 लाख
6.	मणिपुर एवं मेघालय	₹ 95 लाख	₹ 28 लाख
7.	मिजोरम	₹ 95 लाख	₹ 28 लाख
8.	सिक्किम	₹ 75 लाख	₹ 28 लाख
9.	दिल्ली	₹ 95 लाख	₹ 40 लाख
10.	पुदुचेरी	₹ 75 लाख	₹ 28 लाख
11.	दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप	₹ 75 लाख	—
12.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	₹ 75 लाख	—
13.	चण्डीगढ़, लद्दाख	₹ 75 लाख	—

नोट–राज्य सभा के चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ₹ 40 लाख है.

जमानत राशि (Security Deposit)

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति	*₹ 15,000·00*
लोक सभा निर्वाचन – *सामान्य वर्ग हेतु*	*₹ 25,000·00*
लोक सभा निर्वाचन – *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु*	*₹ 12,500·00*
राज्य सभा – *सामान्य वर्ग हेतु*	*₹ 25,000·00*
राज्य सभा –*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*	*₹ 12,500·00*
राज्य विधान सभा एवं विधान परिषद् – *सामान्य वर्ग हेतु*	*₹ 10,000·00*
राज्य विधान सभा एवं विधान परिषद् – *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*	*₹ 5,000·00*

यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है.

भारत में चुनाव सुधारों से जुड़े कतिपय प्रमुख मुद्दे

- *निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता*
- *राजनीति का अपराधीकरण*
- *अपराधियों का राजनीतिकरण*
- *राजनीतिक दलों में परिवारवाद के प्रभुत्व से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास*
- *सरकारी खर्चे पर लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव*
- *भुगतान आधारित समाचारों का प्रभुत्व*
- *निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार*
- *अनिवार्य मतदान की व्यवस्था*
- *राजनीतिक दलों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत लाना*
- *लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराना*
- *चुनावों में कालेधन का प्रयोग*
- *चुनावों के दौरान हिंसा एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा*
- *चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग*
- *मूक उम्मीदवार (Dummy Candidate) एवं गैर-गम्भीर उम्मीदवार (Non-serious Candidate)*
- *बढ़ता जातिवाद*
- *धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण*

राजस्थान की रही, जहाँ 1·3% मतदाताओं ने 'नोटा' को पसन्द किया. 'नोटा' का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं का प्रतिशत तेलंगाना में 1·1%, छत्तीसगढ़ में 2·1% तथा मिजोरम में 0·5% रहा.

निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार (Right to Recall)– समाज-सेवी अन्ना हजारे और उनके समर्थकों की यह भी माँग है कि मतदाताओं को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि की गतिविधियों से सन्तुष्ट न हों, तो उसकी सदस्यता समाप्त कराने अर्थात् उसे वापस बुला सकें. प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के सिद्धान्त का प्रतिपादन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था.

गैर-गम्भीर सांसदों/विधायकों की बढ़ती संख्या–'जिसकी जितनी संख्या भारी-उतनी उसकी भागीदारी' के सिद्धान्त पर लोक सभा और विधान सभा में ऐसे सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो विधायी कार्यों, आर्थिक-सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति गम्भीर नहीं हैं. इस कटु वास्तविकता का अनुमान सदनों की कार्यवाहियों के दौरान सदस्यों की लगातार घटती संख्या से लगाया जा सकता है. सरकार बचाने या गिराने जैसे मुद्दों पर सदन में मतदान होने के समय उपस्थित रहने के लिए मुख्य सचेतक द्वारा लिखित आदेश की बाध्यता से ही सदस्य सदन में उपस्थित रहते हैं. वह भी केवल हाँ या न का बटन दबाने के लिए या सदन में हल्ला-गुल्ला करने के लिए.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति अविश्वास–2014 में लोक सभा के निर्वाचन 2017 एवं 2022 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के हाथों बुरी तरह से पराजित कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं अन्य क्षेत्रीय दल अपनी पराजय का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ते रहे हैं तथा इसके स्थान पर मतपत्रों के द्वारा मतदान कराए जाने की माँग करते रहे हैं. इनका आरोप है कि इन मशीनों को 'हैक' किया जा सकता है. कोई भी मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में बटन क्यों न दबाए, मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है. दिल्ली एवं पंजाब में आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना (2023 में) में कांग्रेस को इन्हीं मशीनों से कराए गए मतदान से विजयश्री हासिल हुई. इससे ईवीएम को हैक करने का आरोप निराधार सिद्ध हुआ. मतपत्रों के द्वारा मतदान में बूथों पर होने वाले कब्जों, फर्जी मतदान करने की घटनाओं पर तो विराम लगा ही है.

भारत में चुनाव सुधारों की पहल

भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के स्वरूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से आज तक व्यापक बदलाव आया है. विशेष रूप से 1967 के आम चुनावों के बाद से क्षेत्रीयता, जाति एवं वर्ग व्यवस्था के आधार पर कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों के उभार के बाद से लोक सभा एवं विधान सभा ही नहीं वरन् पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायों के चुनाव भी 'किसी भी कीमत' पर जीत लेना ही व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक उम्मीदवार का तथा सामूहिक स्तर पर राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य रहा है. इसी से भारतीय चुनाव प्रणाली में अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है. चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष एवं साफ-सुथरी तथा गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठतर बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं. विभिन्न समितियों/निकायों ने चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं.

- निर्वाचन कानूनों में संशोधन हेतु संयुक्त संसदीय समिति (1971-72)
- वी. एम. तारकुण्डे समिति (1975)
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
- इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)

भारत में चुनाव सुधारों की वास्तविक एवं सर्वाधिक सार्थक पहल तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन द्वारा की गई. उन्होंने भारतीय निर्वाचन प्रणाली में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन किए, जिन्हें उनके उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तरोत्तर और अधिक सशक्त बनाया गया. चुनाव सुधारों में टी. एन. शेषन की पहल निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित रही–

- भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करना.
- चुनावों के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियन्त्रण.
- राज्यों में केन्द्र के अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती एवं देखरेख में चुनाव.
- मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करके फर्जी मतदान को रोकना.
- सभी मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र जारी किया जाना.
- सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनावों में खर्च की सीमा के भीतर ही व्यय करना तथा व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना.
- चुनावों के दौरान निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों पर लिखे विज्ञापनों को उम्मीदवारों द्वारा अपने खर्चे से साफ कराना.
- चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करना.

टी. एन. शेषन एवं उनके उत्तरवर्ती मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के प्रयासों से चुनाव जीतने के लिए–

- मतदाताओं को खरीदने एवं धमकाने, डराने की प्रवृत्तियों पर रोक लगी.
- मतदान वाले दिन शराब की बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबन्ध लगा.
- प्रचार के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक लगी.
- धर्म, जाति, सम्प्रदाय के आधारों पर मतदाताओं से अपील नहीं की जा सकती.
- चुनाव प्रचार के लिए पूजास्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता.
- चुनाव प्रचार के लिए बिना पूर्वानुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता.

टी. एन. शेषन ने भारत निर्वाचन आयोग की श्रेष्ठता की जो मिसाल कायम की उसे उनके उत्तरवर्ती मुख्य निर्वाचन आयुक्तों–एम. एस. गिल, जे. एम. लिंगदोह, टी. एस. कृष्णामूर्ति, बी. बी. टंडन, एन. गोपाल स्वामी, नवीन चावला, एस. वाई. कुरैशी, बी. एस. सम्पत्त, एच. एस. ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति तथा ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा, सुशील चन्द्रा एवं राजीव कुमार ने न केवल बनाए रखा वरन् उत्तरोत्तर और प्रभावशाली बनाया. विभिन्न वर्षों में अपनाए गए चुनाव सुधारों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित प्रकार है–.

- 1971 में पहली बार जारी तथा बाद में अनेक बार संशोधित आदर्श आचार संहिता चुनाव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, अधिकारी, कर्मचारी, उम्मीदवार, राजनीतिक दल के लिए बाध्यकारी है. भले ही इसे विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है.
- मतदाताओं की अर्ह आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया.
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया–रेडियो एवं दूर-दर्शन पर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों की समान पहुँच सुनिश्चित कराई गई.
- न्यायालय से 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सजा प्राप्त कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता.
- कोई भी सांसद/विधायक लाभ के पद पर कार्य कर नहीं कर सकता. यदि ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी.
- सारे देश में सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाने की व्यवस्था. अब प्रत्येक निर्वाचन में वोटर वेरीफाइबिल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की भी अनिवार्य व्यवस्था.

शेष पृष्ठ 133 पर

फोकस 2

चुनावी बॉण्ड असंवैधानिक : गोपनीयता *बनाम* पारदर्शिता के बीच बहस

✍ डॉ. दीपांकर सिंह

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण का सबसे प्रमुख एवं बड़ा स्रोत कॉर्पोरेट घरानों (निजी कम्पनियों) से प्राप्त तथाकथित चंदा रहा है, चाहे वह सार्वजनिक तौर पर खुले रूप में दिया जाए या कम्पनियों/व्यक्तियों द्वारा काले धन के रूप में दिया जाए. हमेशा से केन्द्र एवं राज्यों में सत्ताधारी दलों को इस प्रकार के चंदे का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है, जबकि छोटे दल और विपक्षी राजनीतिक दलों को चंदे में प्राप्त धनराशि कम ही रही है. राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम उजागर न हो इसलिए चुनावी चंदे में गोपनीयता का तर्क देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना लॉन्च की. देश की लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा इस योजना का विरोध किया गया और इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किए गए. तर्क ये दिया गया कि इस योजना में पारदर्शिता का अभाव है. इसलिए यह सूचना पाने का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के कतिपय प्रावधानों सहित भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 19(1)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है.

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. संविधान पीठ ने सर्वसम्मति वाले दो अलग निर्णय सुनाए. एक निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा का 152 पृष्ठ का था. इस निर्णय के अनुसार चुनावी बॉण्ड योजना, 2018 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29सी(1), कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 182(3) आयकर अधिनियम की धारा 13ए(बी) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) का उल्लंघन करती है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपने 74 पृष्ठ के निर्णय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय से सहमत होते हुए चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देने के साथ भारत निर्वाचन आयोग तथा अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदत्त आँकड़ों का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाया.

राजनीतिक दलों के 2017-18 से 2022-23 की अवधि में किए गए वार्षिक ऑडिट से इस अवधि में चुनावी बॉण्डों से प्राप्त निम्न तालिका में उल्लिखित धनराशि को खुलासा हुआ.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चुनावी बॉण्डों से अधिकांश चंदा उन्हीं राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ है, जो केन्द्र और राज्यों में सत्तासीन है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपने निर्णय में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि राजनीतिक दलों को विभिन्न वर्षों में प्राप्त चंदे का बहुलांश कॉर्पोरेट सेक्टर से प्राप्त हुआ है. लगभग 94% चंदा 1 करोड़ के चुनावी बॉण्डों से प्राप्त हुआ है.

तालिका 1 : चुनावी बॉण्डों से राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा (₹ करोड़ में)

राजनीतिक दल	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारतीय जनता पार्टी	210·00	1450·890	2555·00	22·385	1033·700	1294·1499
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	5·00	383·260	317·861	10·075	236·0995	171·0200
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	0·00	97·280	100·4646	42·000	528·1430	325·1000
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	0·00	29·250	20·500	0·000	14·0000	—
तेलंगाना राष्ट्र समिति	0·00	141·500	89·153	0·000	153·0000	—
तेलगूदेशम पार्टी	0·00	27·500	81·600	0·000	3·5000	34·0000
वाईएसआर सी	0·00	99·840	74·350	96·250	60·000	52·000
बीजू जनता दल	0·00	213·500	50·500	67·000	291·000	152·000
डीएमके	0·00	0·00	45·500	80·000	306·000	185·000
एसएचएस	0·00	60·400	40·980	0·000	—	—
आम आदमी पार्टी	0·00	—	17·765	5·950	25·1200	45·4500
जनता दल (यूनाइटेड)	0·00	0·000	13·000	1·400	10·000	—
समाजवादी पार्टी	0·00	0·000	10·840	0·000	3·2100	0·0000
शिरोमणि अकाली दल	0·00	0·000	6·760	0·000	0·5000	0·000
एआईएडीएमके	0·00	0·000	6·050	0·000	0·000	0·000
आरजेडी	0·00	0·000	2·500	0·000	0·000	—
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	0·00	0·000	1·000	0·000	0·000	—
एसडीएफ	0·00	0·500	0·000	0·000	0·000	0·000
एमजीपी	0·00	0·000	0·000	0·000	0·5500	—
कुल योग	**221·03**	**2539·170**	**3441·324**	**325·060**	**2664·8225**	

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में प्रमुख वादी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का विवरण निम्नांकित तालिकानुसार प्रस्तुत किया है–

तालिका 2 : राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा (₹ करोड़ में)

राष्ट्रीय स्तर की पार्टी (2021-22 की स्थिति के अनुसार)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल योग
भारतीय जनता पार्टी	515·500	400·200	698·140	720·407	416·794	548·808	3299·8500
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	36·060	19·298	127·602	133·040	35·890	54·567	406·4570
एनसीपी	6·100	1·637	11·345	57·086	18·150	15·280	109·5980
सीपीआई (एम)	3·560	0·872	1·187	6·917	9·815	6·811	29·1615
तृणमूल कांग्रेस	2·030	0·000	42·986	4·500	0·000	0·250	49·7660
सीपीआई	0·003	0·003	0·000	0·000	0·000	0·000	0·0055
बीएसपी	0·000	0·000	0·000	0·000	0·000	0·000	0·0000
कुल योग	**563·253**	**422·010**	**881·260**	**921·950**	**480·649**	**625·716**	**3894·8380**

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने तालिका-3 के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 94·25% चंदा ₹ 1 करोड़ मूल्य के चुनावी बॉण्डों के रूप में था.

तालिका 3 : मार्च 2018–जुलाई 2023 के बीच 27 चरणों में चुनावी बॉण्डों की बिक्री–मूल्यवर्गवार

चुनावी बॉण्डों का मूल्य वर्ग (रुपए)	बेचे गए चुनावी बॉण्ड		बेचे गए चुनावी बॉण्डों की धनराशि	
	संख्या	% हिस्सा	धनराशि (₹ करोड़ में)	% हिस्सा
1 करोड़	12999	54·13	12999·00	94·25
10 लाख	7618	31·72	761·80	5·52
1 लाख	3088	12·86	30·88	0·22
10 हजार	208	0·86	0·2080	0·01
1 हजार	99	0·4	0·0990	—
कुल योग	**24012**	**100·00**	**13791·8979**	**100.00**

उपर्युक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेनामी बॉण्डों के माध्यम से कॉर्पोरेट कम्पनियों द्वारा चुनावी चंदा दिया गया. 2018-19 से 2021-22 की अवधि में राजनीतिक दलों को जो आय प्राप्त हुई उसका 58 प्रतिशत चुनावी बॉण्डों से प्राप्त हुआ.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने उपर्युक्त आँकड़ों का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय में प्रश्न उठाया कि क्या चुनावी बॉण्ड योजना में गोपनीयता से सम्बन्धित खण्ड का अनुपातिकता परीक्षण को सन्तुष्ट करता है ? चूँकि अधिकांश चंदा सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ, इसलिए चंदा देने वालों की पहचान उजागर होने पर उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लिए जाने के बारे में व्यक्त की गई आशंकाएं गलत सिद्ध हुईं. चुनावी बॉण्ड के माध्यम से योगदान देने वालों में अधिकांश कॉर्पोरेट घराने हैं. न्यामूर्ति खन्ना ने अपने निर्णय में कहा, "किसी कॉर्पोरेट या कम्पनी, विशेष रूप से पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा गोपनीयता का दावा बहुत सीमित आधार पर टिका है, जो सम्भवतया: कम्पनी के व्यवसाय और वाणिज्य के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा तक सीमित है."

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की दृष्टि में राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे के बारे में समस्त सूचना पूर्ण पारदर्शिता के साथ, पाने का मतदाताओं का अधिकार, दान देने वालों की निजता की रक्षा करने की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्वपूर्ण बिन्दु

- निम्नलिखित कानूनों में वित्त अधिनियम, 2017 (जिसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था) के द्वारा किए गए संशोधन असंवैधानिक हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं.
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29सी(1) जिसे वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 137 से संशोधित किया गया.
- आयकर अधिनियम की धारा 13A(b) जिसे वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 11 से संशोधित किया गया.
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 182(3) जिसे वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 154 से संशोधित किया गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1931 की धारा 31(1)(2) जिसे वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 से संशोधित किया गया.
- निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक निजता व सम्बद्धता का अधिकार भी शामिल है.
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत् कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय प्रावधानों को समाप्त करके राजनीतिक दलों को असीमित मात्रा में चंदा लेना मनमाना कृत्य है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता का अधिकार) का हनन है.
- वित्त अधिनियम, 2017 से संशोधित कम्पनी अधिनियम की धारा 182(1) द्वारा कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट अंशदान की स्वतंत्रता देना विधि संगत नहीं है.
- केन्द्र सरकार चुनावी बॉण्ड योजना के खण्ड 7(4) के तहत् गोपनीयता के पीछे अन्तर्निहित उद्देश्य को स्पष्ट करने में विफल रही.
- राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यक्ति की तुलना में किसी कम्पनी के योगदान का प्रभाव अधिक गम्भीर होता है.
- राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा चंदा देना पूरी तरह से कारोबारी लेन-देन है.

- किसी भी दानदाता (राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले) के विरुद्ध प्रतिशोध या उत्पीड़न राजनीतिक दलों के दिए गए चंदे को छुपाने का औचित्य या उद्देश्य नहीं हो सकता.
- असंगतता इस रूप में भी स्पष्ट है कि कानून में बदलाव, गोपनीयता का आवरण देकर, सामूहिक रूप से सूचना पाने के अधिकार और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार पर गम्भीर प्रतिबंध लगाता है और इन अधिकारों में कटौती करता है.
- गोपनीयता नहीं, अपितु पारदर्शिता ही समस्या का निदान और औषधि है.
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का अभिमत है, "यदि चंदा देने वाला किसी राजनीतिक दल को बैंकिंग चैनल से चंदा देता है, तो निजता के अधिकार के उल्लंघन की दलील का कोई अर्थ नहीं हैं." सत्ता में राजनीतिक दलों के पास बैंकों के साथ जानकारी तक असीमित पहुँच हो सकती है. इस दृष्टि से योजना का पूरा उद्देश्य परस्पर विरोधाभासी और असंगत है. गुप्त मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने का अभिन्न अंग है, लेकिन राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक शर्त है. निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र में जानने का अधिकार सर्वोपरि है.
- इस निर्णय के द्वारा कम्पनियों से चंदे की तय सीमा समाप्त कर दी गई. पहले कम्पनी अपने निबल लाभ का अधिकतम 7·5 प्रतिशत हिस्सा ही राजनीतिक दलों को चंदे में दे सकती थी. शीर्ष अदालत ने यह सीमा खत्म करने वाला संशोधन भी रद्द कर दिया.
- भारतीय स्टेट बैंक को अब इससे आगे बॉण्ड जारी करने से रोक दिया गया.
- भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉण्डों के जरिए दिए गए चंदे का विवरण देना होगा और चंदा हासिल करने वाले राजनीतिक दलों का ब्यौरा भी देना होगा.
- भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉण्डों का विवरण भारत निर्वाचन आयोग को देगा.
- भारतीय स्टेट बैंक यह समस्त जानकारी 6 मार्च, 2024 तक भारत निर्वाचन आयोग को देगा.
- ऐसे चुनावी बॉण्ड जिनकी 15 दिनों की वैधता अवधि पूरी नहीं हुई है और जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक भुनाया नहीं गया है. उन्हें राजनीतिक दल सम्बन्धित बॉण्ड खरीदार को वापस कर दें और बैंक उस बॉण्ड की धनराशि बॉण्ड खरीदार के खाते में वापस कर दें.
- निर्वाचन आयोग को भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त जानकारी को 6–13 मार्च के बीच अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.

चुनावी बॉण्ड योजना और उससे सम्बद्ध विधिक जटिलताएं

चुनावी बॉण्ड योजना तत्कालीन वित्त मंत्री (स्व.) अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में घोषित की गई थी. सरकार द्वारा इसे 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया. इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार थी–

- चुनाव बॉण्ड प्रोमिजरी नोट के रूप में ब्याज मुक्त धारक उपकरण थे.
- भारतीय नागरिक एवं भारत में निगमित निकाय इन बॉण्डों का क्रय करने के लिए अर्ह थे.
- ₹ 1000, ₹ 10000, ₹ 1,00,000, ₹ 10,00,000 तथा ₹ 1,00,00,000 के वर्गमूल्य के ये बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से ही खरीदे जा सकते थे.
- इन बॉण्डों को अपना ग्राहक जानों (KYC) मानकों को पूरा करने वाले व्यक्तियों/कम्पनियों/फर्मों द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से ही खरीदा जा सकता था.
- चुनावी बॉण्डों पर खरीदार का नाम और पता अंकित नहीं होता था.
- इन बॉण्डों की वैधता अवधि मात्र 15 दिन थी जिसके भीतर इन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अन्तर्गत पंजीकृत राजनीतिक दलों, जिन्होंने लोक सभा या राज्य विधान सभा के विगत सामान्य चुनावों में कम-से-कम 1 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे, को दिया जा सकता था.
- ये बॉण्ड प्रतिवर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 10 दिन की अवधि के लिए जारी किए गए.
- सामान्य निर्वाचन के वर्ष के दौरान इन्हें खरीदने की अवधि 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती थी.
- चुनावी बॉण्डों को अर्ह राजनीतिक दल द्वारा केवल अपने बैंक खाते में जमा करके ही भुनाया जा सकता था.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी, 2024 को सुनाए गए अपने निर्णय में वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 182(3) के बारे में जो टिप्पणी की है वह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. धारा 182(3) कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के बारे में है. धारा 182(3) के तहत् ऐसे अंशदान को कम्पनी के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए. यह नकद नहीं होना चाहिए तथा इसका उल्लेख लाभ-हानि खाते में किया जाना चाहिए. वर्ष 2017 के संशोधन, जो धन विधेयक के रूप में पारित वित्त विधेयक के माध्यम से किया गया था, वह सीमा हटा दी गई थी जिसके तहत् पिछले 3 वर्षों के लाभ का 7·5 प्रतिशत तक ही दान दिया जा सकता था. इसी संशोधन के द्वारा इस प्रकार के दान का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया.

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि राजनीतिक दलों को असीमित कारोबारी वित्तीयन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धान्त का उल्लंघन करती है. सर्वोच्च न्यायालय ने काले धन पर नियंत्रण के मामले में चुनावी बॉण्ड की क्षमता पर भी संदेह जताया. सर्वोच्च न्यायालय का यह भी अभिमत है कि कम्पनी अधिनियम में किया गया यह संशोधन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(सी) के साथ सुसंगतता के साथ पेश किया गया, जो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त अंशदान का प्रकटीकरण करने से छूट देती है.

2018 में लॉन्च की गई चुनावी बॉण्ड योजना को अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी, 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक, वरन देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है. लोकतंत्र में मतदाता सही चयन के लिए अपने मत का उपयोग उसी दशा में कर सकते हैं जब उन्हें राजनीतिक दलों को मिल रहे धन की जानकारी हो. मौजूदा नियमों के तहत् राजनीतिक दलों के लिए ₹ 20,000 से अधिक के चंदे के स्रोत का खुलासा करना जरूरी है. इसी सीमा के कारण चंदे के बड़ी राशि को छोटे-छोटे वर्गों (₹ 20,000) में बाँटकर किया जाता है. राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अंकेक्षण की कोई सटीक व्यवस्था न हो पाने के कारण इन प्रकटन नियमों से पार पाना चंदा देने वालों तथा राजनीतिक दलों दोनों के लिए आसान है. वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार ने **इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम** पेश की थी जिसकी सहायता से गैर-लाभकारी कम्पनियों को ऐसे निकाय (न्यास) स्थापित करने थे, जो अन्य कम्पनियों (लाभ अर्जन के उद्देश्य से कार्यरत्) और व्यक्तियों से धन जुटा सकें और उसे राजनीतिक दलों को वितरित कर सकें. इन

शेष पृष्ठ 96 पर

फोकस 3

भारत में राजकोषीय संघवाद

✍ डॉ. मनीष देव

शब्द 'राजकोषीय संघवाद' जर्मन में जन्मे, अमरीकी अर्थशास्त्री रिचर्ड मसग्रेव द्वारा 1959 में प्रस्तुत किया गया था. वालेस ई. ओक्स ने 1999 में इसे अग्र प्रकार परिभाषित किया था, 'राजकोषीय संघवाद का सम्बन्ध यह समझने से है कि कौनसे कार्य और उपकरण सर्वोत्तम रूप से केन्द्रीकृत हैं और कौनसे कार्य सरकार के विकेन्द्रीकृत स्तरों के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थिति में निष्पादित किए जा सकते हैं. यह अवधारणा सरकार के सभी रूपों पर लागू होती है—एकात्मक, संघीय और संघ. राजकोषीय संघवाद मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र, राजकोषीय नीति संस्थानों की ऊर्ध्वाधर संरचना और उनकी परस्पर निर्भरता पर विचार करता है. कई स्वीकृत सिद्धांत दक्षता, जैसे कि—जवाबदेही, प्रबंधनीयता और स्वायत्तता के आधार पर विकेन्द्रीकृत राजकोषीय संविधान के लिए एक मजबूत तर्क प्रदान करते हैं. वैकल्पिक रूप से, समय के साथ राजकोषीय संघवाद के क्षेत्र में 'राजकोषीय समतुल्यता', 'विकेन्द्रीकरण' और 'सहायकता' के सिद्धांत भी उभरे हैं.

एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में एकल या बहुस्तरीय सरकार होती है जिसमें सभी सरकारी कार्यों का प्रभावी नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास होता है. (सिंगापुर और मोनेक्को के शहर-राज्य एकल-स्तरीय एकात्मक सरकारें हैं. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, फिलीपींस, पुर्तगाल, स्वीडन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक संविधान पर आधारित बहुस्तरीय सरकारें हैं).

सरकार के संघीय स्वरूप में एक बहुस्तरीय संरचना होती है, जिसमें सरकार के सभी आदेशों में निर्णय लेने की कुछ स्वतंत्र और साझा जिम्मेदारियाँ होती हैं. संघवाद या तो घटक भौगोलिक इकाइयों के 'एक साथ आने' या 'एक साथ रहने' का प्रतिनिधित्व करता है. ('एक साथ आना' संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और हाल ही में यूरोपीय संघ जैसे परिपक्व संघों के लिए मार्गदर्शक ढाँचा रहा है संघवाद का 'एक साथ रहना' दृष्टिकोण, जिसे 'नया संघवाद' भी कहा जाता है, केन्द्रीय नीतियों के साथ क्षेत्रीय और स्थानीय असंतोष को दूर करने के लिए सरकार के राज्य-स्थानीय आदेशों के लिए जिम्मेदारियों को विकेन्द्रीकृत करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है. यह दृष्टिकोण एकात्मक देशों और ब्राजील और भारत जैसे अपेक्षाकृत नए संघों और इराक, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते संघों में संघवाद के सिद्धांतों में वर्तमान रुचि के पीछे प्रेरक शक्ति है.).

संघ प्रणाली में, सामान्य सरकार सदस्य इकाइयों के एजेंट के रूप में कार्य करती है, आमतौर पर स्वतंत्र कर लगाने और खर्च करने की शक्तियों के बिना. (संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमण्डल (सीआईएस), जिसमें अब सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के पूर्व गणराज्यों में से 11 शामिल हैं, सरकार के संघीय स्वरूप का अनुमान लगाते हैं.).

भारत में राजकोषीय संघवाद की कारगरता पर उठते प्रश्नचिह्न

वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने और केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के दौरान यह एक किस्म की परम्परा-सी बन गई है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की सरकारें केन्द्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी को लेकर आपत्ति उठाती रही है. एक प्रकार से यह राजकोषीय संघवाद पर प्रश्नचिह्न लगाने जैसा है. वित्तीय संसाधनों के बँटवारे के बारे में राज्यों की शिकायत नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में उसके साथ अतिरिक्त राजनीतिक अर्थ जुड़ गए हैं.

जब तक केन्द्र और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें रहीं या रहती हैं तब तक कर राजस्व के हस्तान्तरण में इस प्रकार का भेदभाव किए जाने के आरोप नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन जब केन्द्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों या गठबन्धनों की सरकारें होती हैं तब कर राजस्व के हस्तान्तरण में भेदभाव के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं. इस वर्ष कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, केरल की वामपंथी दलों की सरकार, तमिलनाडु की डीएमके सरकार तथा पश्चिमी बंगाल की टीएमसी सरकार ने केन्द्र की लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार पर राजकोषीय संघवाद के स्थापित सिद्धांतों का पालन न करने के आरोप लगाए हैं. यह याद किया जा सकता है कि जिस समय केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी तब गुजरात की सरकार ने भी राजकोषीय संघवाद को लेकर चिंता प्रकट की थी.

- 2 फरवरी, 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केन्द्र द्वारा प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं के तहत् धन देने से कथित इनकार के खिलाफ कोलकाता में दो दिवसीय धरना दिया.
- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक के कई अन्य कांग्रेस मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने—पिछले कुछ वर्षों में सहायता तथा करों और अनुदान के हस्तांतरण में राज्य के साथ किए गए 'अन्याय' के खिलाफ 7 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. सिद्धारमैया ने वित्त आयोग की सिफारिशों में बदलाव के कारण कर हस्तांतरण में ₹ 62,098 करोड़ के नुकसान का हवाला देते हुए केन्द्र सरकार पर कर्नाटक के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.
- आगामी आम चुनावों से पहले विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने की उम्मीद करते हुए, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेता केन्द्र द्वारा संघवाद विशेषकर संसाधनों के हस्तांतरण में विसंगतियाँ पर कथित हमलों के खिलाफ 8 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केरल सरकार द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. यह बैठक विपक्षी राज्यों की एक सभा जैसी बन गई, जिसमें 3 मुख्यमंत्रियों—केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए और राज्यों के लिए न्याय की माँग की.
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने अपने समकक्ष के मुख्यमंत्री केरल पिनाराई विजयन को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके दावे का समर्थन किया गया कि केन्द्र संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत् अपनी शक्ति का 'दुरुपयोग' करके राज्य की उधार सीमा को 'मनमाने ढंग से' प्रतिबंधित कर रहा है.
- तीनों दक्षिणी राज्यों ने आरोप लगाया है कि केन्द्र ने उनकी उधारी पर प्रतिबंध लगा दिया है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण उनके धन का प्रवाह कम हो गया है. इन राज्यों का यह भी कहना है कि जून 2023 में जीएसटी मुआवजे की समाप्ति (जो हमेशा से ज्ञात थी) के कारण उन्हें धन का नुकसान हो रहा है.

दक्षिणी राज्य जनसंख्या नियंत्रण और आय वृद्धि में अपनी उपलब्धियों के लिए स्वयम को पुरस्कारहीन महसूस करते हैं और यह स्वाभाविक भी है. इस तरह के विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित मुद्दों से सम्बन्धित हैं–

1. केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी (यह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र द्वारा निर्देशित है).

2. जीएसटी मुआवजे की समाप्ति (यह इस बात से सम्बन्धित है कि जीएसटी में इस व्यवस्था को कैसे संरचित किया गया था?)

3. राज्य उधार कार्यक्रमों के लिए केन्द्र का समर्थन (यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों पक्षों के पास अपने-अपने तर्क हैं.)

4. राज्यों द्वारा सूखा या बाढ़ राहत जैसी विशेष सहायता की माँग के प्रति केन्द्र सरकार की ग्रहणशीलता (विवेक का एक कार्य).

5. राज्यों में बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्त पोषण. (विवेक का एक कार्य)

6. संसाधनों की अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग, जो केन्द्र के पास है. (केन्द्र द्वारा उप-कर (सीईएसएस) और अधिभार लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है).

उपर्युक्त आधारों के अलावा राज्यों का विरोध राजनीतिक कारणों से भी निर्देशित होता है. राज्य नेतृत्व-विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा शासित-ने आरोप लगाया कि पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं (जिनमें से अनेक राज्य या समवर्ती सूची के विषयों से सम्बन्धित हैं), जो मतदाताओं को आकर्षित करती हैं, इसलिए वे लोकप्रियता और अंततः चुनावों में एनडीए सरकार को लाभ दे रही हैं. इस प्रकार, समान योजनाएं शुरू करने की उनकी (राज्यों) अपनी क्षमता धन की कमी के कारण सीमित है.

राजकोषीय संघवाद के सफल क्रियान्वयन में वित्त आयोग की भूमिका

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के प्रावधानों के तहत् भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. वित्त आयोग केन्द्र के विभाज्यनीय करों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आवंटित करने के लिए उर्ध्वाकार (कुल विभाज्यनीय करों से प्राप्त राजस्व का वह हिस्सा, जो राज्यों को हस्तांतरित किया जाना है) एवं क्षैतिजिक (राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्से का विभिन्न राज्यों के बीच बँटवारा) मानकों को अपनाता है.

यह पाया गया है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल को दिया जाने वाला भार 2005 से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दशकों में सभी 4 दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है. हालाँकि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और आय दूरी जैसे मानदंड पेश किए गए हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं.

वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य राजस्व को समानता के सिद्धांत के अनुरूप वितरित करना है ताकि, जो राज्य पर्याप्त कर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ हैं उनके पास अपने क्षेत्र में विकास को निधि देने और अपनी आबादी की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हों.

15वें वित्त आयोग के अनुसार, 'आयोग ने क्षैतिजिक साझाकरण के मानदंड निर्धारित करने के लिए राजकोषीय जरूरतों, समता (इक्विटी) और प्रदर्शन के सिद्धांतों को सन्तुलित करने का प्रयास किया.'

तालिका 1 में विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा क्षैतिजिक साझाकरण के मानदंड निर्धारित करने के लिए विभिन्न कसौटियों को प्रदत्त भारों को दर्शाया गया है.

विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा क्षैतिजक साझाकरण के मानदंड एवं उन्हें प्रदत्त भार

कसौटी	11वाँ वित्त आयोग (2000-05)	12वाँ वित्त आयोग (2005-10)	13वाँ वित्त आयोग (2010-15)	14वाँ वित्त आयोग (2015-20)	15वाँ वित्त आयोग (2020-26)
जनसंख्या (1971)	10·0	25·0	25·0	17·5	–
जनसंख्या (2011)	–	–	–	10·0	15·0
क्षेत्रफल	7·5	10·0	10·0	15·0	15·0
वन एवं पर्यावरण	–	–	–	7·5	10·0
अधोरचना सूचकांक	7·5	–	–	–	–
आय से दूरी	62·5	50·0	–	50·0	45·0
कर एवं राजकोषीय प्रयास	5·0	7·5	–	–	2·5
राजकोषीय क्षमता दूरी	–	–	47·5	–	–
राजकोषीय अनुशासन	7·5	7·5	17·5	–	–
जनांकिकीय उपलब्धि	–	–	–	–	12·5

तालिका का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता कि वित्त आयोगों ने हस्तांतरण फॉर्मूले में विभिन्न कसौटियों को प्रदत्त भार में किस प्रकार परिवर्तन किया गया है? आय दूरी का हस्तांतरण फॉर्मूले में सबसे बड़ा भार है. हालाँकि 13वें वित्त आयोग ने इस कसौटी को त्याग दिया. 2005 में यह 62·5 के काफी ऊँचे स्तर पर था.

हालाँकि बाद में राज्यों की संसाधन–उत्पादन क्षमता में सुधार के कारण आय दूरी के लिए भार कम कर दिया गया है, फिर भी यह अभी भी काफी अधिक 45 प्रतिशत भार है. आय दूरी की गणना किसी राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी को उस राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से घटाकर की जाती है, जो इस मीट्रिक पर सबसे अधिक स्कोर करता है.

आय दूरी के लिए उच्च भार को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि संघवाद के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अमीर राज्यों को अपने अतिरिक्त राजस्व को कम अमीर राज्यों के साथ साझा करना पड़ता है, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल को दिए गए बढ़ते महत्व ने राजस्व हिस्सेदारी को अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े राज्यों की ओर झुका दिया है.

11वें वित्त आयोग (2000-05) के तहत् हस्तांतरण फॉर्मूले में जनसंख्या का भार केवल 10 प्रतिशत था. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के तहत् 12वें वित्त आयोग (2005-10) द्वारा इसे तेजी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया.

15वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को 15 प्रतिशत महत्व और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12·5 प्रतिशत महत्व दिया है. अब, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की गणना राज्यों की टीएफआर (कुल प्रजनन दर, जो प्रत्येक महिला से पैदा हुए बच्चों की संख्या को शामिल करती है), को देखकर की जाती है और इसका उद्देश्य उन राज्यों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित किया है.

हालाँकि, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए भार की गणना करने का फॉर्मूला टीएफआर को उलट देता है और इसे 1971 की जनसंख्या से गुणा करता है. इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों को एक बार फिर अधिक भार मिल जाता है.

इसी प्रकार, क्षेत्रफल को दिया जाने वाला भार भी 11वें वित्त आयोग के तहत् 7·5 प्रतिशत से दोगुना होकर 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत् 15-15 प्रतिशत हो गया है. इससे पलड़ा बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों के पक्ष में झुक जाता है और केरल जैसे राज्यों के लिए प्रतिकूल है, जिनका क्षेत्रफल बहुत छोटा है.

15वें वित्त आयोग ने उन राज्यों के लिए 2·5 प्रतिशत भारांक पेश किया है, जो अपने कर और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करते हैं, लेकिन 13वें वित्त आयोग के तहत् राजकोषीय अनुशासन का भार 17·5 प्रतिशत से कहीं अधिक था.

दक्षिण के विकसित राज्यों की पीड़ा

अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए इतने कम भार के साथ, राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने या कर संग्रह में सुधार करने के लिए अधिक प्रयास करने की सम्भावना नहीं है. हस्तांतरण फॉर्मूले में बदलते भार से दक्षिणी राज्यों को अधिक नुकसान होता दिख रहा है. यदि 10वें वित्त आयोग (1995 और 2000 के बीच) और 15वें वित्त आयोग (2021 और 2026 के बीच) में राज्यों की हिस्सेदारी की तुलना करें, तो सभी दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है.

विभाज्य पूल में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना संयुक्त रूप से, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की हिस्सेदारी में 1·6, 2·1, 1·6 और 1·3 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है. बिहार में भी 1·3 प्रतिशत अंकों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी 10·1 के साथ दूसरी सबसे बड़ी है, उत्तर प्रदेश के बाद, जिसकी वर्तमान में 17·9 प्रतिशत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.

हस्तांतरण सूत्र

राज्यों के बजट के आँकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा हस्तांतरण फॉर्मूले के कारण कुछ राज्यों को विभाज्य पूल से कहीं अधिक बड़ा हिस्सा मिल रहा है. उदाहरण के लिए, FY24 के बजट अनुमान से पता चलता है कि बिहार को केन्द्र के कर हिस्से के रूप में ₹ 1·02 लाख करोड़ की भारी राशि मिलने वाली है. यह राज्य के कुल कर राजस्व का 67·4 प्रतिशत है. यूपी का हिस्सा भी उतना ही भारी-भरकम ₹ 1·83 लाख करोड़ है, जो कुल कर राजस्व का 42 प्रतिशत है.

दूसरी ओर, हरियाणा में, केन्द्रीय करों का हिस्सा सिर्फ ₹ 11,164 करोड़ (कुल कर राजस्व का 13 प्रतिशत) था. तेलंगाना में, यह ₹ 21,471 करोड़ था. सभी दक्षिणी राज्यों में, केन्द्र के विभाज्य पूल का हिस्सा उनके कुल कर राजस्व का 30 प्रतिशत से कम था.

9 फरवरी, 2024 को राज्य सभा में एक लिखित जवाब में, वित्त मंत्रालय ने FY19 और FY23 के बीच राज्यों द्वारा एकत्र किए गए जीएसटी और प्रत्यक्ष कर पर डेटा साझा किया. इस डेटा के आधार पर बिजनेस लाइन की गणना से पता चला कि केन्द्र के विभाज्य पूल में राज्यों द्वारा योगदान की जाने वाली धनराशि और हस्तांतरण के रूप में उन्हें, जो धनराशि वापस मिलती है, वह समान नहीं है. पूल में जाने वाले कर राजस्व के प्रत्येक एक रुपए के लिए, कुछ राज्यों को दूसरों की तुलना में बहुत अधिक हस्तांतरण प्राप्त होता है.

बिहार को कर राजस्व में मात्र एक रुपये के योगदान के सापेक्ष जहाँ वित्त आयोग की संस्तुति से विभाज्यनीय कर राजस्व में से ₹ 7·26 और उत्तर प्रदेश को ₹ 2·49 प्राप्त हुए, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक को क्रमशः 8 पैसे, 14 पैसे और 17 पैसे मिले. गुजरात को 26 पैसे और तमिलनाडु को 28 पैसे वापस मिले. हालाँकि, इन राज्यों को वापस मिलने वाली राशि कम हो सकती है, क्योंकि गणना में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को ध्यान में नहीं रखा गया है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस डेटा का राज्य-वार विवरण उपलब्ध नहीं है.

राज्यों का यह भी मानना है कि संविधानिक व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने की अवक्षेपित शक्तियाँ (Residual Powers) केन्द सरकार में निहित हैं, अर्थात् जिन करों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की संघीय सूची, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची में से किसी भी सूची में नहीं है उन्हें लगाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है. इसी आधार पर केन्द्र सरकार उपकर और अधिभार लगाती है, लेकिन उनसे प्राप्त कर राजस्व केन्द्र के विभाज्यनीय कर पूल का हिस्सा नहीं है. सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार की अधिक हिस्सेदारी ने विभाज्य पूल को संकुचित कर दिया है और जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने वाले वित्त आयोगों का राजस्व साझा करने का फॉर्मूला उनके हितों के खिलाफ गया है.

राजकोषीय संघवाद का राजनीतिक पहलू

विकसित राज्यों की सत्ताधारी पार्टियाँ हमेशा अपनी सम्पत्ति और जनसंख्या नियंत्रण की बेहतर स्थिति के मोर्चे पर अपने प्रदर्शन के बारे में सोचती हैं. तथाकथित विकसित राज्य बीमारू (BIMARU) राज्यों की अविकसितता पर कम ध्यान देते हैं. बीमारू राज्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में भी पीछे हैं. केन्द सरकार के लिए देश की वृद्धि और विकास की मुख्य चिंताओं में से एक समावेशी विकास के साथ-साथ 'कोई भी पीछे न छूटे' की थीम के साथ समानता मूलक विकास है. यह पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से ही सम्भव है. राज्यों के बीच कर राजस्व के क्षैतिज हस्तांतरण के मानदंड तय करते समय वित्त आयोग की सिफारिशों में भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया है. 15वें वित्त आयोग ने दक्षिणी विकसित राज्यों को जनसंख्या के 15·0 प्रतिशत भार के मुकाबले जनांकिकीय निष्पादन को 12·5 प्रतिशत भार प्रदान करके संसाधन हस्तान्तरण अंतराल को पाटने का प्रयास किया है.

इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अपनी जनता को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने में अधिक उदार हैं. राजस्व आय का एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरण भुगतान पर खर्च किया जाता है. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धन के बड़े पैमाने पर विपथन के उदाहरण हैं. ऐसे परिदृश्य में राज्य अक्सर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने से बचते हैं या केन्द्रीय योजनाओं के लिए अंशदायी हिस्सेदारी/मिलान अनुदान के लिए अपने बजट में प्रावधान नहीं करते हैं.

विवेकशील नीति

परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर राजनीति से परे भी विचार करना आवश्यक है. राजकोष में जो राशि आती है और कुछ राज्यों को, जो हासिल होता है उसके बीच का अन्तर इतना अधिक हो रहा है कि इस ओर राजनीतिक ध्यान आकृष्ट होना लाजिमी है.

केन्द्र सरकार को यह बात समझनी होगी कि वह देश के संसाधनों पर प्राथमिक तौर पर हक नहीं जमा सकती है. खासकर यह देखते हुए कि विकास सम्बन्धी कई कार्य मुख्य तौर पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं. एक संस्थागत व्यवस्था, जो हमारे देश में कारगर रही है और जिसने राजकोषीय संघवाद को मजबूती प्रदान की है वह यह है कि एक के बाद एक विभिन्न वित्त आयोगों ने कर विभाजन का, जो फॉर्मूला तैयार किया, उसका मान रखा गया. भले ही यह केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह फॉर्मूले को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, लेकिन आयोग की अनुशंसाओं को हमेशा स्वीकार किया गया है.

शेष पृष्ठ 104 पर

ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल

ऐतिहासिक व्यक्तित्व

वल्लियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई (1872-1936)

प्रमुख तथ्य

- वल्लियप्पन उगलनाथन चिदम्बरम पिल्लई तमिलनाडु के एक राजनेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. उन्हें 'वीओसी' तथा 'कप्पलोट्टिय तमिलन' नाम से भी जाना जाता है.
- उन्हें भारतीय जलयान उद्योग को सम्मान-जनक स्थान दिलवाने के लिए भी याद किया जाता है.
- वल्लियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई (चिदम्बरम पिल्लई) का जन्म 5 सितम्बर, 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्टापिडारम् में एक प्रख्यात वकील उलगनाथन पिल्लई और परमी अम्माई के घर हुआ था.
- 14 वर्ष की आयु में चिदम्बरम अपने पढ़ाई जारी रखने के लिए तूत्तुक्कुडि गए. उनकी आरम्भिक शिक्षा सेंट जेवियर हाईस्कूल, काल्डवेल हाईस्कूल तूत्तुक्कुडि और हिन्दू कॉलेज हाईस्कूल तिरुनेल्वेली में हुई.
- चिदम्बरम के पिताजी ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली भेजा. इसके पहले उन्होंने तालुका ऑफिस में क्लर्क के पद पर कुछ समय तक काम किए. उन्होंने 1894 में वकालत की परीक्षा पास की और 1895 में ओट्टपिडारम लौट आए और वहाँ उन्होंने वकालत शुरू की.
- चेन्नई में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानन्द आश्रम के संत रामकृष्णान्तर से हुई. उन्होंने उन्हें देश के हित में कुछ करने की प्रेरणा दी. उनकी प्रेरणा से चिदम्बरम ने राजनीति में प्रवेश किया.
- सन् 1990 के बाद चेन्नई में वे तमिल कवि भारतीयार से मिले और दोनों एक-दूसरे के अभिन्न मित्र बन गए.
- चिदम्बरम पिल्लई ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में प्रवेश किया. वर्ष 1905 के अन्त में चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास का दौरा किया और बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी आन्दोलन से जुड़े.
- तूतीकोरिन (वर्तमान थूथुकुडी) में चिदम्बरम पिल्लई के आने के पूर्व तक तिरुनेलवेली जिले में स्वदेशी आन्दोलन ने गति प्राप्त करना शुरू नहीं किया था. चिदम्बरम ने स्वदेशी प्रचार सभा, धर्म संघ नेसवु सालै, नेशनल गोडौन, मद्रास अग्रो इन्ड्स्ट्रियल लिमिटेड और देशाभिमान संगम जैसी संस्थाओं का निर्माण किया. इन संस्थाओं के सहयोग से वहाँ स्वदेशी आन्दोलन ने गति प्राप्त की.
- 1906 तक चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कम्पनी (SSNCO) के नाम से एक स्वदेशी मर्चेंट शिपिंग संगठन स्थापित की. इस कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश स्वामित्व वाली ब्रिटिश इंडिया नेवीगेशन कम्पनी (BISNC) के आधिपत्य एवं एकाधिकार को समाप्त करना था और वे अपने इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहे.
- चिदम्बरम पिल्लई और शिवा को उनके प्रयासों हेतु तिरुनेलवेली स्थित कई वकीलों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने स्वदेशी संगम या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक' नामक एक संगठन का गठन किया.
- तूतीकोरिन कोरल मिल्स की हड़ताल (1908) की शुरूआत के साथ राष्ट्रवादी आन्दोलन ने एक द्वितीयक चरित्र प्राप्त कर लिया.
- गांधीजी के चम्पारण सत्याग्रह (1917) से पहले भी चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में मजदूर वर्ग का मुद्दा उठाया था और इस तरह वह इस सम्बन्ध में गांधीजी के अग्रगामी थे.
- उन्होंने मेयाराम (1914), मेयारिवु (1915), एंथोलॉजी (1915), आत्मकथा (1946), थिरुकुरल के मनकुदावर के साहित्यिक नोट्स के साथ (1917), टोल्कपियम के इलमपुरनार के साहित्यिक नोट्स के साथ (1928) आदि कृतियों की रचना की.
- चिदम्बरम पिल्लई की मृत्यु 18 नवम्बर, 1936 को तूतीकोरिन में हुई.

स्कंदगुप्त (455 ई.–467ई.)

प्रमुख तथ्य

- गुप्त शासक कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ. उसका शासनकाल 455 ई. से 467 ई. तक रहा.
- स्कंदगुप्त के शासनकाल के अध्ययन के स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उसके द्वारा जारी किए गए अभिलेख हैं.
- उसके 'जूनागढ़ अभिलेख' से जानकारी मिलती है कि उसने मौर्यों द्वारा निर्मित **सुदर्शन झील** का जीर्णोद्धार करवाया था.
- जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को परास्त कर वहाँ पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त करने का उल्लेख है.
- स्कंदगुप्त द्वारा जारी **'इंदौर ताम्रपत्र लेख'** (146 गुप्त संवत् अर्थात् 465 ई.) से सूर्य पूजा तथा सूर्य मन्दिर में दीपक जलाए जाने के लिए दान दिए जाने का विवरण है.
- स्कंदगुप्त का भितरी स्तम्भ लेख उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के भितरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है.
- 'भितरी स्तम्भलेख' के स्कंदगुप्त का पुष्यमित्रों और हूणों से संघर्ष का भी पता चलता है.
- स्कंदगुप्त का **'कहौम अभिलेख'** उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है.
- **'कहौम अभिलेख'** में उल्लिखित विवरण से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकारों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया.
- गुप्त सम्राट् स्कंदगुप्त का **'गढ़वा शिलालेख'** इलाहाबाद के करछना तहसील के गढ़वा स्थान पर प्राप्त हुआ. (148 गुप्त संवत् अर्थात् 467 ई.) यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख था.
- उसको अपने शासनकाल में बर्बर 'म्लेच्छ' (जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित) हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा. स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर देश से बाहर खदेड़ दिया.
- भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री **'सुंगयुन'** (515–520 ई.) ने अपने यात्रा विवरण में गंधार पर शासन करने वाले 'तिगिन' को प्रथम हूण शासक के रूप में उल्लिखित किया है.
- स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में नागवंशी शासकों को भी पराजित किया.
- स्कंदगुप्त के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सुराष्ट्र तक विस्तारित थी.
- उसने वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण 'पदम्भागवत' का विरुद्ध धारण किया.
- स्कंदगुप्त ने भितरी नामक स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी.
- सुदर्शन झील के तट पर वहाँ के राज्यपाल चक्रपालित ने विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी.

- बर्बर हूणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की.
- स्कंदगुप्त ने तीन प्रकार के सिक्के—धनुर्धर, राजा और लक्ष्मी तथा अश्वारोही प्रकार के सिक्के चलाए. पश्चिमी और मध्य भारत में उसने चाँदी के सिक्के जारी किए.
- स्कंदगुप्त के बाद **पुरुगुप्त विक्रम प्रकाशादित्य** (467–69 ई.) शासक हुआ. इसी समय से गुप्त साम्राज्य की सीमाएं संकुचित होना शुरू हो गई थीं.

राजेन्द्र प्रथम (1012 ई.–1044 ई.)

प्रमुख तथ्य

- चोल शासक राजराज प्रथम की मृत्यु के उपरान्त उसका योग्यतम पुत्र राजेन्द्र प्रथम सम्राट बना. सम्राट् बनने के बाद उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया.
- अपने शासन के पाँचवें वर्ष (1017 ई. में) राजेन्द्र प्रथम ने सम्पूर्ण श्रीलंका को जीत लिया तथा वहाँ के शासक **महिन्द पंचम** को बन्दी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहाँ 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई.
- राजेन्द्र प्रथम ने **अरब सागर** स्थित **सदिमन्तीब** नामक द्वीप पर भी अपना अधिपत्य स्थापित किया. किसी भी चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का सर्वप्रथम अभियान था.
- श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त राजेन्द्र ने **पाण्ड्यों** तथा **चेरो** पर भी आक्रमण किया. इन राज्यों को विजित करने के पश्चात् उसने अपने पुत्र **राजाधिराज** को पाण्ड्य प्रदेश का वायसराय (महामण्डलेश्वर) नियुक्त किया एवं उसे **चोल पाण्ड्य** की उपाधि दी.
- उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक **महीपाल** को परास्त किया. गंगा घाटी के इस अभियान की सफलता पर राजेन्द्र ने **'गंगैकौण्ड चोल'** का विरूद धारण किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में उसने **'गंगैकोण्डचोलपुरम्'** नामक नई राजधानी की स्थापना की.
- नवीन राजधानी **'गंगैकोण्डचोलपुरम'** के निकट सिंचाई के लिए उसने **'चोलगंगम्'** नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया.
- राजेन्द्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ई. **कडारम** (आधुनिक केद्दह) के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध थी. श्री विजय साम्राज्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक विस्तारित था.
- राजेन्द्र प्रथम के चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पारकर कडारम के श्री विजय नरेश **संग्राम कुलोतुंगवर्मन** को परास्त किया और निकोबार द्वीप समूह एवं मलय प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित **बारह द्वीपों** पर अधिकार कर लिया.
- श्री विजय साम्राज्य पर राजेन्द्र प्रथम के आक्रमण के दो कारण थे—
  1. श्री विजय साम्राज्य सम्भवतः पूर्वी जगत् के साथ चोलों के व्यापारिक सम्पर्क और विनिमय में बाधा बना हुआ था.
  2. औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार.
- उसके **तिरुवालंगाडु** एवं **करंदाई** (तंजौर) अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है.
- चूँकि श्रीलंका एवं मालद्वीप पर चोल नियत्रंण बना हुआ था जिसके कारण पूर्वी जगत् विशेषतः चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था.
- राजेन्द्र द्वारा बंगाल पर आक्रमण तमिल प्रदेश से प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था.
- राजेन्द्र प्रथम के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का व्यापक विकास हुआ. उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई. राजेन्द्र प्रथम के विद्यानुराग की पुष्टि उसके द्वारा धारण उसकी उपाधियों जैसे—**पण्डित चोल, मुडिगुंडचोल** आदि से होती है.
- 1044 ई. में राजेन्द्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र **राजाधिराज** प्रथम उत्तराधिकारी बना तथा सफलता प्राप्त की.

रबीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941)

प्रमुख तथ्य

- बहुआयामी अनेक प्रतिभाओं के धनी कवीन्द्र रबीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कलकत्ता के जोदासांकी ठाकुरबाड़ी में हुआ था.
- उनकी पहली कविता 1874 ई. में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो सर्वत्र सराही गई. इस कविता का विषय प्रकृति प्रेम और राष्ट्रप्रेम दोनों ही थे.
- रबीन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से काफी प्रेम था.
- उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया. ब्रिटिश लेखकों में वे शीले से अत्यधिक प्रभावित थे.
- उन्हें संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था. इसी कारण उनकी रचनाओं में तीनों साहित्यों का पुट मिलता है. Evening Song नामक पुस्तक से वे उच्च स्तर के लेखकों की श्रेणी में आ गए.
- रबीन्द्र ने जनसाधारण तक अपना सन्देश पहुँचाने के लिए हितवादी और साधना नामक पत्रिकाओं का सम्पादन प्रारम्भ किया और जनसाधारण तक अपना राष्ट्रवादी और मानवतावादी सन्देश पहुँचाने लगे.
- 1903 ई. में इन्हीं पत्रिकाओं में उनका एक काव्य संग्रह 13 खण्डों में प्रकाशित हुआ.
- उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास 'गोरा' था, जो उन्होंने 1903-07 ई. के बीच लिखा. इसका मुख्य पात्र गोरा नामक शिक्षित युवक था जिसने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने पारम्परिक संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने पारम्परिक मूल्यों को त्याग दिया था. इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने मूल संस्कृति के प्रति आस्था रखने के भाव उजागर किए हैं और देशभक्ति की भावना बढ़ाने का प्रयास किया.
- टैगोर ने इस वास्तविकता को जाना कि गाँव ही भारतीय संस्कृति और राजनीति का आधार है.
- रबीन्द्र ने अपने लेखों में भारतीयों को संदेश दिया कि वे पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण न करें, बल्कि अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व करें.
- उन्होंने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए भी विचार रखें. वे भली-भाँति जानते थे कि कोरे विचार समाजोत्थान या लोक कल्याण नहीं कर सकते. अत उन्होंने 1901 ई. में शान्ति निकेतन की स्थापना की जहाँ वे छात्रों को अपने तरीके से शिक्षित करते थे.
- रबीन्द्रनाथ टैगोर को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार माना गया. उनकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर थी.
- 1913 ई. में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया. गीतांजलि एक भक्ति काव्य है, जो वैष्णव गीतों पर आधारित है. इसके माध्यम से कवि ने भारतीयता एवं भक्ति का संदेश दिया है.
- भारतीय समाज की दयनीय दशा को देखते हुए रबीन्द्रनाथ टैगोर ने विचार दिया कि खराब आर्थिक दशा और निम्नस्तरीय ग्रामीण जीवन में केवल शिक्षा ही सुधार ला सकती है.
- उन्होंने सामूहिक खेती और कुटीर उद्योगों के साथ-साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा को सामाजिक विकास के लिए आवश्यक बताया.
- 1905 के बंग-भंग विरोधी आन्दोलन के दौरान टैगोर ने अपनी कविताओं द्वारा देशभकित की भावना का संचार किया.

- उनके 'अमार सोनार बांग्ला' नामक गीत ने राष्ट्रीय आन्दोलन को हवा दी. यह गीत जुबां-जुबां पर आ गया. जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा.
- 1911 ई. में टैगोर ने 'जन गण मन अधिनायक' की रचना की, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना.
- टैगोर ने अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को समृद्ध तो किया ही साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन में जान भी फूँक दी.

ऐतिहासिक स्थल

पाटलिपुत्र

प्रमुख तथ्य

- बिहार की वर्तमान राजधानी पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था.
- प्राचीन भारत में यह नगर पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध तक यह विभिन्न राजनैतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा.
- पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर मगध के हर्यकवंशी राजा उदायिन् या उदयभद्र (460–444 ई.पू.) ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित किया. मगध के केन्द्र में स्थित होने के कारण यह नगर राजधानी के निमित्त अधिक उपयुक्त था.
- बुद्धकाल में यह भारत का महानगर माना जाता था. यहाँ से अनेक व्यापारिक मार्ग होकर गुजरते थे जिससे यह व्यापार-वाणिज्य का भी प्रमुख केन्द्र बना.
- मौर्य युग में इस नगर की महती उन्नति हुई. यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इस नगर का विस्तृत वर्णन करता है.
- मेगस्थनीज के अनुसार यह 9½ मील लम्बा 1¾ मील चौड़ा था. नगर के बीचों-बीच चन्द्रगुप्त मौर्य का विशाल राजप्रासाद स्थित था, जो विशालता एवं भव्यता में सूसा और एकबतना के महलों से भी बढ़कर था. नगर का प्रबन्ध 5-5 सदस्यों वाली छः समितियाँ करती थीं.
- **अशोक के समय में इस नगर में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था.** उसने यहाँ कई स्तूप एवं विहार भी बनवाए थे.
- मौर्यों के बाद शुगों के समय में भी पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी बनी रही. पतंजलि ने इसके प्रसादों का उल्लेख किया है.
- यवनों के आक्रमण से इस नगर की भी क्षति हुई, लेकिन कालांतर में इस नगर ने गुप्तवंश के पुनः एक विशाल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया.
- चीनी यात्री फाहियान इसकी प्रशंसा करते हुए बताता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर था जहाँ के लोग सुखी एवं समृद्ध थे. उसने चन्द्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन करते हुए लिखा है कि इसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया लगता था. अशोक का स्तूप भी उसने देखा था.
- चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में यहाँ नौ लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की मण्डली (नवरत्न) निवास करती थी.
- उदयगिरि गुहालेख से पता चलता है कि पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन व्याकरण, न्याय, राजनीति का प्रकाण्ड पण्डित था तथा सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी आर्यभट्ट भी यहीं निवास करते थे.
- गुप्तयुग में सांस्कृतिक केन्द्र होने के साथ-साथ पाटलिपुत्र एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र भी था. यह उत्तरापथ के व्यापारिक मार्ग से सम्बन्धित था. यहाँ के व्यापारी विभिन्न देशों को जाते थे तथा यहाँ के बाजार बिक्री की बहुमूल्य वस्तुओं से सजे रहते थे.
- गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटिलपुत्र नगर का गौरव घटने लगा. परवर्ती राजवंशों ने अपनी राजधानी इसके स्थान पर कन्नौज में स्थापित कर लिया.
- सातवीं शती में हुएनसांग ने इस नगर को वीरान देखा था और यहाँ के मठ, मन्दिर, स्तूप आदि नष्ट हो गए थे.
- कनिंघम ने इस नगर के विनाश के लिए गंगा नदी की बाढ़ को उत्तरदायी बताया है. चीनी तथा बौद्ध साधनों में भी गंगा के जल-प्लावन के कारण पाटलिपुत्र के नष्ट होने का विवरण सुरक्षित है.
- स्पूनर ने पटना के समीप कुमराहार नामक स्थान से खुदाइयाँ करके विशाल मौर्य प्रासाद के अवशेष प्राप्त किए. इन सबके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र इसी स्थान पर रहा होगा.
- साहित्य में पाटलिपुत्र के कुछ अन्य नाम—कुसुमपुर, कुसुमध्वज, पुष्पपुर आदि भी मिलते हैं.

पट्टडकल

प्रमुख तथ्य

- पट्टडकल कर्नाटक प्रान्त के बीजापुर जिले में मालप्रभा नदी के तट पर बसा है.
- 992 ई. के एक लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ चालुक्य वंशी राजाओं की राजधानी थी जहाँ वे अपना अभिषेक कराते थे.
- पट्टडकल को चालुक्य वास्तु एवं तक्षण कला का प्रमुख केन्द्र माना जाता है.
- यहाँ से 10 मंदिर मिले हैं जिनमें 4 उत्तरी तथा 6 दक्षिणी शैली में निर्मित हैं. पाप-नाथ का मंदिर, विरुपाक्ष मंदिर तथा संगमेश्वर के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं.
- यहाँ से प्राप्त विरुपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक सुन्दर तथा आकर्षक है. इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी ने 740 ई. में कराया था.
- विरुपाक्ष मंदिर के सामने नन्दिमण्डप, चारों ओर वेदिका तथा एक तोरणद्वार बना है. बाहरी दीवार में बने ताखों में शिव, नाग आदि की मूर्तियाँ रखी हैं तथा रामायण के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है.
- पट्टडकल के सभी मंदिरों में स्तूप के आकार के शिखर निर्मित हैं तथा उनमें कई तल्ले हैं. प्रत्येक तल्ले में मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं. मंदिर पूर्णतया पाषाण-निर्मित हैं. यहाँ के मन्दिर उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला के बीच की कड़ी हैं.

नासिक

प्रमुख तथ्य

- नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है.
- शक सातवाहन युग में यह बौद्धधर्म का प्रमुख स्थल था.
- इस स्थान से बौद्ध गुफाओं का एक समूह मिला है. इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए निर्मित करवाया गया था. यहाँ कुल 17 गुफाओं का निर्माण हुआ जिनमें 16 विहार तथा एक चैत्य है.
- यहाँ से प्राप्त प्राचीनतम विहार में सातवाहन नरेश कृष्ण का एक लेख प्राप्त हुआ है. यहाँ स्थित बड़े विहारों में 'नहपान विहार' प्रथम है जिसमें 16 कोठरियाँ बनी हैं. इसमें नहपान के दामाद उषावदात का एक लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि उसने बौद्ध संघ को एक विहार दान में दिया था.
- इसके अतिरिक्त सातवाहन नरेशों—गौतमीपुत्र शातकर्णि तथा यज्ञश्री के समय के भी एक-एक विहार यहाँ से मिलते हैं.
- नासिक के चैत्यगृह का निर्माण प्रथम शती ईसा पूर्व में हुआ था. इसके मण्डप में सीधे खम्भे लगे हैं. उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख में दानकर्ताओं के नाम हैं. इसे 'पाण्डु-लेख' कहा जाता है.
- नासिक का एक प्राचीन नाम गोवर्धन भी था.

शेष पृष्ठ 101 पर

वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति

कर्पूरी ठाकुर

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई. इसके अलावा इस वर्ष उनकी जन्मशती के उपलक्ष्य में बिहार में तीन दिवसीय राजकीय समारोह आयोजित किया जा रहा है.

प्रमुख तथ्य

- 24 जनवरी, 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया गाँव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने 1940 मे पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया. इस दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद वे 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में रहे तथा 1945 में रिहा हुए.
- 1948 में वे आचार्य नरेन्द्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले सोशलिस्ट पार्टी के प्रादेशिक मंत्री बने.
- वह 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य बने थे.
- सन् 1967 के आम चुनाव के बाद उन्हें बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया गया. इस पद पर वे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी, 1968 तक रहे.
- मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल सोशलिस्ट पार्टी एवं भारतीय क्रांति दल की सरकार में दिसम्बर 1970 से जून 1971 तक रही.
- इसके बाद दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में दिसम्बर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे.
- 17 फरवरी, 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया.
- बिहार के वंचित समुदायों के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे कर्पूरी ठाकुर को 'जन नायक' (People's Hero) के नाम से भी जाना जाता है, हाशिए पर मौजूद लोगों की समानता और सशक्तिकरण एवं दलितों के उत्थान के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर एक स्थायी छाप छोड़ी. उनकी विरासत भारत में समकालीन राजनीति और सामाजिक सुधारों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है.

कर्पूरी ठाकुर का लोकजीवन में योगदान

- **अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना**—सन 1967 में जब वे पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया. इसके पीछे उनका तर्क था कि लड़कियों के विवाह में मैट्रिक की परीक्षा पास करना बड़ी अड़चन बन रहा था. आकलन कराए जाने पर पता चला कि अधिकतम छात्राएं अंग्रेजी में ही अनुत्तीर्ण होती हैं जिसकी वजह से स्त्री शिक्षा की दर कम होने साथ ही मैट्रिक का परिणाम भी खराब होता जा रहा है. इसी उद्देश्य से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी.
- **आरक्षण नीति**—कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में, सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया. यह नीति, जिसे 'कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला' के नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग की सिफारिशों की अग्रदूत थी. इस नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 3% आरक्षण प्रस्तावित था.
- **भूमि सुधार**—मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भूमि सुधारों की शुरूआत की जिसके कारण जमींदारों से भूमिहीन दलितों को भूमि का पुनर्वितरण हुआ, उनकी भूमि सुधार नीति के कारण उन्हें 'जननायक' (People 's Hero) की उपाधि मिली.
- **सामाजिक कल्याण पहल**—उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1971 में वृद्धावस्था पेंशन की शुरूआत की और 1977 में मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी. उनके ये निर्णय बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने और युवाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई.
- **शराब बंदी नीति**—कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में शराब बंदी लागू की.

भारत रत्न

- *यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.*
- *भारत रत्न देने की शुरूआत 2 जनवरी, 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने की थी. पहली बार वर्ष 1954 में यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था.*
- *यह सम्मान जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना, असाधारण सेवा/प्रदर्शन हेतु दिया जाता है.*
- *यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसम्बर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया.*
- *खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला है.*
- *विदेशी मूल के तीन लोगों—मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भी यह सम्मान दिया जा चुका है.*
- *अब तक 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है.*

राजनीति, शासन व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय

चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme—EBS)

सुर्खियों में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राजनीतिक परिदृश्य में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अपने एक ऐतिहासिक फैसले में देश के चुनावी बॉण्ड योजना और सम्बन्धित संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी बॉण्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत् सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

प्रमुख तथ्य

- चुनावी बॉण्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है. यह योजना राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देती है.
- चुनावी बॉण्ड योजना 29 जनवरी, 2018 को लागू हुई थी. ध्यातव्य है कि चुनावी बॉण्ड योजना (EBS) की घोषणा पहली बार वर्ष 2017 के बजट सत्र में की गई थी. बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉण्ड को सक्षम करने के लिए वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कम्पनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था.
- केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत् पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या राज्य विधान सभा के लिए डाले गए वोटों में से कम-से-कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के पात्र हैं.
- चुनावी बॉण्ड भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से चेक या डिजिटल तंत्र के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं (नकद की अनुमति नहीं है) ये बॉण्ड ₹ 1,000, ₹ 10,000, ₹ 1 लाख, ₹ 10 लाख और ₹ 1 करोड़ के गुणकों में बेचे जाते हैं.
- चुनावी बॉण्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं तथा इनका नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकता है.
- भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएँ ही इसे खरीद सकती हैं.
- क्रय करने के बाद दानकर्ता इस बॉण्ड को अपनी पसंद की पार्टियों को दान में दे सकता है. यह ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा माँगे जाने पर देय होता है.
- राजनीतिक दलों को ऐसे बॉण्डों को प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुनाने और अपने चुनावी खर्चों को निधि देने का विकल्प होता है. वर्ष 2022 में इस योजना में संशोधन किया गया. इस संसोधन के अन्तर्गत एक नया पैरा पेश किया गया, जिसके अनुसार राज्यों की विधान सभा और विधानमंडल वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के आम चुनाव के वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी.
- चुनावी बॉण्ड केवल विशिष्ट समय अवधि के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजना को निरस्त किए जाने का आधार

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा है कि गुमनाम चुनावी बॉण्ड सूचना के अधिकार और संविधान की धारा 19(1)(ए) का उल्लंघन करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है.
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में किया गया संशोधन, जो कम्पनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान की अनुमति देता है, स्पष्ट रूप से मनमाना है.
- न्यायलय ने सरकार के इस तर्क की आलोचना की कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के आय के स्रोत जानने का अधिकार नहीं है.
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से चंदा, वित्तीय सहायता से बदले में बदले की व्यवस्था हो सकती है.
- के.एस. पुट्टास्वामी मामले (2017) में जिसमें निजता के अधिकार को बरकरार रखा था, को संदर्भित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्दिष्ट आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test) पर भरोसा करते हुए कहा केन्द्र सरकार को एक नई प्रणाली डिजाइन करने पर विचार करना चाहिए जो आनुपातिकता को संतुलित करती है और समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है.

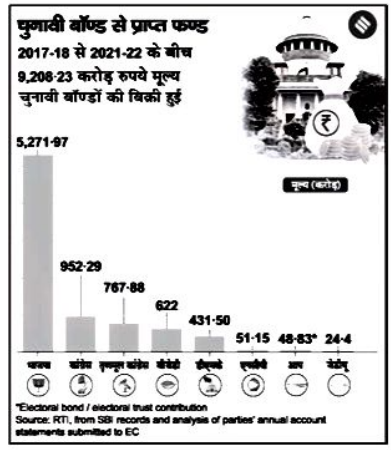

चुनावी बॉण्ड योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण

- चुनावी बॉण्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव है. चुनावी बॉण्ड की गोपनीयता का मामला केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए है, दान प्राप्त करने वाले दल के लिए नहीं.
- चुनावी बॉण्ड स्टेट बैंक द्वारा बेचे जाते थे, जो सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है, इस कारण सरकार को यह पता रहता है कि उसके राजनैतिक विरोधियों को कौन चंदा दे रहा है.
- यह योजना मतदाताओं की फंडिंग के स्रोत को जानने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे राजनीतिक जवाबदेही कम हो जाती है.
- इस योजना द्वारा काले धन के प्रवाह और व्यवसायों द्वारा पक्षपात की सम्भावना को बढ़ावा मिल सकता है.
- इस योजना द्वारा काले धन के प्रवाह और व्यवसायों द्वारा पक्षपात की सम्भावना को बढ़ावा मिल सकता है अर्थात् क्रोनी पूँजीवाद की सम्भावना बढ़ जाती है.
- आलोचकों का मानना है कि 'चुनावी बॉण्ड' राजनैतिक वित्त के संग्रह का भ्रामक माध्यम है, क्योंकि धन का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है.
- यह योजना सत्तारूढ़ दल को अनैतिक और असंगत रूप से लाभ पहुँचाती है, क्योंकि अधिकांश बॉण्ड कॉर्पोरेट्स द्वारा खरीदे जाते हैं और सत्तारूढ़ दल को प्राप्त होते हैं.
- इस योजना में निषिद्ध स्रोतों से प्राप्त अनुदान की ट्रैकिंग मुश्किल होती है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता प्रभावित होती है.

भारत में चुनावी वित्तपोषण के सम्बन्ध में सुझाव

- भारत में राजनैतिक दान की सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी दल पर कुछ बड़े दानकर्ताओं चाहे वे व्यक्ति हों, निगम हों या नागरिक समाज संगठन हों, का अतिशय प्रभाव न हो. इसके अलावा कुछ व्यक्तियों या संगठनों, उदाहरण के लिए विदेशी नागरिकों या कम्पनियों के दान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
- सरकार द्वारा राजनैतिक दलों के व्यय की सीमाएं निर्धारित कर देनी चाहिए. व्यय पर आरोपित सीमाएं राजनीति को वित्तीय होड़ से बचाती हैं.
- भारत में राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए. उदाहरण के लिए, जर्मनी में राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्व के आधार पर सार्वजनिक धन प्रदान किया जाता है.

- एक अन्य विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष (National Election Fund) की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें सभी दानकर्ता दान दे सकें. बाद में राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर धन आवंटित किया जा सकता है.

पर्यावरण एवं प्रदूषण

हिमालय में वनाग्नि (Forest Fires in the Himalayas)

सुर्खियों में क्यों ?

इस वर्ष शीत ऋतु में हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर हिमाचल तथा उत्तराखण्ड में वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आई हैं. भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, 16 अक्टूबर, 2023 से 16 जनवरी, 2024 के बीच वनाग्नि की 2,050 घटनाएँ हुईं, जो विगत् वर्ष इसी अवधि के दौरान वनाग्नि की 296 घटनाओं की तुलना में काफी अधिक है.

प्रमुख तथ्य

- सूखे जंगलों या झाड़ियों जैसे ज्वलनशील वातावरण में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होकर फैलने वाली भयानक आग को वनाग्नि कहा जाता है. ऐसी आग प्रायः एक बड़े क्षेत्र में और काफी लम्बे समय तक अनियंत्रित रूप से जलती रहती है. सामान्यतया दीर्घकालीन गर्मी, शुष्क मौसम या बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक कारक या मानवीय लापरवाही वनाग्नि का कारण होते हैं.
- जंगल में लगने वाली आग का मुख्य कारण, जलवायु परिवर्तन होता है. वनाग्नि जंगल में स्थित सूखी लकड़ियाँ या अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण तेजी से फैलती है. कई बार जंगलों में लगने वाली आग का कारण बिजली गिरना या अत्यधिक सूखी लकड़ियाँ या पेड़-पौधों के सूखे पत्ते भी होते हैं.
- भारत में, वनाग्नि की घटनाएं आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान होती है. इन महीनों में जमीन सूखी लकड़ियों, घास, खरपतवार और सूखे पत्तों से भर जाती है. ऐसे में छोटी-सी चिंगारी भी वनाग्नि का कारण बन जाती है. कुछ उदाहरणों में तापमान अधिक होने के समय सूखे पेड़ों की शाखाओं के आपस में रगड़ने से होने वाले घर्षण से भी जंगल में आग लग जाती है.
- आमतौर पर वनाग्नि को 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है–
  1. क्राउन आग,
  2. सतही वनाग्नि,
  3. भूमिगत वनाग्नि.
- क्राउन आग से पेड़ अपनी पूरी लम्बाई अर्थात् ऊपर तक जल जाते हैं. ये सबसे तीव्र और खतरनाक जंगली आग होती है.
- सतही वनाग्नि मुख्य रूप से सतही आग के रूप में हो सकती है, जिसमें जमीन पर पड़े कूड़े (पत्ते और टहनियाँ एवं सूखी घास आदि) में आग लगती है.
- भूमिगत वनाग्नि मुख्य रूप कम तीव्रता की ऐसी वनाग्नि जिसमें सतह एवं इसके नीचे के कार्बनिक पदार्थ और कूड़े में आग लगती है. अधिकांश घने जंगलों में मृदा की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का आवरण पाया जाता है. ऐसी वनाग्नि आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत होने के साथ सतह से कुछ मीटर नीचे तक लग सकती है. यह आग बहुत धीरे-धीरे फैलती है तथा ज्यादातर मामलों में इस प्रकार की आग का पता लगाना और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये महीनों तक जारी रह सकती है जिससे मृदा का वनस्पति आवरण नष्ट हो सकता है.

हिमालय क्षेत्र में वनाग्नि के कारण

- सामान्यतः वनाग्नि के दो प्राथमिक कारण होते हैं–मानव जनित और प्राकृतिक.
- **मानव जनित कारण**–अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 90% जंगलों की आग मानव जनित होती हैं. मानव जनित लापरवाही, जैसे कि कैंपफायर को बिना बुझाए छोड़ दिया जाना या सिगरेट पीने के बाद कहीं भी लापरवाही से फेंक देना आदि इस प्रकार की वनाग्नि के मुख्य कारण हैं. दुर्घटनाएँ, जानबूझकर की गई आगजनी, कूड़े को गलत तरीके से जलाना और आतिशबाजी आदि भी जंगल की आग के अन्य प्रमुख कारणों में से हैं.
- **प्राकृतिक कारण–**

  1. आकाशीय बिजली–वनाग्नि के पीछे आकाशीय बिजली प्रमुख कारणों में से एक है.

  2. ज्वालामुखी विस्फोट–आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की ऊपरी परत में उपस्थित गर्म मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल जाता है. गर्म लावा बाहर आकर जंगल में आग का कारण बनता है.

  3. तापमान–उच्च वायुमंडलीय तापमान और सूखापन जंगलों में आग लगने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित करते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह पर हवा का तापमान बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप कार्बन डाई ऑक्साइड और जंगल की आग फैलने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है.

  4. ज्वलनशील वृक्ष प्रजातियाँ–चीड़ पाइन जैसे अग्नि-प्रवण और ज्वलनशील वृक्ष प्रजातियों की उपस्थिति से वनाग्नि का खतरा बढ़ जाता है. हिमाचल का लगभग 15% वन क्षेत्र चीड़ से आच्छादित है.

  5. दीर्घकालीन सूखा रहने से खतरा–कई महीनों तक बारिश या बर्फबारी के बिना लंबे समय तक सूखा रहने से क्षेत्र में वनाग्नि का खतरा बढ़ जाता है.

पर्यावरण पर वनाग्नि के प्रभाव

- जैव विविधता, पौधों और जानवरों के विलुप्त होने का खतरा.
- वैश्विक तापमान में वृद्धि.
- वातावरण में CO_2 की वृद्धि.
- आदिवासियों और ग्रामीणों की आजीविका का नुकसान.
- मृदा अपरदन मिट्टी और उत्पादन की उत्पादकता पर दुष्प्रभाव.
- माइक्रॉक्लाइमेट (किसी विशेष छोटे जगह की जलवायु) में परिवर्तन.
- वन संसाधनों का नुकसान.
- ओजोन परत को नुकसान.
- जलग्रहण क्षेत्रों का क्षरण.

भारत में वन अग्नि निवारण और प्रबंधन

- शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से मानव जनित आग की रोकथाम की जा सकती है. इन जागरूकता कार्यक्रमों में वन-सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इंजीनियरिंग कार्य, लोगों की भागीदारी और शिक्षा और प्रवर्तन शामिल होने चाहिए.
- वनाग्नि की रोकथाम के लिए संयुक्त वन अग्नि प्रबंधन के माध्यम से लोगों की भागीदारी पर अधिक जोर दिया जाए.
- वनाग्नि रोकने के लिए एक समन्वित नेटवर्क को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वनाग्नि की सूचना तुरन्त मिल सके.
- आग का पता लगाने में रिमोट सेंसिंग तकनीक को उचित महत्व दिया जाना चाहिए.
- सफल अग्नि प्रबंधन और प्रशासन के लिए, देश में एक राष्ट्रीय अग्नि खतरा रेटिंग प्रणाली (एनएफडीआरएस) और अग्नि पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जानी है.
- वनाग्नि की घटना की जानकारी मिलने पर तेजी के साथ बचाव कार्य एवं तदुपरांत अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए.

- वनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

आर्थिक एवं वित्तीय अवधारणाएं

भौगोलिक संकेतक (GI)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में कई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication—GI) टैग प्रदान किया गया है. वर्तमान में देखा गया है कि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication—GI) प्राप्त करने के लिए प्रक्रियागत जटिलताओं के साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है.

प्रमुख तथ्य

- किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाए या निर्मित किए किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प तथा औद्योगिक वस्तु) को जीआई टैग प्रदान किया जाता है.
- बौद्धिक सम्पदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक सम्पत्ति और भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार किया गया, साथ ही इसके संरक्षण पर अधिक बल भी दिया गया हैं.
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का अन्तर्राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था ट्रिप्स (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right—TRIPS) समझौते के तहत्, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत् किया जाता है. जीआई टैग, चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है.
- जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रदान किए जाने का आधार किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता एवं पहचान है.
- किसी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि "उक्त उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जिस क्षेत्र के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है."
- भौगोलिक संकेतक किसी विशेष क्षेत्र या राज्य की सार्वजनिक सम्पत्ति है. इसे दूसरों को सौंपा या हस्तांतरित, गिरवी नहीं रखा जा सकता है. यदि जीआई टैग के अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो यह टैग उसके उत्तराधिकारी को स्थानांतरित हो जाता है.
- भारत में जीआई टैग किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं.
- कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान की जाती है. उदाहरण के लिए–बासमती चावल. जीआई टैग के तहत् बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड इत्यादि राज्य का अधिकार है.
- भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था.
- भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है–महाबलेश्वर–स्ट्रॉबेरी, जयपुर–ब्लू पोटरी, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पाश्मीना, हिमाचल का काला जीरा, छत्तीसगढ़ का जीराफूल और ओडिशा की कंधमाल हल्दी इत्यादि.

GI-टैग पंजीकरण के सन्दर्भ में भारत की स्थिति

- GI रजिस्ट्री के अनुसार दिसम्बर 2023 तक, बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत भारत की तरफ से केवल 1,167 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 547 उत्पाद पंजीकृत किए गए हैं. अन्य देशों की तुलना में आवेदनों की दृष्टि से भारत GI पंजीकरण के मामले में बहुत पीछे है.
- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के वर्ष 2020 के आँकड़ों के अनुसार 15,566 पंजीकृत उत्पादों के साथ जर्मनी GI पंजीकरण के मामले में सबसे आगे है, इसके बाद चीन (7,247 उत्पाद) का स्थान आता है.
- वैश्विक स्तर पर, पंजीकृत GI उत्पादों में शराब और उससे सम्बन्धी उत्पादों का हिस्सा 51·8% है, इसके बाद कृषि उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ (29·9%) हैं.
- उत्पादों की प्रकृति की दृष्टि से भारत में हस्तशिल्प (लगभग 45%) और कृषि (लगभग 30%) में अधिकांश GI उत्पाद शामिल हैं.

भारत में GI टैग के सम्बन्ध में बाधाएं

- वर्तमान में GI अधिनियम, 1999 वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है और इसे समसामयिक बनाने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है. इसके साथ ही प्रक्रिया के सरल अनुपालन के लिए पंजीकरण फॉर्म और आवेदन प्रसंस्करण समय को सरल बनाने की आवश्यकता है.
- भारत के सन्दर्भ में GI संकेतक की वर्तमान आवेदन स्वीकृति अनुपात केवल लगभग 46% है. इसका मुख्य कारण संस्थागत विकास की कमी है, जो प्रक्रियागत प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है. मार्गदर्शन और समर्थन की कमी के कारण उत्पादक अकसर GI पंजीकरण के बाद संघर्ष करते हैं.
- GI अधिनियम,1999 में 'उत्पादकों' की अस्पष्ट परिभाषा के कारण मध्यस्थों की भागीदारी बढ़ जाती है. इस कारण वास्तविक उत्पादकों को मध्यस्थों की तुलना में अपेक्षित लाभ कम होता है.
- कुछ कृषिगत उत्पादों जैसे–चाय और बासमती चावल के मामलों में अक्सर क्षेत्राधिकार, पेटेंट, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट जैसे विवादों सामने आते हैं परिणामस्वरूप GI के विकास पर कम ध्यान दिया जाता है.

GI-आधारित उत्पादों पहचान और उनके सुझाव के लिए सुझाव

- GI आधारित उत्पादों प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को उत्पादकों को संवर्धित किए जाने की आवश्यकता है.
- उत्पादकों को सीधा लाभ सुनिश्चित करने के लिए 'गैर-उत्पादकों या बिचौलियों' के उन्मूलन किया जाना चाहिए.
- GI हितधारकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, कौशल निर्माण और डिजिटल साक्षरता से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए.
- सरकारी मीडिया के माध्यम से GI आधारित उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए.
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा GI उत्पादों पर ध्यान वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा दे सकता है.
- एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ GI को एकीकृत करने से GI उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा.
- सरकार द्वारा बाजार आउटलेट योजनाएं, विशेष रूप से ग्रामीण बाजार (ग्रामीण हाट) को बढ़ावा देने से, GI उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा.

- उपभोक्ताओं का GI उत्पादों की गुणवत्ता के प्रति विश्वास सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए.
- GI उत्पादों को स्टार्टअप के साथ संरेखित करना और उनके प्रदर्शन को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ जोड़ना सामाजिक विकास के साथ-साथ GI उत्पादों के विकास में योगदान में योगदान दे सकता है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डर्मेटोमायोसाइटिस (Dermatomyositis)

सुर्खियों में क्यों ?

दंगल फिल्म में में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुहानी भटनागर का 19 वर्ष की अवस्था में बीमारी से निधन हो गया. डॉक्टरों के अनुसार वे डर्मेटोमायोसाइटिस (Dermatomyositis) नामक बीमारी से ग्रस्त थीं.

प्रमुख तथ्य

- डर्मेटोमायोसिटिस मांसपेशी रोगों के समूह की एक दुर्लभ बीमारी है, जिसे ऑटो इम्यून बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है.
- ऑटो इम्यून उन बीमारियों को कहा जाता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अलग तरह से काम करता है. इस वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और वो बीमारियों से लड़ पाने में असमर्थ हो जाता है.
- यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सामान्यतया यह 50 से 70 वर्ष की आयु के वयस्कों को ज्यादा प्रभावित करता है.
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस बीमारी के होने की सम्भावना दोगुनी होती है.
- इस बीमारी से पीड़ित कुछ लोगों में संयोजी ऊतक विकार, जैसे–ल्यूपस या रुमेटीइड गठिया भी होता है.

डर्मेटोमायोसाइटिस के लक्षण–डर्मेटोमायोसिटिस के लक्षण अचानक नजर आ सकते हैं या समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हो सकते हैं. सामान्य तौर पर डर्मेटोमायोसिटिस के रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं–

- धूप के सम्पर्क में आने वाले क्षेत्रों पर लाल या बैंगनी दाने, जिनमें दर्द या खुजली हो सकती है.
- ऊपरी पलकों की लाल या बैंगनी सूजन (हेलियोट्रोप).
- पैरों, कोहनियों, घुटनों और पैर की उंगलियों पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे (गॉट्रॉन पपल्स).
- जोड़ जो ठंड की स्थिति में जकड़न महसूस करते हैं और पीले और दर्दनाक हो जाते हैं और गर्म होने पर बेहतर महसूस करते हैं (रेनॉड की घटना).
- पपड़ीदार, खुरदुरी, शुष्क त्वचा, जिससे बाल पतले हो सकते हैं.
- नाखूनों के आस-पास सूजे हुए, लाल क्षेत्र.
- कैल्शियम जमा होने के कारण त्वचा के नीचे कठोर गाँठें (कैल्सिनोसिस).
- गर्दन, कूल्हे, पीठ और कंधों की मांसपेशियों में कमजोरी.
- निगलने में परेशानी होना और आवाज बदलना.
- थकान, बुखार और वजन कम होना.
- मांसपेशियों में दर्द.
- मांसपेशियों में कमजोरी के कारण कुर्सी से उठने या बिस्तर से उठने में परेशानी होना.

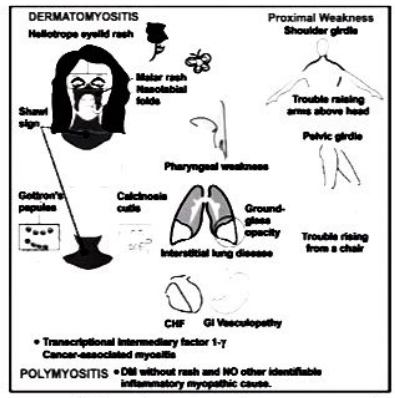

डर्मेटोमायोसाइटिस के कारण–यद्यपि डर्मेटोमायोसिटिस का कोई सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन सम्भावित कारणों में शामिल हैं–

- इस बीमारी की ऑटोइम्यून बीमारी के साथ बहुत समानता है, जिसमें रोगी का इम्यून सिस्टम गलती से रोगी के शरीर के ऊतकों पर ही हमला करने लगता है. पर्यावरणीय कारकों में वायरल संक्रमण, धूप में रहना, कुछ दवाएं और धूम्रपान शामिल हो सकते हैं.
- कुछ रोगियों में डर्मेटोमायोसिटिस का कारण वंशानुगत जीन होता है.
- कोई संक्रमण, दवा या वातावरण में कोई अन्य जोखिम जो इस बीमारी को मानव शरीर में उत्प्रेरित कर सकता है.

सम्बन्धित स्थितियाँ–डर्मेटोमायोसिटिस अन्य रोगों का कारण बन सकता है या रोगी को उनके विकसित होने के उच्च जोखिम में डाल सकता है, जिनमें शामिल हैं–

- **रेनॉड**–इस स्थिति के कारण ठण्डे तापमान के सम्पर्क में आने पर रोगी की उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ, गाल, नाक और कान पीले पड़ जाते हैं.
- **अन्य संयोजी ऊतक रोग**–अन्य संयोजी ऊतक रोग जैसे–ल्यूपस, रुमेटीइड गठिया, स्क्लेरोडर्मा और स्जोग्रेन सिंड्रोम आदि डर्मेटोमायोसिटिस के साथ हो सकते हैं.
- **हृदय रोग**–यह हृदय की मांसपेशियों में सूजन का कारण बन सकता है. डर्मेटोमायोसिटिस से पीड़ित लोगों में कंजेस्टिव हृदय विफलता की समस्या विकसित हो सकती है.
- **फेफड़ों की बीमारी**–इंटरस्टिशियल फेफड़े की बीमारी डर्मेटोमायोसिटिस के साथ हो सकती है. इंटरस्टिशियल फेफड़े की बीमारी विकारों के एक समूह को संदर्भित करती है, जो फेफड़ों के ऊतकों पर घाव का कारण बनती है, जिससे फेफड़े कठोर और लोचदार हो जाते हैं. लक्षणों में सूखी खाँसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है.
- **कैंसर**–वयस्कों में डर्मेटोमायोसिटिस को कैंसर, विशेष रूप से महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर के विकास की बढ़ती संभावना से जोड़ा जाता है.

इलाज–डर्मेटोमायोसिटिस का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन यह बीमारी लक्षणों के आधार पर नियंत्रित की जा सकती है. इस रोग की चिकित्सा में एक से अधिक प्रकार के उपचार के साथ-साथ उपचार को समय के साथ बदलने की आवश्यकता भी हो सकती है. उपचार में शामिल हैं–

- **शारीरिक चिकित्सा**–विशेष व्यायाम मांसपेशियों को फैलाने और मजबूत करने में मदद करते हैं. इसमें ऑर्थोटिक्स या सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है.
- **त्वचा का उपचार**–त्वचा पर चकत्तों से बचने के लिए रोगी को धूप में निकलने से बचना होगा और एंटीहिस्टामाइन दवाओं या त्वचा पर लगाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी स्टेरॉयड क्रीम के साथ खुजली वाली दवा से त्वचा के चकत्ते का इलाज किया जाता है.
- **सूजनरोधी औषधियाँ**–सामान्यतः सूजनरोधी औषधियाँ स्टेरॉयड दवाएं या कॉर्टिकोस्टेरॉयड होती हैं. ये शरीर में सूजन को कम करते हैं.
- **शल्य चिकित्सा**–यदि रोगी की त्वचा में दर्द या संक्रमण हो जाए, तो उसके नीचे जमा कैल्शियम (कैल्सिनोसिस) को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है. ●●●

राजनीतिशास्त्र लेख

लोक सभा और विधान सभा के चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2022 को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की संशोधित सीमा को अधिसूचित किया गया. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था. इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग ने श्री हरीश कुमार, सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी, श्री उमेश सिन्हा, महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग और श्री चंद्र भूषण कुमार, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की सदस्यता वाली एक समिति का गठन किया. समिति से अपेक्षा की गई कि वह चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव से सम्बन्धित लागत कारकों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों का अध्ययन करके उपयुक्त सिफारिश करेगी. समिति द्वारा राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे. समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है. इसमें चुनाव-प्रचार के बदलते तरीकों को भी शामिल किया गया है, जो धीरे-धीरे आभासी अभियान की ओर बढ़ रहा है.

क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्न में से किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
I. राज्य		**रुपए**	**रुपए**
1.	आंध्र प्रदेश	95,00,000	40,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	75,00,000	28,00,000
3.	असम	95,00,000	40,00,000
4.	बिहार	95,00,000	40,00,000
5.	छत्तीसगढ़	95,00,000	40,00,000
6.	गोवा	75,00,000	28,00,000
7.	गुजरात	95,00,000	40,00,000
8.	हरियाणा	95,00,000	40,00,000
9.	हिमाचल प्रदेश	95,00,000	40,00,000
10.	झारखण्ड	95,00,000	40,00,000
11.	कर्नाटक	95,00,000	40,00,000
12.	केरल	95,00,000	40,00,000
13.	मध्य प्रदेश	95,00,000	40,00,000
14.	महाराष्ट्र	95,00,000	40,00,000
15.	मणिपुर	95,00,000	28,00,000
16.	मेघालय	95,00,000	28,00,000
17.	मिजोरम	95,00,000	28,00,000
18.	नगालैण्ड	95,00,000	28,00,000
19.	ओडिशा	95,00,000	40,00,000
20.	पंजाब	95,00,000	40,00,000
21.	राजस्थान	95,00,000	40,00,000
22.	सिक्किम	75,00,000	28,00,000
23.	तमिलनाडु	95,00,000	40,00,000
24.	तेलंगाना	95,00,000	40,00,000
25.	त्रिपुरा	95,00,000	28,00,000
26.	उत्तर प्रदेश	95,00,000	40,00,000
27.	उत्तराखण्ड	95,00,000	40,00,000
28.	पश्चिम बंगाल	95,00,000	40,00,000
II. संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	75,00,000	—
2.	चंडीगढ़	75,00,000	—
3.	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	75,00,000	—
4.	दिल्ली	95,00,000	40,00,000
5.	लक्षद्वीप	75,00,000	—
6.	पुदुचेरी	75,00,000	28,00,000
7.	जम्मू-कश्मीर	95,00,000	40,00,000
8.	लद्दाख	75,00,000	—

उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा को बढ़ाने की राजनीतिक दलों की माँग पर विचार करते हुए और 2014 से 2021 तक मतदाताओं की संख्या 834 मिलियन से बढ़कर 936 मिलियन (12·23% अधिक) हो जाने और 2014-15 से 2021-22 तक लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में 240 से 317 तक (32·08% तक), वृद्धि हो जाने से उपजी परिस्थितियों पर विचार करते हुए समिति ने उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं. आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च सीमा को बढ़ाने का फैसला किया. तद्नुसार, संशोधित सीमाएं कानून, न्याय मंत्रालय और विधायी विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया, जो इस प्रकार है–

लोक सभा और राज्य विधान सभा चुनावों के उम्मीदवारों के खर्च की संशोधित सीमा

पूर्व व्यय सीमा (2014)	बढ़ी हुई व्यय सीमा (6 जनवरी, 2022 से प्रभावी)
संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए	
₹ 70 लाख	₹ 95 लाख
₹ 54 लाख	₹ 75 लाख
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए	
₹ 28 लाख	₹ 40 लाख
₹ 20 लाख	₹ 28 लाख

केन्द्रीय सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ गठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए–

निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2022 है, जो अधिसूचना जारी किए जाने की दिनांक 6 जनवरी, 2022 से प्रभावी है. ●●●

63वाँ सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23

—डॉ. बी. के. अग्रवाल

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 वित्तीय में वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत किया गया है. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में सरकारी कम्पनी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–कोई भी कम्पनी जिसमें कम-से-कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूँजी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो उसे सरकारी कम्पनी या सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है इसमें एक ऐसी कम्पनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी है.

आच्छादन

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण में पारम्परिक रूप से कुछ वैधानिक निगमों के अलावा, उन सरकारी कम्पनियों को भी शामिल किया गया है जिनमें 50% से अधिक इक्विटी धारिता केन्द्र सरकार के पास है. इन कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियाँ, यदि भारत में पंजीकृत हैं, जहाँ किसी सार्वजनिक उपक्रम की 50% से अधिक इक्विटी है, तो उन्हें भी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है. विभागीय रूप से संचालित सार्वजनिक उद्यमों, बैंकिंग संस्थानों और बीमा कम्पनियों को इस सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है. सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 इस शृंखला का 63वाँ प्रकाशन है. सर्वेक्षण में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 402 सार्वजनिक उद्यम शामिल किए गए हैं, जिनमें से 254 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम परिचालित हैं.

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार हैं–

सर्वेक्षण में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों को कृषि, खनन और अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन और सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करके विभिन्न दृष्टिकोण से सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक सांख्यिकीय डेटा प्रदान किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मापदण्डों के संदर्भ में सर्वेक्षण परिणामों की मुख्य विशेषताएं चित्र 1 में दर्शाई गई हैं.

- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की **कुल चुकता पूँजी** (Total Paid-up capital) 31 मार्च, 2022 को ₹ 3·59 लाख करोड़ से 40·85% बढ़ कर 31 मार्च, 2023 को ₹ 5·05 लाख करोड़ हो गई.
- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कुल **वित्तीय निवेश** (Financial Investment) 31 मार्च, 2022 को ₹ 22·89 लाख करोड़ से 10·75% बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹ 25·35 लाख करोड़ हो गया.

⌘ केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में 31 मार्च, 2023 को कुल वित्तीय निवेश में 65·85% हिस्सा सेवा क्षेत्र का, 26·11% विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन का तथा 4·14% खनन और अन्वेषण का था, जबकि कृषि का हिस्सा नगण्य था.

⌘ सम्बन्धित समूहों में, कुल वित्तीय निवेश में वित्तीय सेवाओं का हिस्सा 51·12% बिजली उत्पादन का 14·35%, पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन) का 6·42% और पावर ट्रांसमिशन का 5·42% था. अन्य सजातीय समूहों की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम थी.

⌘ उच्चतम वित्तीय निवेश वाले शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैं.

- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में **नियोजित पूँजी** (Capital Employed) 31 मार्च, 2022 को ₹ 34·78 लाख करोड़ से 9·71% बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹ 38·16 लाख करोड़ हो गई.
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालित केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के संचालन से कुल **सकल राजस्व** (Total Revenue) ₹ 37·90 लाख करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के कुल सकल राजस्व ₹ 31·36 लाख करोड़ से 20·83% अधिक था है.

⌘ वित्त वर्ष 2022-23 में संचालन से कुल सकल राजस्व में यह वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम (रिफाइनरी और मार्केटिंग), परिवहन और लॉजिस्टिक्स और पावर जेनरेशन कॉग्नेट ग्रुप में हुई वृद्धि के कारण थी.

⌘ क्षेत्रों में, विनिर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन क्षेत्र में सेवाओं और खनन और अन्वेषण के बाद सबसे अधिक हिस्सेदारी थी. वित्त वर्ष 2022-23 में तीन कॉग्नेट ग्रुप्स पेट्रोलियम (रिफाइनरी एण्ड मार्केटिंग), ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग और पावर जेनरेशन ने मिलकर सकल राजस्व में 69·53% का योगदान दिया.

चित्र-1 : केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की उपलब्धियों के कतिपय सूचक (₹ लाख करोड़ में)

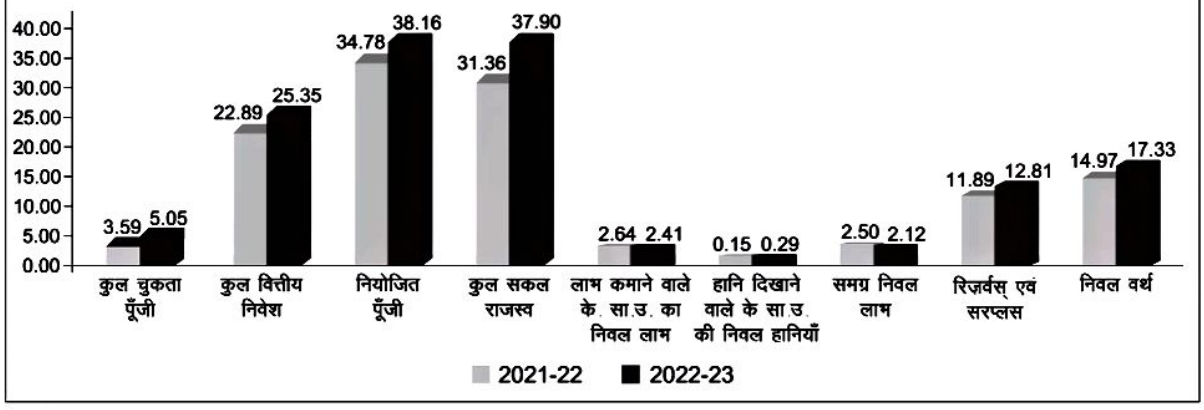

⌘ वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले वाले शीर्ष पाँच केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम और एनटीपीसी लिमिटेड हैं.

- लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का **शुद्ध लाभ** (Ney Profit) वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 2·41 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 2·64 लाख करोड़ की तुलना में 8·88% की कमी दर्शाता है. उच्चतम शुद्ध लाभ वाले शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में ओएनजीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड हैं.

चित्र-2 : के.सा.उ. की उपलब्धियाँ
(₹ लाख करोड़ में)

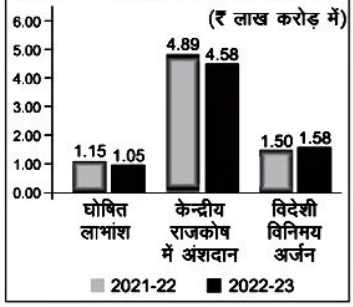

- घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का **शुद्ध घाटा** (Net loss) वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 0·29 लाख करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 0·15 लाख करोड़ था, जो 97·31% की वृद्धि दर्शाता है. घाटे में चल रहे प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड शामिल हैं.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का **कुल शुद्ध** लाभ ₹ 2·12 लाख करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 2·50 लाख करोड़ था, जो 15·08% की कमी दर्शाता है.

⌘ लाभ में बड़ा हिस्सा कोयला कॉग्नेट समूह का था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 0·28 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 0·42 लाख करोड़ हो गया. कोयला समूह के भीतर, कुल शुद्ध लाभ में वृद्धि में प्रमुख योगदान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (₹ 0·05 लाख करोड़) का है.

- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का **रिजर्व और सरप्लस** (Reserves and Surplus) 31 मार्च, 2023 को ₹ 12·81 लाख करोड़ था, जो 31 मार्च, 2022 को ₹ 11·89 लाख करोड़ से 7·73% अधिक है.
- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों **का शुद्ध मूल्य** (Net Worth) 31 मार्च, 2022 को ₹ 14·97 लाख करोड़ से 15·75% बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹ 17·33 लाख करोड़ हो गया.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिचालनरत 117 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों द्वारा **लामांश** (Dividend) घोषित किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1·15 लाख करोड़ के मुकाबले ₹ 1·05 लाख करोड़ रहा, जो 8·15% की कमी दर्शाता है.
- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), निगम कर (कॉर्पोरेट कर), केन्द्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केन्द्रीय खजाने में सभी सीपीएसई **का योगदान** (Contribution towards Exchequer) वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 4·89 लाख करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 4·58 लाख करोड़ रहा, जो 6·20% की कमी दर्शाता है. उत्पाद शुल्क में अंशदान ₹ 2·65 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2021-22 में) से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 2·31 लाख करोड़ होने के कारण संग्रह में कमी आई है. केन्द्रीय खजाने में योगदान देने वाले शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड हैं.
- माल और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से संचालित केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की **विदेशी मुद्रा आय** (Foreign Exchange Earnings) वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 1·58 लाख करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1·50 लाख करोड़ थी, जो 5·56% की वृद्धि दर्शाती है. इस श्रेणी के अन्तर्गत शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम हैं. मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड.
- सभी **कार्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर)** पात्र 166 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का सीएसआर व्यय (CSR Expenditure) वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 4,128 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 4,584 करोड़ से 9·94% कम रहा है. सीएसआर के तहत् सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में ओएनजीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैं.
- सभी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का **अनुसंधान एवं विकास व्यय** (Research & Development Expenditure) वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 7,233 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 6,668 करोड़ से 8·47% अधिक था. इस मद में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं.

चित्र-3 के.सा.उ. की उपलब्धियाँ : सीएसआर व्यय तथा आर एण्ड डी
(₹ करोड़ में)

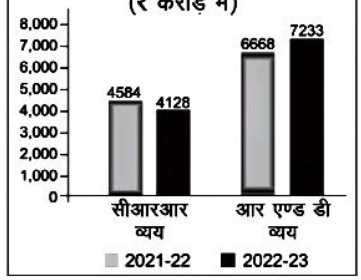

- भारत के स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले 63 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का कुल **बाजार पूँजीकरण** (एम-कैप) (Market Capitalization) 31 मार्च, 2023 को ₹ 16·69 लाख करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2022 को ₹ 15·46 लाख करोड़ से 7·95% अधिक था. एम-कैप में वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ताओं में मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (173%), रेल विकास निगम लिमिटेड (105%), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (91%) और 5 अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं, जिनमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई है.

●●●

आर्थिक लेख

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल संवर्धन : वर्तमान आवश्यकता

—राजामनु गौतम

भारत के विशाल और विविध परिदृश्य में, ग्रामीण युवा देश की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता है. देश की 65% से अधिक आबादी और 68% युवा ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं. हाल ही में लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव द्वारा आयोजित एक सामूहिक चर्चा में, जब अधिकांश ग्रामीण युवाओं से भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे अपने गाँव में रहना पसंद करते हैं. यद्यपि शहरीकरण की प्रचलित प्रवृत्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2047 तक लगभग 50% भारतीय आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, किन्तु यह महत्वपूर्ण होगा कि उन लोगों को नजरअंदाज न किया जाए, जो गाँवों में रहना पसंद करते हैं.

हालाँकि, विकसित होते आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के बीच, कौशल उन्नयन की आवश्यकता भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए एक गम्भीर आवश्यकता के रूप में उभरी है. जैसे-जैसे दुनिया ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, ग्रामीण युवाओं को प्रासंगिक और समसामयिक कौशल से लैस करना उनके सशक्तिकरण और ग्रामीण समुदायों की समग्र उन्नति के लिए अनिवार्य हो गया है. यह लेख भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल उन्नयन के महत्वपूर्ण महत्व, उनके समग्र विकास और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान के लिए चुनौतियों, अवसरों और सम्भावित मार्गों की खोज पर प्रकाश डालता है.

गौरतलब है कि भारत में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, कृषि, इसके सम्बद्ध क्षेत्रों के साथ, देश में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है. देश में लगभग 70% ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं तथा कई ग्रामीण परिवारों के युवा परिवार के स्वामित्व वाले खेतों पर काम करके अपने परिवार की आय में मदद करते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बड़े व्यावसायिक बदलाव का अनुभव कर रही है और अधिकांश कृषक कृषि छोड़कर गैर-कृषि नौकरियों में शामिल हो रहे हैं, जो कृषि संकट की ओर इशारा करता है; राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आँकड़ों के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3·4 करोड़ किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए. यह न केवल ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि को एक महत्वाकांक्षी व्यवसाय बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, बल्कि वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को भी उजागर करता है. परिणामस्वरूप वर्तमान में कृषि मात्रा आजीविका का साधन बनती जा रही है तथा इस क्षेत्र से पलायनवादिता बढ़ी है.

एनएसएसओ के अनुसार, 2020 में ग्रामीण पुरुष और महिला युवाओं के बीच बेरोजगारी दर क्रमशः 17·4% और 13·6% थी. सार्थक रोजगार की तलाश में इन युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को नियंत्रित करने के लिए, छात्रों को प्रासंगिक ग्रामीण कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है ताकि वे जहाँ वे वर्तमान में रहते हैं वहाँ अपना जीवन सुरक्षित कर सकें. स्कूलों में चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि अधिकांश छात्रों की शैक्षिक/रोजगार आकांक्षाएं उन विकल्पों तक ही सीमित थीं, जो उनके गाँवों के आसपास उपलब्ध थे. दिल्ली सरकार 'स्किल्स ऑन व्हील' पहल के साथ जो हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह के अपस्किलिंग अवसर छात्रों के दरवाजे तक लाए जाने चाहिए.

ग्रामीण आबादी के लिए वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

- ग्रामीण भारत में वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य ग्रामीण आबादी को कुशल बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लेसमेंट के बहुत कम या कोई अवसर नहीं हैं. वर्तमान में, ग्रामीण शिक्षा शायद ही कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है, जोकि उन अधिकांश युवाओं के लिए एक क्षुब्धता है, जो कथित तौर पर जीवन कौशल सीखने के लिए स्कूलों पर निर्भर हैं.
- एलएससी वॉयस 2023 सर्वेक्षण (11 जिलों के 15,856 युवाओं पर) से पता चला कि 19 से 22 वर्ष की आयु के दो-तिहाई युवाओं ने कभी भी किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, उनमें से केवल 5% ने इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था. यदि स्कूलों में सीखने को ग्रामीण जीवन कौशल से जोड़ा जाए, तो ग्रामीण शिक्षा में एक सक्षम पीढ़ी का पोषण करने की क्षमता होगी.
- हालाँकि, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की कमी और केवल शिक्षाविदों पर अधिक ध्यान देने के कारण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास इन क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, इतना कि लगभग 93·7 प्रतिशत युवाओं को 2017-18 में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला था.

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) का महत्व

भारत में ग्रामीण युवाओं को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए उनकी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उनका कौशल बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. यद्यपि उनके लिए कौशल उन्नयन के निम्नलिखित महत्व हो सकते हैं—

- प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका, जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय बदलाव, शहरीकरण और मूल्य शृंखलाओं का वैश्वीकरण जैसे वैश्विक मेगाट्रेंड काम की प्रकृति और कौशल की माँग को बदल रहे हैं. काम का भविष्य भी तेजी से बदल रहा है और उद्योग आज शिक्षित से अधिक कुशल कार्यबल की माँग करते हैं. इसलिए जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए आगे चलकर कौशल, और कौशल उन्नयन अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे.
- चूँकि ग्रामीण युवा भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी बेरोजगारी को सम्बोधित करना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आज एक भारतीय कर्मचारी को 2022 तक भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होने के लिए लगभग 100 दिनों की रीस्किलिंग की आवश्यकता है. अपस्किलिंग कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के कौशल और सम्भावित नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच अन्तर को मिटा सकते हैं, बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं.
- कौशल उन्नयन कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं. इससे स्थानीय उद्यमों का निर्माण, रोजगार के अवसर और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास

हो सकता है. ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में योगदान दे सकता है, क्योंकि भारत की कुल आबादी का लगभग 68% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है.

- ग्रामीण भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुँच अपेक्षाकृत कम है, ग्रामीण युवाओं का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुँच से वंचित है. आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 3·1% पुरुषों (18–29 वर्ष) को कौशल विकास का लाभ मिला, जबकि शहरी पुरुष युवाओं को 7% का लाभ मिला. कौशल उन्नयन पहल कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण समुदायों से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके इस अन्तर को दूर करने में मदद कर सकती है.
- प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने विभिन्न उद्योगों को बदल दिया है और नई रोजगार सम्भावनाएं तलाशी हैं. ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी-सम्बन्धी कौशल में प्रशिक्षित करने से वे बदलते रोजगार बाजार के अनुकूल ढल सकते हैं और उभरते अवसरों का लाभ उठा सकते हैं.
- ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना यह सुनिश्चित करके समावेशी विकास में योगदान देता है कि सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अवसरों तक समान पहुँच मिले. यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर और रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास की आवश्यकता को कम करके शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटने में मदद करता है.
- ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार में सुधार भारत को संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एजेंडा 2030 के करीब लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता), लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास), और लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा) की पूर्ति के लिए.

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल उन्नयन की चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और कार्यक्रमों तक पहुँच का अभाव होता है, जिससे ग्रामीण आबादी के बीच कौशल बढ़ाने के अवसर सीमित हो जाते हैं. ग्रामीण विद्यालयों में हुए अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्रों के पास उपलब्ध विकल्पों की कमी के कारण शैक्षिक और रोजगार की आकांक्षाएं सीमित हैं. ब्रेकथ्रू, क्वेस्ट एलायंस और प्रथम ऐजुकेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में लाइफ स्किल्स कोलैबोरेटिव द्वारा आयोजित एक संयुक्त सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण भारत में 80% युवाओं को अभी भी व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना बाकी है, जो एक महत्वपूर्ण कौशल अन्तर पर बल देता है.
- ग्रामीण भारत में वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य में प्लेसमेंट के अवसरों की कमी है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) ग्रामीण आबादी को कौशल प्रदान करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर पर्याप्त प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने में विफल रहते हैं. 'एलएससी वॉयस 2023 सर्वेक्षण' के अनुसार, 19 से 22 वर्ष की आयु के 66% युवाओं ने कभी भी किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, कौशल विकास पर फोकस की कमी ग्रामीण युवाओं की सम्भावनाओं को बाधित करती है, जो जीवन कौशल सीखने के लिए स्कूलों पर निर्भर रहते हैं.
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक चुनौतियों और उच्च स्तर की गरीबी का सामना करना पड़ता है. नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, भारत की बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 14·96% थी. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 19·28% की बहुआयामी गरीबी और शहरी क्षेत्रों में 5·27% गरीबी दर थी. ये सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ कौशल बढ़ाने की पहल में बाधाएं पैदा कर सकती हैं, क्योंकि व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का खर्च उठाने में कठिनाई हो सकती है या कौशल विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है.
- बेहतर रोजगार के अवसरों का आकर्षण अकसर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन की ओर ले जाता है. इस प्रवासन को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा को बनाए रखने के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तियों को उनके वर्तमान स्थानों में आजीविका सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में अकसर लैंगिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ महिलाओं और लड़कियों को उच्च स्तर के भेदभाव, दुर्व्यवहार और शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक सीमित पहुँच का अनुभव होता है. ग्रामीण समुदायों में समावेशी कौशल उन्नयन पहल के लिए इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है.
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण अपस्किलिंग पर अनुसंधान अपेक्षाकृत सीमित है, जिससे लक्षित नीतियों और हस्तक्षेपों को विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. विशिष्ट चुनौतियों को समझने और प्रभावी समाधान तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक डेटा और अनुसंधान तक पहुँच महत्वपूर्ण है.

डिजिटल डिवाइड और अपस्किलिंग प्रयास

भारत में डिजिटल विभाजन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसरों तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण बाधा रहा है. हालाँकि, इस विभाजन को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. 2017 में शुरू किए गए प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है. इस पहल के माध्यम से, ग्रामीण भारत के लाखों व्यक्तियों को डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्राप्त हुई है. इसके अतिरिक्त, विभिन्न कॉर्पोरेट, गैर-लाभकारी और शैक्षिक स्टार्टअप; ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता और सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी प्लेटफार्मों का लाभ उठा रहे हैं.

ई-लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण कौशल में सहायक

हाल के वर्षों में, ई-लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं. ये प्लेटफॉर्म शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच अन्तर को पाटते हुए सुलभ और लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने सहायक साबित हो सकते हैं–

- **प्रथम मुक्त विद्यालय**–यह प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना है. वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार के पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करते हैं, जो व्यक्तियों को नए कौशल हासिल करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं.

- **एनआईआईटी फाउंडेशन**—एनआई-आईटी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों सहित वंचित समुदायों को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर केन्द्रित है. वे आईटी, स्वास्थ्य सेवा और रिटेल जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों को रोजगार बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल युक्त करते हैं.
- **स्किल इंडिया**—स्किल इंडिया एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है. वे ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने के लिए विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफार्मों के साथ सहयोग करते हैं.
- **एनपीटीईएल**—नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हेंस्ड लर्निंग (NPTEL) दरअसल इंजीनियरिंग और साइंस के कोर्स कंटेंट्स तैयार करने के लिए भारत के 7 प्रमुख इंडियन इंस्टीट्यूट्स (IIT–दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, रुड़की, कानपुर और खड़गपुर) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) की एक शानदार पहल है जिसकी शुरूआत वर्ष 2003 में हुई थी. भारत के 5 प्रमुख IITs (IIT–दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास) और IISc ने प्रत्येक कोर्स के लिए कम-से-कम 40 घंटे के कोर्स कंटेंट को तैयार करने के लिहाज से 100 प्रमुख कोर्सेज के लिए वेब बेस्ड कंटेंट्स और विडियोज तैयार किए हैं. यहाँ कोर्स पूरा करने के बाद आप ऑप्शनल सर्टिफिकेशन एग्जाम भी दे सकते हैं.
- **स्वयं पोर्टल**—भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को संसद में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल 'स्वयं' की घोषणा की थी, यह देश में ही आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किया गया पोर्टल देश के 9वीं क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज मुहैया करवाता है. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से स्टूडेंट्स को मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करवाने के लिए तैयार किया गया है.
- **डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)**—दिशा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है. इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और उन्हें डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है. दिशा के माध्यम से, व्यक्ति अपनी डिजिटल साक्षरता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संसाधनों तक पहुँच सकते हैं.
- **ई-विद्यालोक**—ई-विद्यालोक एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है. वे स्वयंसेवी शिक्षकों को लाइव ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों से जोड़ते हैं, जिससे सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में भी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित होती है.

ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए नीतिगत अनुशंसाएं

भविष्य में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को और बढ़ाने के लिए, प्रशासन कुछ सुझावों को अपना सकती है उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

- ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाएं, जो विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों. इन कार्यक्रमों को उन्हें व्यावहारिक कौशल युक्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिनकी उनके स्थानीय समुदायों में माँग है.
- ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर-लाभकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना. यह सहयोग प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करने, मार्गदर्शन प्रदान करने और नौकरी प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करने में मदद कर सकता है.
- ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधनों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार करने में निवेश करें. इसमें विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और किफायती उपकरणों तक पहुँच प्रदान करना शामिल है.
- उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण को कौशल उन्नयन कार्यक्रमों में एकीकृत करना चाहिए. ग्रामीण युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल और वित्तीय ज्ञान के साथ सशक्त बनाने से वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम हो सकते हैं.
- मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करें, जो ग्रामीण युवाओं को समान पृष्ठभूमि के सफल व्यक्तियों से जोड़ते हैं, जो उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरित कर सकते हैं. रोल मॉडल ग्रामीण युवाओं की कौशल उन्नयन यात्रा को प्रेरित करने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
- अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित कौशल को पहचानने और प्रमाणित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए. इससे ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ सकती है और उन्हें रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है.

इन नीतिगत सिफारिशों को लागू करके, हम ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए एक सहायक वातावरण बना सकते हैं, जिससे वे अपनी क्षमता को उजागर कर सकें और ग्रामीण समुदायों की वृद्धि और विकास में योगदान कर सकें.

●●●

शेष पृष्ठ 79 का

प्रकटीकरण मानकों के लिए न्यास स्थापित करने वाली मूल कम्पनी की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह योजना परवान न चढ़ सकी.

राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट सेक्टर से प्राप्त होने वाले गुमनाम चंदे की व्यवस्था पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिए जाने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भारतीय चुनाव प्रणाली की अपारदर्शी व्यवस्था का अन्त हो गया प्रतीत होता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है. भारत में 2018 से पूर्व भी चुनाव होते थे और राजनीतिक दल कम्पनियों तथा व्यक्तियों से चंदा लेते थे, क्योंकि धीरे-धीरे चुनावी खर्च बढ़ता जा रहा है. चुनावों में प्रति उम्मीदवार ₹95 लाख/₹75 लाख (लोक सभा निर्वाचन) तथा विधान सभाओं में ₹40 लाख/₹28 लाख की सीमा व्यावहारिक रूप से अर्थहीन है. वास्तविक व्यय इससे कई गुना अधिक होता है. उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्चों में पार्टी द्वारा किए गए खर्चे शामिल नहीं होते हैं. लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव-प्रचार के लिए प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनों, रैलियाँ आयोजित करने, नेताओं के आने-जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करने आदि पर अनाप-शनाप खर्च करता है. इस खर्च की भरपायी चंदे से होती है. अब चाहे वह पारदर्शी स्रोत से आए या अपारदर्शी स्रोत (काला धन) से. समस्या गम्भीर है. राजनीतिक चंदे से सम्बद्ध कानूनों में शीघ्र सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिन पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए. ●●●

समाजशास्त्रीय लेख

भारतीय लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव

—गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'

वैश्वीकरण एक सीमाहीन दुनिया की परिकल्पना करता है, जो दुनिया को एक वैश्विक गाँव बनाता है. यह विभिन्न देशों के लोगों, कम्पनियों और सरकारों के बीच वार्ता एवं परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है. वैश्वीकरण के समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम देखे जाते हैं. वैश्वीकरण का प्रभाव समाज में तीव्र परिवर्तन और अनिश्चितता हेतु उत्तरदायी है. भारतीय समाज में मध्य वर्ग का उभार वैश्वीकरण का ही परिणाम है. यह न केवल लोक संस्कृतियों को सार्वभौमिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तनों हेतु भी उत्तरदायी है. वैश्वीकरण से लोक संस्कृतियों को अपने भौतिक क्षेत्र से परे अन्तरक्षेत्रीय सम्बन्ध बनाने और दुनिया भर में सर्वोत्तम सामग्री व माध्यम का चयन करने का अवसर मिला है. अब लोक संस्कृतियों के पास अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप बेहतर प्रथाओं को अपनाने के अवसर हैं. सूचना प्रौद्योगिकी ने विशाल संसाधनों से नए विचार, प्रतिस्पर्द्धी और मनोरंजन के उपकरण प्रदान किए हैं. वैश्वीकरण ने काम और शिक्षा के सम्बन्ध में समाजों की गतिशीलता को बढ़ाया है. लोगों के पास उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे पाठ्यक्रमों का चयन करने के अधिक अवसर हैं. इसने लोगों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और वरीयताओं के सम्बन्ध में उपलब्ध सभी विचारधाराओं के आधार पर एक समग्र विचारधारा तैयार करने और एक वैश्विक मनोविज्ञान बनाने का मौका दिया है. हालाँकि, अधिक उत्पादों व सामग्रियों की उपलब्धता ने समाज में उपभोक्तावाद की स्थायी प्रथा को जन्म दिया है. वैश्वीकरण से सामाजिक बंधन और सम्बन्ध भी कमजोर हुए हैं, जिससे छद्म सम्बन्धों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप समाज में आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति बढ़ी है, जबकि करुणा, सहनशीलता और सहानुभूति की मात्रा घटी है. पाश्चात्य मूल्यों एवं विचारों के अनुकूलन से स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं में विश्वास का ह्रास हुआ है. अपनी मौलिक प्रथाओं के बारे में भी हीन व पक्षपाती विचार प्रबल हुआ है. यह परिवार एवं विवाह जैसी बुनियादी सामाजिक संस्थाओं को भी नुकसान पहुँचा रहा है. वैश्वीकरण ने युवाओं को गेमिंग डिसऑर्डर और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी हानिकारक गतिविधियों की ओर धकेला है. वैश्वीकरण ने विचारधारा, लोक संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी के संयोजन से सांस्कृतिक प्रथाओं पर विनाशकारी प्रभाव डाला है.

लोक संस्कृति का परिचय—संस्कृति विभिन्न तत्वों का बोध कराने वाली जीवन की विविध प्रवृतियों से सम्बन्धित है. संस्कृति बहुअर्थी और विविध भावों की सामूहिक अभिव्यक्ति है. प्रायः मानव जीवन की बाह्य प्रवृत्तिमूलक प्रेरणाओं से विकसित व्यवस्था को सभ्यता, जबकि अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से निर्मित व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं. लोक का अभिप्राय व्यक्तिगत पहचान न होकर सामूहिक पहचान है, जबकि संस्कृति लोक जीवन की सामाजिक परम्परा से प्राप्त चिंतन, अनुभव और व्यावहारिक रीतियों की सामूहिक अभिव्यक्ति है. इस तरह लोक संस्कृति मानव के विविध क्रिया-कलापों, परम्पराओं, रीति-रिवाजों, विचारों, आस्था-विश्वासों, संस्कारों आदि की सामूहिक अभिव्यक्ति है.

संस्कृति का वैश्वीकरण—आर्थिक सम्बन्धों के आधुनिक साधनों के विकास और वैश्विक बाजार के विकास के साथ विश्व प्रणाली में राष्ट्रों का एकीकरण तेज हो रहा है. 'संस्कृति का वैश्वीकरण' पिछली सदी के विशेषता अस्सी के दशक के अन्त में राष्ट्रों के अभिसरण और लोगों के सांस्कृतिक सम्बन्धों के विस्तार के सम्बन्ध में सामने आया था. यह लोगों को एक-दूसरे के साथ अधिक संवाद करने और एक-दूसरे के बारे में जानने की जिज्ञासा में विस्तारित हुआ है. वैश्वीकरण सांस्कृतिक सम्पर्कों का विस्तार, राष्ट्रों के बीच दूरियों को पाटने के लिए संचार और ज्ञान, परिवहन और आर्थिक सम्बन्धों के आधुनिक साधनों के विकास के साथ वैश्विक प्रणाली में राष्ट्रों के एकीकरण को बढ़ा रहा है. इसके चलते लोगों और मानव प्रवास के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों का विस्तार हो रहा है. हालाँकि, इससे सांस्कृतिक पहचान के समक्ष संकट भी उत्पन्न हो गया है. युवा पीढ़ी एक-दूसरे के फैशन, प्राथमिकताओं और आदतों से सीखती है, जिससे वे एक जैसे (चेहराहीन) बन जाते हैं. आत्मसातीकरण अथवा चेहराहीन (अपने मूल अस्तित्व को भूल जाने) होने से सांस्कृतिक विशिष्टता के समक्ष पहचान का संकट बढ़ रहा है, क्योंकि इससे बड़े राष्ट्र की निम्न संस्कृति का अवशोषण और एक महान राष्ट्र की संस्कृति में सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक (जैसे—लोक संस्कृतियाँ) का विघटन हो रहा है, जबकि समकालीन समाज में सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सभ्यता की सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में मापा गया है.

वैश्विक समाज की अंतःनिर्भरता सामाजिक और आर्थिक आधार पर है. संस्कृति के वैश्वीकरण से तात्पर्य केवल स्थानीय संस्कृति को वैश्विक संस्कृति से जोड़ना मात्र नहीं है, अपितु स्थानीय संस्कृति की स्थानीयता को मूल रूप में बनाए रखते हुए इसे वैश्विक स्तर पर अपने मूल रूप में स्थापित करना भी है. वैश्वीकरण दुनिया के सभी देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है. इससे केवल अर्थव्यवस्था पर ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि विश्व स्तर पर राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं. पर्यटन, सोशल मीडिया, पारम्परिक मीडिया, समाचार मीडिया, आमने-सामने संचार, मनोरंजन और शिक्षा सहित कई कारक सांस्कृतिक वैश्वीकरण का कारण बन रहे हैं. भूमण्डलीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों का सीमा रहित आवागमन हुआ है, जिसके चलते मानवीय विवेक पर आधारित एक वैश्विक सभ्यता का निर्माण हुआ है, जिसमें विश्व स्तर पर समान मूल्यों का विकास हो रहा है, जो सांस्कृतिक विशिष्टता समय, स्थान और लोगों के समूहों तक सीमित थीं, वे इन सीमाओं को तोड़कर वैश्विकता की ओर बढ़ रही हैं. भारतीय लोक संस्कृतियों के विभिन्न पहलू हैं. ये बहुत ही पारम्परिक संस्कृतियाँ हैं, इनके प्रति हर किसी की अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय है. इसलिए भारतीय संस्कृति बहुत अनूठी है और इसमें विभिन्न प्रथाएं हैं. हालाँकि, वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में युवा वर्ग पारम्परिक पहलुओं पर विश्वास नहीं करते हैं, जिसके चलते समय के साथ लोक संस्कृतियाँ बदल रही या उनमें क्षरण हो रहा है. भारतीय लोक संस्कृतियाँ अविश्वसनीय रूप से जटिल और मनमौजी भी हैं.

लोक संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव—वैश्वीकरण ने मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को वैश्विक आयाम प्रदान किया है. आज भारत की कई सांस्कृतिक विरासतें वैश्विक पहचान हासिल कर चुकी हैं. उदाहरण के लिए, योग जो भारत की प्राचीन जीवन पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, आज पूरी दुनिया उसे 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' (21 जून) के रूप में मना रही है. हिन्दुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक कुम्भ मेला, जो कभी

भारत तक सीमित था, वह अब वैश्विक पहचान हासिल कर चुका है. इसी तरह रामायण का पारम्परिक प्रदर्शन वाला लोक नृत्य रामलीला, केरल के शास्त्रीय रंगमंच का अद्वितीय रूप कुटियाट्टम (संस्कृत थिएटर), वैदिक जाप की परम्परा, राजस्थान में सपेरा जाति का नृत्य व लोक गीत कालबेलिया, पश्चिम बंगाल और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय छऊ नृत्य, केरल के पारम्परिक अनुष्ठान थियेटर से सम्बद्ध लोक नृत्य मुदियेट्टू, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से सम्बद्ध लद्दाख का बौद्ध जप, पारम्परिक गायन और नृत्य से सम्बद्ध मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और ताँबे के बर्तन गुजरात का गरबा नृत्य विदेशों में अपनी अमिट छाप कायम कर चुके हैं. ये सभी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में भी शामिल हैं.

लोक संगीत किसी विशेष समुदाय की सांस्कृतिक या संगीत परम्पराओं में गहराई से निहित शैली है. वैश्वीकरण से विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच की सीमाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं. वैश्वीकरण ने संगीत को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बना दिया है. वैश्वीकरण ने विभिन्न संगीत शैलियों और परम्पराओं के संलयन को जन्म दिया है. इसने लोक संगीत की नई उप-शैलियों को भी जन्म दिया है जिनमें जैज़, रॉक और हिप-हॉप जैसी शैलियों के तत्व शामिल हैं.

वैश्वीकरण ने स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराया है. उदाहरण के लिए, कोरियाई शो 'स्क्विड गेम' ने नेटफ्लिक्स के माध्यम से वैश्विक सफलता प्राप्त की है. साहित्य की तरह फिल्में भी समाज और लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं. इनके माध्यम से स्थानीय समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति, परम्पराएं, लोक गीत और लोकनृत्य अभिव्यक्त करता है.

वैश्वीकरण के चलते आज छठ पूजा और दिवाली दुनिया के सुदूर देशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. इण्डोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन, थाइलैंड आदि देशों में दिवाली का त्योहार भारत की भाँति मनाया जाता है.

लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव—वैश्वीकरण के कारण लोक समाज आज बाजारवाद की चपेट में आ चुका है. आज का लोक समाज शहरों की तरफ बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है. अलगाववाद, परिवार में कलह और छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे विचार लोक समाज में रच बस चुके हैं. 'लोक संस्कृति' को लोग साधारणतया 'ग्रामीण संस्कृति' का पर्याय मान लेते हैं, जबकि यह उन सभी लोगों की संस्कृति है, जो किसी समुदाय का हिस्सा हैं, जिनकी कुछ परम्पराएं और मान्यताएं हैं. वर्तमान में पश्चिमी संस्कृति, उपभोक्तावाद और पॉपुलर संस्कृति ने बड़ी तेजी से अपने पाँव पसारे हैं, जिसके चलते लोक संस्कृतियाँ अपने मूल चरित्र-चित्रण को तेजी से खो रही हैं. वैश्वीकरण घरेलू संस्कृतियों, सामाजिक एकजुटता और स्थिरता को खतरे में डाल रहा है. भारतीय समाज में विवाह एक सामाजिक परम्परा है, जिसमें तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब तलाक का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. हमारी लोक संस्कृतियों में आर्थिक बचत करने की परम्परा रही है, लेकिन वैश्वीकरण भौतिकवादी जीवन को आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब मानता है. लोक संस्कृतियों के स्थापित मूल्य तेजी से पतित हो रहे हैं, जबकि मूल्य, व्यक्तियों, परिवारों, सामाजिक समूहों, पेशेवर संघों, उद्यमों, संस्थाओं, मीडिया, विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक संस्थानों और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के स्तर पर मानव आचरण को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

आज सांस्कृतिक सामग्रियों का व्यावसायिक उपयोग धारा प्रवाह हो गया है और व्यक्ति पर लोकप्रिय संस्कृति की छाप गहराती जा रही है. पश्चिमी संस्कृति धीरे-धीरे लोक संस्कृति को निगल रही है. भोगवादी प्रवृत्ति का शिकार होने वालों में नारी और युवा वर्ग तो हैं ही, लोक जीवन पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है.

मातृभाषा लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति है और वैश्वीकरण ने मातृभाषा की विविधता को सीमित किया है. जिस भाषा में इंसान सबसे पहले बोलना सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है. देश की भाषायी विविधता के कारण ही किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है और मातृभाषा के महत्व को समझते हुए कोठारी आयोग (1964–66) ने 'त्रि-भाषा सूत्र' दिया था. वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं थीं जिसके चलते देश में मातृभाषा पर यह कहावत खूब प्रचलित है कि यहाँ "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी", लेकिन वैश्वीकरण ने हमारी भाषायी विविधता को सीमित करने का काम किया है. वैश्वीकरण ने पहनावा-ओढ़ावा, खान-पान, साहित्य-सिनेमा के साथ-साथ भाषायी तौर पर भी लोगों को एकरूपता की तरफ जबरदस्ती अग्रसर किया है. वैश्वीकरण ने मातृभाषा के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी की हैं. आजकल मशीन की भाषा ही उद्योग जगत् को पसन्द है. ऑनलाइन युग में अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं का बोलबाला है. शोध, अनुसन्धान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन भाषाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जो मशीन और तकनीक के लिए अनुकूल हैं. नौकरी की भाषा भी मातृभाषा से शिफ्ट होकर अंग्रेजी हो चुकी है, जिसके चलते वर्ष 1961 में भारत में भाषाओं की कुल संख्या 1652 थीं, लेकिन 1971 में यह घटकर मात्र 808 रह गई. भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण 2013 की मानें तो पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं और 197 भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं. व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव, पारम्परिक बसावट में कमी और पूँजीवाद के दौर में रोजगार प्रारूप में परिवर्तन ने मातृभाषाओं को पतन की ओर अग्रसर किया है.

निष्कर्ष एवं सुझाव—वैश्वीकरण का वर्तमान दौर संस्कृतियों के टकराहट और संक्रमण का है. यह एक ओर क्षेत्रीय संस्कृतियों के समक्ष संकट पैदा कर रहा है. दूसरी ओर यह प्रत्येक संस्कृति के लिए खुला अवसर उपलब्ध कराता है कि वह विश्व पटल पर स्वयं को सिद्ध कर सके. वैश्वीकरण का यह प्रवाह एकतरफा नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृतियाँ, क्षेत्रीय से वैश्विक और वैश्विक से क्षेत्रीय दोनों दिशा में प्रवाह करती हैं अर्थात् कोई भी अवधारणा या सिद्धान्त अपना एक तरफा प्रभाव लेकर नहीं आता है. उसके मानव जीवन पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. हमारी लोक संस्कृतियों पर वैश्वीकरण का प्रभाव भी कुछ इसी तरह का है. वैश्वीकरण के प्रभावों में भिन्नता का एक सबसे बड़ा कारण इसको समझने और स्वीकार करने में असमानता भी है. भारतीय लोक संस्कृति पर वैश्वीकरण का मिला-जुला प्रभाव रहा है, कहीं इसने भारतीय समाज में प्रचलित स्त्रीवादी और जातिवादी जड़ता को तोड़ा है, तो कहीं पारिवारिक सम्बन्धों को विघटित किया है. संस्कृति के लिए वैश्विक द्वार खोलने का काम वैश्वीकरण ने ही किया है जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रीय संस्कृतियाँ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है.

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने जनजातियों के लोक जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है, जिसके चलते जनजातियों की पारम्परिक जीवन-शैली बहुत तेजी से बदल रही है. भारत की जनजातियों के सन्दर्भ में वैश्वीकरण उनकी विशिष्ट पहचान के लिए खतरा बनकर खड़ा है. हालाँकि, यह आशा की जाती है कि वैश्वीकरण पारम्परिक समाजों के साथ-साथ भारतीय जनजातियों की पारम्परिक संस्कृति, मान्यताओं और जीवन शैली को लाभ भी पहुँचा सकता है.

कुल मिलाकर, तमाम चुनौतियों के बावजूद वैश्वीकरण ने आधुनिक कला और लोक संस्कृति के विकास को एक सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदान की है. स्थानीय कलात्मक परिदृश्य

शेष पृष्ठ 133 पर

सागरीय कृषि लेख

समुद्री शैवाल : भविष्य का चिकित्सीय भोजन

शैवाल जड़, तना और पत्ती विहीन ऐसे थैलोफाइट हैं, जो इस पृथ्वी पर प्रकाश-संश्लेषण का बड़ा भाग सम्पन्न करते हैं अर्थात् इस पृथ्वी ग्रह में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदाता हैं. शैवालों को गुणों का अथाह सागर माना गया है. वैज्ञानिकों ने शैवालों को 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन माना है. उल्लेखनीय है कि समुद्री शैवाल की कृषि को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में कच्छ, गुजरात के कोटेश्वर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. इससे पूर्व फरवरी 2021 में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् द्वारा समुद्री शैवाल मिशन और एक 'सक्षम' ऐप लॉन्च किया गया था. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समुद्री उत्पादन में विविधता लाने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना था. यह मिशन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् (टीआईएफएसी) की पहल है जिसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया है.

उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में समुद्री शैवाल और सूक्ष्म शैवाल के कई उपयोग हैं. समुद्री शैवाल फाइबर, आयोडीन और विटामिन-के जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हजारों वर्षों से तटीय समुदायों के लिए भोजन, पशु चारा और उर्वरक का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं. कोम्बू और नोरी जैसे समुद्री शैवाल पूर्वी एशिया में एक अभिन्न और पारम्परिक खाद्य स्रोत हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन विश्व स्तर पर सबसे अधिक समुद्री शैवाल का उपभोग करते हैं. समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन 32 मिलियन टन से भी अधिक है इसका मूल्य लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर है कुल वैश्विक उत्पादन का 57 प्रतिशत हिस्सा अकेला चीन उत्पादित करता है वहीं 28 प्रतिशत हिस्सा इंडोनेशिया तथा तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, जबकि भारत वैश्विक समुद्री शैवाल का मात्र 0·01 से 0·02 प्रतिशत उत्पादन करता है. खाद्य समुद्री शैवाल और सूक्ष्म शैवाल अब दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, विशेष रूप से, यूरोप में जहाँ स्वास्थ्य लाभों में बढ़ती रुचि के कारण खाद्य समुद्री शैवाल उत्पादों की माँग बढ़ रही है.

समुद्री शैवाल के अर्क का उपयोग आमतौर पर आइसक्रीम और सलाद, ड्रेसिंग जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण में तथा गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है. लाल समुद्री शैवाल का उपयोग अगर जैसे जिलेटिन विकल्प के उत्पादन के लिए भी किया जाता है. जैसे-जैसे समुद्री शैवाल और सूक्ष्म शैवाल की वैश्विक माँग बढ़ रही है, यह महत्वपूर्ण है कि उनकी निरन्तर कटाई और खेती की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े. अच्छी प्रबंधन प्रथाओं के बिना, समुद्री शैवाल की खेती में पानी की गुणवत्ता में बदलाव और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान सहित कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एमएससी और एक्वाकल्चर स्टीवर्डशिप काउंसिल (एएससी) ने संयुक्त समुद्री शैवाल मानक बनाया, जो टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार समुद्री शैवाल उत्पादन को मान्यता देता है और सुधार के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क प्रदान करता है. समुद्री शैवाल और सूक्ष्म शैवाल के सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स, जलीय कृषि फीड और जैव प्लास्टिक्स सहित कई अन्य उपयोग हैं. सूक्ष्म शैवाल बड़ी मात्रा में तेल का भी उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है. उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में समुद्री शैवाल और सूक्ष्म शैवाल के कई उपयोग हैं. समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती, यह अपने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रारूपों के सरलतम रूप का प्रबंधन करता है.

अपने सबसे उन्नत रूप में इसमें शैवाल के जीवन चक्र को पूरी तरह से नियंत्रित करना शामिल है. तमिलनाडु और गुजरात तटों तथा लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास समुद्री शैवाल (सीवीड) प्रचुर मात्रा पाया जाता है.

एक अनुमान के अनुसार, यदि सीवीड की खेती भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के 10 मिलियन हेक्टेयर या 5 प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है, तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है.

एक नया समुद्री शैवाल (सीवीड) उद्योग स्थापित हो सकता है. यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ा योगदान कर सकता है, समुद्री उत्पादों में वृद्धि कर सकता है, शैवालों की जल क्षेत्रों में अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है, लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित कर सकता है, जैव ईंधन का 6·6 अरब टन उत्पादन कर सकता है. कई समुद्री शैवाल (सीवीड) में प्रति शोथ (एंटी-इंफ्लेमेटरी) और जीवाणु रोधी (एंटी-माइक्रोबियल) एजेंट विद्यमान होते हैं. उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हजारों वर्षों से विरासत में प्राप्त हुए हैं. कुछ समुद्री शैवाल (सीवीड) में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं अतः शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये अंततः लोगों में घातक ट्यूमर और ल्यूकेमिया के उपचार में प्रभावी साबित होंगे.

मुख्यतः आर्थिक विकास के लिए, समुद्री शैवाल की खेती करके जल कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है. समुद्री शैवाल (सीवीड) आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं. विनिर्माण में उनके कई उपयोगों में, टूथपेस्ट और फलों की जैली जैसे वाणिज्यिक सामानों में प्रभावी बाध्यकारी एजेंट (पायसीकारक) और कार्बनिक सौंदर्य प्रसाधन तथा त्वचा देखभाल उत्पादों में लोकप्रिय सॉफ्नर (इमोलियेंट्स) के रूप में उपयोग किया जाता है.

समुद्री शैवाल जैव संकेतक, भी होते हैं. जब कृषि, जलीय कृषि उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है, तो यह पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (अलगल ब्लूम) होता है. समुद्र शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को सन्तुलित करते हैं. समुद्री शैवाल आयरन सीक्वेस्टर के रूप में भी उपयोगी हैं. प्रकाश-संश्लेषण के लिए लौह खनिज पर निर्भरता बहुत अधिक है. जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है, तो समुद्री शैवाल (सीवीड) इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं. समुद्री शैवाल (सीवीड) द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है. समुद्री शैवाल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का पूर्तिकर्ता भी होते हैं. प्रकाश-संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं. ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं. ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं.

समुद्री शैवाल (सीवीड) पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है. ये जंगल मछली, घोंघे आदि के

लिए नर्सरी का कार्य करते हैं. सीवीड की अनेक प्रजातियाँ हैं, जैसे—ग्रेसिलिरिया एडुलिस, ग्रेसिलिरिया कैसा, ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा, सरगस्सुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि पाई जाती हैं.

पोषण के लिए, समुद्री शैवाल (सीवीड) विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं तथा कई सीवीड स्वादिष्ट भी होते हैं.

तमिलनाडु में समुद्री शैवाल (सीवीड) की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) हेतु स्थान चुना गया है. समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य शृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

जलवायु परिवर्तन निरन्तर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल के बीच मिश्रण कम हो रहा है जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो रही है. अतः सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं. लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की यह कमी, सूक्ष्म शैवाल प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं. सूक्ष्म शैवाल के उदाहरण—डायटम, डायनोफ्लैगलेट, क्लोरेला आदि हैं. सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्मजीव हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों जैसे—जल, चट्टानों और मृदा में पाए जाते हैं. वे स्थलीय पौधों की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषक दक्षता प्रस्तुत करते हैं और विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन के एक महत्वपूर्ण अंश के लिए जिम्मेदार हैं.

महासागर दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग तीन-चौथाई हिस्से को कवर करता है, जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन, आजीविका, वाणिज्य और सुरक्षा जैसे उभरते जटिल और परस्पर विकास के मुद्दों के लिए एक विशाल क्षेत्र प्रदान किया जाता है. ग्लोबल ओशन कमीशन के अनुमानों के अनुसार, समुद्री संसाधन दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 5 से 6 प्रतिशत योगदान करते हैं, 3 अरब लोगों की नौकरियों को सुरक्षित करते हैं और 350 लाख लोगों की आजीविका को बनाए रखते हैं.

विश्व बैंक के अनुसार, ब्लू इकॉनमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों का सतत् उपयोग को सन्दर्भित करती है. इसे अकसर 'समुद्री अर्थव्यवस्था', 'तटीय अर्थव्यवस्था' या 'महासागरीय अर्थव्यवस्था' के रूप में सन्दर्भित किया जाता है, यह अवधारणा अभी नवजात अवस्था में है और इसे अभी एक परिचालन परिप्रेक्ष्य से एक व्यापक परिभाषा में समझाया जाना बाकी है. मजबूत स्वास्थ्य के इस संकेतक का श्रेय आहार समुद्री शैवाल को दिया जाता है. कई समुद्री शैवालों में सूजनरोधी और रोगाणुरोधी एजेंट होते हैं. उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हजारों वर्षों से मौजूद हैं, प्राचीन रोमन लोग इनका उपयोग घाव, जलन और चकत्तों के इलाज के लिए करते थे. 'समुद्री शैवाल' समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है, जो समुद्र के साथ-साथ नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में उगते हैं. चूँकि उनके पास एक विशाल कोशिका है, यह आणविक जीवविज्ञानी के लिए लाभकारी है, जो सेलुलर प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वे इसे देख सकते हैं और नग्न आँखों से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं. इस कारण से एसिटाबुलरिया (एक कोशिकीय शैवाल) को एक आदर्श जीव माना जाता है. ये विभिन्न प्रवाल भित्तियों के साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरे का सामना कर रहे हैं. वे वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण महासागर अम्लीकरण के लिए अत्यधिक प्रवण हैं, क्योंकि जीनस एसिटाबुलरिया समूह के पौधों में समृद्ध कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिनके सूखने पर इनका वजन लगभग आधा हो जाता है अर्थात् कैल्शियम के अच्छे स्रोत भी होते हैं इनका उपयोग अम्लीय मृदा के उपचार में भी किया जा सकता है. शैवालों के प्रकाश संश्लेषक वर्णक पौधों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण हैं और उनकी कोशिकाएं पौधों एवं जानवरों के मध्य पाए जाने वाली विशेषताओं से भिन्न हैं. ऑक्सीजन उत्पादकों और लगभग सभी जलीय जीवन के लिए खाद्य आधार के रूप में उनकी पारिस्थितिक भूमिकाएं हैं.

वे कच्चे तेल एवं भोजन के स्रोत तथा मनुष्यों के लिए कई दवा और औद्योगिक उत्पादों हेतु आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं. अभी हाल ही में केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में समुद्री शैवाल की कृषि को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है. इस सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री शैवाल की खेती को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करना और समुद्री शैवाल की कृषि को बढ़ावा देने पर जोर देना है.

समुद्री शैवाल की खेती पर यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो समुद्री शैवाल उत्पादों के रोजगार सृजन का एक विकल्प है. कृत्रिम सिल्क बनाने में जापान में सारगासम तथा सोडे को मिलाकर एक गोंद जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिससे कृत्रिम सिल्क बनाई जाती है. साबुन उद्योगों में पोरफाइरा के समान लाल शैवाल यूरोप तथा जापान में साबुन बनाने के उपयोग में लाया जाता है. समुद्री किनारों समुद्री शैवालों को जलाकर राख प्राप्त की जाती है और उससे क्षार (अल्कलीज) बनाए जाते हैं. इन क्षारों से साबुन व फिटकरी बनती है. व्यापारिक वस्तुओं के निर्माण में कोन्दूस नामक लाल शैवाल व कैराजोनियम की विभिन्न प्रजातियों से एक श्लेष्मिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है. यह रंग, शैम्पू, टूथपेस्ट, चमड़े की सफाई, दुग्ध उद्योग, डबलरोटी उद्योग, जूतों की पॉलिस ब्रश तथा दूध की बँकलेट आदि बनाने में प्रयुक्त होता है, इसे कैरेगिनिन कहते हैं.

समुद्री शैवाल जैलिडियम, ग्रेसीलेरिया, जिगार्टिना, हिफनिया आदि लाल शैवालों से एक नाइट्रोजन रहित जैल के समान श्लेष्मिक पदार्थ मिलता है, जिसे एगर कहते हैं. जापान में संसार का 95 प्रतिशत 'एगर' (जैलीनुमा पदार्थ) का उत्पादन होता है. यह सूक्ष्म जीवों का संवर्धन माध्यम है. उसके अलावा इसे सौन्दर्य प्रसाधनों, फलों की बैली, खाद्य सामग्री, औषधियों में प्रयुक्त किया जाता है. आयोडीन उद्योगों में पूरी तरह से शैवालों का ही उपयोग किया जाता रहा है, जैसे—लैमिनेरिया डिजिटेटा, फ्यूकस बेसिक्खोसस तथा एसनिया इत्यादि से आयोडीन प्राप्त किया जाता है.

रबर उद्योगों में शैवालों का प्रयोग क्रीमिंग तथा स्टेबिलाइजिंग एजेन्ट के रूप में किया जाता है. यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबर बनाने के काम आते हैं. फ्यूकस, लैमिनेरिया की कोशिका भित्ति से एल्विन प्राप्त होता है, जिसे रबर उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है. आइसक्रीम उद्योगों में केल्प्स से प्राप्त हुआ कलिल जैल (कोलयडल जैल) एल्विन बहुत से उद्योगों में काम आता है. इसका सबसे प्रमुख उपयोग आइसक्रीम उद्योगों में है. आइसक्रीम जमाने से पहले उसमें थोड़ा एल्विन मिला दिया जाता है, जिससे वह बिल्कुल नर्म व चिकनी रहती है.

कार्बनिक पदार्थों में समुद्री खरपतवार जैसे—रौडमेनिया के शुष्क आसवन से ब्रोमीन प्राप्त की जाती है. इन्हीं से बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे—एसीटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसीटोन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं. पशु चारे के रूप में समुद्री शैवाल (मरीन सीवीड्स) को अनेक देशों में भूसे अथवा चारे की तरह पशुओं को खिलाया जाता है. समुद्री खरपतवार कहलाने वाले लमिनेरिया, फ्यूकस,

एस्कोफिल्लम, सारगासम) आदि को डेनमार्क, फ्रांस, चीन, स्कॉटलैण्ड, अमरीका आदि में पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं. ऐसा पाया गया है कि जिन मुर्गियों को एस्कोफिल्लम फ्यूकस खाद्य दिया गया, उनके अण्डों में आयोडीन, प्रचुर मात्रा में मिली. इसी प्रकार समुद्री शैवाल मिश्रित भोजन देने पर पशुओं के दूध में फैट अधिक पाया गया. पशु भोजन में माइक्रोसिस्टिस का सर्वाधिक प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें विटामिन 4 से 8 प्रतिशत प्रचुर मात्रा में होता है. शैवालों में मुख्यतया विटामिन ए, सी डी ई पाए जाते हैं. जापान में पेल्वेशिया को गायों को खिलाया जाता है. इस प्रकार यह देखा गया कि हरे शैवालों के अतिरिक्त भूरे व लाल शैवाल पशु भोजन के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हैं. भोजन के लिए लाल शैवाल बहुत अच्छा साधन है. पोरफाइरा परफोरेटय तथा पी. टेनेरा कैलिफोर्निया व चीन में खाए जाते हैं. इसी प्रकार कोडियम, अल्वा, एलेरिया, सारगासम) आदि समुद्री शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं.

पोरफाइरा में, तो प्रोटीन लगभग 50 प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट लगभग (50 प्रतिशत तथा अच्छी मात्रा में विटामिन ए, बी, सी तथा ई पाए जाते हैं. लेमिनेरिया सैकेरिना से कोम्बू व मोनोस्ट्रोमा से ऐनोरी भोज्य पदार्थ बनाया जाता है. एक नमकीन भोज्य पदार्थ, जिसे 'डल्स' कहते हैं रोडिमेनिया से बनाया जाता है. स्कॉटलैण्ड में इसे तम्बाकू की पत्तियों की तरह चबाया जाता है. चावल के खेतों में नील-हरित शैवालों का प्रयोग चावल की उपज को लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ा देता है.

भूरे व लाल शैवालों में पोटैशियम अधिक मात्रा में होता है व नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम मात्रा में. इस प्रकार यदि नील-हरित शैवालों का प्रयोग भूरे-लाल शैवालों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए, तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है. इनका प्रयोग ऊसर अथवा बंजर भूमि को आसानी के साथ उपजाऊ बना सकता है. दक्षिण कोरिया, में आलोसाइरा के द्वारा यह कार्य सफलतापूर्वक किया गया है. यह हरी-नीली शैवाल ऊसर भूमि को नाइट्रोजन स्थिरीकरण से उपजाऊ बना देती है. साइटोनीमा, नोस्टॉक, एनाबीना आदि क्षारीय नम भूमि में आसानी से उगते हैं तथा भूमि का पीएच कम करके क्षारीयता कम करते हैं. इससे भूमि उपजाऊ व खेती के योग्य बन जाती है. दक्षिण कोरिया में अम्लीय अनुपजाऊ भूमि को ओलोसाइरा फर्टिलिस्सिमा का उपयोग कर खेती योग्य बनाया जाता है. इसी प्रकार जिस भूमि में कैल्शियम की कमी होती है, उसमें लिथोफिल्लम व कारा मिलाया जाता है. थीवी के अनुसार, यदि भिण्डी की फसल की उपज बढ़ानी हो, तो मिट्टी में समुद्री शैवाल मिला देने चाहिए.

आज कई देशों के समान भारत में भी समुद्री शैवालों का मिश्रण बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है. इन समुद्री शैवाल से बने जैव उर्वरक कृषि उत्पादन क्षेत्र में वरदान साबित हो रहे हैं. भारत में लगभग 844 समुद्री शैवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं. 7500 किमी का विशाल तटीय क्षेत्र भारत में है. समुद्री शैवाल की खेती के अनेक लाभों के बावजूद भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समान व्यवसाय खेती उपयुक्त पैमाने पर नहीं की जाती है. समुद्री शैवाल की खेती के लिए गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक के तटवर्ती इलाके आदर्श स्थल के रूप में प्रस्तावित किए जा सकते हैं. भारत समुद्री शैवाल की बड़े पैमाने पर खेती के लिए बीज की आपूर्ति हेतु समुद्री शैवाल नर्सरी की स्थापना कर खाद्य समुद्री शैवाल के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की स्थापना कर सकता है तथा समुद्री शैवाल (सीवीड) क्लस्टर का विकास करके भारतीय समुद्री शैवाल क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है एवं लगभग 300 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन नए समुद्री शैवाल (सीवीड) उद्योगों की स्थापना करके कर सकता है, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होगी, शैवाल प्रस्फुटन को कम किया जाएगा एवं महासागरों को स्वस्थ रखकर लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकेगा. साथ ही, पर्यावरण हितैषी जैव ईंधन, जैव एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा.

भारत में 46 समुद्री शैवाल आधारित उद्योग होने के बावजूद विशेष रूप से अगर (जैली के प्रकार का विशिष्ट पदार्थ) के लिए 21 और एल्गिनेट उत्पादन के लिए 25 इनकी परिचालन दक्षता कच्चे माल की कमी से बाधित है. समुद्री शैवाल मिशन पहल का उद्देश्य मूल्य संवर्द्धन के लिए समुद्री शैवाल की खेती तथा उसका वाणिज्यीकरण करना ही है. इसका लक्ष्य भारत की 7,500 किमी लम्बी तटरेखा पर कृषि को विस्तारित करना है.

यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि समुद्री शैवाल उत्पादों का वाणिज्यीकरण प्रारम्भ हो चुका है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) ने 2 समुद्री शैवाल-आधारित न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों, कैडलमिन टीएम, इम्यूनलगिन अर्क (कैडलमिन टीएम/एमई) और कैडलमिन टीएम एंटीहाइपरकोलेस्ट्रोलेमिक अर्क (कैडलमिन टीएमआईएमई) का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया है. समुद्री शैवाल के उपयोग अनंत हैं समुद्र के समान अथाह हैं, जिसमें लैक्सेटिव, फार्मास्युटिकल कैप्सूल, घेंघा/थायराइड उपचार, कैंसर चिकित्सा, अस्थि प्रतिस्थापन एवं हृदय सम्बन्धी सर्जरी भी शामिल हैं.

उपाख्यानात्मक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन मिस्रवासियों ने इसका उपयोग स्तन कैंसर के उपचार हेतु भी किया था.

पर्यावरण-अनुकूल 'हरित' प्रौद्योगिकी से विकसित इन उत्पादों का उद्देश्य विषाणु रोधी (एंटी-वायरल) प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल अथवा डिस्लिपिडेमिया (कोलेस्ट्रॉल का असन्तुलन) की रोकथाम करना है. तमिलनाडु में स्थित बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क समुद्री, शैवाल के महत्व को उजागर करता है. ●●●

शेष पृष्ठ 85 का

- जैन तीर्थों में भी नासिक की गणना की गई है.
- रामायण की कथाओं से सम्बन्धित कई स्थल भी यहाँ विद्यमान हैं.

धारा

प्रमुख तथ्य

- वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित धारा अथवा धारा नगरी मालवा के सुप्रसिद्ध परमार शासक भोज की राजधानी थी. उसने अपनी राजधानी उज्जयिनी से हटाकर इसी नगर में स्थापित किया था.
- इस नगरी को भोज ने विविध प्रकार से अलंकृत करवाया.
- राजा भोज के समय में यह नगरी, विद्या और कला का प्रसिद्ध केन्द्र बन गई.
- भोज ने यहाँ सरस्वती का मंदिर तथा एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया था.
- ऐसी अनुश्रुति कि वह धारा में प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था.
- सरस्वती मंदिर के समीप भोज एक विजयस्तम्भ स्थापित किया तथा भोजपुर नामक नगर की स्थापना करवाई. कहा जाता है कि भोज की मृत्यु धारा, सरस्वती तथा विद्वान् सभी निराश्रित हो गए थे–

"अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती।
पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवं गते।।

- परमारों के बाद धारा पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया. ●●●

कृषि लेख

वायु प्रदूषकों का पौधों पर प्रभाव

—डॉ. आर. एस. सेंगर

"सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO) ओजोन (O_3) और प्रसुप्त कणिकीय तत्व वायु संदूषक हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति की हानि में सबसे अधिक योगदान है. वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव को दृश्य तथा अदृश्य दो प्रकार की क्षति में विभक्त किया जा सकता है. अन्दरूनी कोशिकीय क्षति के परिणामस्वरूप पत्तियों की सतह पर दाग व धब्बे होते हैं. इस प्रकार की क्षति कृषि उपज के मूल्य को घटा देती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आभास महत्वपूर्ण होता है. इसके कारण उपज घट जाती है, जबकि क्षतिपूर्ण पत्ती की सतह के अंश परजीवियों को पौधे में आगमन का रास्ता देते हैं. संदूषक से होने वाली अदृश्य क्षति, पौधे की जैव रासायनिक तथा कार्यिकीय प्रक्रम पर प्रभाव डालती है और प्रभावपूर्ण तरीके से वृद्धि तथा उपज में कमी लाती है तथा खाद्यान्न गुणवत्ता को परिवर्तित कर देती है. अधिक संदूषक स्तर का अल्पकालिक अनावरण प्रत्यक्ष क्षति का रूप है, जबकि दीर्घकालिक अनावरण या फिर सामान्य रूप से बढ़ा हुआ प्रदूषण अप्रत्यक्ष क्षति के स्वरूप है. प्रत्यक्ष क्षति खेतों में पहचानी जा सकती है, जबकि अप्रत्यक्ष क्षति उपज में कमी को फसल के अंत में ही जानी जा सकती है."

पौधों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. जीव कोशिकाओं की हानि या बदलाव संदूषित वायु के प्रभाव, वनस्पति पर प्रत्यक्ष प्रभाव का उदाहरण है. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और ऑक्साइडस ऑफ नाक्स (Nox) का संवेदनशील मिट्टी के अम्लीयकरण में योगदान है, जिसके साथ आधार धनायन का क्षय तथा क्षेत्रीय वनस्पति पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है. अमोनिया उत्सर्जन दीर्घकालीन सुपोषण, कुपोषण वाली मिट्टी में बढ़ावा देता है. इसी के साथ अतिरिक्त नाइट्रोजन का जमाव, अल्पकालीन तेज पैदावार को बढ़ावा भी देता है. वनस्पति को वायु के विभिन्न प्रदूषणों से प्रतिक्रिया के बारे में ज्ञान की कमी का होना एक हानिकारक संकेत है. वायु संदूषक विभिन्न स्रोतों तथा विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं, जैसे—उद्योगों, विद्युत् संयंत्रों, परिवहन, जैव-दहन आदि. वायु प्रदूषण का वनस्पति पर प्रभाव अग्रलिखित कारकों द्वारा पड़ता है—

- संदूषक स्रोत से दूरी
- संदूषक की अनावरण अवधि
- वायुमण्डलीय परिस्थितियाँ

ऐसे पेड़-पौधों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव अधिक पाया जाता है, जोकि शहरों, हवाई अड्डों, राजमार्गों, विद्युत् संयंत्रों, भट्टी एवं कारखानों के समीप पाए जाते हैं. ईंट, मिट्टी के बर्तन, रासायनिक उर्वरकों, सीमेंट, रंगलेप, रासायनिक पदार्थों, कागज की लुग्दी इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों के समीप पाए जाने वाली वनस्पतियों पर भी वायु संदूषकों का गहरा प्रभाव पड़ता है. इस क्रम में विभिन्न संदूषकों और फसलों पर पड़ने वाले इनके प्रभाव.

सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)

मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन है. अन्य स्रोतों में मुख्य रूप से कोयला (निचला दर्जा, अधिक सल्फर मात्रा) और ईंधन तेल (प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल) है. सामान्य तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत विद्युत् संयंत्रों में कोयले का दहन है. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) एक प्राथमिक संदूषक है, इसलिए इसकी सघनता सीधे तौर से क्षेत्रीय उत्सर्जन फैलाव व उत्सर्जन ऊँचाई से सम्बन्धित है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) की अधिक मात्रा औसतन शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित है. उद्योगों व विद्युत् संयंत्रों की ऊँची चिमनियाँ प्रभावी रूप से भूतल पर कम सांद्रता में उपयोगी है, भले ही इसके दीर्घकालिक लाभ अल्प हैं. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) की मात्रा वायुमण्डल में अधिक होती है.

नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOX)

नाइट्रस ऑक्साइड (NO) और नाइट्राइट (NO_2) का प्रभाव वनस्पति पर काफी अच्छे से जाना जाता है. NO_2 प्रमुख रूप से माध्यमिक प्रदूषक है, जोकि प्राथमिक प्रदूषक NO और O_3 (ओजोन) में होने वाली रासायनिक क्रिया के बाद उत्पन्न होता है. NO का NO_2 में शीघ्र रूपांतरण वायुमण्डल में NOX (दोनों पदार्थों का मिलान) के भार को बढ़ाता है जिसमें स्रोत की दूरी पर NO_2 अधिक होती है. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) की ही तरह यह संदूषक दहन क्रिया के बाद उत्पन्न होते हैं. SO_2 का उत्सर्जन सल्फर की अधिकता से बढ़ाता है, जबकि NO_2 का उत्सर्जन अन्य घटकों पर निर्भर करता है. NO का मुख्य स्रोत अधिक तापमान (>1400 डिग्री सेल्सियस) के साथ वायुमण्डलीय नाइट्रोजन (N) और ऑक्सीजन (O) की उपस्थिति में दहन क्रिया है. ईंधन में N का होना भी कुछ हद तक योगदान देता है. स्थिर स्रोतों (ताप तथा विद्युत् उत्पादन) और परिवहन में जीवाश्म ईंधन का दहन NO_2 के प्रमुख स्रोत हैं.

सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और O_3 की तुलना में उपचर्मीय प्रतिरोध NO_2 के लिए कम है जिसके कारण से पौधे की पत्तियों में NO का प्रमुख प्रवेश द्वार रन्ध्र है. NO का जैव रासायनिक प्रभाव काफी अलग है और यह अभी पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि इनमें से कौनसा ऑक्साइड अधिक विषेला है. NO की उच्च मात्रा पौधे की वृद्धि को कम करती है, जबकि कम मृदा नाइट्रोजन की स्थिति में थोड़ी मात्रा में NO पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है. हालाँकि पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है. NO_2 का अनावरण प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है. जैसे कि सूखे, विनाशकारी कीट और पाले के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता/पत्तियों पर हरित रोग के साथ ऊतकक्षयी चक्रत्ता उच्च NO_2 अनावरण के कारण हो सकती है, जो कि प्रत्यक्ष क्षति का एक असामान्य उदाहरण है. दीर्घकालीन NO अनावरण के कारण पौधे की वृद्धि में कमी आती है, जिसकी वजह प्रकाश-संश्लेषण का अवरोधन है. NO और अन्य संदूषकों का संयोजन सह-क्रियाशील प्रभाव दिखाता है, जिसका तात्पर्य संयोजन के बाद संदूषक वनस्पति पर अधिक प्रभाव डालना है. सह-क्रियाशीलता अधिकतर NO_2 और SO_2 में होती है, परन्तु NO_2 और O_2 में भी देखी गई है.

ओजोन (O_3)

दूसरे गैसीय संदूषकों से भिन्न, ओजोन प्राकृतिक तौर पर अधिक सांद्रण में ही अस्तित्व मे आती है. 20वीं सदी की शुरूआत में अब तक आधार ओजोन (O_3) तल सांद्रता निरन्तर 10 से 20 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) से बढ़कर 20 से 40 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) हो गई है. ओजोन (O_3) की सांद्रता दो अलग-अलग क्रियाओं के परिणामस्वरूप होती है—समताप मण्डल से क्षोभ मण्डल में O_3 का हस्तांतरण और प्रकाश रासायनिक क्रिया. प्रकाश-रासायनिक क्रिया में O_3, NO_2 का प्रकाश-अपघटन के साथ परमाणु और आणविक ऑक्सीजन का संयोजन और NO तथा O_3 के ह्रास के साथ NO_2 का बनना. वाष्पशील हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन प्राकृतिक रूप से जंगल की वनस्पतियों से होता है. शहरी क्षेत्रों में सड़क परिवहन इसका मुख्य स्रोत है. इसी के साथ पेंट और आसंजक में उपयोग होने वाला विलायक महत्वपूर्ण स्रोत है. सड़क परिवहन के उत्सर्जन में ईंधन के

वाष्प व बिना जले हुए उत्सर्जन के कण और अधूरे जले हुए हाइड्रोकार्बन के साथ गाड़ी के धुएँ का उपचयन उत्पाद होता है.

प्रसुप्त कणिकीय तत्व

प्रसुप्त कणिकीय तत्व ठोस तथा द्रव्य में विभाजित होता है जिसकी माप श्रेणी लगभग 0·1-2·5 माइक्रो मीटर व्यास होती है. यद्यपि संदूषक सघनता की माप के लिए सामान्य रूप कणों को मापने के लिए PM10 को प्रयोग में लाया जाता है जिसका तात्पर्य है, वायु में उपस्थित कण जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर कम है. इस श्रेणी में अधिकतर कुल कणिकीय तत्व आते हैं. प्रसुप्त कणिकीय तत्व को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—प्राथमिक कणिकीय तत्व जो प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित होता है, जैसे—गाड़ियों का धुआँ, तथापि माध्यमिक कणिकीय तत्व जो अन्य योगों के पारस्परिक क्रिया से बनते हैं, जैसे कि NO_2 के प्रकाशोपचयन से नाइट्रेट की उत्पत्ति. सामान्यतः अधिक मोटे कण (2·5·10 माइक्रोमीटर) प्राकृतिक तथा जैविक कणों से बनते हैं, जबकि सूक्ष्म भाग (<2·5 माइक्रोमीटर) मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें नाइट्रेट और सल्फेट शामिल हैं. प्रसुप्त कणिकीय तत्व एक नगरीय प्रदूषण परन्तु यह कण के आकार पर निर्भर करता है. प्रसुप्त कणिकीय तत्व के उत्सर्जन के स्रोत विकसित और विकासशील क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं, जैसे कि जंगल की आग, क्षेत्रीय उद्योग और कम विकसित आधारभूत संरचना उल्लेखनीय ढंग से कणीय बहुतायत पर योगदान देती है.

प्रसुप्त कणिकीय तत्व से अनेक प्रकार के प्रभाव वनस्पति जीव तत्व पर पड़ते हैं जो कि अधिकतर कण की रासायनिक संरचना पर आधारित होते हैं. भारी धातु तथा विषाक्त कण पौधों में पादप आविषालुता तथा उग्र निक्षेपण से होने वाली अपघर्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप क्षति पहुँचाते हैं. अधिक मात्रा में कणों का पत्तियों पर जमाव प्रकाश संचरण का हरित लवक तक पहुँचने में अवरोध पैदा करता है जिससे रन्ध्र में अधिधारण तथा गैसीय विनियम क्षमता में कमी आती है. इसके फलस्वरूप वनस्पति में पानी की कमी आती है और अन्य कार्यिकीय प्रक्रिया भी भंग होती है, जैसे कि कोपल का टूटना, परागण तथा प्रकाश के अवशोषण/परावर्तकता में परिवर्तन/कणिकीय अनावरण के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि रोगाणुओं से सक्रमण तथा दीर्घकालिक आनुवांशिकीय संरचना में फेर-बदल. कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि कणिकीय अनावरण से कुछ सकारात्मक परिणाम भी समाने आए हैं जिनके कारण वायुमण्डल से पोषक कण का ग्रहण करना तथा प्रयोग करना है.

फ्लोराइड (F)

फ्लोराइड युक्त पदार्थ वायु और कणिकीय संदूषक की तरह जाने जाते हैं, जोकि औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित होते हैं. एल्यूमीनियम स्मेलटर व फॉस्फोरस खान का कारखाना इसके प्रमुख उत्सर्जक होते हैं. यह कोयला दहन, स्टील निर्माण, ईट के भट्टों व काँच के कारखानों से भी निकलती है.

गैसीय और कणीय फ्लोराइड पत्तियों को सतह पर जमा होकर प्रत्यक्ष रूप से पुरानी या क्षीण उपचर्म को भेद लेती है. पत्तियों की सतह पर पानी में घुला हुआ फ्लोराइड विसरण के द्वारा उपचर्म में सोख लिया जाता है. रन्ध्र के द्वारा सोखी गई गैसीय फ्लोराइड एपोप्लास्ट में वाष्पोत्सर्जन बहाव से पत्तियों के सिरे और किनारों पर विषाक्त स्तर में एकत्र हो जाती है. पौधों की प्रजातियाँ फ्लोराइड के प्रति अलग-अलग संवेदनशीलता रखती है, जैसे कि तरुण शंकु वृक्ष फ्लोराइड से काफी प्रभावित हो जाते हैं, जबकि चाय और कपास फ्लोराइड संदूषण से प्रभाव शून्य रहती है. एल्यूमीनियम स्मेलटर के उत्सर्जन से कई प्रजातियों की पत्तियों के सिरे और किनारे हरित रोग और ऊतक-क्षयी चक्रता के रूप में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि फ्लोराइड, अमीनो अम्ल और प्रोटीन के प्रकाश-संश्लेषण चयापचयन और श्वसन में कमी लाता है. पत्तियों पर फ्लोराइड के जमाव के कारण चरने वाले पशुओं में फ्लोरोसिस पाया जाता है. ईंट के भट्टे, स्मेलटर, फॉस्फेट उर्वरक उद्योगों के निकट के चरागाहों में चरने वाले पशुओं में फ्लोरोसिस विकसित हो जाता है. इससे पेशी तथा हड्डी तन्त्र में नुकसान हो सकता है, जिसमें दाँत का मुलायम होना, चर्वण में परेशानी, लगड़ापन व चलने में तकलीफ होती है.

ओजोन गैस का प्रभाव

SO_2 और NO की तरह O_3 का पौधे के पोषक तत्व के रूप में कोई भूमिका न होने के कारण O_3 के द्वारा होने वाली विषाक्तता का विश्लेषण जटिल नहीं है. पौधे में पत्ती के उपचर्म द्वारा O_3 का स्थानांतरण नगण्य है, जबकि लगभग सम्पूर्ण O_3 रंध्र के द्वारा पत्तियों में उद्वहण होता है. उपरंध्र छिद्र में O_3 के प्रवेश के बाद कोशिका-भित्ति से सम्बन्धित जलीया मैट्रिक्स O_3 के साथ क्रिया करके प्लाज्मा झिल्ली के संवेदनशील संघटकों का उपचयन कर देता है. अल्पकालीन उच्च O_3 सांद्रणता का पत्तियों पर अनावरण प्रत्यक्ष क्षति के लक्षणों को दर्शाता है जिसके कारण संभवतः पत्तियों की क्षतिग्रस्त झिल्ली की पारगम्यता को सुधारने या पूर्ति करने में असमर्थता है. O_3 की बड़ी पत्तियों पर तीक्ष्ण क्षति के लक्षण हैं—हरित रोग, विरंजन, कांस्यन, धब्बे पड़ना, स्टिपलिंग, ऊतकक्षयी चक्रत्ता. दीर्घकालीन अनावरण में पत्तियों पर दृश्य प्रभाव पड़ना

सारणी-1 : मुख्य प्रदूषकों संदूषकों के स्रोत, क्षति और प्रभाव की श्रेणी का संक्षेप

संदूषक	मुख्य स्रोत	मुख्य क्षति	मुख्य प्रभाव की श्रेणी
SO_2	विद्युत् उत्पादन, उद्योग इकाई, घरेलू व व्यावसायिक, गर्म करने की पद्धति	प्रत्यक्ष पत्तियों की हानि, पौधों के विकास में बदलाव, शैवाल और ब्रायोफाइट्स का निर्मूलन, जंगलों का क्षरण.	स्थानीय
	विद्युत् उत्पादन, परिवहन	पौधों के विकास में बदलाव, माध्यमिक तनाव के प्रति परिष्कृत संवेदनशीलता सुपोषण.	स्थानीय
O_3	हाइड्रोकार्बन से बना माध्यमिक संदूषक	प्रत्यक्ष पत्तियों की हानि, पौधों के विकास में बदलाव, जंगलों का क्षरण.	स्थानीय
प्रसुप्त कणिकीय तत्व	परिवहन, विद्युत् उत्पादन, उद्योग, घरेलू ताप	पौधों के विकास में बदलाव, माध्यमिक तनाव के प्रति परिष्कृत संवेदनशीलता.	स्थानीय
फ्लोराइड	उत्पादन एवं स्मेल्टिंग उद्योग	पौधों के विकास में कमी, चरने वाले पशुओं में फ्लोरोसिस.	स्थानीय

जरूरी नहीं है, परन्तु कभी-कभी हरित रोग, अकाल पत्तियों का गिरना तथा विगलन के कारण यद्यपि दीर्घकालीन अनावरण से पौधों की वृद्धि में कमी के कारण उपज में क्षति भी हो सकती है 14 घण्टे के लिए 0·04 से 1 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) तक ओजोन का अनावरण संवेदनशीन पौधों में क्षति प्रदर्शित करता है. एक पौधे की विभिन्न प्रजातियाँ ओजोन के प्रति अतिसंवेदनशीलता में भिन्नता दर्शाती हैं, उदाहरणतः सेम, आलू, प्याज, पालक, तम्बाकू, मीठी मकई.

इथीलीन (C_2H_4)

वाहनों के द्वारा निकलने वाली विषाक्त गैसों में इथीलीन भी एक उत्पाद है, जोकि वायुमण्डल के लिए हानिकारक होती है. 24 घण्टे के लिए 0·001 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) पर यह गैस ऑर्किड फूलों के बाह्य को भूरा कर देती है एवं उन्हें मुरझा देती है. टमाटर और काली मिर्च के पौधों में 0·1 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) पर 6 घण्टे के लिए अनावरण अधेकुंचन का मूल कारण होता है. पौधों में क्षति की सीमा वायुमण्डलीय तापमान, पौधों की प्रजाति और इथीलीन की सांद्रता पर निर्भर करती है.

पारा की वाष्प (Hg)

अन्य संदूषकों की अपेक्षा मर्करी वाष्प का अनावरण पौधों में पत्तियों से अधिक पुष्पों के लिए संवेदनशील होता है. समान्यतः इस गैस के क्षति के लक्षण 24 घण्टे के भीतर प्रकट हो जाते हैं, जो 5 दिनों तक लगातार बढ़ते रहते हैं.

पौधों पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव

पत्तियों में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) रन्ध्रों के द्वारा प्रवेश करता है. इसी के साथ यह गीली परत पर महत्वपूर्ण दर से एकत्रित होता है. जहाँ पर यह सल्फाइड या बाईसल्फाइड को बनाने के लिए टूटता है और उपचर्म मोम के साथ क्रिया करता है. क्षतिग्रस्त उपचर्म के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) कुछ मात्रा में पत्तियों में प्रवेश कर जाती है. कणिकीय तरल पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता आंतरिक सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) मात्रा का विवेचनात्मक प्रभाव निर्धारित करता है. उच्च वर्गीय पौधों में अंतरकोशिकीय अम्लता और क्षारीयता अनुपात को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, जबकि शैवालों में नियंत्रण तन्त्र काफी साधारण होता है. सम्भवतः यही एक कारण है और सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के प्रभाव से शैवाल अधिक सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन क्षेत्रों में 'शैवाल मरुस्थल' बना देते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) से प्रत्यक्ष क्षति को पत्तियों के ऊतक हरित रोग के रूप में देखा जा सकता है जिसमें मरे हुए ऊतक रंग द्रव्य के खण्डित हो जाने के कारण सफेद हो जाते हैं. स्पष्ट तौर से प्रत्यक्ष क्षति न होने पर भी सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) वनस्पति के विकास और पैदावार में कमी लाता है. विशेष मृदा और जलवायु में खाद में बदलाव के साथ सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन में कमी कुछ देशों में सल्फर का अभाव लाया है. अप्रत्यक्ष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) रोगाणु और कीटों पर प्रभाव डालने के साथ फसलों की उपज में भी बदलाव लाते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता एवं अनावरण अवधि-इन दोनों की वृद्धि वनस्पति में क्षति की मात्रा की वृद्धि का कारण होता है. 4 घण्टे के लिए 0·5 अथवा 8 से 24 घण्टे के लिए 0·25 पार्ट्स/मिलियन (पीपीएम) पर इसका अनावरण संवेदनशील पौधों को क्षति पहुँचाता है. बसंत ऋतु के अंत और जेठ के आगमन के दौरान जब पौधों में पर्याप्त नमी, उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, प्रकाशमान सूर्य होता है तब पौधे सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.

ब्रोमीन (Br_2) और आयोडीन (I)

ये गैसें वनस्पतियों के लिए अत्यधिक विषाक्त होती है. तत्परता से हाइड्रोजन आयोडाइड एवं आयोडीन पौधों में अवशोषित और संचित हो जाती है और इसका प्रत्यक्ष क्षति लक्षण सल्फर डाइऑक्साइड के समान ही होता है. 18 घण्टे की अवधि के लिए 0·1 पार्ट्स/मिलियन पर पौधों में क्षति होती है.

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण पौधों में हरित रोग, विघलन और अधोकुंचन की समस्या होती है. एक सप्ताह के लिए 100 पार्ट्स/मिलियन से कम अनावरण पौधों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है.

हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)

हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का अनावरण पौधों में शिथिलता उत्पन्न करता है और लक्षण 48 घण्टों के बाद विकसित होते हैं. 40 पार्ट्स/मिलियन पर 4 घण्टे से नीचे इस गैस का अनावरण वनस्पतियों पर कोई भी हानि नहीं उत्पन्न करता है.

वायु प्रदूषण के कारण कृषि उत्पादकता में 10 से 15 प्रतिशत नुकसान होता है. वायु प्रदूषण में कमी लाने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु विकास के साथ वायु प्रदूषण जुड़ा हुआ है और इसे पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है. इस प्रकार शोधों में यह प्रयास किया जा रहा है कि फसलों की तनाव प्रतिरोधी किस्में बनाई जाए, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में लाभदायक पैदावार सम्भव हो सके. वर्तमान परिदृश्य में कृषि को वायु प्रदूषण का प्रभावी ढंग से सामना करना है. इसके लिए कई देशों में बचाव प्रक्रिया के क्षेत्र में शोध हो रहे हैं.

●●●

शेष पृष्ठ 82 का

बहरहाल इस अवसर पर केन्द्र सरकार ने हस्तांतरण के फॉर्मूले का भावना के स्तर पर उल्लंघन किया है. पिछले कुछ वर्षों में उन उपकरों और शुल्कों में बढ़ोतरी हुई है, जो राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले करों में नहीं आते. इससे केन्द्र के पास वे संसाधन बढ़े हैं जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता.

स्पष्ट है कि इससे केन्द्र और राज्यों के बीच आपसी विश्वास में कमी आएगी. यह ऐसा व्यवहार है जिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है. केन्द्र सरकार ने विकास योजनाओं पर होने वाले व्यय के लिए हस्तांतरण पर शर्तें लगाना भी आरम्भ कर दिया है.

देश के मौजूदा ढाँचे को देखें, तो केन्द्र सरकार स्वाभाविक तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की इस बुनियादी शिकायत को दूर नहीं कर सकती है कि गरीब और अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में उनसे ज्यादा कर वसूला जा रहा है. यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसे चतुराईपूर्वक हल करना होगा. अतीत में ऐसा किया जाता रहा है, परन्तु केन्द्र सरकार इस समस्या का पर्यवेक्षण करते हुए सावधानीपूर्वक कदम उठा सकती है.

केरल के सुझाव के मुताबिक केन्द्र सरकार को राज्य निवेश फंडों से ऋण लेने सम्बन्धी दिक्कतों की समीक्षा करनी चाहिए. उसे उपकरों और शुल्कों के जरिए राजस्व संग्रह भी कम करना चाहिए. विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राज्यों को हस्तांतरण में मनमानापन कम करने की भी पर्याप्त वजह है. इसमें से कुछ स्वचालित बनाया जा सकता है. इसके अलावा सरकारी व्यय प्रबंधन प्रणाली का डिजिटलीकरण किया जा सकता है.

अन्य प्रकार के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट और बिना भेदभाव की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए. एक तरीका यह भी है कि शर्तों से निपटने के लिए तकनीकी उपाय अपनाए जाएं, परन्तु राजकोषीय संघवाद पर जोर देने की व्यापक समस्या को केवल राजनीतिक ढंग से ही हल किया जा सकता है.

देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हैं. बड़ी नीतिगत चुनौती यह है कि उन राज्यों में राजकोषीय संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए, जो वृद्धि और राजस्व जुटाने में पीछे छूट गए हैं.

●●●

सार संग्रह

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति

1. सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परम्परा प्रारम्भ की गई थी ***–यूनानी शासकों द्वारा***
2. कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया ***–महायान***
3. सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं ? ***–जैन धर्म***
4. दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा ***–तुगलक वंश (1320 ई. से 1414 ई. तक)***
5. वह शिलालेख जिसमें सम्राट् अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है ***–मास्की शिलालेख***
6. कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मन्दिर तथा बैकुण्ठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ? ***–नंदीवर्मन द्वितीय ने***
7. महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलीफेंटा गुफाओं का निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ ? ***–राष्ट्रकूट***
8. सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था ***–महमूद गजनवी***
9. भारत के राष्ट्र चिह्न में प्रयुक्त शब्द 'सत्यमेव जयते' किस उपनिषद् से लिया गया है ? ***–मुण्डक उपनिषद् से***
10. वह वंश जिसे भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है– ***–गुप्त काल को***

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

11. भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था ***–आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण***
12. वह नेता जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ***–सरदार वल्लभ भाई पटेल को***
13. महात्मा गांधीजी ने किस आन्दोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया ? ***–अहमदाबाद आन्दोलन के दौरान***
14. वह वायसराय जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया ***–लॉर्ड रिपन***
15. ठगी प्रथा का उन्मूलन करने में किस गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी ? ***–लॉर्ड विलियम बैंटिंक***
16. बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी ***–19 जुलाई, 1905 को***
17. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था ? ***–अमृतसर अधिवेशन, 1919 में***
18. पूना पैक्ट सम्बन्धित था ***–दलित वर्ग से***
19. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी ***–सुभाष चन्द्र बोस द्वारा***
20. किस बात ने गाँधीजी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने पर बाध्य किया ? ***–चौरी-चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने***

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

21. भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था ? ***–द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919***
22. लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों की निर्योग्यता से सम्बन्धित प्रश्नों का निर्णयन किया जाता है ***–राष्ट्रपति द्वारा***
23. किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी ? ***–61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा***
24. नीति-निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है ***–सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर***
25. उपराष्ट्रपति पद हेतु कम-से-कम कितनी आयु आवश्यक है ? ***–35 वर्ष***
26. किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है ? ***–बंदी प्रत्यक्षीकरण***
27. भारत का राष्ट्रपति राज्य सभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है ? ***–12 सदस्य***
28. किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है ? ***–केशवानंद भारती वाद में***
29. प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है ? ***–गृह मंत्रालय के***
30. महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत् दिया गया है ? ***–73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा***

पर्यावरण एवं जैव विविधता

31. ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना, पृथ्वी का तापमान हो जाता है ***–18°C***
32. वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ***–वर्ष 1980 में***
33. मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है ***–कार्बन डाइऑक्साइड***
34. पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है ***–जीवमण्डल***
35. भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ***–22 मई को***
36. सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ***–उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में***
37. जैव विविधता निर्भर करती है ***–जलवायु, तापमान एवं आर्द्रता पर***
38. अल्फा विविधता है ***–किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या***
39. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का मुख्यालय स्थित है ***–नैरोबी (केन्या) में***
40. जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ? ***–नार्मन मायर्स***

भारत एवं विश्व का भूगोल

41. मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है ? **–आइसोहाइट**
42. 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है **–देहरादून में**
43. संयुक्त राज्य अमरीका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान 'होमस्टेक' किस राज्य में स्थित है ? **–दक्षिण डकोटा में**
44. सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौनसी दवा बनाई जाती है ? **–कुनैन**
45. पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है **–जीव भूगोल के अन्तर्गत**
46. सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है ? **–4 जुलाई**
47. भारत की सबसे लम्बी सुरंग 'पीर पंजाल सुरंग' किस राज्य में है ? **–जम्मू-कश्मीर में**
48. सर्वप्रथम 'इंडिया' शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया ? **–ग्रीक**
49. जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है ? **–राजस्थान में**
50. विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात किस देश में है ? **–वेनेजुएला (दक्षिण अफ्रीका) में**

भारतीय अर्थव्यवस्था

51. लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है **–मुद्रास्फीति**
52. भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था ? **–दादा भाई नोरोजी ने**
53. भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है ? **–कृषि**
54. भारत में प्रथम निश्चित पूँजी बैंक कौनसा है ? **–बैंक ऑफ हिन्दुस्तान**
55. सहकारी साख संगठन का शुभारम्भ कब हुआ ? **–1904 ई.**
56. वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है **–रेपो दर**
57. भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है ? **–केरल**
58. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है ? **–डॉ. मनमोहन सिंह**
59. अर्थशास्त्र में 'ग्रेशम नियम' का सम्बन्ध है **–मुद्रा के संचालन से**
60. कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है ? **–रिजर्व बैंक के पास**

सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी

61. भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी ? **–1972 ई. में**
62. परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ था ? **–सन् 1956 ई. में**
63. भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से जोड़ा गया था ? **–बैकानूर से**
64. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौनसा था ? **–रोहिणी-125**
65. भारत का प्रथम परमाणु बिजलीघर कहाँ प्रारम्भ हुआ ? **–तारापुर में**
66. भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है ? **–ट्रॉम्बे में**
67. आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है ? **–अबटु ग्रंथि की सूजन कम करने को**
68. मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है **–हिपेरिन की उपस्थिति**
69. हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है ? **–76 वर्ष**
70. 'गैसों का दाब' ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है ? **–मैनोमीटर**

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा

71. भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है **–दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व**
72. भारत के उत्तरी मैदानों में शीतऋतु में वर्षा होती है **–पश्चिमी विक्षोभों से**
73. कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है **–अक्षांश के कारण**
74. UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) की स्थापना कब हुई है ? **–21 मार्च, 1994**
75. ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी **–जोसेफ फोरियर ने**
76. वह देश जहाँ प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है **–बांग्लादेश में**
77. 'रेड डाटा बुक' अथवा 'रेड लिस्ट' से सम्बन्धित संगठन है **–आईयूसीएन**
78. वेटलैण्ड दिवस मनाया जाता है **–2 फरवरी को**
79. गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी **–वर्ष 2016 में**
80. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है **–नई दिल्ली में**

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

81. पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है ? **–11-15 वर्ष**
82. मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है **–मन तथा शरीर का विकास**
83. नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धान्त स्पष्ट किया है **–कोहलबर्ग ने**
84. किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, विकास एक सतत् और धीमी प्रक्रिया है ? **–स्किनर**
85. विकास में वृद्धि से तात्पर्य है **–आकार, सोच, समक्ष कौशलों में वृद्धि**
86. बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है **–शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना**
87. शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है **–बच्चे का सर्वांगीण विकास**
88. वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है **–3 वर्ष की आयु में**
89. स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है **–बाल्यावस्था को**

90. 'वातावरण वह बाहरी शक्ति है, जो हमें प्रभावित करती है. किसका कथन है ? *–रॉस का*

कृषि

91. भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौनसा है ? *–उत्तर प्रदेश*
92. किस राज्य को 'भारत का धान्य भण्डार' कहा जाता है ? *–पंजाब*
93. नीलगिरि के पहाड़ी क्षेत्रों में कौनसी फसल उगाई जाती है ? *–कॉफी*
94. भारत के किस राज्य में गेहूँ की खेती नहीं होती है ? *–तमिलनाडु*
95. भारत के लम्बे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है ? *–संयुक्त राज्य अमरीका*
96. शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौनसी है ? *–मूँगफली*
97. नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है ? *–उत्तर प्रदेश में*
98. किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखण्डन से होता है ? *–काली मिट्टी*
99. किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है ? *–जलोढ़ मिट्टी में*
100. विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौनसा है ? *–थाइलैण्ड*

कम्प्यूटर ज्ञान

101. इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें ..... कहा जाता है. *–डोमेन नाम प्रणाली*
102. एक ई-मेल, जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है, लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है *–स्पूफिंग*
103. IPV6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है *–128 बिट*
104. किस दृष्टि के अनुसार किसी पर्सनल कम्प्यूटर के कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है ? *–अभिधारण काल*
105. डिस्क पर भण्डारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहा जाता है ? *–न्यूनीकरण*
106. कम्प्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है ? *–एकीकृत आवेश*
107. कम्प्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं ? *–सिलिकॉन*
108. किसी डिस्पले डिवाइस पर विजुअल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौनसा कम्प्यूटर भाग जिम्मेदार है ? *–GPU*
109. वह कम्प्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को प्रोसेस करता है *–हाइब्रिड कम्प्यूटर*
110. एक कम्प्यूटर में दो प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? *–पैरेलल प्रोसेसिंग*

खेलकूद

111. सुल्तान अजलान शाह कप सम्बन्धित है *–हॉकी से*
112. ओलम्पिक चिह्न का अर्थ है *–निरन्तरता*
113. विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है ? *–2 जुलाई*
114. भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारम्भ किया ? *–तुर्क*
115. अर्जुन पुरस्कार प्रारम्भ हुआ *–1961 ई. में*
116. शतरंज का जन्मदाता देश कहा जाता है *–भारत*
117. 'गुगली' किस खेल से सम्बन्धित शब्द है ? *–क्रिकेट*
118. 'द्रोणाचार्य पुरस्कार' की शुरूआत किस वर्ष हुई ? *–1985 ई.*
119. भारत में फेडरेशन कप किस खेल से सम्बन्धित है ? *–फुटबाल*
120. भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौनसा है ? *–इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (दिल्ली)*

विविध

121. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे *–मदन मोहन मालवीय*
122. वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है *–मुहम्मद गौरी*
123. भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है *–आन्ध्र प्रदेश*
124. शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है *–चैत्र*
125. विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौनसा है ? *–टोक्यो*
126. किस कम्पनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारम्भ की ? *–ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे*
127. ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था ? *–उस्ताद ईसा*
128. कौनसे देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है ? *–चीन*
129. अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है ? *–स्विट्जरलैण्ड*
130. शरीर में सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि कौनसी होती है ? *–थॉयराइड*

●●●

नवीनतम आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

बीपीएससी की सिविल सर्विसेज, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसआई, कौंस्टेबिल एवं बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अप-टू-डेट पुस्तक

उपकार बिहार सामान्य ज्ञान

Code 109
₹ 150.00

बिहार जातिगत जनगणना (2023)

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 तथा बजट 2023-24
- बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं 2022-23
- टॉपिकवाइज परीक्षोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न
- समसामयिक तथ्य 2022-23

डॉ. बी. एल. शर्मा एवं संजय सुमन

उपकार प्रकाशन, आगरा-5

• E-mail : care@upkar.in
• Website : www.upkar.in

सामान्य अध्ययन

(द्वितीय प्रश्न-पत्र)

खण्ड I

प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए–

(a) भारतीय संविधान से सम्बन्धित मूल ढाँचे के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–भारतीय संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अन्दर ही संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को शंकरी प्रसाद *बनाम* भारत संघ मामले के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. विभिन्न न्यायिक निर्णयों की शृंखला (शंकरी प्रसाद मामला, सज्जन सिंह मामला, गोलकनाथ *बनाम* पंजाब राज्य मामला) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती *बनाम* केरल राज्य मामले (1973) में अपने विस्तृत निर्वचन के माध्यम से संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया.

माननीय न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे को परिभाषित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने में सक्षम है, परन्तु वह आधारिक ढाँचे (मूल ढाँचे) में न तो संशोधन कर सकती है न ही उसे न्यून या संक्षिप्त कर सकती है. माननीय न्यायालय के अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान उसकी आधारशिला है जिस पर हमारी संविधान की विशाल इमारत खड़ी है. उसमें संशोधन या छेड़छाड़ करने से संविधान की इमारत ताश के पत्तों की भाँति बिखर सकती है.

उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय ने आधारभूत ढाँचे की सीमाओं को परिभाषित नहीं किया है यद्यपि विभिन्न न्यायिक निर्णयन में अपने निर्वचन के माध्यम से कुछ सिद्धान्तों यथा लोकतन्त्र, गणराज्य, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन, संघीय व्यवस्था इत्यादि को आधारभूत ढाँचे का भाग घोषित किया है. यह सिद्धान्त मनमाने संशोधनों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जो इन मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन कर सकते हैं.

आलोचकों का तर्क है कि यह न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है, जो संविधान को आकार देने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के लोकतान्त्रिक सिद्धान्त को चुनौती देता है. उनका यह भी तर्क है कि 'आधारिक संरचना' व्यक्तिपरक है और न्यायिक विवेकाधीन है, जिससे इसके सम्भावित दुरुप्रयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं.

वर्तमान समय तक इस सिद्धान्त के प्रभाव के आलोक में यह कहा जा सकता है कि आधारभूत ढाँचे के सिद्धान्त ने संसदीय संशोधन की शक्ति के बावजूद भारतीय संविधान के सारतत्व/आत्मतत्व को संरक्षित करने, स्थिरता सुनिश्चित करने एवं मौलिक मूल्यों को बनाए रखने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह संवैधानिक लचीलेपन और आवश्यक सिद्धान्तों के बीच नाजुक सन्तुलन को दर्शाते हुए, **चल रही विद्वानों और न्यायिक बहस का विषय बना हुआ है.**

(b) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) हेतु आरक्षण तर्कसंगत है ? टिप्पणी कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–भारतीय संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने एवं उन्हें मुख्यधारा में विलीन करने हेतु राज्य को उपबन्ध करने में समर्थ किया गया है. केन्द्रीय विधायिका ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक (10% कोटा विधेयक) पारित किया है, जिसने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ग्रहण किया है.

आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित है, यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है. इनके अनुसार केवल आर्थिक मानदण्डों पर आधारित आरक्षण कुछ हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव/क्षति को प्रभावी ढंग से लक्षित नहीं कर सकता है. वे तन्त्र के सम्भावित दुरुप्रयोग और वास्तविक रूप में जरूरतमन्द लोगों के उत्थान के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को विधिमान्य ठहराते हुए यह अधिकथित किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा समानता और संविधान की मूल संरचना तथा मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त आरक्षण, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है. आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज में शामिल करने के लिए बल्कि वंचित वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है. न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य को विधिसम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति है.

समर्थकों का तर्क है कि यह वित्तीय चुनौतियों का सामना करने वालों को अवसर प्रदान करके सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को सम्बोधित करता है. इसके अतिरिक्त यह समावेशिता सुनिश्चित करता है तथा विशेषाधिकार प्राप्त एवं वंचित समुदायों के बीच अन्तर को पाटता है. इनका मानना है कि आर्थिक स्थिति भी शिक्षा और रोजगार तक पहुँच में बाधा बन सकती है. इसके साथ-साथ यह आरक्षण से जुड़े कलंक को धीरे-धीरे दूर करने मे सहायक होगा, क्योंकि आरक्षण ऐतिहासिक रूप से जाति से सम्बन्धित रहा है और अक्सर ऊँची जाति आरक्षण के माध्यम से आने वालों को हेय दृष्टि से देखती है.

पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त भी ऐसे कई लोग या वर्ग हैं, जो भूख और गरीबी से त्रस्त परिस्थितियों में जी रहे हैं. संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण की संवैधानिक मान्यता दी गई है.

(c) भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–संविधान को एक गतिशील एवं जीवन्त दस्तावेज माना जाता है. हमारे संविधान निर्माताओं ने परिवर्तित होती परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को समायोजित करने के लिए इसमें संशोधन करने का अधिकार केन्द्रीय विधायिका (संसद) को प्रदान किया है. भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान के संशोधन करने से सम्बन्धित उपबन्ध किए गए हैं.

भारतीय संविधान में संशोधन की मुख्यतः दो प्रक्रिया वर्णित हैं–

संविधान के कुछ उपबन्धों में संसद द्वारा साधारण बहुमत (50% +1) से संशोधन किया जा सकता है, जैसे–नए राज्यों का गठन एवं उनके नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन.

संविधान के कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो तिहाई), जैसे–मौलिक अधिकार तथा नीति-निदेशक तत्वों में संशोधन.

इसके अतिरिक्त यदि विषय संघीय विषयों से सम्बन्धित है अर्थात् उसमें राज्य के हित निहित है, तो उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, जैसे–संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण.

गौरतलब है कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर केशवानन्द भारती *बनाम* केरल राज्य (1973) मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर मर्यादाएं आरोपित की गई है. इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी पाठ में संशोधन करने के लिए अधिकृत है, परन्तु वह आधारभूत ढाँचे में संशोधन उसको न्यून या संक्षिप्त नहीं कर सकती है.

आलोचनात्मक विश्लेषण—संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त राज्य अमरीका जैसी संवैधानिक अभिसमय या संवैधानिक सभा जैसी किसी विशेष संस्था का कोई प्रावधान नहीं है.

संविधान में संशोधन करने के लिए केवल केन्द्रीय विधायिका अर्थात् संसद को अधिकृत किया गया है. राज्य विधायिकाएं संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव शुरू नहीं कर सकती हैं (सिवाय विधानपरिषद् के सृजन एवं समाप्ति के मामले को छोड़कर).

संविधान के प्रमुख भाग को संसद द्वारा अकेले विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है. केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधानमण्डलों की सहमति की आवश्यकता होती है वह भी आधे राज्यों के अनुसमर्थन की.

संशोधन की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया के समान है. विशेष बहुमत को छोड़कर, संवैधानिक संशोधन विधेयकों को सामान्य विधेयकों की तरह ही संसद द्वारा पारित किया जाना है.

किसी भी देश का संविधान उसकी ऐतिहासिक अनुभव, तात्कालिक तथा सम्भावित परिस्थितियों का उत्पाद या परिणाम होता है. हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संशोधन प्रक्रिया के सन्दर्भ में हमारे संविधान को कठोर तथा नम्य के अद्भुत सन्तुलन के रूप में परिणत किया है. यह प्रक्रिया न तो इतनी लचीली है कि सत्तारूढ़ दलों को अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बदलाव करने की अनुमति दे सके और न ही यह इतनी कठोर है कि बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने में असमर्थ हो.

(d) बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य-योजना प्रस्तुत करती है. (7 अंक)

उत्तर—प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है, जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है. एक संविधान में प्रस्तावना इसके निर्माताओं के विचारों, उनके उद्देश्यों, उनके ऐतिहासिक अनुभव और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धान्तों को प्रस्तुत करता है. प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का वर्णन है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है.

प्रस्तावना हमारे राजनीतिक पूर्वजों/स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा राष्ट्र निर्माण के सन्दर्भ में देखे गए स्वर्णिम स्वप्न यथाविधि का शासन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, पदसोपानिक व्यवस्था का उन्मूलन एवं समतामूलक समाज की स्थापना, व्यक्ति का पूर्ण विकास एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समाज में समरसता एवं बन्धुत्व की भावना तथा राष्ट्र की अखण्डता को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित उद्देश्यों को पूर्ति हेतु कार्य-योजना प्रस्तुत करती है.

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति, लोकतान्त्रिक व्यवस्था की बहाली तथा शक्ति के स्रोत को जनता में निहित कर प्रस्तावना का शुभारम्भ 'हम भारत के लोग' शब्द से करके राज्य की प्रकृति को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के रूप में परिणत किया गया है. समता मूलक समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से इसमें तीन प्रकार के न्याय अर्थात् सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख है.

व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में आदर्श परिस्थितियों के सृजन हेतु पाँच प्रकार की स्वतन्त्रता यथा— विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का वर्णन किया गया है. राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने, अनेकता में एकता को चरितार्थ करने हेतु विविधता को समायोजित करते हुए आपसी भाईचारे एवं बंधुता की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है.

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के स्वप्निल भारत के निर्माण से सम्बन्धित विचारों को उद्घाटित करती है तथा इसकी पूर्ति हेतु कार्य-योजना भी प्रस्तुत करती है.

(e) जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए? (7 अंक)

उत्तर—बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण, 2023 के निष्कर्ष जारी किए. इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या अब 13·07 करोड़ से कुछ अधिक है, जो 2011 की जनगणना में लगभग 10 करोड़ थी. बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया है कि बिहार की आबादी में 'पिछड़े समुदाय' की हिस्सेदारी लगभग 63% है. जिसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36·01% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वर्ग है. इसके अतिरिक्त 27·13% अन्य पिछड़ा वर्ग, 19·65% अनुसूचित जाति, 1·68% अनुसूचित जनजाति, 14% यादव, 3% मुसहर और 3·65% ब्राह्मण है. इन निष्कर्षों का राज्य एवं राष्ट्रीय चुनावों तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान में व्यापक निहितार्थ है.

जाति लम्बे समय से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, जो मतदान पैटर्न, नीतिगत निर्णय और सामाजिक गतिशीलता को आकार देती है. बिहार में जाति जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने से जनसंख्या की सामाजिक संरचना की अधिक सटीक और विस्तृत समझ प्राप्त हुई है, जिससे राजनीतिक रणनीतियों एवं गठबन्धनों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है.

जाति जनगणना से प्राप्त निष्कर्ष (डेटा) लक्षित नीतियों एवं विकास पहलों को तैयार करने, विभिन्न समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चिन्ताओं को सम्बोधित करने में सहायक हो सकता है. राजनेता इन सूचनाओं का प्रयोग अपने चुनावी वादों को पूरा करने, विशिष्ट जाति समूहों से अपील करने और विविध सामाजिक ताने-बाने के अनुरूप गठबन्धन बनाने के लिए कर सकते हैं.

जाति जनगणना से राजनीति गठबन्धनों का पुनर्गठन हो सकता है. पार्टियाँ जाति जनसांख्यिकी की नई समझ के आधार पर स्वयं को पुनः संगठित कर सकती है, ऐसे गठबन्धनों का निर्माण कर सकती है, जो विशेष जाति समूहों के साझा हितों और आकांक्षाओं को पूरा करते हों. इसके परिणामस्वरूप सत्ता की गतिशीलता में बदलाव हो सकता है और उन पारम्परिक वोटिंग ब्लॉकों पर प्रभाव पड़ सकता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से बिहार की राजनीति को प्रभावित किया है.

जाति जनगणना विभिन्न स्तर पर व्याप्त असमानताओं को उजागर करती है, जो राजनीतिक नेताओं को सामाजिक न्याय और समावेशिता से सम्बन्धित मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए प्रेरित करेगी. हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच समर्थन और वैधता हासिल करने का प्रयास करते हुए, पार्टियाँ कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों के मुद्दों की वकालत करने की होड़ कर सकती हैं.

जाति जनगणना के निष्कर्षों के सम्बन्ध में प्रमुख चिन्ता यह है कि इससे जातिगत पहचान दृढ़ हो सकती है तथा इससे राजनीतिक पक्षपात, जाति आधारित राजनीति की बाढ़ आ सकती है. इन चिन्ताओं के बावजूद इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के विभिन्न समूहों की आबादी पर सटीक डेटा आवश्यक है. जाति जनगणना सकारात्मक कार्यवाही नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी सहायता कर सकती है.

प्रश्न 2. (a) भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत सम्बन्ध पर चर्चा कीजिए. वर्तमान

सन्दर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए. (38 अंक)

उत्तर—भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का सृजन करता है तथा अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका शक्ति को निहित करता है. परन्तु भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो वेस्टमिस्टर मॉडल पर आधारित है. इस मॉडल के अन्तर्गत जहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तथा औपचारिक कार्यपालक प्रमुख होते हैं वही प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं.

राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74(1) तथा अनुच्छेद 75(3) पर दृष्टिपात करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है. अनुच्छेद 53 जहाँ राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति को निहित करता है, वहीं अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता तथा परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी (जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे) और राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा. वहीं अनुच्छेद 75(3) यह कहता है कि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी.

उपर्युक्त अनुच्छेदों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संघ के क्रिया-कलाप के विषय में निर्णय लेने की सर्वोच्च व अन्तिम शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित की गई है, क्योंकि लोक सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद् को बनाया गया है न कि राष्ट्रपति को. यू.एन. राव *बनाम* इन्दिरा गांधी मामले में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मंत्रिपरिषद् का विधायिका तथा कार्यपालिका पर वास्तविक नियन्त्रण होता है.

प्रधानमंत्री चूँकि मंत्रिपरिषद् का प्रधान होता है अतः वह वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है. राष्ट्रपति प्रायः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है. राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री के कहने पर किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता है. इस प्रकार प्रधानमंत्री का पूरे मंत्रिपरिषद् पर नियन्त्रण होता है.

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य सेतु का कार्य करता है. संविधान के अनुच्छेद 78(ख) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वह मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें तथा अन्य सूचना जो राष्ट्रपति माँगे वह उन्हें प्रदान करें.

बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति की भूमिका में भी परिवर्तन आया है. पूर्व में जहाँ गठबन्धन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति के पास विकल्प व विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग की सम्भावना अधिक होती थी, वहीं पूर्ण बहुमत की सरकार के दौर में तथा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के कारण (श्रीमती इन्दिरा गांधी, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में) इस स्थिति में परिवर्तन आया है.

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका को बढ़े हुए कार्यकारी अधिकार द्वारा चिह्नित किया जा सकता है, जैसाकि सक्रिय नीति पहल, राजनयिक व्यस्तताओं और संकट प्रबन्धन जैसे आयामों में देखा जा सकता है. प्रधानमंत्री का पद निर्णायक नेतृत्व का केन्द्र बिन्दु बन गया है, जो राष्ट्र के स्वप्न को आकार दे रहा है.

अथवा

(b) "भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक-साथ प्रयासों में निहित है—राज्य-आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता." उपर्युक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. (38 अंक)

उत्तर—संघवाद का भारतीय मॉडल राष्ट्र के ताने-बाने में जटिल रूप से बुना गया है, जो एक एकीकृत राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपने राज्यों की विविधता को सन्तुलित करता है. अपने मूल में, भारतीय संघवाद राज्य—आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने और एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के एक अद्वितीय समामेलन को दर्शाता है.

भारतीय संघवाद का एक प्रमुख पहलू राष्ट्र के ढाँचे के भीतर सांस्कृतिक विविधताओं को पहचानने और संरक्षित करने पर जोर देता है. भाषाओं, धर्मों और परम्पराओं की विशाल और विविध टेपेस्ट्री के साथ, भारत की संघीय संरचना विकेन्द्रीकरण के महत्व को स्वीकार करती है. भारत में राज्यों को विशेष रूप से भाषा, शिक्षा और संस्कृति से सम्बन्धित मामलों में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है. विविधता की यह मान्यता संविधान में निहित है, जो सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत विषयों के वितरण के माध्यम से राज्यों को शक्तियाँ प्रदान करती हैं.

इसके साथ ही संविधान की एकता और अखण्डता प्रावधानों में एक बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है. उदाहरण के लिए राष्ट्रपति शासन केन्द्र सरकार को कानून और व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करने और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने के लिए कुछ परिस्थितियों में राज्य पर नियन्त्रण सम्भालने की अनुमति देता है. यह तन्त्र व्यापक भारतीय राजनीति के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, भले ही इसमें शामिल राज्यों के मामलों में अस्थायी हस्तक्षेप शामिल हो.

हालाँकि संघवाद के भारतीय मॉडल को चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. राज्यों के पुनर्गठन, अधिक स्वायत्तता की माँग और संसाधनों पर विवाद जैसे मुद्दे सांस्कृतिक विविधता को पहचानने और एक मजबूत राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के बीच तनाव को उजागर करते हैं. इन दोनों लक्ष्यों के बीच एक नाजुक सन्तुलन बनाना एक सतत् चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए निरन्तर संवाद और अनुकूलन की आवश्यकता होती है.

निष्कर्षतः भारतीय संघवाद की प्रकृति जटिल है, जो राज्य—आधारित सांस्कृतिक विविधताओं का जश्न मनाने और एक एकजुट भारतीय राजनीतिक समुदाय को बनाए रखने के बीच एक नाजुक सन्तुलन का प्रतीक है. इस मॉडल की सफलता भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद की समृद्ध टेपेस्ट्री को दबाए बिना एकता को बढ़ावा देने, इन दोहरी गतिविधियों को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करती है.

प्रश्न 3. (a) बिहार में गठबन्धन की राजनीति के मूल सिद्धान्तों को, विशेषतः राष्ट्रीयहितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से, विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए. (38 अंक)

उत्तर—गठबन्धन राजनीति का तात्पर्य सामूहिक रूप से शासन करने के लिए राजनीतिक दलों के मध्य गठबन्धन या साझेदारी के गठन से है. राज्यों के सन्दर्भ में इस दृष्टिकोण को प्रायः विविध हितों को समायोजित करने और स्थिर शासन सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है. गठबन्धन राजनीति के मूल सिद्धान्त संवाद, समझौता और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के इर्द-गिर्द घूमते हैं.

भारत के कई विविध राज्यों की तरह बिहार में गठबन्धन की राजनीति क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से आकार लेती है. बिहार में गठबन्धन की राजनीति के मूल सिद्धान्तों को समझने के लिए ऐतिहासिक सन्दर्भ, सामाजिक गतिशीलता और इस ढाँचे के भीतर राष्ट्रीय हितों की खोज की आवश्यकता है.

ऐतिहासिक रूप से, बिहार राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, जहाँ कई गठबन्धन सरकारें देखी गई हैं. राज्य का विविध सामाजिक—आर्थिक परिदृश्य, ग्रामीण कृषि समुदायों और शहरी केन्द्रों के मिश्रण के साथ, प्रायः एक खण्डित राजनीतिक परिदृश्य की ओर ले जाता है. जाति कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विभिन्न दल समर्थन हासिल करने के लिए स्वयं को जाति के आधार पर जोड़ते

हैं. इसलिए, बिहार में गठबन्धन की राजनीति स्वाभाविक रूप से जटिल जाति समीकरणों का प्रतिबिम्ब है, जो राज्य के राजनीतिक ताने-बाने पर हावी है.

बिहार में गठबन्धन की राजनीति का पहला बुनियादी सिद्धान्त समावेशी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमता है. विभिन्न जातियों और समुदायों की विविध आबादी के साथ, राजनीतिक दल व्यापक–आधारित समर्थन सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन–निर्माण में संलग्न हैं. यह समावेशिता केवल एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि बिहार की सामाजिक वास्तविकताओं की प्रतिक्रिया भी है. गठबन्धन सरकारें अक्सर विभिन्न हित समूहों के बीच एक समझौता होती हैं, जो एक सन्तुलन बनाने का प्रयास करती हैं, जो राज्य की आबादी की विभिन्न आकांक्षाओं को समायोजित करता है.

इसके अतिरिक्त, बिहार में गठबन्धन की राजनीति क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जटिल रूप से जुड़ी हुई है. राज्य की अनूठी सामाजिक –आर्थिक चुनौतियाँ और विकासात्मक जरूरतें क्षेत्र–विशिष्ट नीतियों की माँग करती हैं. गठबन्धन सरकारें, स्वभावतः क्षेत्रीय माँगों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली विविध पार्टियाँ शामिल होती हैं, यह विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ बिहार के विभिन्न हिस्सों की विशिष्ट चिन्ताओं को सम्बोधित करने के लिए तैयार की जाती हैं, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान मिलता है.

राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में बड़े राजनीतिक परिदृश्य में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है. लोकसभा में राज्य का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व, इसकी विविध जनसांख्यिकी के साथ मिलकर, इसे भारत के एक सूक्ष्म जगत् के रूप में स्थापित करता है. बिहार में गठबंधन की राजनीति, जब राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन में योगदान कर सकती है. बिहार की आबादी की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समायोजित करके, राज्य में गठबन्धन सरकारें उन राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, जो व्यापक भारतीय आबादी के साथ प्रतिध्वनित होती हैं.

हालाँकि यह सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं कि बिहार में गठबन्धन की राजनीति वास्तव में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करती है. गठबन्धन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक सन्तुलन अक्सर समझौतों की ओर ले जाता है, जो हमेशा बड़े अच्छे के साथ संरेखित नहीं हो सकता है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच सन्तुलन बनाना एक सतत् चुनौती है जिसके लिए कुशल राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी शासन की आवश्यकता है.

निष्कर्षतः बिहार में गठबन्धन की राजनीति के मूल सिद्धान्त राज्य की सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता, जाति समीकरण और क्षेत्रीय आकांक्षाओं में गहराई से निहित हैं. हालाँकि ये सिद्धान्त अधिक समावेशी और क्षेत्र–विशिष्ट शासन में योगदान करते हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित करने के लिए एक नाजुक सन्तुलन की आवश्यकता होती है. राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के मामले में बिहार में गठबन्धन की राजनीति की सफलता, क्षेत्रीय माँगों के जटिल जाल को पार करने और राष्ट्र के व्यापक कल्याण के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण तैयार करने की क्षमता पर निर्भर करती है.

अथवा

(b) स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य-पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से, बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ, स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए. (38 अंक)

उत्तर–स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबन्धन है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ शासन मे लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है अर्थात् स्थानीय सरकार शासन के विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज तथा शहरी संस्थानों जैसे तृणमूल स्तर के संस्थानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

बिहार में पंचायती राजव्यवस्था स्थानीय शासन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है. यह प्रणाली सहभागी लोकतन्त्र को बढ़ावा देने, सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने तथा तृणमूल स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है.

उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया. तत्पश्चात् बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (वर्ष 2006 और 2021 में संशोधित अधिनियम) अधिनियमित किया.

बिहार में पंचायत राज प्रणाली की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है–ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्. यह संस्थान स्थानीय प्रशासन, योजना और विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं. पंचायत राज को सशक्त बनाने में उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधन, स्वायत्तता तथा प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है.

सशक्तिकरण का एक उदाहरण बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन में देखा जा सकता है. यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम-से-कम 100 दिनों के रोजगार की गारण्टी देता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर है. इसके माध्यम से पंचायतें न केवल निर्णय लेने में शामिल होती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी शामिल होती हैं, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ती हैं.

इसी प्रकार, बिहार में नगर निगम और नगर पालिकाएँ जैसी शहरी संस्थाएं शहरी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इन संस्थानों को सशक्त बनाने में वित्तीय शक्तियाँ सौंपना, पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है. उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल में बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है, जिससे स्वच्छता सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबन्धन में सुधार हुआ है.

हालाँकि चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान है. सीमित वित्तीय स्वायत्तता और धन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भरता अक्सर स्थानीय निकायों के प्रभावी कामकाज में बाधा बनती है. बिहार में, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त क्षमता–निर्माण उपायों के मामले सामने आए हैं, जिससे पंचायतों और शहरी संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है.

बिहार में स्थानीय सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए, नागरिक भागीदारी की सीमा, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है. हालाँकि काफी सुधार व प्रगति हुई है तथापि स्थानीय निकायों को और अधिक सशक्त बनाने, वित्तीय स्वतन्त्रता बढ़ाने और राज्य में अधिक जीवन्त और प्रभावी स्थानीय सरकार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए शासन की चुनौतियों का समाधान करने के मामले में सुधार की आवश्यकता है.

खण्ड II

प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए–

(a) भारतीय मानसून तन्त्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–भारतीय मानसून की क्रियाविधि विभिन्न कारकों से प्रभावित एक जटिल मौसम सम्बन्धी घटना है. मानसून मुख्य रूप से मौसमी हवाएं हैं, जो मौसम में बदलाव के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं. मानसून की अवधि आमतौर पर 100 से 120 दिनों के बीच होती है, जो जून की शुरुआत से सितम्बर के मध्य तक होती है. मानसून की विशेषता सामान्य वर्षा

में अचानक वृद्धि है, जिसे मानसून का विस्फोट कहा जाता है.

ऐसे कई सिद्धान्त हैं जिन्होंने भारत के मानसून तन्त्र को समझाने की कोशिश की है. मानसून का उल्लेख ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इन ग्रंथों में मानसून तन्त्र का कोई उल्लेख नहीं है. मानसूनी हवाओं का पहला वैज्ञानिक अध्ययन अरब व्यापारियों द्वारा किया गया था. अरब व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे और मानसून पैटर्न उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था. दसवीं शताब्दी में, एक अरब खोजकर्ता अल मसूदी ने उत्तरी हिन्द महासागर के ऊपर समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं के उलट होने का विवरण दिया. सत्रहवीं शताब्दी में, सर एडमंड हैली ने मानसून को उनके अलग-अलग ताप के कारण महाद्वीपों और महासागरों के बीच थर्मल विरोधाभासों के परिणामस्वरूप बताया.

मानसून की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

- मानसूनी हवाएं मौसमी हवाएं हैं, जो मौसम के अनुसार प्रवाहित होती हैं.
- ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो भागों में बँट जाती हैं–पहली, अरब सागरीय मानसून एवं दूसरी, बंगाल की खाड़ी का मानसून.
- भारत में ग्रीष्म ऋतु में इन हवाओं की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर एवं शीत ऋतु में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम होती है.
- ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं समुद्र से स्थल भाग की ओर चलने के कारण उष्ण व आर्द्र होती हैं, जबकि शीत ऋतु में ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण ठण्डी और शुष्क होती हैं.
- भारत में वर्षा मुख्यतः मानसूनी हवाओं से ही होती है. वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण-पश्चिमी मानसून हवाओं से प्राप्त होता है.
- भारतीय मानसून से होने वाली वर्षा अनिश्चित है अर्थात् कई बार मानसून के समय एवं उसकी मात्रा में अन्तर भी आ जाता है.

ये विशेषताएं सामूहिक रूप से भारतीय मानसून की अनूठी और प्रभावशाली प्रकृति को परिभाषित करती हैं, जो क्षेत्र की जलवायु, भूगोल और आजीविका को आकार देती हैं.

(b) भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं ? क्या से घरेलू माँग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं ? भारत के लिए सम्भावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं ? समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–इण्डिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत की 80% से अधिक ऊर्जा जरूरतें तीन ईंधनों से पूरी होती हैं–कोयला, तेल और ठोस बायोमास. वही 2022 में 46% हिस्सेदारी के साथ कोयला देश का शीर्ष ऊर्जा स्रोत है, बढ़ते वाहन स्वामित्व और सड़क परिवहन के उपयोग के कारण तेल की खपत और आयात तेजी से बढ़ा है तथा अभी भी खाना पकाने के ईंधन के रूप में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के कवरेज के विस्तार में हालिया सफलता के बावजूद, 660 मिलियन भारतीयों ने पूरी तरह से आधुनिक, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन या प्रौद्योगिकियों पर स्विच नहीं किया है.

समय के साथ शहरीकरण और जनसंख्या बढ़ने से ऊर्जा की माँग बढ़ेगी. अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी का अनुमान है कि 2040 तक भारत की ऊर्जा माँग लगभग 5% प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है. भारत की अन्तिम ऊर्जा खपत 2007 से 2017 तक 50% बढ़ गई, सभी क्षेत्रों में वृद्धि के साथ, लेकिन औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में सबसे बड़ी वृद्धि हुई. फलस्वरूप ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की माँग भी लोकप्रिय रूप में दिखाई देने लगी है, गौरतलब है कि भारत में छत पर सौर पैनलों का चलन बढ़ रहा है, उदाहरण के लिए हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की शुरुआत इसी उद्देश्य से की है. यह विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण न केवल पारम्परिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की भी अनुमति देता है. सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए शीर्ष तीन राज्य राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे. अपितु देश में एक विशाल समुद्र तट और अनुकूल हवा की स्थिति है, जो पवन ऊर्जा को शक्ति का एक उत्कृष्ट सम्भावित स्रोत बनाती है. पवन फार्म ऊर्जा माँगों को पूरा करने का एक प्रभावी और टिकाऊ तरीका साबित हुए हैं, खासकर तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में.

साथ ही देश में नदियों का एक मजबूत नेटवर्क है, जो पनबिजली ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण सम्भावित स्रोत बनाता है. पनबिजली संयन्त्र न केवल ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हैं बल्कि बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई जैसे अन्य लाभ भी प्रदान करते हैं. नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2021 में 843 मेगावाट जल-विद्युत् क्षमता जोड़ी, जिससे कुल क्षमता 3 गीगावॉट तक बढ़ गई.

ऊर्जा के इन नवीकरणीय स्रोतों में निवेश करके, भारत पारम्परिक जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, पर्यावरणीय क्षरण से निपट सकता है और एक हरित, स्वच्छ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

(c) भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए. (8 अंक)

उत्तर–भारतीय पर्यटन क्षेत्र देश में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, यह रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और क्षेत्रीय विकास को गति देता है, तथा वर्ष 2028 तक, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग द्वारा $59 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करने का अनुमान है. अभी हाल ही में हुई भारत की जी20 अध्यक्षता और भारत @75 आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के आलोक में, पर्यटन मंत्रालय ने आन्तरिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 को 'भारत भ्रमण वर्ष' के रूप में नामित किया है.

भारत सरकार ने आगामी 25 वर्षों के लिए रणनीतिक रोडमैप के साथ, अमृतकाल के दौरान पर्यटन को विकसित करने के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण की कल्पना की है. इसका उद्देश्य 2047 में जब हम भारत @100 मनाएंगे, तब तक भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी यात्रा गन्तव्य के रूप में स्थापित करना है, यद्यपि भारत का आउटबाउंड पर्यटन बाजार बढ़ रहा है और वर्ष 2032 तक भारतीय पर्यटन उद्योग का अनुमानित सीएजीआर 11·4% होगा, वर्तमान में भारत के लिए पर्यटन और होटल उद्योग विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है.

पर्यटन उद्योग देश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक गुणक है और यह अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि देश का लक्ष्य तेजी से आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करना है. पर्यटन गतिविधियाँ भारत के आकर्षण के सम्बन्ध में अन्य देशों के साथ सम्बन्ध विकसित करता है और भारत की सॉफ्ट पॉवर में योगदान देता है.

आमतौर पर देश में पर्यटन के भविष्य को चलाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है बढ़ता मध्यम वर्ग और बढ़ी हुई खर्च योग्य आय. ध्यातव्य है की भारत एक लोकप्रिय चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है, जिसमें अत्याधुनिक अस्पताल और किफायती स्वास्थ्य सेवा विश्वभर से रोगियों को आकर्षित कर रही है तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति और डिजिटल प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, देश में ऑनलाइन यात्रा बुकिंग और अनुकूलित यात्रा अनुभवों में भी वृद्धि देखी जा रही है, यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की उम्मीद है.

हालाँकि, भारत में पर्यटन उद्योग की निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, सुरक्षा और पर्यावरणीय

स्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान करने की भी आवश्यकता है.

(d) बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक-आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए.
(7 अंक)

उत्तर—बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जो विभिन्न सरकारी नीतियों और सामाजिक गतिशीलता से प्रभावित है. हाल ही में जारी बिहार के जाति सर्वेक्षण आँकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का 19·65% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी 15·91% थी.

वहीं अनुसूचित जनजाति समूह राज्य का 1·68% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की लगभग 1% आबादी अनुसूचित जनजाति की थी. इसके साथ ही बिहार में 42% से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार गरीब हैं. हालिया सर्वेक्षण में शामिल अनुसूचित जातियों में से केवल 5·76% ने स्कूली शिक्षा पूरी की है. साथ ही राज्य में एससी सदस्यों के लिए कुल 38 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र तथा एसटी और अन्य के लिए 2 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं. बिहार में एससी और एसटी समुदायों के सामने आने वाली प्राथमिक चिन्ताओं में से एक पर्याप्त शिक्षा के अवसरों की कमी है. परिणामस्वरूप, राज्य में एससी और एसटी आबादी के बीच निरक्षरता दर अन्य समुदायों की तुलना में न्यूनतम बनी हुई है. कौशल विकास के अवसरों की कमी और औपचारिक रोजगार तक सीमित पहुँच के कारण भी इन समूहों के भीतर गरीबी अधिक है.

ऐतिहासिक रूप से, इन समुदायों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है और उन्हें भूमि अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, जिससे उनके आर्थिक अवसर सीमित हैं. यद्यपि भूमि वितरण कार्यक्रमों सहित कृषि सुधार लागू किए गए हैं, फिर भी भूमि स्वामित्व और कृषि का मुद्दा इस समुदायों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है.

इसके अतिरिक्त, त्वरित आर्थिक विकास के चरण के दौरान एससी और एसटी परिवारों की आर्थिक और रहने की स्थिति में बदलाव का अनुभव आया है, जो असमान सुधारों की ओर संकेत करता है तथा राज्य में उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है.

(e) भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए, जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो. **(7 अंक)**

उत्तर—भारत के भौगोलिक विभाग इसकी भौतिक विशेषताओं की उल्लेखनीय विविधता को प्रदर्शित करते हैं, जो भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान और वायुमण्डलीय प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेती हैं. भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों/विभागों में विभाजित किया जा सकता है—

- **उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पर्वत**—इस क्षेत्र में राजसी हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और उत्तरपूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो विश्व के सबसे ऊँचे और सबसे लम्बे युवा वलित पर्वतों को प्रदर्शित करती हैं.
- **उत्तरी मैदान**—पूर्व से पश्चिम तक 3200 किमी तक फैला यह क्षेत्र सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेपों की विशेषता वाला एक प्रमुख स्थान रखता है.
- **प्रायद्वीपीय पठार**—600-900 मीटर की ऊँचाई सीमा वाला एक अनियमित त्रिकोण, नदी के समतल से 150 मीटर की ऊँचाई से उठता हुआ, पठार एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजन है.
- **भारतीय रेगिस्तान**—इस प्रभाग में महान भारतीय रेगिस्तान शामिल है, जो अपने शुष्क और बंजर परिदृश्य के लिए जाना जाता है.
- **तटीय मैदान**—भारत की विविध तटरेखा विशिष्ट तटीय मैदानों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताएं हैं.
- **द्वीप समूह**—भारत की भौगोलिक विविधता इसके द्वीपों तक फैली हुई है, प्रत्येक द्वीप देश के समृद्ध प्राकृतिक परिदृश्य में योगदान देता है.

ये भौगोलिक प्रभाग भारत के प्राकृतिक परिदृश्य में मूल्यवान अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जबकि बिहार, 24°20'10" उत्तर और 27°31'15" उत्तरी अक्षांश और 83°19'50" पूर्व और 88°17'40" पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है, जो विविध भौगोलिक विभाजनों की विशेषता है. इन प्रभागों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- **शिवालिक पर्वतमाला और तराई क्षेत्र**—बिहार में पश्चिमी चम्पारण का उत्तर-पश्चिमी भाग शिवालिक पर्वतमाला और उसके तराई क्षेत्र के विस्तार का क्षेत्र है, जो 932 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है. यह क्षेत्र बिहार में तृतीयक चट्टान प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और इसे रामनगर दून सहित तीन भागों में विभाजित किया गया है.
- **गंगा का मैदान**—उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ, गंगा का मैदान राज्य के भूगोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस क्षेत्र की विशेषता गंगा नदी के जलोढ़ निक्षेप हैं, जो परिदृश्य को आकार देते हैं और राज्य के कृषि महत्व में योगदान करते हैं.
- **दक्षिणी पठारी क्षेत्र**—दक्षिणी पठारी क्षेत्र बिहार की विविध भौगोलिक संरचना को जोड़ता है, जिसमें स्थिर मैदानी भूमि, विच्छेदित पठार और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं शामिल हैं.

ये भौगोलिक विभाजन बिहार के समृद्ध और विविध परिदृश्य में योगदान करते हैं, जो राज्य की भूवैज्ञानिक और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं.

प्रश्न 5. (a) बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए. राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro-climatic zone) को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है ? यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं ? इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए. **(38 अंक)**

उत्तर—बिहार की जलवायु कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें इसका स्थान, स्थलाकृति और हिमालय पर्वत से निकटता शामिल है. राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं—अक्षांश और देशान्तर, राज्य की स्थलाकृति विविध है, बंगाल की खाड़ी से निकटता जिससे राज्य में मानसूनी हवाओं और वर्षा के पैटर्न प्रभावित होता है, राज्य में गंगा, सोन और कोसी सहित नदियों का एक विशाल नेटवर्क है, जो राज्य की जल निकासी प्रणाली को प्रभावित करती है और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है तथा मानवजनित कारक जैसे—वनों की कटाई, औद्योगीकरण और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियाँ भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तन्त्र में परिवर्तन करके राज्य की जलवायु को प्रभावित करती हैं. वहीं बिहार को मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान और क्षेत्र के आधार पर चार मुख्य कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है.

राज्य चार कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है—

1. जोन I : उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान—इस क्षेत्र में बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढी, सीवान और वैशाली जिले शामिल हैं. यहाँ प्रति वर्ष औसतन 1400-1600 मिमी के साथ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है. तापमान 10°C से 40°C के बीच रहता है. इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना और जूट हैं.

2. जोन II : उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान– इस क्षेत्र में अररिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा जिले शामिल हैं. यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 1200-1400 मिमी के साथ जोन I की तुलना में थोड़ी कम वर्षा होती है. तापमान 9°C से 42°C के बीच रहता है. इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन हैं.

3. जोन III ए: दक्षिण-पूर्वी जलोढ़ मैदान – इस क्षेत्र में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिले शामिल हैं. यहाँ राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, औसतन 1000-1200 मिमी प्रतिवर्ष. तापमान 11°C से 43°C के बीच रहता है। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन हैं.

4. जोन III बी : दक्षिण-पश्चिमी जलोढ़ मैदान– इस क्षेत्र में भोजपुर, बक्सर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर और पटना जिले शामिल हैं. इसकी जलवायु जोन III ए के समान है, लेकिन थोड़ा अधिक तापमान के साथ. इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन हैं.

बिहार के कृषि-जलवायु क्षेत्रीकरण ने राज्य में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने में मदद की है. प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी जलवायु परिस्थितियों को समझकर, किसान सबसे उपयुक्त फसलों और खेती के तरीकों का चयन कर सकते हैं. इससे फसल की पैदावार बढ़ी है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है.

यद्यपि राज्य में चार अलग-अलग मौसम हैं–ग्रीष्म, शीत, मानसून और मानसून के बाद. सभी मौसम की अवधि पूरे वर्ष में अलग-अलग है; क्षेत्र की स्थलाकृति, अक्षांश और देशान्तर के आधार पर अलग-अलग तीव्रता के साथ. ग्रीष्म मौसम आमतौर पर मार्च से मई तक रहता है, जो तरबूज और ककड़ी जैसी जायद फसलों के लिए उपयुक्त है, जबकि शीत ऋतु दिसम्बर से फरवरी तक होती है, जो गेहूँ, जौ और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए अनुकूल होता है. वहीं कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानसून का मौसम जून से सितम्बर तक होता है, जो चावल, मक्का और जूट जैसी खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण है. उसके बाद अक्टूबर से नवम्बर तक मानसून के बाद का मौसम होता है, इस दौरान फसलों की कटाई और बुआई पर असर पड़ता है. ये मौसम कृषि पद्धतियों को आकार देने और बिहार में समग्र जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

यद्यपि राज्य में कृषि कैलेंडर को आकार देने और विभिन्न फसलों की सफलता निर्धारित करने में विविध मौसम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राज्य में मौसमी बदलाव फसल पैटर्न, जल प्रबन्धन और समग्र कृषि पद्धतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं. अलग-अलग मौसम विविध फसल की खेती के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे पूरे वर्ष निरन्तर कृषि उत्पादन सुनिश्चित होता है.

अपितु राज्य की कृषि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है, विशेषकर उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा। प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को उचित फसल प्रौद्योगिकी, फसल बीमा और बीज बैंकों के रख-रखाव के माध्यम से प्रबन्धित किया जाता है.

बिहार राज्य उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और भूजल संसाधनों से सम्पन्न है, जो इसकी समृद्ध और विविध कृषि में योगदान देता है. यह सब्जियों और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, दालें और गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलों की महत्वपूर्ण खेती होती है तथा मौसमी विविधताओं और पानी की आवश्यकताओं के अनुरूप चावल, गेहूँ, मक्का और दालों जैसी विशिष्ट फसलों की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बिहार की कृषि की मौसमी गतिशीलता विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फसल की खेती को अपनाने के महत्व को रेखांकित करती है, जिससे पूरे वर्ष टिकाऊ और उत्पादक कृषि पद्धतियाँ सुनिश्चित होती हैं.

अथवा

(b) भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है ? विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए. (38 अंक)

उत्तर– भारत में, 'शहर' और 'कस्बों' को भारत की जनगणना में परिभाषित किया गया है–जो भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करता है. दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय पर है.

शहर और कस्बे शहरी बस्तियों का हिस्सा हैं. राज्य के कानून द्वारा घोषित नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि वाले सभी स्थानों को वैधानिक शहर कहा जाता है.

वे स्थान जो अग्रलिखित मानदण्डों को पूरा करते हैं, शहर कहलाते हैं–

- 5,000 की न्यूनतम जनसंख्या;
- कम-से-कम 75 प्रतिशत पुरुष मुख्य काम-काजी आबादी गैर-कृषि कार्यों में लगी हुई है और
- जनसंख्या का घनत्व कम-से-कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो.

भारतीय शहरों को जनसंख्या, विकास और बुनियादी ढाँचे सहित विभिन्न कारकों के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है–टियर 1 शहर सबसे अधिक विकसित हैं, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई जैसे महानगर शामिल हैं. नासिक जैसे टियर 2 शहरों में सम्पत्ति की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं और बुनियादी ढाँचागत विकास जारी है. बांसवाड़ा और गंगटोक जैसे टियर 3 और टियर 4 शहरों की विशेषता बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सुविधाओं का विकास है, टियर 4 शहरों की आबादी 10,000 से 19,999 के बीच है. ये वर्गीकरण पूरे भारत में शहरी विकास और संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

जनसंख्या के आकार के आधार पर कस्बों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है–

वर्ग I : 1,00,000 और अधिक; वर्ग II : 50,000 से 99,999; वर्ग III : 20,000 से 49,999; वर्ग IV : 10,000 से 19,999; वर्ग V : 5,000 से 9,999 जबकि 1,00,000 और उससे अधिक की आबादी वाले कस्बों को शहर कहा जाता है.

भारतीय रिजर्व बैंक 'टियर केन्द्रों' को परिभाषित करने के लिए समान जनसंख्या मानदण्ड का उपयोग करता है यह एक अवधारणा है, जिसका उपयोग बैंक शाखा/एटीएम विस्तार आदि के लिए प्रोत्साहन डिजाइन करने में किया जाता है. 5,000 से कम आबादी वाले शहरों को टियर-6 कहा जाता है. टियर-1 में महानगरीय और शहरी केन्द्र शामिल हैं, टियर-2, 3 और 4 में अर्द्ध-शहरी केन्द्र शामिल हैं और टियर-5 और 6 में ग्रामीण केन्द्र शामिल हैं.

2011 की जनगणना के अनुसार, 2001-2011 के दौरान भारत की शहरी आबादी 2·76 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर के साथ 377 मिलियन हो गई और पूरे देश में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27·7 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31·1 प्रतिशत हो गया है. 2001-2011 के दौरान 3·3 प्रतिशत के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जहाँ 62·17% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है. लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्र और कुल जनसंख्या के आधार पर देखा जाए, तो तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसके बाद केरल (47·7 प्रतिशत) है, जो महाराष्ट्र (45·2 प्रतिशत) से आगे है.

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में से 11·29% लोग शहरी क्षेत्रों में, जबकि 88·71% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे. राज्य के शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 895 महिलाएं थीं. इसके अतिरिक्त बिहार के शहरी क्षेत्रों में बाल (0-6 आयु) लिंग अनुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 912 लड़कियाँ थीं. इस प्रकार बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुल बच्चे (0-6 आयु वर्ग) कुल शहरी आबादी का 14·89% थे तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 921 महिलाएं थीं तथा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 938 लड़कियाँ थीं.

बिहार में अधिकांश शहरी आबादी गरीबी में रहती है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच बहुत कम है. 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में शहरी गरीबी दर 47·53% थी, जो राष्ट्रीय औसत 28·61% से काफी अधिक है. स्वास्थ्य के सन्दर्भ में, शहरी क्षेत्रों में केवल 38% घरों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच है और आधे से अधिक के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुँच है.

बिहार में कार्यबल भागीदारी दर 2001 में 51·7% से बढ़कर 2011 में 55·3% हो गई, जिसमें अधिकांश कार्यबल कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में लगे हुए थे.

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, राज्य में शहरी क्षेत्रों के भविष्य के लिए कुछ सकारात्मक संकेत हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तीव्र गति से बढ़ रही है और यह जारी रहने की सम्भावना है, क्योंकि सरकार बुनियादी ढाँचे और विकास में निवेश करना जारी रखेगी. हाल के वर्षों में बिजली तक पहुँच वाले घरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

प्रश्न 6. (a) भारतीय नियोजन के सन्दर्भ में अर्थशास्त्र के 'ट्रिकल-डाउन' सिद्धान्त, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए.

(38 अंक)

उत्तर—अर्थशास्त्र का ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त एक ऐसी अवधारणा है जिस पर भारत सहित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के सन्दर्भ में व्यापक रूप से बहस और विश्लेषण किया गया है. इसे रीगनॉमिक्स या आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, यह सिद्धान्त इस विचार के इर्द-गिर्द घूमता है कि अमीर और बड़े निगमों को प्रदान किए गए आर्थिक लाभ अंततः बाकी आबादी तक 'रिसकर' पहुँचेंगे, जिससे समग्र आर्थिक विकास और समृद्धि होगी. राज्य की महामंदी के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के प्रोत्साहन प्रयासों और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आयकर कटौती के उपयोग दोनों को 'ट्रिकल-डाउन' के रूप में वर्णित किया गया.

ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त के प्रमुख तत्व

- **कर छूट और लाभ**—सिद्धान्त के अनुसार निगमों और अमीरों के लिए कर छूट और लाभ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और अंततः सभी को लाभान्वित करेंगे.
- **कम विनियमन और कर कटौती**—ट्रिकल-डाउन अर्थशास्त्र में उच्च-आयकर ब्रैकेट के साथ-साथ निगमों के लिए कम विनियमन और कर कटौती शामिल है.
- **आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र**—ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र से जुड़ा है, जो दावा करता है कि सभी कर कटौती से आर्थिक विकास होता है.

ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त के लाभ

- **आर्थिक विकास**—यद्यपि ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त आर्थिक विकास की ओर ले जाता है, क्योंकि यह निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है. ऐसा माना जाता है कि अमीरों पर करों को कम करने से उनके पास निवेश करने के लिए अधिक खर्च करने योग्य आय होगी, जो बदले में नौकरियाँ पैदा करती है और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है.
- **रोजगार सृजन**—यह सिद्धान्त सुझाव देता है कि कर कटौती जैसी अमीरों को लाभ पहुँचाने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर, यह उन्हें व्यवसायों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे नौकरियाँ पैदा होती हैं. यह सिद्धान्त मानता है कि व्यवसायी अपने परिचालन का विस्तार करते हुए अधिक श्रमिकों को काम पर रखेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
- **नवाचार और तकनीकी उन्नति**—यह सिद्धान्त नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है. इसके अनुसार शीर्ष कमाई करने वालों की सम्पत्ति में वृद्धि से, उनके पास अनुसन्धान और विकास में निवेश करने के लिए अधिक संसाधन होंगे, जिससे नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा जो पूरे समाज को लाभान्वित करेंगे.
- **कर राजस्व में वृद्धि**—समर्थकों का तर्क है कि ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त से लम्बे समय में कर राजस्व में वृद्धि हो सकती है. सिद्धान्त के अनुसार अमीरों के लिए कर दरों को कम करने से, उन्हें काम करने, निवेश करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा. यह बदले में, उच्च आय और मुनाफा उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम-स्वरूप सरकार के लिए कर राजस्व में वृद्धि होती है.
- **उपभोक्ता लाभ**—जैसे-जैसे अमीर और अमीर होते जाएंगे, उनकी बढ़ी हुई खर्च करने की शक्ति से मध्यम और निम्न-आय समूहों सहित पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा. तर्क यह है कि जब अमीर लोग सामान और सेवाएं खरीदते हैं, तो इससे माँग पैदा होती है, जो बदले में, आर्थिक विकास को गति देती है और उत्पादों और अवसरों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करके उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाती है.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बिन्दु ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त के समर्थकों द्वारा दिए गए तर्कों को दर्शाते हैं. आलोचकों का तर्क है कि लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, यह सिद्धान्त हमेशा आर्थिक विकास की ओर नहीं ले जाता है, अपितु आय असमानता को बढ़ाता है.

इस सिद्धान्त की सीमाएं और आलोचनाएं

भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे कई सीमाओं और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है—

- **असमान आय वितरण**—भारत में ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त की मुख्य आलोचनाओं में से एक महत्वपूर्ण आय असमानता है. आर्थिक विकास का अनुभव करने के बावजूद, लाभ समाज के निम्न-आय वर्ग तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाया है. अमीर अनुपातहीन रूप से अमीर हो गए हैं, जबकि गरीब गरीबी और सीमित अवसरों से जूझ रहे हैं.
- **समावेशिता का अभाव**—इस सिद्धान्त के अनुसार आर्थिक विकास स्वचालित रूप से सभी के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है, लेकिन भारतीय सन्दर्भ में, ऐसा नहीं है दलित और आदिवासी जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भेदभाव और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक विकास से लाभ उठाने की उनकी क्षमता में बाधा आ रही है.
- **रोजगार सृजन की कमी**—आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धान्त रोजगार सृजन के मुद्दे को पर्याप्त रूप से सम्बोधित नहीं करता है, खासकर भारत जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व और बड़े अनौपचारिक

क्षेत्र वाले देश में. अकेले आर्थिक विकास श्रम बल के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसरों की गारण्टी नहीं देता है, जिससे अल्परोजगारी और बेरोजगारी बढ़ती है.

- **सामाजिक विकास पर फोकस की कमी**—यह सिद्धान्त आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण जोर देता है और मानता है कि सामाजिक विकास अपने आप हो जाएगा. हालाँकि, यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढाँचे जैसे सामाजिक विकास में निवेश के महत्व को पहचानने में विफल रहता है, जो भारत जैसे देश में समावेशी विकास और गरीबी में कमी के लिए महत्वपूर्ण है.
- **कमजोर विनियमन और शासन**—ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त मानता है कि आर्थिक विकास के लाभ उचित रूप से वितरित किए जाएंगे. हालाँकि, भारत में कमजोर विनियमन और शासन ने अक्सर आर्थिक अभिजात वर्ग को प्रणाली का शोषण करने की अनुमति दी है, जिससे भ्रष्टाचार, कर चोरी और आय असमानता बिगड़ती है.
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा**—ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त अक्सर ग्रामीण विकास पर शहरी और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देता है. ऐसे देश में जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि या अन्य ग्रामीण-आधारित गतिविधियों में लगा हुआ है, यह उपेक्षा ग्रामीण-शहरी विभाजन को बढ़ा सकती है और समग्र समावेशी विकास में बाधा डाल सकती है.
- **पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताएं**—ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त पर्यावरणीय स्थिरता को पर्याप्त रूप से सम्बोधित नहीं करता है और प्रदूषण और संसाधन की कमी, जैसे आर्थिक विकास की नकारात्मक बाहरीताओं को नजरअंदाज करता है. महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे भारत को एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के साथ आर्थिक विकास को सन्तुलित करे.

भारतीय सन्दर्भ में, ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त गहन जाँच और बहस का विषय रहा है, जबकि इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन हो सकता है, यद्यपि इसके आलोचक आय असमानता को सम्बोधित करने और गरीबों को प्रभावी ढंग से लाभ पहुँचाने में इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं. भारतीय सन्दर्भ में ट्रिकल-डाउन सिद्धान्त की प्रासंगिकता और अनुप्रयोग को समझने के लिए जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है.

अथवा

(b) 'भारत की मानसून प्रणाली', इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए.

(38 अंक)

उत्तर—भारत की जलवायु, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरह मानसून के मौसम के दौरान गर्म और आर्द्र होती है.

मानसून नाम अरबी शब्द 'मौसिम' से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है. मानसून, मौसमी हवाएं (आवधिक हवाएं) हैं, जो मौसम बदलने के साथ दिशा बदल देती हैं. मानसून एक मौसमी पवन पैटर्न है, जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से भूमि की ओर तथा शीत ऋतु में भूमि से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है. कुछ विद्वान मानसूनी पवनों को बड़े पैमाने की स्थलीय और समुद्री हवाएं मानते हैं.

यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में दो प्रकार का मानसून तन्त्र देखने को मिलता है—

1. दक्षिण-पश्चिम मानसून—दक्षिण-पश्चिम मानसून भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून का नाम इसी के आधार पर रखा गया है. यह तिब्बती पठार पर बनने वाली तीव्र निम्न दबाव प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश लाता है, शुरुआती बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट आती है. जब मानसून का भारत में आगमन होता है, तो प्रचंड गड़गड़ाहट और बिजली के साथ नमी ले जाने वाली हवाएँ चलती हैं.

केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मानसून का जून के पहले सप्ताह में आगमन हो जाता है, जबकि आन्तरिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव जुलाई के पहले सप्ताह में देखने को मिलता है. मध्य जून से मध्य जुलाई तक दैनिक तापमान 5°C से 8°C तक गिर जाता है. यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीपीय भूमि पर पहुँचते ही इन पवनों की दक्षिण-पश्चिमी दिशा उत्तर-पश्चिम भारत पर राहत और तापीय निम्न दबाव द्वारा संशोधित होती है तथा जैसे-जैसे ये पवनें मुख्य भूमि के निकट आती है, इनका दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है—अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा.

2. उत्तर-पूर्वी मानसून—उत्तर-पूर्व मानसून भारत में उत्तर-पूर्व से प्रवेश करता है, इस प्रकार के मानसून में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है.

हिन्द महासागर से नमी मानसूनी पवनों द्वारा लाई जाती है. पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण भारत तक सीमित है, जो अक्टूबर से दिसम्बर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और दक्षिण आन्तरिक कर्नाटक में बारिश लाता है. निम्न दबाव प्रणालियाँ, चक्रवात सम्बन्धित वर्षा का कारण बनते हैं, जिसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है. यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा ऋतु है, इन तीन महीनों के दौरान राज्य में वार्षिक वर्षा का 48% प्राप्त होता है.

अपितु मानसून का मौसम भारत की कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समय है. हालाँकि, शरद ऋतु की शुरुआत के साथ, मानसून पीछे हटने लगता है. इससे एक ऐसी अवधि शुरू होती है जिसे लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है. यह अवधि सूखे से लेकर बाढ़ तक, मौसम सम्बन्धी कई चुनौतियाँ ला सकती है. इसका असर फसल की पैदावार से लेकर परिवहन नेटवर्क तक सभी पर पड़ता है. लौटता हुआ मानसून एक जटिल और गतिशील मौसम सम्बन्धी घटना है. देश की कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रबन्धन के लिए इसके पैटर्न और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है.

भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव—

भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण मौसम घटना, भारतीय मानसून, जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित हो रहा है.

- **बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता और अनियमित व्यवहार**—जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अवधि में वर्षा के फैलाव में अधिक परिवर्तनशीलता आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप कम समय में अधिक स्थानीयकृत, अत्यधिक भारी बारिश की घटनाएं हो रही हैं.
- **कुल वर्षा में कमी**—चरम घटनाओं के कारण वर्षा में वृद्धि की धारणा के बावजूद, भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के आकलन से संकेत मिलता है कि पिछले 60 वर्षों में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा में वास्तव में 6% की कमी आई है. यह कमी, वर्षा के पैटर्न में बढ़ती परिवर्तनशीलता के साथ मिलकर, इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करती है.
- **आर्द्र और अधिक अनियमित मानसून**—अध्ययनों से पता चला है कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को आर्द्र और अधिक अनियमित बना रहा है. तापन की प्रत्येक अतिरिक्त

डिग्री से मानसूनी वर्षा में 5% की वृद्धि होने की सम्भावना है, जिससे मानसून का मौसम मजबूत और अधिक अराजक हो जाएगा.

- **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता**—भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक है. देश को विभिन्न जलवायु मैट्रिक्स पर गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना, विनाशकारी चक्रवातों में वृद्धि और अत्यधिक गर्मी की लहरें शामिल हैं.

ये कारक, मानसून की बदलती प्रकृति के साथ मिलकर, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पेश करते हैं.

भारतीय मानसून का वितरण

भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेमी है, लेकिन इसमें स्थानिक विविधताएं बहुत अधिक हैं—

- **उच्च वर्षा वाले क्षेत्र**—सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर, साथ ही उप-हिमालयी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर और मेघालय की पहाड़ियों में होती है. यहाँ वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है.
- **मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र**—गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखण्ड और बिहार को कवर करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप में 100-200 सेमी के बीच वर्षा होती है.
- **कम वर्षा वाले क्षेत्र**—पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार में 50-100 सेमी के बीच वर्षा होती है.
- **अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र**—प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश (रॉयल सीमा), कर्नाटक (उत्तरी आंतरिक क्षेत्र) और महाराष्ट्र (मराठावाड़ा विदर्भ), लद्दाख के कम वर्षा वाले क्षेत्र और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 50 सेमी से कम वर्षा होती है.

पूर्व और पश्चिम जेट स्ट्रीम

जेट स्ट्रीम एक उच्च गति वाली वायु की पट्टी है, जो वायुमण्डल के ऊपरी स्तरों में पाई जाती है, आमतौर पर 8 से 12 किलोमीटर की ऊँचाई पर. यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन वास्तव में दो मुख्य जेट स्ट्रीम हैं—ध्रुवीय जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबन्धीय जेट स्ट्रीम.

ध्रुवीय जेट स्ट्रीम ध्रुवों के करीब स्थित है और ठण्डी ध्रुवीय हवा और निचले अक्षांशों से गर्म हवा के बीच की सीमा पर बनती है, जैसाकि नाम से पता चलता है, यह आमतौर पर यूरोप, उत्तरी अमरीका और एशिया सहित मध्य अक्षांशों को प्रभावित करता है. इन क्षेत्रों में अधिकांश मौसम पैटर्न के लिए ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, क्योंकि यह कम और उच्च दबाव प्रणाली और चक्रवात जैसी मौसम प्रणालियों की गति और तीव्रता को प्रभावित करती है.

दूसरी ओर, उपोष्ण कटिबन्धीय जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, आमतौर पर 30 डिग्री अक्षांश के आसपास. इसका निर्माण ध्रुव की ओर बढ़ने वाली गर्म उष्ण कटिबन्धीय वायु और उच्च अक्षांशों से आने वाली ठण्डी वायु के बीच की सीमा से होता है. उपोष्ण कटिबन्धीय जेट स्ट्रीम अपने ध्रुवीय समकक्ष की तुलना में अधिक मजबूत और स्थिर होती है. इसका प्रवाह आमतौर पर पूर्व की ओर अधिक सुसंगत होता है और कुछ मौसमों के दौरान उपोष्ण कटिबन्धीय और मध्य अक्षांशों के मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

दोनों जेट धाराएं वैश्विक वायुमण्डलीय परिसंचरण प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विश्वभर में ऊष्मा और आर्द्रता के परिवहन में मदद करती हैं.

भारतीय मानसून प्रणाली देश की कृषि, जल आपूर्ति और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है. इसकी व्यवहार्यता आजीविका बनाए रखने और आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की भविष्यवाणी और प्रबन्धन के लिए मानसून प्रणाली और उससे जुड़ी जेट धाराओं की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है.

खण्ड III

प्रश्न 7. निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए—

(a) आधुनिक समाज में कम्प्यूटर की क्या भूमिका है ? (8 अंक)

उत्तर—कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा (इनपुट) स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और परिणाम (आउटपुट) प्रदान करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है. कम्प्यूटर अपने शुरुआत में एक साधारण कैलकुलेटर से आधुनिक समय में एक सुपर कम्प्यूटर तक की विकास यात्रा पूरी कर चुका है. आधुनिक समाज में कम्प्यूटर के उपयोग को कई समूहों में विभाजित किया जा सकता है. जैसे—

- **व्यवसाय में कम्प्यूटर की भूमिका**—कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग जो हमें पत्रों, रिपोर्टों, दस्तावेजों को तैयार करने और सम्पादित करने के अतिरिक्त कुछ ही सेकण्ड में मैन्युअल रूप से टाइप करने में सक्षम बनाती है.
- **बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कम्प्यूटर की भूमिका**—बजट संचालित करने वाले संगठनों में बचत खातों, सावधि जमा, ऋण, निवेश, लाभप्रदता विश्लेषण आदि से जुड़े डेटा का प्रसंस्करण आदि में भूमिका.
- **उद्योगों में कम्प्यूटर की भूमिका**—औद्योगिक उत्पादन में कर्मचारियों, ग्राहकों, बिक्री, उत्पाद जानकारी, उत्पादन कार्यक्रम आदि से एकत्र किए गए डेटा को संसाधित करने में कम्प्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.
- **शिक्षा में कम्प्यूटर की भूमिका**—वर्तमान में छात्र पंजीकरण, कक्षा निर्धारण, परीक्षा परिणामों की प्रोसेसिंग, छात्रों और शिक्षकों के व्यक्तिगत डेटा भण्डारण जैसे मामलों को प्रशासन की सहायता के लिए कम्प्यूटर द्वारा तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है.
- **चिकित्सा क्षेत्र में कम्प्यूटर की भूमिका**—वर्तमान में टेली मेडिसन के द्वारा कम्प्यूटर-आधारित उपकरणों के अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से डॉक्टरों को बीमारियों का निदान करने में मदद मिली है. उदाहरण के लिए, माइक्रो-प्रोसेसर-आधारित वॉयस सिस्टम, स्पीच सिंथेसाइजर, रोगी के रक्तचाप, शरीर के तापमान, ईसीजी (इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ) जैसे मनोवैज्ञानिक चर की निगरानी करने और कुछ असामान्य होने पर चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है.
- **कानूनी क्षेत्र में कम्प्यूटर की भूमिका**—कम्प्यूटर के उपयोग से वकीलों , प्रशिक्षु वकीलों और कानून के छात्रों को बिना समय बर्बाद किए प्रासंगिक डेटा ढूँढने और बेहतर सेवा प्राप्त करने में मदद मिलती है.
- **प्रशासनिक क्षेत्र में कम्प्यूटर की भूमिका**—वर्तमान समय में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारें जनता तक अधिक-से-अधिक सेवाएँ वितरण का प्रयास करती है, जिसमें कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण तकनीकी डिवाइस के रूप में भूमिका निभाता है. कम्प्यूटर का उपयोग करके सेवा कर और आयकर संग्रह को सरल बनाया गया. इसी तरह सेना में, कम्प्यूटर स्टोर इन्वेण्ट्री का उपयोग स्क्रीन पर युद्ध सिमुलेशन तक आयोजित किया जाता है. सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है. ऐसे ही कम्प्यूटर उपकरणों का उपयोग करके यातायात की दिशा का पता

लगाकर यातायात प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबन्धित किया जा सकता है.

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान आधुनिक समाज में हमारी छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकता तक कम्प्यूटर की भूमिका है.

(b) समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक (टेक्नोलॉजी) एवं सामाजिक विकास में सम्बन्ध की विवेचना कीजिए. (8 अंक)

उत्तर—समाज लोगों का एक समूह है जो एक समुदाय में एक साथ रहता है जिसमें कुछ प्रकार की सरकार के साथ-साथ कुछ नियम और अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है. आधुनिक लोकतान्त्रिक देशों में सरकार इसी समाज के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करती है. एक प्रतिनिधि के तौर पर सरकार समाज के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं का संचालन करती हैं, जिसके निष्पादन और वितरण में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसलिए कहा भी जाता है कि वर्तमान समय में तकनीक के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है.

आज हमारा प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी रूप में तकनीक पर निर्भर है. यही कारण है कि प्रौद्योगिकी और समाज के बीच वर्तमान सम्बन्ध बहुआयामी है. प्रौद्योगिकी ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे हमारे रहने, काम करने, संवाद करने और सोचने के तरीके पर असर पड़ा है. प्रौद्योगिकी ने हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

तकनीक एवं सामाजिक विकास में सम्बन्ध

- वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से समाज कल्याण सम्बन्धी योजनाओं, वित्तीय सहायता, सूचना आदि त्वरित और आसान हो गया है. वर्तमान में भारत की जीडीपी में आईटी उद्योग का योगदान लगभग 8% से 10% तक है. इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सतत् विकास लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है.
- भारत जैसे देश जहाँ आज भी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है. ग्रामीण विकास में भी आईटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. अब आईटी के माध्यम से दूरदराज के लोगों तक भी सेवाएं उपलब्ध कराना आसान हुआ हैं. ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ने से नई व्यावसायिक सम्भावनाओं के द्वार खुल रहे हैं. किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की युवा पीढ़ी के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकियों और समाधानों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने सम्पूर्ण कृषि मूल्य शृंखला में नवीन व्यवसाय मॉडल के उद्भव को जन्म दिया है. ये मॉडल इनपुट, प्रसंस्करण सहित विभिन्न चरणों को शामिल करते हैं और वितरण. नतीजतन, यह परिवर्तन न केवल ग्रामीण प्रवासन पर अंकुश लगाता है बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को भी आकर्षित करता है, जिससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में तेजी आती है.
- प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और कुशल सूचना विनिमय सुनिश्चित करना सम्भव हुआ है. पारदर्शिता जहाँ लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाता है, वहीं कुशल सूचना विनिमय किसी योजना और कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करता है.
- प्रौद्योगिकी और समाज के बीच सम्बन्धों का भविष्य में भी प्रक्षेपवक्र कई प्रमुख रुझानों से आकार लेने की सम्भावना है, जिसमें स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाना, इंटरनेट और 5जी नेटवर्क का निरन्तर विकास और डेटा का बढ़ता महत्व शामिल है. इन प्रौद्योगिकियों में दक्षता, उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है.
- वर्तमान में एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों ने रोगों के निदान और उपचार के तरीके में क्रान्ति ला दी है. साथ ही, मेडिकल रोबोट और टेलीमेडिसिन के विकास ने स्वास्थ्य सेवा को खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, सुलभ बना दिया है. प्रौद्योगिकी ने विनिर्माण और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाई है. उदाहरण के लिए स्वचालन, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के उपयोग से उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लागत कम हुई है और उत्पादन में वृद्धि हुई है. बिग डेटा और एनालिटिक्स ने समाज के निर्णय लेने के तरीके में क्रान्ति ला दी है, जिससे परिणामों में सुधार हुआ है ओर दक्षता में वृद्धि हुई है.

हालाँकि दूसरी ओर इसने कुछ चिन्ताओं जैसे डेटा की सुरक्षा, साइबर क्राइम, मैनुअल रोजगार में कमी को भी बढ़ावा दिया है.

(c) बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए. (7 अंक)

उत्तर—बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है. यह उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखण्ड से घिरा हुआ है. बिहार की पूर्वी और उत्तरी भारत के विशाल बाजारों से निकटता, कोलकाता और हल्दिया जैसे बन्दरगाहों तक पहुँच और पड़ोसी राज्यों से कच्चे माल के स्रोतों और खनिज भण्डार तक पहुँच के कारण राज्य को एक अद्वितीय स्थान-विशिष्ट लाभ प्राप्त है. इसके साथ ही राज्य में विज्ञान और प्राद्यौगिकी के उपयोग से औद्योगिक विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है.

वर्ष 2023-24 में, मौजूदा कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी 104·62 बिलियन होने का अनुमान है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 और 2023-24 के बीच राज्य की जीएसडीपी 11·03% की सीएजीआर (₹ में) दर से बढ़ी है. बिहार ने फसल की पैदावार को अनुकूलित करने के लिए सतत् कृषि तकनीकों, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स का बेहतर उपयोग किया है. यही कारण है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, बिहार वर्तमान में देश भर में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और फलों का आठवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है. खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा राज्य में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है. बिहार स्टार्ट उप नीति-2016 और कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

विनिर्माण के सन्दर्भ में स्वचालन और उन्नत विनिर्माण प्रौद्यौगिकी के कार्यान्वयन ने पारम्परिक उद्योगों को आधुनिक बनाया है. उदाहरण के लिए, बिहार में कपड़ा क्षेत्र में स्वचालित करघे और डिजिटल कपड़ा छपाई की शुरुआत के साथ एक तकनीकी बदलाव देखा गया है. राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से अनेक तकनीकी आधार समाधानों को सम्मिलित करते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 को लागू किया गया है.

इसके अतिरिक्त बिहार में प्रौद्यौगिकी पार्कों और अनुसन्धान संस्थानों की उपस्थिति ने नवाचार के एक पारिस्थितिकी तन्त्र को बढ़ावा दिया है. उदाहरण के लिए, पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क, दरभंगा आईटी पार्क आदि. सात निश्चय योजना के 7वें निश्चय (अवसर बढ़े , आगे बढ़े) के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में तकनीकी शिक्षा के लिए एक पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई.

(d) कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए. (7 अंक)

उत्तर—कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है. कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तब सामने आया जब चीन के हुबेई प्रान्त के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 30 जनवरी, 2020 को इसे वैश्विक चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया. शीघ्र ही इसके तेजी से प्रसार के कारण भारत सहित विश्वभर के अन्य देशों में पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया. लॉकडाउन के साथ ही लोगों की जीवनशैली पूर्णता डिजिटल जीवनशैली में बदल गई. चाहे वह काम, शिक्षा, मनोरंजन या दैनिक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए हो.

कोविड-19 के दौरान नई तकनीक और सहायता

- ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक मोबाइल ऐप 'आरोग्य सेतु', की शुरुआत की गई. इसके माध्यम से COVID-19 रोगियों को ट्रैक करने, रोगियों की जानकारी उपलब्ध कराने आदि में सहायता मिली.
- कोविन या कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) का विस्तार है, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीन वितरण प्रणाली तन्त्र को प्रभावी ढंग से शुरू करने और बढ़ाने के लिए एक डिजिटल तकनीकी मंच के रूप में सहायक रहा.
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**—कोविड-19 के दौरान किसी भी मीटिंग के लिए एक ही स्थान पर जूम और स्काइप जैसे ऐप्स का उपयोग किया गया. ये ऐप्स किसी संस्था के कर्मचारियों या लोगों के डेस्कटॉप/लैपटॉप/मोबाइल फोन पर आसानी से चलाए जा सकते हैं.
- **रोबोटिक्स**—आइसोलेशन वार्डों में मरीजों को भोजन, दवाइयाँ आदि देकर उनकी देखभाल करने के लिए रोबोटों को तैनात किया गया. उदाहरण के लिए, चीन में, लिटिल पीनट नामक रोबोट का इसी उद्देश्य से प्रयोग काफी चर्चा में रहा. ऐसे ही अमरीका के वाशिंगटन में मरीजों के इलाज के लिए विकी नामक रोबोट का उपयोग किया गया.
- **टेली-मेडिसिन**—इस तकनीक के माध्यम से बड़े आधुनिक अस्पतालों द्वारा दूरदराज के स्थानों के मरीजों की सुरक्षित जाँच और उपचार किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, प्रैक्टो, लाइब्रेट, 1एमजी आदि.
- **स्वायत्त वाहन और ड्रोन**—इनका उपयोग दवाओं और खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए किया जा रहा है. ड्रोन का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करने, संगरोध आदेशों के गैर-अनुपालन पर नजर रखने और थर्मल इमेजिंग के लिए भी किया जा रहा है.
- **वर्चुअल बायोमेट्रिक्स**—इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर के साथ एकीकृत चेहरे और आईरिस पहचान समाधानों का तेजी से स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है. भारत में सरकार और कई निजी कम्पनियों ने सम्पर्क-आधारित बायोमेट्रिक समय और उपस्थिति प्रणाली को निलम्बित कर दिया है. इनका उपयोग संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए भी किया गया.
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता**—एआई बीमारी के निदान और इलाज विकसित करने में मदद कर रहा है। Tencent, DiDi और Huawei जैसी कई प्रमुख तकनीकी कम्पनियों के क्लाउड कम्प्यूटिंग संसाधनों और सुपर कम्प्यूटरों का उपयोग वायरस के इलाज या वैक्सीन के विकास को तेजी से ट्रैक करने के लिए किया गया.

(e) सतत् विकास में तकनीक (टेक्नोलॉजी) की भूमिका पर एक नोट लिखिए. (7 अंक)

उत्तर—वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रौद्योगिकी में प्रगति ने हमें सूचना तक पहुँच बढ़ाने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन में सुधार तक विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाया है. हालाँकि, प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानता में भी योगदान दे सकती है. ऐसे में, सतत् विकास की आवश्यकता बढ़ रही है, जिसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता है.

सतत् विकास को 'ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है.' इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन आयामों के बीच सन्तुलन की आवश्यकता होती है. प्रौद्योगिकी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन समाधानों को सक्षम करके सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत् विकास में योगदान देने का एक तरीका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है. तेल और कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन कई वर्षों से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत रहे हैं. हालाँकि, जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे कि सौर, पवन और जल विद्युत, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं और ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत प्रदान करने की क्षमता रखते हैं. प्रौद्योगिकी में प्रगति ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बना दिया है, जिससे वे जीवाश्म ईंधन के लिए तेजी से आकर्षक विकल्प बन गए हैं.

एक अन्य तरीका जिससे प्रौद्योगिकी सतत् विकास में योगदान दे सकती है, वह है टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना. पर्यावरणीय क्षरण में कृषि का प्रमुख योगदान है, उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के उपयोग से मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का "ह्रास होता है. हालाँकि, प्रौद्योगिकी किसानों को अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में सक्षम कर सकती है, जैसे कि शून्य जुताई खेती और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग, जिनके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और वे कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर सकती हैं.

प्रौद्योगिकी टिकाऊ परिवहन प्रथाओं को बढ़ावा देकर सतत् विकास में भी योगदान दे सकती है. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है. हालाँकि, प्रौद्योगिकी में प्रगति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को सक्षम किया है, जिनमें उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है.

अंततः, प्रौद्योगिकी सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देकर सतत् विकास में योगदान दे सकती है. जैसे-जैसे विश्व तेजी से शहरीकृत होता जा रहा है, सतत् शहरी विकास की आवश्यकता और अधिक बढ़ती जा रही है. सतत् शहरी विकास के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच सन्तुलन की आवश्यकता होती है. प्रौद्योगिकी स्मार्ट शहरों के विकास को सक्षम कर सकती है, जो संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, अपशिष्ट को कम करने और निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं. इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी हरित इमारतों के विकास को सक्षम कर सकती है,

जो ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होने के लिए डिजाइन की गई हैं. सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देकर, प्रौद्योगिकी शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकती है.

प्रश्न 8. (a) तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है. उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है. (36 अंक)

उत्तर—वर्तमान में टेक्नोलॉजी हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है. आज कोई भी समय या स्थान ऐसा नहीं है जहाँ प्रौद्योगिकी कोई भूमिका न निभाती हो. प्रौद्योगिकी ने जहाँ एक ओर हमें लाभान्वित किया है वहीं दूसरी ओर इसके कुछ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी हैं. कई विद्वानों और पर्यावरणविदों का मानना है कि लोगों द्वारा प्रौद्योगिकी के नकारात्मक उपयोग से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हुई है. प्रौद्योगिकी के वरदान के साथ अभिशाप होने के बारे में पर्यावरणविदों की राय है कि प्रौद्योगिकी अकेले हानिकारक नहीं है, बल्कि जो इसे अभिशाप बनाती है, वह है मनुष्यों द्वारा इसका गलत उपयोग.

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग : पर्यावरण के लिए अभिशाप

प्रौद्योगिकी विकास के बाद मशीनों और ऑटोमोबाइल की माँग और खपत में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद इसके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. हालाँकि मशीनों और ऑटोमोबाइल ने जहाँ एक ओर औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया वहीं दूसरी और कारों, हवाई जहाजों, बिजली संयन्त्रों और कारखानों से वायुमण्डल में मानवजनित कार्बन उत्सर्जन को भी बढ़ाया है. वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2 टन है. वहीं वैश्विक कार्बन उत्सर्जन औसत 4·7 टन रहा. उल्लेखनीय है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 50 से 200 वर्षों तक वायुमण्डल में बनी रहती है, इस कारण इसका प्रभाव लम्बे समय तक रहता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में एक है.

वैज्ञानिकों के अनुसार सदी की शुरुआत से पृथ्वी की औसत सतह का तापमान 0·8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर है. प्रोफेसर ब्रायन होस्किन्स द्वारा बताया गया कि CO_2 का स्तर लगभग 4·5 मिलियन वर्षों में सबसे अधिक है, जिसका प्राथमिक घटक जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई है, जो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का एक अन्य कारण है. उद्योगों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रकार के गैसीय उत्सर्जन और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन पानी की खराब गुणवत्ता का प्रमुख कारण है. जल निकायों में विषाक्तता बढ़ने का कारण यह है कि नाइट्रोजन का जमाव पानी में उर्वरक की तरह काम करता है, जो शैवाल के निर्माण को बढ़ावा देता है, जो बदले में पानी की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन को अवरुद्ध करता है और उनके लिए यूट्रोफिक स्थिति बनाता है, जो उन्हें धीरे-धीरे नष्ट कर देता है. पानी की खराब गुणवत्ता का एक अन्य कारण खेतों से पानी में कीटनाशकों का बहाव है, जिससे यह प्रदूषित होता है और इस तरह यह जलीय जीवन के जीवित रहने के लिए अनुपयुक्त वातावरण बन जाता है.

टेक्नोट्रैश, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई-कचरा भी कहा जाता है, यह प्रयोग किया हुआ अवांछित विद्युत् या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कचरा है. नियमित कूड़े के साथ फेंका गया टेक्नोट्रैश आमतौर पर लैंडफिल में चला जाता है. अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स में गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री और भारी धातुएं और विषाक्त सामग्री होती हैं, जो जमीन में जाने से हमारे द्वारा पीने वाले पानी, हमारे द्वारा खाए जाने वाले पौधों और क्षेत्र के आसपास रहने वाले जानवरों को दूषित कर सकते हैं. ये विषाक्त पदार्थ विभिन्न बीमारियों के साथ कैंसर तक का कारण भी बन सकते हैं.

इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण में भी प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग इसका कारण बनता है, क्योंकि तकनीकी प्रगति के कारण मानव ने अधिक यात्रा करना शुरू कर दिया है. इन यात्रा माध्यमों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों से स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे बढ़ रहे हैं. मुख्य प्रदूषकों में ओजोन, सीसा, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं.

विश्व पर्यावरण क्षति का एक और बड़ा हिस्सा वनों की कटाई से होता है जहाँ मनुष्य शहरों का विस्तार करने के लिए बिना सोचे-समझे जंगलों को साफ कर रहे हैं और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण थोड़े ही समय में पेड़ों का सफाया हो रहा है. समय के कारण बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं और यही कारण है कि विश्व में अत्यधिक जलवायु परिवर्तन हो रहा है.

फोन और टैबलेट जैसे तकनीकी उत्पाद मानव जाति के लिए अपरिहार्य हो गए हैं वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी के परिणाम-स्वरूप उच्च विकिरण उत्पन्न होता है और इससे जुड़ी निरन्तर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जिससे वातावरण में विकिरण के कारण पक्षियों की विलुप्ति भी होती है.

हालाँकि प्रौद्योगिकी अपने आप में नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है, बल्कि यह तटस्थ है. इसका उपयोग इसे नकारात्मक या सकारात्मक बनाता है. यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने प्रौद्योगिकी को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया है जिसके माध्यम से अगर सकारात्मक दिशा दी जाए तो पर्यावरण कि रक्षा भी कि जा सकती है. उदाहरण के लिए, जन्म नियन्त्रण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को प्रौद्योगिकी का सकारात्मक परिणाम माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या विश्व स्तर पर सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है. ऐसे ही जियोइंजीनियरिंग की एक अन्य तकनीकी अवधारणा ने वायुमण्डल से CO_2 को हटाने और विषाक्त पदार्थों के हानिकारक प्रभावों को कम करने का प्रयास किया है. बायोरेमेडिएशन का कार्यान्वयन एक ऐसी ही खोज है, जो मिट्टी या पानी में धातुओं की विषाक्तता को कम करने के लिए प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है. प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इंटरनेट है, जो लोगों को विश्व स्तर पर जुड़ने में मदद करता है जिससे सूचना का मुक्त प्रवाह होता है और ज्ञान के बारे में जागरूकता बढ़ती है.

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी सभी पर्यावरणीय मुद्दों को ठीक करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन सही ढंग से उपयोग किए जाने पर यह निश्चित रूप से इसकी बेहतरी में योगदान दे सकती है. जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण प्रौद्योगिकी से नहीं, बल्कि उसके कुप्रबन्धन से प्रभावित होते हैं. यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रौद्योगिकी का अनियन्त्रित और अनधिकृत उपयोग पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन अगर सही तरीके से लक्षित किया जाए तो इसमें पर्यावरण को बहाल करने की क्षमता भी है.

(b) हम लोगों के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में नैनोटेक्नोलॉजी के पास असीम सम्भावनाएं हैं. मानव स्वास्थ्य के सन्दर्भ में नैनोटेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए. (36 अंक)

उत्तर—नैनोटेक्नोलॉजी विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है, जो बेहद छोटे उपकरणों और संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण में सहायक होता है. इसके माध्यम से किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलीक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है.

वर्तमान में नैनोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जिसमें विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यावरण

और ऊर्जा भण्डारण, रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी और कृषि शामिल हैं. नैनोटेक्नोलॉजी में उपकरणों का पैमाना 1 से 100 नैनोमीटर (एनएम) के बीच होता है. नैनोमीटर एक मीटर के एक अरबवें हिस्से के बराबर माप की एक बहुत छोटी इकाई है. उदाहरण के लिए, कागज की एक शीट लगभग 1,00,000 नैनोमीटर मोटी होती है.

मानव जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में नैनोटेक्नोलॉजी सहायक—चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल में नैनोमेडिसिन, नैनोटेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इमेजिंग और डायग्नोस्टिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में छोटे और अधिक पोर्टेबल सिस्टम, नैनो-रैम, नैनो ऑप्टोमैकेनिकल एसआरएएम (स्टेटिक रैम), नैनोटेक्नोलॉजी पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में नवाचार से ईंधन उत्पादन और उपयोग की दक्षता में सुधार जैसे सोलर पेंट या फोटोवोल्टिक पेंट-सौर पैनलों की जगह ले सकते हैं. किसी भी सतह पर सोलर पेंट लगाने से वह सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने और उसे बिजली में बदलने में सक्षम हो जाएगा. इसका उपयोग घरों और कारों में किया जा सकता है. पर्यावरणीय दूषित पदार्थों का पता लगाने और उनके समाधान में मदद जैसे नैनोबैटरी रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरियों को लम्बे समय तक चलने में मदद करने के लिए किया जाता है. ऐसे ही कृषि क्षेत्र में नैनो उर्वरक, हाइब्रिड पॉलिमर का उपयोग, नैनोइमल्शन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर आधारित नैनोकण-रोगाणुरोधी एजेण्टों के रूप में उपयोग किया जाता है.

मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग—वर्तमान में नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से सामान्य से लेकर असाध्य रोगों के उपचार और निदान जैसे स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है. स्वास्थ्य देखभाल में नैनोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग से न सिर्फ स्वास्थ्य उपचार आसान बल्कि यह पहले से अधिक परिणामी और सुचारू हुआ है.

उदाहरण के लिए, वर्तमान में अनेक नैनोटेक्नोलॉजी उपकरण जैसे मधुमेह के स्तर को नियन्त्रित करने के लिए मधुमेह पैड, दिल के दौरे के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, धमनियों में प्लाक की जाँच के लिए नैनोचिप्स नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिए नैनोकैरियर आदि का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया है.

वर्तमान में नैनोफाइबर की मदद से भारत में विकलांग आबादी की बड़ी संख्या के लिए कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, ऊतक इंजीनियरिंग और कृत्रिम अंग घटकों में किया जा रहा है. नैनोस्पंज का उपयोग विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और उन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिए किया जा सकता है. ऐसे ही नैनोफ्लेयर्स का उपयोग रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा रहा है. 'स्मार्ट पिल्स' शब्द जो नैनो-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सन्दर्भित करता है इसे फार्मास्युटिकल पिल्स की तरह आकार और डिजाइन किया जा सकता है लेकिन यह सेंसिंग, इमेजिंग और दवा वितरण जैसे अधिक उन्नत कार्य करने में सक्षम होता हैं. भविष्य में नैनोबॉट्स जो सूक्ष्म आकार के रोबोट हैं, लघु सर्जन के रूप में कार्य कर सकते हैं. इनका उपयोग इंट्रासेल्युलर संरचनाओं की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए शरीर में प्रवेश कराया जाता है.

हालाँकि नैनोटेक्नोलॉजी के उपयोग की कुछ चिन्ताएं भी हैं, जैसे मानव शरीर के जैव रासायनिक मार्गों और प्रक्रियाओं पर नैनोकणों के प्रभाव के बारे में उचित जानकारी और विशेषज्ञता का अभाव, महँगी प्रक्रियाएं और उपचार, विषाक्तता और जोखिम के बारे में चिंतित निहित हैं. ●●●

उपकार

गृह रक्षक महानिदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित

दिल्ली होमगार्ड्स (स्वयंसेवक) भर्ती परीक्षा

- सामान्य ज्ञान अभियोग्यता
- गणितीय योग्यता
- तर्कशक्ति परीक्षण

नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित

दिल्ली प्रदेश से सम्बन्धित तथ्यों का विशेष संकलन

नवीनतम समसामयिकी का समावेश

Code 2750
₹ 199.00

डॉ. लाल एवं जैन

उपकार प्रकाशन, आगरा-5
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

उपकार

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

वरिष्ठ निजी सहायक | निजी सहायक | कनिष्ठ न्यायिक सहायक

(टियर-1) भर्ती परीक्षा

नवीनतम करेंट अफेयर्स के साथ

- नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
- अध्यायवार अध्ययन सामग्री
- 'दिल्ली प्रदेश' से सम्बन्धित विशेष प्रश्नों का समावेश
- विषय विशेषज्ञों द्वारा संकलित

डॉ. लाल एवं जैन

Code 2748
₹ 240.00

English Edition
Code 3078 ₹ 260.00

उपकार प्रकाशन, आगरा-5
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

वाणिज्य

1. सीधे वेतन आधारित बिक्री प्रतिकर योजना की हानियाँ निम्नलिखित में से कौनसी हैं ?
   1. बिक्री की मात्रा पर लाभ से अधिक बल दिया जाता है.
   2. बिक्री प्रतिनिधि ग्राहकों को अति संचय करवा सकता है.
   3. अभिप्रेरण प्रभाव कम होता है.
   4. शीर्ष बिक्रीकर्ताओं को आकर्षित करना या बनाए रखना कठिन होता है.
   5. बिक्री प्रतिनिधि उस उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं, जिसके विक्रय में कम प्रयास करना पड़े.

   नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
   (A) केवल 3, 4, 5
   (B) केवल 1, 2, 3
   (C) केवल 2, 4, 5
   (D) केवल 1, 3, 4

2. निम्नलिखित में से कौनसा आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व के अधीन एक अनुषंगी संस्थान है ?
   (A) भारतीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (आईआईबीएम)
   (B) राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (एनआईबीएम)
   (C) भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्थान (आईआईबीएफ)
   (D) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सहायक सेवाएं (आईएफटीएएस)

3. अवबोधन की प्रक्रिया में प्रेरकों के चयन को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक निम्नलिखित में से कौनसा नहीं है ?
   (A) अनुभव
   (B) मेल-जोल (घनिष्ठता)
   (C) पुनरावृत्ति
   (D) विलक्षणता (अनूठापन)

4. किसी प्रश्नावली से 'ऑर्डर बायस' को दूर करने हेतु शोधकर्ता निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग करता है ?
   1. केन्द्रीय प्रश्न
   2. बहुविषयक ग्रिड प्रश्न
   3. वातायन प्रविधि
   4. फिल्टर प्रश्न
   5. संकेतक प्रश्न

   नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
   (A) केवल 2, 5 और 1
   (B) केवल 4, 5, 2
   (C) केवल 5, 2, 3
   (D) केवल 3, 4, 1

5. वह आक्रामक कार्यनीति, जो नए उत्पादों या प्रौद्योगिकियों को आरम्भ करती है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा के नियम पुनः गढ़े जाते हैं तथा प्रतिस्पर्धी के साथ प्रत्यक्ष टकराव का परिहार होता है, उसे कहा जाता है–
   (A) फ्लैंकिंग (B) बाईपास
   (C) एन्सर्किलमेंट (D) गुरिल्ला

6. निम्नलिखित किन परिस्थितियों व दशाओं में क्रेता सावधान का सिद्धान्त लागू होता है ?
   (A) जब वस्तुएं विवरण देने के माध्यम से बेची जाती हैं
   (B) जब वस्तुएं प्रतिदर्श व नमूनों द्वारा बेची जाती हैं
   (C) जब वस्तुएं अन्तर्निहित शर्तों एवं वारंटियों के अन्तर्गत बेची जाती हैं
   (D) जब क्रेता अपने उद्देश्यों के बारे में विक्रेता को सूचित नहीं करता और अपने स्वयं के कौशल एवं निर्णय पर निर्भर रहता है

7. कोई कम्पनी जब वह अपने को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने सम्बन्धी कार्यनीति को बना रही होती है, तो उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले चरण हैं–
   1. कब इसकी शुरूआत (प्रवेश) करना है, इसका निर्णय करना.
   2. किन बाजारों में प्रवेश करना है, इसका निर्णय करना.
   3. वैश्विक स्तर पर स्थापित होना या नहीं होना, इसका निर्णय करना.
   4. प्रवेश के तरीके (साधन) का चुनाव करना.
   5. चुनी हुई बाजार में कैसे प्रवेश पाना है ? इसका निर्णय करना.

   नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–
   (A) 5, 4, 3, 2, 1
   (B) 3, 1, 5, 4, 2
   (C) 3, 2, 1, 5, 4
   (D) 1, 2, 3, 5, 4

8. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

   सूची-I (अवधारणा)
   (a) सतत चालित व्यापार अवधारणा
   (b) समरूपता
   (c) लागत संकल्पना
   (d) भौतिकता

   सूची-II (उद्देश्य/प्रयोग)
   1. एक अवधि से दूसरी अवधि की एक फर्म द्वारा सामान लेखाकरण.
   2. किसी एक मद या घटना के सापेक्षित आकार या महत्व से सम्बन्ध स्थापित कराना.
   3. एक व्यावसायिक इकाई के दिवालिया होने की एक अनुपयुक्त अवधारणा.
   4. परिसम्पत्तियों के लिए लेखा हेतु प्रयुक्त सामान्य आधार.

   निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	4	1
(B)	1	2	3	4
(C)	1	2	4	3
(D)	3	1	4	2

9. निम्नलिखित में से किसी वस्तु की माँग में वृद्धि के कौनसे कारण हैं ?
   1. उपभोक्ता की आय में वृद्धि.
   2. स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि.
   3. सम्पूरकों के मूल्य में वृद्धि.
   4. स्थानापन्न वस्तुओं की संख्या में वृद्धि.
   5. पण्य वस्तुओं की पसन्द में वृद्धि.

   नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
   (A) केवल 1, 2 और 3
   (B) केवल 3, 4 और 5
   (C) केवल 2, 4 और 5
   (D) केवल 1, 2 और 5

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं. एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

    अभिकथन (A) : सामान्यतः विनिर्माता कम्पनियाँ विक्रय एवं पट्टा बैंक व्यवस्था का प्रयोग स्थायी परिसम्पत्तियों में किए जाने वाले निवेश को मुक्त करने हेतु करती हैं.

कारण (R) : विक्रय एवं पट्टा व्यवस्थाओं में कम्पनियाँ किसी परिसम्पत्ति का विक्रय पट्टा देने वाली कम्पनी को कर देती है और अपने व्यवसाय में परिसम्पत्ति का निर्बाध रूप से प्रयोग करके लाभ उठाने हेतु पुनः इसे पट्टा पर ले लेती हैं.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

11. निम्नलिखित में से किन बाजार संरचनाओं में उत्पाद विभेदीकृत और अत्यधिक स्थानापन्न होते हैं ?
1. पूर्ण प्रतिस्पर्धा
2. एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा
3. अल्पाधिकार
4. द्वयाधिकार
5. एकाधिकार

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 3 और 4

12. नीचे दो कथन दिए गए हैं. एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : संभार तन्त्र प्रबन्धन का एकमात्र उद्देश्य फैक्ट्री से ग्राहकों को प्रस्तुत किए जा रहे उत्पादों सम्बन्धी कार्यकलापों को समन्वित करना.

कारण (R) : संभार तन्त्र प्रबन्धन विपणन कार्य का एकमात्र उत्तरदायित्व है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अभिशासन हेतु वैधानिक/विधिक रूप-रेखा कौनसे हैं ?
1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976.
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1966.
3. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989.
4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949.
5. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932.

नीचे दिए गए विकल्पों मे से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 5

14. निम्नलिखित नियामक नैतिक सिद्धान्तों में से किसमें नैतिक निर्णयन के विचारण के रूप में 'निर्णय से निवक लाभ' पाया जाता है ?

(A) कर्तव्य नीति
(B) न्याय सिद्धान्त
(C) अंशधारक नीति
(D) उपयोगितावाद

15. दो चरों की स्थिति में प्राक्कलित (आकलित) समाश्रयण समीकरण $y = 60 + 5x$ है. वर्गों का कुल योग 15730 है और त्रुटि के कारण वर्ग का योग 1530 हो गया है. इस जानकारी के आधार पर आकलित समाश्रायण एक ..... होता है.

(A) पुअरेस्ट फिट (सर्वाधिक कम उपयुक्त)
(B) मॉमरेड फिट (संयत उपयुक्त)
(C) गुड फिट (पर्याप्त उपयुक्त)
(D) बेस्ट फिट (सर्वाधिक उपयुक्त)

16. आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत बन्द होने या जारी रखने का निर्णय के मामले में उपयुक्त कर योजना दृष्टिकोण योजना कौनसी है ?
1. व्यावसायिक हानि और गैर-समायोजित ह्रास को अग्रसारित किया जाता है और लाभ तथा हानि के साथ समायोजित किया जा सकता है.
2. हानिग्रस्त कम्पनी और लाभकारी कम्पनी का कर लाभ प्राप्त करने हेतु एक साथ विलय किया जा सकता है.
3. व्यवसाय बन्द किया जाता है, जिस वर्ष में उस वर्ष के लिए 33AB और 115VT धारा के अन्तर्गत कटौती का लाभ वापस लिया जा सकता है, उसे कर योग्य माना जा सकता है.
4. अधिनियम की धारा 80IB/80IC शर्त के अन्तर्गत ऐसे उपक्रम को कटौती स्वीकृत की जाती है.
5. एक व्यक्ति के पास एक से अधिक व्यवसाय है, तो हानि जनित व्यवसाय को बन्द नहीं किया जा सकता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 4, 5
(C) केवल 3, 4, 5
(D) केवल 1, 3, 5

17. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (रिटेल स्टोर प्रारूप)

(a) डिस्काउंट (b) स्पेशियलिटी
(c) कैटगरी किलर (d) सुपर मार्केट

सूची-II (उत्पाद वर्गीकरण)

1. बहुत सँकरा एवं गहरा
2. चौड़ा एवं उथला
3. चौड़ा एवं गहरा
4. सँकरा एवं बहुत गहरा

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	1	3	4
(B)	1	2	3	4
(C)	4	2	3	1
(D)	2	1	4	3

18. निम्नलिखित में से कौनसे मूल्य ओक्टोपस (OCTAPACE) ढाँचे के भाग नहीं हैं ?

(A) खुलापन
(B) प्रसार
(C) अग्रलक्षिता (पूर्वपहल)
(D) स्वायत्तता

19. बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौनसा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है ?

(A) पूर्ण प्रतिस्पर्धा
(B) एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा
(C) अल्पाधिकार
(D) द्वयाधिकार

20. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I

(a) पूलिंग (पूलन)
(b) वित्तीय प्रतिरक्षण

(c) प्राकृतिक प्रतिरक्षण
(d) नेटिंग

सूची-II

1. अनेक देशों में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना.
2. ऋण देने एवं परिवेष्ठ (लैगिंग) के माध्यम से विदेश विनिमय जोखिम में कमी करना.
3. दो अलग-अलग देशों की मुद्रा में समकालिक उधारी का ऋण.
4. सम्बन्धितों द्वारा नकदी का प्रतिरक्षण एवं प्रबन्ध.

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	2	3
(B)	4	3	1	2
(C)	4	2	3	1
(D)	1	2	3	4

21. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण देशों के मध्य होने वाले व्यापार एवं निवेश से मुक्त प्रवाह से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने का एक प्रयास है. इसी प्रकार का एक सह संघ (एसोसिएशन) एनएएफटीए है. नाफ्टा (एनएएफटीए) में निम्नलिखित कौनसे देश सम्मिलित हैं ?
(A) यूएसए, कनाडा, मैक्सिको
(B) यूएसए, कनाडा, ब्राजील
(C) यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील
(D) कनाडा, मैक्सिको, पनामा

22. किसी जनसंख्या का माध्य 200 एवं मानक विचलन 50 है. मान लीजिए कि 100 के आकार वाले एक साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, तब उस प्रतिदर्श के माध्य की जनसंख्या माध्य के ± 5 होने की क्या सम्भावना है ?
(A) 0·7523
(B) 0·6928
(C) 0·9544
(D) 0·6826

23. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (अनुवर्ती परिणाम)

(a) व्यक्ति अर्थदण्ड और अभियोजन के अधीन होता है.
(b) कानून की कमजोरियों का लाभ उठाकर कर कम किया जाता है.
(c) मुख्य उद्देश्य कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करता है.
(d) यह निर्णय कार्य में एक मार्गदर्शक है.

सूची-II (कराधान दृष्टिकोण)

1. कर प्रबन्धन 2. कर परिहार
3. कर अपवंचन 4. कर योजना

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	4	1
(B)	2	4	3	1
(C)	3	2	1	4
(D)	3	1	4	2

24. सर्वाधिकारवाद जिसे सत्तावाद (प्राधिकारवाद) भी कहा जाता है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक समूह अथवा राज्य के (प्राधिकार) की शक्ति के अधीन होती है. निम्नलिखित में से कौनसा एक सर्वाधिकारवाद का एक प्रकार नहीं है ?
(A) धर्मशासित (B) दक्षिणपंथी
(C) जनजातीय (D) रूढ़िवादी

25. ग्राहकों के सन्दर्भ में नैतिक एवं सामाजिक सरोकार से सम्बन्धित क्षेत्र कौनसे हैं ?
1. उत्पाद सुरक्षा
2. उचित मूल्य
3. उचित वेतन (मजदूरी)
4. टीक्यूएम
5. समुचित प्रकटीकरण एवं सूचना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 3 और 4
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1 और 5
(D) केवल 1, 2 और 5

26. नीचे दो कथन दिए गए हैं. एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : जब एक साझेदार सेवानिवृत्त होता है, तो वर्तमान मूल्य के अनुसार सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है.

कारण (R) : तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं के सही मूल्यों को दिखाना चाहिए.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है
(D) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

27. क्रय शक्ति समता सिद्धान्त की पूर्वधारणाओं में शामिल किया जाता है–
1. किसी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तन करने पर कोई शुल्क नहीं (लागत रहित) लगाया जाता है.
2. पूँजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है.
3. वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है.
4. वित्तीय प्रतिभूति के क्रय एवं विक्रय पर किसी प्रकार का लेन-देन शुल्क नहीं लगाया जाता है.
5. किसी एक देश से दूसरे देश में वस्तु के परिवहन पर कोई लागत नहीं आती है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 4, 3
(C) केवल 5, 1, 3
(D) केवल 4, 1, 5

28. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (प्रयोजन)

(a) इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (ईएफटी) के सभी पहलुओं का अध्ययन करना
(b) एनबीएससी पर कार्य समूह
(c) ऋण उधार की वैकल्पिक विधियों पर सुझाव देना
(d) विदेशी विनिमय बाजार पर विशेषज्ञ समूह

सूची-II (समिति)

1. राशिद जिलानी समिति (1994)
2. सोधानी समिति (1994)
3. मालेगाँव समिति (1995)
4. शेरे समिति (1995)

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	1	2	4
(B)	2	1	3	4
(C)	1	3	2	4
(D)	4	3	1	2

29. अन्तःक्षेपी मुद्रा अग्रलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होता है ?

(A) वह मुद्रा जिसका चयन निर्यातकर्ता अपने द्वारा किए जाने वाले निर्यात सम्बन्धी बीजक तैयार करने हेतु करता है.

(B) वह मुद्रा जिसमें सीमा-पार (विदेशी) के संव्यवहारों का भुगतान किया जाता है.

(C) वह मुद्रा जिसके सन्दर्भ में घरेलू मुद्रा उद्धरित की जाती है.

(D) संव्यवहार वाहक मुद्रा.

30. एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी निम्न कर प्रणाली में लाभ और उच्च कर प्रणाली में हानि बनाने हेतु किस कीमत का प्रयोग करती है ?

(A) विभाजनात्मक कीमत

(B) अन्तर विभाजनात्मक कीमत

(C) नियन्त्रक कम्पनी कीमत

(D) स्थानान्तरण कीमत

31. जब कोई कर्मचारी किसी संगठन को छोड़ता है, तो नियुक्ति सम्बन्धी पण्यावर्त लागत निम्नलिखित में से कौनसी है ?

(A) विज्ञापन

(B) साक्षात्कार

(C) प्रशिक्षण

(D) नियोक्ता शुल्क

32. भारत की मुद्रा बाजार को विकसित करने के लिए उठाए गए सोपानों को सर्वप्रथम से अद्यतन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

1. ब्याज दर स्वैट्स (आईआरएस) का आरम्भ.
2. वाणिज्यिक पत्र का आरम्भ.
3. बैंक दर से सम्बद्ध वे एण्ड मीन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) का आरम्भ.
4. लिक्विडिटी एडजेस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) का आरम्भ.
5. रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) का क्रियान्वयन.

नीचे दिए गए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 3, 2, 4, 1, 5

(B) 4, 3, 2, 5, 1

(C) 2, 4, 3, 1, 5

(D) 2, 3, 4, 1, 5

33. वास्तविक जगत में सामान्यतः स्थानापन्न प्रभाव आय प्रभाव की अपेक्षा व्यापक होता है, क्योंकि–

(A) उपभोक्ता सामान्यतः अपनी आय का अल्पांश मात्र किसी एक पण्यवस्तु पर खर्च करता है

(B) उपभोक्ता प्रायः पण्य वस्तुओं की अल्पमात्रा का उपभोग करता है

(C) उपभोक्ता अपनी आय का अल्पांश ही उपभोग पर खर्च करता है

(D) उपभोक्ता की आय सापेक्षित रूप से उपभोग से कम ही होती है

34. निम्नलिखित किन सन्दर्भों में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम में नया संशोधन किया था ?

1. विलय अथवा अधिग्रहण की राशि यदि ₹ 2,000 करोड़ से अधिक की है, तो सीसीआई को सूचित किया जाने की आवश्यकता होगी.
2. संयोजन के मूल्य के निर्धारण हेतु समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटकर 150 दिन कर दिया गया है.
3. 'अनन्य विक्रय करार' को 'अनन्य सौदेबाजी करार' से प्रतिस्थापित किया गया है.
4. वे प्रतिष्ठान, जोकि समरूप अथवा समान व्यापार में संलग्न नहीं हैं. वे भी अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा विरोधी करार के भाग माने जाएंगे.
5. 'टाई-अप करारों' पुनर्बिक्री मूल्य अनुरक्षण और 'अनन्य विवरण करार' जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को पुनर्परिभाषित किया गया है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2 और 3

(B) केवल 3 और 5

(C) केवल 1, 2, 3 और 4

(D) केवल 1, 2, 3, 4 और 5

35. शोध अभिकल्प में प्रायोगिक निरूपण (निदान) निम्नलिखित में से किसके बारे में सूचित करता है ?

(A) आश्रित चर का चयन

(B) स्वतंत्र चर को परिभाषित करना

(C) स्वतंत्र चर का चयन

(D) आश्रित चयन को प्रभावित करना

36. एक बिन्दु प्राक्कलनकर्ता को तब संगत माना जाता है, जब.....

(A) इसमें लघुत्व (कम-से-कम) मानक त्रुटि हो.

(B) इसका अपेक्षित मूल्य (मान), जनसंख्या मानदण्ड के बराबर होता है.

(C) जैसे-जैसे प्रतिदर्श आकार बड़ा होता है, यह जनसंख्या मानदण्ड के करीब (निकट) होने की ओर प्रवृत्त होता है.

(D) यह सभी प्रकार की उपलब्ध जानकारी (सूचना) पर आधारित होता है.

37. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (हरफिन्डाल सूचकांक मान)

(a) 0

(b) 0-1,000

(c) 1,000-1,800

(d) 1,800-10,000

सूची-II (बाजार का प्रकार)

1. उत्पाद संघ के उच्च जोखिम सहित अल्पाधिकार
2. अल्पाधिकार
3. एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा
4. अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	4	3	2	1
(C)	2	1	3	4
(D)	1	3	2	4

38. 'A' एक मोबाइल नाबालिक 'B' को बेचता है, जोकि इसका भुगतान चेक द्वारा करता है. 'A' चेक को 'C' के लिए पृष्ठांकित कर देता है, जो इसे विश्वास व मूल्य के रूप में लेता है और चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है. क्या 'C' चेक के भुगतान के लिए बाध्य (लागू करना) कर सकता है ?

(A) 'C' चेक भुगतान के लिए केवल 'A' को बाध्य कर सकता है.

(B) 'C' चेक के भुगतान के लिए 'A' अथवा 'B' को बाध्य कर सकता है.

(C) 'C' चेक के भुगतान हेतु 'A' और 'B' दोनों को बाध्य कर सकता है.

(D) 'C' चेक भुगतान के लिए केवल 'B' को बाध्य कर सकता है.

39. परिचालन दृष्टिकोण से पर्यावरणीय लेखा परीक्षा के भाग निम्नलिखित में से कौनसे हैं ?

1. पर्यावरण प्रबन्धन तंत्र अंकेक्षण
2. सामाजिक अंकेक्षण
3. अनुपालन अंकेक्षण
4. स्थल सम्पत्ति अंकेक्षण
5. ऊर्जा अंकेक्षण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 3, 4, 5

(B) केवल 1, 3, 4
(C) केवल 2, 3, 4
(D) केवल 1, 4, 5

40. सामान्य परिभाषा प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित किए जाते हैं. उन्हें तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–
1. विश्लेषण की इकाई निर्धारित करना.
2. प्रासंगिक चरों को निर्धारित करना.
3. प्रबन्धकीय निर्णय विवरण (कथनों) एवं शोध उद्देश्य को लिखना.
4. शोध प्रश्नों और/शोध प्राक्कल्पना को लिखना.
5. मुख्य समस्याओं की पहचान करना.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) 1, 2, 5, 4, 3 (B) 3, 4, 1, 2, 5
(C) 2, 5, 1, 3, 4 (D) 5, 3, 1, 2, 4

41. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–
सूची-I (संगठन में मानव व्यवहार का उद्देश्य)
(a) उपलब्धि (b) नियन्त्रण
(c) प्रसार (d) निर्भर
सूची-II (विशेषता)
1. दूसरों के लिए सरोकार
2. स्वविकास के लिए सरोकार
3. उत्कृष्टता के लिए सरोकार
4. सुव्यवस्था के लिए सरोकार
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	2	1
(B)	4	3	2	1
(C)	2	4	1	3
(D)	3	4	1	2

42. किसी कम्पनी द्वारा कीमत लक्ष्य निर्धारित कर उस कीमत पर कम्पनी द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पाद का निर्माण ..... कहलाता है.
(A) प्रतिष्ठा कीमत निर्धारण
(B) स्तरीय कीमत निर्धारण (प्राइस लाइनिंग)
(C) कीमत सुमेलन
(D) मूल्य कीमत निर्धारण

43. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–
सूची-I (एटी कर्णी वैश्वीकरण सूचकांक)
(a) आर्थिक एकीकरण
(b) निजी (व्यक्तिगत) एकीकरण
(c) प्रौद्योगिकीय एकीकरण
(d) राजनीतिक एकीकरण
सूची-II (चर)
1. अन्तर्राष्ट्रीय टूरिज्म एवं ट्रेवल
2. इंटरनेट प्रयोक्ता
3. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
4. बहुपक्षीय संधियों का अनुसमर्थन
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	2	1
(B)	3	1	2	4
(C)	3	2	1	4
(D)	4	1	2	3

44. निम्नलिखित देशों का कौनसा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं ?
(A) लाओस, कम्बोडिया, ब्रूनेई
(B) मलेशिया, थाइलैण्ड, ताइवान
(C) म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग
(D) फिजी, लाओस, कम्बोडिया

45. निम्नलिखित में से कौनसे आरबीआई द्वारा अधिसूचना घरेलू प्रत्यार्पित साख दर निर्धारण अभिकरण हैं ?
1. ब्रिकवर्क रेटिंग्स
2. सक्रिय दर निर्धारण (रेटिंग)
3. सीआरआईएसआईएल रेटिंग्स
4. स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स
5. मूडीज
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 3 और 5

46. यदि सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो CPIO/SPIO का सूचना (जानकारी) प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित क्या-क्या प्रस्तुत करने का वैधानिक कर्तव्य है ?
1. सूचना आयुक्त की शक्तियाँ एवं कार्य.
2. आवेदन अस्वीकार करने का कारण.
3. लोक प्राधिकारियों के वैधानिक कर्तव्य.
4. अपीलकर्ता प्राधिकारी सम्बन्धी विवरण.
5. इस प्रकार के अस्वीकरण के विरुद्ध अपील करने हेतु वरीय अवधि.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 3 और 5
(D) केवल 2, 4 और 5

47. एक विश्वविद्यालय में X को दिनांक 1 जुलाई, 2022 को प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया. उसको 30 अप्रैल, 2023 को स्थायी किया गया. वर्ष 2023-24 के कर निर्धारित हेतु पूर्व वर्ष की अवधि क्या होगी ?
(A) 1 जुलाई, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक
(B) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक
(C) 1 अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक
(D) 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक

48. भारत में विदेशी व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) विदेशी व्यापार को सरल बनाता है एवं उसे प्रोत्साहित करता है एवं भारत की विदेश व्यापार नीति को भी क्रियान्वित करता है. डीजीएफटी भारत सरकार के किस मंत्रालय से शासित होता है ?
(A) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(B) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(C) वित्त मंत्रालय
(D) विदेश मंत्रालय

49. भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने (धारिता) में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा-जोखा किया जाता है ?
(A) चालू खाता
(B) पूँजी खाता
(C) शासकीय (ऑफिसियल) आरक्षित खाता
(D) विदेशी विनिमय खाता

50. निम्नलिखित में से किस खण्डीकरण मानदण्डों में उपभोक्ता के चयन सम्बन्धी व्यवहार की पूर्वानुमेयता सर्वाधिक होती है ?
(A) मनोवैज्ञानिक
(B) जनांकिकीय
(C) व्यवहारपरक
(D) भूजनांकिकीय

51. किसी आँकड़ा समुच्चय में बहिर्वर्तियों की विद्यमानता की स्थिति में निम्न-लिखित में से कौनसी केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन ठीक से कर सकता है ?
1. बहुलक
2. ट्रिम्ड (सुव्यवस्थित) माध्य
3. अंकगणितीय माध्य
4. माध्यिका
5. हरात्मक माध्य

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2
(B) केवल 2, 3
(C) केवल 3, 5
(D) केवल 2, 4

52. निम्नलिखित सूचना के आधार पर नियोजित कुल पूँजी पर प्राप्तियों की गणना कीजिए–

शुद्ध लाभ	₹ 1,00,000
कर हेतु उपबन्ध	₹ 1,00,000
निवेश से आय	₹ 10,000
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	₹ 4,50,000
चालू परिसम्पत्तियाँ	₹ 1,50,000
डिबेंचर पर ब्याज	₹ 10,000
आरक्षित निधि	₹ 1,00,000

(A) 30% (B) 50%
(C) 60% (D) 40%

53. किसी फर्म के इष्टतम पूँजी बजट को किस प्रतिच्छेद बिन्दु द्वारा दर्शाया जाता है ?

(A) प्रतिभूति बाजार रेखा और पूँजी बाजार रेखा
(B) पूँजी वक्र का भारित औसत लागत और पूँजी वक्र का सीमान्त लागत
(C) निवेश अवसर वक्र और पूँजी का सीमान्त लागत
(D) पूँजी वक्र का भारित औसत लागत और निवेश अवसर वक्र

54. कोई बॉक्स प्लाट एक ग्राफिकल (आलेखीय) सारांश है, जिससे आँकड़ों को मापा जाता है–

1. माध्य 2. Q_1
3. माध्यिका 4. Q_3
5. बहुलक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 3, 5
(B) केवल 1, 3, 5
(C) केवल 3, 4, 2
(D) केवल 4, 2, 1

55. प्रक्रिया लागत के सोपानों को आरम्भ से तथा प्रक्रियाधीन इन्वेन्ट्री पर समाप्ति के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–

1. कुल लागत का सार में प्रक्रिया मालसूची का वर्णन प्रस्तुत करना.
2. समतुल्य इकाई के सन्दर्भ में उत्पाद की गणना करना.
3. प्रति समतुल्य इकाई लागत की गणना करना.
4. भौतिक इकाइयों (उत्पाद) के प्रवाह का सार प्रस्तुत करना.
5. कार्य पूर्ण करने वाली इकाइयों और समाप्ति प्रक्रियाधीन इकाइयों के लिए कुल लागत निर्दिष्ट करना.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 4, 2, 1, 3, 5
(B) 2, 3, 4, 1, 5
(C) 3, 2, 1, 4, 5
(D) 5, 4, 1, 2, 3

56. बैंकिंग क्षेत्र के सन्दर्भ में स्प्रेड को निम्नलिखित में से किन कार्यकलाओं के रूप में परिभाषित किया गया है ?

1. फॉरेक्स
2. निवल ब्याज आय
3. दर संवेदी परिसम्पत्ति
4. परिसम्पत्ति अनुपात
5. उत्तोलन अनुपात

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 3 और 5
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 4
(D) केवल 2 और 5

57. यह मत किसने दिया कि "श्रमिक सम्पत्ति के जनक थे और इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति के किसी भी आकलन में शामिल करना चाहिए" ?

(A) विलियम फार
(B) विलियम पेट्टी
(C) विलियम सी. पाइल
(D) फ्लेम होल्टज

58. पर्याप्त रूप से मुद्रांकित एवं विधिवत् सम्बोधित किए गए एक स्वीकृत पत्र को प्रेषण हेतु भेजा जाता है, जहाँ .....

(A) स्वीकर्ता के वरण पर संविदा शून्यकरणीय है.
(B) प्रस्तावकर्ता के वरण पर संविदा शून्यकरणीय है.
(C) कोई संविदा नहीं है.
(D) एक वैध संविदा है.

59. निम्नलिखित किन परिस्थितियों/दशाओं में कोई एजेंट (अभिकर्ता) तीसरे पक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ?

1. यदि कोई गुप्त (अप्रकट) नियोक्ता के लिए कार्य करता है.
2. व्यापार व्यवहार एवं सम्बन्धित प्रथाएं एजेंट को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाती हैं.
3. यदि कोई एजेंट नियोक्ता के नाम से संविदा पर हस्ताक्षर करता है.
4. यदि कोई एजेंट नामित नियोक्ता के लिए कार्य करता है.
5. यदि कोई एजेंट विदेशी नियोक्ता के लिए कार्य करता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 1, 2 और 5
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 2, 3 और 4

60. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित अग्रिम कर भुगतान को आरोही क्रम (धारा 207 से धारा 211) में क्रमबद्ध कीजिए–

1. अग्रिम कर की किश्त और देय तिथि.
2. अग्रिम कर के भुगतान हेतु देयता.
3. निर्धारिती के स्वयं के दस्तावेज/रिकॉर्ड द्वारा अग्रिम कर भुगतान.
4. अग्रिम कर के भुगतान हेतु देयता की शर्त.
5. अग्रिम कर की संगणना.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 1, 2, 3, 4, 5
(B) 2, 4, 5, 3, 1
(C) 2, 4, 5, 1, 3
(D) 3, 4, 5, 1, 2

61. यूरो मुद्रा बाजार की निम्नलिखित कौनसी विशेषताएं हैं ?

1. यूरो मुद्रा बाजार की भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं.
2. यूरो मुद्रा बाजार विनियमित होती है.
3. यूरो मुद्रा बाजार में जमा-बीमा नहीं होता है.
4. अधिकतम ब्याज देय अथवा प्रभार्य करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है.
5. यूरो मुद्रा बाजार सीआरआर एवं एसएलआर प्रतिबन्ध लागू नहीं होते हैं.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 5, 4
(C) केवल 5, 3, 1
(D) केवल 4, 1, 5

62. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (गैर-प्राचलिक परीक्षण प्राचलिक परीक्षण का प्रतिस्थानी)

(a) फ्रीडमैन परीक्षण
(b) मॉन-ह्विटनी U परीक्षण
(c) क्रुस्कल-वालिस परीक्षण
(d) विलकॉक्सन साइन्ड रैंक परीक्षण

सूची-II (प्राचलिक परीक्षण)

1. एक दिशीय एनोवा
2. t-परीक्षण
3. युग्मित t-परीक्षण
4. द्वि-दिशीय एनोवा

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	3	4	2
(B)	4	2	1	3
(C)	3	1	2	4
(D)	2	4	3	1

63. पराकर्म प्रपत्र को नकारने हेतु वसूली अधिकार में आने वाले निम्नलिखित चरणों (सोपानों) को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–
1. निकराई (नोटिंग)
2. मुआवजा (प्रतिकार)
3. नकार-प्रमाणन
4. अस्वीकार करने सम्बन्धी नोटिस
5. शास्तियाँ (अर्थदण्ड)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) 4, 1, 3, 2, 5
(B) 3, 4, 1, 2, 5
(C) 3, 4, 5, 2, 1
(D) 1, 3, 4, 2, 5

64. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए–

सूची-I (कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुसूचियाँ)

(a) अनुसूची-I
(b) अनुसूची-II
(c) अनुसूची-III
(d) अनुसूची-IV

सूची-II (अन्तर्निहित विषय)

1. मूल्य ह्रास का परिकलन
2. स्वतंत्र निदेशकों हेतु नियमावली
3. संस्थापन प्रलेख
4. तुलन-पत्र को तैयार करना और लाभ एवं हानि सम्बन्धी विवरण को तैयार करना

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	1	4	3
(B)	3	1	4	2
(C)	3	4	1	2
(D)	1	3	2	4

65. अग्रलिखित में से कौनसी निजी एक्विटी और उद्यम पूँजी की असामान्य विशेषता है ?
(A) दोनों उन कम्पनियों में निवेश करते हैं, जो पब्लिक से पूँजी प्राप्त करने अथवा जुटाने में सक्षम नहीं है
(B) उनके निवेश का उपयोग निवेशीय कम्पनियों के वित्तीय अथवा पुनर्संरचना के प्रचालन के लिए होता है
(C) उच्च निवल मालियत वाली संस्थाओं द्वारा पूँजी अंशदान के स्वतंत्र पूल द्वारा उनकी स्थापना होती है
(D) उनके कार्य कतिपय नियमों द्वारा नियमित होते हैं

66. अनुभवाश्रित अध्ययनों से इंगित होता है कि दीर्घकालिक औसत लागत (एलएसी) वक्र का आकार होता है–
(A) L-आकार (B) U-आकार
(C) S-आकार (D) V-आकार

67. निम्नलिखित में से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह को प्रभावित करने वाले आपूर्ति कारकों (घटकों) के रूप में माना जाता है ?
1. ग्राहक पहुँच (सुगम्यता)
2. आर्थिक वरीयताएं
3. संसाधन उपलब्धता
4. व्यापार बाधाओं का परिहार
5. लॉजिस्टिक

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 4
(C) केवल 3 और 5
(D) केवल 1 और 5

68. निर्माताओं एवं खुदरा व्यापारियों के लिए अपनी पेशकश की ब्रैंड करने के कारण निम्नलिखित में से कौनसे हैं ?
1. उत्पाद की गुणवत्ता के स्तर को मापने में सहायक होता है.
2. प्रीमियम कीमत निर्धारण में समर्थ बनाता है.
3. कॉर्पोरेट पहचान कार्यक्रमों में सहायक होता है.
4. किसी उत्पाद के स्रोत के सन्दर्भ में सूचना प्रदान करता है.
5. ग्राहक की निष्ठा को विकसित करता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1, 2, 3, 5
(B) केवल 2, 3, 5
(C) केवल 1, 2, 3, 4
(D) केवल 1, 4, 5

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन-I : निगमन का प्रमाण-पत्र एक निर्णायक साक्ष्य है, जिसमें पंजीकरण के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन हुआ है.
कथन-II : निगमन के बाद यदि कम्पनी पूर्व-निगमन संविदा के सन्दर्भ में एक नई संविदा करती है, तो प्रवर्तकों की देयता समाप्त हो जाएगी.
उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) कथन I और II दोनों सत्य हैं
(B) कथन I और II दोनों असत्य हैं
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है

70. एक वर्ष के दौरान इक्विटी स्टॉक का आय प्रतिफल 12·5 रहा. उस वर्ष मुद्रास्फीति की दर 3·5 थी. वास्तविक (मुद्रास्फीति-समायोजित) प्रतिफल था–
(A) 9·26 प्रतिशत
(B) 16·00 प्रतिशत
(C) 7·65 प्रतिशत
(D) 8·70 प्रतिशत

71. जब एक अवयस्क बच्चे की आय को माता या पिता की आय में सम्मिलित किया जाता है, तो माता या पिता को कितनी कटौती की अनुमति होगी ?
(A) ₹ 1,500
(B) ₹ 2,000
(C) माता या पिता की आय के साथ सम्मिलित वास्तविक आय में जो कम हो
(D) कोई कटौती नहीं

72. प्रतियोगी बाजारों के सिद्धान्त के अनुसार यहाँ तक कि कुछ विक्रेताओं के मध्य प्रबल प्रतिस्पर्धा हो सकती है. यदि ····· और ·····
1. उत्पाद विभेदीकृत होता है
2. माँग में अधिक लोच होती है
3. बाजार में प्रवेश पूर्ण निःशुल्क होता है
4. मजबूत प्रवेश निकास अवरोध होता है
5. बाजार से निकास पूर्णतः लागत रहित होता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 5
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 3 और 5

73. एसईआरवीक्यूएएल (SERVQUAL) उपागम के अनुसार अग्रलिखित सेवा-अंतरालों को तर्कसंगत अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए–

1. सेवा सम्बन्धी गुणवत्ता विनिर्देशन एवं सेवा सुपुर्दगी के मध्य अन्तराल.
2. ग्राहक की अपेक्षाओं एवं प्रबन्धकीय प्रत्यज्ञ ज्ञान (अवबोधन) के मध्य अन्तराल.
3. अनुभूत सेवा एवं अपेक्षित सेवा के मध्य अन्तराल.
4. प्रबन्धकीय प्रत्यक्ष ज्ञान एवं सेवा सम्बन्धी गुणवत्ता विनिर्देशन के मध्य अन्तराल.
5. सेवा सुपुर्दगी एवं बाह्य सम्प्रेषण के मध्य अन्तराल.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 4, 1, 2, 5, 3
(B) 2, 4, 1, 5, 3
(C) 1, 3, 2, 4, 5
(D) 3, 1, 2, 5, 4

74. किसी नाबालिक को बालिग होने वाली उम्र पार कर लेने के पश्चात् उस नाबालिग द्वारा किया गया करार.....

(A) उसके द्वारा अनुसमर्थित किया जा सकता है.
(B) उसके द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया जा सकता है.
(C) शून्य हो जाता है.
(D) वैध हो जाता है.

75. A और B बराबर के साझेदार हैं, जब साझेदारी समाप्त होती है, तो उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 40,000 और ₹ 50,000 है. सभी परिसम्पत्तियों के विक्रय एवं देयताओं के भुगतान के पश्चात् ₹ 80,000 रोकड़ शेष बचता है, तो प्रापण पर कितनी धनराशि का लाभ या हानि होती है ?

(A) ₹ 10,000 (लाभ)
(B) ₹ 20,000 (लाभ)
(C) ₹ 30,000 (लाभ)
(D) ₹ 10,000 (हानि)

76. उपभोक्ता प्रचार हेतु साधन निम्नलिखित में से कौनसे हैं ?

1. प्राइस ऑफ
2. रिफंड
3. कूपन
4. इवेंट स्पॉन्सरशिप
5. ऑफ इन्वायस

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4, 5
(C) केवल 1, 4, 5
(D) केवल 2, 3, 4

77. कृषि आय के लिए कौनसा सही है ?

1. स्वयं द्वारा उगाए गए घास वृक्ष और बाँस से आय
2. भूमि से व्युत्पन्न किराया व आय
3. बाजार के अनुकूल उत्पाद बनाने से आय
4. कृषि उत्पाद के भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि से आय
5. फार्म हाउस से आय

नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 2, 3, 5
(B) केवल 2, 4, 5
(C) केवल 1, 3, 4
(D) केवल 3, 4, 5

78. कोलिन्स द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित नेतृत्व स्तरों को कालानुक्रम के उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

1. नेतृत्वकर्ता सक्षम प्रबन्धक होता है.
2. नेतृत्वकर्ता कार्यकारी अधिकारी होता है.
3. नेतृत्वकर्ता अत्यधिक समर्थ व्यक्ति होता है.
4. नेतृत्वकर्ता एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता होता है.
5. नेतृत्वकर्ता टीम सदस्य (संभागी) के रूप में कार्य करने वाला होता है.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 2, 3, 4, 1, 5
(B) 3, 5, 1, 4, 2
(C) 3, 1, 5, 4, 2
(D) 3, 5, 1, 2, 4

79. भारत में म्यूचुअल फण्ड का विनियमन कौन करता है ?

(A) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया
(B) उद्योग और आन्तरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग
(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(D) वित्तीय सेवा विभाग

80. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : राष्ट्रीय बाजारों के मध्य की बाधाओं को दूर करके व्यापार समूह (खण्ड) अधिक बड़े व्यापार क्षेत्र के कारण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न (सृजित) करते हैं.

कारण (R) : बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, स्थानीय उद्योगों के समापन (बन्द हो जाने) की ओर अग्रसित करती है एवं घरेलू उपभोग को नुकसान पहुँचाता है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है
(D) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है

81. परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (सरफॉसी अधिनियम, 2012 के अनुसार) के कार्यकलापों के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए–

1. 2 प्रतिशत प्रबन्धन शुल्क प्रभारित (लगाती) करती हैं.
2. बैंक को प्रतिभूति प्राप्तियाँ निर्गमित करती हैं.
3. बैंक को भुगतान करती हैं.
4. बैंक को छूट पर ऋण प्राप्त करती हैं.
5. प्रतिलाभ (वसूली) क्रियान्वित करती हैं.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 4, 3, 1, 5, 2
(B) 4, 2, 5, 1, 3
(C) 4, 2, 3, 5, 1
(D) 4, 1, 2, 5, 3

82. निम्नलिखित वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग को उल्लेखनीय आय लोच के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

1. सामान्य उपभोग सेवाएं
2. आवश्यक वस्तुएं
3. विलास वस्तुएं
4. निम्नस्तरीय वस्तुएं
5. सेवाएं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) 4, 2, 1, 5, 3
(B) 4, 3, 2, 1, 5
(C) 3, 5, 2, 1, 4
(D) 2, 1, 4, 3, 5

83. "यह वास्तव में कानून को तोड़े बिना कर बचाने की एक कला है." यह किससे सम्बन्धित है ?

(A) कर प्रबन्धन
(B) कर परिवर्जन
(C) कर योजना
(D) कर अपवंचन

84. किस समिति ने बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु एक व्यापक रूपरेखा की संस्तुति की थी ?
(A) घोष समिति (1993)
(B) सोधनी समिति (1994)
(C) मल्होत्रा समिति (1993)
(D) कालिया समिति (1994)

85. विलय एवं अधिग्रहण द्वारा उत्पन्न दुश्चिंता के निराकरण हेतु निम्नलिखित में से किन हस्तक्षेपों का प्रयोग किया जा सकता है ?
1. एकीकरण प्रक्रिया को तेज करना.
2. नवीन दृष्टि, समान लक्ष्य और संगठित प्रतीकों को सुस्पष्ट करना.
3. कर्मचारियों को परामर्श एवं प्रतिबल प्रबन्धन प्रशिक्षण देना.
4. सेवा समापन समारोह जैसे कार्यों को बन्द करना.
5. पति/पत्नी, मित्रों, पर्यवेक्षकों एवं सहकर्मियों द्वारा सामाजिक सहायता देना.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 2, 3, 4
(C) केवल 1, 3, 5
(D) केवल 1, 2, 5

86. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 से 64 में उल्लिखित ऑल्ट्रेशन प्रॉपर' में शामिल हैं–
1. अनियमित शेयरों को रद्द करना.
2. निर्गमित शेयरों को रद्द करना.
3. नए शेयरों को निर्गमित करने से शेयर पूँजी में वृद्धि.
4. शेयरों के विमोचन से शेयर पूँजी में कमी.
5. पूर्णतः प्रदत्त शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन एवं इसके विपरीत.
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 2, 3, 4
(B) केवल 1, 3, 5
(C) केवल 3, 4, 5
(D) केवल 1, 2, 3

87. विक्रय प्रस्ताव के पूर्व भावी ग्राहक के सन्दर्भ में विक्रयकर्ता द्वारा जितना अधिक सम्भव हो उतना अधिक जानना जिस विक्रय सोपान के अन्तर्गत आता है, वह कहा जाता है–
(A) उपागम (B) पूर्वेक्षण
(C) पूर्वउपागम (D) प्रस्तुतिकरण

88. अग्रलिखित में से कौनसी कार्यकलाप आधारित लागत निर्धारण की सीमा नहीं है ?
(A) यह उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न समर्थनकारी कार्यकलापों में शामिल रहता है.
(B) यह निर्णयन-प्रकिया के लिए प्रासंगिक सूचना प्रदान नहीं करता है.
(C) सभी कीमतें किसी विशेष कार्यकलाप के साथ आसानी से चिह्नित नहीं की जा सकती हैं.
(D) एबीसी प्रणाली की स्थापना लागत के साथ-साथ परिचालन एवं अद्यतनीकरण लागत बहुत अधिक होती है.

89. सक्षमताओं से सम्बन्धित कौशल एवं सामर्थ्य निम्नलिखित में से कौनसे हैं ?
1. विश्लेषण
2. बौद्धिक जिज्ञासा
3. संगठन
4. समस्या-समाधान
5. कार्यभार ग्रहण करना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1, 3, 4
(B) केवल 1, 2, 3
(C) केवल 2, 3, 4
(D) केवल 1, 4, 5

90. कारों तथा उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से कौनसी विज्ञापन आयोजन रणनीति उपयुक्त है ?
(A) सूचनात्मक रणनीति
(B) भावात्मक रणनीति
(C) अभ्यासगत (हैबीचुअल) रणनीति
(D) तोषण रणनीति

निर्देश–(प्रश्न 91 से 95 तक) नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

पूर्णदत्त भुगतान माध्यम के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के साथ अन्तःप्रचालित सम्बन्धी मार्गदर्शन डिजिटल वालेट को और अधिक व्यवहारिक बनाता है. यूपीआई के माध्यम से वर्धित शुल्क रहित लेन-देन भुगतान बैंक ग्राहकों और व्यापारियों के लिए वालेट की स्वीकार्यता में विस्तार कर सकता है. यह मुख्यतः यूपीआई की व्यवहार्यता परस्पर समान स्तर पर जो एक बैंक से दूसरे बैंक में मध्य लागत रहित भुगतान और बैंक से व्यापारी के मध्य लेन-देन को बढ़ाता है. यूपीआई के माध्यम से तेजी से बढ़ते हुए लेन-देन के अवसर को ध्यान में रखकर ग्राहकों के व्यवहार जो उनके बैंक खातों से शून्य शुल्क से निर्धारित होता है. अपने अस्तित्व के लिए भुगतानकर्ता बैंक–जो जमा राशि स्वीकार कर सकता है, परन्तु उन्हें ऋण देने की मनाही है. उन्हें यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है. उन्हें एक भिन्न व्यावसायिक इकाई बनने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत उन्हें पूर्ण सेवा बैंक का लाभ मिलता है.

ऐसे प्रयोग से यूपीआई को विस्तार मिलेगा और इससे परस्पर देशों की सीमा पार से प्रेषित धन के तौर पर विविधीकरण होगा. ग्राहकों को रूपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को मुद्रा विनिमय द्वारा राशि दी जा सकेगी और स्थायी निर्देश का उपयोग कर बिलों के भुगतान में वृद्धि होगी. यूपीआई का डिजिटल रुपए के साथ एकीकृत होना होगा जिसका परीक्षण खुदरा एवं थोक लेन-देन के सन्दर्भ में चल रहा है. डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म स्पर्श रहित पेमेंट्स के बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा.

इसमें डिजिटल लेन-देन जैसे बिलिंग और क्रेडिट प्रोफाइलिंग के लिए अतिरिक्त यूपीआई कॉन्टेक्टलेस (संसर्ग रहित) सुविधा शामिल है. आरम्भिक अंगीकरण आशावादी अपेक्षाओं को पार कर गया, लेकिन सिद्धान्ततः व्यापारी छूट दर में दी गई रियायतों के कारण हुआ है. अगले चरण में व्यापार करने के लिए यूपीआई समाधान देने का कार्य करेगा इसे कभी-न-कभी ऋण देने सम्बन्धी व्यवस्था को भी अपने क्रियाकलाप में शामिल करना होगा, ताकि यह वाणिज्य का व्यापक माध्यम बन सके. बुनियादी ढाँचा में फिटनेस को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि वित्त के क्षेत्र में नवाचार सम्भव हो. पेमेंट बैंकों का डिजिटल लेन-देन के साथ सुदृढ़ सह-सम्बन्ध है. यह निर्माण हो रहे तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यूपीआई दिशा-निर्देश के अन्तःप्रचालनीयता इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाता है.

91. गद्यांश के अनुसार स्पर्शरहित (कॉन्टेक्टलैस) भुगतान सम्बन्धी आधारभूत ढाँचा फिनटेक को कैसे सशक्त करेगा ?
(A) यूपीआई के साथ अन्तः संचालनशीलता से
(B) वित्त में नवाचार से
(C) यूपीआई इकोसिस्टम के साथ एकीकरण से
(D) पूर्ण सेवा बैंकों के साथ एकीकरण से

92. निम्नलिखित में कौनसे प्रयोग में लाए गए तरीकों से भुगतानकर्ता बैंकों के विकास अपेक्षित है ?
1. डिजिटल रुपए के साथ यूपीआई का एकीकरण.
2. डिजिटल लेन-देन से पेमेंट बैंकों का विस्थापन.

3. सीमा पार प्रेषण को यूपीआई सुविधा.
4. स्पर्शरहित पेमेंट आधारभूत ढाँचा से सुरक्षित दूरी.
5. रूपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपभोक्ता को ऋण.

दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(A) केवल 1, 2, 3
(B) केवल 3, 4, 5
(C) केवल 1, 3, 5
(D) केवल 2, 4, 5

93. उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार भुगतानकर्ता बैंकों को अपने लिए विशिष्ट व्यावसायिक इकाई बनाने की क्या आश्यकता है ?

(A) यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए
(B) क्योंकि भुगतानकर्ता बैंकों की पूर्ण सेवा बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा है
(C) क्योंकि भुगतानकर्ता बैंकों को अधिदेश है कि वे वित्त क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दें
(D) ताकि ऋण देने के लिए वे अधिकृत हों

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं. एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : भुगतानकर्ता बैंक, जो जमा स्वीकार कर सकता है, लेकिन ऋण नहीं दे सकता, को उसे यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाए जाने की आवश्यकता है.

कारण (R) : यूपीआई के माध्यम से लेन-देन पर वर्धित शुल्क भुगतानकर्ता बैंक ग्राहकों तथा व्यापारियों के बीच वालेट की स्वीकृति को बढ़ा सकता है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है
(D) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन-I : आरम्भिक यूपीआई अंगीकरण आशावादी अपेक्षाओं को व्यापारी छूट देर में रियायत दिए जाने के कारण पार कर गया है.

कथन-II : यूपीआई का भावी विकास व्यापार करने के लिए समाधान उपलब्ध कराना और वाणिज्य का माध्यम बनने पर होगा.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

निर्देश–(प्रश्न 96 से 100 तक) निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उससे सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

द्वितीयक बाजारों में अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लोक्ड अमाउंट (एएसबीए) जैसी प्रस्तावित सुविधा में उनकी आय क्षमता को बढ़ाते हुए निवेशकों को सुरक्षित करने के तत्व पाए जाते हैं. मौजूदा समय में प्राथमिक बाजार में यह इस प्रकार कार्य करता है कि मुद्रा निवेशकों के खाते में निरुद्ध रहता है और अर्जित ब्याज पाता है जब तक आरम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) के जारीकर्ता अभिदान स्वीकार करते हैं. द्वितीयक बाजारों के लिए इसको दोहराना (प्रतिकृति) इसमें शामिल पक्षों की संख्या के साथ-साथ संव्यवहार के प्रकारों के कारण अधिक जटिल है. द्वितीयक बाजार में विविध प्रत्याभूतियों के लिए उत्तोलन सहित उत्तोलन के बिना निवेशक विभिन्न कालावधियों में विभिन्न प्रकार के क्रमादेश देता है. एएसबीए जैसे तन्त्र के लिए इन सभी चरों का समावेश करते हुए अति सक्रिय वातावरण में प्रतिपक्षों के साथ एस्क्रो अरेंजमेंट शामिल है. तकनीकी चुनौतियाँ विचारणीय हो सकती हैं, किन्तु अजेय नहीं हो सकती हैं. इस क्रम में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निवेशकों के लिए ऐसा ढाँचा प्रदान करने के प्रयास की सही दिशा में है. यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) व्यापार हेतु प्रयुक्त मुद्रा को सीधे तौर पर समाशोधन निगमों को हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसका दलालों के साथ समाधान किया जा सकता है. यह ब्रोकर डिफाल्ट के मामले में दलालों के साथ व्यर्थ मुद्रा प्रवाह व धन के दुरुपयोग को कम करता है तथा गिरावट को रोकता है. मध्यावर्तियों के सामूहिक खातों से बचाते हुए सीधे तौर पर समाधान का मार्ग भी प्रस्तावित करता है. सेबी ने निवेशकों के रोकड़ के साथ-साथ उनकी प्रत्याभूतियों की सुरक्षा के नियामक के रूप में कार्य किया है.

सेबी ने दलालों को राहत प्रदान की है, जो समाशोधन निगमों (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) के लिए ग्राहक की मुद्रा की धारा प्रतिकूलता के कारण फ्लोट आय खोने की कगार पर खड़े हैं. आवधिक जमा धारणाधिकार या म्यूचुअल फण्ड इकाई के स्वरूप में धारा प्रतिकूल ग्राहक फण्डों के निवेश के लिए दलालों को अधिकृत किया गया है. इसके लिए मध्यस्थता शुल्क कम रखना चाहिए, जबकि बाजार नियामक ब्रोकर चैनल के माध्यम से निधि समाशोधन के लिए प्रणाली को सचेत कर देता है. प्रणालीगत भूल-चूक ठीक करने के लिए फ्लोट आय द्वारा जिसे सहायता प्राप्त है उनके सम्बन्ध उच्च दलाली शुल्क का अधिरोपण एक प्रकार का सुधार है. इससे छूट प्रदान करने वालों के रूप में प्रचलित दलाली के लाभों को समाप्त करने पर संकेन्द्रित किया जा सकता है.

96. व्यापार हेतु मुद्रा का हस्तान्तरण सीधे तौर पर समाशोधन निगम (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) को निम्नलिखित द्वारा करने की अनुमति होती है–

(A) एस्क्रो अरेंजटमेंट
(B) यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
(C) ई-बैंकिंग
(D) क्रेडिट कार्ड

97. द्वितीयक जटिल बाजार हेतु एबीएसए की अनुकृति बनाने के कारण कौन-कौनसे हैं ?

1. लेन-देन के प्रकार
2. ब्रोकरों की अधिक संख्या में उपस्थिति
3. सेबी (एसईबीआई) मार्गदर्शिका की अप्रयुक्तता
4. पक्षकारों की संख्या
5. कालावधि में भिन्नता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 3, 4, 5
(B) केवल 1, 2, 3
(C) केवल 1, 4
(D) केवल 2, 3

98. गद्यांश में प्रयुक्त अप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) किस बाजार से सम्बन्धित है ?

(A) प्राथमिक बाजार
(B) द्वितीयक बाजार
(C) मुद्रा बाजार
(D) फॉरेक्स बाजार

99. सेबी ने निवेशकों को रोकड़ एवं ..... के संरक्षण के लिए नियामक के रूप में कार्य किया है.

(A) प्रत्याभूतियों
(B) लाभांश आय
(C) संदाय सम्बन्धी शिकायतें
(D) सार्वजनिक जमा

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं. एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में–

अभिकथन (A) : सेबी (एसईबीआई) ने ऐसे ब्रोकरेज (दलाली) को राहत दिया है, जो ग्राहक मुद्रा से समाशोधन नियमन के प्रतिकूल प्रवाह वाले लेखा पर फ्लोट (प्रवर्तन) आय खाने की स्थिति में हैं.

कारण (R) : ब्रोकरेज (दलाली) को आवधिक जमा प्रतिधारण या म्यूचुअल फण्ड इकाइयों के रूप में ग्राहक की निधि को धारा प्रतिकूल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A)
2. (D) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व के अधीन निम्नलिखित 5 अनुषगी (Subsidiary) संस्थान कार्य कर रहे हैं–
   - **DICGC**–Deposit Insurance and Credit Guarantee Corp. of India
   - **BRBNMPL**–Bhartiya Reserve Bank Note Mudaran Pvt. Ltd.
   - **ReBIT**–Reserve Bank Information Technology Pvt. Ltd.
   - **IFTAS**–Indian Financial Technology and Allied Services
   - **RBIH**–Reserve Bank Innovation Hub
3. (A) 4. (D)
5. (B) **गुरिल्ला रणनीति** (Guerilla Strategy)–वह विपणन व्यूहरचना जिसका प्रयोग अपरम्परागत तरीकों से उत्पादों व सेवाओं को बेचने के लिए किया जाता है. युद्धभूमि से लिए गए 'गुरिल्ला' शब्द का अभिप्राय छिपकर आक्रामक तरीके से दुश्मन पर आक्रमण करना होता है. आजकल कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा भी प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए इस अपरम्परागत और विशिष्ट विपणन नीति का अनुसरण किया जाता है.
6. (D) 'क्रेता सावधान रहो' का सिद्धान्त गर्भित शर्तों व गर्भित आश्वासनों के अलावा अन्य सभी परिस्थितियों में लागू होता है. यदि कोई क्रेता अपनी आवश्यकता या उद्देश्य से विक्रेता को अवगत करा देता है, तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होता है.
7. (C) 8. (D) 9. (D) 10. (B) 11. (B)
12. (B) 13. (A) 14. (D) 15. (C) 16. (D)
17. (D)
18. (B) 'OCTAPACE' संस्कृति का व्यावहारिक भावार्थ होता है. तेजी से बढ़ने वाली संस्कृति/संगठन के विकास व विस्तार के लिए इस फ्रेमवर्क की अनुपालना पर बल दिया जाता है. इसके 8 आयाम (Dimensions) निम्नलिखित हैं–
    O–Openness (खुलापन)
    C–Collaboration (सहयोग)
    T–Trust (विश्वास)
    A–Autonomy (स्वायत्तता)
    P–Pro-Active (सक्रियता)
    A–Authenticity (प्रामाणिकता)
    C–Confrontation (टकराव)
    E–Experimentation (प्रयोग)
19. (C) 20. (B)
21. (B) सन् 1994 में स्थापित 'NAFTA' (North American Free Trade Agreement) के तीन राष्ट्र संघ हैं– USA, Canada और Mexico, किन्तु 2020 में इस संगठन का नाम बदलते हुए इसे पुनर्स्थापित किया गया है और अब इसे NAFTA (नाफ्टा) के स्थान पर 'USMCA' (USA, Mexico and Canda) के नाम से पुकारा जाता है.
22. (D)
23. (C) **कर परिहार** (Tax avoidance) से अभिप्राय उस रणनीति से है, जिसमें कर नियमों में विद्यमान कमियों का अनुचित लाभ उठाते हुए करभार को न्यून किया जाता है. इसका प्रयोग कर देयता उत्पन्न होने से पहले ही किया जाता है और कानूनों की अनुपालना के साथ कर बचाव किया जाता है.

    कर अपवंचन (Tax Evasion) के अन्तर्गत धोखाधड़ी का सहारा लेकर बचाव के प्रयास किए जाते हैं, इसे कर-चोरी भी कहते हैं. यह गैर-कानूनी तरीके से करभार को कम करने का अनुचित तरीका है. इसका प्रयोग कर देयता उत्पन्न होने के बाद किया जाता है तथा आरोपी को दण्डित भी किया जा सकता है.
24. (D) 25. (D) 26. (B) 27. (C) 28. (D)
29. (C) 30. (C) 31. (C)
32. (D) विभिन्न सोपानों का व्यवस्थित क्रम निम्नानुसार है–
    1. वाणिज्यिक पत्र (C.R.) का प्रारम्भ–1990
    2. डब्ल्यू.एम.ए. का प्रारम्भ–1997
    3. एल.ए.एफ. का प्रारम्भ–1998
    4. आई.आर.एस. का प्रारम्भ–1999
    5. आर.टी.जी.एस. का प्रारम्भ–2004
33. (A) 34. (D) 35. (B) 36. (C) 37. (B)
38. (A) 'C' द्वारा भुगतान के लिए केवल 'A' को ही बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि चेक का निर्गमनकर्ता आवश्यक है, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है.
39. (B) 40. (D) 41. (D)
42. (B) **'प्राइस लाइनिंग'** मूल्य निर्धारण की वह व्यूहरचना है, जिसमें गुणवत्ता और सुविधा के अनुसार विभिन्न ग्राहकों से भिन्न-भिन्न मूल्य वसूलते हुए कुल विक्रय और लाभों को बढ़ाया जा सकता है अर्थात् एक साथ अनेक मूल्य बिन्दुओं पर उत्पाद को बेचने की रणनीति प्राइस लाइनिंग रणनीति कहलाती है (इसका सर्वोत्तम उदाहरण स्मार्टफोन है.).
43. (B) 44. (A) 45. (A) 46. (D)
47. (D) 'एक्स' के वेतन शीर्षक की आय का निर्धारण हेतु 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि को आधार माना जाएगा अर्थात् विगत वर्ष या वित्तीय वर्ष जुलाई से ही प्रारम्भ होगा.

    कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year-A.Y.) से अभिप्राय 12 माह की वह अवधि, जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होती है और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है.

    विगत वर्ष (Previous Year)–कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित विगत वर्ष की अवधि 12 माह से कम भी हो सकती है. इसका शुभारम्भ आज प्रारम्भ होने के साथ होता है. यदि किसी की आय आगामी वर्ष की 31 मार्च से पहले ही बन्द हो जाती है, तो उसी अवधि को विगत वर्ष माना जाएगा, जिसमें आय प्राप्त हुई है. विगत वर्ष को ही **वित्तीय वर्ष** (Financial Year) कहा जाता है.
48. (A)
49. (C) भुगतान सन्तुलन (Balance of Payment : BoP) के अन्तर्गत मूलतः चार खाते हैं–
    - चालू खाता (Current Account)
    - पूँजी खाता (Capital Account)
    - शासकीय आरक्षित खाता (Official Reserve Account)
    - एकतरफा अन्तरण खाता (One-sided Transfer Account)

    शासकीय या आधिकारिक आरक्षित खाते के अन्तर्गत राजकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण से विनिर्मित उत्पादों तथा विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने से सम्बन्धित होने वाले परिवर्तनों को दर्ज किया जाता है.
50. (C) 51. (D)

52. (D) **नियोजित पूँजी पर प्रत्यय की गणना :**

सूत्र : Return on Capital Employed

$$= \frac{\text{Earnings Before Interest and taxes (EBIT)}}{\text{Total Assets} - \text{Total Current Liabilities}} \times 100$$

यहाँ पर ब्याज और कर से पूर्व की आय (EBIT) की गणना निम्नानुसार की गई है–

EBIT = Net Profit + Tax Paid + Interest on Investment – Interest on Debentures

= ₹ 1,00,000 + 1,00,000 + 10,000 – 10,000

= ₹ 2,00,000

अतः ROCE

$$= \frac{₹\,2{,}00{,}000 (EBIT)}{₹\,5{,}00{,}000 (4{,}50{,}000 + 1{,}50{,}000 - 1{,}00{,}000)} \times 100$$

$$= \frac{₹\,2{,}00{,}000}{₹\,5{,}00{,}000} \times 100$$

= 40%

टिप्पणी :

(i) कर आयोजन को चालू दायित्व के रूप में कुल सम्पत्तियों में से घटाया गया है.

(ii) प्रश्न में कर की दर का उल्लेख नहीं होने के कारण यह माना गया है कि कम्पनी ने कर आयोजन के बराबर (₹ 1 लाख) का कर चुकाया है.

(iii) Interest on Debentures को Non-recurring income के रूप में घटाया गया है.

53. (C) 54. (C) 55. (A) 56. (C) 57. (B)

58. (D)

59. (B) **एजेंट का तृतीय पक्षकारों के प्रति वैयक्तिक दायित्व**–निम्नलिखित दशाओं में एक एजेंट को तृतीय पक्षकारों के प्रति वैयक्तिक दायित्व बनता है–

- विदेशी नियोक्ता की दशा में
- अप्रकट नियोक्ता की दशा में
- समझौते से दायित्व स्वीकार करने पर
- बनावटी एजेंट की दशा में
- अनुबन्ध पर एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने की दशा में
- अविद्यमान नियोक्ता के लिए कार्य करने पर
- कपटपूर्ण कार्यों की दशा में
- व्यापार की प्रथानुसार
- अधिकारों के बाहर कार्य करने पर
- दण्डनीय अपराधों के लिए आदि

60. (B) 61. (C) 62. (B) 63. (A)

64. (B) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अग्रलिखित 7 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है–

- **अनुसूची-I :** ज्ञापन और अनुच्छेद
- **अनुसूची-II :** मूल्य ह्रास की गणना
- **अनुसूची-III :** तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते का विवरण
- **अनुसूची-IV :** स्वतंत्र संचालकों के लिए संहिता
- **अनुसूची-V :** प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशक व प्रबन्धक की नियुक्ति
- **अनुसूची-VI :** बुनियादी ढाँचा परि-योजनाएं
- **अनुसूची-VIII :** निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

65. (B) 66. (A) 67. (C) 68. (B) 69. (A)

70. (D) **वास्तविक प्रतिफल की गणना :**

सूत्र–

मुद्रास्फीति समायोजित प्रतिफल

$$= \left[\frac{1 + \text{प्रतिफल \%}}{1 + \text{मुद्रास्फीति \%}} - 1\right] \times 100$$

$$= \left[\frac{1{\cdot}125}{1{\cdot}035} - 1\right] \times 100$$

= [1·086956 – 1] × 100

= ·086956 × 100

= 8·6956 or 8·70%

71. (A) **नाबालिग बच्चे की आय को क्लब करने पर छूट**–आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1A) के अनुसार, यदि माता-पिता की आय में नाबालिग बच्चे की आय जोड़ी जाती है, तो ऐसे माता-पिता द्वारा प्रति नाबालिग ₹ 1500 तक की छूट दी जा सकती है. यह छूट सम्मिलित आय तक सीमित होगी.

72. (D) 73. (B) 74. (B)

75. (D) **प्रापण (Realisation) पर लाभ/हानि की गणना :**

A की पूँजी	=	₹ 40,000
B की पूँजी	=	₹ 50,000
कुल दायित्व	=	₹ 90,000
(–) बाकी धनराशि	=	₹ 80,000
प्राप्ति पर हानि	=	₹ 10,000

76. (D) 77. (A) 78. (B) 79. (C) 80. (C)

81. (B) 82. (A) 83. (B) 84. (C) 85. (C)

86. (B) 87. (C) 88. (A) 89. (A) 90. (A)

91. (B) 92. (C) 93. (B) 94. (A) 95. (A)

96. (B) 97. (C) 98. (B) 99. (A) 100. (B)

●●●

शेष पृष्ठ 76 का

- प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन करते समय एक शपथपत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपने ऊपर न्यायालय में लम्बित वादों का विवरण, अपनी तथा अपने निकट सम्बन्धियों की चल-अचल सम्पत्तियों तथा देनदारियों का विवरण देने की अनिवार्यता.
- शपथपत्र में झूठी जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है.
- ईवीएम में नोटा (None of the Above) बटन का प्रावधान.
- उच्च न्यायालय में दायर निर्वाचन सम्बन्धी याचिकाओं की सुनवाई 6 माह के भीतर पूरी कर लेना.
- सांसदों/विधायकों के विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित आपराधिक वादों की त्वरित सुनवाई हेतु प्रावधान.
- मतदानकर्मियों के लिए मतदान केन्द्रों का निर्धारण कम्प्यूटर आधारित रैण्डम विधि द्वारा.
- भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की देखरेख में चुनाव.
- मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान. ●●●

शेष पृष्ठ 98 का

को अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में प्रवेश करने की अनुमति दी है. समकालीन कला और लोक संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न पहलों के विकास हेतु वित्तपोषण को प्रोत्साहित किया है. बाजार के विकास के साथ रचनात्मकता, लोक संस्कृति के उत्थान के क्षेत्र में व्यापक रुचियों का प्रवाह बढ़ा है. संस्कृति के वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान से परम्पराओं के अभिसरण में योगदान दिया है. सांस्कृतिक वैश्वीकरण को दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार, उपभोक्ता संस्कृति के अभिसरण और अन्तर्राष्ट्रीय संचार के विकास से बहुआयामी विस्तार मिला है. इससे दुनिया भर में राष्ट्रीय संस्कृतियों का प्रचार होता है. हालाँकि, लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटनाएं राष्ट्रीयता को विस्थापित कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय में बदल सकती हैं. कुछ विद्वान् इसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की हानि मानते हैं, जबकि कुछ राष्ट्रीय संस्कृति का पुनरुद्धार कहते हैं. ●●●

उपकार कॅरियर डेवलपमेंट सीरीज

महान व्यक्तित्व

महान व्यक्तियों के जीवन पर प्रेरणादायक सामग्री

Code 226 ₹ 140.00

उपकार प्रकाशन, आगरा-5

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

सामान्य अध्ययन

(प्रथम प्रश्न-पत्र)

1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

क्षेत्र	सम्बन्धित देश
1. उत्तरी किवू	–डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो
2. कारबाख	–यूक्रेन
3. जपोरिजिया	–जापान

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

2. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. वर्ष 2023 का खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साई-राज सहित कुल 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया.
   2. मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पिछले 2 वर्षों की अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है.

   उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

3. हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन है.
   2. हरित हाइड्रोजन का उपयोग मात्र छोटे उद्योगों के लिए ही अनुकूल माना जाता है.

   उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

4. हाल ही में चर्चित रहा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के संदर्भ में कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
   1. इस ग्रुप ने केन्द्र सरकार से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
   2. शांति समझौते में प्रमुखतः परेश बरुआ, अरबिंद राजखोवा व अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट सम्मिलित हुए.

   उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

   कूट :
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

5. आदित्य एल-1 के सन्दर्भ में कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?
   1. इसे पीएसएलवी सी-57 द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपित किया गया.
   2. इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलिस्कोप, हाई एनर्जी एल-1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सहित कुल 7 पेलोड लगे हुए हैं.
   3. एल-1 बिन्दु पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच ऐसा स्थान है, जहाँ गुरुवाकर्षण सबसे कम होता है.

   कूट :
   (A) केवल 1 और 2
   (B) केवल 2 और 3
   (C) केवल 3
   (D) 1 और 3

6. हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक्सपोसैट उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. यह खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए भारत का पहला ध्रुवणमापी (Polarimeter) मिशन है.
   2. इस मिशन की सफलता के बाद भारत, अमरीका, चीन और रूस के बाद ऐसा चौथा देश हो गया है, जो ब्लैक होल्स का अध्ययन करेगा.

   उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

7. भारत के सबसे लम्बे सी-ब्रिज अटल सेतु के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   1. यह सेतु दक्षिण मुम्बई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के न्हावा शेवा से जोड़ता है.
   2. इस पुल की कुल लम्बाई 21·8 किमी है.
   3. इस पुल को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा नाम दिया गया है.

   उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
   (A) केवल एक (B) केवल दो
   (C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

8. स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

सर्वेक्षण-2023 पुरस्कार	पुरस्कृत
1. सबसे स्वच्छ शहर	–सूरत
2. सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य	–छत्तीसगढ़
3. सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड	–महू छावनी बोर्ड (महाराष्ट्र)

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

9. हाल ही में जारी हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के अनुसार सही युग्म की पहचान कीजिए–
   1. कुल हिम तेंदुओं की संख्या – 1030
   2. देश में सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या – हिमाचल प्रदेश (477)
   3. गणना में राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी – भारतीय वन्य जीव संस्थान

   कूट :
   (A) केवल एक (B) केवल दो
   (C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

10. ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. ब्रिक्स वर्तमान में 10 सदस्यीय समूह बन गया है.
    2. 5 नए सदस्यों में ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात सम्मिलित हुए हैं.
    3. 5 नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स का नया नाम ब्रिक्स +5 हो गया है.

    उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
    (A) केवल 1
    (B) केवल 2 और 3
    (C) केवल 1 और 3
    (D) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. हाल ही में जापान का 'स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टीगेटिंग मून मिशन' इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया.
    2. जापान, चन्द्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत के बाद दूसरा देश है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

12. हाल ही में भारत द्वारा अपना 75वाँ गणतंत्र दिवस मनाया गया इसके संदर्भ में कौनसा/से कथन सहीं है/हैं ?
1. पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की उपस्थिति रही.
2. गणतंत्र दिवस समारोह की झाँकियों में उत्तर प्रदेश की झाँकी को ओवरऑल प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया.
3. वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था.
4. इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत और फ्रांस ने वर्ष 2025 को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष मनाने पर सहमति जताई.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) इनमें से कोई नहीं

13. हेनली एण्ड पार्टनर्स द्वारा जारी विभिन्न देशों की पासपोर्ट्स सूची के संदर्भ में सही युग्मों की पहचान कीजिए–
1. सर्वाधिक वीजा रहित गंतव्य वाले देश –फ्रांस, फिनलैण्ड, ऑस्ट्रिया
2. भारत की पिछले वर्ष की तुलना में रैंकिंग सुधार –6 अंकों का सुधार
3. अन्तिम स्थान पर देश —सोमालिया और अफगानिस्तान

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

14. 16वें वित्त आयोग के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है.
2. अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत् की जाती है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

15. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है/हैं–
1. इसे 1 जनवरी, 2024 को लागू किया गया.
2. यह योजना भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल-1 के समान भविष्य में अन्य ऐसे मिशनों को लॉन्च करने की योजना है.

कूट :
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

16. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समीक्षा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत अनुमानित है.
2. उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीआईआर) 2021 में 28·5 है.
3. वर्ष 2023 में कुल जीएसटी संग्रह ₹ 1·5 लाख करोड़ से अधिक हुआ है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

17. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समीक्षा 2024 के आधार पर समावेशी विकास नीतियों की उपलब्धियों के संदर्भ में विचार कीजिए–
1. कुल जनधन खातों की संख्या 51·6 करोड़ पहुँच गई है.
2. 10·11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं.
3. 2·6 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

18. अन्तरिम बजट, 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. लगातार 10 बार केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है.
2. तात्कालीन वित्त मंत्री सीतारमण का यह लगातार आठवीं बार बजट पेश करना है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1 न ही 2

19. अंतरिम बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दुओं के संदर्भ में विचार कीजिए–
1. अंतरिम बजट का कुल आकार ₹ 47·66 लाख करोड़ है.
2. वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5·1 प्रतिशत अनुमानित है.
3. पूँजीगत व्यय को बढ़ाकर 11·11 लाख करोड़ किया गया है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

20. अंतरिम बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. वित्त वर्ष 2025 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 10·5% अनुमानित है.
2. प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य ₹ 21·99 लाख करोड़ रखा गया है.
3. विनिवेश का लक्ष्य ₹ 50,000 करोड़ अनुमानित है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

21. केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार प्रथम पाँच मदें जिस पर सर्वाधिक व्यय का अनुमान है–
1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप
2. रक्षा क्षेत्र
3. राज्यों को अंतरण
4. सामाजिक कल्याण
5. ग्रामीण विकास

कूट :
(A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 3, 4 और 5
(C) केवल 1, 4 और 5
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

22. केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार के आय के साधनों में प्रथम 5 मदों का अवरोही क्रम है–
1. उधार और अन्य देयताएं
2. आय कर
3. निगम कर
4. माल और सेवा कर
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

कूट :
(A) 1, 2, 3, 4, 5
(B) 5, 4, 3, 2, 1
(C) 1, 2, 3, 5, 4
(D) 1, 2, 4, 3, 5

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 5·9 प्रतिशत अनुमानित है.
2. अंतरिम बजट 2024-25 में प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) जीडीपी का 1·5 प्रतिशत अनुमानित है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

24. अंतरिम केन्द्रीय बजट 2024-25 में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में विचार कीजिए–
1. अंतरिम बजट में सरकार का कुल व्यय ₹ 47,65,768 करोड़ प्रस्तावित है.
2. कुल व्यय में लगभग 24·9 प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुगतान के लिए अनुमानित है.
3. अंतरिम बजट घोषणा में लखपति दीदी के लक्ष्य को 3 करोड़ निर्धारित किया गया है.
4. अंतरिम बजट घोषणा में विनिवेश प्राप्तियों से ₹ 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है.
5. 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं ?
(A) केवल तीन (B) केवल चार
(C) सभी पाँच (D) इनमें से कोई नहीं

25. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए–
1. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 7 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कुल 9 श्रेणियों में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है.
2. इस वर्ष आदित्य विजय ब्रम्हणे को वीरता के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

कूट :
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

26. गोल्डन ग्लोब पुरस्कार (2023) के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म (ड्रामा) —पुअर थिंग्स
2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक —क्रिस्टोफर नोलन
3. सर्वश्रेष्ठ पटकथा —एनाटॉमी ऑफ ए फॉल
4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (ड्रामा) —लिली ग्लैडस्टोन

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

27. मुंशीशिवगाँव की संधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. यह संधि पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी.
2. इस संधि के अनुसार निजाम चौथ तथा सरदेशमुखी की बकाया राशि के भुगतान के साथ ही शम्भाजी द्वितीय को कोई सहायता नहीं देगा.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

28. मराठा साम्राज्य से अलग हुए वंशों की राजधानी के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. सिंधिया वंश की राजधानी –उज्जैन
2. होल्कर वंश की राजधानी –इंदौर
3. गायकवाड़ वंश की राजधानी –बड़ौदा

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

29. दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. इनका जन्म पंजाब (लाहौर) में 'मौरबी' नामक गाँव में हुआ था.
2. इनके बचपन का नाम 'मूल शंकर' था.
3. इन्होंने वर्ष 1875 में 'सत्यार्थ प्रकाश' ग्रंथ की रचना व तत्पश्चात् 1878 में आर्य समाज की स्थापना की.
4. इनके गुरु बिरजानंद की पुस्तक 'गौकरुणानिधि' से प्रेरित होकर इन्होंने 'गौरक्षिणी सभा' की स्थापना की.

उपर्युक्त कथनों में कितने सही नहीं हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) सभी चार

30. रजिया सुल्तान (1236–40 ई.) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. मुबारक शाह ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया.
2. रजिया ने कुवा और कुलाह के स्थान पर पर्दा प्रथा को बढ़ावा दिया.
3. रजिया ने अबीसीनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-आखूर नियुक्त किया.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

31. वर्ष 1793 में आई 'कार्नवालिस संहिता' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. 'कार्नवालिस संहिता', 'शक्तियों के पृथक्करण सिद्धान्त' पर आधारित थी.
2. इसमें कार्नवालिस ने जिला कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति को वापस ले लिया.
3. इसमें जिला दीवानी न्यायालयों के लिए एक नए पद जिला न्यायाधीश का सृजन किया गया.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

32. मन्दिर निर्माण की नागर शैली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. नागर शैली के मन्दिर हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में विशेषत: निर्मित है.
2. इसमें मन्दिर निर्माण की 'पंचायतन शैली' को अपनाया जाता है.
3. इस शैली के मन्दिरों के शिखर पर 'आमलक' की स्थापना होती है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

33. अयोध्या में निर्मित राम मन्दिर के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. मुख्य वास्तुकार —चंद्रकांत बी. सोमपुरा
2. मुख्य मूर्तिकार —अरुण योगीराज (मैसूर)
3. मन्दिर निर्माण शैली —नागर शैली

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

34. इसमें सजा की एक निश्चित अवधि पूरी कर लेने के बाद किसी दण्ड या सजा की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है. इसमें कारावास जीवन से विराम के बजाय दण्ड में कमी कर दी जाती है. यह परिभाषा सम्बन्धित है–
(A) पैरोल से (B) परिहार से
(C) फर्लो से (D) सभी से

35. निम्नलिखित संवैधानिक शब्दावली के संदर्भ में विचार कीजिए–
1. लघुकरण (Commutation) –सजा की प्रकृति को बदलना
2. प्रविलम्बन (Re-Prieve) –किसी दण्ड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया
3. विराम (Respite) –विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक
(B) केवल दो
(C) सभी तीन
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

36. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards—NAAQS) में प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है–
1. पीएम 10
2. बेंजो पाइरीन
3. आर्सेनिक
4. कार्बन डाइऑक्साइड
5. निकिल

कूट :
(A) केवल 1, 2, 3 और 4
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 3, 4 और 5
(D) केवल 1, 2, 3 और 5

37. पोम्पे रोग के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. हाल ही में पोम्पे रोग से ग्रस्त भारत की पहली रोगी निधि शिरोल का निधन हुआ है.
2. पोम्पे रोग एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है, जो अल्फा एंजाइम एसिड ग्लूकोसिडोस की कमी से होता है.
3. पोम्पे रोग को लाइसोसोमल भण्डारण रोग के बारे में भी जाना जाता है.

उपर्युक्त में कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

38. कॉप-28 (दुबई) के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हस्ताक्षरित लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2·0 (Lead IT 2·0) के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सम्मिलित है–
1. समावेशी और न्यायसंगत औद्योगिक परिवर्तन
2. निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी का सह-विकास
3. उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन

कूट :
(A) केवल 1 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) इनमें से कोई नहीं

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. कंगनहल्ली शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ 'राण्यो अशोक' उल्लिखित हुआ है.
2. अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिष्टा ने की थी.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

40. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. प्रथम जैन संगोष्ठी का आयोजन –पाटलिपुत्र
2. मौर्य प्रशासन में 'लक्षणाध्यक्ष' –टकसाल का अध्यक्ष
3. निकोलो मनूची –रोमवासी

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. वर्ष 1929 में जारी 'दीपावली घोषणा' पत्र का सम्बन्ध डोमिनियन स्टेट्स से है.
2. दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन निष्कासन को 'Evie of Ace Evirs' की संज्ञा दी है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

42. भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस संसदीय समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ?
(A) लोक लेखा समिति
(B) पारक्लन समिति
(C) नियम समिति
(D) कार्य मंत्रणा समिति

43. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए–
1. बुल्गारिया 2. चेक रिपब्लिक
3. हंगरी 4. लातविया
5. लिथुआनिया 5. रोमानिया

उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ लगती हैं ?
(A) केवल दो (B) केवल तीन
(C) केवल चार (D) केवल पाँच

44. अग्रलिखित में कौनसी लोक सभा की अनन्य शक्तियाँ हैं ?
1. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना.
2. मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करना.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 (D) न तो 1, न ही 2

45. निम्नलिखित फसलों में कौनसी एक, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है ?
(A) गन्ना (B) गेहूँ
(C) धान (D) कपास

46. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

पर्वत	**शिखर**
1. गढ़वाल हिमालय	–नामचा बरवा
2. कुमाऊँ हिमालय	–नंदा देवी
3. नोकरेक	–सिक्किम हिमालय

उपर्युक्त युग्मों में कौनसा/से सही सुमेलित है/हैं ?
(A) 1 और 2 (B) केवल 2
(C) 1 और 3 (D) केवल 3

47. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

आर्द्रभूमि	**अवस्थान**
1. अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण	–कर्नाटक रिजर्व
2. मगदी केरे संरक्षण	–तमिलनाडु रिजर्व
3. कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य	–केरल
4. होकेरा आर्द्रभूमि	–पंजाब
5. सस्थाम्कोत्ता	–तमिलनाडु

उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल तीन (B) केवल चार
(C) केवल एक (D) सभी पाँच

48. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

1. फणम	सिक्के
2. कुलाह-दारन	सैयद
3. आर्यदेव	जैन विद्वान

उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीन (D) इनमें से कोई नहीं

49. भारत में, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ?
(A) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्
(B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) उपभोक्ता मामले विभाग
(D) व्यय प्रबंधन आयोग

50. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

	जलाशय	राज्य
1.	कालानई	तमिलनाडु
2.	मैघोन	छत्तीसगढ़
3.	घाटप्रभा	तेलंगाना
4.	हीराकुंड	कर्नाटक

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल दो युग्म
(B) केवल तीन युग्म
(C) सभी चारों युग्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है ?
(A) चींटी (B) कॉक्रोच
(C) केकड़ा (D) मकड़ी

52. अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों में सम्मिलित नहीं है–
1. ओजोन
2. सल्फर डाइऑक्साइड
3. नाइट्रोजन ऑक्साइड
4. कार्बन मोनोक्साइड

कूट :
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 4
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

53. निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है ?
(A) बैंकों में आरक्षित नगदी निधि अनुपात में वृद्धि
(B) बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि
(C) लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि
(D) देश की जनसंख्या में वृद्धि

54. जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए–
1. कॉपिपोड
2. साइनोबैक्टीरिया
3. डायटम
4. फोरैमिनिफेरा

उपर्युक्त में से कौनसे जीव महासागरों की आहार शृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद हैं ?
(A) 1 और 2 (B) 2 और 3
(C) 3 और 4 (D) 1 और 4

55. गुप्त वंश के पतन से लेकर आरम्भिक सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में अग्रलिखित में से किन राज्यों का शासन था ?
1. मगध के गुप्त
2. मालवा के परमार
3. थानेसर के पुष्यभूति
4. कन्नौज के मौखरि
5. देवगिरि के यादव
6. वल्लभी के मैत्रक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए–
(A) 1, 2 और 5 (B) 1, 3, 4 और 6
(C) 2, 3 और 4 (D) 5 और 6

56. निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं ?
(A) मोमबत्ती का जलना
(B) पानी का जमना
(C) खाना पकाना
(D) लोहे में जंग लगना

57. अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय द्वारा स्रावित जठर रस में विद्यमान होता है
(B) एसीटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है
(C) इमली में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है
(D) नींबू और संतरे के रस में क्रमशः सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है

58. अंगकों और उनके प्रकार्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–
1. माइट्रोकाण्ड्रिया–श्वसन
2. हरित लवक–प्रकाश-संश्लेषण
3. राइबोसोम–प्रोटीन का परिवहन
4. अंतर्द्रव्यी जालिका–प्रोटीन संश्लेषण

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल दो (B) केवल तीन
(C) सभी चार (D) इनमें से कोई नहीं

59. निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका भित्ति विद्यमान नहीं होती है ?
(A) जीवाणु (B) डायटम
(C) मशरूम (D) फीताकृमि

60. शिवाजी से सम्बद्ध निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए–
1. अफजल खान पर आक्रमण
2. तोरण पर कब्जा
3. शाइस्ता खान पर आक्रमण
4. जावली को राज्य में मिला लेना

नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर दीजिए–
(A) 2, 4, 1, 3 (B) 4, 2, 1, 3
(C) 1, 2, 3, 4 (D) 3, 1, 2, 4

61. पद और उनके अर्थ से सम्बन्धित अग्रलिखित युग्मों में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है ?
(A) नागरक्कणी –नगरम के स्वामित्वाधीन भूमि
(B) नट्टर –नर नाग देवता
(C) यूप –यज्ञ-बलि स्तम्भ
(D) वीरागल –तमिलनाडु क्षेत्र में 'वीर शिला'

62. चोल कालीन नटराज की कांस्य प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. शिव को उनके दाहिने पैर पर संतुलित रूप से खड़े हुए दिखाया गया है, जो तिरोभाव का द्योतक है.
2. शिव को उनके बायाँ पैर उठाए हुए भुजंगत्रासित की स्थिति में दिखाया गया है, जो भक्त के मन हो माया हटा देने का द्योतक है.
3. मुख्य दाहिना हाथ डमरू पकड़े हुए है, जो शिव का प्रिय वाद्य है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

63. आसियान (ASEAN) के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
1. सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता वार्षिक रूप से बारी-बारी से आती है.
2. सदस्य देशों के बीच मतदान के द्वारा अध्यक्षता पर निर्णय लिया जाता है.
3. आसियान का आदर्श वाक्य है, "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय".
4. 12 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए–
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4

64. मेघों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. मेघों के दो प्रमुख प्रकार स्तरी मेघ और कपासी मेघ हैं.
2. स्तरी, वर्षा-स्तरी और स्तरी-कपासी मेघ ऊँचे मेघों के प्रकार हैं.
3. जिन मेघों के नाम के साथ निम्बो (Nimbo) संलग्न है, वे वर्षा करते हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसे कथन सही हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) 1, 2 और 3
(C) केवल 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

65. यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
(A) मुद्रा की माँग में वृद्धि होगी
(B) मुद्रा गुणक कम हो जाएगा
(C) मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी
(D) मुद्रा की माँग घट जाएगी

66. असम के वैष्णव संत शंकरदेव के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
1. उनकी शिक्षाओं को प्रायः भागवत धर्म के रूप में जाना जाता है.
2. उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए सत्रों या मठों और नाम घरों या प्रार्थना घरों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया.
3. उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्ति-घोष शामिल है.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) केवल 3

67. भारत के 'ब्लू ग्रोथ' से क्या अभिप्राय है ?
(A) भारतीय वायु सेना का उन्नयन
(B) किसानों को पीड़कनाशी का उपयोग करने से हतोत्साहित करना
(C) समुद्री और समुद्रवर्ती सेक्टरों में संधारणीय वृद्धि को सहायता प्रदान करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति
(D) भारत के असंगठित क्षेत्र में शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण

68. निम्नलिखित युग्मों में कौनसा/से सुमेलित नहीं है ?
1. डिस्कवरी ऑफ इण्डिया –जवाहरलाल नेहरू
2. संस्कृति के चार अध्याय –रामधारी सिंह दिनकर
3. हिन्दू वे ऑफ लाइफ –डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
4. नेशनल कल्चर ऑफ इण्डिया –आबिद हुसैन

कूट :
(A) सभी चारों युग्म
(B) तीन युग्म
(C) दो युग्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. निम्नलिखित युग्मों में कौनसा/से सुमेलित है ?
1. अरिकामेदु – रोमन कॉलोनी
2. खोतान – रेशम मार्ग
3. वेगराम – गांधार कला
4. मुजिरिस – बंदरगाह

कूट :
(A) सभी चारों युग्म
(B) तीन युग्म
(C) दो युग्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. निम्नलिखित में कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है ?
1. नेचुरल हिस्ट्री – स्ट्रैबो
2. इण्डिका – मेगस्थनीज
3. ज्योग्राफी – टॉलेमी

कूट :
(A) सभी तीनों युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल एक युग्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

71. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सुमेलित है ?

चीनी यात्री	यात्रा काल
1. फाहियान	– 399–412 ई.
2. ह्वेनसांग	– 675–695 ई.
3. इत्सिंग	– 630 – 645 ई.

कूट :
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

72. अंकोरवाट मन्दिर के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. इसे सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कंबोज राज्य की राजधानी में बनवाया गया था.
2. यह मन्दिर भगवान शिव को समर्पित है.
3. इस मन्दिर का सबसे बड़ा उत्कीर्ण चित्र समुद्रमंथन का है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही नहीं है ?
(A) केवल 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

73. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
1. थाइलैण्ड की प्राचीन राजधानी 'अयुत्थाया' थी.
2. थाइलैण्ड को 'स्याम' नाम से जाना जाता था.

कूट :
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2
(D) न तो 1 न ही 2

74. मन्दिर निर्माण की क्षेत्रीय शैलियों के सम्बन्ध में कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?

क्षेत्रीय शैली	क्षेत्र
1. लाट	ओडिशा
2. पर्वतीय	हिमालयी क्षेत्र
3. कलिंग	प. बंगाल

कूट :
(A) सभी तीनों युग्म
(B) केवल दो युग्म
(C) केवल एक युग्म
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. नागर स्थापत्य शैली के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. इस मन्दिर निर्माण शैली में प्रदक्षिणा पथ का अभाव होता है.
2. मण्डप पर आमलक की स्थापना होती है.
3. देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) इस शैली से निर्मित है.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

76. नागर स्थापत्य शैली के मन्दिरों की आधार से शिखर तक वास्तुकला बनावट के आधार पर सही क्रम है–
(A) अधिष्ठान–जगती–प्रदशिक्षा पथ–शिखर–आमलक
(B) अधिष्ठान–प्रदशिक्षा पथ–जगती–शिखर–आमलक
(C) अधिष्ठान–प्रदशिक्षा पथ–जगती–आमलक–शिखर
(D) जगती–अधिष्ठान–प्रदशिक्षा पथ–आमलक–शिखर

77. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
1. भरदूत स्तूप – मध्य प्रदेश
2. उदयगिरी गुफाएं – ओडिशा
3. बराबर गुफाएं – तमिलनाडु

कूट :
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

78. निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए–
1. लेपाक्षी मन्दिर
2. सांची स्तूप
3. अजंता की गुफाएं
उपर्युक्त स्थलों में से कौनसा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है ?
(A) केवल 1 (B) केवल 1 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) इनमें से कोई नहीं

79. कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है–
(A) पूर्वोत्तर भारत में सूती वस्त्र में हाथ से की गई चित्रकारी
(B) दक्षिण भारत में सूती वस्त्र में हाथ से की गई चित्रकारी
(C) उत्तर-पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र में हाथ से की गई चित्रकारी
(D) भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी

80. सुप्रसिद्ध पेंटिंग 'बणी ठणी' किस शैली की है ?
(A) बूँदी शैली
(B) जयपुर शैली
(C) काँगड़ा शैली
(D) किशनगढ़ शैली

81. 'एरियल मेटाजिनोमिक्स' के संदर्भ में सही है–
(A) किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवांशिक रचना को समझना
(B) किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना
(C) भूमितल और जल निकायों से पादप एवं जन्तु प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए वायुवाहित युक्तियों का प्रयोग करना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिए–
1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय विधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) ये सभी

83. निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए–
1. सरकारी बॉण्ड बाजार
2. कॉल मनी मार्केट
3. ट्रेजरी बिल मार्केट
4. स्टॉक बाजार
पूँजी बाजार में, उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं ?
(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) केवल तीन (D) ये सभी

84. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए–
1. आर्मीनिया
2. अजरबैजान
3. क्रोएशिया
4. रोमानिया
5. उज्बेकिस्तान
उपर्युक्त में से कौनसे तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं ?
(A) 1, 2 और 4
(B) 1 और 3
(C) 2 और 5
(D) 3, 4 और 5

85. 'ब्लू कार्बन' क्या है ?
(A) महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहीत कथन
(B) वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन
(C) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन
(D) वायुमण्डल में विद्यमान कार्बन

86. प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे ?
(A) नाटककार (B) दार्शनिक
(C) जैन संत (D) इनमें से कोई नहीं

87. निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए–
1. ब्राह्मणी 2. नागावली
3. सुवर्णरेखा 4. वंशधारा
उपर्युक्त में से कौनसी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं ?
(A) 1 और 2 (B) 2 और 4
(C) 3 और 4 (D) 1 और 3

88. 'सियाचिन हिमनद' कहाँ स्थित है ?
(A) अक्साई चिन के पूर्व में
(B) लेह के पूर्व में
(C) गिलगिट के उत्तर में
(D) नुब्रा घाटी के उत्तर में

89. भारत के इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए–

	प्रसिद्ध स्थल	वर्तमान राज्य
1.	भीलसा	– मध्य प्रदेश
2.	द्वारसमुद्र	– महाराष्ट्र
3.	गिरिनगर	– गुजरात
4.	स्थानेश्वर	– उत्तर प्रदेश

उपर्युक्त में से कौनसे युग्म सही सुमेलित हैं ?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 4
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 2 और 4

90. संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, जिसमें–
(A) संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है
(B) सरकार, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है
(C) सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है
(D) सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किन्तु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है

91. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
कथन :
I. ध्वनि तरंग का तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है.
II. ध्वनि तरंग की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर होती है.
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
कथन :
I. ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती.
II. ध्वनि तरंगें प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं और संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है.
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है
(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है
(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
कथन :
I. भारत सरकार अधिनियम, 1935 से केन्द्र में द्वैध शासन आरम्भ हुआ.

II. प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई.

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

94. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

कथन :

I. जहाँगीर के राज्य-काल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुँची.

II. औरंगजेब का राजदरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था.

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

कथन :

I. पादप प्लवक महासागर में सर्वाधिक जैव कार्बन उत्पन्न करते हैं.

II. शैवाल शीत जल जीवोम में उत्पन्न होता है.

उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

96. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

कथन :

I. भूविक्षेपी वायु, समदाब रेखाओं के समांतर, 600 मीटर की ऊँचाई के ऊपर बहती है.

II. भूविक्षेपी वायु वह क्षैतिज वायु वेग है, जिसमें कोरिऑलिस बल क्षैतिज दाब बल का संतुलन करता है.

उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा एक सही है ?

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या है

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं तथा कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है

97. निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है ?

(A) सूत्रकणिका, केन्द्रक, हरितलवक

(B) सूत्रकणिका, गॉल्जीकॉय, केन्द्रक

(C) सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला, केन्द्रक

(D) हरितलवक, केन्द्रक, राइबोसोम

98. निम्नलिखित संक्रामक रोगों पर विचार कीजिए–

1. पीलिया
2. क्षयरोग
3. रेबीज
4. गठिया

उपर्युक्त में से कौनसा/से जल संक्रामक रोग नहीं है/हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 2, 3 और 4

(D) 1, 3 और 4

99. भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए–

1. इटानगर
2. इम्फाल
3. अगरतला
4. आइजोल

सूर्योदय के समय के हिसाब से उपर्युक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौनसा है ?

(A) 3, 2, 1, 4 (B) 2, 1, 4, 3

(C) 1, 4, 3, 2 (D) 4, 3, 2, 1

100. भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए–

1. शिकारी देवी
2. भद्रा
3. सिमलीपाल
4. पचमढ़ी

दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार, उपर्युक्त वन्य जीव अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौनसा है ?

(A) 1, 2, 3, 4 (B) 2, 4, 3, 1

(C) 2, 3, 4, 1 (D) 3, 1, 2, 4

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A) उत्तरी किवू, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है. कारबाख, अजरबैजान में स्थित है. जपोरिजिया, रूस और यूक्रेन के बीच एक विवादित क्षेत्र है.

2. (D) मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को प्रदान किया गया. इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने वर्ष 2023 में सम्पन्न एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता.
   - मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है.

3. (A) जब पानी में विद्युत् धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह इसे इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से मौलिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर देता है और यदि इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पवन या सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत से आती है, तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है.
   - वर्तमान में हरित हाइड्रोजन को सभी छोटे-बड़े उद्योगों के लिए जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

4. (A) पूर्वोत्तर राज्य असम में 7 अप्रैल, 1979 में असम के शिवसागर जिले में स्वतंत्र असम की माँग को लेकर गठित इस संगठन ने हाल ही में केन्द्र व असम सरकार से शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं.
   - शांति समझौता में संगठन के राजखोवा व अनूप चेतिया के नेतृत्व वाले गुट ने ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए है. इस शांति समझौता से परेश बरुआ उल्फा (स्वतंत्र) गुट इससे बाहर रहा.

5. (C) लैग्रेंज बिन्दु (एल-1) सूर्य की हैलो ऑर्बिट में है, जहाँ सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में सन्तुलन होता है.

- आदित्य एल-1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित धवन अन्तरिक्ष केन्द्र से पीएसएएलवी सी-57 के जरिए 2 सितम्बर, 2023 को किया गया था.

6. (A) एक्सपोसैट उपग्रह खगोलीय चरम स्थितियों में भी खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए भारत का पहला ध्रुवणमापी मिशन है, जो पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशन व आकाशगंगा आदि का अध्ययन करेगा. इसके साथ ही भारत, ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमरीका के बाद दूसरा देश है. एक्पोसैट उपग्रह को पीएसएलवीसी-58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है. इसमें विशेष अनुसन्धान कार्य हेतु दो पेलोड्स, पोलिक्स (Polix) तथा XSPET (X-RAY Spectroscopy) हुए हैं.

7. (C) **अटल सेतु–पूरा नाम**–अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी–न्हावा शेवा
   - कुल लम्बाई–21·8 किमी (समुद्र के ऊपर 16·5 किमी, जमीन पर 5·3 किमी)
   - उद्घाटन–12 जनवरी, 2024 (प्रधानमंत्री द्वारा)

   वित्त एजेंसी–कुल लागत (₹ 17,843 करोड़) का लगभग 80 प्रतिशत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (JICA) द्वारा व शेष केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा साझा किया गया है.

8. (A) **स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 पुरस्कार**
   - आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वितरण (8वाँ संस्करण).
   - सबसे स्वच्छ शहर (1 लाख प्लस जनसंख्या)–सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से.
   - इंदौर लगातार सातवें वर्ष प्रथम स्थान पर, स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले संस्करण (2016) में मैसूर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया था.
   - सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य–महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़.
   - सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड–महू छावनी बोर्ड (मध्य प्रदेश).
   - सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स–वाराणसी और प्रयागराज.

9. (A) **हिम तेंदुआ के सम्बन्ध में पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण**
   - **सर्वेक्षण कार्यक्रम**–एसपीएआई (Snow Leopard Population Assessment in India) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019 से 2023 के बीच दो चरणों में सम्पन्न.
   - कुल संख्या–718, सर्वाधिक, लद्दाख (477).
   - राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी; भारतीय वन्य जीव संस्थान.
   - हिम तेंदुआ; **वैज्ञानिक नाम**–Panthera uncia, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ **(IUCN)** द्वारा 'असुरक्षित' (Vulnerable) सूची में रखा गया है.

10. (A)
    - ब्रिक्स मूलतः BRIC के नाम से चार देशों यथा ब्राजील, रूस, भारत (इंडिया) व चीन का समूह था. इसे वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में UNGA से इतर **BRIC** विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया. इसकी पहली शिखर बैठक 16 जून, 2009 को रूस में **येकाटेरिनबर्ग में हुई थी.** दक्षिण अफ्रीका को अप्रैल 2011 में औपचारिक रूप से समूह का सदस्य बनाए जाने से यह BRIC से BRICS हो गया.
    - हाल ही में 1 जनवरी, 2024 से 5 नए सदस्य (इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र व संयुक्त अरब अमीरात) जुड़ने से यह संगठन अब 10 सदस्यीय हो गया है. हालाँकि, वर्तमान में भी इसका नाम BRICS ही है.

11. (D)
    - जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा (JAXA) द्वारा चन्द्र मिशन 'स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टीगेटिंग मून' (SLIM) को सफलतापूर्वक चन्द्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई.
    - अमरीका, सोवियत संघ, चीन व भारत के पश्चात् जापान विश्व का ऐसा पाँचवाँ देश है, जो चन्द्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा है.

12. (D)
    - यह छठा अवसर था जब फ्रांस का कोई राष्ट्रपति, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ है. हाल के वर्षों में 2016 में फ्रेंकोइस होलैंड, वर्ष 2008 में निकोलस सरकोजी, व 1998 में तात्कालीन राष्ट्रपति जैक शिराक सम्मिलित हुए हैं.
    - 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए वर्ष 2023 यानि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अलसीसी मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे.
    - 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की झाँकियों में ओवरऑल (ओडिशा) की झाँकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि राम मन्दिर थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश की झाँकी को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है.

13. (D)
    - हेनली एण्ड पार्टनर्स द्वारा जारी पासपोर्ट्स रैंकिंग में कुल छह देश (फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन) 194 देशों/गंतव्यों में वीजा रहित यात्रा के साथ प्रथम स्थान पर है.
    - हेनले पासपोर्ट्स रैंकिंग-2024 में भारत कुल 62 देशों/गंतव्यों में बिना वीजा यात्रा सुनिश्चित करते हुए 80वें स्थान पर है. यह पिछले वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त रैंकिंग 84 से 4 पायदान ऊपर है.
    - हेनले रैंकिंग में अफगानिस्तान सबसे अन्तिम स्थान पर है.

14. (D)
    - संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत् राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसम्बर, 2023 को किया है.
    - नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है.
    - 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से 5 वर्ष के लिए लागू होगी. वर्तमान में 31 मार्च, 2026 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं.

15. (C) प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य है. इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2024 को लॉन्च किया गया.

16. (C) 17. (C)

18. (A) मोदी सरकार के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में यह 12वाँ बजट (दूसरा अन्तरिम बजट) है. वहीं वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह लगातार छठा बजट है.

19. (C) 20. (C)

21. (D) प्रथम 5 मदें जिस पर सर्वाधिक व्यय का अनुमान है–
    (1) ब्याज भुगतान–11,90,440
    (2) परिवहन–5,44,039
    (3) रक्षा–4,54,773
    (4) प्रमुख सब्सिडी–3,81,175
    (5) राज्यों को अंतरण–2,86,808

22. (D) आय के साधनों की कुल मदें (यदि कुल आय ` 1 है)
(1) उधार और अन्य देयताएं (28 पै.), (2) आय कर (19 पै.), (3) माल और सेवा कर और अन्य कर (18 पै.), (4) निगम कर (17 पै.), (5) ऋण भिन्न प्राप्तियाँ (7 पै.), (6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (5 पै.), (7) सीमा शुल्क (4 पै.), (8) ऋण भिन्न पूँजी प्राप्तियाँ (1 पै.).

23. (A) केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा ₹ 16,85,494 करोड़ अनुमानित है. यह सकल घरेलू उत्पाद का 5·1 प्रतिशत है. उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5·9 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था, संशोधित आकलन में यह 5·8 प्रतिशत अनुमानित है.

24. (C)

25. (B) कला एवं संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार समाज सेवा व खेलकूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से चुने गए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया गया.

26. (C) गोल्डन ग्लोब अवार्डस् 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म (ड्रामा कैटेगरी) का पुरस्कार क्रिस्टोफरनोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर को दिया गया है.

27. (C) 28. (C)

29. (C)
- स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के 'मौरबी' नामक गाँव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था. इनके बचपन का नाम मूलशंकर था.
- इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तथा 1875 में आर्य समाज की मुम्बई में स्थापना की, जिसका मुख्यालय 1877 में लाहौर बनाया गया.
- दयानन्द सरस्वती ने गोधन संरक्षण के लिए 'गौरक्षिणी सभा' की स्थापना की तथा 'गौकरुणानिधि' नामक पुस्तक की रचना की.

30. (C) सुल्तान इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. रजिया ने सिंहासन पर बैठते ही पर्दा प्रथा त्याग दी और पुरुषों के समान कुबा (कोट) और कुलाह (टोपी) पहनकर दरबार में आने लगी.

31. (D) 32. (D) 33. (C) 34. (B)

35. (C) **दण्ड से सम्बन्धित प्रमुख शब्दावलियाँ**
- **क्षमा (Pardon)**—सजा को पूर्णतः माफ कर देना.
- **लघुकरण (Commutation)**—सजा की प्रकृति को बदलना जैसे—मृत्युदण्ड को कठोर कारावास में बदलना.
- **परिहार (Remission)**—सजा की अवधि को बदलना जैसे—2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना.
- **विराम (Respite)**—विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना जैसे—शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण.
- **प्रविलम्बन (Reprieve)**—किसी दण्ड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जैसे—फाँसी को कुछ समय के लिए टालना.

36. (D) NAAQ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् CPCB द्वारा अधिसूचित चिह्नित किए गए प्रदूषकों के सन्दर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं. NAAQS के तहत् प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है—पीएम 10, पीएम 2·5, SO_2, NO_2, CO, NH_3, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजो–पाइरीन, आर्सेनिक और निकिल.

37. (C) 38. (C) 39. (C) 40. (C)

41. (C) 42. (A)

43. (A) हंगरी और रोमानिया यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं. अन्य जो देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं—रूस, बेलारूस, पोलैण्ड, स्लोवाकिया आदि.

44. (B) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है, तो आरोप को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर चलाया जा सकता है. अतः भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया/महाभियोग लोक सभा या राज्य सभा में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है.

45. (C) 46. (B)

47. (C)
- अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व–कर्नाटक
- कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य–तमिलनाडु
- होकेरा आर्द्रभूमि—जम्मू और कश्मीर
- संस्थाम्कोत्ता—केरल

48. (C) 49. (D)

50. (A) घाटप्रभा, कर्नाटक में व हीराकुंड, ओडिशा में स्थित बाँध है.

51. (A)

52. (A) सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_2) अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस हैं.

53. (C)

54. (B) सायनोबैक्टीरिया और डायटम, प्राथमिक उत्पादक, जबकि कॉपिपोड और फोरैमिनिफेरा द्वितीयक उत्पादक हैं.

55. (B)
- परमार राजवंश ने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक पश्चिम मध्य भारत में मालवा और निकटवर्ती क्षेत्रों पर शासन किया.
- देवगिरि के यादव ने लगभग 850 ई. से 1335 ई. तक तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भू-भाग पर शासन किया जिसमें महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक व मध्य प्रदेश आदि सम्मिलित था.

56. (A) मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है. इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं. भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं जा सकता. मोमबत्ती जलने पर उसका कुछ भाग मोम के तौर पर नीचे जम जाता है और बाकी जलने पर ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है.

57. (C) इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है. ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है.

58. (C) 59. (D) 60. (A) 61. (B)

62. (D)

63. (B) 8 अगस्त को प्रतिवर्ष आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 में हुई थी. आसियान सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है. वर्ष 2023 के लिए आसियान दिवस की थीम 'ASEAN Matters : Epicentrum of Growth' है.

64. (A)

65. (B) मुद्रा गुणक की गणना आवश्यक आरक्षित अनुपात (Required reserve ratio) के व्युत्क्रम के रूप में की जाती है. मुद्रा गुणक का मान जनता तथा बैंकों के व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है.

66. (C) 67. (C) 68. (D) 69. (A)

70. (B)

71. (A)
- फाहियान—399–412 ई.
- ह्वेनसांग—630–645 ई.
- इत्सिंग—675–695 ई.

72. (A) अंकोरवाट मन्दिर भगवान विष्णु को समर्पित है.

73. (C)

74. (C)
- लाट–गुजरात
- पर्वतीय–हिमालयी क्षेत्र
- कलिंग–उड़ीसा (ओडिशा)

75. (C)
- नागर स्थापत्य शैली के मन्दिरों में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ के साथ इसके शिखर पर 'आमलक' की स्थापना होती है.
- देवगढ़ का दशावतार मन्दिर, झाँसी (उत्तर प्रदेश), भीतरगाँव का मन्दिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश), तिगवा का विष्णु मन्दिर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) आदि इस शैली में निर्मित प्रमुख मन्दिर हैं.

76. (A) आधार से शिखर तक सही क्रम है–
- अधिष्ठान–जगती–प्रदशिक्षा पथ–गर्भ-गृह–शिखर–आमलक
- अर्द्धमण्डप–मण्डप–महामण्डप–अन्तराल–उरुशृंग–कलश

77. (C) बराबर की गुफाएं, बिहार राज्य के जहानाबाद जिला से लगभग 25 किमी दूर मकदूमपुर नामक पहाड़ी क्षेत्रों में है.

78. (B) गुफाओं, पहाड़ों को तराश कर और महलों की दीवारों पर बने चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं. अजंता एलोरा और बाघ की गुफाएं इसके प्रमुख उदाहरण हैं. लेपाक्षी मन्दिर (आंध्र प्रदेश) की दीवारों पर भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं.

79. (B) 80. (D) 81. (B)

82. (A)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग –102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 से संवैधानिक दर्जा
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग –गैर-सांविधिक निकाय
- राष्ट्रीय विधि आयोग –गैर-सांविधिक निकाय
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग –गैर-सांविधिक निकाय

83. (B) सरकारी बॉण्ड बाजार और स्टॉक बाजार, पूँजी बाजार में सम्मिलित हैं. कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट, मुद्रा बाजार का हिस्सा है.

84. (C) तुर्की राज्यों के संगठन में अजरबैजान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, टर्की और उज्बेकिस्तान हैं.

85. (A) 'ब्लू कार्बन' तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहीत कार्बन है. मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय जंगलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन जमा करते हैं.

86. (A)

87. (B) ब्राह्मणी नदी एक ऋतु प्रवाह नदी है, जो उड़ीसा (ओडिशा) राज्य में बहती है. सुवर्ण रेखा, नदी झारखण्ड से निकलती है.

88. (D) 'सियाचिन हिमनद' नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है.

89. (A)
- भीलसा–मध्य प्रदेश
- द्वारसमुद्र–कर्नाटक
- गिरिनगर–गुजरात
- स्थानेश्वर–हरियाणा

90. (B) 91. (B) 92. (A) 93. (B)
94. (C) 95. (B) 96. (A) 97. (A)

98. (C) पीलिया (Jaundice) एक जल-संक्रामक रोग है. अन्य रोगों में जैसे– क्षयरोग (Tuberculosis) एक जीवाणु जनति रोग, रेबीज, विषाणु जनित रोग और गठिया एक गैर-संक्रामक रोग है.

99. (B)

100. (C) शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, कर्नाटक में, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, उड़ीसा (ओडिशा) में तथा पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है.

●●●

शेष पृष्ठ 42 का

चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स (2024) में सेना की टीम का प्रथम स्थान

चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में 2 चरणों में हुआ. पहले चरण में लद्दाख में लेह में आइस हॉकी व स्पीड स्केटिंग की स्पर्द्धाएं 2–6 फरवरी को हुईं, जबकि 21–25 फरवरी को जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग में स्की माउंटेनियरिंग (Ski Mountaineering), एल्पाइन स्नीइंग (Alpine Skiing), स्नोबोर्डिंग (Snowbording), नॉर्डिक स्कीइंग (Nordic Skiing) व गंडोला (Gandola) का आयोजन हुआ. यह पहला ही अवसर था जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख में भी हुआ. इससे पूर्व ऐसे तीनों खेल क्रमशः 2020, 2021 व 2023 में जम्मू-कश्मीर में ही कराए गए थे.

शान : खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाला हिम तेंदुआ (Snow Leopard), जिसे शीन-ए-शी (Sheen-e-She) तथा लद्दाख क्षेत्र में शान (Shan) नाम दिया गया था. इन खेलों का शुभंकर (Mascot) था.

दो चरणों में सम्पन्न चौथे **खेलो इंडिया विंटर गेम्स** में सर्वाधिक 10 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक जीतकर ओवरऑल चैम्पियनशिप सेना ने जीती. 9 स्वर्ण व 2 रजत पदकों के साथ दूसरा स्थान कर्नाटक का रहा. महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे, जबकि उत्तराखण्ड का पाँचवाँ स्थान रहा.

●●●

चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका

स्थान	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	स्वर्ण	रजत	कांस्य	योग
1	सेना	10	5	6	21
2	कर्नाटक	9	2	0	11
3	महाराष्ट्र	7	8	7	22
4	हिमाचल प्रदेश	4	4	9	17
5	उत्तराखण्ड	3	3	1	7
6	लद्दाख	2	6	7	15
7	तेलंगाना	2	1	0	3
8	उत्तर प्रदेश	2	1	0	3
9	जम्मू-कश्मीर	1	6	4	11
10	आईटीबीपी	1	4	3	8
11	मध्य प्रदेश	1	1	2	4
12	आन्ध्र प्रदेश	0	1	0	1
13	हरियाणा	0	0	3	3

सामान्य अध्ययन-I

1. दार्शनिक विषयों से सम्बन्धित बौद्ध ग्रंथ का नाम है–
(A) त्रिपिटक
(B) विनय पिटक
(C) अभिधम्म पिटक
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. जैन धर्म के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है/हैं ?
1. जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है.
2. ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए–
1. वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं.
2. छांदोग्योपनिषद् को सबसे प्राचीन उपनिषद् माना जाता है.
3. 'असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय' श्लोक, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है–
कूट :
(A) 2, 3 सही हैं
(B) 1, 2 सही हैं
(C) 1, 3 सही हैं
(D) 1, 2, 3 सही हैं

4. किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है ?
(A) परिपादल (B) तोलकप्पियम
(C) कुरल (D) अहनानरु

5. किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बाँध का निर्माण करवाया ?
(A) कृष्णदेव राय
(B) रामराय
(C) देवराय प्रथम
(D) हरिहर

6. सैन्धव सभ्यता के किस स्थल से ममी जैसी आकृति प्राप्त हुई है ?
(A) लोथल
(B) हड़प्पा
(C) मोहनजोदड़ो
(D) रोपड़

7. पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत (मैकाल पर्वत) की कन्या 'मेकलसुता' कहा गया है ?
(A) नर्मदा (B) ताप्ती
(C) गोदावरी (D) बेतवा

8. भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था–
(A) इल्तुतमिश
(B) इब्राहिम शर्की
(C) इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय
(D) मोहम्मद गेसूदराज

9. 'दीवान-ए-मखफी' शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई ?
(A) माहम अनगा
(B) जेबुन्निसा
(C) औरंगजेब
(D) सलीमा बेगम

10. निम्नलिखित स्मारकों को उनसे सम्बन्धित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(a) दोहरा गुम्बद	1. शेरशाह
(b) अष्टभुजीय मकबरा	2. मुहम्मद
	3. आदिल शाह
(c) सत्य मेंहराबीय मकबरा	4. बलबन
(d) गोल गुम्बद	5. सिकन्दर लोदी

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	3	2	4	1
(C)	4	1	3	2
(D)	4	3	2	1

11. किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था ?
(A) प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध
(B) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
(C) तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
(D) चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध

12. शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि 'विद्यापति' को संरक्षण प्रदान किया था ?
(A) मुबारक शाह शर्की
(B) हुसैन शाह शर्की
(C) इब्राहिम शाह शर्की
(D) मोहम्मद शाह शर्की

13. निम्नलिखित में से कौनसा/से सही सुमेलित है ?

पुस्तक	लेखक
1. किताब-उल-रेहला	–इब्नबतूता
2. तुगलकनामा	–जियाउद्दीन
3. शाहनामा	–फिरदौसी
4. तहकीक-ए-हिन्द	–अबुबकर

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) 1 तथा 3 (B) 2 तथा 4
(C) 1 तथा 4 (D) 2 तथा 3

14. मुगलकाल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था ?
(A) कारकुन
(B) आमिल
(C) सिपहसालार
(D) मीर-ए-बहर

15. गवर्नर जनरल तथा उनके समय हुए कार्य के गलत युग्म की पहचान कीजिए–
(A) BHU की स्थापना–लॉर्ड हार्डिंग
(B) CID की स्थापना–लॉर्ड कर्जन
(C) अम्बेला अभियान–लॉर्ड एल्गिन प्रथम
(D) AMU की स्थापना–लॉर्ड रीडिंग

16. भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी ?
(A) सरदार वल्लभभाई पटेल
(B) अबुल कलाम आजाद
(C) जे.बी. कृपलानी
(D) जवाहरलाल नेहरू

17. ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया ?
(A) 1772 में (B) 1813 में
(C) 1833 में (D) 1854 में

18. किस स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ने 'लाठी' और 'अखाड़ा' क्लब की स्थापना की ?
(A) चन्द्रशेखर आजाद
(B) सचिन्द्रनाथ सान्याल
(C) मास्टर सूर्यसेन
(D) बाल गंगाधर तिलक

19. 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को 'बूढ़ी गांधी' कहा जाता है ?
(A) वीणा चटर्जी
(B) उषा मेहता
(C) मातंगिनी हजारा
(D) लक्ष्मी सहगल

20. 1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रान्त से सिपाहियों का चयन नहीं किया था ?
(A) गोरखा
(B) सिख एवं पंजाबी
(C) मध्य प्रान्त
(D) उत्तर प्रान्त

21. क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार-पत्र पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए–
(A) जमींदार – सिराजुद्दीन
(B) भवानी मन्दिर – बारीन्द्र घोष
(C) फ्री हिन्दुस्तान – तारकनाथ दास
(D) संध्या – सचिन्द्रनाथ सान्याल

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था.
2. 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था.
3. 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता डब्ल्यू.एच. रसूल था.
उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए–
कूट :
(A) 1 और 2 (B) 2 और 3
(C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए–
1. फॉरवर्ड ब्लॉक
2. अगस्त प्रस्ताव
3. आजाद हिन्द फौज का गठन
4. मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस
कूट :
(A) 1, 2, 3, 4 (B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 4, 2, 3 (D) 4, 1, 2, 3

24. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है ?
(A) लॉर्ड कैनिंग
(B) लॉर्ड डलहौजी
(C) लॉर्ड लिटन
(D) लॉर्ड विलियम बेंटिक

25. महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था ?
(A) दक्षिण अफ्रीका के नटाल में (1906)
(B) चम्पारण में (1917)
(C) अहमदाबाद में (1918)
(D) दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में (1906)

26. इको साउण्डिंग का प्रयोग होता है–
(A) समुद्र की गहराई मापने के लिए
(B) ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए
(C) ध्वनि में कम्पन उत्पन्न करने के लिए
(D) भूकम्प की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए

27. यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए, तो सबसे अधिक सम्भावना किस बात की होगी ?
(A) पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी
(B) पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी
(C) हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी
(D) हमारे वर्ष की अवधि बढ़ जाएगी

28. नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है–
कथन (A) : बर्फ का टुकड़ा पेय को ठण्डा बना देता है.
कारण (R) : बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठण्डा हो जाता है.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए–
(A) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है
(B) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है
(D) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है

29. निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा एक सुमेलित नहीं है ?
(A) पैडोलॉजी–पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन
(B) ऐन्थोलॉजी–फूलों का अध्ययन
(C) एण्टोमोलॉजी–जन्तु विज्ञान की शाखा
(D) ट्रोफोलॉजी–पोषण का अध्ययन

30. भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष सम्वर्धन और प्राधिकरण केन्द्र (IN-SPACe) का मुख्यालय कहाँ है ?
(A) तिरुवनन्तपुरम
(B) बेंगलूरू
(C) अहमदाबाद
(D) नागपुर

31. आयोडीन की प्राप्ति होती है–
(A) सारगैसम से
(B) लेमिनेरिया से
(C) रोडिमेनिया पल्माटा से
(D) कॉंड्रस से

32. श्यानता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
1. तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है.
2. तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है.
3. ठोस में श्यानता का अभाव होता है.
4. शहद और ग्लसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) 1 तथा 2
(B) 3 तथा 4
(C) 1, 2 तथा 4
(D) 1, 3 तथा 4

33. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची I (धातु)	**सूची-II (सम्बन्धित रोग)**
(a) आर्सेनिक	1. फेफड़े का कैंसर
(b) कैडमियम	2. मस्तिष्क सूजन
(c) पॉलीविनाइल क्लोराइड	3. हड्डियों में कमजोरी
(d) बेरियम	4. श्वसन सम्बन्धी समस्या

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	2	3	1	4
(B)	1	3	2	4
(C)	4	3	2	1
(D)	1	3	4	2

34. एकसमान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसके गुरुत्व केन्द्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
(A) भार की ओर हट जाएगा
(B) भार से दूर हट जाएगा
(C) छड़ के केन्द्र पर रहेगा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है–
(A) ओजोन–कीटाणुनाशक के रूप में
(B) सल्फर–फंगीसाइड के रूप में
(C) ग्राफीन–आतिशबाजी के रूप में
(D) सिलिकॉन–कृत्रिम हीरा के निर्माण में

36. निम्नलिखित में से कौनसा पौधा कीट पकड़ता है ?
(A) स्लाइमैक्स (B) नीरियम
(C) नेपन्थस (D) एकेशिया

37. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I	**सूची-II**
(a) सोडियम बेंजोएट	1. फलों के रस का परिरक्षण
(b) कैल्सियम हाइड्राक्साइड	2. पेट्रोलियम शोधन में
(c) नाइट्रिक अम्ल	3. ब्लीचिंग पाउडर

(d) सल्फ्यूरिक अम्ल 4. फोटोग्राफी

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	4	3	2
(B)	1	3	4	2
(C)	1	2	3	4
(D)	1	4	2	3

38. **कथन (A) :** प्रकृति में लगभग 20-22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं.
कथन (R) : इनमें से सभी अमीनों एसिड स्तनियों के शरीर में नहीं बनते हैं.
दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (A) सही है, (R) गलत है
(B) (A) गलत है, (R) सही है
(C) (A), (R) दोनों सही है, तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(D) (A), (R) दोनों सही है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है

39. निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से 'सीलियक रोग' हो जाता है ?
(A) विटामिन C (B) विटामिन D
(C) विटामिन E (D) विटामिन K

40. रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान-प्रदान किसके माध्यम से होता है ?
(A) ग्रंथियों के माध्यम से
(B) ऊतक द्रव्य के माध्यम से
(C) रक्त के माध्यम से
(D) संयोजी ऊतक के माध्यम से

41. भारत के राष्ट्रपति के सन्दर्भ मे निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है.
2. भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

42. किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
1. व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए.
2. उसे दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

43. संविधान का कौनसा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से सम्बन्धित है ?
(A) भाग VII (B) भाग XIV
(C) भाग XVII (D) भाग XX

44. राष्ट्रपति की शक्तियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही हैं ?
1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है.
2. विधायी शक्ति के माध्यम से, वह पहले सत्र में संसद को सम्बोधित कर सकता है.
3. कार्यकारी शक्ति के माध्यम से, वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है.
4. वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है.
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) 1 और 2 (B) 2 और 3
(C) 3 और 4 (D) 2 और 4

45. भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौनसी विशेषताएं अमरीकी संविधान से ली गई हैं ?
1. मौलिक अधिकार
2. मौलिक कर्तव्य
3. न्यायिक समीक्षा
4. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
कूट :
(A) 1 और 2 (B) 1 और 3
(C) 1 और 4 (D) 2 और 4

46. "यदि हमारे संविधान के तहत् किसी पदाधिकारी की तुलना अमरीकी राष्ट्रपति से की जानी है, तो वह प्रधानमंत्री है न कि संघ का राष्ट्रपति". यह कथन निम्नलिखित में से किसका है ?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) मानवेंद्रनाथ राय
(C) बी.एन. राव
(D) बी.आर. अम्बेडकर

47. भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया' किस देश के संविधान से ली गई है ?
(A) संयुक्त राज्य अमरीका
(B) ब्रिटेन
(C) आयरलैंड
(D) यूएसएसआर

48. भारत में अविश्वास प्रस्ताव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है.
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है.
3. अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है.
उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

49. **कथन (A) :** संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है.
कारण (R) : उच्चतम न्यायालय को अवमानना के मामलों में दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है.
दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है
(C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है
(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है

50. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए–
सूची-I
(a) अनुच्छेद 60
(b) अनुच्छेद 90
(c) अनुच्छेद 94
(d) अनुच्छेद 155
सूची-II
1. राष्ट्रपति द्वारा शपथ
2. स्पीकर को हटाना
3. राज्य सभा के उपराष्ट्रपति को हटाना
4. राज्यपालों की नियुक्ति

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	3	2	4
(B)	1	2	3	4
(C)	1	4	2	3
(D)	4	1	3	2

51. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ?
    (A) दूसरी अनुसूची – संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन
    (B) तीसरी अनुसूची – शपथ का प्रारूप
    (C) सातवीं अनुसूची – विधायी शक्तियों का वितरण
    (D) पाँचवी अनुसूची – राज्य सभा में सीटों का आवंटन

52. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है.
    2. भारत में अमरीका की तरह अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं.

    उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है ?
    (A) केवल 1
    (B) केवल 2
    (C) 1 और 2 दोनों
    (D) न तो 1, न ही 2

53. विधान परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. विधान परिषद् में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधान सभा सदस्यों की एक-तिहाई निर्धारित की गई है.
    2. विधान परिषद् में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है.
    3. विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए.

    उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है ?
    (A) केवल 1
    (B) केवल 1 और 3
    (C) केवल 2 और 3
    (D) 1, 2 और 3

54. भारत में न्यायपालिका द्वारा 'रिट जारी करने का प्रावधान' किस देश से लिया गया है ?
    (A) ब्रिटेन (B) अमरीका
    (C) आस्ट्रेलिया (D) दक्षिण अफ्रीका

55. अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत् राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है ?
    (A) अनुच्छेद 166
    (B) अनुच्छेद 200
    (C) अनुच्छेद 201
    (D) अनुच्छेद 263

56. अनुच्छेद 352 के तहत् राष्ट्रीय आपात-काल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है ?
    (A) 2 माह के भीतर
    (B) 1 माह के भीतर
    (C) 6 माह के भीतर
    (D) 1 वर्ष के भीतर

57. नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. इसका प्रावधान संविधान के भाग-5 में किया गया है.
    2. यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है.
    3. वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता.

    कूट :
    (A) 1 और 2 (B) 2 और 3
    (C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

58. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

    सूची-I
    (a) दसवीं अनुसूची
    (b) नौवीं अनुसूची
    (c) सातवीं अनुसूची
    (d) आठवीं अनुसूची

    सूची-II
    1. भाषाएं
    2. दल-बदल कानून
    3. कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण
    4. विधायी शक्तियों का वितरण

    कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	1	2	4
(B)	2	3	4	1
(C)	3	1	4	2
(D)	4	2	1	3

59. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I	**सूची-II**
(a) भाग-6	1. आपात उपबन्ध
(b) भाग-14	2. निर्वाचन
(c) भाग-15	3. राज्य
(d) भाग-18	4. संघ व राज्य की सेवाएं

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	1	2
(B)	3	4	2	1
(C)	3	1	2	4
(D)	1	2	4	3

60. विधि आयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    1. भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था.
    2. वर्तमान में भारत में 22वाँ विधि आयोग कार्यरत् है, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं.
    3. इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है.

    उपर्युक्त कथनों में कौनसा/से सही हैं ?
    (A) 1 और 2 (B) 2 और 3
    (C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

61. पैगोंग त्सो झील के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
    1. यह झील सिक्किम में स्थित है.
    2. झील का एक-तिहाई हिस्सा चीन में और दो-तिहाई हिस्सा भारत में है.

    नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–
    (A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
    (C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

62. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए–

सूची-I (देश)	**सूची-II (राजधानी)**
(a) लिथुआनिया	1. बमाको
(b) अल्बानिया	2. विनियस
(c) माली	3. तिराने
(d) लिचेंस्टीन	4. वादूज

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	2	1	4
(B)	1	3	2	4
(C)	2	3	1	4
(D)	4	2	1	3

63. गन्ने के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
    1. यह एक ऊष्णकटिबन्धीय तथा साथ ही उपोष्णकटिबन्धीय फसल है.

2. गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है.

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

64. रोम किस नदी के तट पर स्थित है ?
(A) पियावे (B) टाइबर
(C) आडिजे (D) पो

65. भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है ?
(A) मालदीव, गैबॉन, ब्राजील
(B) सोमालिया, स्पेन, इण्डोनेशिया
(C) टोगो, कांगो, मालदीव
(D) मैक्सिको, भारत, केन्या

66. नदी डेल्टा के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही नहीं है/हैं ?
1. एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे–समुद्र या झील से मिलती है.
2. नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है.

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

67. निम्नलिखित में से कौनसे दो सही सुमेलित हैं ?

	ज्वालामुखी पर्वत	अवस्थिति
1.	कोटोपैक्सी	इक्वाडोर
2.	विसुवियस	फिलीपींस
3.	फुजियामा	जापान
4.	किलिमंजारो	अंगोला

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

कूट :

(A) 1 तथा 2 (B) 3 तथा 4
(C) 1 तथा 3 (D) 2 तथा 4

68. श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक् करता है–
(A) पुलिकट झील से
(B) चिल्का झील से
(C) कोल्लेरू झील से
(D) वेम्बनाड झील से

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है–

अभिकथन (A) : पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकम्पीय तरंग है.

कारण (R) : पृष्ठीय तरंग, तरंग की दिशा के समानान्तर कम्पन करती है.

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है
(C) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है

70. विति लेवु, वानुआ लेवु द्वीप हैं–
(A) ग्रेनाडा के (B) मॉरिशस के
(C) न्यूगिनी के (D) फिजी के

71. दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. यह गोंडवानालैंड का ही एक भाग है.
2. यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है.
3. यहाँ की चट्टानों में रूपान्तरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं.

उपर्युक्त में से सही कथन है–

(A) 1 तथा 2 (B) 2 तथा 3
(C) 1 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3

72. डागर बैंक, जार्जेज बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका भाग है ?
(A) महाद्वीपीय मग्नतट
(B) महाद्वीपीय मग्नढाल
(C) गहरे सागरीय मैदान
(D) महासागरीय गर्त

73. क्षोभ सीमा के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य नहीं है ?
(A) यह क्षोभमण्डल और ओजोन मण्डल को अलग करता है
(B) यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है
(C) इसकी मोटाई 1-1·5 किमी तक पायी जाती है
(D) इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं

74. काली मृदा के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं.
2. इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखण्डन से हुआ है.
3. इसे रेगुर कहा जाता है.

उपर्युक्त में से सही कथन है–

(A) 1 तथा 2 (B) 2 तथा 3
(C) 1 तथा 3 (D) 1, 2 तथा 3

75. निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है ?
(A) रोहतांग दर्रा – हिमाचल प्रदेश
(B) देब्सा दर्रा – जम्मू-कश्मीर
(C) माना दर्रा – उत्तराखण्ड
(D) नाथूला – सिक्किम

76. निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं–
(A) न्यूगिनी > बोर्नियो > ग्रीनलैंड > मेडागास्कर
(B) मेडागास्कर > ग्रीनलैंड > बोर्नियो > न्यूगिनी
(C) ग्रीनलैंड > न्यूगिनी > बोर्नियो > मेडागास्कर
(D) ग्रीनलैंड > मेडागास्कर > न्यूगिनी > बोर्नियो

77. जब जल प्रवाह में बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे हो जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है–
(A) अपघर्षण (B) सन्निघर्षण
(C) संक्षारण (D) जलगति क्रिया

78. मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है ?
(A) जम्मू-कश्मीर
(B) हिमाचल प्रदेश
(C) उत्तराखण्ड
(D) सिक्किम

79. ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से सम्बन्धित है ?
(A) तंजानिया (B) चिली
(C) मैक्सिको (D) ईरान

80. निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा सुमेलित नहीं है ?
(A) ग्रेट जल-प्रपात – पोटोमैक नदी
(B) सेलिलो जल-प्रपात – कोलम्बिया नदी
(C) हुंडरु जल-प्रपात – नर्मदा नदी
(D) जोग जल-प्रपात – शरावती नदी

81. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I (टाइगर रिजर्व)

(a) रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य
(b) अमनगढ़ टाइगर रिजर्व
(c) दुधवा टाइगर रिजर्व
(d) पीलीभीत टाइगर रिजर्व

सूची-II (जिला)

1. लखीमपुर-खीरी
2. पीलीभीत
3. चित्रकूट
4. बिजनौर

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	4	1	2
(B)	3	1	4	2
(C)	2	3	1	4
(D)	4	3	1	2

82. निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए–

कथन : एक लम्बी अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से महासागर अम्लीकरण होता है.

कारण : वायुमण्डल से CO_2 के अवशोषण के कारण समुद्र के पीएच मान में कमी आती है.

कूट :

(A) कथन और कारण दोनों गलत हैं
(B) कथन और कारण दोनों सही हैं
(C) कथन सही और कारण गलत है
(D) कथन गलत और कारण सही है

83. कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था ?

(A) पृथ्वी सम्मेलन
(B) जैव विविधता अभिसमय
(C) क्योटो प्रोटोकाल
(D) पेरिस समझौता

84. वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है ?

(A) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(B) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल (IPCC)
(C) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC)
(D) विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

85. पारिस्थितिक तन्त्र में ऊर्जा प्रवाह के सम्बन्ध में क्या असत्य है ?

(A) इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य-शृंखलाओं के माध्यम से होता है
(B) ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है
(C) प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है
(D) उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं

86. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) कब प्रारम्भ किया गया ?

(A) 2017 (B) 2018
(C) 2019 (D) 2020

87. निम्नलिखित में से कौनसा अभिसमय खतरनाक रसायनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है ?

(A) राटरडम कन्वेंशन
(B) स्टॉकहोम कन्वेंशन
(C) वियना कन्वेंशन
(D) बॉन कन्वेंशन

88. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए–

(a) प्रोजेक्ट एलिफेंट
(b) प्रोजेक्ट टाइगर
(c) प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल
(d) इण्डियन राइनों विजन, 2020

1. 1975 2. 1973
3. 2005 4. 1992

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	2	3	1
(B)	4	1	2	3
(C)	4	2	1	3
(D)	4	3	2	1

89. पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौनसी है ?

(A) जीन बैंक
(B) इन विट्रो जीन बैंक
(C) फील्ड जीन बैंक
(D) क्रायो बैंक

90. निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत् अधिसूचित नहीं किया जाता है ?

(A) राष्ट्रीय उद्यान
(B) वन्य जीव अभयारण्य
(C) टाइगर रिजर्व
(D) बायोस्फीयर रिजर्व

91. निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी ?

(A) कानपुर (B) प्रयागराज
(C) वाराणसी (D) बलिया

92. 'एक तहसील एक उत्पाद योजना' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?

1. यह भारत सरकार की एक पहल है.
2. 'एक जनपद एक उत्पाद' की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

कूट :

(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

93. मिशन कुशल कर्मी के सन्दर्भ में अग्र-लिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?

1. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया हैं.
2. इसके तहत् कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी.

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए–

कूट :

(A) केवल 1 (B) 1 तथा 2 दोनों
(C) केवल 2 (D) न तो 1 न ही 2

94. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. इस मिशन के तहत् उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोडमैप तैयार किया है.
2. ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा.
3. निर्मित रोडमैप के तहत् प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे.
4. मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोडमैप के लक्ष्यों को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूहों में बाँटा गया है.

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन कीजिए–

कूट :

(A) 1 और 2 (B) 3 तथा 4
(C) 1 तथा 4 (D) 1 तथा 3

95. एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है–

(A) काँच – फिरोजाबाद
(B) चिकनकारी – लखनऊ
(C) लकड़ी का काम – सहारनपुर
(D) टेरीकोटा – मिर्जापुर

96. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए–

सूची-I

(a) परिक्रमा मेला
(b) आयुर्वेद महोत्सव
(c) कजरी महोत्सव
(d) ध्रुपद मेला

सूची-II

1. झाँसी 2. वाराणसी
3. अयोध्या 4. मिर्जापुर

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	3	1	4	2
(B)	3	2	4	1
(C)	2	3	4	1
(D)	3	2	1	4

97. निम्नलिखित में से कौनसा सुमेलित नहीं है ?
(A) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट —मेरठ
(B) राष्ट्रीय चीनी अनुसन्धान संस्थान —कानपुर
(C) नेशनल इंस्टीट्यूट और बायो-लोजिकल्स —नोएडा
(D) राष्ट्रीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान —लखनऊ

98. ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है—
(A) आगरा (B) ग्रेटर नोएडा
(C) फिरोजाबाद (D) लखनऊ

99. उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौनसा जिला चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है ?
(A) लखीमपुर-खीरी
(B) बलिया
(C) सोनभद्र
(D) ललितपुर

100. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है ?
(A) राधा सागर झील — मथुरा
(B) कीठम झील — आगरा
(C) कीर्ति सागर झील — झाँसी
(D) सरसई नावर झील — इटावा

101. निम्नलिखित में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है ?
(A) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) —पेरिस
(B) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) —जिनेवा
(C) विश्व आर्थिक मंच (WEF) —न्यूयॉर्क
(D) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) —वाशिंगटन डी.सी.

102. केन्द्रीय टसर अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है ?
(A) मेघालय (B) बहरामपुर
(C) रांची (D) कोलकाता

103. निम्नलिखित में से कौनसा सुमेलित नहीं है ?
(A) विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस —5 जून
(B) विश्व वानिकी दिवस —21 मार्च
(C) विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस —28 जुलाई
(D) विश्व आर्द्रभूमि दिवस —2 फरवरी

104. प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाएं और उनके लक्ष्य के सम्बन्ध में कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है ?
(A) सर्व शिक्षा योजना—सम्पूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना
(B) शिक्षा मित्र योजना—प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना
(C) ऑपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना —प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाना
(D) शिक्षा गारण्टी योजना—सभी वर्गों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना

105. उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है ?
(A) मथुरा (B) आगरा
(C) मिर्जापुर (D) कन्नौज

106. भारत की जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है—
(A) यनम (B) कुरंगकुमे
(C) लांगलेंग (D) किफरे

107. भारत की जनगणना-2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केन्द्रशासित प्रदेश कौनसा है ?
(A) दिल्ली
(B) पुदुचेरी
(C) अंडमान निकोबार द्वीप समूह
(D) दमन एवं दीव

108. भारत की जनगणना-2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केन्द्रशासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौनसा है ?
(A) दिल्ली
(B) दादरा नगर हवेली
(C) अंडमान निकोबार द्वीप समूह
(D) लक्षद्वीप

109. 'सूर सरोवर पक्षी विहार' स्थित है—
(A) कन्नौज (B) मैनपुरी
(C) महोबा (D) आगरा

110. सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए—

सूची-I (किनारे बसे शहर)	सूची-II (नदी)
(a) मिर्जापुर	1. केन
(b) लखनऊ	2. गोमती
(c) बांदा	3. सई
(d) प्रतापगढ़	4. गंगा

दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए—
कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	2	1	3
(B)	4	2	3	1
(C)	2	4	1	3
(D)	3	2	1	4

111. उत्तर प्रदेश की योजनाओं में निम्नलिखित में से कौनसा सही सुमेलित नहीं है ?
(A) किसान मित्र योजना —2001
(B) किसान बही योजना —2002
(C) कृषक दुर्घटना बीमा योजना —2004
(D) कामधेनु योजना —2014

112. मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है/हैं ?
1. समिति में छः सदस्य होते हैं.
2. तीन सदस्य RBI से होते हैं.
3. अन्य तीन सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं.
4. RBI गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है.
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन कीजिए—
कूट :
(A) 1, 2 और 3
(B) 2, 3 और 4
(C) 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 तथा 4

113. खादी एवं ग्रामोद्योग के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. इसकी स्थापना 1967 ई. में हुई थी.
2. यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक शीर्ष संस्था है.
उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
कूट :
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1, न ही 2

114. भारत में वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. भारत में वैट का प्रारम्भ 1 अप्रैल, 2006 को किया गया था.
2. इसे एल.के. झा समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था.
उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है ?
कूट :
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1, न ही 2

115. कृषि वर्धक निधि की घोषणा किसके लिए की गई है ?

सभी प्रकार की मासिक पत्रिका मैगजीन पढ़ने वाले इस पेज को किलक करे जरूर करे 👇

https://t.me/Magazine9876

Those who read all types of monthly magazines must join this group.

Please touch this page

👆 👆

(A) कृषि अवसंरचना विकास
(B) एग्री स्टार्टअप्स
(C) कृषि निर्यात
(D) कृषि अनुसन्धान एवं विकास

116. राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था ?
(A) 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत्
(B) 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत्
(C) 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत्
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

117. मसाला बॉण्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. मसाला बॉण्ड विदेशी बाजारों से धन जुटाने हेतु भारतीय मुद्रा (रुपए) में जारी किया जाता है.
2. मसाला बॉण्ड केवल किसी भारतीय इकाई/कॉर्पोरेट संस्था द्वारा ही जारी किया जा सकता है.
3. पहला मसाला बॉण्ड सन् 2017 में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु जारी किया गया.

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं ?
(A) 1, 2 (B) 2, 3
(C) 1, 3 (D) 1, 2 और 3

118. निम्नलिखित में से सुमेलित है–
1. कस्तूरीरंगन समिति–राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से सम्बन्धित
2. आर.एन. मल्होत्रा समिति–MSMEs के ढाँचे की समीक्षा से सम्बन्धित
3. आबिद हुसैन समिति–छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव से सम्बन्धित

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए–
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

119. नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?
(A) इसकी स्थापना 1982 में हुई
(B) यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है
(C) यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित शीर्ष वित्तीय संस्था है
(D) इसका मुख्यालय मुम्बई में है

120. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
2. इसके कई उप-समूह हैं जिनमें खाद्य और पेय पदार्थ ईंधन तथा प्रकाश, आवास एवं कपड़े शामिल हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1, न ही 2

121. ट्राइफेड के बारे में निम्नलिखित में कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) ट्राइफेड का गठन वर्ष 1987 में हुआ
(B) इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया
(C) इसका मुख्य उद्देश्य उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है
(D) इसने अपने कार्यों की शुरूआत वर्ष 1998 में मुम्बई स्थित मुख्य कार्यालय से की

122. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए–

सूची-I
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
(b) अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड
(c) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड
(d) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

सूची-II
1. 1975 2. 1953
3. 1950 4. 1949

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए–
कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	1	2	3	4
(B)	3	2	4	1
(C)	2	3	4	1
(D)	4	3	2	1

123. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. मुद्रा अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है.
2. मुद्रा अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महँगा हो जाता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1, न ही 2

124. भारत में बेरोजगारी के आँकड़े प्रकाशित करता है–
(A) वित्त आयोग
(B) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
(C) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
(D) योजना आयोग

125. निम्नलिखित में से कौनसी समिति/समितियाँ गरीबी से सम्बन्धित है/हैं ?
1. लकड़वाला समिति
2. सी. रंगराजन समिति
3. तेंदुलकर समिति
4. नरसिंहम समिति

कूट :
(A) केवल 2 और 3
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) केवल 3 और 4

126. आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन (खुले बाजार की क्रियाएं) किसकी खरीद और बिक्री को सन्दर्भित करता है ?
(A) वाणिज्यिक बिल
(B) विदेशी मुद्रा
(C) सोना
(D) सरकारी ऋणपत्र

127. भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है–
(A) अहमदाबाद में
(B) हैदराबाद में
(C) चेन्नई में
(D) बेंगलूरू में

128. केन्द्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 'अमृत काल सप्तर्षि प्राथमिकताओं' में शामिल नहीं है–
(A) समावेशी विकास
(B) युवा शक्ति
(C) अवसंरचना और निवेश
(D) नारी सशक्तिकरण

129. हाल ही में चर्चित कडावुर स्लेण्डर लेरिस अभयारण्य कहाँ स्थित है ?
(A) तमिलनाडु (B) केरल
(C) तेलंगाना (D) आन्ध्र प्रदेश

130. प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया ?
(A) गुजरात (B) हरियाणा
(C) मध्य प्रदेश (D) महाराष्ट्र

131. किस राज्य सरकार द्वारा 'हमार बेटी, हमार मान' अभियान की शुरूआत की गई ?
(A) बिहार (B) हरियाणा
(C) पंजाब (D) छत्तीसगढ़

132. सुमेलित नहीं है–
(A) फॉरगॉटन रिफ्यूजीज–नन्दिता हक्सर
(B) द लिविंग माउण्टेन–पी.सी. बाला सुब्रमण्यम

(C) डिवोर्स एण्ड डेमोक्रेसी—सौम्य सक्सेना
(D) द लास्ट व्हाइट मैन—मोहसिन हामिद

133. सूची-I से सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए—

सूची-I
(a) लियो वराडकर
(b) बेंजामिन नेतन्याहू
(c) सत्विनी राबुका
(d) लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा

सूची-II
1. इजरायल के राष्ट्रपति
2. आयरलैंड के प्रधानमंत्री
3. ब्राजील के राष्ट्रपति
4. फिजी के प्रधानमंत्री

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए—

कूट :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(A)	4	3	2	1
(B)	2	1	4	3
(C)	1	2	3	4
(D)	2	1	3	4

134. जनवरी 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी ?
(A) बेंगलूरू (B) मंगलुरू
(C) धारवाड़ (D) बेल्लारी

135. सर्वाधिक वार्षिक आय (कमाई) करने वाली Top-25 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रही—
(A) इगा स्वियाटेक
(B) पी.वी. सिंधु
(C) एम्मा रेडकानू
(D) नाओमी ओसाका

136. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. खिरगीज जनजाति किर्गिस्तान में पाई जाति है.
2. कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति बुशमैन है.

सत्य कथन की पहचान कीजिए—
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न ही 1 और न ही 2

137. विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण (World employment and social outlook) रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है ?
(A) विश्व बैंक
(B) अंकटाड
(C) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(D) विश्व आर्थिक मंच

138. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौनसा है ?
(A) लखनऊ (B) अगरतला
(C) पटना (D) इंदौर

139. निम्नलिखित में से किस स्थान पर 18वें अन्तर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया ?
(A) लखनऊ (B) कोच्चि
(C) वाराणसी (D) हैदराबाद

140. खेलो इण्डिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश की मेजबानी में सम्पन्न हुए. उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजन नहीं हुआ ?
(A) लखनऊ (B) गोरखपुर
(C) कानपुर (D) वाराणसी

141. अप्रैल 2023 मे नाडा (NADA) द्वारा किस भारतीय महिला वेटलिफ्टर को 4 वर्षों के लिए प्रतिबन्धित किया गया है ?
(A) मीराबाई चानू
(B) संजीता चानू
(C) संगीता चानू
(D) अपर्णा चानू

142. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु केन्द्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है ?
(A) राजीव कुमार
(B) टी.वी. सोमनाथन
(C) अरविंद पनगड़िया
(D) के.एम. जोसेफ

143. किस राज्य के एक गाँव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है ?
(A) अरुणाचल प्रदेश
(B) त्रिपुरा
(C) मिजोरम
(D) गोवा

144. भारत का पहला इण्डियन बायोलोजिकल डाटा सेन्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है ?
(A) राजस्थान (B) नई दिल्ली
(C) हरियाणा (D) पंजाब

145. वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index), 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है ?
(A) 107वें (B) 110वें
(C) 111वें (D) 105वें

146. वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया ?
(A) The Seven Moons of Maali Almeida
(B) Prophet Song
(C) Small Cities of Joy
(D) Dance of the Eagle

147. 'सखारोव फ्रीडम पुरस्कार' किसके द्वारा दिया जाता है ?
(A) संयुक्त राष्ट्र संघ
(B) रूसी संघ द्वारा
(C) यूरोपीय संघ
(D) यूनिसेफ

148. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. विश्व का पहला नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम जार्जिया में स्थित है.
2. भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उदघाटन इंदौर में हुआ.

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा कथन सत्य है ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) न तो 1, न तो 2
(D) 1 और 2 दोनों

149. कृतज्ञ (KRITAGYA) हैकथान किस क्षेत्र से सम्बन्धित है ?
(A) कृषि
(B) विज्ञान और प्रौद्योगिकी
(C) स्टार्टअप
(D) शिक्षा

150. जूस (JUICE) मिशन का सम्बन्ध है—
(A) नासा (NASA)
(B) इसरो (ISRO)
(C) यूरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी (ESA)
(D) जाक्सा (JAXA)

उत्तर व्याख्या सहित

1. (C) अभिधम्म पिटक को सात पुस्तकों में विभाजित किया गया है, अर्थात् धातुकथा, धम्मसंगनी, पथन, कथावत्थु, विभंग, पुग्गलपन्नतुई और यमक. यह पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धान्त और दर्शन से सम्बन्धित है. विनय पिटक में संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम एवं विनियम शामिल है. सुत्तपिटक में मुख्य शिक्षण या धम्म शामिल है.

2. (B) महावीर के अनुसार प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है. भौतिक कारक नाशवान है, आध्यात्मिक कारक बाहरी है एवं लगातार स्वयं को विकसित कर रहा है. उनके अनुसार आत्मा कर्म के कारण

बन्धन की अवस्था में है. भगवान महावीर 24 महान् तीर्थंकरों की परम्परा में अन्तिम थे. ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे.

3. (D) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं. वेदों की संख्या तो 4 है, लेकिन वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को शामिल किया जाता है. छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद् माना जाता है तथा यह सामवेद का उपनिषद् है. 'असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय' श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद् से लिया गया है.
4. (C) कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है. इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है, इसे 'तमिल साहित्य का बाइबिल' अथवा 'पंचम वेद' भी माना जाता है. कुरल की रचना तिरुवल्लूवर ने की थी.
5. (C) संगम वंश के शासक देवराय प्रथम ने जनहित में अनेक कार्य किए जैसे—जल की समस्या के समाधान के लिए तुंगभद्रा नदी पर बाँध का निर्माण करवाया. सेना में मुसलमानों की भर्ती सर्वप्रथम देवराय प्रथम द्वारा की गई. 1420 में इटली का यात्री निकोलो कोन्टी देवरॉय प्रथम के दरबार में आया.
6. (A) लोथल से मिली ममी की आकृति से इसके प्राचीन मिस्र के साथ सम्बन्ध होने का अनुमान लगाया जाता है. लोथल खम्भात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है. इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव द्वारा की गई. लोथल में दुर्ग तथा आवासीय नगर के लिए पृथक्-पृथक् टीले नहीं थे, बल्कि समूचे क्षेत्र को एक दीवार से घेरा गया था.
7. (A) पुराणों के अनुसार माँ नर्मदा की उत्पत्ति के समय इनका वेग इतना था कि कोई पर्वत उनके आवेग को सहन नहीं कर पा रहा था, तब विंध्यपुत्र मेकल पर्वत ने आवेग को अपने ऊपर धारण किया इसलिए नर्मदा का नाम मेकलसुता भी है.
8. (C) इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय (बीजापुर) पहला शासक था, जिसने उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था. मोहम्मद गेसूदराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है. वली दकनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है.
9. (B) जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी. विद्रोही शहजादे अकबर का समर्थन करने के कारण औरंगजेब ने जेबुन्निसा को दिल्ली के निकट सलीमगढ़ के किले में कैद कर लिया था. कैद में रहते हुए जेबुन्निसा ने अनेक हृदय विदारक कविताएं 'दीवान-ए-मखफी' शीर्षक से लिखी.
10. (C)

● स्मारक	शासक
● दोहरा गुम्बद	सिकन्दर लोदी
● अष्टभुजीय मकबरा	शेरशाह
● सत्य मेंहराबीय मकबरा	बलबन
● गोल गुम्बद	मुहम्मद आदिल शाह

11. (A) प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध 1767–69 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ. इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों तथा निजाम से सन्धि कर एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाया. हालाँकि, कालान्तर में निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया. प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलेस्ट था. इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया तथा मद्रास की सन्धि करने पर विवश किया.
12. (C) जौनपुर का शर्की राजवंश कला एवं साहित्य का महान् संरक्षक था. इब्राहिम शाह शर्की ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर को कुछ समय के लिए संरक्षण प्रदान किया था. विद्यापति ने 'कीर्तिलता काव्य' में जौनपुर का रोचक वर्णन किया है.
13. (A)

● किताब-उल रेहला	इब्नबतूता
● तुगलकनामा	अमीर खुसरो
● शाहनामा	फिरदौसी
● तहकीक-ए-हिन्द	अलबरूनी
● चचनामा	अबूबकर
6. फतवा-ए-जहांदारी	जियाउद्दीन बरनी

14. (D) मुगलकालीन पदाधिकारी एवं उनके कार्य—
    - सिपहसालार-प्रान्त की व्यवस्था देखना व भूमि कर संग्रह में सहायता करना.
    - मीर-ए-बहर-सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना.
    - आमिल-यह परगने का वित्त अधिकारी था. इसका प्रमुख कार्य भूमिकर का निर्धारण तथा वसूली करना था.
    - कारकुन-इनका प्रमुख कार्य परगने के हिसाब-किताब को लिखना था.
15. (D) लॉर्ड चेम्सफोर्ड का भारत में कार्यकाल 1916 से 1921 तक था. इनके ही शासनकाल में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई.
16. (D) 14 जुलाई, 1942 को काँग्रेस के वर्धा अधिवेशन (गुजरात) में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. 7 अगस्त, 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ. इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन सरदार पटेल ने किया था. 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कुछ संशोधनों के पश्चात् स्वीकार कर लिया गया. इसी के साथ 9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हो गया. 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत् सभी काँग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.
17. (B) 1813 ई. में जब कम्पनी का चार्टर जारी किया गया, तो उसमें शिक्षा सम्बन्धी एक धारा जोड़ दी गई थी. गवर्नर जनरल और उनकी परिषद् कानूनी तौर पर यह निर्देश दे सकती है कि निजी क्षेत्रों से सैनिक, नागरिक और व्यावसायिक खर्च और ऋण का ब्याज घटा देने के बाद पट्टे, राजस्व और मुनाफे की बची हुई रकम में से प्रत्येक वर्ष कम-से-कम ₹ 1 लाख की कुल राशि साहित्य के पुनरुत्थान, पढ़े-लिखे भारतीयों को प्रोत्साहन देने और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के लिए खर्च की जाएगी.
18. (D) बाल गंगाधर तिलक ने 'गौहत्या विरोधी समिति' एवं लाठी तथा अखाड़ा क्लब की स्थापना की. तिलक ने मराठा तथा केसरी पत्रिका का सम्पादन किया. अपनी सजा के दौरान मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य की रचना की.
19. (C) भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान तामलुक में अंग्रेजों की गोली का शिकार हुई मातंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है. इसके द्वारा आन्दोलन के दौरान लगभग 6000 समर्थकों के साथ तामलुक पुलिस स्टेशन पर नियन्त्रण के लिए जुलूस निकाला गया था. उसी भीड़ के नियन्त्रण के लिए अंग्रेजों द्वारा चलाई गई गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी.

20. (C) 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख एवं पंजाबी तथा उत्तर प्रान्त से सिपाहियों का चयन किया था. अवध को सैनिकों की पौधशाला कहते थे, क्योकि 1857 के विद्रोह के पहले सेना में बंगाल एवं अवध के सैनिक सर्वाधिक थे, परन्तु विद्रोह के बाद उनकी संख्या घटा दी गई एवं उनकी जगह पंजाबी एवं गोरखा सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई.

21. (D) बंगाल विभाजन विरोधी आन्दोलन के दौरान 1906 में ब्रह्मबांधव उपाध्याय द्वारा संध्या समाचार-पत्र शुरू किया गया था. इसका सम्पादन और प्रकाशन ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने स्वयं किया था, जबकि सचिन्द्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की.

22. (D) 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था. 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता डब्ल्यू. एच. रसूल था, यह लन्दन से आया था तथा टाइम्स पत्र का संवाददाता था.

23. (C)
- फॉरवर्ड ब्लॉक – 3 मई, 1939
- अगस्त प्रस्ताव – 1940
- आजाद हिन्द फौज का गठन – 21 अक्टूबर, 1943
- मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस – 22 दिसम्बर, 1939

24. (B) विधवा पुनर्विवाह में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य तथा आचार्य ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का था. इसके अतिरिक्त धोंदो केशव कर्वे, मद्रास के वीरेसलिंगम पुंतुलु एवं विष्णुशास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान था. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, परन्तु उसे पारित करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है. कैनिंग ने 26 जुलाई, 1856 को हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम नियम XV पारित किया था.

25. (C) महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल जहाँ मजदूरों एवं मालिकों में प्लेग बोनस के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा था, में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का प्रयोग किया था. जिसके परिणामस्वरूप मजदूरों को 35 प्रतिशत बोनस का भुगतान प्राप्त होने का सकारात्मक परिणाम सामने आया.

26. (A) **इको साउण्डिंग**–महासागर या समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है, जो महासागर के तल से टकराकर लौट आती है. प्रतिध्वनि के लौटने में जो समय लगता है, उसके आधार पर गहराई निर्धारित कर ली जाती है.

27. (C) कैपलर के ग्रहों के गति सम्बन्धी नियमों के अनुसार, "किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है." दूरी बढ़ने के साथ परिक्रमण काल बढ़ेगा एवं दूरी कम होने के साथ परिक्रमण काल कम होगा.

28. (A) बर्फ का टुकड़ा पेय को ठण्डा बना देता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठण्डा हो जाता है.

29. (A) पैडोलॉजी उनके प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन है. यह पेडोजेनेसिस, मृदा आकारिकी और मृदा वर्गीकरण से सम्बन्धित है.

30. (C) भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिक्ष सम्वर्धन और प्राधिकरण केन्द्र (IN-SPACe) का मुख्यालय बोपल, अहमदाबाद में है.

31. (B) आयोडीन, लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है. सारगैसम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है. स्कॉटलैंड में रोडिमेनिया पल्माटा नामक शैवाल का प्रयोग तम्बाकू की भाँति किया जाता है. कॉंड्रस नामक शैवाल से श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो शृंगार प्रसाधनों सैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि बनाने के काम आता है.

32. (D) शहद और ग्लसरीन जैसे तरल पदार्थ में श्यानता अधिक होती है, इसलिए कम श्यानता वाले तरल की तुलना में उनका प्रवाह शीघ्रता से रूक जाता है. तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है. तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता में वृद्धि होती है. ठोस में श्यानता का अभाव पाया जाता है.

33. (D)
- आर्सेनिक – फेफड़े का कैंसर
- कैडमियम – हड्डियों में कमजोरी
- पॉलीविनाइल क्लोराइड – श्वसन सम्बन्धी समस्या
- बेरियम – मस्तिष्क सूजन

34. (A) किसी वस्तु का गुरूत्व केन्द्र वह बिन्दु होता है, जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, फिर वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए. इसलिए गुरुत्व केन्द्र छड़ की उस दिशा की ओर हट जाएगा जिस ओर भार रखा जाएगा.

35. (C) ग्राफीन कार्बन की पतली परत है, जिसकी मोटाई कार्बन के एक अणु के बराबर होती है. यह विद्युत् का सुचालक होता है. इसका प्रयोग कम्प्यूटर चिप, टच स्क्रीन व विभिन्न संचार उपकरण बनाने में किया जाता है. आतिशबाजी में फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है.

36. (C) नेपन्थस एक कीटभक्षी पौधा है, जो कीटों को पकड़ता है. यह प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है. नेपन्थस के अलावा घटपर्णी, युट्रीकुलेरिया भी कीटभक्षी पौधे हैं.

37. (B)
- सोडियम बेंजोएट–फलों के रस का परिरक्षण
- कैल्सियम हाइड्राक्साइड–ब्लीचिंग पाउडर
- नाइट्रिक अम्ल–फोटोग्राफी
- सल्फ्यूरिक अम्ल –पेट्रोलियम शोधन में

38. (C) प्रकृति में लगभग 20-22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं. इसमें से लगभग 10 अमीनो एसिड मानव शरीर में पाए जाते हैं, जबकि लगभग इतने ही अमीनो एसिड बाहर से लेने पड़ते हैं. अतः (A), (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है.

39. (B) विटामिन D की कमी से सीलियक रोग हो जाता है. इससे अस्थियों में विकृतियाँ तथा बौनापन विकसित हो जाता है. विटामिन D की कमी से होने वाले अन्य रोग टिटैनी, ऑस्टियोमैलीशिया है.

40. (B) रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान-प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है. ऊतक की प्रत्येक कोशिका इस तरल के द्वारा घिरी होती है. कोशिकाओं का सारा रासायनिक आदान-प्रदान कोशिका कला के आर-पार, इसी तरल के माध्यम द्वारा होती है.

41. (C) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, "भारत का एक राष्ट्रपति होगा." जबकि अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता का निर्धारण करता है. राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संविधान में केवल एक ही आधार बताया गया है और

वह है—संविधान का अतिक्रमण. अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है.

42. (C) राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है. वह राष्ट्रपति की भाँति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है. राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है. प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, हालाँकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. संविधान में किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल दो योग्यताएं निर्धारित की गई है—(1) वह भारत का नागरिक हो. (2) उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.

43. (D) संविधान का भाग XX में उल्लेखित अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से सम्बन्धित है.

44. (A) भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं. विधायी शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरूआत और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को सम्बोधित कर सकते हैं. संसद के सदनों के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी विधायी शक्ति के अन्तर्गत आती है. सैन्य शक्ति के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध या शान्ति स्थापना की घोषणा कर सकता है.

45. (B)
- मौलिक अधिकार — अमरीका
- मौलिक कर्तव्य — सोवियत संविधान (रूस)
- न्यायिक समीक्षा — अमरीका
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया — जापान

46. (D) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार, "यदि हमारे संविधान के तहत् किसी पदाधिकारी की तुलना अमरीकी राष्ट्रपति से की जानी है, तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ के राष्ट्रपति."

47. (C) भारतीय संविधान में 'राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया' आयरलैंड के संविधान से ली गई है. इसके अलावा राज्य के नीति-निदेशक तत्व तथा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली भी आयरलैंड से ही ली गई है.

48. (D) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अन्तर्गत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ लोक सभा में ही लाया जा सकता है. अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोक सभा के नियम 198 में है. इस नियम के तहत् लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है.

49. (B) संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ एवं कार्य सतत् स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं. उन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी सन्दर्भ के रूप में पहचाना जाता है. अनुच्छेद 129 के तहत् अवमानना के लिए दण्डित करने की उसकी शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे किसी भी कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है.

50. (A)
- (a) अनुच्छेद 60 — राष्ट्रपति द्वारा शपथ
- (b) अनुच्छेद 90 — राज्य सभा के उपराष्ट्रपति को हटाना
- (c) अनुच्छेद 94 — स्पीकर को हटाना
- (d) अनुच्छेद 155 — राज्यपालों की नियुक्ति

51. (D) राज्य सभा में सीटों के आवंटन के बारे में उपबन्ध चौथी अनुसूची में किया गया है, जबकि पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित है.

52. (A) भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है. भारत में अमरीका के विपरीत अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित की गई है.

53. (B) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद् में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान सभा सदस्यों के एक-तिहाई तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित की गई है. विधान परिषद् का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए.

54. (A) संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है. मौलिक अधिकारों के रक्षार्थ अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत् उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता है. यह रिट ब्रिटिश कानून से ग्रहण की गई है, जिसे विशेषाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है.

55. (B) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है, जबकि अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति या तो विधेयक को अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है.

56. (B) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 1 माह के भीतर स्वीकृति देना आवश्यक होता है. संसदीय अनुमोदन के पश्चात् आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है.

57. (C) भारतीय संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है. इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परन्तु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण नहीं करता. इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् यह भारत या किसी भी राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है.

58. (B)
- दसवीं अनुसूची — दल-बदल कानून
- नौवीं अनुसूची — कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण
- सातवीं अनुसूची — विधायी शक्तियों का वितरण
- आठवीं अनुसूची — भाषाएं

59. (B)
- संविधान का भाग-6 — राज्यों के लिए प्रावधान
- संविधान का भाग-14 — संघ व राज्य के अधीन सेवाएँ
- संविधान का भाग-15 — निर्वाचन
- संविधान का भाग-18 — आपात उपबन्ध

60. (A) भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 में किया गया था.

वर्तमान में भारत में 22वाँ विधि आयोग कार्यरत् है, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं. विधि आयोग का कार्यकाल समान्यतः 3 वर्ष का होता है. इसका कार्य मौजूदा कानूनों की प्रासंगिकता की जाँच करना है.

61. (D) पैगोंग त्सो झील लद्दाख में लगभग 4,350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है. यह दुनिया की सबसे ऊँची खारे जल की झील हैं. यह लगभग 160 किमी तक फैली हुई हैं तथा झील का एक-तिहाई हिस्सा भारत में और दो-तिहाई हिस्सा चीन में स्थित है.

62. (C)

देश	**राजधानी**
अल्बानिया	तिराना
लिथुआनिया	विनियस
लिचेंस्टीन	वादूज
माली	बमाको

63. (A) गन्ना ऊष्ण कटिबन्धीय तथा साथ ही उपोष्णकटिबन्धीय फसल है. यह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तथा 75 सेमी से 100 सेमी के बीच वार्षिक वर्षा वाले गर्म तथा आर्द्र जलवायु मे अच्छी तरह से वृद्धि करता है.

64. (B) इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है.

65. (A) भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है. इक्वाडोर, कोलम्बिया, ब्राजील (दक्षिण अमरीका), गैबॉन, कांगो, लोकतान्त्रिक गणराज्य, युगाण्डा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिपे, सोमालिया (अफ्रीका), मालदीव, इण्डोनेशिया, किरिबाती (एशिया).

66. (C) एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे–समुद्र या झील से मिलती है. गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है.

67. (C)

ज्वालामुखी पर्वत	**अवस्थिति**
कोटोपैक्सी	इक्वाडोर
विसुवियस	इटली
फुजियामा	जापान
किलिमंजारो	तंजानिया

68. (A) श्रीहरिकोटा आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अवस्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है. यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है. इस द्वीप पर सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र स्थित है.

69. (B) भूकम्पीय तरंगें मूल रूप से दो प्रकार की होती है–भूगर्भिक तरंगें और पृष्ठीय तरंगें. भूगर्भिक तरंगें मूल पर ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है और पृथ्वी के माध्य से यात्रा करने वाली सभी दिशाओं में संचलन करती है. भूगर्भिक तरंगें सतह की चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती है और तरंगों के समूह उत्पन्न करती है जिन्हें पृष्ठीय तरंगें कहा जाता है. यह तरंगें सतह के साथ चलती हैं. पृष्ठीय तरंगें प्रसार की दिशा के लम्बवत् कम्पन करती हैं तथा इन्हें सबसे हानिकारक तरंगें माना जाता है.

70. (D) फिजी में 333 द्वीप शामिल हैं, लेकिन इसकी 87 प्रतिशत आबादी दो द्वीपों–विति लेवु और वानुआ लेवु में केन्द्रित है.

71. (C) प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीन भूखण्ड प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों से निर्मित है. यह गोंडवानालैंड का ही एक भाग है. इसका निर्माण आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से हुआ है जिनका अब नीस एवं सीस्ट के रूप में रूपान्तरण हो चुका है.

72. (A) महाद्वीपों का विस्तृत सीमान्त, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों एवं खाड़ियों से घिरा होता है, महाद्वीपीय मग्नतट कहा जाता है. मग्नतट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र हैं. डागर बैंक एवं जार्जेज बैंक जैसे प्रमुख मस्त्यन क्षेत्र इसी के अन्तर्गत आते हैं. संसार का लगभग 20% पेट्रोलियम एवं गैस भी महाद्वीपीय मग्नतटों से प्राप्त किया जाता है.

73. (A) क्षोभमण्डल एवं समताप मण्डल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा या टोपोपाज कहा जाता है. यह 1-1·5 किमी मोटी परत होती है जिसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं. यहाँ तापमान स्थिर रहता है. क्षोभसीमा में हवा का तापमान विषुवत् रेखा पर –80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर –45 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है.

74. (D) काली मृदा का निर्माण क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के चादरीय निक्षेप एवं उनके विखण्डन से हुआ है. मृदा का रंग काला होने की वजह से इसे काली मिट्टी कहा जाता है. इस प्रकार की मृदा में सापेक्षतः लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं. यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जिसके कारण इसे कपासी मृदा या रेगुर भी कहा जाता है.

75. (B) देब्सा दर्रा जम्मू-कश्मीर में न होकर हिमांचल प्रदेश में अवस्थित है. यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है.

76. (C)

77. (B) जब किसी जल प्रवाह में बहने वाले पदार्थ आपस में घर्षण कर छोटे हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं, जबकि जब किसी जल प्रवाह में बहने वाले पदार्थ तल तथा किनारों को क्षारित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं. जब घुलनशील चट्टानें जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग हो जाती है, तो वह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है.

78. (B) मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है जिसे 'छोटा यूनान' के नाम से जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश में अवस्थित अन्य प्रमुख घाटियाँ हैं– सांगला घाटी, किन्नोर घाटी, पार्वती घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, चम्बा घाटी इत्यादि.

79. (B) ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमरीका महाद्वीप का सबसे ऊँचा सक्रीय ज्वालामुखी शिखर है, जो चिली एवं अर्जेन्टीना देश की सीमा पर स्थित है.

80. (C)
- हुंडरु – स्वर्णरेखा नदी जलप्रपात
- धुआधार – नर्मदा नदी जलप्रपात
- विक्टोरिया – जांबेजी नदी जलप्रपात

81. (A)

टाइगर रिजर्व	**जिला**
रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य	चित्रकूट
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व	बिजनौर
दुधवा टाइगर रिजर्व	लखीमपुर खीरी
पीलीभीत टाइगर रिजर्व	पीलीभीत

82. (B) उपर्युक्त कथन और कारण दोनों सत्य हैं. तीव्र आधुनिकीकरण के कारण उत्सर्जित हो रही CO_2 के वायुमण्डल से अवशोषण के कारण महासागरों के रसायनिक संगठन में तीव्र परिवर्तन हो रहा है तथा उनमें अम्लता के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है.

83. (C) क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी

उत्सर्जन के कटौती लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है. इस प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 में प्रभाव मे आया. कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया, जिसमें निम्नलिखित 3 'बाजार व्यवस्थाओं' का उल्लेख किया गया–

1. एमिशन ट्रेडिंग
2. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म
3. ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन

84. (D) वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी की जाती है. इस रिपोर्ट में निम्नलिखित जलवायु संकेतकों के बारे में विवरण जारी किया जाता है–तापमान, महासागरीय ऊष्मा, महासागरीय अम्लीकरण, समुद्र जलस्तर में वृद्धि, हिमनद, चरम मौसमी घटनाएं.

85. (C) पारिस्थितिक तन्त्र में प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाती है जिससे प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानातरित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा में कमी आती जाती है.

86. (C) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का प्रारम्भ वर्ष 2019 में किया गया. इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियन्त्रण और निवारण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना है. प्रारम्भ में इसके तहत् देश के 132 शहरों में वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक कणकीय पदार्थों (PM10 और PM2·5) की सान्द्रता में 20 से 30% की कमी लाने का लक्ष्य था. हाल ही में केन्द्र सरकार ने लक्ष्य को संशोधित करते हुए कणकीय पदार्थों (PM10 और PM2·5) की सान्द्रता में वर्ष 2026 तक 40% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

87. (A) वर्ष 2004 में लागू हुआ राटरडम कन्वेंशन का उद्देश्य खतरनाक रसायनों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में पक्षकार देशों के मध्य साझा जिम्मेदारी और प्रयासों को बढ़ावा देना है. इसमें कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है.

88. (C)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट – 1992
- प्रोजेक्ट टाइगर – 1973
3. प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल – 1975
4. इण्डियन राइनों विजन, 2020 – 2005

89. (D) पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक क्रायो बैंक है. जहाँ 100 वर्षों से अधिक के लिए पादपों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाना सम्भव होता है. इन विट्रो जीन बैंक में मध्यम अवधि 2 वर्ष से कम के लिए संरक्षण किया जाना सम्भव होता है तथा फील्ड जीन बैंक विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की पारम्परिक विधि होती है.

90. (D) बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं, जिनमें स्थलीय, समुद्री तथा तटीय परिस्थितिकी तन्त्र शामिल होते हैं. किसी बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षण के आधार पर कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र में विभाजित किया जाता है.

91. (B) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के अनुसार प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर गंगा के किनारे रिवर आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा. यह देश की इकलौती ऐसी रिवर आर्ट गैलरी होगी, जहाँ देश-दुनिया के पर्यटक कुम्भ और प्रयागराज की संस्कृति के रंगों से सीधा रूबरू हो सकेंगे.

92. (C) उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' योजना की सफलता के बाद 'एक तहसील एक उत्पाद' योजना पर कार्य करने का निर्णय लिया है.

93. (D) मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है.

94. (C) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए पाँच वर्ष का रोडमैप तैयार किया है. इसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूहों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा. निर्मित रोडमैप के तहत् 5 वर्षों के अन्दर राज्य में 5 लाख 50 हजार 868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाएगा. मिशन द्वारा इस रोडमैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूहों में बाँट दिया गया है.

95. (D) टेरीकोटा का काम गोरखपुर में होता है.

96. (A)
- परिक्रमा मेला – अयोध्या
- आयुर्वेद महोत्सव – झाँसी
- कजरी महोत्सव – मिर्जापुर
- धुपद मेला – वाराणसी

97. (A) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है.

98. (B) ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में स्थित है.

99. (C) उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है. ये चार राज्य हैं–छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड. उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा आठ राज्यों तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश (दिल्ली) से लगती है. राज्य की न्यूनतम सीमा हिमांचल प्रदेश से तथा सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है.

100. (C) कीर्तिसागर झील महोबा में स्थित है. यह झील राजा कीर्तिवर्मन द्वारा बनवाई गई थी.

101. (C) विश्व आर्थिक मंच (WEF) का मुख्यालय कोलोग्नी (जेनेवा) में है.

102. (C) 1. केन्द्रीय टसर अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्थान –रांची (झारखंड)
2. केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान संस्थान –बहरामपुर (पश्चिम बंगाल)
3. केन्द्रीय इरी अनुसंधान संस्थान –मेघालय

103. (A) विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवम्बर को तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है.

104. (D) **शिक्षा गारण्टी योजना**–यह योजना 1997 में शुरू की गई थी, जो बच्चे अब तक स्कूल नहीं जा पाए, उनको बुनियादी शिक्षा दिलाने का सर्व शिक्षा अभियान का यह एक महत्वपूर्ण घटक है.

105. (A) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे पहले मूर्ति निर्माण का केन्द्र स्थापित हुआ, जिसे मथुरा मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है. शुंग काल से लेकर गुप्तकाल के मध्य विकसित हुई मथुरा की कला में पाषाण एवं मृत्तिका के माध्यम से नवीन प्रयोग किए गए. यहाँ संस्कृति, धर्म और कला की कई त्रिवेणियों के दर्शन होते हैं.

106. (B) भारत की जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का कुरंगकुमे (111·01%) है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला नगालैंड का लांगलेंग (–58·39%) है.

107. (B) भारत की जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश क्रमशः केरल (1084) तथा पुदुचेरी (1037) है. देश मे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश क्रमशः हरियाणा (879) तथा दमन एवं दीव (618) है.

108. (B) भारत की जनगणना-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश क्रमशः बिहार (1106) तथा दिल्ली (11320) है. देश मे न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश क्रमशः अरुणाचल प्रदेश (17) तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह (46) है.

109. (D) सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है.
1. कन्नौज—लाख बहोशी पक्षी विहार
2. मैनपुरी—समान पक्षी विहार
3. महोबा—विजय सागर पक्षी विहार

110. (A) मिर्जापुर — गंगा
लखनऊ — गोमती
बांदा — केन
प्रतापगढ़ — सई

111. (B) किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी जोतों की जानकारी कराना था.

112. (D) मौद्रिक नीति समिति में छः सदस्य होते हैं, जिसमें तीन सदस्य RBI से होते हैं तथा तीन अन्य सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. RBI गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है.

113. (B) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 1957 में हुई. इसका मुख्यालय मुम्बई में है. यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाली एक शीर्ष संस्था है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना एवं विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करना है.

114. (D) सर्वप्रथम 1976 में एल.के. झा समिति के द्वारा वैट की अनुशंसा की गई थी तथा इसे असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल, 2005 को लागू किया गया था. यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण पर आरोपित किया जाता है.

115. (B) कृषि वर्धक निधि की घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए की गई है. इस निधि के गठन का उद्देश्य किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है.

116. (B) राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत् प्रारम्भ किया गया था. इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना था.

117. (A) मसाला बॉण्ड भारतीय कॉर्पोरेट द्वारा विदेशी बाजारों में धन जुटाने हेतु स्थानीय मुद्रा में न जारी करके भारतीय मुद्रा (रुपए) में जारी किया जाता है. पहला मसाला बॉण्ड सन् 2014 में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) द्वारा अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण हेतु जारी किया गया. मसाला बॉण्ड के माध्यम से एकत्रित पूँजी का एकीकृत टाउनशिप और सस्ते आवासीय प्रोजेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट में नहीं निवेशित किया जा सकता है और न ही इस पूँजी को पूँजी बाजारों में निवेशित किया जा सकता है.

118. (B) ● आर.एन. मल्होत्रा समिति—बीमा क्षेत्र में सुधारों से सम्बन्धित
● यू.के. सिन्हा समिति—एमएसएमई क्षेत्र के ढाँचे की समीक्षा से सम्बन्धित.

119. (B) नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई. यह वर्तमान में भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित शीर्ष वित्तीय संस्था है. यह प्रत्यक्ष ऋण आवण्टित नहीं करता है.

120. (B) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है तथा इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है. यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे—भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अन्तर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं. इसके कई उप-समूह हैं जिनमें खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन तथा प्रकाश, आवास एवं कपड़े, बिस्तर एवं जूते शामिल हैं.

121. (D) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) का गठन 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक—आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के माध्यम से जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना है. इसने अपने कार्यों की शुरूआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की.

122. (A) ● क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक —1975
● अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड —1953
● अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड —1950
● केन्द्रीय सिल्क बोर्ड —1949

123. (C) अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है. अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महँगा हो जाता है.

124. (B) भारत में बेरोजगारी सम्बन्धित आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी किए जाते हैं.

125. (B) स्वतंत्र भारत में अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है.
● योजना आयोग कार्य समूह (1962)
● वी.एम. दांडेकर और एन. रथ (1971)
● अलघ समिति (1979)
● लकड़ावाला समिति (1993)
● तेंदुलकर समिति (2009)
● रंगराजन समिति (2014)

126. (D) आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन (खुले बाजार की नीति) सरकारी ऋणपत्र के खरीद और बिक्री को सन्दर्भित करता है.

127. (C) भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई शहर में की जा रही है. यह पार्क 184·25 एकड़ में बनाया जा रहा है. इस पार्क का निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है. यह पार्क लगभग 71·7 लाख मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करने की क्षमता रखता है.

128. (D) केन्द्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 'अमृत काल सप्तर्षि प्राथमिकताओं' में शामिल हैं—
● समवेशी विकास
● अन्तिम छोर तक पहुँचना
● युवा शक्ति
● वित्तीय क्षेत्र
● हरित विकास

- क्षमता उभारना
- अवसंरचना एवं निवेश

129. (A) हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले कडावुर स्लेण्डर लेरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया. स्लेण्डर लेरिस छोटे निशाचर स्तन पायी है, जो वनों में रहते हैं और धीमी गति से पेड़ों पर चलते हैं तथा अपने जीवन का अधिकांश समय पेड़ों पर ही व्यतीत करते हैं.

130. (A) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया. यहाँ विश्व के पहले CNG टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ विश्व का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम होगा.

131. (A) हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 'हमार बेटी, हमार मान' अभियान की शुरूआत की गई. इस अभियान के तहत् महिला पुलिस अफसरों ने बालिकाओं से मुलाकात कर उनके कानूनी अधिकार, गुड टच बैड टच, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव एवं उनके अधिकारों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की.

132. (A) द लिविंग माउण्टेन के लेखक अमिताभ घोष है. पी.सी. बाला सुब्रमण्यम 'रजनी के मंत्र' पुस्तक के लेखक हैं.

133. (B) ● लियो वराडकर–आयरलैंड के प्रधानमंत्री
● बेंजामिन नेतन्याहू–इजरायल के राष्ट्रपति
● सत्विनी राबुका–फिजी के प्रधानमंत्री
● लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा–ब्राजील के राष्ट्रपति

134. (A) 28 जनवरी, 2023 को गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी. यह भारत का 7वाँ विश्वविद्यालय होगा, जहाँ फोरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार होंगे. उल्लेखनीय है कि पहला सेन्ट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो वर्ष 1897 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो 1904 से प्रारम्भ हुआ था.

135. (D) फोर्ब्स ने सालाना कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों कि सूची जारी की है, जिसमें नाओमी ओसाका (टेनिस) 51·1 मिलियन डॉलर आय के साथ शीर्ष स्थान पर रही, वहीं इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी पी.वी. सिंधु शामिल रही, जिन्हें 12वाँ स्थान प्राप्त हुआ.

136. (C) मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर का पठार और थ्यानशान पर्वतमाला के क्षेत्र में खिरगीज जनजाति निवास करती है. यह मंगोल प्रजाति से सम्बन्धित है तथा ऋतु प्रवास करते हैं. इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है. इनके निवास गृह को युर्ट कहते हैं. बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है. यह प्राय: नग्न रहते हैं. बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट तथा जंगली वनस्पतियों को एकत्र करना है. यह झोपड़ियों तथा गुफाओं में रहते है. यह मुख्यत: सर्वभक्षी होते हैं. दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं.

137. (C) विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण (World employment and social outlook) रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है.

138. (C) सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है. पटना नगर निगम ने 29 मई, 2023 को सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया.

139. (B) 18वें अन्तर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में किया गया.

140. (C) 2023 के खेलो इण्डिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, उत्तर प्रदेश के मेजबानी में सम्पन्न हुआ. यह आयोजन उत्तर प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर तथा वाराणसी में सम्पन्न हुआ.

141. (B) अप्रैल 2023 में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा भारतीय महिला वेटलिफ्टर संजीता चानू को 4 वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया गया.

142. (B) वर्ष 2023 में केन्द्र सरकार ने पेंशन के मुद्दे पर विचार करने एवं उससे सम्बन्धित अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन करेंगे.

143. (B) त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के दासपारा गाँव को देश के पहले जैव गाँव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है. यह गाँव देश का पहला संशोधित बायो विलेज है, जहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. इस गाँव मे कृषि में जैविक उर्वरक का ही उपयोग किया जाता है.

144. (C) भारत का पहला इंडियन बायो-लोजिकल डाटा सेन्टर हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है. ₹ 100 करोड़ की लागत से बनाए गए इस सुविधा सेन्टर में 1 घण्टे के अन्दर किसी बीमारी की जीनोम सिक्वेंसिंग की जा सकेगी. यह डाटा सेन्टर उच्च क्षमता वाले ब्रह्म सुपर कम्प्यूटर सुविधा से सुसज्जित है.

145. (C) वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, यह भारत में भुखमरी के गम्भीर स्तर को दर्शाता है. इस इंडेक्स में भारत के पडोसी देशों; पाकिस्तान (102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें) और श्रीलंका (60वें) ने भारत से बेहतर स्थान हासिल किया. इसकी गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है–अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर.

146. (B) वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच की पुस्तक प्रॉफेट सॉन्ग (पैगम्बर सॉन्ग) को प्रदान किया गया.

147. (C) सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है. वर्ष 2023 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता महसा अमिनी को प्रदान किया गया.

148. (D) भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर (मध्य प्रदेश) में किया गया. इसे इन्फेंट्री रिसर्च सेन्टर और म्यूजियम का नाम दिया गया है. इस इन्फेंट्री संग्रहालय में 1747 से 2020 तक इन्फेंट्री के इतिहास की सभी झलकियाँ मौजूद रहेंगी.

149. (A) कृतज्ञ (KRITAGYA) फसल सुधार हेतु त्वरित प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथान है. इसका उद्देश्य भारत में फसल उत्पादन में संधारणीयता और लचीलेपन को सुनिश्चित करना है. इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) के द्वारा किया जा रहा है.

150. (C) जूस (JUICE) मिशन का सम्बन्ध यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेन्सी से है. 13 अप्रैल, 2023 को इस अन्तरिक्ष एजेन्सी द्वारा बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए 'जूस' (JUICE) मिशन प्रारम्भ किया गया है. ●●●

आगामी बैंक पी.ओ., एम.बी.ए. आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न

उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता

1. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (MSME) का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है ?
(A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) 50

2. भारत के समग्र विनिर्माणी उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत रहता है ?
(A) 25 (B) 35
(C) 45 (D) 55

3. भारत के कुल वस्तुगत निर्यातों में एमएसएमई उत्पादों का योगदान 2022-23 में लगभग कितने प्रतिशत रहा ?
(A) 25 (B) 35
(C) 45 (D) 55

4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत् ₹ 2000 की कौनसी किश्त का वितरण 28 फरवरी, 2024 को किया गया ?
(A) 13वीं (B) 14वीं
(C) 15वीं (D) 16वीं

5. अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ने फरवरी 2024 में व्यक्त किया है ?
(A) 6·0 प्रतिशत (B) 6·5 प्रतिशत
(C) 7·0 प्रतिशत (D) 7·5 प्रतिशत

6. निफ्टी (NIFTY) किस शेयर बाजार से सम्बन्धित शेयर मूल्य सूचकांक है ?
(i) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज
(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
निम्नलिखित में से सही उत्तर छाँटिए–
(A) केवल (i)
(B) केवल (ii)
(C) (i) व (ii) दोनों
(D) (i) व (ii) में से कोई नहीं

7. 'निफ्टी' में कितनी कम्पनियों के शेयर मूल्य समाहित है ?
(A) 15 (B) 30
(C) 50 (D) 100

8. बाजार पूँजीकरण (M-Cap) की दृष्टि से फरवरी 2024 के अंत में अग्रलिखित में से किस कम्पनी का शीर्ष स्थान था ?
(A) टीसीएस
(B) अडाणी एण्टरप्राइजेज
(C) एचडीएफसी बैंक
(D) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.

9. प्रसिद्ध उद्यमी अजीम प्रेमजी आईटी क्षेत्र की किस कम्पनी के संस्थापक रहे हैं ?
(A) विप्रो (B) इन्फोसिस
(C) एचसीएल (D) एक्सेंजर

10. नैस्कॉम (NASSCOM) किस क्षेत्र की कम्पनियों का संगठन है ?
(A) सॉफ्टवेयर (B) दूरसंचार
(C) विद्युत् (D) वित्त

11. रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी निम्नलिखित में से किस निकाय के चेयरमैन जनवरी 2024 में नियुक्त किए गए हैं ?
(A) ट्राई (TRAI)
(B) इरडा (IRDA)
(C) सेबी (SEBI)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने जनवरी 2024 में व्यक्त किया है ?
(A) 6·3 प्रतिशत (B) 6·7 प्रतिशत
(C) 7·3 प्रतिशत (D) 7·7 प्रतिशत

13. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के जनवरी 2024 के पूर्वानुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में आर्थिक वृद्धि 2024 में सर्वोच्च रहेगी ?
(A) भारत (B) चीन
(C) जापान (D) अमरीका

14. केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के लिए 1 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट में सन्दर्भित वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है ?
(A) 2·1 प्रतिशत (B) 3·1 प्रतिशत
(C) 4·1 प्रतिशत (D) 5·1 प्रतिशत

15. सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अधिकृत पूँजी में वृद्धि सरकार ने फरवरी 2024 में की है. यह अधिकृत पूँजी अब कितनी की गई ?
(A) ₹ 21,000 करोड़
(B) ₹ 31,000 करोड़
(C) ₹ 41,000 करोड़
(D) ₹ 51,000 करोड़

16. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमाओं पर 2023-24 में कितने प्रतिशत ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड ने फरवरी 2024 में की है ?
(A) 7·25 प्रतिशत
(B) 8·25 प्रतिशत
(C) 9·25 प्रतिशत
(D) 9·40 प्रतिशत

17. 2023-24 की मौद्रिक नीति की छठी अन्तिम द्वैमासिक समीक्षा फरवरी 2024 में की गई. इस समीक्षा के बाद बैंकों के लिए रेपो दर अब कितनी है ?
(A) 3·5 प्रतिशत (B) 4·0 प्रतिशत
(C) 4·5 प्रतिशत (D) 5·0 प्रतिशत

18. निम्नलिखित में से किस दिन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है ?
(A) 24 जनवरी (B) 26 जनवरी
(C) 24 फरवरी (D) 26 फरवरी

19. केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2024 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर, 2024 से देश में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remuneration Prices) कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा ?
(A) ₹ 315 (B) ₹ 340
(C) ₹ 365 (D) ₹ 390

20. राजनीतिक दलों को चंदे प्रदान करने के लिए शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे फरवरी 2024 में रद्द कर दिया है. यह बॉण्ड किस बैंक से खरीदे जा सकते थे ?
(A) भारतीय रिजर्व बैंक
(B) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से
(C) केवल भारतीय स्टेट बैंक से
(D) चुनींदा अधिसूचित बैंकों से

21. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की फरवरी 2024 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2023 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी ?
(A) 89 करोड़ (B) 109 करोड़
(C) 119 करोड़ (D) 139 करोड़

शेष पृष्ठ 176 पर

समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इण्डिया कार्यक्रम द्वारा आयोजित पहले जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेन्दुओं की संख्या लगभग 718 है, हिम तेन्दुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में है ?
(A) लद्दाख
(B) उत्तराखण्ड
(C) हिमाचल प्रदेश
(D) सिक्किम

2. निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार कीजिए–
I. जननायक कर्पूरी ठाकुर
II. लालकृष्ण आडवाणी
III. एम. एस. स्वामीनाथन
IV. चौधरी चरण सिंह
V. पी. वी. नरसिंहराव
उपर्युक्त में से कितनों को वर्ष 2024 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई ?
(A) केवल 2 (B) केवल 3
(C) केवल 4 (D) सभी 5

3. समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य/संघ-शासित क्षेत्र में स्थित है ?
(A) अरुणाचल प्रदेश
(B) सिक्किम
(C) हिमाचल प्रदेश
(D) लद्दाख

4. समाचारों की सुर्खियों में रहा 'व्यास जी का तहखाना' किस शहर में स्थित है ?
(A) अयोध्या (B) मथुरा
(C) वाराणसी (D) उज्जैन

5. निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारम्परिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारम्भ करने की पहल प्रारम्भ की है ?
(A) कर्नाटक (B) केरल
(C) तमिलनाडु (D) असम

6. प्रयोगशाला में विकसित मांस के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
(A) सिंगापुर के रेस्तराओं और होटलों में प्रयोगशाला में विकसित मांस के व्यंजन परोसे जाते हैं
(B) प्रयोगशाला में विकसित मांस शाकाहारी है
(C) सेन्ट्रल मैरीन रिसर्च संस्थान, कोच्चि ने प्रयोगशाला में मछली के मांस को विकसित करने की परियोजना प्रारम्भ की है
(D) प्रयोगशाला में विकसित मांस स्वाद बनावट तथा पौष्टिक तत्वों के मामले में मूल उत्पाद की ही भाँति होता है

7. निम्नलिखित में से कौनसा राज्य समूह संवर्द्धित पारबती-काली सिंध–चम्बल-ईआरसीपी लिंक परियोजना का हिस्सा है ?
(A) मध्य प्रदेश, राजस्थान
(B) राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
(C) राजस्थान, उत्तर प्रदेश
(D) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश

8. 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ दी ईयर सम्मान प्रदान किया गया ?
(A) अमरीकी गायिका टेलर स्विफ्ट (मिडनाइट)
(B) माइली साइरस (एण्डलेस समर वैकेशन्स)
(C) लाना डेल रे (डिड यू नो दैट दियरस ए टनेल अण्डर ओशेन)
(D) जेनियल मोनी (दी एज ऑफ प्लेजर)

9. अमरीका गायिका टेलर स्विफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
(A) उनके गीत संग्रह 'मिडनाइट' को 66वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ दी ईयर सम्मान दिया गया
(B) टेलर विश्व की पहली ऐसी शख्स हैं जिनके चार गीत संग्रहों को एल्बम ऑफ दी ईयर अवार्ड मिला है
(C) टेलर स्विफ्ट ने कुल 14 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं
(D) उपर्युक्त सभी 26 एमी

10. 66वें ग्रैमी एवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवॉर्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया ?
(A) अमरीकी गायिका टेलर स्विफ्ट के गीत संग्रह 'मिडनाइट' को
(B) माईली साइरस के गीत फ्लावर
(C) किलर माइक के गीत साइंटिस्ट्स एण्ड इंजीनियर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

11. 66वें ग्रैमी अवार्ड्स-2024 में भारतीयों को मिले पुरस्कारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
(A) तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन–3 ग्रैमी पुरस्कार
(B) बाँसुरी वादक राकेश चौरसिया–2 ग्रैमी पुरस्कार
(C) शंकर महादेवन–2 ग्रैमी पुरस्कार
(D) गणेश राजगोपालन–1 ग्रैमी पुरस्कार

12. 66वें ग्रैमी अवार्ड्स-2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला ?
(A) दिस मोमेंट (शक्ति बैण्ड)
(B) मिडनाइट (टेलर स्विफ्ट)
(C) फ्लावर (माईली साइरस)
(D) साइंटिस्ट्स एण्ड इंजीनियर्स (किलर माइक)

13. 66वें ग्रैमी अवार्ड्स-2024 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित 'अबन्डस इन मिलेट्स को 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक परफार्मेंस में नामित किया गया
II. बेस्ट म्यूजिक परफार्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड 'पश्तो' को मिला
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) दोनों I एवं II
(D) न I और न II

14. 7 फरवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखण्ड का मुख्यमंत्री है ?
(A) शिबू सोरेन (B) हेमन्त सोरेन
(C) सीता सोरेन (D) चंपई सोरेन

15. समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य (स्वतंत्रता के बाद) कौनसा है ?
(A) उत्तर प्रदेश (B) उत्तराखण्ड
(C) मध्य प्रदेश (D) असम

16. समान नागरिक संहिता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. उत्तराखण्ड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी विधान सभा ने 7 फरवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया.
II. यह कानून उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा.
III. भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित अनुच्छेद

44 में सारे देश में समान नागरिक संहिता अपनाए जाने की अपेक्षा की गई है.

IV. उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सर्वोच्च न्यायालय की सेवा-निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है.

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

17. भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की बीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?
(A) म्यांमार
(B) भूटान
(C) नेपाल
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

18. चुनावी बॉण्ड योजना को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस बारे में निम्नलिखित में से किस कानून में किए गए संशोधनों को 'असंवैधानिक' करार दिया है ?
I. आयकर अधिनियम
II. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
III. कम्पनी अधिनियम
उपर्युक्त में से कितने सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

19. फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व में कहाँ बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्माण कराए गए हिन्दू मंदिर का उद्घाटन किया गया ?
(A) अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात)
(B) दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)
(C) बाली (इण्डोनेशिया)
(D) पोर्ट लुइस (मॉरिशस)

20. ट्रांसपेरेंसी इण्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है ?
(A) 80वें (B) 85वें
(C) 93वें (D) 97वें

21. निम्नलिखित साहित्यकारों के नामों पर विचार कीजिए–
I. संस्कृत साहित्यकार जगद्गुरु रामभद्राचार्य
II. उर्दू साहित्यकार गुलजार (सम्पूर्ण सिंह कालरा)
III. हिन्दी उपन्यासकार मृदुला गर्ग
IV. तमिल लेखक पेरूमल मुरूगन
उपर्युक्त में से कितनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

22. 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान में निम्नलिखित में किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है ?
I. सबको न्याय
II. नव भारत नव संकल्प
III. विधि जागृति अभियान
IV. न्याय सेतु
सही कूट हैं–
(A) केवल I एवं II
(B) केवल I, III, IV
(C) केवल III
(D) सभी I, II, III, IV

23. सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) इसका गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत् किया गया
(B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है
(C) यह एक गैर-सांविधिक निकाय है
(D) इस समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है

24. नीचे दिए गए कार्यक्रमों पर विचार कीजिए–
I. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
II. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
III. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
IV. सौभाग्य योजना
V. मिशन पोषण 2·0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी
उपर्युक्त में से कितने कार्यक्रमों ने 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 24·82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ?
(A) केवल 2 (B) केवल 3
(C) केवल 4 (D) ये सभी

25. उच्चाधिकार प्राप्त के राधाकृष्णन समिति ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रत्यायन (Accreditation) प्रणाली अपनाए जाने की सिफारिश की है ?
I. C से A^{++} तक का ग्रेड प्रणाली
II. बाइनरी प्रत्यायन प्रणाली
III. मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड प्रत्यायन प्रणाली
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल II
(B) केवल I एवं II
(C) केवल II एवं III
(D) उपर्युक्त सभी

26. इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलोग्स-2024 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वोत्तम नवोन्मेष पुरस्कार प्रदान किया गया ?
(A) SVAMITVA योजना
(B) PM SVANidhi योजना
(C) PM POSHAN योजना
(D) PM DevINE योजना

27. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के सन्दर्भ में भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है ?
(A) सभी वर्गों के लिए सकल नामांकन अनुपात–28·4%
(B) अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सकल नामांकन अनुपात–27·2%
(C) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सकल नामांकन अनुपात–25·8%
(D) अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात–26·9%

28. 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है ?
(A) जाति जनगणना
(B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की कार्यप्रणाली
(C) भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली
(D) राजकोषीय प्रबन्धन

29. निम्नलिखित में से किसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 'नॉटी बॉय' तथा 'स्मार्ट बॉय' कहा जाता है ?
(A) PSLV
(B) LVM3
(C) GSLV-F14
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

30. अभी हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टलों पर विचार कीजिए–
I. Navigate पोर्टल
II. प्रेस सेवा पोर्टल
III. स्थानीय केबिल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय पंजी का विकास
IV. केन्द्रीय संचार ब्यूरो

उपर्युक्त में से कौनसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहलें हैं ?
(A) केवल I एवं IV
(B) केवल II एवं III
(C) सभी I, II, III एवं IV
(D) केवल I एवं II

31. 'ओडिसियस' नामक एक अन्तरिक्ष यान अभी हाल ही में चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरा है. यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है ?
(A) चीन
(B) रूस
(C) सं. रा. अमरीका
(D) फ्रांस

32. सर्वोच्च न्यायालय ने चण्डीगढ़ नगर निगम के मेयर पद पर पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित करने में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया ?
(A) अनुच्छेद 141
(B) अनुच्छेद 142
(C) अनुच्छेद 143
(D) अनुच्छेद 144

33. ओपेन एआई द्वारा लॉन्च किए गए 'सोरा' (SORA) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?
(A) सोरा एक कृत्रिम मेधा मॉडल है, जो पाठ्य (Text) आधारित निर्देशों के अनुसार वास्तविक एवं काल्पनिक दृश्य सृजित कर सकता है
(B) सोरा केवल 30 मिनट तक की अवधि के टेक्स्ट-टू-वीडियो ही बना सकता है
(C) सोरा बहु अभिलक्षणों के साथ जटिल दृश्य सृजित करने में सक्षम है
(D) सोरा यह समझने में सक्षम है कि उसके उपयोगकर्ता ने क्या निर्देश दिया है, साथ ही यह भी कि ऐसी चीजें भौतिक जगत् में किस रूप में विद्यमान हैं

34. स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पण्डाराम भूमि निम्नलिखित में किस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में स्थित है ?
(A) लक्षद्वीप
(B) दादरा एवं नागर हवेली
(C) गोवा
(D) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

35. न्यायाधिकरण की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?
(A) न्यायाधिकरण, प्रशासनिक अथवा कर-विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं
(B) न्यायाधिकरण शासी कानूनों के तहत् सरकार को कोई नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते
(C) न्यायाधिकरण गैर-संवैधानिक निकाय है
(D) उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की निर्विवाद शक्ति प्राप्त है

36. भारत में सम्पोषणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें प्रारम्भ की गई हैं–
I. राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन
II. परम्परागत कृषि विकास योजना
III. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास
IV. नदियों के दोनों किनारों पर जैविक खेती का विकास
उपर्युक्त में से सही कथन है–
(A) केवल I, II एवं III
(B) केवल III एवं IV
(C) केवल I, III एवं IV
(D) सभी I, II, III एवं IV

37. नारंगी रंग का मेढक (Purple Frog) कहाँ पाया जाता है ?
(A) अन्नामलाई पहाड़ियाँ
(B) विन्ध्य पर्वत माला
(C) शिवालिक पहाड़ियाँ
(D) छोटा नागपुर

38. स्वीडन में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित 'इलेक्ट्रॉनिक मृदा (ई–सॉइल) किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है ?
(A) बारानी खेती
(B) हाइड्रोपोनिक्स
(C) ढालू क्षेत्रों में खेती
(D) चरागाही खेती

39. डार्क एनर्जी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए–
I. डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रहस्यमयी स्वरूप है, जो ब्रह्माण्ड की समग्र ऊर्जा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
II. ब्रह्माण्ड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी तथा 27% हिस्सा डार्क मैटर है.
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) दोनों I एवं II
(D) न I और न II

40. भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पायी जातीं ?
(A) कच्छ की खाड़ी
(B) सुन्दरवन डेल्टा
(C) मन्नार की खाड़ी
(D) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A) स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इण्डिया कार्यक्रम द्वारा कराए गए सेंसस के अनुसार 2023 में भारत में हिम तेन्दुओं की संख्या 718 थी. हिम तेन्दुओं की सर्वाधिक संख्या केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख (477) है, उसके बाद उत्तराखण्ड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21) तथा जम्मू एवं कश्मीर (9) का स्थान है.
2. (D)
3. (D) पूर्वी लद्दाख के चुशुल क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास चीनी सैनिक भारतीय चरवाहों से उलझ गए थे.
4. (C) वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में स्थित 'व्यास जी का तहखाना' में हिन्दुओं–व्यास परिवार के पुजारियों को पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान कर दी है.
5. (D) असम में माघ बिहू के कटाई त्यौहार पर भैंसों एवं बुलबुल की लड़ाई का आयोजन वर्षों से होता आ रहा था. असम सरकार इस पारम्परिक प्रदर्शन को फिर से चालू करना चाहती है.
6. (B) संवर्धित मछली का मांस या प्रयोगशाला में विकसित मछली का मांस मछली में विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके और उन्हें पशु घटक मुक्त मीडिया का उपयोग करके प्रयोगशाला सेटिंग में विकसित करके उत्पादित किया जाता है.
7. (A) 29 जनवरी, 2024 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संवर्द्धित पारबती-काली सिंध-चम्बल-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सम्पर्क परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए PKC–ERCP एक अन्तर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है.
8. (A) 9. (D) 10. (B)
11. (C) शक्ति बैण्ड में शामिल शंकर महादेवन, वी. सेल्वा गणेश एवं गणेश राजगोपालन को एक-एक ग्रैमी पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया.
12. (A)

13. (C) अबन्ड्स इन मिलेट्स गीत की रचना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीकी गायक फाल्गुनी के साथ मिलकर की है. उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित राकेश चौरसिया, अमरीकी बेंजो वादक बेला फलेक तथा बेस वादक एडगर मेयर के गीत 'पुश्तो' को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ग्रैमी पुरस्कार मिला.

14. (D) धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को 31 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार कर लिए जाने से उपजी परिस्थितियों के बीच हेमन्त सोरेन द्वारा इसी दिन मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद उन्हीं के मंत्रिमण्डल में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने 2 फरवरी, 2024 को झारखण्ड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.

15. (B)

16. (D) समान नागरिक संहिता के कतिपय प्रावधान हैं—पुत्रों एवं पुत्रियों को समान सम्पत्ति अधिकार, विधिमान्य एवं अविधिमान्य बच्चों के बीच भेद समाप्त, गोद लिए बच्चों एवं जैविक रूप से जन्मे बच्चों के बीच समावेशिता, मृत्योपरान्त समान सम्पत्ति अधिकार. लिव-इन-रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, परित्यक्त महिलाएं अपने अभिभावकों से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारिणी.

17. (A) भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 8 फरवरी, 2024 को तात्कालिक प्रभाव से म्यांमार की सीमा पर लोगों की वीजा मुक्त आवाजाही पर प्रतिबन्ध लगा दिया है. अब म्यांमार सीमा से भारत आने वाले विदेशियों के भारत द्वारा निर्गत वीजा के आधार पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा.

18. (C)

19. (A) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 फरवरी, 2024 को दुबई अबूधाबी शेख जायद मार्ग पर अबूधाबी में एशिया के सबसे बड़े हिन्दू मन्दिर का उद्घाटन किया गया. यह मन्दिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा दान दी गई 27 एकड़ भूमि पर कराया गया है.

20. (C) 21. (B)

22. (D) हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ द्वारा 24 जनवरी, 2024 को भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर उद्घाटन किया गया.

23. (C)

24. (C) नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी, 2024 को जारी Multidimensional Poverty in India Since 2005-06 में यह दावा किया गया है कि भारत में पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मिशन पोषण 2·0, सक्षम आँगनवाड़ी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रमों की बदौलत 2013-14 एवं 2022-23 के बीच 24·82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकल आए हैं.

25. (C)

26. (A) SVAMITVA योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, जो 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी. इस योजना को इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में आयोजित 'पब्लिक पॉलिसी डायलोग्स-2024 में इन्नोवेशन सैण्डबॉक्स प्रस्तुतीकरण में सर्वोत्तम नवोन्मेष पुरस्कार हेतु चुना गया.

27. (D) 28. (B)

29. (C) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा स्वदेशी संसाधनों से विकसित GSLV को पहले 'नॉटी बॉय' नाम दिया गया था, क्योंकि इसके 15 प्रेक्षणों में से 4 प्रक्षेपण असफल रहने के कारण इसे इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा 'नॉटी बॉय' नाम दिया गया, लेकिन 17 जनवरी, 2024 को इसी यान द्वारा भारत की तीसरी पीढ़ी के मौसम सम्बन्धी उपग्रह INSAT-3 DS को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए जाने पर इसे 'स्मार्ट बॉय' नाम दिया गया है.

30. (C) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 22 फरवरी, 2024 को नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत (NaviGate) पोर्टल, जो एक द्विभाषायी प्लेटफॉर्म है जिस पर सरकारी योजनाओं, पहलों एवं अभियानों के बारे में जानकारी दो भाषाओं में उपलब्ध है; प्रेस सेवा पोर्टल केन्द्रीय संचार ब्यूरो तथा स्थानीय केबिल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय पंजी का विकास पहलें लॉन्च कीं.

31. (C) अमरीकी अंतरिक्ष एजेन्सी 'नासा' द्वारा वित्तपोषित मानव रहित वाणिज्यिक रोबोट है, जो आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत् चन्द्रमा पर मानव अन्वेषणों का भविष्य में मार्ग प्रशस्त करेगा.

32. (B) चण्डीगढ़ मेयर के चुनाव में रिटर्निंग ऑफीसर अनिल मसीह द्वारा आप और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के पक्ष में पड़े 8 मतों को निरस्त करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया था. इसे पहले पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक खण्ड पीठ ने रिटर्निंग ऑफीसर के निर्णय को रद्द करते हुए आप-कांग्रेस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया. ऐसा अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकार के तहत् किया गया.

33. (B) सोरा केवल एक मिनट तक की अवधि के ही वीडियो जारी कर सकता है.

34. (A)

35. (C) भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323-A तथा 323-B जोड़कर न्यायाधिकरणों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है. अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से सम्बन्धित है, जबकि अनुच्छेद 323-B के प्रावधानों के अन्तर्गत संसद तथा राज्य विधानमण्डल करारोपण, विदेशी विनिमय आयात-निर्यात, उद्योग एवं श्रम, भूमि सुधार, शहरी सम्पत्ति पर सीमा, संसद/विधानमण्डलों के लिए चुनाव, खाद्य सामग्री, किराया एवं किराएदार अधिकार जैसे विषयों से सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु न्यायाधिकरण गठित करने के लिए कानून बना सकते हैं.

36. (A)

37. (A) तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों में बैंगनी मेढक की दो प्रजातियाँ– नासिका बट्राचुस सहाद्रेनसिस (Nasikabatrachus Sahadrensis) तथा नासिका बट्राचुस भूपति पाई जाती है. इसके अतिरिक्त केरल के पश्चिमी घाट में ये बहुतायत में पाए जाते हैं.

38. (B)

39. (C) डार्क एनर्जी एक अदृश्य प्रभाव है, जो ब्रह्माण्ड के त्वरित विस्तार के लिए उत्तरदायी है. यह गुरुत्वाकर्ष के विपरीत होती है, जो वस्तुओं को एक साथ आकर्षित करता है. डार्क एनर्जी एक प्राकृतिक बल है, जो आकाशगंगाओं को एक-दूसरे से दूर धकेलती है.

40. (B) भारत में प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मालवन, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में पाई जाती हैं. ●●●

भारतीय अर्थव्यवस्था : एक समीक्षा 2024 पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौनसा कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ किया गया ?
   (A) सर्वशिक्षा अभियान
   (B) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
   (C) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
   (D) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

2. 2014–23 अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौनसा कर सुधार नहीं अपनाया गया ?
   (A) सीमा शुल्कों की दरों में व्यापक रूप से कमी करना तथा विवेकीकरण
   (B) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू करना
   (C) निगम कर एवं आयकर दरों को कम करना
   (D) सोवेरियन वेल्थ निधियों एवं पेंशन निधियों को करारोपण से छूट देना

3. कारोबारी सुगमता बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित में से कौनसी पहल सहायक रही है ?
   I. विकास एजेण्डा में सरकार और निजी क्षेत्र की व्यापक साझेदारी.
   II. आत्मनिर्भर भारत हेतु नई सार्वजनिक उद्यम नीति.
   III. उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किया जाना.
   उपर्युक्त में से कितनी पहलें सही हैं ?
   (A) केवल 1
   (B) केवल 2
   (C) सभी 3
   (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. छोटे आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून में संशोधन किया गया है ?
   (A) कम्पनी अधिनियम, 2013
   (B) भारतीय दण्ड संहिता, 1862
   (C) ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016
   (D) विदेशी विनिमय का संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974

5. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बचाने तथा तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौनसे उपाय अपनाए गए ?
   I. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजना प्रारम्भ की गई.
   II. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की परिभाषा को संशोधित किया गया.
   III. खुदरा एवं थोक कारोबार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की परिधि में लाया गया.
   IV. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के विलम्बित भुगतानों की समस्या का निराकरण करने के लिए TReDS को लागू करना.
   उपर्युक्त में से कितने सही हैं ?
   (A) केवल 1 (B) केवल 2
   (C) केवल 3 (D) उपर्युक्त सभी

6. समावेशी आर्थिक नीतियों को अपनाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं हैं ?
   (A) महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन–12·56 करोड़
   (B) निर्धनों के लिए शौचालयों का निर्माण–11·72 करोड़
   (C) बैंकों में जन-धन खाते खोले गए–51·6 करोड़
   (D) पक्के मकानों का निर्माण–2·6 करोड़

7. नवम्बर 2023 में वृहत् जलविद्युत् सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता कितनी थी ?
   (A) 156·23 GW
   (B) 162·97 GW
   (C) 179·57 GW
   (D) 201·56 GW

8. वित्त वर्ष 2023-24 (AE) में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में सापेक्षिक हिस्से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सही सुमेलित है ?
   I. विनिर्माण : 17·7%
   II. निर्माण : 8·7%
   III. सेवाएं : 54·6%
   सही कूट है–
   (A) केवल I एवं II
   (B) केवल II
   (C) केवल II एवं III
   (D) I, II, III सभी

9. निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए–
   I. प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को नीची लागत वाले बैंक खातों तक पहुँच सुनिश्चित की है.
   II. प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) ने सरकारी लाभों को सीधे जन-धन खातों में अन्तरण सुनिश्चित किया है.
   सही कूट है–
   (A) कथन I तथा II दोनों सही हैं तथा कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण है
   (B) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
   (C) कथन I सही है, कथन II गलत है
   (D) कथन II सही है, कथन I गलत है

10. निम्नलिखित जिंसों पर विचार कीजिए–
    I. दुग्ध
    II. दलहन
    III. मसाले
    IV. गन्ना
    V. सब्जियाँ
    उपर्युक्त में से कौनसी जिंसों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है ?
    (A) केवल I, II एवं III
    (B) केवल I, III, V
    (C) केवल II, III, IV एवं V
    (D) I, II, III, IV एवं V सभी

11. निम्नलिखित में से किन वस्तु समूहों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है ?
    (A) फल, सब्जियाँ, गन्ना
    (B) चाय, गेहूँ, चावल
    (C) फिश फार्मों में उत्पादित मछली, कपास, चीनी
    (D) उपर्युक्त सभी

12. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
    I. खरीफ और रबी की 22 फसलों के लिए विपणन सत्र हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है.
    II. कोपरा (मिलिंग), कोपरा (गोला), डी-हस्कड कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कलेण्डर वर्ष के लिए घोषित किया जाता है.

III. गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है.

सही कूट है–

(A) केवल I

(B) केवल I एवं II

(C) केवल I एवं III

(D) I, II, III सभी

13. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

I. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 में बना.

II. जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा शासित 42 केन्द्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया.

सही कूट है–

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I एवं II दोनों

(D) न I और न II

14. भारत में ऑनलाइन भुगतानों हेतु निम्नलिखित में से कौनसा इण्डिया स्टैक की भुगतान परत का हिस्सा है ?

I. यूनीफाइड पेमेण्ट्स इण्टरफेस (UPI)

II. आधार पेमेण्ट्स ब्रिज (APB)

III. आधार समर्थित भुगतान सेवा (AEPS)

IV. पेटीएम

सही कूट है–

(A) केवल I, II, III

(B) केवल IV

(C) केवल I

(D) I, II, III, IV सभी

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

I. विश्व के सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक बाजारों में से एक प्रमुख बाजार भारत है.

II. फिनटेक उद्योग में विश्व में संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूके के बाद भारत का तीसरा स्थान है.

उपर्युक्त में से सही है–

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I एवं II दोनों

(D) न I और न II

16. वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से किस देश में खाद्य मूल्य सूचकांक सर्वाधिक था ?

(A) भारत (B) जर्मनी

(C) यूके (D) सं.रा. अमरीका

17. निम्नलिखित में से कौनसी योजना बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित किए जाने पर केन्द्रित है ?

I. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

II. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना

III. प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन

IV. प्रधानमंत्री आवास योजना

सही कूट है–

(A) केवल I, II

(B) केवल III, IV

(C) केवल I, III, IV

(D) I, II, III, IV सभी

18. निम्नलिखित में से किस पहल ने राजकोषीय दक्षता संवर्द्धन एवं संसाधनों के रिसावों के न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ?

I. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

II. जन-धन योजना–आधार मोबाइल–त्रयी

सही कूट है–

(A) केवल I (B) केवल II

(C) I एवं II दोनों (D) न I और न II

19. निम्नलिखित में से किसे 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' कहा जाता है ?

(A) लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(B) आँगनवाड़ी केन्द्र

(C) आयुष्मान भारत-हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र

(D) दिल्ली एवं पंजाब के मुहल्ला क्लीनिक

20. निम्नलिखित में से किसका सम्बन्ध शिक्षा से है ?

I. परख (PARAKH)

II. पीएम-श्री (PM SHREE)

III. निपुण भारत (NIPUN BHARAT)

IV. प्रथम (PRATHAM)

सही कूट है–

(A) केवल I, II, III

(B) केवल II, III, IV

(C) केवल I, III, IV

(D) I, II, III, IV सभी

21. निम्नलिखित में से कौनसी योजना उद्यमिता विकास में योगदान दे रही है ?

I. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

II. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

III. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

सही कूट है–

(A) केवल I एवं II

(B) केवल I, II, IV

(C) केवल I, II, III

(D) I, II, III, IV सभी

22. नारी शक्ति वन्दन अधिनियम का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किससे है ?

(A) सभी प्रकार के अत्याचारों से महिलाओं की सुरक्षा

(B) कक्षा 12 से स्नातकोत्तर तक लड़कियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

(C) लोक सभा एवं विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण

(D) स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में महिलाओं के लिए अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा

23. भारत सरकार ने कितनी महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

(A) 50 लाख (B) 1 करोड़

(C) 2 करोड़ (D) 3 करोड़

24. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?

I. माध्यमिक शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात 2004-05 में 24·5% से दोगुना से अधिक बढ़ाकर 2021-22 में 58·2% हो गया है.

II. उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात 2000-01 में 6·7% से 4·25 गुना बढ़कर 2021-22 में 28·5% हो गया.

सही कूट है–

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I एवं II दोनों

(D) न I और न II

25. 29 दिसम्बर, 2023 को भारत के विदेशी विनिमय प्रारक्षित भण्डार 623·2 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर थे. ये कितने महीने के आयात बिल का भुगतान करने में सक्षम थे ?

(A) 7 माह (B) 8 माह

(C) 9 माह (D) 10 माह

26. विगत दशक में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) स्थिर रही है. निम्नलिखित में से कौनसा निष्कर्ष उपर्युक्त कथन का समर्थन करता है ?

I. सितम्बर 2023 को भारत की कुल देयताओं जिनमें से अधिकांश अनिवसियों द्वारा किए गए निवेश हैं, में वर्ष-दर-वर्ष 6·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

II. सितम्बर 2023 को भारत की कुल आस्तियों, जिनमें से अधिकांश प्रारक्षित आस्तियाँ हैं, में वर्ष-दर-वर्ष 10·2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

शेष पृष्ठ 171 पर

आर्थिक घटनाचक्र : बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. वित्त वर्ष 2023-24 के द्वितीय त्रैमास (जुलाई-सितम्बर) में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा है ?
   (A) 1·0% (B) 1·7%
   (C) 2·3% (D) 3·1%

2. ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?
   (A) हमास-इजरायल युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीच हमास, हूती विद्रोहियों तथा हिजुबुल्ला के साझा हमलों से बचाव के लिए एक पहल
   (B) यह लाल सागर, अदन की खाड़ी के रास्ते मालवाहक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने सम्बन्धी एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है
   (C) यह पहल सं.रा. अमरीका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा प्रारम्भ की गई है
   (D) इसका सम्बन्ध लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर यमन के विद्रोहियों हूतियों द्वारा मिसाइलों/ड्रोनों से किए जा रहे हमलों से बचाव करने से है

3. भारत का पहला 'कृत्रिम मेधा शहर' किस शहर में विकसित किया जा रहा है ?
   (A) सिकन्दराबाद (तेलंगाना)
   (B) बेंगलूरू (कर्नाटक)
   (C) विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
   (D) लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

4. वर्ष 2024 के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   I. औसत दर्जे के मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2023 में ₹ 10860 प्रति क्विंटल से 3 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024 में ₹ 11160 प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
   II. बाल कोपरा (गोला) का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2023 में ₹ 11750 प्रति क्विंटल से 2 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024 में ₹ 12000 प्रति क्विंटल कर दिया गया है
   उपर्युक्त में से सही है–
   (A) केवल I
   (B) केवल II
   (C) I एवं II दोनों
   (D) न I और न II

5. भारत में कोपरा (नारियल) के उत्पादन और विपणन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
   I. केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष कलेण्डर वर्ष के लिए मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा (गोला) तथा डी-हस्कड कोकोनट के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित करती है.
   II. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (एनसीसीएफ) कोपरा और डी-हस्कड नारियल की खरीद कीमत सहायता योजना के तहत् सीधे किसानों से करती है.
   III. केरल तथा तमिलनाडु मिलिंग कोपरा के तथा कर्नाटक बाल कोपरा के बड़े उत्पादक राज्य हैं.
   उपर्युक्त में से सही है–
   (A) केवल I एवं II
   (B) केवल II एवं III
   (C) केवल I एवं III
   (D) I, II एवं III सभी

6. भारत नेट परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
   (A) इसके अन्तर्गत देश की 2·5 लाख ग्राम पंचायतों को 4G नेटवर्क युक्त ब्रॉडबैण्ड सेवाओं से जोड़ा जा रहा है
   (B) इसका क्रियान्वयन विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है
   (C) इस परियोजना हेतु संसाधन 'डिजिटल भारत निधि' से उपलब्ध कराए जाते हैं
   (D) 31 दिसम्बर, 2023 तक देश की सभी ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैण्ड सेवा से जुड़ चुकी है

7. भारतीय बैंकों की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ अनुपात सितम्बर 2023 में किस स्तर पर था ?
   (A) 1·2% (B) 0·8%
   (C) 0·6% (D) 0·4%

8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सितम्बर 2023 के अन्त में भारतीय बैंकों का पूँजी पर्याप्तता अनुपात कितना था ?
   (A) 14·6% (B) 15·8%
   (C) 16·6% (D) 17·3%

9. भारत में डिजिटल बैंकिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है ?
   I. वर्तमान में भारत में कतिपय फिनटेक्स 'नियो बैंक' के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं.
   II. भारत में जुपीटर, एफआईमनी, नियो, रोजर एक्स नियो बैंक्स के रूप में कार्यरत् है.
   सही कूट है–
   (A) केवल I (B) केवल II
   (C) I एवं II दोनों (D) न I और न II

10. 16वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है ?
    (A) डॉ. अरविन्द पनगढ़िया
    (B) डॉ. राजीव कुमार
    (C) अरविन्द सुब्रमण्यन
    (D) वी. अनन्त नागेश्वरम

11. 16वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
    I. इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत् 31 दिसम्बर, 2023 को किया गया.
    II. डॉ. अरविन्द पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
    III. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की अवधि के लिए होंगी.
    उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
    (A) केवल I एवं II
    (B) केवल II
    (C) I, II, III सभी
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. निम्नलिखित में से कौनसा कानून बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के नियम-कायदों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है ?
    I. संयुक्त राज्य अमरीका का महँगाई नियंत्रण अधिनियम (आईआरए)
    II. यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम)

सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

13. संयुक्त राज्य अमरीका में पारित महँगाई नियंत्रण अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
I. इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी विनिर्माण हेतु भारी सब्सिडी प्रदान की गई है.
II. विनिर्माण में स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान करना.
III. मुक्त व्यापार समझौते (FTA) करने वाले देशों से ही उपकरणों के इस्तेमाल को वरीयता प्रदान करना.
IV. चीन से आयातित उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाना
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

14. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2023 में हुई वृद्धि ने भारतीय रिजर्व बैंक को असुरक्षित खुदरा ऋणों पर जोखिम भारांकन को बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा ?
I. भारतीय क्रिप्टो करेंसी बाजार के परिमाण
II. इक्विटी व्युत्पन्नकों की ट्रेडिंग
III. तीनपत्ती, रमी, लूडो तथा क्रिकेट से सम्बन्धित प्रतिस्पर्धाएं
सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल I एवं II
(C) केवल I एवं III
(D) I, II, III सभी

15. प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसम्बर, 2023 को देश की पहली अमृत भारत ट्रेन्स को नवविकसित अयोध्या धाम स्टेशन से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया. ये हैं–
I. दरभंगा-अयोध्या धाम-आनन्द विहार टर्मिनल (नई दिल्ली)
II. माल्दा टाउन-सर एम. विश्वेसरइया टर्मिनल (बेंगलूरू)
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I एवं II दोनों (D) न I और न II

16. वर्ष 2023 में भारत से निर्यातित कॉफी का मूल्य कितना था ?
(A) ₹ 9585 करोड़
(B) ₹ 8723 करोड़
(C) ₹ 6984 करोड़
(D) ₹ 5255 करोड़

17. गारन्टीशुदा कीमत योजना किस दाल की खरीद के लिए प्रारम्भ की गई है ?
(A) मसूर (B) चना
(C) तूर (अरहर) (D) उड़द

18. किसानों से सीधे तूर (अरहर) दाल खरीदने की गारन्टीशुदा कीमत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) तूर की खरीद के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों से दाल खरीदी जाएगी
(B) दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नेफेड/एनसीसीएफ द्वारा की जाएगी
(C) खरीदी गई दाल का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (DBT) द्वारा किसानों के खातों में किया जाएगा
(D) पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसान खुले बाजार में तूर दाल की बिक्री नहीं कर सकेंगे

19. ओडिशा के निम्नलिखित प्रसिद्ध उत्पादों पर विचार कीजिए–
I. लांजिया साओरा (पेंटिंग)
II. डुंगरिया कोंध कढ़ाई वाली शॉल
III. खजूरी गुड़
IV. ढेंकनाल मगजी (खाद्य पदार्थ)
V. सिमिलीपाल काई चटनी
VI. नयागढ़ कांतिमुंडी बैंगन
VII. कोरापुट काला जारी चावल
उपर्युक्त में से कितने पदार्थों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) दर्जा प्रदान किया गया है ?
(A) केवल 4 (B) केवल 5
(C) केवल 6 (D) सभी 7

20. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर कितनी रह सकती है ?
(A) 6·3% (B) 6·8%
(C) 7·3% (D) 7·5%

21. वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम अग्रिम अनुमानों में अनुमानित क्षेत्रवार संवृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है ?
(A) कृषि पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वानिकी : 4·3%
(B) विनिर्माण : 6·5%
(C) निर्माण : 10·7%
(D) सेवाएं : 7·7%

22. समाचारों की सुर्खियों में रहा 'स्वयं सिद्ध' के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?
(A) योग को लोकप्रिय बनाने की जनजागरण पहल
(B) भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय उत्पाद
(C) आयुष औषधियों के विपणन का एकीकृत कार्यक्रम
(D) छोटे बच्चों को पढ़ाने की एक अभिनव तकनीक

23. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए–
I. आइसलैण्ड
II. लीश टेंस्टीन
III. नॉर्वे
IV. स्विट्जरलैण्ड
उपर्युक्त में से कितने देश यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के सदस्य हैं ?
(A) केवल 2
(B) केवल 3
(C) सभी 4
(D) उपर्युक्त से कोई नहीं

24. विशेष आहरण अधिकार (SDR) के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) एसडीआर एक अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व है जो सदस्य राष्ट्रों के विदेशी विनिमय रिजर्व का हिस्सा है
(B) एसडीआर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्गत एक करेंसी है
(C) एसडीआर का सृजन अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान हेतु किया गया था
(D) एसडीआर का मूल्य अमरीकी डॉलर, यूरो, युआन, येन, ब्रितानी पाउण्ड से युक्त करेंसी बास्केट के आधार पर तय होता है

25. भारत सरकार के प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए–
I. निबल प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष 2013-14 में ₹ 6·38 लाख करोड़ से 160·32% बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 16·64 लाख करोड़ हो गया.
II. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में प्रत्यक्ष कर वर्ष 2013-14 में 5·62% से बढ़कर 2022-23 में 6·11% हो गया.
उपर्युक्त में से सही है–
(A) केवल I (B) केवल II
(C) केवल I एवं II(D) न I और न II

26. वर्ष 2022-23 में भारत में कितने आयकर रिटर्न दाखिल किए गए ?
(A) 5·39 करोड़ (B) 6·38 करोड़
(C) 7·96 करोड़ (D) 7·78 करोड़

27. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) इस योजना की घोषणा 22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की गई

(B) इस योजनान्तर्गत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे
(C) इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा
(D) योजना का लक्ष्य निर्धनों एवं मध्य वर्ग के परिवारों में बिजली बिल की लागत को कम करना है

28. किसी देश द्वारा निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में किए गए लेन-देनों पर विचार कीजिए–
I. वस्तुओं का व्यापार
II. सेवाओं का व्यापार
III. हस्तान्तरण भुगतान
उपर्युक्त में से कितने प्रकार के लेन-देन भुगतान सन्तुलन के चालू खाते के संघटक हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

29. भारत में विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक कौनसा निकाय है ?
(A) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
(B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) भारतीय स्टेट बैंक
(D) भारतीय प्रतिभूतियाँ एवं विनिमय बोर्ड

30. भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जारी एक अध्ययन 'मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इन इण्डिया सिंस 2005-06' के अनुसार 2013-14 एवं 2022-23 के बीच भारत के कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं ?
(A) 24·8 करोड़ (B) 23·5 करोड़
(C) 22·8 करोड़ (D) 21·6 करोड़

31. नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार 2013-14 एवं 2022-23 के बीच बहुआयामी निर्धनता में रह रहे लोगों की संख्या के सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई थी ?
(A) मध्य प्रदेश (B) राजस्थान
(C) उत्तर प्रदेश (D) बिहार

32. बहुआयामी निर्धनता की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है ?
(A) सबीना एल्काइर एवं जेम्स फोस्टर
(B) अमर्त्य सेन
(C) महबूब अल हक
(D) जीन ड्रेज़

33. नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस निकाय के साथ मिलकर राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक विकसित किया है जिसको प्रयुक्त करके राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर बहुआयामी निर्धनता का आकलन किया जा सकता है ?
I. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
II. ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एण्ड ह्यूमन डेवलेपमेंट एनीशिएटिव
III. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
IV. विश्व बैंक
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 4

34. अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन के महत्वपूर्ण मार्ग हैं–
I. होर्मुज की खाड़ी
II. मलक्का जलडमरूमध्य
III. बाब अल-मांडेब जलडमरूमध्य
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) सभी 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

35. वर्ष 2022-23 (ब.अ.) में केन्द्र एवं राज्यों का शिक्षा पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत था ?
(A) 6·5% (B) 7·2%
(C) 9·5% (D) 10·6%

36. वर्ष 2022-23 (ब.अ.) में केन्द्र एवं राज्य सरकारों का स्वास्थ्य पर व्यय इनके सम्मिलित कुल व्यय का कितने प्रतिशत था ?
(A) 3·2% (B) 5·3%
(C) 6·1% (D) 6·9%

37. भारत में सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है–
(A) एचडीएफसी बैंक
(B) आईसीआईसीआई बैंक
(C) एसबीआई कार्ड्स
(D) एक्सिस बैंक

38. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए–
I. आन्ध्र प्रदेश II. गुजरात
III. कर्नाटक IV. तमिलनाडु
उपर्युक्त में से कितने राज्य पाँचवें लॉजिस्टिक्स, ईज़ एक्रास डिफरेन्ट स्टेट्स (LEADS) 2023 में 'फास्ट मूवर्स' संवर्ग में है ?
(A) केवल 2
(B) केवल 3
(C) सभी 4
(D) उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

39. नीति आयोग द्वारा विकसित बहुआयामी निर्देशांक के आगणन में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया गया है ?
(A) परिवार का आय स्तर
(B) नागरिकों के बैंक खाते
(C) नागरिकों की आवास व्यवस्था
(D) नागरिकों को उपलब्ध पेयजल सुविधा

40. निम्नलिखित में से कौनसा राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग, 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी (Best Performer) संवर्ग में है ?
I. गुजरात II. महाराष्ट्र
III. कर्नाटक IV. तेलंगाना
सही कूट है–
(A) केवल I एवं III
(B) केवल I, II, III
(C) केवल I
(D) I, II, III, IV सभी

उत्तर व्याख्या सहित

1. (A)
2. (A) हमास-इजरायल युद्ध से उपजी परिस्थितियों के बीच ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले ऐसे सभी जहाजों पर ड्रोनों और रॉकेटों से हमले किए हैं जिन पर इजरायल समर्थक देशों के झण्डे लगे हैं.
3. (D) उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में भारत का पहला 'कृत्रिम मेधा शहर' (AI City) विकसित करने पर कार्य कर रही है.
4. (C) 5. (D)
6. (D) 11 दिसम्बर, 2023 तक देश की 208635 ग्राम पंचायतों तक 675466 किमी ऑप्टीकल फाइबर केबिल विछायी जा चुकी थी.
7. (B) शुद्ध गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ अनुपात का आगणन बैंकों के निबल अग्रिमों/ऋणों के सापेक्ष किया जाता है, जो बैंकों के बकाया कुल अग्रिमों/ऋणों में प्रावधानित धनराशि को घटाकर प्राप्त होता है.
8. (C) 9. (C) 10. (A) 11. (C)
12. (C) 13. (D) 14. (D)
15. (C) अमृत भारत ट्रेन एलएचबी पुश-पुल ट्रेन है. गैर-वातानुकूलित अमृत भारत ट्रेन में आगे और पीछे दोनों ओर इंजन लगेंगे. इन ट्रेनों में सुन्दर और आकर्षक गद्देदार सीटें, सामान रखने के लिए रैक, मोबाइल चार्जर पॉइन्ट, एलईडी लाइटें, सीसीटीवी, जनसूचना प्रणाली आदि लगाई गई हैं.
16. (A) वर्ष 2023 में भारत ने ₹ 9585 करोड़ ($ 1161 मिलियन) मूल्य की 377178 टन कॉफी का निर्यात किया, जो परिमाणात्मक रूप से वर्ष 2022 (398718 टन) की तुलना में 5·5 प्रतिशत कम था. डॉलर मूल्य में वर्ष 2023 का निर्यात ($ 1161 मिलियन) वर्ष 2022 के निर्यात $ 1115 मिलियन से 4·5 प्रतिशत अधिक था. रुपए मूल्य में कॉफी का वर्ष 2023 में निर्यात (₹ 9585 करोड़) वर्ष 2022 के निर्यात ₹ 8723 करोड़ से 9·51 प्रतिशत अधिक रहा. कॉफी का सर्वाधिक निर्यात

इटली को किया जाता है. इसके बाद जर्मनी तथा रूस का स्थान है.

17. (C)
18. (D) दाल बिक्री पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसान तूर दाल कहीं भी बेच सकते हैं.
19. (D) 20. (C)
21. (A) वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्रक की विकास दर 1·8% अनुमानित है.
22. (B) भारतीय स्टेट बैंक ने दीनदयाल उपाध्याय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका (DAY-NRLM) के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम सम्भव कागजी कार्रवाई के ₹ 5 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का एक उत्पाद है.
23. (C) यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक अन्तर-सरकारी संगठन है, जो आइसलैण्ड, लीशटेंस्टीन, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैण्ड के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है.
24. (B) 25. (C)
26. (D) भारत में दाखिल किए गए आयकर रिटर्नों की संख्या वित्त वर्ष 2013-14 में 3·8 करोड़ से 104·91% बढ़कर 2022-23 में 7·78 करोड़ हो गई.
27. (C) 28. (C)
29. (B) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय कोषों का अभिरक्षक है. विदेशी विनिमय कोषों में विदेशी करेंसियों, स्वर्ण भण्डार, विशेष आहरण अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व की स्थिति आते हैं.
30. (A) नीति आयोग के आकलनानुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता के अन्तर्गत जीवनयापन कर रहे लोगों का अनुपात वर्ष 2013-14 में 29·17% से घटकर 2022-23 में 11·28% रह गया है. 2019–21 के बीच यह अनुपात 14·96% था.
31. (C) 2013-14 एवं 2022-23 के बीच उत्तर प्रदेश में 5·94 करोड़, बिहार में 3·77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2·3 करोड़ तथा राजस्थान में 1·87 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए.
32. (A)
33. (A) नीति आयोग ने भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एण्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OAHI) के साथ मिलकर विकसित किया है.
34. (C) होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है, जो फारस की खाड़ी से खुले महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है. मलक्का जलडमरूमध्य अण्डमान सागर (हिन्द महासागर) और दक्षिण चीन सागर प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाला मार्ग है. बाब अल-मंडेव यमन और अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती और इरिट्रिया के बीच एक जलडमरूमध्य है.
35. (C) वित्त वर्ष 2022-23 (ब.अ.) में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का शिक्षा पर व्यय ₹ 7,57,138 करोड़ था, जो इनके कुल व्यय ₹ 80,08,684 करोड़ का 9·5% था.
36. (D) वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का कुल व्यय ₹ 80,08,684 करोड़ अनुमानित था जिसमें से 6·9% (₹ 5,48,855 करोड़) स्वास्थ्य पर खर्च किया गया.
37. (A) एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार 23 जनवरी, 2024 तक उसके द्वारा 2 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे, जो किसी एक बैंक द्वारा जारी किए गए सर्वाधिक थे. इसके बाद आईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड्स तथा एक्सिस बैंक का स्थान था.
38. (D) पाँचवें LEADS, 2023 में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु (तटीय राज्य संवर्ग), हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश (भूमि सीमाओं से घिरे राज्य संवर्ग), असम, सिक्किम तथा त्रिपुरा (पूर्वोत्तर राज्य संवर्ग) तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली (संशा.क्षे. संवर्ग) एचीवर्स संवर्ग में है.
39. (A) 40. (A) ●●●

शेष पृष्ठ 167 का

सही कूट है–
(A) केवल I
(B) केवल II
(C) I एवं II दोनों
(D) न I और न II

27. भारत द्वारा 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCC) में दाखिल राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदानों (NDCs) के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) नवम्बर 2023 में कुल विद्युत् स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का हिस्सा 43·9% था
(B) अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन सघनता को 2005 के स्तर से 2019 तक 33 प्रतिशत कर लिया था
(C) वर्ष 2019 तक 1·97 अरब टन CO_2 eg अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित किया जा चुका था
(D) भारत के सार्वजनिक नगर परिवहन के 40 प्रतिशत वाहन स्वच्छ ईंधन संचालित है

28. निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए–
I. सोलर पार्कों का विकास
II. रूफ टॉप सोलर स्कीम
III. नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज
IV. स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम
उपर्युक्त में से कौनसे कार्यक्रम ने ऊर्जा बचत एवं गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाने में योगदान दिया है ?
(A) केवल I, II, III
(B) केवल I, II, IV
(C) केवल I, II, V
(D) I, II, III, IV, V सभी

29. भारत में निम्नलिखित में से कौनसी योजना ऊर्जा दक्षता प्रोन्नयन पर केन्द्रित नहीं है ?
(A) सौभाग्य योजना (SAUBHAGYA)
(B) पीएम-कुसुम (PM-KUSUM)
(C) उजाला (UJALA)
(D) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

30. 'LiFE' के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?
(A) Lifestyle for Environment आन्दोलन 2021 में घोषित किया गया
(B) यह भारत के नेतृत्व में चलाया गया आन्दोलन है
(C) इसके अन्तर्गत संवर्गों में 75 गैर-सम्पूर्ण सरल पर्यावरण मित्रवत् कार्ययोजनाएं चिन्हित की गई हैं
(D) इसका क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है

उत्तर व्याख्या सहित

1. (C)	2. (A)	3. (C)	4. (A)
5. (D)	6. (A)	7. (C)	8. (D)
9. (A)	10. (A)	11. (D)	12. (D)
13. (C)	14. (A)	15. (C)	16. (B)
17. (D)	18. (C)	19. (C)	20. (D)
21. (B)	22. (C)	23. (C)	24. (C)
25. (D)	26. (C)	27. (D)	28. (D)
29. (A)	30. (D)		●●●

कि समुद्री कृषि क्या होती है ?

☞ समुद्री शैवाल की खेती, जिसे समुद्री कृषि के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और कटाई की कार्यविधि है. समुद्री शैवाल समुद्री पौधों का एक विविध समूह है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मनुष्यों को कई लाभ प्रदान करता है. अपने उच्च पोषण मूल्य और बहुमुखी उपयोग के साथ, समुद्री शैवाल की खेती ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है.

समुद्री शैवाल की खेती की प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण में समुद्री शैवाल प्रजातियों की खेती शामिल है, जैसे कि समर्पित समुद्री शैवाल फार्म या समुद्र में निलम्बित खेती प्रणाली. ये प्रणालियाँ समुद्री शैवाल के विकास के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करती हैं, जिनमें पोषक तत्वों से भरपूर जल, इष्टतम सूर्य का प्रकाश और उचित जल संचलन शामिल हैं.

समुद्री शैवाल की खेती खाद्य उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है. यह विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जो इसे स्वस्थ आहार का एक मूल्यवान घटक बनाता है. इसके अतिरिक्त, समुद्री शैवाल के अर्क का उपयोग दवाओं, त्वचा देखभाल उत्पादों और उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है.

समुद्री शैवाल की खेती से कई पर्यावरणीय लाभ भी मिलते हैं. समुद्री शैवाल जल से अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पोषक तत्वों के प्रदूषण के प्रभाव को कम करते हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. वे कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं, वायुमण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है.

कुल मिलाकर, समुद्री शैवाल की खेती खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए एक स्थायी और आशाजनक समाधान प्रस्तुत करती है. जैसे-जैसे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, समुद्री शैवाल की खेती विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने की क्षमता रखती है.

कि प्राचीन ढोकरा कला क्या है ?

☞ भारत एक ऐसा देश है, जहाँ विभिन्न कलाओं व संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है. सभी प्रकार की कलाएं किसी-न-किसी रूप में इतिहास से जुड़कर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती है. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ढोकरा कला भी इन्हीं कलाओं में से एक है. इस कला का दूसरा नाम घढ़वा कला भी है. यह कला प्राचीन होने के साथ-साथ असाधारण भी है.

इस कला में ताँबा, जस्ता व रांगा (टीन) आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन व रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं. इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है. इसलिए इसे मोम क्षय विधि (Vax Loss Process) भी कहते हैं.

इस कला का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है.

ढोकरा कारीगरों के अनुसार, वर्तमान में इन कारीगरों की सबसे बड़ी समस्या है– जीएसटी नई टैक्स प्रणाली का पालन कर पाना, इसके कारण इनके द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री लगभग आधी हो गई है.

वर्तमान बाजार में इस कला के पारम्परिक स्वरूप बदल गया है. मधुमक्खियों से प्राप्त मोम, जोकि इस कला की प्राथमिक आवश्यकता थी, अब उसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इतनी महँगी हो चुकी है कि इसे खरीदना आसान नहीं है. पारम्परिक पशु मूर्तियों–घोड़े, हाथी, ऊँट और ऐसी ही अन्य मूर्तियाँ–धीरे-धीरे पेपरवेट्स, पेन होल्डर, मोमबत्ती होल्डर जैसी अधिक कार्यात्मक चीजों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं.

हालाँकि, छत्तीसगढ़ का ओकरा स्टूडियो भारत के 4,000 वर्ष पुरानी इस शिल्पकला को संरक्षित करने में मदद कर रहा है.

कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है ?

☞ फ्लोर टेस्ट, जिसे 'विश्वास मत' के रूप में भी जाना जाता है, विधायी निकायों में यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सत्तारूढ़ सरकार अभी भी सदन का विश्वास रखती है या नहीं. यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है कि क्या एक सरकार, जिसे अपना बहुमत खोने का संदेह है, अभी भी बहुमत विधायकों का समर्थन बरकरार रखती है.

विधायी सत्र के दौरान, अध्यक्ष के पास शक्ति परीक्षण शुरू करने का अधिकार होता है. ऐसी स्थिति में जहाँ विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत् शक्ति परीक्षण बुलाने का अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने, शिवराज सिंह चौहान और अन्य *बनाम* अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य (2020) के मामले में, जब सरकार के बहुमत खोने का प्रथम दृष्टया संकेत हो, तो फ्लोर टेस्ट बुलाने के अध्यक्ष के अधिकार की पुष्टि की थी.

फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को देखें, तो जब सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत की वैधता पर प्रश्न उठाया जाता है, तो बहुमत के समर्थन का दावा करने वाली पार्टी के नेता को विश्वास मत लाना होगा. मुख्यमंत्री विश्वास मत की माँग के लिए एक प्रस्ताव शुरू करते हैं, जहाँ उपस्थित विधायक अपना वोट डालते हैं. यदि अधिकांश सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो सरकार सत्ता बरकरार रखती है; अन्यथा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है.

मतदान प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ध्वनि मतदान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वोटों के भौतिक विभाजन सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है.

कि हैलोजन क्या होते हैं ?

☞ हैलोजन रासायनिक तत्वों का एक समूह है, जो आवर्त सारणी के समूह 17 से सम्बन्धित है. इस समूह में फ्लोरीन (F), क्लोरीन (Cl), ब्रोमीन (Br), आयोडीन (I) और एस्टैटिन (At) शामिल हैं. हैलोजन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु हैं और अपने अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं.

हैलोजन कमरे के तापमान पर विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में मौजूद होते हैं–फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन एक तरल है और आयोडीन एक ठोस है. एस्टैटिन रेडियोधर्मी है और अत्यंत दुर्लभ है. वे विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं–फ्लोरीन हल्का पीला है, क्लोरीन हरा-पीला है, ब्रोमीन लाल-भूरा है, आयोडीन बैंगनी है और एस्टैटिन सम्भवतः काला है.

हैलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उन्हें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं. वे अपने अष्टक को पूरा करने और एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों, विशेषकर धातुओं के साथ आसानी से यौगिक बनाते हैं. हैलोजन मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट हैं, जो प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में सक्षम हैं. बढ़ते परमाणु आकार और घटती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण समूह में फ्लोरीन से आयोडीन तक हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है.

हैलोजन जैविक प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि थायराइड हॉर्मोन (आयोडीन) और एंजाइमों के कार्य में तथा जल शुद्धिकरण से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और वस्त्रों के उत्पादन तक कई औद्योगिक प्रक्रियाएं हैलोजन और उनके यौगिकों पर निर्भर करती हैं. साथ ही हैलोजन यौगिकों का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है. ●●●

प्रश्न–फोटो-वोल्टेइक पदार्थ क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं ?

उत्तर–विद्युत् संचालन की दृष्टि से पदार्थों को तीन वर्गों में बाँटा गया है–चालक, अर्द्धचालक तथा कुचालक. इन पदार्थों में एक चौथा पदार्थ भी खोजा गया है, जिसे सुपरकंडक्टर कहा जाता है.

सुपरकंडक्टर पदार्थों के वर्ग में कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, जो दृश्यमान प्रकाश में लाए जाने पर चालक बन जाते हैं. ऐसे पदार्थ फोटो-कंडक्टर कहलाते हैं. इस वर्ग में कुछ पदार्थों में से दृश्यमान प्रकाश में लाए जाने पर दो सतहों के बीच अन्तर पैदा हो जाता है. इन्हें फोटो-वोल्टेइक पदार्थ कहा जाता है. फोटो-वोल्टेइक सामग्री में सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फेट, इंडियम एंटीमोनाइड आदि शामिल हैं. इन पदार्थों की फोटो कंडक्टिंग विशेषताएं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के ऊर्जा अन्तर से जुड़ी हुई हैं. चूँकि प्रत्येक पदार्थ का यह बैंड निश्चित होता है, इसलिए, सौर विकिरण का उपयोग वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है. मुख्य फोटो-वोल्टेइक सामग्री में कुछ खास प्रकार के पदार्थ अल्प मात्रा में शामिल करने से ऊर्जा में थोड़ी-सी वृद्धि करना सम्भव है. सोलर सेलों व जेनरेटरों के निर्माण में यही सिद्धान्त कार्य करता है.

फोटो-वोल्टेइक सामग्री में सिलिकॉन सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध है. इसे रेत (Sand) से तैयार किया जा सकता है. श्रेष्ठ सोलर सेल एक स्फाटकीय सिलिकॉन से प्राप्त किए जाते हैं.

प्रश्न–ऊष्मा बजट (Heat Budget) क्या है ?

उत्तर–सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊष्मा का लगभग 35 प्रतिशत अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है. (6 प्रतिशत वायुमण्डलीय प्रकीर्णन द्वारा, 27 प्रतिशत बादलों से परावर्तन द्वारा और 2 प्रतिशत भूतल से परावर्तन द्वारा). इसी प्रकार 14 प्रतिशत ऊष्मा का अवशोषण जलवाष्प, बादलों, धूलिकणों तथा कुछ स्थायी गैसों के माध्यम से वायुमण्डल द्वारा कर लिया जाता है. शेष 51 प्रतिशत ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है. (34 प्रतिशत प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से और 17 प्रतिशत विसरित दिवा प्रकाश से). इस प्रकार सूर्य से विकीर्ण कुल सौर ऊष्मा का 51 प्रतिशत पृथ्वी का ऊष्मा बजट है. वायुमण्डल का ऊष्मा बजट, सौर ऊष्मा का 48 प्रतिशत होता है. वायुमण्डल को 14 प्रतिशत ऊष्मा सौर विकिरण से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है और 34 प्रतिशत पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा मिलती है. वायुमण्डल और पृथ्वी को सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उतनी ही ऊष्मा का ह्रास भी होता है, जिससे उनका ऊष्मा संतुलन बना रहता है. पृथ्वी को सौर ऊष्मा का जो 51 प्रतिशत प्राप्त होता है उसमें से 23 प्रतिशत भूतल से दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण द्वारा नष्ट हो जाता है, 17 प्रतिशत शून्य में वापस चला जाता है, 6 प्रतिशत प्रभावी किरण के रूप में वायुमण्डल को गर्म करता है और शेष 9 प्रतिशत भाग ऊष्मा विक्षोभ तथा संवहन के रूप में चला जाता है. यही पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन है जिसके अन्तर्गत सौर विकिरण द्वारा प्राप्त कुल ऊष्मा और दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा नष्ट ऊष्मा की मात्रा बराबर हो जाती है और भूतल पर ऊष्मा संतुलन प्राप्त होता है.

प्रश्न–ट्रांसपोंडर्स क्या हैं ? इनके क्या उपयोग हैं ?

उत्तर–उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के संकेतों को ग्रहण करने और उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं.

किसी भी उपग्रह में ट्रांसपोंडर्स की संख्या उपग्रहों में लगे बैंड की विड्थ (Width) पर निर्भर करती है. आमतौर पर किसी भी उपग्रह में 12 ट्रांसपोंडर होते हैं. अपलिंक ट्रांसमिशन के लिए 3·9 से 6·4 गीगा हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी (आवृत्ति) बैंड वाले ट्रांसपोंडर का प्रयोग किया जाता है, जिसे उपग्रह के माध्यम से 3·7 और 42 गीगा हर्ट्ज के तरंगों में परिवर्तित कर पृथ्वी पर भेजा जाता है. वीडियो के लिए 40 मेगा हर्ट्ज के तरंगों वाली ट्रांसपोंडर का प्रयोग किया जाता है.

जिस उपग्रह में 24 ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, उसका उपयोग केवल प्रत्यावर्ती ध्रुवीय तरंग (Polarization) के लिए होता है और जिस उपग्रह में 12 ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, उसका उपयोग केवल समानांतर ध्रुवीय तरंगों के लिए होता है.

प्रश्न–ई-हेरिटेज क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है ?

उत्तर–भारत की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है. इसके तहत् कम्प्यूटर के माध्यम से थ्री-डी तस्वीरों को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है. वास्तुकला, मूर्तिकला, नाट्यकला, संगीत व साहित्य के विविध आयामों को डिजिटाइल कर कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाएगा. डिजिटल चित्रों से मूर्तियों के कई आयामों को देखा जा सकता है और दूसरे धातुओं को देखा जा सकता है और दूसरे धातुओं अथवा सामग्री से उनकी आकृति भी तैयार की जा सकती है. डेटा सुरक्षित होने से नकली मूर्तियों को पहचाना जा सकेगा और असली मूर्तियों के किसी भी हिस्से के टूट जाने पर उसका वह हिस्सा जोड़ा जा सकेगा.

प्रश्न–ट्रांसएंब्रियो क्या है और इसके क्या उपयोग हैं ?

उत्तर–यह एक ऐसी तकनीक है, जिससे ऐसे ट्रांसजेनिक जानवरों को तैयार करना सम्भव होगा, जिन्हें रोग नहीं लगेंगे. इसका विकास अमरीकी वैज्ञानिकों ने किया है. इस तकनीक की विशेष बात यह है कि इससे वैज्ञानिकों को चूहे और मूषक ही नहीं, बल्कि सभी स्तनधारी प्रजातियों के बदले हुए जीन वाले जानवर तैयार करने में सहायता मिलेगी.

प्रश्न–अंटार्कटिका अनुसंधान से सम्बन्धित अंटार्कटिका संधि क्या है ?

उत्तर–अंटार्कटिका (दक्षिणी ध्रुव) पहले एक रहस्यमय क्षेत्र था. यह अत्यधिक ठंडा प्रदेश है, जिसे खनिज संसाधनों से समृद्ध माना जाता है. इन संसाधनों के उपयोग करने के प्रयास चल रहे हैं.

दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर पहुँचने वालों में सर्वप्रथम श्रेय नॉर्वे निवासी एंडरसन को दिया है. अमरीकी नौसेना अधिकारी बायर्ड ने 1928 में प्रथम 'अंटार्कटिका दल' (Antarctica Expendition) का नेतृत्व किया था. इस अभियान दल के बाद ही यात्राओं, अनुसंधानों तथा व्यापक सर्वेक्षणों का ऐसा दौर प्रारम्भ हुआ, जो निरन्तर जारी है.

अंटार्कटिका में वैज्ञानिक खोज की शुरूआत वर्ष 1957-58 में हुई, जो अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष भी था और तब से विभिन्न देशों द्वारा इस पूरे महादेश और इसके महासागरों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है. महीने के लम्बे विचार-विमर्श के बाद 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमरीका और सोवियत संघ सहित 12 देशों ने भाग लिया. 14 अनुच्छेदों वाली इस संधि का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अन्वेषणों की स्वतंत्रता है. इस महाद्वीप का शांतिपूर्ण उपयोग करना है. यह संधि 1961 से प्रभाव में है. ●●●

प्रथम पुरस्कृत निबन्ध

जाति व्यवस्था की ओर वापस लौटती भारतीय राजनीति

—प्रभाष पाठक

आमतौर पर संस्कृतियाँ अपने स्वरूप में स्थानीय होती हैं. संसार की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक भारतीय संस्कृति अनेक तत्वों के स्तरीकरण से व्युत्पन्न विविधताओं से परिपूर्ण है. संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशानुगत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है. वंशानुगत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर-जातिगत स्तरीकरण है. वंशानुगत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है. जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है, तो वंशानुगत स्तरीकरण निर्मित हो जाता है. सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अन्तर्गत पद-स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है. स्पष्टतः भारतीय समाज जाति के लिहाज से ऐतिहासिक रूप से पदक्रमित सामाजिक स्तरीकरण रहा है.

भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ समतावादी मूल्य पर आधारित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हुई, तब जाति व्यवस्था के परम्परागत नियमों में बहुत तेजी से परिवर्तन होने लगा. औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, स्त्री-जागरूकता तथा गतिशीलता में वृद्धि होने से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल पड़ने लगे. इसके साथ ही अनेक सामाजिक अधिनियमों ने भी जाति व्यवस्था की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया. स्वयं जाति व्यवस्था से उत्पन्न दोषों ने भी लोगों में इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह उत्पन्न कर दिया था. पहले की तुलना में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जाति का महत्व थोड़ा कम अवश्य हुआ है, परन्तु राजनीति के धरातल में इसकी सत्यता की जाँच की जाए, तो यह देश का हर नागरिक स्वीकार करेगा, कि जातिवाद का मुद्दा सभी राजनीतिक दलों द्वारा सुलगाया हुआ है, ताकि समय-समय पर राजनीतिक हवा देकर इससे लाभ उठाया जा सके. वर्तमान में भारतीय राजनीति पुनः जाति व्यवस्था की ओर वापस लौट रही है या नहीं, इस सम्बन्ध में हमें जाति क्या है? जाति व्यवस्था का स्वरूप क्या है? इसका राजनीति से कैसा सम्बन्ध है एवं वर्तमान में राजनीति और जाति की परस्पर निर्भरता पर विस्तृत चर्चा के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुँचना समुचित प्रतीत होता है.

जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के Caste का हिन्दी रूपांतरण है. Caste (कास्ट) शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द Casta से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल से है. कास्ट शब्द लैटिन भाषा के Castus से भी घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, जिसका अर्थ विशुद्ध या अमिश्रित है. साथ ही जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है—जन्म. इस प्रकार जाति का अर्थ वंशानुक्रम पर आधारित विशेष सामाजिक समूह से लगाया जाता है. स्पष्ट शब्दों में जाति प्रथा जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था का नाम है. जे. हट्टन के अनुसार, "जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज अनेक आत्मकेन्द्रित एवं एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् इकाइयों में विभाजित रहता है." जाति का वास्तविक अर्थ एक सामाजिक समूह के रूप में लिया जाता है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है. विद्वान् काले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तो इसे हम जाति कहते हैं. हबल का मानना है कि अंतर्विवाह और वंशानुक्रमण द्वारा प्रदत्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति है.

भारतीय जाति प्रथा अपनी तरह की विचित्र और रोचक संस्था है. भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था ने ना केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों को ही प्रभावित किया है, अपितु राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया है. वैसे भी राजनीति केवल सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है. सामाजिक संस्था के रूप में यह वृहद् मजबूती के साथ खड़ी है तथा आधुनिकीकरण के युग में भी जाति अभी विद्यमान है. यद्यपि जाति के अन्दर बहुत परिवर्तन आ गया है, परन्तु यह राजनीति और राजनीतिक दलों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है तथा कोई भी राजनीतिक दल इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता. जाति भारतीय राजनीति में जोड़ने वाली और बाँटने वाली दोनों कारकों के रूप में कार्य करती है. जाति की विशिष्ट पहचान के प्रति सकारात्मक आकर्षण ही एकसमान मूल्यों के प्रति आकर्षण को जन्म देता है. लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है कि उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त करके अपनी स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए. भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहना सही होगा कि भारतीय राजनीति जाति के इर्द-गिर्द घूमती है.

जाति व्यवस्था का राजनीति में सकारात्मक परिणाम देखें, तो जाति आधारित राजनीति ने सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया को जन्म दिया है. इसके कारण समाज के वंचित और कमजोर समूह को मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिलता है जिससे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होती है. विभिन्न समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलता है. पिछले तीन दशकों के दौरान जाति की राजनीति ने उच्च जातियों से मध्यवर्ती जातियों में सत्ता के हस्तांतरण को जन्म दिया है, तो दूसरी ओर नेतृत्व की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है और प्रांतीय स्तर पर अन्य पिछड़े वर्ग के नेतृत्व का आविर्भाव हुआ है. स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में जाति जागरूकता का सशक्त उपकरण, संचार का माध्यम और प्रतिनिधित्व भागीदारी और नेतृत्व का प्रभावी साधन है. वैसे भी भारत में स्थापित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल्य जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है. आज के बदलते परिवेश में, जब भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व मंच पर अपने सुदृढ़ उपस्थिति की दस्तक दे रहा है, ऐसे में जातिवाद की अपरिहार्य भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. प्रोफेसर रुडोल्फ के शब्दों में कहें, तो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में जातिवाद वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों एवं तरीकों की खोज की जा रही है, जिसके जरिए भारत को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा गया है.

उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद जातिवाद की धारणा प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत प्रतीत होती है. सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जा सकता. जाति आधारित राजनीति गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाती है और कहीं-न-कहीं इसके कारण मूल्य-आधारित राजनीति पर व्यक्तिगत राजनीति को बहुलता मिलती है. साथ ही इसने व्यक्ति आधारित राजनीति और वंशवाद की जड़ों को मजबूत बनाने में अहम् भूमिका निभाई है. इसने राजनीतिक दलों के स्वरूप को भी अलोकतांत्रिक बनाया है. इसके कारण समाज में जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है. जाति-आधारित राजनीति ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को जातिगत संदर्भों तक सीमित कर दिया. भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में माना जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा होता है, उस क्षेत्र में

जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है. अतः स्पष्ट है कि जाति और राजनीति के मध्य अंतःक्रिया पाए जाने का परिणाम यह हुआ कि बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो गया है.

प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक उल्लेखनीय पक्ष भारतीय राजनीति में जाति की घुसपैठ है. जाति समूहों के बीच पारम्परिक सामाजिक मतभेदों को जानबूझकर कठोर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता में बदल दिया जाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान राजनीति ने विभिन्न जाति समूहों को एक नई राजनीतिक आवाज प्रदान की है तथा उन्हें प्रमुख जातियों के खिलाफ संगठित किया है. इस तरह की मैकियावेलियन राजनीति ने जाति की राजनीति के पारम्परिक व्याकरण को फिर से परिभाषित किया है तथा राजनीति में जाति की प्रासंगिकता पर फिर से जोर दिया है. प्रोफेसर रजनी कोठारी ने लिखा है कि आज राजनीति एक प्रतियोगी उद्यम है और इसका उद्देश्य गति पर लक्षण की प्राप्ति के लिए शक्ति को अर्जित करना है. अतः उन्होंने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स' में यह दलील दी थी कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हो रहा है. उनके अनुसार राजनीति पर जाति का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा है, बल्कि जाति का राजनीतिकरण हुआ है. रजनी कोठारी के अनुसार भारत में जाति के राजनीतिकरण ने दलगत राजनीति को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने साबित किया कि एक औसत जाति प्रथा को अपने राजनीतिक संगठन के जाल में ले आने से राजनीति को अपने लिए मसाला मिल जाता है, तो दूसरी ओर राजनीति में सक्रिय होने से जातीय समूह को अपनी पहचान बनाने तथा पद एवं शक्ति प्राप्त करने का अवसर भी मिल जाता है. चुनाव के दौरान जाति को उपयोगी एवं सुविधाजनक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है. भारतीय राज्यों में राजनीति को राजनीतिक सत्ता के लिए प्रमुख जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी देखा गया है.

यह भी मान्य है कि जाति राष्ट्रीय राजनीति को खंडित करती है. जाति एक सामाजिक वास्तविकता में रहने वाली संस्था बनी हुई है, जैसाकि मायरो विनर ने कहा है कि ऑर्थोप्रेक्सी अभी भी जारी है. जाति और राजनीति के मध्य अंतःक्रिया पाए जाने का परिणाम यह हुआ है कि बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो गया है. रजनी कोठारी द्वारा कहा गया जिज्ञासु संज्ञानात्मक अंतराल अवधारणा द्वारा जिसने परम्परा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व को समझाया है. इस प्रक्रिया में जैसे जाति राजनीति को बदलता और प्रभावित करती रही है वैसे ही राजनीति भी जाति व्यवस्था को प्रभावित और बदलती रही है. राजनीतिक जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति को किसी अन्य समूह की तुलना में अपनी जाति के प्रति अधिक वफादार होना आवश्यक है इसलिए यह लोगों के बीच राष्ट्रवाद के बजाय जातिवाद को बढ़ावा देता है. लोकतंत्र में जातिवाद ने कहीं-ना-कहीं किसी एक जाति विशेष के सीमित हितों को वरीयता देकर बहुसंख्यकों के हितों को प्रभावित किया. इस सच्चाई को कोई कितना भी नकारे, मगर आज भी भारतीय जनतंत्र की मुख्य राजनैतिक धुरी नागरिक नहीं, बल्कि जाति ही है.

लोकतांत्रिक आदर्श मानव समानता की पूर्ण धारणा रखते हैं, जबकि जाति व्यवस्था असमानता में विश्वास करती है. हाल के वर्षों में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और शिक्षा जैसे उपायों के माध्यम से जाति व्यवस्था को खत्म करने और अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं. वास्तव में जाति और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एक-दूसरे के विरोधी मूल्यों के प्रतीक हैं. बिहार सरीखे राज्यों में जाति आधारित जनगणना के द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाकर जातीय अस्मिता की मुखर राजनीति वाले राज्यों में अगर सामाजिक समीकरण के अनुरूप राजनीतिक समीकरण बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं. स्पष्ट है कि भारत में हाल के दिनों में जाति आधारित आरक्षण व जनगणना के उद्भव ने पुनः सभी दलों के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन तैयार कर दी है.

निष्कर्ष–एलेक्जेंडर पोप ने कहा था कि राजनीति कुछ इंसानों के लाभार्थ बहुत से व्यक्तियों का उन्माद है. भारतीय संदर्भ में देखें, तो यह कथन उचित एवं प्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका वास्तव में रक्त धमनियों की तरह है. जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे खुले तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया जाता. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत पहले कहा था कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा, जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन रही है. जब राजनीतिक फायदा उठाने की बात होती है, तो जाति का सवाल खड़ा कर दिया जाता है. वैसे भी भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है. यह केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की खाई पैदा नहीं करती, अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करती है. जातिवाद से आक्रांत समाज की कमजोरी विस्तृत क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती, जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की अपेक्षा करते हुए पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं को वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधानुकरण करता रहता है, वह समाज पिछड़ जाता है. **इतिहासकार विंसेंट स्मिथ** का यह सुविचारित मत था कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय संवैधानिक प्रणाली के माध्यम से जातिवाद की कठोरता और भेदकारी प्रवृत्तियाँ कम होने के बजाय और बढ़ेंगी. जातीय जनगणना की माँग और वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में हम सभी अपनी आँखों से देख रहे हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जाति राजनीति उत्तरोत्तर बलवान होती जा रही है. अतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति जाति व्यवस्था की ओर वापस नहीं लौट रही है. ●●●

उपकार छत्तीसगढ़

प्री-डी.एल.एड. परीक्षा

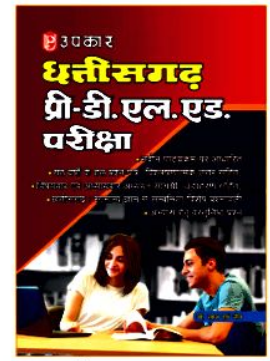

- नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित
- गत वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (विश्लेषणात्मक उत्तर सहित)
- विषयवार एवं अध्यायवार अध्ययन सामग्री (उदाहरण सहित)
- छत्तीसगढ़ : सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित विशेष प्रश्नावली
- अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न

कोड : 1361
मूल्य : ₹ 355.00
डॉ. लाल एवं जैन

उपकार प्रकाशन, आगरा-5 | E-mail : care@upkar.in | Website : www.upkar.in

सभी प्रकार की मासिक पत्रिका मैगजीन पढ़ने वाले इस पेज को किलक करे जरूर करे 👇

https://t.me/Magazine9876

Those who read all types of monthly magazines must join this group.

Please touch this page

👆 👆

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-535 का परिणाम

प्रथम

द्वितीय

तृतीय

विषय : "जाति व्यवस्था की ओर वापस लौटती भारतीय राजनीति."

प्रथम– प्रभाष पाठक
अवर सांख्यिकी पदाधिकारी
नीलकंठ नगर, तिलकामांझी
भागलपुर, बिहार
पिन–812 001

द्वितीय– डॉ. राजीव कुमार सिंह
क्वार्टर नं. 10, ब्लॉक-19 पुष्प विहार,
सेक्टर-1, नई दिल्ली–110 017

तृतीय– विभव सक्सेना S/o श्री रघुवंश चन्द्र सक्सेना
4-बी, बल्लभ नगर कॉलोनी
पीलीभीत–262 001 (उत्तर प्रदेश)

अन्य प्रशंसनीय प्रयास

1. महेंद्र धाकड़ (पटवारी)
ग्राम–बरोदिया
तहसील–बमोरी
जिला–गुना (म. प्र.)

2. जीतेन्द्र कुमार सिंह रावत
C/o धर्मकाँटा, अनाज मंडी
सुनेहरा रोड,
सबलगढ़, मुरैना–476 229

3. राखी कुमारी
बाबाजी कुटी, बनगाँव
सहरसा, बिहार–852 201

4. नीरज कुमार आजाद
स्कूल प्रवक्ता
गांधी नगर, चंदौती
गया (बिहार)

5. समाधी वर्मा
कुंवर टोला
सहरसा
बिहार–852 201

➡ उपर्युक्त प्रशंसित निबन्ध प्रतियोगियों में से प्रत्येक को उपकार प्रकाशन की ₹ 300 मूल्य की वांछित पुस्तक/पुस्तकें भेंटस्वरूप प्रदान की जाएंगी. **कृपया अपनी पसन्द की पुस्तक अलग से प्रकाशक के नाम पत्र द्वारा सूचित करें.** यदि ₹ 300 से अधिक मूल्य की पुस्तक की माँग की गई है, तो उसके मूल्य में से ₹ 300 पुरस्कारस्वरूप कम कर दिए जाएंगे.

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक–218 का सर्वशुद्ध हल एवं पुरस्कार विजेता

प्रतियोगिता के नियमानुसार प्रवेश प्रारूप-पत्र पर प्राप्त हलों के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने में सफल हुए हैं. **'प्रतियोगिता दर्पण'** उनकी सफलता पर शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है तथा उनकी खोजपूर्ण प्रवृत्ति के प्रति आभार व्यक्त करती है.

पुरस्कृत विजेता

प्रथम पुरस्कार मो. अख्तर जमाल
C/o वन स्टॉप सोल्यूशन,
किला घाट मस्जिद के सामने
पोस्ट+जिला–दरभंगा (बिहार) पिन–846 004

द्वितीय पुरस्कार शाहिदा परवीन
C/o एस. अख्तर हसन
मोहल्ला–सेनापत कालोनी, पोस्ट–लाल बाग
जिला–दरभंगा (बिहार) पिन–846 004

तृतीय पुरस्कार अब्दुल जब्बार अंसारी
C/o जाहिद हुसैन
डढ़िया बेलार
जिला–समस्तीपुर (बिहार) पिन–848 129

सर्वशुद्ध हल

1. (B)	2. (C)	3. (C)	4. (B)	5. (C)	6. (D)	7. (A)
8. (C)	9. (B)	10. (C)	11. (A)	12. (A)	13. (C)	14. (C)
15. (A)	16. (D)	17. (C)	18. (D)	19. (A)	20. (B)	21. (B)
22. (D)	23. (A)	24. (D)	25. (A)	26. (B)	27. (B)	28. (A)

शेष पृष्ठ 161 का

22. 'ट्राई' की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2023 के अंत में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शनों में वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शन लगभग कितने प्रतिशत है ?
(A) 3 प्रतिशत (B) 6 प्रतिशत
(C) 9 प्रतिशत (D) 12 प्रतिशत

23. दूरसंचार के 22 लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज (LSAs) में से निम्नलिखित में से किस एरिया में टेलीडेंसिटी सबसे कम है ?
(A) उत्तर प्रदेश (B) बिहार
(C) असम (D) हिमाचल प्रदेश

24. भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है. इस पुस्तक के तहत् देय पुरस्कार राशि इस वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है ?
(A) ₹ 15 लाख (B) ₹ 25 लाख
(C) ₹ 50 लाख (D) ₹ 1 करोड़

25. टेक्सटाइल क्षेत्र की विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2024 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2024 में हुआ ?
(A) नई दिल्ली (B) गौतमबुद्ध नगर
(C) सूरत (D) अहमदाबाद

उत्तरमाला

1. (B)	2. (B)	3. (C)	4. (D)	5. (C)
6. (B)	7. (C)	8. (D)	9. (A)	10. (A)
11. (A)	12. (B)	13. (A)	14. (D)	15. (A)
16. (B)	17. (C)	18. (C)	19. (B)	20. (C)
21. (C)	22. (A)	23. (B)	24. (A)	25. (A)

●●●

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

1. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, किस देश की न्याय-प्रणाली से प्रेरित है ?
   (A) आस्ट्रेलिया
   (B) कनाडा
   (C) ब्रिटेन
   (D) फ्रांस

2. कुछ स्थितियों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौनसा है ?
   (A) 259
   (B) 256
   (C) 257
   (D) 258

3. पहली बार बिहार के किस जिले में पंचायती राज लागू नहीं किया गया था ?
   (A) भागलपुर
   (B) छपरा
   (C) मुजफ्फरपुर
   (D) राँची

4. जैव-विविधता का मापन कितने आधार पर किया जाता है ?
   (A) 4 (B) 5
   (C) 3 (D) 2

5. प्लैंकटानिक जीव, समुद्री जीवोम कहाँ मिलते हैं ?
   (A) सतह पर
   (B) पेंदी पर
   (C) मध्यवर्ती भाग में
   (D) प्रत्येक भाग में

6. नेकटॉन क्या है ?
   (A) तैरने वाला जीव
   (B) एक समुद्री पौधा
   (C) मछलियों का भोजन
   (D) एक द्वीप

7. पठारी भागों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है ?
   (A) कृषि
   (B) खनन
   (C) पशुपालन
   (D) व्यापार

8. भूपटल पर वलन का निर्माण निम्नलिखित में से किस शक्ति से होता है ?
   (A) क्षैतिज (B) तिर्यक
   (C) लम्बवत् (D) आरीय

9. एण्डीज का गायातिरी भूकम्प कैसा था ?
   (A) विवर्तनिक
   (B) समस्थितिक
   (C) वितलीय
   (D) ज्वालामुखीय

10. बसोहली कला के चित्रों का विषय है–
    (A) सामाजिक
    (B) धार्मिक
    (C) आर्थिक
    (D) सांस्कृतिक

11. तान को मुख्यतः बाँटा जाता है–
    (A) तीन भागों में
    (B) चार भागों में
    (C) आठ भागों में
    (D) सात भागों में

12. गुजरात में लोक शैली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है ?
    (A) साथिया
    (B) चौक पूरना
    (C) अपहन
    (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. "नृत्य, संगीत का, दृश्यीकरण है" यह उक्ति निम्नलिखित महापुरुष की है–
    (A) अरस्तू
    (B) भरतमुनि
    (C) सुमन लैंगर
    (D) गोपीकृष्ण

14. किसने कहा था, "मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ ?"
    (A) रबीन्द्रनाथ टैगोर
    (B) सुकरात
    (C) रामकृष्ण परमहंस
    (D) प्लेटो

15. मुगलकाल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा था–
    (A) बसावन
    (B) मंसूर
    (C) दसवन्त
    (D) बीरबल

16. पारे की छोटी-छोटी बूँदें रूद्धोष्म रूप से मिलकर एक बड़ी बूँद बनाती है. बूँद का ताप–
    (A) बढ़ जाता है
    (B) घट जाता है
    (C) अपरिवर्तित रहता है
    (D) बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है

17. श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के निम्न भाग के लिए आँख-दृश्यता (Visibility) सर्वाधिक है–
    (A) नीला
    (B) हरा-पीला
    (C) पीला
    (D) लाल

18. क्लोरोबेंजीन निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करके डी.डी.टी. देता है–
    (A) फिनोल
    (B) क्लोरल
    (C) फॉर्मिक एसिड
    (D) एसिटिलिन

19. 'किताब-इ-नौरस' के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे ?
    (A) सोमेश्वर देव
    (B) फकीरूल्ला
    (C) इब्राहिम आदिलशाह
    (D) नान्यभूपाल द्वितीय

20. 'मानसोल्लास' ग्रंथ की रचना किस सदी में हुई ?
    (A) 9वीं
    (B) 10वीं
    (C) 12वीं
    (D) 14वीं

21. सालगसूड प्रबन्धों की संख्या कितनी है ?
    (A) 5
    (B) 6
    (C) 7
    (D) 8

22. 6 × 4 ड्राइव चैसिस गाड़ी में कितने पहिए होते हैं ?
    (A) 6 (B) 4
    (C) 8 (D) 12

23. धावकों को अपने खेल-प्रदर्शन में उन्नयन के लिए दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ और परिपूरक को कहते हैं–
    (A) हेल्थ फूड्स
    (B) थेरापेटिक फूड्स
    (C) अर्गोजेनिक फूड्स
    (D) न्यूट्रास्यूटिकल्स

24. अग्रलिखित में से कौनसा रोग बुढ़ापा से सम्बन्धित नहीं है ?

(A) बुलीमिया
(B) प्रेसबाइक्यूसिस
(C) मैकुलर रोग
(D) डिमेंशिया

25. सबसे पहले निम्नलिखित स्थान में आर्टिजन (पातालतोड़) कुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी–
(A) मुम्बई
(B) न्यूयॉर्क
(C) टोकियो
(D) आर्टिया

26. सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे अधिक सीखता है–
(A) समूह सम्पर्क द्वारा
(B) जनसम्पर्क द्वारा
(C) व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

27. संलग्न चित्र को पहचानिए–

(A) विश्वेश्वरैया
(B) बंकिमचन्द्र चटर्जी
(C) बाल गंगाधर तिलक
(D) सी.वी. रमण

28. पार्श्व में दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किनका है ?

(A) इमैनुएल मैक्रॉं
(B) स्टीवन स्पीलबर्ग
(C) लूला दा सिल्वा
(D) नोवाक जोकोविच

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के नियम

1. इसमें सभी विद्यार्थी अथवा किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्याशी भाग ले सकेंगे.
2. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को निर्धारित तिथि तक अपने उत्तर भेजना आवश्यक है. प्रविष्टियाँ सामान्य डाक से ही भेजी जाएं तथा लिफाफे पर बाईं ओर **'सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता'** अवश्य लिखें.
3. प्रतियोगिता के उत्तर पत्रिका में दिए गए प्रपत्र पर ही मान्य होंगे.
4. उत्तर-पत्र में प्रश्न के क्रमांक के आगे चार खाने बने हैं. प्रतियोगी जिस उत्तर को ठीक समझें उस कॉलम में केवल गुणा (×) का चिह्न लगाएं. एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देने पर वह प्रश्न निरस्त कर दिया जाएगा.
5. प्रतियोगी जितने प्रश्न हल करें उनकी संख्या स्वयं अवश्य लिखें.
6. अशुद्ध उत्तर देने पर अंक काटे जाएंगे.
7. सर्वाधिक शुद्ध हल भेजने वाले प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कारस्वरूप ₹ 900 दिए जाएंगे. उससे कम शुद्ध हल भेजने वाले प्रतियोगियों को क्रमशः द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा, जो क्रमशः ₹ 700 व ₹ 500 का होगा. यदि किसी पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों की संख्या एक से अधिक होगी, तो पुरस्कार राशि उनमें समान रूप से विभक्त कर दी जाएगी.
8. पुरस्कार के विषय में सम्पादक का निर्णय सर्वमान्य होगा. किसी भी दशा में वह न्यायालय का विषय नहीं होगा.

प्रतियोगिता प्रवेश प्रारूप

सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता क्रमांक–219 का हल भेजने की अन्तिम तिथि 10 अप्रैल, 2024

नाम श्री/कु./श्रीमती _____

पूरा पता _____

_____

_____

राज्य ..... **पिन कोड नं.** ☐☐☐☐☐☐

मो. नं. _____

आयु ..... **शैक्षणिक योग्यता** .....

प्रतियोगिता परीक्षा जिसकी तैयारी कर रहे/रही हैं _____

_____

मैंने प्रतियोगिता दर्पण द्वारा आयोजित **सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता** के नियमों का अध्ययन कर लिया है और मैं उनसे सहमत हूँ।

.....
(हस्ताक्षर)

परिणाम

कुल हल किए प्रश्नों की संख्या _____

शुद्ध हल प्रश्नों की संख्या _____

अशुद्ध हल प्रश्नों की संख्या _____

अर्जित अंक _____

उत्तर-पत्र

प्रश्न संख्या	A	B	C	D	प्रश्न संख्या	A	B	C	D
1.	☐	☐	☐	☐	15.	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	16.	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	17.	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	18.	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	19.	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐	20.	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	21.	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☐	☐	☐	22.	☐	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	23.	☐	☐	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	24.	☐	☐	☐	☐
11.	☐	☐	☐	☐	25.	☐	☐	☐	☐
12.	☐	☐	☐	☐	26.	☐	☐	☐	☐
13.	☐	☐	☐	☐	27.	☐	☐	☐	☐
14.	☐	☐	☐	☐	28.	☐	☐	☐	☐

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक राहुल जैन द्वारा मैसर्स प्रतियोगिता दर्पण के लिए उन्हीं के द्वारा थॉमसन प्रेस (इंडिया) लि. 18/35 देहली–मथुरा रोड, फरीदाबाद–121 007 (हरियाणा) से मुद्रित एवं 2/11A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-2 से प्रकाशित

New Fresh Arrivals

Code 791
₹ 335/-

प्रतियोगिता दर्पण

संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री. विभिन्न विश्वविद्यालयों के

भारतीय अर्थव्यवस्था

के प्रश्न-पत्र एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी.

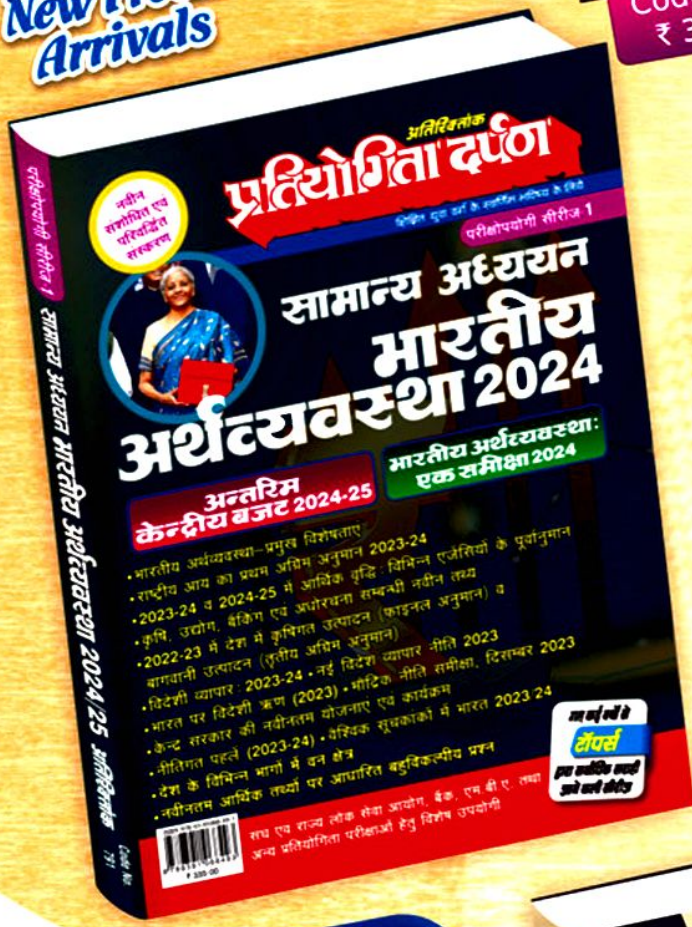

अन्तरिम केन्द्रीय बजट 2024-25

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा 2024

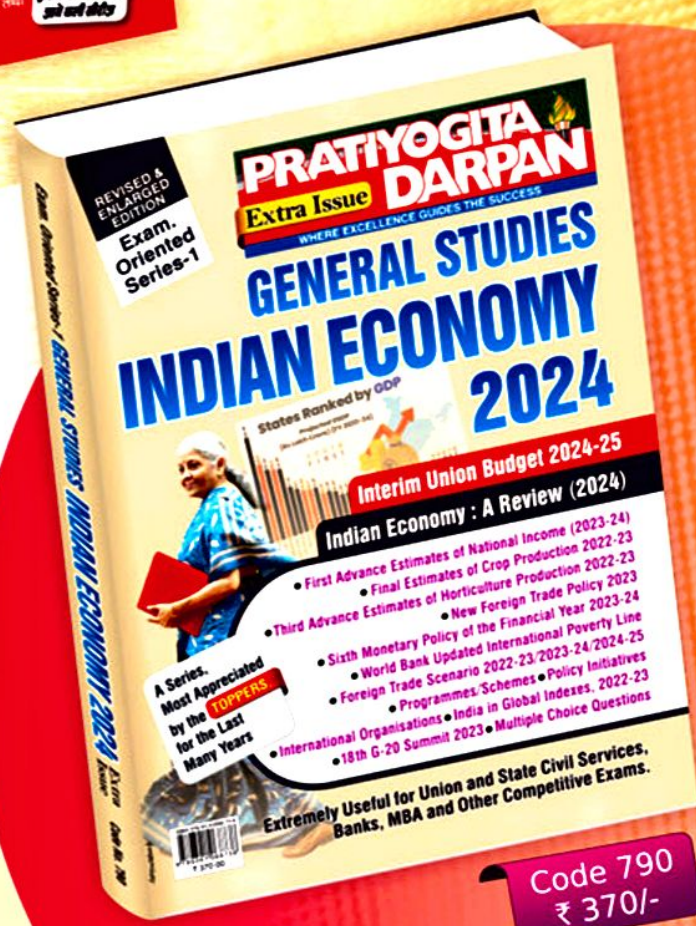

Code 790
₹ 370/-

Scan the QR Code with your mobile and buy QRPD012D

Download FREE QR Scanner app from the app store

Available on :

pdgroup.in amazon Flipkart

sales@pdgroup.in | www.pdgroup.in

• आगरा 2531101 • नई दिल्ली 23251844, 43259035
• पटना 2303340 • हल्द्वानी मो. 07060421008

Posting Date : 5, 6 & 7 Mar., 2024 (Agra-2)
Publishing Date : 5 Mar., 2024 Postal Regd. No. AGRA-047/2024-26
RNI No. 38696/79

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Heartiest Congratulations
to all candidates selected in CSE 2022

हिन्दी माध्यम में 40+ चयन

39 IN TOP 50 SELECTIONS IN CSE 2022
from various programs of VISIONIAS

= हिंदी माध्यम टॉपर =

1 AIR ISHITA KISHORE
2 AIR GARIMA LOHIA
3 AIR UMA HARATHI N
66 AIR KRITIKA MISHRA
YOU CAN BE NEXT

लाइव/ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं

कोई क्लास न छूटे
रिकॉर्डेड क्लासेस, मिनी टेस्ट, डेली असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री के साथ पूर्णतः रिवीजन करें

अभ्यास प्रीलिम्स 2024
आल इंडिया प्रीलिम्स (GS+CSAT) मॉक टेस्ट सीरीज
100+ शहरों में
पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas

PT 365
प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 वर्ष का समसामयिक घटनाक्रम केवल 60 घंटे में
23 फरवरी | 5 PM

लक्ष्य: प्रारंभिक परीक्षा
Lakshya
मेंटरिंग कार्यक्रम 2024
▸ वैयक्तिकृत और व्यवस्थित सलाह
▸ परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण
▸ अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहयोग
1 मार्च

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2025
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा
NCERT और मूलभूत किताबों से मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने और आपकी तैयारी की नींव मजबूत करने के लिए
DELHI: 5 मार्च, 1 PM
BHOPAL: 11 जून
LUCKNOW: 5 जून
JAIPUR: 21 फरवरी
JODHPUR: 7 मार्च

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज
प्रत्येक 3 में से 2 सफल उम्मीदवारों द्वारा चयनित
प्रारंभिक
○ सामान्य अध्ययन
○ सीसैट
मुख्य
○ सामान्य अध्ययन
○ निबंध ○ दर्शनशास्त्र

CSAT क्लासेस 2024
विश्लेषणात्मक कौशल, तार्किक तर्क, समझ, सामान्य मानसिक क्षमता और बुनियादी संख्यात्मकता की गहन समझ।
प्रवेश प्रारंभ

DELHI • 1st Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI